भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन

अप्रैल 2026

खंड 80 अंक 4

संपादक समिति
संजय हंसदा
रवि शंकर
रेखा मिश्र
राजीब दास
सुनिल कुमार
राजीव जैन
स्नेहल हेरवाडकर
वी. धन्या
श्वेता कुमारी
अनिर्बन सान्याल
सुजाता कुंडू

संपादक
राधेश्याम वर्मा

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के
निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा
मासिक आधार पर प्रकाशित की जाती है।
इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए
बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है।
हस्ताक्षरित आलेखों में व्यक्त विचारों के लिए
लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2026

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः उत्पादन की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन की सदस्यता के लिए कृपया 'हाल के प्रकाशन' खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को
https://bulletin.rbi.org.in पर देखा जा सकता है।

आरएनआई संख्या 13997/67

भारतीय रिज़र्व बैंक, शाहिद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से जी. वी. नथनयेल द्वारा मुद्रित और प्रकाशित।
जयंत प्रिंटरी एलएलपी. 352/54, गिरगांव रोड, मुरलीधर मंदिर कंपाउंड, ठाकुरद्वार पोस्ट ऑफिस के पास, मुंबई - 400 002 द्वारा मुद्रित।

विषय-वस्तु

द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (अप्रैल 6-8, 2026)

गवर्नर का वक्तव्य: अप्रैल 8, 2026 1

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6 से 8 अप्रैल 2026 7

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य 11

मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अप्रैल 2026 13

भाषण

भारत की विकास यात्रा और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में RBI की भूमिका 117
श्री संजय मल्होत्रा

वित्त में एआई: क्या बदल सकता है, क्या कभी नहीं बदलना चाहिए 123
श्री स्वामीनाथन जे.

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति 129

वर्तमान सांख्यिकी **159**

हाल के प्रकाशन **217**

द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (अप्रैल 6-8, 2026)

गवर्नर का वक्तव्य: अप्रैल 8, 2026

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6 से 8 अप्रैल 2026

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अप्रैल 2026

*गवर्नर का वक्तव्य**

श्री संजय मल्होत्रा

सुप्रभात और नमस्कार। मैं आप सभी का 2026-27 की पहली पॉलिसी में स्वागत करता हूँ, जिसका आयोजन एक ऐसे समय में किया गया है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में आई बाधाओं के कारण अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

संघर्ष शुरू होने से पहले, भारत के समष्टि-आर्थिक मूलभूत सिद्धांत सुदृढ़ संवृद्धि और कम मुद्रास्फीति के साथ आत्मविश्वास दिखा रहे थे। मार्च में हालात तब बिगड़ गए, जब संघर्ष और बढ़ गया तथा उसमें और तीव्रता आ गई। मौजूदा समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी तत्व, पिछले संकटों के मुकाबले और साथ ही कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ज़्यादा मज़बूत स्थिति में हैं, जिससे इसकी आघात-सहनीयता और बढ़ जाती है।

वैश्विक संवृद्धि को अब बढ़ते हुए अधोगामी जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऊर्जा की कीमतों में आई भारी तेज़ी और विभिन्न उद्योगों के लिए इनपुट की कमी ने मुद्रास्फीति की आशंकाओं को बढ़ा दिया है, और तेल बाज़ारों में भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम को बढ़ा दिया है। चल रहे संघर्ष के कारण उत्पन्न हुई बढ़ती अनिश्चितता, भावी संभावनाओं को प्रभावित कर रही है। सुरक्षित निवेश स्थलों (Safe haven) की ओर हो रहे प्रवाह ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर अवमूल्यन का दबाव डाला है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर मज़बूत हुआ है। जहाँ एक ओर धातु और सोने जैसी कमोडिटी की कीमतें नरम पड़ी हैं, वहीं दूसरी ओर वित्तीय बाज़ार अधिक अस्थिर हो गए हैं। इक्विटी बाज़ार में बड़े पैमाने पर सुधार देखने को मिला है। सॉवरेन बॉन्ड प्रतिफल, जो पहले से ही दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता संबंधी चिंताओं के कारण उच्च स्तर पर थे, अब मुद्रास्फीति के डर के कारण, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में और भी बढ़ गए गए हैं ।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 6, 7 और 8 अप्रैल को बैठक करके नीतिगत रेपो दर पर विचार-विमर्श किया और इससे संबंधित निर्णय लिया। बदलते समष्टि-आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों तथा भावी संभावनाओं का विस्तार से आकलन करने के बाद, एमपीसी ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर ही यथावत् रखा जाए; इसके परिणामस्वरूप, स्थाई जमा सुविधा (एसडीएफ़) दर 5.00 प्रतिशत पर और सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ़) दर तथा बैंक दर 5.50 प्रतिशत पर ही बने रहेंगे। एमपीसी ने तटस्थ रुख को जारी रखने का भी निर्णय लिया।

अब मैं संक्षेप में इन निर्णयों का औचित्य प्रस्तुत करूँगा।

एमपीसी ने यह पाया कि पिछली पॉलिसी बैठक के बाद से, भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं काफी बढ़ गई हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति काबू में है और तय लक्ष्य से नीचे है। हालांकि, मुद्रास्फीति संभावना के लिए ऊर्ध्वगामी जोखिम बढ़ गए हैं; इसकी वजह ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव और मौसम में संभावित गड़बड़ियां हैं, जो खाद्य पदार्थों की कीमतों पर असर डाल सकती हैं। मूल मुद्रास्फीति का दबाव कम बना हुआ है, हालांकि आपूर्ति शृंखला में रुकावटें और 'सेकंड-राउंड इफ़ेक्ट' का जोखिम मुद्रास्फीति संबंधी भावी रुख को अनिश्चित बना देते हैं।

एमपीसी ने आगे यह भी कहा कि फरवरी 2026 तक के उच्च आवर्ती संकेतक से पता चलता है कि आर्थिक गतिविधियों में मज़बूत रफ़्तार बनी रहेगी। संवृद्धि को मज़बूत निजी खपत और निवेश की मांग से लगातार समर्थन मिल रहा है। हालाँकि, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से संवृद्धि की गति में रुकावट आने की संभावना है। ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी, अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई और बीमा लागत में वृद्धि से जुड़ी ज़्यादा इनपुट लागत, और आपूर्ति शृंखला में आने वाली रुकावटें, जिनसे डाउनस्ट्रीम सेक्टरों के लिए ज़रूरी इनपुट की उपलब्धता सीमित हो जाएगी, संवृद्धि को नुकसान पहुँचा सकती हैं। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। इससे संघर्ष के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिलनी चाहिए।

एमपीसी का मानना है कि संघर्ष की तीव्रता और अवधि, और इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा और अन्य बुनियादी ढांचे को होने वाला नुकसान, मुद्रास्फीति और संवृद्धि की संभावनाओं के लिए जोखिम पैदा करता है। हालाँकि, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद अब ज़्यादा मज़बूत है, जिससे अतीत की तुलना में इसकी आघात-सहनीयता और बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था को आपूर्ति में

* गवर्नर का वक्तव्य - 8 अप्रैल 2026.

अचानक आई कमी का सामना करना पड़ रहा है। बदलते हालात और संवृद्धि-मुद्रास्फीति के बदलते अनुमानों पर नज़र रखना और इंतज़ार करना ही समझदारी है। इसलिए, एमपीसी ने नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने के पक्ष में वोट दिया; साथ ही वह सतर्क भी बनी हुई है, प्राप्त सूचनाओं पर बारीकी से नज़र रख रही है और जोखिमों के संतुलन का आकलन कर रही है। एमपीसी ने तटस्थ रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया, और प्राप्त सूचनाओं पर सोच-समझकर प्रतिक्रिया देने की अपनी सहूलियत को बरकरार रखा।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

भारतीय अर्थव्यवस्था पर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का प्रभाव

इससे पहले कि मैं संवृद्धि और मुद्रास्फीति संबंधी आकलन प्रस्तुत करूँ, मैं संक्षेप में उन माध्यमों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जिनके ज़रिए मौजूदा संघर्ष का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। पहला, कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोत्तरी के कारण आयातित मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती हैं और यह चालू खाता घाटे को और बढ़ा सकती हैं। दूसरा, ऊर्जा बाज़ारों, उर्वरकों और अन्य वस्तुओं में आने वाली बाधाएँ उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे घरेलू उत्पादन में कमी आ सकती है। तीसरा, बढ़ती अनिश्चितता, जोखिम से बचने की बढ़ती प्रवृत्ति और सुरक्षित निवेश की मांग से घरेलू चलनिधि की स्थिति, आर्थिक गतिविधियों, उपभोग और निवेश पर असर पड़ सकता है। चौथा, वैश्विक संवृद्धि की कमजोर संभावनाओं से बाहरी मांग कम हो सकती है और रेमिटेंस का प्रवाह घट सकता है। अंत में, वैश्विक वित्तीय बाजारों से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से घरेलू वित्तीय स्थितियां सख्त हो सकती हैं और इससे उधार लेने की लागत बढ़ सकती है। कुल मिलाकर, अगर आपूर्ति शृंखला की बहाली में देरी होती है, तो शुरुआती आपूर्ति आघात मध्यम अवधि में मांग आघात में बदल सकता है।

संवृद्धि

नई जीडीपी शृंखला (आधार वर्ष 2022-23) के अनुसार, 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि[1] 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह आर्थिक गतिविधियों में अंतर्निहित मज़बूत गति की पुष्टि करता है, जिसे सहायक नीतिगत उपायों, चल रहे संरचनात्मक सुधारों और अनुकूल वित्तीय स्थितियों के बीच, मज़बूत उपभोग और निवेश[2] का समर्थन प्राप्त है।

आगे चलकर, ऊर्जा और दूसरी कमोडिटी की बढ़ी हुई कीमतें, साथ ही होर्मुज़ जलडमरूमध्य में रुकावटों की वजह से इनपुट की उपलब्धता में आने वाली दिक्कतें, 2026-27 में संवृद्धि पर असर डाल सकती हैं। हालाँकि, सरकार ने आपूर्ति शृंखला में व्यावधानों के असर को कम करने के लिए, आवश्यक क्षेत्रों में इनपुट की सप्लाई सुनिश्चित करने में पहले से ही सक्रियता दिखाई है।[3] दूसरी ओर, सेवा क्षेत्र में लगातार बनी गति, जीएसटी के युक्तिकरण का प्रभाव, और वित्तीय संस्थानों तथा कंपनियों का मज़बूत तुलन-पत्र, आर्थिक गतिविधियों को लगातार सहारा देती रहेंगे। कृषि क्षेत्र की संभावनाओं को जलाशयों के अच्छे जल स्तर से बल मिल रहा है।[4] कारोबारी उम्मीदें आशावादी बनी हुई हैं,[5] और प्रमुख संकेतक विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में निरंतर सुदृढ़ता की ओर इशारा कर रहे हैं।[6] इसके अलावा, कई कार्यनीतिक और उभरते क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर सरकार का विशेष ध्यान भारत की आगामी संवृद्धि यात्रा के लिए शुभ संकेत है।

मांग के स्तर पर, 2026–27 में निजी उपभोग को विवेकाधीन खर्च से सहारा मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण मांग मज़बूत बनी

[1] मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित (GVA) में वर्ष-दर-वर्ष(व-द-व) 7.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों की संवृद्धि दर में कमी देखी गई, जो 2025-26 में 2.4 प्रतिशत रही; वहीं औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि दर बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो गई और सेवा क्षेत्र में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

[2] राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों (एसएई) के अनुसार, 2025-26 में GDP संवृद्धि 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो 2024-25 के 7.1 प्रतिशत और 2023-24 के 7.2 प्रतिशत से अधिक है। निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफ़सीई) और सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफ़सीएफ़) में क्रमशः 7.7 प्रतिशत और 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफ़सीई) में पिछले वर्ष की तुलना में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[3] स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ के बंद होने के मद्देनज़र, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: (i) पूरे देश में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की स्थिर उपलब्धता सुनिश्चित करना, और (ii) इस क्षेत्र में कार्यरत भारतीय जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा करना (पीआईबी, 22 मार्च 2026)।

[4] दिनांक 2 अप्रैल 2026 तक, 166 प्रमुख जलाशयों में अखिल भारतीय जल भंडारण कुल क्षमता का 47 प्रतिशत है; जबकि एक वर्ष पहले यह 40 प्रतिशत और पिछले दस वर्षों का औसत 37 प्रतिशत था। वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) के अनुसार, कुल खाद्यान्न उत्पादन में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

[5] मार्च 2026 में पीएमआई विनिर्माण भावी उत्पादन सूचकांक 67.3 पर रहा। अप्रैल 2025 से भावी उत्पादन सूचकांक 56.3 से ऊपर बना हुआ है।

[6] 2025-26 की चौथी तिमाही में जीएसटी ई-वे बिलों में 17.2 प्रतिशत की मज़बूत बढ़ोतरी हुई। चौथी तिमाही में कुल जीएसटी राजस्व में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मोटर वाहन बिक्री (रिटेल) में 22.2 प्रतिशत का विस्तार हुआ। फरवरी 2026 में स्टील की खपत में 12.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सीमेंट उत्पादन में 9.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। मार्च में पेट्रोलियम की खपत में वृद्धि की गति धीमी होकर 2.2 प्रतिशत रह गई, जो फरवरी 2026 में 5.5 प्रतिशत थी। मार्च के लिए पीएमआई सर्विसेज़ फरवरी के 58.1 से घटकर 57.5 पर आ गया है।

हुई है।[7] कृषि के लिए अनुकूल स्थितियों और एक स्वस्थ श्रम बाज़ार के चलते इसमें और तेज़ी आने की संभावना है।[8] जीएसटी की युक्तिकरण के लाभदायक प्रभाव और सेवा क्षेत्र की मज़बूत गतिविधियों की मदद से, शहरी खपत के और मज़बूत होने की संभावना है। जहाँ एक तरफ़ सरकार अवसंरचना संबंधी व्यय पर ज़ोर दे रही है[9], वहीं दूसरी तरफ़, ज़्यादा क्षमता के इस्तेमाल[10], सुदृढ़ ऋण संवृद्धि[11] और अनुकूल वित्तीय स्थितियों के चलते, निजी क्षेत्र के निवेश में आई तेज़ी के बने रहने की उम्मीद है। बाहरी मोर्चे पर, मुख्य शिपिंग रास्तों में रुकावटों, माल ढुलाई और बीमा की लागत में बढ़ोतरी, और संघर्ष के कारण वैश्विक माँग में कमी आने से, माल के निर्यात पर बुरा असर पड़ सकता है। हालाँकि, माल के निर्यात को हाल के व्यापार समझौतों से फ़ायदा मिल सकता है, जबकि सेवा निर्यात[12] के मज़बूत बने रहने की उम्मीद है।

इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है; जिसमें पहली तिमाही में 6.8 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 7.0 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 7.2 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। हालाँकि, संघर्ष का और बढ़ना और उसका व्यापक रूप से फैलना, वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ी हुई अस्थिरता और मौसम से जुड़ी घटनाएँ घरेलू संवृद्धि की संभावना पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। आधारभूत अनुमानों के लिए जोखिम अधोगामी हैं, और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण अत्यंत अनिश्चितता बनी हुई है।

मुद्रास्फीति

जनवरी–फरवरी के दौरान, खाद्य समूह में मुद्रास्फीति[13] के साथ, हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे बनी रही (क्रमशः 2.7 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत), जबकि पिछले चार महीनों में इसमें अपस्फीति देखी गई थी[14]। ईंधन संबंधी वस्तुओं में मुद्रास्फीति[15] मध्यम रही। मूल मुद्रास्फीति 3.7 प्रतिशत[16] रही और अंतर्निहित मूल्य दबाव स्थिर रहे, जैसा कि बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर मूल मुद्रास्फीति के 2.1 प्रतिशत के काफी निम्न स्तर से स्पष्ट है।

मुद्रास्फीति-संभावना की बात करें तो, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण ऊर्जा कीमतों में हालिया उछाल एक जोखिम के रूप में सामने आया है। यद्यपि पेट्रोल और डीज़ल के खुदरा मूल्य अब तक अपरिवर्तित रहे हैं, उच्च वैश्विक ऊर्जा कीमतों के संचरण के परिणामस्वरूप कुछ अन्य ईंधन संबंधी वस्तुओं में मूल्य वृद्धि हुई है[17]। निकट भविष्य में, सुदृढ़ रबी उत्पादन, पर्याप्त जलाशय स्तर तथा खाद्यान्नों के पर्याप्त सुरक्षित भंडारण[18] के कारण, खाद्य मूल्य संबंधी संभावना स्थिर बना रहेगा। एल नीनो

[7] जनवरी-फरवरी 2026 में, दोपहिया वाहनों और ट्रैक्टरों की खुदरा बिक्री में क्रमशः 23.2 प्रतिशत और 28.5 प्रतिशत की द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज की गई।

[8] मासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफ़एस) के अनुसार, फरवरी में अखिल भारतीय बेरोज़गारी दर 4.9 प्रतिशत के निचले स्तर पर बनी रही। 2025-26 की चौथी तिमाही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत काम की मांग में 21.0 प्रतिशत की गिरावट आई।

[9] केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) 2026-27 में 11.5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का अनुमान है। प्रभावी पूंजीगत व्यय (जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता अनुदान भी शामिल है) में 22.1 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

[10] आरबीआई के तिमाही आदेश बही, माल-सूची और क्षमता उपयोग (ओबीआईसीयूएस) सर्वेक्षण के अनुसार, 2025-26 की तीसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का मौसमी रूप से समायोजित क्षमता उपयोग (सीयू) 75.5 प्रतिशत रहा, जो 73.9 प्रतिशत के दीर्घकालिक औसत से थोड़ा ही अधिक था।

[11] फरवरी 2026 में, कपड़ा, रसायन, मूल धातु, रत्न और आभूषण तथा इंजीनियरिंग सामानों के लिए बैंक ऋण में वर्ष-दर-वर्ष क्रमशः 8.2 प्रतिशत, 19.1 प्रतिशत, 15.2 प्रतिशत, 40.2 प्रतिशत और 36.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[12] सेवाओं के निर्यात में जनवरी 2026 में 9.8 प्रतिशत और फरवरी 2026 में 9.7 प्रतिशत की तेज़ वृद्धि हुई।

[13] खाद्य एवं पेय पदार्थ खंड ने फरवरी में 3.4 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की, जिसमें 'मांस, ताजा, शीतित अथवा जमा हुआ', 'फल एवं सूखे-मेवे', 'तेल एवं वसा', और 'मछली एवं अन्य समुद्री खाद्य पदार्थ' श्रेणियों ने क्रमशः 9.7 प्रतिशत, 8.6 प्रतिशत, 7.4 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की।

[14] सितंबर-दिसंबर 2025 के दौरान, सीपीआई खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह ने वर्ष-दर-वर्ष (-) 3.7 से (-) 1.4 प्रतिशत के दायरे में अपस्फीति दर्ज की (पिछली सीपीआई (2012=100) श्रृंखला के अनुसार)।

[15] ईंधन में 'विद्युत, गैस एवं अन्य ईंधन' समूह तथा 'व्यक्तिगत परिवहन उपकरणों के लिए ईंधन एवं स्नेहक' वर्ग शामिल हैं, जिन दोनों में फरवरी 2026 में 0.1 प्रतिशत की मध्यम मुद्रास्फीति दर्ज की गई।

[16] यह दिसंबर 2025 की सीपीआई- 2012 शृंखला में दर्ज 4.8 प्रतिशत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है, जिसका कारण आवास मुद्रास्फीति में कमी तथा बहुमूल्य धातु की श्रेणी में मुद्रास्फीति में गिरावट है, जो आंशिक रूप से बहुमूल्य धातुओं के विनिर्देशन में बुलियन कीमतों के स्थान पर आभूषण कीमतों को शामिल करने संबंधी परिवर्तन को दर्शाता है।

[17] पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण हुई ऊर्जा कीमतों में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप, घरेलू एलपीजी की कीमतों में ₹60 की वृद्धि हुई ; वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में दो चरणों में पहले ₹115 प्रति सिलेंडर और तत्पश्चात ₹195.5 प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई; थोक खरीदारों (औद्योगिक उपयोग) के लिए डीज़ल की कीमतों में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई; तथा मार्च 2026 से प्रीमियम पेट्रोल के कुछ प्रकारों की कीमतों में लगभग ₹2 प्रति लीटर की वृद्धि हुई।

[18] 16 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, चावल एवं गेहूं का भंडार क्रमशः 742 लाख टन (बफर मानक का 9.7 गुना) तथा 229 लाख टन (बफर मानक का 1.7 गुना) था।

की स्थितियों के उभरने की संभावना जोखिम उत्पन्न करती है[19]। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2026-27 के लिए 4.6 प्रतिशत सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान किया गया है, जिसमें पहली तिमाही में 4.0 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 4.4 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 5.2 प्रतिशत; तथा चौथी तिमाही में 4.7 प्रतिशत मुद्रास्फीति रहने का अनुमान है। मूल मुद्रास्फीति 4.4 प्रतिशत पर अनुमानित है। बहुमूल्य धातुओं को हटा दें तो, मूल मुद्रास्फीति अनुमान और भी कम हो जाता है, जो संकेत करता है कि अंतर्निहित मुद्रास्फीति दबाव नियंत्रित बने रहने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति बढ़ने के जोखिम बने हुए हैं।

बाह्य क्षेत्र

वैश्विक व्यापार में 2025 की तुलना में 2026 के दौरान संवृद्धि की गति में मंदी आने की संभावना है, जिसका कारण शुल्क-संबंधी अनिश्चितताओं का बने रहना, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष तथा उच्च ऊर्जा कीमतें हैं।[20] भारत के माल निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) आधार पर जनवरी–फरवरी 2026 के दौरान 0.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो प्रमुख बाजारों में निर्यात की कमी से प्रभावित थी।[21] माल आयात में 22.2 प्रतिशत की द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज की गई, जो मुख्यतः स्वर्ण आयात में वृद्धि[22] से प्रेरित थी, और परिणामस्वरूप व्यापार घाटा बढ़ा।[23] वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के दौरान सेवा निर्यात[24] तथा अंतर्वाह विप्रेषण प्राप्तियों[25] में अपेक्षित मज़बूती दिखी जिससे 2025-26 में भारत का चालू खाता घाटा मध्यम एवं संधारणीय स्तर के भीतर बने रहने की उम्मीद है। वैश्विक अनिश्चितताओं में वृद्धि तथा प्रमुख ऊर्जा वस्तुओं की ऊँची कीमतें 2026-27 में भारत के चालू खाता घाटे के बढ़ने का जोखिम उत्पन्न करती हैं। प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ हाल के द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार समझौतों से भारत के व्यापार एवं निवेश अवसरों को प्रोत्साहन मिलने, व्यापारिक भागीदारों का विस्तार एवं विविधीकरण होने तथा भारत के वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।[26]

बाह्य वित्तपोषण के क्षेत्र में, सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) में सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की गई, जबकि निवल एफ़डीआई में सुधार देखा गया।[27] ग्रीनफील्ड एफ़डीआई परियोजनाओं के लिए भारत एक आकर्षक गंतव्य बना हुआ है।[28] भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफ़पीआई) में, इक्विटी खंड से बहिर्वाह के कारण, 2025-26 में 16.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया, जिसके पश्चात 2026-27 (6 अप्रैल तक) में 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह हुआ।[29] बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा अनिवासी जमाओं के अंतर्गत प्रवाह 2024-25 की तुलना में संयत रहे।[30] 3 अप्रैल 2026 तक की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 697.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। मानक भंडार पर्याप्तता मानकों, जिनमें आयात अवधि (लगभग 11 माह) तथा बाह्य ऋण (91.1 प्रतिशत) शामिल

[19] संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल ओशेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, जून–अगस्त 2026 के दौरान एल नीनो के आने की संभावना (62 प्रतिशत) है तथा इसके कम से कम दिसंबर 2026 तक बने रहने की संभावना है।

[20] डबल्यूटीओ (मार्च 2026) के अनुसार, वैश्विक वस्तु एवं सेवा व्यापार की मात्रा वृद्धि, वर्ष 2025 के 4.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2026 में 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

[21] भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों (जो 2024-25 में कुल निर्यात का 52.6 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं) में से 7 गंतव्यों (38.5 प्रतिशत हिस्सेदारी) में निर्यात में गिरावट दर्ज की गई। इन 10 गंतव्यों में, जनवरी–फरवरी 2026 के दौरान, नीदरलैंड (14.2 प्रतिशत) तथा यूनाइटेड किंगडम (6.3 प्रतिशत) के अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका को किए गए निर्यात में 17.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

[22] आयात मात्रा में तथा स्वर्ण कीमतों में वृद्धि के कारण स्वर्ण आयात में वृद्धि हुई। जनवरी–फरवरी 2026 के दौरान स्वर्ण आयात मात्रा में 146.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में स्वर्ण कीमतों में 74.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[23] भारत के माल आयात में वृद्धि की दर माल निर्यात की तुलना में अधिक रहने के कारण, व्यापार घाटा जनवरी–फरवरी 2025 के 37.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर जनवरी–फरवरी 2026 में 61.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

[24] फरवरी 2026 के दौरान भारत के सेवा निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष 9.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सेवा आयात में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। निवल सेवा निर्यात में फरवरी 2026 में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2025-26 (अर्थात अप्रैल–फरवरी 2025-26) के दौरान अब तक सेवा निर्यात में 8.9 प्रतिशत तथा आयात में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप सेवा व्यापार अधिशेष में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[25] 2025-26 की तीसरी तिमाही के दौरान भारत की अंतर्वाह विप्रेषण प्राप्तियाँ वर्ष-दर-वर्ष 5.1 प्रतिशत बढ़कर 37.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गईं। 2025-26 (अर्थात अप्रैल–दिसंबर 2025-26) के दौरान अब तक निवल विप्रेषण प्राप्तियों में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[26] यूनाइटेड किंगडम और ओमान के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं; यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफ़टीए) के साथ व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया था; न्यूज़ीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते निष्पादित किए जा चुके हैं; तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा की गई है।

[27] अप्रैल–फरवरी 2025-26 के दौरान भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) प्रवाह, एक वर्ष पूर्व के 74.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 18.1 प्रतिशत बढ़कर 88.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसी अवधि में निवल एफ़डीआई प्रवाह 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो एक वर्ष पूर्व के 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

[28] एफ़डीआई बाजार के आंकड़ों के अनुसार, 2025-26 (अप्रैल–जनवरी) के दौरान भारत में 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की घोषणाएँ की गईं (अप्रैल–जनवरी 2024-25 में 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर) । सूचना प्रौद्योगिकी और बैंकिंग क्षेत्रों में अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जनरल कैटालिस्ट और एमयूएफ़जी बैंक द्वारा शीर्ष 5 ग्रीनफील्ड एफ़डीआई परियोजनाओं की घोषणाएँ निवेशकों की आशावादिता और सुदृढ़ एफ़डीआई पाइपलाइन को दर्शाती हैं।

[29] 2025-26 के दौरान, भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफ़पीआई) के अंतर्गत इक्विटी खंड में 18.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया, जबकि ऋण खंड में 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह हुआ। 1–6 अप्रैल 2026 के दौरान, भारत में एफ़पीआई के अंतर्गत क्रमशः इक्विटी और ऋण खंडों से 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया।

[30] बाह्य वाणिज्यिक उधार के अंतर्गत निवल अंतर्वाह, एक वर्ष पूर्व के 16.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर, अप्रैल–फरवरी 2025-26 के दौरान 11.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। अनिवासी जमा में अप्रैल–फरवरी 2025-26 के दौरान 11.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया, जो अप्रैल–फरवरी 2024-25 के 14.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है।

हैं, के संदर्भ में उक्त भंडार पर्याप्त है। समग्र रूप से, भारत के बाह्य क्षेत्र के संकेतक अनुकूल बने हुए हैं।[31] तथापि, वैश्विक भू-राजनीतिक, व्यापार एवं निवेश संबंधी अनिश्चितताओं के उच्च स्तर को देखते हुए, बदलते परिदृश्य पर सतत निगरानी अपेक्षित है।

सुदृढ़ समष्टि आर्थिक मूल-तत्वों के बावजूद, 2025-26 में भारतीय रुपया पिछले वर्षों के औसत की तुलना में अधिक अवमूल्यित हुआ। इस संदर्भ में, मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि हमारी विनिमय दर नीति यथावत् बनी हुई है। विशेष रूप से, विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप का उद्देश्य विनिमय दर के किसी विशिष्ट स्तर या दायरे को लक्षित किए बिना अत्यधिक एवं विघटनकारी अस्थिरता को कम करना है। यह हमारी दीर्घकालिक नीति के अनुरूप है, जिसके अनुसार विनिमय दरें बाज़ार द्वारा निर्धारित होती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक इस नीति के प्रति प्रतिबद्ध है और अत्यधिक अथवा विघटनकारी अस्थिरता को विवेकपूर्ण ढंग से नियंत्रित करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्व-पूर्ति अपेक्षाएँ, मूलभूत कारकों से परे जाकर, मुद्रा संबंधी गतिविधियों को और अधिक न बढ़ाएँ।

चलनिधि एवं वित्तीय बाज़ार स्थिति

प्रणालीगत चलनिधि, जिसे चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के अंतर्गत निवल स्थिति के अनुसार मापा जाता है, पिछली एमपीसी बैठक के बाद से औसतन प्रतिदिन ₹2.3 लाख करोड़ के अधिशेष पर रही।[32] इसके पश्चात, भारित औसत मांग दर (डबल्यूएसीआर), सिवाय मार्च महीने के अंत में, कॉरिडोर के निचले अर्धभाग में कारोबार करती रही[33]। अल्पावधि मुद्रा बाज़ार दरें, विशेषकर वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों की दरें, उच्च स्तर पर बनी रहीं[34]। फरवरी में आए गिरावट के रुझान के साथ जी-सेक प्रतिफल अधिकांशतः स्थिर बने रहे किन्तु पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक प्रतिफल में वृद्धि तथा ऊर्जा मूल्यों में वृद्धि के कारण पुनः सुदृढ़ हो गए।[35] ऋण बाज़ार में संचारण संतोषजनक बना रहा।[36]

बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने हेतु, रिज़र्व बैंक ने सक्रिय रूप से स्थायी एवं अस्थायी चलनिधि प्रयास किए।[37] आगे, हम चलनिधि प्रबंधन में सक्रिय एवं पूर्व-निवारक बने रहेंगे तथा अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करेंगे।

वित्तीय स्थिरता

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की पूंजी पर्याप्तता, चलनिधि, आस्ति गुणवत्ता एवं लाभप्रदता संबंधी प्रणाली-स्तरीय वित्तीय मानक सुदृढ़ बने हुए हैं।[38] इसी प्रकार, एनबीएफसी के प्रणाली-स्तरीय मानक भी मज़बूत हैं, जिनमें पर्याप्त पूंजी स्थिति तथा बेहतर सकल एनपीए अनुपात शामिल हैं।[39]

---

[31] भारत का जीडीपी की तुलना में बाह्य ऋण अनुपात, मार्च 2025 के अंत में 19.8 प्रतिशत से बढ़कर, दिसंबर 2025 के अंत में 20.4 प्रतिशत हो गया, जबकि निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) दिसंबर 2025 के अंत में जीडीपी के (-) 7.1 प्रतिशत पर आ गई, जो मार्च 2025 के अंत में जीडीपी के (-) 9.0 प्रतिशत पर थी।

[32] दिसंबर और जनवरी के दौरान चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के अंतर्गत औसत दैनिक निवल अवशोषण क्रमशः ₹0.82 लाख करोड़ और ₹0.79 लाख करोड़ रहा। फरवरी 2026 में, एलएएफ़ के अंतर्गत औसत दैनिक निवल अवशोषण बढ़कर ₹2.6 लाख करोड़ हो गया। मार्च 2026 में, औसत दैनिक निवल अवशोषण ₹1.7 लाख करोड़ रहा तथा अप्रैल (6 अप्रैल 2026 तक) में बढ़कर ₹3.5 लाख करोड़ हो गया।

[33] डबल्यूएसीआर नीति रेपो दर से औसतन 6 आधार अंक नीचे रही।

[34] फरवरी की मौद्रिक नीति घोषणा के बाद से 3-माह की खजाना बिल, 3-माह के जमा प्रमाणपत्र तथा 3-माह के वाणिज्यिक पत्र की दरें क्रमशः औसतन 5.32 प्रतिशत, 7.18 प्रतिशत और 7.29 प्रतिशत रहीं।

[35] 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल, 27 फरवरी 2025 के 6.66 प्रतिशत की तुलना में, 6 अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार 7.05 प्रतिशत तक बढ़ा।

[36] वर्तमान सुगमता चक्र (फरवरी 2025–फरवरी 2026) के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की नई तथा बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डबल्यूएएलआर) में क्रमशः 89 आधार अंक (जिसमें 92 आधार अंकों की कमी ब्याज दर प्रभाव के कारण) और 87 आधार अंकों की गिरावट आई। जमा पक्ष में, नई तथा बकाया जमाओं पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डबल्यूएडीटीडीआर) में इसी अवधि के दौरान क्रमशः 97 आधार अंक और 47 आधार अंक की कमी दर्ज की गई।

[37] रिज़र्व बैंक ने ₹1,50,000 करोड़ की ओएमओ खरीद नीलामियाँ आयोजित कीं तथा फरवरी और मार्च 2026 के दौरान 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की दीर्घावधि विदेशी मुद्रा क्रय/विक्रय स्वैप नीलामी आयोजित की।

[38] **एससीबी मानदंड:** दिसंबर 2025 में प्रणाली-स्तरीय जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 16.91 प्रतिशत था, जो विनियामकीय न्यूनतम स्तर से काफी अधिक है। गैर-निष्पादित आस्तियों का अनुपात कम हुआ (जीएनपीए अनुपात दिसंबर 2024 के 2.42 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2025 में 1.89 प्रतिशत; एनएनपीए अनुपात दिसंबर 2024 के 0.55 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2025 में 0.44 प्रतिशत)। दिसंबर 2025 के अंत में 125.85 प्रतिशत के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के साथ चलनिधि बफर सुदृढ़ बने रहे। दिसंबर 2025 में, आस्तियों पर वार्षिकीकृत प्रतिलाभ (आरओए) तथा इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) क्रमशः 1.32 प्रतिशत और 12.95 प्रतिशत रहे। निवल ब्याज मार्जिन दिसंबर 2025 में 3.28 प्रतिशत रहा (दिसंबर 2024 में 3.49 प्रतिशत)।

[39] **एनबीएफसी मानदंड:** दिसंबर 2025 में एनबीएफसी का कुल सीआरएआर 25.59 प्रतिशत तथा टियर I सीआरएआर 23.71 प्रतिशत था, जो विनियामकीय न्यूनतम आवश्यकताओं से काफी अधिक है। जीएनपीए अनुपात दिसंबर 2024 के 2.52 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2025 में 2.14 प्रतिशत हो गया, जबकि एनएनपीए अनुपात भी दिसंबर 2024 के 1.10 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2025 में 0.93 प्रतिशत हो गया। इस क्षेत्र का आरओए दिसंबर 2024 के 2.89 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2025 में 2.71 प्रतिशत हो गया। एनआईएम दिसंबर 2024 के 4.54 प्रतिशत से थोड़ा सा घटकर दिसंबर 2025 में 4.43 प्रतिशत हो गया।

उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सभी स्रोतों से ऋण 14.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की दर से बढ़ा, जबकि एक वर्ष पूर्व यह 11.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) था[40]। बैंक ऋण वृद्धि ने अपनी उर्ध्वगामी प्रवृत्ति बनाए रखी[41] तथा यह वैविध्यपूर्ण बनी रही।

अतिरिक्त उपाय

अब मैं कारोबार-सुगमता, पूंजी पर्याप्तता तथा बाज़ार विकास संबंधी कुछ उपायों की घोषणा करूँगा।

कारोबार-सुगमता को प्रोत्साहन देना

कारोबार-सुगमता को प्रोत्साहन देने के लिए तीन उपाय प्रस्तावित हैं।

सर्वप्रथम, बैंक के निदेशक मंडल के समय-सदुपयोग को सुगम बनाने हेतु, हमारे सभी विद्यमान अनुदेशों की व्यापक समीक्षा के उपरांत, हम उन विषयों को संशोधित एवं युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करते हैं जिन पर ध्यान अपेक्षित है।

द्वितीय, आपको स्मरण होगा कि हमने हाल ही में एक विस्तृत अभ्यास किया था जिसके अंतर्गत 9000 से अधिक विनियामकीय अनुदेशों को समेकित कर उन्हें 238 मास्टर निदेशों में रूपांतरित किया गया था। इसी प्रकार का एक समेकन अभ्यास अब हमारे सभी पर्यवेक्षी अनुदेशों के लिए भी पूर्ण कर लिया गया है।

तृतीय, एमएसएमई में कारोबार-सुगमता को बढ़ावा देने हेतु, हम टीआरईडीएस(TReDS) प्लेटफॉर्म पर उनके ऑनबोर्डिंग के समय समुचित सावधानी की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव करते हैं।

पूंजी पर्याप्तता का समर्थन

बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के संबंध में दो उपाय प्रस्तावित हैं।

सर्वप्रथम, सीआरएआर की गणना में त्रैमासिक लाभ को शामिल करने हेतु एनपीए प्रावधान संबंधी शर्त को हटाने का प्रस्ताव है।

द्वितीय, गत वर्षों के दौरान विवेकपूर्ण ढांचे में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, निवेशों के मूल्य में होने वाली गिरावट से बचाव के लिए एक अतिरिक्त बफर के रूप में निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व (आईएफ़आर) के रखरखाव की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

मुद्रा बाज़ार का विकास

मीयादी मुद्रा बाज़ार के और विकास के लिए, हमने इस बाज़ार खंड में गैर-बैंक संस्थाओं की कुछ अतिरिक्त श्रेणियों को अनुमति देने का निर्णय लिया है। वर्तमान में, केवल बैंक और एकल प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी) ही इस बाज़ार में भाग लेने के पात्र हैं। हम मीयादी मुद्रा बाज़ार में एसपीडी की उधार-सीमा को भी बढ़ा रहे हैं।

समापन टिप्पणियाँ

अंत में, पश्चिम एशिया संघर्ष बढ़ने से वैश्विक आर्थिक परिस्थितियाँ एवं रुझान प्रतिकूल हुए हैं। इनका संवृद्धि-मुद्रास्फीति संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जैसा कि पूर्व में दोहराया गया है, हम बदलती हुई स्थिति पर पूरी तरह से नज़र रखेंगे और ऐसी नीतियां लागू करेंगे जिनमें अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता दी जाए।

धन्यवाद। नमस्कार और जय हिन्द।

---

[40] बैंक तथा गैर-बैंक स्रोतों से वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधनों का कुल प्रवाह ₹40.4 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹32.2 लाख करोड़ था। गैर-खाद्य बैंक ऋण (₹6.9 लाख करोड़) तथा गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा कॉर्पोरेट बांड निर्गम (₹1.7 लाख करोड़) से प्रवाह में वृद्धि हुई जो कि पूर्वोक्त वृद्धि के प्रमुख कारक रहे।

[41] बैंक ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 13.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (15 मार्च 2026 को समाप्त पखवाड़े के अनुसार), जबकि एक वर्ष पूर्व यह 11.0 प्रतिशत थी (आरबीआई की पाक्षिक धारा 42 विवरणी के आधार पर)। मई 2025 से ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ी है।

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2026-27
मौद्रिक नीति समिति का संकल्प
*6 से 8 अप्रैल 2026**

मौद्रिक नीति निर्णय

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 60वीं बैठक 6 से 8 अप्रैल 2026 तक श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। एमपीसी के सदस्य डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगत भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. पूनम गुप्ता और श्री इन्द्रनील भट्टाचार्य बैठक में शामिल हुए।

उभरते समष्टि-आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों तथा संभावना का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद, एमपीसी ने सर्वसम्मति से चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.00 प्रतिशत, तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.50 प्रतिशत पर बनी रहेगी। एमपीसी ने तटस्थ रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति की संभावना

वैश्विक संभावना

पश्चिम एशिया में संघर्ष छिड़ने से वैश्विक आपूर्ति शृंखला में भारी रुकावट आई है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने एक अभूतपूर्व चुनौती खड़ी हो गई है – कीमतें बढ़ गई हैं और वैश्विक संवृद्धि कम हो गई है। ऐसे माहौल में, मौद्रिक नीति के सामने एक मुश्किल दुविधा है – नीतिगत सख्ती करके मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को नियंत्रित रखना, और साथ ही संवृद्धि पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को कम से कम रखना। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में लंबे समय तक राजकोषीय स्थिरता को लेकर चिंताओं के कारण सॉवरेन बॉन्ड प्रतिफल पहले से ही उच्च थे; अब मुद्रास्फीति के डर से वे और भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा, इक्विटी मूल्यांकन (वैल्यूएशन) में भी सुधार देखने को मिला है। वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल के चलते, अमेरिकी डॉलर में तेज़ी आई है; 'सेफ हेवन' (सुरक्षित निवेश) की मांग से इसे बल मिला है, जिससे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर दबाव बढ़ा है। संघर्ष का और अधिक तेज़ होना, इसका लंबे समय तक चलना और इसका भौगोलिक दायरा बढ़ना – ये सभी वैश्विक संभावना के लिए प्रमुख नकारात्मक जोखिम बने हुए हैं।

घरेलू दृष्टिकोण

घरेलू स्थिति के संबंध में, भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 में आघात-सह बना रहा। नए जीडीपी शृंखला (आधार वर्ष 2022-23) के दूसरे प्रारंभिक अनुमानों (एसएई) के अनुसार, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वर्ष-दर-वर्ष 7.6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। निजी उपभोग और स्थिर निवेश ने समग्र संवृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि निवल बाह्य मांग नरम बनी रही। आपूर्ति के संबंध में, अनुमानित वास्तविक जीवीए संवृद्धि 7.7 प्रतिशत रही, जो उत्साहित सेवा क्षेत्र और मजबूत विनिर्माण गतिविधि से प्रेरित थी।

आगे चलकर, ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों के साथ-साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में विघटन के कारण आपूर्ति आघात, 2026-27 में घरेलू उत्पादन पर एक बाधा के रूप में कार्य करेगा। वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ी हुई अस्थिरता और इसके घरेलू वित्तीय परिस्थितियों पर प्रभाव- विस्तार, संवृद्धि की संभावनाओं पर दबाव डालेगा। बाह्य स्थिति के संबंध में, यदि संघर्ष लंबे समय तक चलता है, तो प्रमुख जहाज यात्रा मार्गों में विघटन और इसके साथ आने वाली माल ढुलाई और बीमा लागत में वृद्धि के कारण वस्तुओं के निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, सेवा क्षेत्र में बने रहने वाली गति, जीएसटी सुधार का लगातार प्रभाव, विनिर्माण में बढ़ता क्षमता उपयोग, तथा वित्तीय संस्थानों और कॉर्पोरेट के स्वस्थ तुलन- पत्र को घरेलू मांग को समर्थन देते रहना चाहिए। इस परिदृश्य में, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित कई कार्यनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने पर सरकार का ध्यान, भारत के आगामी संवृद्धि पथ के लिए शुभ संकेत है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए और यह मानते हुए कि संघर्ष का नकारात्मक प्रभाव आगे के समय तक सीमित रहेगा, 2026-

* 8 अप्रैल, 2026 को जारी।

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2026-27

27 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 6.9 प्रतिशत अनुमानित है, जिसमें पहली तिमाही में 6.8 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 7.0 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 7.2 प्रतिशत (चार्ट 1) होगी। इसके अलावा, संघर्ष के आगे बढ़ने, इसके व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में जारी रहने और ऊर्जा के बुनियादी ढांचे की क्षति के संबंध में अनिश्चितता, साथ ही मौसम से संबंधित घटनाओं के कारण घरेलू संवृद्धि की संभावना पर नकारात्मक जोखिम बना हुआ है।

नए सीपीआई शृंखला (2024=100) के अनुसार, फरवरी 2026 में हेडलाइन मुद्रास्फीति जनवरी के 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से अनुकूल न होने वाले आधार प्रभावों के कारण हुई, भले ही गति निर्बल बनी रही। जबकि फरवरी में खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, मूल (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) मुद्रास्फीति यथावत् बनी रही। मूल्यवान धातुओं को छोड़कर, जनवरी और फरवरी में मूल मुद्रास्फीति 2.1 प्रतिशत पर मध्यम बनी रही, जो अंतर्निहित मुद्रास्फीति दबावों की कमजोरी को सुझाती है।

चल रहे संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की कीमतों में बड़ी अस्थिरता उत्पन्न की है, जिससे निकट अवधि की मुद्रास्फीति संभावना में काफी अनिश्चितता आई है। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि का प्रभाव चुनिंदा ईंधनों, जैसे प्रीमियम पेट्रोल, एलपीजी और औद्योगिक उपयोग के लिए डीजल, संबंधी कीमतों में वृद्धि के रूप में दिखाई दिया है। दूसरी ओर, मजबूत रबी फसल के कारण निकट अवधि में खाद्य आपूर्ति की संभावनाएं बढ़ी हैं, जिससे कुछ राहत मिली है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2026-27 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही में 4.0 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 4.4 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 5.2 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 4.7 प्रतिशत होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष और संभावित एल नीनो की स्थितियों (जो दक्षिण-पश्चिम मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं) के कारण लगातार उच्च ऊर्जा कीमतें, मुद्रास्फीति पर ऊर्ध्वगामी जोखिम उत्पन्न करती हैं (चार्ट 2)। 2026-27 के लिए मूल मुद्रास्फीति 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, और मूल्यवान धातुओं को छोड़कर यह और भी कम है, जो यह संकेत देता है कि अंतर्निहित मुद्रास्फीति दबाव नियंत्रित रहने की आशा है।

मौद्रिक नीति संबंधी निर्णयों का औचित्य

पिछली नीतिगत बैठक के बाद से, भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं काफी बढ़ गई हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और लक्ष्य से नीचे है, लेकिन मुद्रास्फीति संभावना के लिए

चार्ट 1: वास्तविक जीडीपी वृद्धि का त्रैमासिक अनुमान (व-द-व)

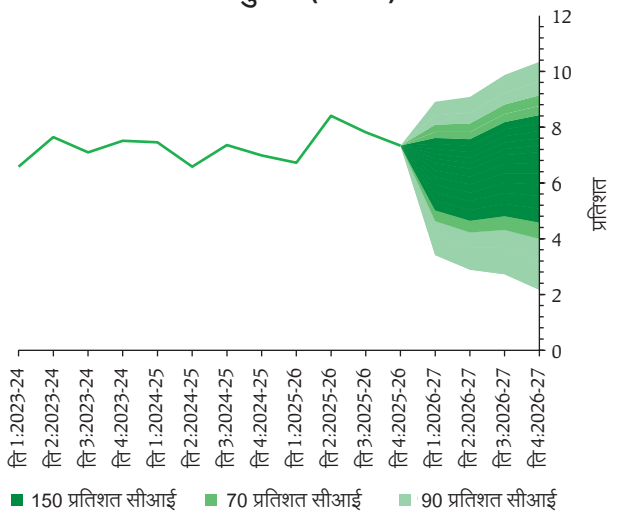

चार्ट 2: सीपीआई मुद्रास्फीति का त्रैमासिक अनुमान (वर्ष-दर-वर्ष)

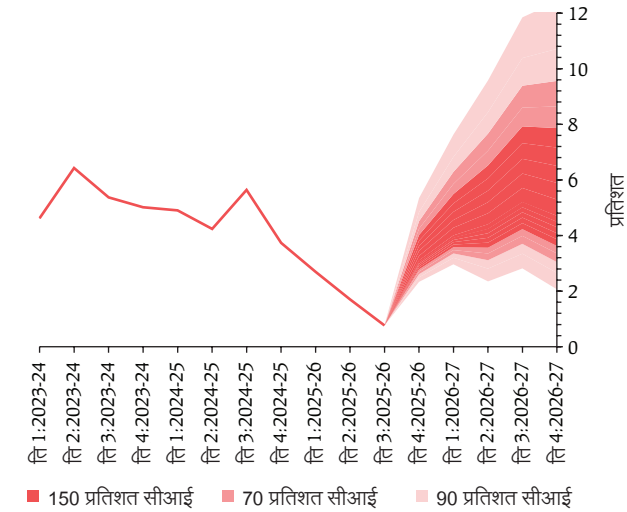

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2026-27

ऊर्ध्वगामी जोखिम बढ़ गया है; इसका कारण ऊर्जा की कीमतों के दबाव में बढ़ोतरी और मौसम में संभावित गड़बड़ियां हैं, जो खाद्य मूल्यों को प्रभावित कर रहा है। मूल मुद्रास्फीति का दबाव कम बना हुआ है, हालांकि आपूर्ति शृंखला में रुकावटें और दूसरे दौर के प्रभाव (सेकंड-राउंड इफ़ेक्ट) का जोखिम, भविष्य में मुद्रास्फीति पथ को अनिश्चित बना देते हैं।

फरवरी 2026 तक के उच्चावृति संकेतक से पता चलता है कि आर्थिक गतिविधियों में मज़बूत गति बनी रहेगी। संवृद्धि के आवेग को मज़बूत निजी उपभोग और निवेश की मांग से लगातार समर्थन मिल रहा है। हालाँकि, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का संवृद्धि पर बुरा असर पड़ेगा। ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी, अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई और बीमा लागत में वृद्धि से जुड़ी अधिक इनपुट लागत, और साथ ही आपूर्ति शृंखला में रुकावटों के कारण डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के लिए प्रमुख इनपुट की उपलब्धता सीमित हो सकती है, जिससे संवृद्धि बाधित होगी। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं, जिनसे इस संघर्ष के बुरे असर को कम करने में मदद मिलनी चाहिए।

एमपीसी ने यह पाया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की तीव्रता और अवधि, तथा इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा और अन्य बुनियादी ढांचों को होने वाला नुकसान, मुद्रास्फीति और संवृद्धि की संभावनाओं के लिए जोखिम उत्पन्न करता है। हालाँकि, भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल आधार अब अधिक मज़बूत स्थिति में हैं, जिससे इसमें अतीत की तुलना में अब आघात- सहनीयता बढ़ ई है। अर्थव्यवस्था इस समय आपूर्ति आघातों का सामना कर रही है। बदलते हालात और उभरती संवृद्धि -मुद्रास्फीति संभावना पर नज़र रखते हुए इंतज़ार करना ही समझदारी है। तदनुसार, एमपीसी ने नीतिगत दरों को यथावत् रखने के पक्ष में वोट किया; साथ ही वह पूरी तरह सतर्क बनी हुई है, प्राप्त सूचनाओं पर बारीकी से नज़र रख रही है और जोखिमों के संतुलन का आकलन कर रही है। एमपीसी ने तटस्थ रुख को जारी रखने का भी निर्णय लिया, ताकि प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विवेकपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया देने का सहूलियत बना रहे।

एमपीसी की बैठक के कार्यवृत्त 22 अप्रैल 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे।

एमपीसी की अगली बैठक 3 से 5 जून 2026 के दौरान निर्धारित है।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) विनियमन; (ii) पर्यवेक्षण; (iii) भुगतान प्रणालियों; और (iv) वित्तीय बाज़ारों से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है:

I. विनियमन

1. जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की गणना में त्रैमासिक लाभों के समावेशन हेतु दिशानिर्देशों की समीक्षा – वाणिज्यिक बैंकों

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को सीआरएआर की गणना में त्रैमासिक निवल लाभों को शामिल करने की अनुमति है, बशर्ते कि पिछले वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों में से किसी भी तिमाही के अंत में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए किए गए वृद्धिशील प्रावधान, उन चारों तिमाहियों के औसत से 25 प्रतिशत से अधिक विचलित न हुए हों। समीक्षा के बाद, इस शर्त को समाप्त करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में संशोधन निदेश का मसौदा शीघ्र ही जन- सामान्य की टिप्पणियों के लिए जारी किए जाएंगे।

2. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफ़आर) संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा

बैंक वर्तमान में अपने निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के सापेक्ष एक अतिरिक्त बफर के रूप में निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफ़आर) रखते हैं, जो बाज़ार भाव पर दर्शाने (एमटीएम) की आवश्यकताओं के अधीन होता है। वर्तमान में, वाणिज्यिक बैंक (जिनमें स्थानीय क्षेत्र बैंक शामिल हैं, लेकिन लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं हैं) पहले से ही बाज़ार जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार का रख- रखाव करते हैं और निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन संबंधी संशोधित नियमों का भी पालन करते हैं। इन लागू विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ऐसे वाणिज्यिक बैंकों के लिए आईएफ़आर की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव है। अन्य बैंक श्रेणियों के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों को भी संशोधित किया जा रहा है, ताकि आईएफ़आर पर विनियामक सीमाओं का पालन करने में ऐसे बैंकों को आने वाली परिचालनगत चुनौतियों का समाधान किया जा सके और सभी बैंक श्रेणियों में अनुदेशों में एकरूपता लाई जा सके, जिससे विनियामक स्पष्टता और निरंतरता बढ़ेगी। इस संबंध में निदेश का मसौदा शीघ्र ही जन-सामान्य के परामर्श के लिए जारी किए जाएंगे।

3. बैंकों के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत मामलों की समीक्षा

बैंकों के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले मामले और उन मामलों की आवधिकता, स्वयं बोर्ड ही निर्धारित करते हैं, जिसके लिए वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सात मुख्य विषयों से मार्गदर्शन लेते हैं। साथ ही, रिज़र्व बैंक ने कतिपय ऐसी नीतियां और मामले भी अनिवार्य किए हैं जिन्हें बोर्ड के सामने अनुमोदन, समीक्षा या जानकारी के लिए रखा जाना आवश्यक है। बोर्ड अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें, और कार्यनीति तथा जोखिम प्रबंधन पर अधिक केंद्रित व गुणवत्तापूर्ण चर्चा कर सकें, इस उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने ऐसे सभी अनुदेशों की व्यापक समीक्षा की और उन्हें तर्कसंगत बनाने का कार्य किया है। इस संबंध में निदेश का मसौदा शीघ्र ही जन- सामान्य के परामर्श के लिए जारी किए जाएंगे।

II. पर्यवेक्षण

4. पर्यवेक्षी अनुदेशों का समेकन

रिज़र्व बैंक ने अनुदेशों की प्रासंगिकता को निरंतर बनाए रखने हेतु समय-समय पर उनका मूल्यांकन करके अनुपालन लागत को कम करते हुए, अपने विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचे को बेहतर बनाने और मजबूत करने का लगातार प्रयास किया है। इस प्रयोजन हेतु ही, रिज़र्व बैंक ने 2025 में 'यथास्थिति' के आधार पर विनियामक अनुदेशों के व्यापक समेकन का कार्य किया था। इस कार्य में 9000 से अधिक मौजूदा विनियामक परिपत्रों/ दिशानिर्देशों को 238 कार्य-वार मास्टर निदेशों (एमडी) में समेकित करना शामिल था, जो विनियमित संस्थाओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए विशिष्ट थे। अब पर्यवेक्षी अनुदेशों के लिए भी इसी तरह का कार्य किया गया है। तदनुसार, नौ कार्यात्मक क्षेत्रों तक के मौजूदा पर्यवेक्षी अनुदेशों को समेकित करने वाले 64

मास्टर निदेशों के मसौदे आज आरबीआई की वेबसाइट पर जन-सामान्य की टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं।

III. भुगतान प्रणाली

5. व्यापारिक प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (ट्रेड्स) में एमएसएमई को शामिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना

एमएसएमई के लिए समय पर कार्यशील पूंजी तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, 2014 में व्यापारिक प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (ट्रेड्स) के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे और बाद में 2018[1] में उन्हें अद्यतन किया गया। 2023 में बीमा कंपनियों को चौथे प्रतिभागी के रूप में शामिल करते हुए ट्रेड्स के दायरे का और विस्तार किया गया। एमएसएमई के लिए कारोबार करने में सुगमता को बढ़ावा देने और उनकी ट्रेड्स पर अधिकाधिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई को सम्मिलित करते समय उनकी उचित जांच-पड़ताल की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव है। अन्य मौजूदा अनुदेशों की भी एक व्यापक समीक्षा की गई है, और शीघ्र ही निदेश का मसौदा जन- सामान्य के परामर्श के लिए जारी किए जाएंगे।

IV. वित्तीय बाज़ार

6. मीयादी मुद्रा बाज़ार का विकास

एक सक्रिय मीयादी मुद्रा बाज़ार, बाजार प्रतिभागियों के लिए वित्तपोषण का एक वैकल्पिक माध्यम प्रदान करने के अलावा, एक दिवसीय मुद्रा बाज़ार और दीर्घकालिक ब्याज दरों के बीच कड़ी बनाकर मौद्रिक नीति के प्रसार को बढ़ावा देने में भी सहायक है। वर्तमान में, कतिपय विवेकपूर्ण सीमाओं के साथ केवल बैंकों और एकल प्राथमिक व्यापारी ही मीयादी मुद्रा बाज़ार में भाग लेने के पात्र हैं। सहभागिता की गहनता और मीयादी मुद्रा बाज़ार खंड में चलनिधि को और बढ़ाने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि (क) मीयादी मुद्रा बाज़ार खंड में प्रतिभागियों के आधार को आवास वित्त कंपनियों, कंपनियों आदि सहित गैर-बैंक प्रतिभागियों, जैसे एआईएफआई, एनबीएफसी आदि को शामिल करके विस्तारित किया जाए; और (ख) एकल प्राथमिक व्यापारियों के लिए मीयादी मुद्रा बाज़ार में उधार लेने की सीमा बढ़ाई जाए। संशोधित निदेश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

[1] https://www.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=3504

कार्यकारी सारांश

वैश्विक विकास सुदृढ़ बना रहा, लेकिन अपने ऐतिहासिक औसत से नीचे रहा, साथ ही एआई-आधारित निवेश और अनुकूल वित्तीय स्थितियों ने टैरिफ और भू-राजनीतिक बाधाओं के प्रभाव को कुछ हद तक कम किया। ऊर्जा की कीमतों और अस्थिर वित्तीय बाज़ारों के कारण पैदा हुए मुद्रास्फीति के नए जोखिम, वैश्विक समष्टि-आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य में और अधिक अनिश्चितता लाते हैं।

बढ़ती अनिश्चितता और अस्थिर पूंजी प्रवाह के बीच, 2025-26 की दूसरी छमाही में घरेलू वित्तीय बाजारों में बीच-बीच में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। दूसरी छमाही के दौरान प्रणाली की चलनिधि अधिशेष में बनी रही। मुद्रा बाज़ार की दरें काफी हद तक प्रणाली की चलनिधि और मौद्रिक नीति के उपायों के अनुरूप ही रहीं। घरेलू और वैश्विक संकेतों के मिले-जुले प्रभाव से दीर्घकालिक सरकारी बॉण्ड प्रतिफल में बढ़ोतरी हुई और इक्विटी बाजारों में अस्थिरता आ गई। दूसरी छमाही के अंत में, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बारे में चिंताओं के बीच, भारतीय रुपये पर अवमूल्यन का दबाव और बढ़ गया, जिससे यह अपने पिछले रिकॉर्ड निचले स्तरों को भी पार कर गया। जहां एक ओर बैंक ऋण में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा और वास्तविक आर्थिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता रहा, वहीं दूसरी ओर गैर-बैंकिंग स्रोतों से मिलने वाले वित्तपोषण में भी वृद्धि हुई। दूसरी छमाही में नीतिगत दरों का ऋण और जमा, दोनों ही दरों में ट्रान्समिशन जारी रहा और मौजूदा नरमी के इस दौर में कुछ रुकावटों के बावजूद यह मजबूत बनी रही। हाल के महीनों में, ऋण की मांग लगातार बनी रहने और ऋण तथा जमा वृद्धि के बीच लगातार बढ़ते अंतर के कारण बैंकों को अपनी मीयादी जमा दरों में वृद्धि करनी पड़ी, साथ ही, वित्तपोषण में आ रही कमी को पूरा करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के माध्यम से भी संसाधन जुटाए गए।

2025-26 की दूसरी छमाही में घरेलू आर्थिक गतिविधियां भी सुदृढ़ बनी रहीं, जो मुख्य रूप से निजी उपभोग की वजह से है, जिसे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की मांग, जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने और मौद्रिक सहजता से समर्थन मिला। संरचनात्मक सुधारों, अनुकूल वित्तीय स्थितियों और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के संबंध में सरकार का विशेष जोर ने निवेश गतिविधियों को बढ़ावा दिया। आपूर्ति पक्ष की बात करें तो, सेवा क्षेत्र में तेजी बनी रही और विनिर्माण क्षेत्र भी मजबूत हुआ, हालांकि, मौसम संबंधी बाधाओं के कारण कृषि संबंधी गतिविधियां धीमी पड़ गईं। आर्थिक गतिविधियों में अंतर्निहित गति, जिसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार समझौतों में हुई प्रगति से और भी बल मिला है, भारत के समग्र विकास परिदृश्य के लिए एक शुभ संकेत है। भू-राजनीतिक तनाव, वस्तुओं की अस्थिर कीमतें और आपूर्ति-शृंखला संबंधी बाधाओं से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियां परिदृश्य के लिए गिरावट के जोखिम पैदा करते हैं। विशेष रूप से, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के और अधिक तीव्र होने की स्थिति में, विभिन्न डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के लिए इनपुट की आपूर्ति बाधित हो सकती है, जो विकास में रुकावट पैदा कर सकती है।

भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति अक्टूबर 2025 में देखे गए अपने ऐतिहासिक निचले स्तरों से ऊपर उठी, लेकिन उसके बाद भी यह निर्धारित लक्ष्य से नीचे ही बनी रही। मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी की मुख्य वजह खाद्य समूह था, जहां बेस इफ़ेक्ट के कम होने से अपस्फीति की स्थिति पलट गई। ईंधन समूह में मुद्रास्फीति नरम रही, और कीमती धातुओं को छोड़कर, कोर मुद्रास्फीति भी नियंत्रण में रही। नई सीरीज़ शुरू होने से कार्यप्रणाली में जो बड़े बदलाव आए हैं, उनका मुद्रास्फीति पर काफी असर पड़ा है, जैसे, खाद्य समूह में मुद्रास्फीति का बढ़ना और कोर मुद्रास्फीति का कम होना। फरवरी 2026 तक, लागत से जुड़ी वास्तविक स्थितियों : जैसे इनपुट लागत, मजदूरी लागत, और मार्जिन में कोई बड़ा दबाव देखने को नहीं मिला। हालांकि, आयातित मुद्रास्फीति का योगदान लगातार बढ़ रहा है और मार्च में आयातित इनपुट लागत का दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में संघर्ष के कारण आई अचानक तेजी का असर भी कई अलग-अलग माध्यमों से पड़ने की संभावना है।

आगे चलकर, भू-राजनीतिक तनावों के बढ़ने और वैश्विक व्यापार में जारी रुकावटों के बावजूद, भारत का समष्टि-आर्थिक परिदृश्य सुदृढ़ बना हुआ है। लगातार विकास, कम मुद्रास्फीति और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण जैसे मजबूत आधार भारत को वैश्विक अनिश्चितताओं के बढ़ते प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने की क्षमता प्रदान करते हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बाद से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी, जो आपूर्ति में भारी रुकावटों के कारण और भी बढ़ गई है, ने मुद्रास्फीति बढ़ने और विकास घटने के जोखिम पैदा किए हैं, जिसे असमेट्रिक फैन चार्ट्स, परिदृश्यों और संवेदनशीलता विश्लेषण के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। इन उथल-पुथल भरे समयों से गुजरते हुए, भारत की मौद्रिक नीति विकास को समर्थन देते हुए मूल्य स्थिरता को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करती रहेगी।

I. बाह्य परिवेश

लंबे समय से चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं के बीच वैश्विक विकास अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे बना हुआ है। एआई से संबंधित निवेश और जारी सहज वित्तीय परिस्थितियाँ गतिविधियों के लिए सहायक हैं, भले ही आस्तियों की कीमत में बढ़े हुए उतार-चढ़ाव के दौर बाज़ार की बदलती भावना को दर्शाते हैं। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति का रुख सतर्क बने रहने के साथ केंद्रीय बैंकों द्वारा इन घटनाक्रमों पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण हाल ही में ऊर्जा की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति में वृद्धि का जोखिम बढ़ गया है और वैश्विक विकास का परिदृश्य अस्पष्ट हो गया है।

पश्चिम एशिया में संघर्ष की शुरुआत से पहले बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा वैश्विक विकास में संशोधन करते हुए उसे बढ़ाया गया था। हालांकि, अपने मार्च इकोनॉमिक आउटलुक में, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने अपने 2026 के विकास अनुमान को कायम रखा किन्तु अपने 2027 के पूर्वानुमान को मामूली रूप से कम कर दिया, जो संघर्ष से उत्पन्न मध्यम अवधि के जोखिमों में वृद्धि को दर्शाता है। वैश्विक विकास अभी भी अपने ऐतिहासिक औसत से नीचे रहने का अनुमान है। यह परिदृश्य पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति पर अत्यधिक निर्भर है: एक शीघ्र समाधान संभवतः होने वाले नुकसान को सीमित कर देगा, जबकि इसमें और तेजी एवं लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अधिक गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही, चालू व्यापार और नीतिगत गतिरोध परिदृश्य के बारे में अनिश्चितता को मजबूत कर रहे हैं। मुद्रास्फीति के परिणाम मिले-जुले बने हुए हैं, कुछ प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (एई) नए सिरे से बढ़ते मूल्य दबाव के बीच लक्ष्य से ऊपर बनी हुई हैं, जिससे नीतिगत सख्ती की ओर अपेक्षा से अधिक तेजी से बदलाव की प्रत्याशाएं बढ़ रही हैं। वैश्विक इक्विटी बाजार काफी हद तक सुदृढ़ बने हुए हैं, जो मुख्य रूप से एआई से संबंधित प्रौद्योगिकी शेयरों द्वारा समर्थित हैं। हालांकि, विस्तारित मूल्यांकन, अन्य सॉफ्टवेयर उद्योगों पर संभावित प्रभाव-विस्तार और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बारे में चिंताओं ने अशांति की घटनाएं उत्पन्न की हैं। फरवरी तक अमेरिकी डॉलर का मूल्य सामान्यतः कम होता रहा, जिससे उभरती बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए वित्तपोषण की स्थिति आसान हो गई; लेकिन पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद सुरक्षित निवेश की मांग पर इसमें मजबूती आई। सुरक्षित निवेश की मांग और केंद्रीय बैंक की खरीद पर सोना बार-बार नई ऊंचाई पर पहुंच गया, लेकिन पश्चिम एशिया संघर्ष तेज होने और डॉलर के मजबूत होने के कारण अधिकांश लाभ उलट गया। आपूर्ति में व्यवधान और मजबूत मांग परिदृश्य के कारण बेस मेटल की कीमतों में वृद्धि हुई है।

I.1 वैश्विक आर्थिक स्थितियाँ

वर्ष 2025 में, वैश्विक आर्थिक गतिविधि ने उच्च टैरिफ, बढ़ी हुई नीतिगत अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद सुदृढ़ता प्रदर्शित किया क्योंकि टैरिफ उपायों का समग्र प्रभाव शुरू में किए गए अनुमान से कम गंभीर निकला। प्रमुख भागीदारों के साथ अमेरिकी व्यापार सौदों ने राहत प्रदान की, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले और उसके पश्चात फरवरी में की गई नई टैरिफ घोषणाओं ने अनिश्चितता को फिर से जगाया है। अपने जनवरी 2026 विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2026 के लिए अपने वैश्विक विकास अनुमान को 20 बीपीएस से बढ़ाकर 3.3 प्रतिशत कर दिया, जो मुख्य रूप से मजबूत एआई से संबंधित निवेश और राजकोषीय खर्च को दर्शाता है। इसने अपने 2027 के अनुमान को 3.2 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। संघर्ष शुरू होने के बाद, ओईसीडी ने अधिक सतर्क तस्वीर प्रस्तुत की है। मार्च के अपने आर्थिक परिदृश्य में, इसने 2026 के लिए अपने वृद्धि अनुमान को 2.9 प्रतिशत पर कायम रखा क्योंकि पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई तकनीकी से संबंधित निवेश और सहायक राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों में मजबूत गति से होने की उम्मीद है। हालांकि, इसने अपने 2027 के अनुमान को मामूली रूप से 10 बीपीएस से घटाकर 3.0 प्रतिशत कर दिया।

प्रमुख एई में, 2025 के दौरान अमेरिकी वास्तविक जीडीपी वृद्धि में उतार-चढ़ाव आया, जो चौथी तिमाही में टैरिफ अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और आंशिक सरकारी

मौद्रिक नीति वक्तव्य

शटडाउन के प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि, अंतर्निहित आर्थिक गतिविधि व्यापक रूप से सुदृढ़ बनी रही। वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में मजबूत वृद्धि के बाद, चौथी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि कम हो गई, जो कमजोर निर्यात और कम सरकारी खर्च के कारण उम्मीदों से कम हो गई (सारणी I.1)। अक्टूबर 2025 के बाद से, गैर-कृषि पेरोल लाभ स्पष्ट रूप से धीमा हो गया जबकि बेरोजगारी दर मोटे तौर पर स्थिर रही। मार्च में समग्र पीएमआई 2023 के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया क्योंकि मजबूत विनिर्माण गतिविधि को सेवाओं में संकुचन ने इसकी भरपाई की। मिशिगन विश्वविद्यालय के सर्वेक्षण द्वारा मापा गया उपभोक्ता भावना, मार्च में थोड़ा कम होने से पहले फरवरी तक लगातार तीन महीनों तक सुधार हुआ। हालांकि, यह ऐतिहासिक मानकों के सापेक्ष कमजोर बना हुआ है क्योंकि मुद्रास्फीति और नौकरी की चिंताएं बनी हुई हैं।

सारणी I.1: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि

(प्रतिशत)

देश	ति1-2025	ति2-2025	ति3-2025	ति4-2025	2025 (ई)	2026 (पी)	2027 (पी)
तिमाही-दर-तिमाही, मौसमी रूप से समायोजित, वार्षिक दर (तिमाही-दर-तिमाही, एसएएआर)							
कनाडा	2.1	-0.9	2.4	-0.6	1.6	1.6	1.9
यूरो क्षेत्र	2.4	0.6	1.2	0.8	1.4	1.3	1.4
जापान	1.1	2.4	-2.6	1.3	1.1	0.7	0.6
दक्षिण कोरिया	-0.9	2.7	5.4	-0.6	1.0	1.9	2.1
यूके	2.6	0.8	0.3	0.2	1.4	1.3	1.5
यूएस	-0.6	3.8	4.4	0.7	2.1	2.4	2.0
(वर्ष-दर-वर्ष)							
ब्राज़ील	3.2	2.4	1.8	1.8	2.5	1.6	2.3
चीन	5.4	5.2	4.8	4.5	5.0	4.5	4.0
भारत	7.0	6.7	8.4	7.8	7.3	6.4	6.4
इंडोनेशिया	4.9	5.1	5.0	5.4	5.0	5.1	5.1
फ़िलिपींस	5.4	5.5	3.9	3.0	5.1	5.6	5.8
रूस	1.4	1.1	0.6		0.6	0.8	1.0
दक्षिण अफ़्रीका	0.9	0.7	2.1	0.8	1.3	1.4	1.5
थाईलैंड	3.1	2.8	1.2	2.5	2.1	1.6	2.2

मेमो:

विश्व	2025 (ई)	2026 (पी)	2027 (पी)
वर्ष-दर-वर्ष			
उत्पादन	3.3	3.3	3.2
व्यापार की मात्रा	4.1	2.6	3.1

ई: अनुमान पी: पूर्वानुमान

टिप्पणियाँ: 1. भारत का डेटा वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के अनुरूप है; *उदाहरण* के लिए 2025, अप्रैल 2025-मार्च 2026 से संबंधित है।

2. 2026 और 2027 के लिए अनुमान आईएमएफ डब्ल्यूईओ, जुलाई 2026 अपडेट से लिए गए है।

स्रोत: आधिकारिक सांख्यिकीय एजेंसियां; ब्लूमबर्ग; विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट, जनवरी 2026, आईएमएफ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अन्य एई के बीच, जापान की जीडीपी अमेरिकी टैरिफ से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी, वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में इसमें संकुचन आई क्योंकि निर्यात में गिरावट आई और सख्त ऊर्जा-दक्षता मानकों के कारण आवासीय निवेश गिर गया। चौथी तिमाही में, आवासीय निवेश और सरकारी व्यय में पलटाव से समर्थन प्राप्त होने से जीडीपी में मामूली वृद्धि हुई। नई सरकार द्वारा राजकोषीय विस्तार से निकट अवधि के वृद्धि को समर्थन मिलने की उम्मीद है। सेवाओं और औद्योगिक गतिविधि दोनों में मार्च में पीएमआई में विस्तार कम हो गया। यूरो क्षेत्र में, निवल निर्यात से अवरोध के बावजूद मजबूत निवेश और सरकारी खर्च के कारण तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई। चौथी तिमाही में वृद्धि कमजोर हो गई क्योंकि निवेश और सरकारी खर्च धीमा हो गया। वर्ष 2026 की पहली तिमाही में अब तक, यूरो क्षेत्र में समग्र पीएमआई ने फरवरी में विस्तार का संकेत दिया, जिसमें नए कारखाने के ऑर्डर बढ़ने के बीच विनिर्माण में उछाल आया। यूके में कमजोर सेवा गतिविधियों और निर्माण क्षेत्र में गिरावट के कारण तीसरी और चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर नियंत्रित रही। नवंबर के यूके के बजट से राजस्व का समर्थन करने और बढ़ते सार्वजनिक ऋण पर चिंताओं को कम करने की उम्मीद है। पीएमआई रीडिंग द्वारा इंगित किए गए अनुसार मजबूत व्यावसायिक गतिविधि के हालिया संकेतों के बावजूद दिसंबर और जनवरी 2026 में बेरोजगारी लगभग पांच साल के उच्च स्तर 5.2 प्रतिशत तक बढ़ने से श्रम बाजार में नरमी आई है।

प्रमुख ईएमई में, चीन को 2025 में उच्च टैरिफ, एक स्थिर संपत्ति बाजार और कमजोर घरेलू खपत से विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने अपने 5.0 प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य को प्राप्त किया। तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि कम हो गई क्योंकि फ्रंट-लोडेड ट्रेड परिणाम सामने आए, और सकल स्थायी पूंजी निर्माण में गिरावट आई। संपत्ति क्षेत्र में मंदी बनी रहने के बावजूद सरकारी प्रोत्साहन उपायों ने खपत का समर्थन किया। विशेष रूप से, चीन के विदेशी व्यापार ने 2025 में रिकॉर्ड अधिशेष

दर्ज किया, जो उच्च अमेरिकी टैरिफ के बीच नए बाजारों में विविधीकरण से प्रेरित है। हालांकि, मार्च 2026 में विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में गतिविधि धीमी होने के कारण पीएमआई विस्तार की गति में कमी आई।

ब्राजील की जीडीपी वृद्धि चौथी तिमाही में 1.8 प्रतिशत (व-द-व) पर स्थिर रही क्योंकि विनिर्माण में संकुचन से सेवा और कृषि में वृद्धि की भरपाई की गई थी। वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में बेरोजगारी दर में गिरावट के बावजूद घरेलू खपत कमजोर रही, जो सख्त वित्तीय स्थितियों को दर्शाती है। विनिर्माण और सेवाओं दोनों क्षेत्रों में बिक्री में गिरावट के कारण मार्च में समग्र पीएमआई में संकुचन हुआ। बढ़ते प्रतिबंधों और उच्च ब्याज दरों के कारण घरेलू मांग में आई कमी के बीच निवल निर्यात में नरमी के कारण तीसरी तिमाही में रूस की वृद्धि कमजोर हो गई। दक्षिण अफ्रीका में भी, विनिर्माण और खनन में संकुचन के कारण चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में कमी आई, जबकि सेवा और कृषि क्षेत्र सुदृढ़ रहे। हालांकि, कमजोर चौथी तिमाही के बाद, कंपोजिट पीएमआई वर्ष 2026 की पहली तिमाही (फरवरी तक) में न्यूट्रल स्तर पर रहा, जो स्थिर व्यापारिक स्थितियों को दर्शाता है।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा दिसंबर में आसियान[1] अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि में संशोधन करते हुए बढ़ाया गया था, जिससे सितंबर के पूर्वानुमान से 2025 के अनुमान को 20 बीपीएस बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया गया था, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में तीसरी तिमाही के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। बाहरी वातावरण में सुधार और सहायक सार्वजनिक खर्च को देखते हुए 2026 के लिए वृद्धि अनुमानों को भी 10 बीपीएस बढ़ाकर 4.4 प्रतिशत कर दिया गया था।

उच्च-आवृत्ति संकेतकों की ओर मुड़ते हुए, ओईसीडी के समग्र प्रमुख संकेतकों (सीएलआई) से पता चला है कि अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं वर्ष 2025 की चौथी तिमाही और वर्ष 2026 की पहली तिमाही (फरवरी तक) (चार्ट I.1ए) के दौरान अपनी दीर्घकालिक प्रवृत्ति से ऊपर रहीं। वैश्विक समग्र पीएमआई फरवरी में विस्तार क्षेत्र में मजबूती से रहा, जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में वृद्धि से प्रेरित है (चार्ट I.1 बी)। हालांकि, मार्च में उत्पादन और नए ऑर्डर में कमी आने के कारण विनिर्माण गतिविधि की गति धीमी हो गई।

लिबरेशन डे यूएस टैरिफ घोषणाओं द्वारा लाई गई बढ़ती टैरिफ-संबंधित अनिश्चितता से व्यवधानों के बावजूद, वैश्विक व्यापारिक कारोबार की मात्रा वर्ष 2025 की चौथी तिमाही तक लगातार नौ तिमाहियों के लिए विस्तारित हुई। विस्तार

चार्ट I.1: सर्वेक्षण संकेतक

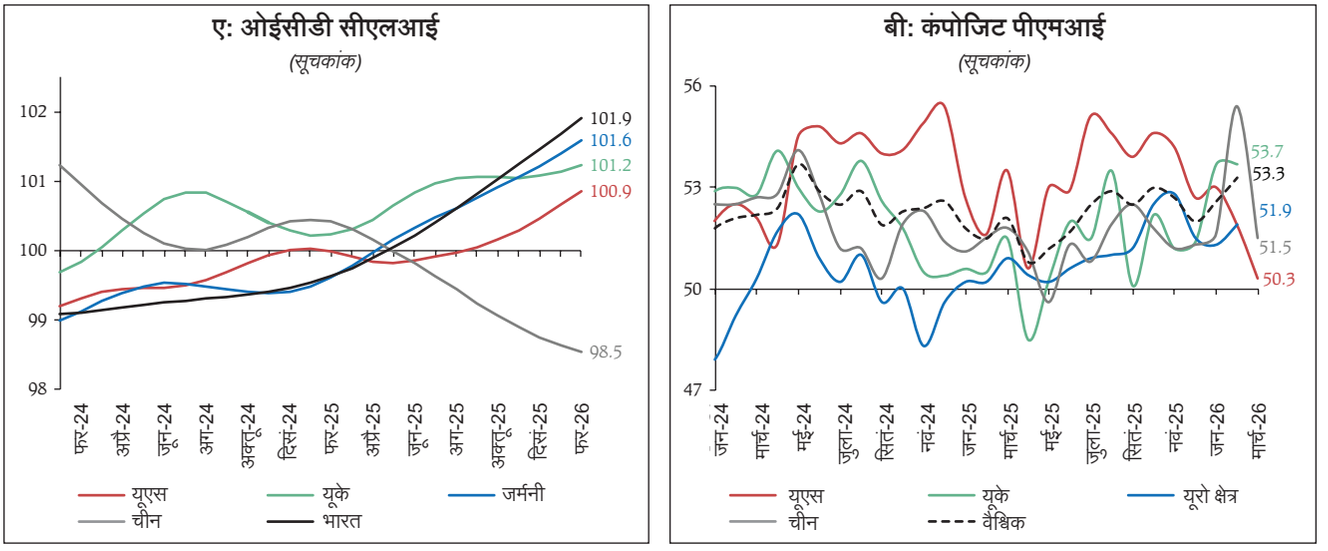

स्रोत: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी); और ब्लूमबर्ग।

[1] दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) में ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

को द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था और उभरते बाजार और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं दोनों द्वारा निर्यात और आयात की फ्रंट-लोडिंग द्वारा समर्थित था (चार्ट I.2ए)। विश्व व्यापार संगठन (मार्च 2026) से पता चलता है कि 2025 में व्यापार की मात्रा में 4.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो एआई से संबंधित उत्पादों में मजबूत व्यापार से प्रेरित है और काफी हद तक टैरिफ एवं अनुकूल समष्टि आर्थिक स्थितियों से मुक्त हैं। हालांकि, विश्व व्यापार संगठन का अनुमान है कि लगातार नीतिगत अनिश्चितता और कमजोर वैश्विक मांग के कारण 2026 में वैश्विक व्यापार वृद्धि दर तेजी से घटकर 1.9 प्रतिशत रह जाएगी। 2025 के दौरान माल ढुलाई दरें, जैसा कि फ्रेटोस बाल्टिक ग्लोबल इंडेक्स में परिलक्षित होता है, अपने 2024 के औसत से नीचे रहीं, जो शिपिंग लागत पर कम दबाव का संकेत देती हैं (चार्ट I.2बी)।

I.2 पण्य कीमतें और मुद्रास्फीति

वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के बाद से, ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स द्वारा दर्शाई गई पण्य कीमतें, कीमती धातुओं की मजबूत सुरक्षित-निवेश मांग के कारण बीच-बीच में उछाल के साथ धीरे-धीरे बढ़ी है (चार्ट I.3ए)। पण्य कीमतों में मुख्य रूप से क्षेत्र-विशिष्ट मूलभूत कारकों के कारण भिन्नता आई है, क्योंकि कीमती और औद्योगिक धातुओं में तीव्र वृद्धि देखी गई है (बॉक्स I.1)। पर्याप्त आपूर्ति के कारण कृषि कीमतें काफी हद तक अपरिवर्तित रहीं। वैश्विक खाद्य कीमतों में वर्ष 2025 की चौथी तिमाही की तुलना में वर्ष 2026 की पहली तिमाही में मामूली वृद्धि हुई जो मांस, अनाज और वनस्पति तेल (चार्ट I.3बी) द्वारा प्रेरित थी।

पिछली तिमाही के सापेक्ष वर्ष 2026 की पहली तिमाही में ऊर्जा की कीमतें बढ़ीं, जो मुख्य रूप से आपूर्ति व्यवधानों के कारण कच्चे तेल से प्रेरित थीं। पर्याप्त आपूर्ति के बीच ब्रेंट क्रूड 2025 की चौथी तिमाही में कमजोर हुआ, लेकिन मार्च में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के कारण कीमतें तेजी से बढ़ीं (चार्ट I.3सी)।

सोने की कीमतें वर्ष 2025 की चौथी तिमाही और 2026 के पहले दो महीनों तक बढ़ीं, जो लगातार व्यापार तनाव, केंद्रीय बैंक की खरीद और नरम अमेरिकी डॉलर पर सुरक्षित-निवेश मांग द्वारा समर्थित हैं। हालांकि, अमेरिकी मौद्रिक नीति पर बदलती प्रत्याशाओं, डॉलर मूल्यवृद्धि, उच्च यूएस प्रतिफल और मुनाफावसूली पर मार्च में इसमें गिरावट आई। आपूर्ति में कमी और टैरिफ को लेकर अनिश्चितता के कारण तांबे की कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे जोखिम प्रीमियम में वृद्धि हुई। आपूर्ति में कमी और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने के कारण एल्युमीनियम और जस्ता की कीमतों में वृद्धि हुई। चीन से बेहतर मांग परिदृश्य और सरकार के नए प्रोत्साहन उपायों तथा अर्थव्यवस्था के हरित प्रौद्योगिकियों की ओर बढ़ने से मूल धातुओं को और समर्थन मिला। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने वैश्विक पण्य बाजारों में अनिश्चितता को और बढ़ा दिया। हालांकि, अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के साथ ही धातु की कीमतों में आई तेजी

चार्ट I.2: विश्व व्यापार मात्रा

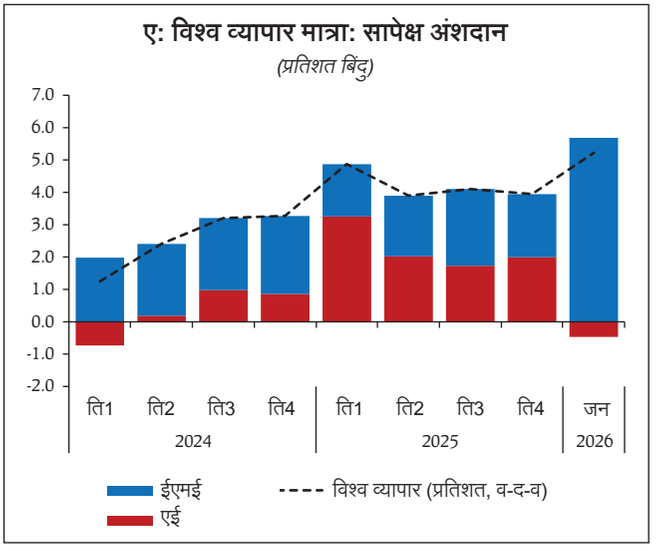

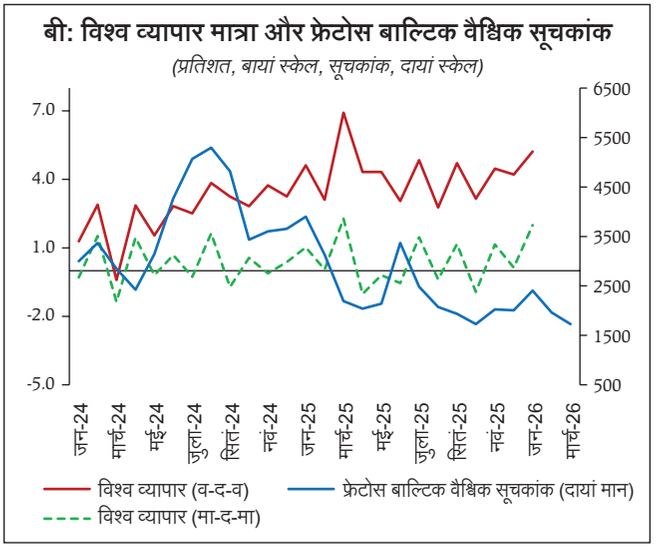

स्रोत: सीपीबी नीदरलैंड; और आरबीआई स्टाफ गणना।

चार्ट I.3: पण्य कीमतें

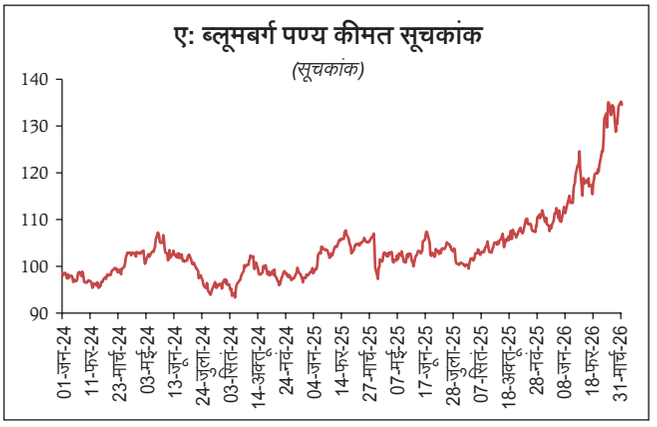

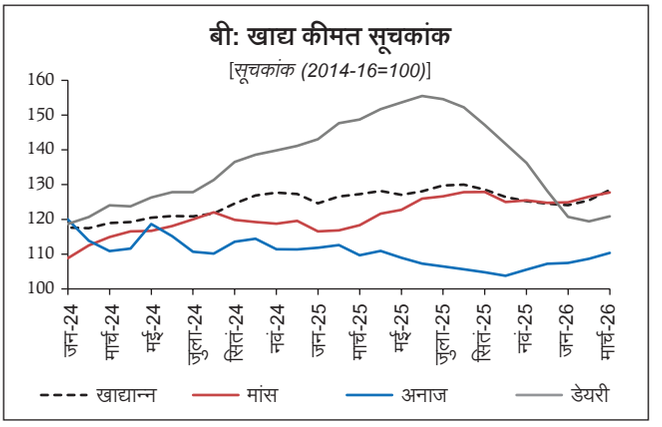

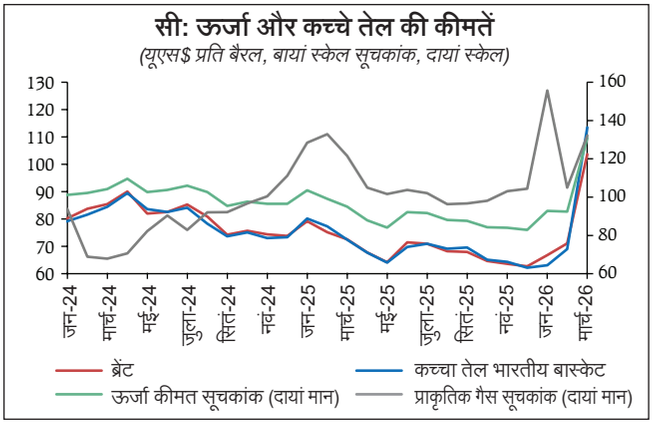

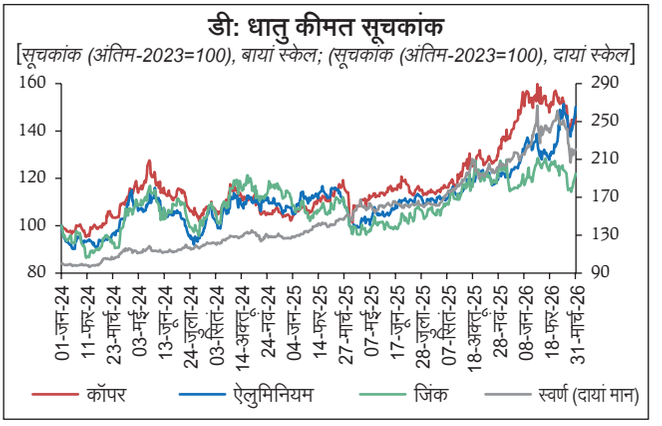

स्रोत: खाद्य और कृषि संगठन; विश्व बैंक; ब्लूमबर्ग; तथा पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार।

फीकी पड़ गई, क्योंकि अमेरिकी प्रतिफल में वृद्धि और सुरक्षित निवेश के लिए प्रवाह में वृद्धि के कारण मार्च में अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ (चार्ट I.3डी)।

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक मुद्रास्फीति हालांकि असमान गति से जारी रही। एक कमजोर अमेरिकी

बॉक्स.I.1 सोने की कीमतों में उफान की स्थिति?

2024 से सोने की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि, अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना और वैश्विक मौद्रिक नीति में सख्ती के दौर के अंत के बाद प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति में ढील की बढ़ती प्रत्याशाएं हैं। कीमतों में भारी उछाल आया – अपेक्षाकृत कम समय में ही ये दोगुनी से अधिक हो गईं; 2023 के अंत में लगभग 2,060 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर फरवरी 2026 तक 5,000 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गईं और बार-बार नए उच्च स्तर पर पहुंच गईं। इस अवधि के दौरान, सोना वैश्विक स्तर पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली संपत्तियों में शुमार रहा (चार्ट I.1.1)। हालांकि इस वृद्धि का एक हिस्सा मजबूत सुरक्षित निवेश की मांग और बढ़ी हुई अनिश्चितता को दर्शाता है, लेकिन वृद्धि की गति और निरंतरता 2025 के दौरान एक उफान स्थिति के निर्माण की संभावना का संकेत देती है। ऐसी उफान की स्थितियों में आमतौर पर कीमतों में तेजी से और तीव्र उछाल आता है – जिसे विस्फोटक व्यवहार कहा जाता है – जिसके बाद तीव्र गिरावट आती है (फिलिप्स एट अल., 2011)। फिर भी, इनका पता लगाना मुश्किल बना हुआ है: इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि उछाल के बाद होने वाली गिरावटें पूर्वानुमानित होती हैं, जिससे मूलभूत कारकों में होने वाले परिवर्तनों के प्रति तर्कसंगत प्रतिक्रियाओं के अतार्किक उत्साह में अंतर करना कठिन हो जाता है, जो अप्रत्यक्ष या अनदेखे हो सकते हैं (शिलर, 2000)। इन पहचान संबंधी समस्याओं से बचने के लिए, सांख्यिकीय विधियाँ मूलभूत कारकों का प्रत्यक्ष मॉडलिंग करने के बजाय कीमतों के समय-श्रृंखला गुणों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। विशेष रूप से, वे ऐसी अत्यंत उफान स्थिति विशिष्ट विस्फोटक प्रकृति का लाभ उठाती हैं, जहाँ

(जारी...)

मौद्रिक नीति वक्तव्य

चार्ट I.1.1: आस्ति रिटर्न

(प्रतिशत)

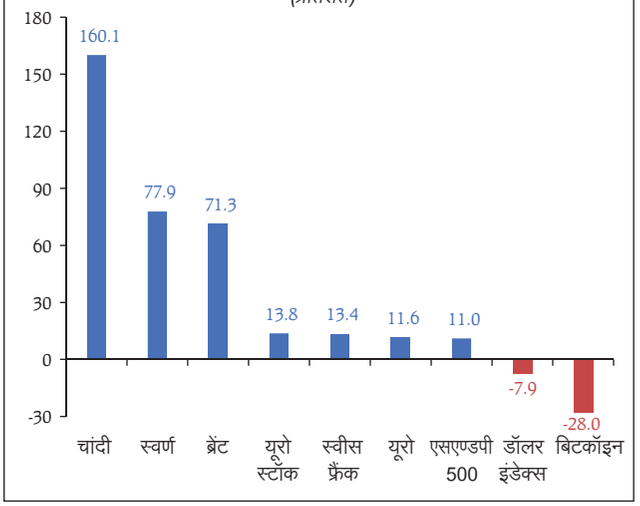

चार्ट I.1.2: स्वर्ण कीमत के लिए रोलिंग एडीएफ आँकड़े

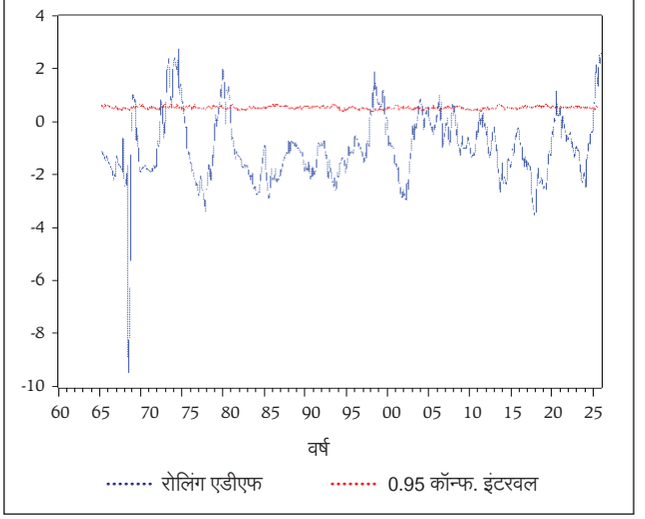

टिप्पणी: रिटर्न की गणना 1 जनवरी, 2025 से 16 फरवरी, 2026 तक की गई है।
स्रोत: विश्व बैंक कमोडिटी मूल्य डेटा (पिंक शीट); ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

डेटा उत्पन्न करने की प्रक्रिया ऊपर की ओर बहाव के साथ अस्थिर हो जाती है, जिससे कीमतों में तेजी से वृद्धि होती है (इवांस, 1991)। इसने यूनिट-रूट-टाइप समान प्रक्रियाओं के उपयोग को प्रेरित किया है, जिसमें ऐसी अत्यंत नाजुक स्थिति की उपस्थिति ऑटोरेग्रेसिव जड़ से मेल खाती है, जो योग से अधिक है और विस्फोटक गतिशीलता का संकेत देती है (फिलिप्स एट अल., 2015)। अनुभवजन्य अध्ययन केवल मूलभूत कारकों से ऐसी उफान स्थिति का अनुमान लगाने के बजाय देखी गई मूल्य श्रृंखलाओं में ऐसे विस्फोटक प्रकरणों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

इसकी जांच करने के लिए, राइट-टेल्ड ऑगमेंटेड डिकी-फुलर (आरएडीएफ) पद्धति का उपयोग किया गया है, जिसे 1960 से आगे के मासिक डेटा पर रोलिंग एडीएफ रिग्रेशन के माध्यम से लागू किया गया है, ताकि कीमतों में अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव की पहचान की जा सके। हालांकि यह दृष्टिकोण तेजी के दौर का पता लगाने में उपयोगी है, लेकिन यह परिसंपत्ति मूल्य उफान स्थिति की पहचान करने का निर्णायक परीक्षण नहीं है। यह तब भी अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव को इंगित कर सकता है जब कीमतों में तेजी से वृद्धि यह मौलिक कारकों में बदलाव, संरचनात्मक विच्छेद या अस्थिरता के समूह के कारण हो रही हो और यह इसकी संभावित उलटफेर के सटीक समय की भविष्यवाणी नहीं करता है। परिणाम बताते हैं कि 2025 में परीक्षण सांख्यिकी 95 प्रतिशत महत्वपूर्ण सीमा से ऊपर चली गई, जो सोने की कीमतों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण विस्फोटक गतिशीलता की अवधि को इंगित करती है (चार्ट I.1.2)। सोने की कीमतों में अचानक गिरावट मार्जिन कॉल और लीवरेज्ड पोजीशन के परिसमापन को ट्रिगर कर सकती है, जिससे निवेशकों को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है और बाजारों में अस्थिरता आती है। यह पोर्टफोलियो आवंटन और बाजार की भावना को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे इक्विटी, बॉन्ड और मुद्राओं में व्यापक पुनर्मूल्यांकन हो सकता है।

कुल मिलाकर, साक्ष्य बताते हैं कि 2025 में सोने की कीमतों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण विस्फोटक गतिशीलता का दौर शुरू हुआ, जो उफान जैसे व्यवहार के अनुरूप है। कीमतों में यह तीव्र और निरंतर उछाल बाजार में अत्यधिक उत्साह और अंतर्निहित जोखिमों में संभावित वृद्धि की ओर इशारा करता है।

संदर्भ:

1. इवांस, जी. डब्ल्यू. (1991). पिटफाल्स इन टेस्टिंग फॉर एक्सप्लोसिव बबल्स इन एसेट प्राईसेज। अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, 81(4), 922–930।
2. फिलिप्स, पी. सी. बी., वू, वाई., और यू, जे. (2011).एक्सप्लोसिव बिहेवियर इन दि 1990 एनएसडीएक्यू: व्हेन डिड एक्जूबरेंस एस्कलेट एसेट वैल्यूज ? इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिव्यू, 52(1), 201–226.
3. फिलिप्स, पी. सी. बी., शी, एस., और यू, जे. (2015). टेस्टिंग फॉर मल्टिपल बबल्स: हिस्टोरिकल एपिसोड ऑफ एक्जूबरेंस एण्ड कोलैप्स इन दि एस एण्ड पी 500। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिव्यू, 56(4), 1043–1078.
4. शिलर, आर. जे. (2000). ईरैशनल एक्जूबरेंस। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

डॉलर ने विशेष रूप से उभरते बाजारों में बड़े विदेशी मुद्रा जोखिम के साथ आयातित मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में मदद की। नवीनतम ओईसीडी आर्थिक आउटलुक के अनुसार, चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष के आसपास बढ़ी हुई अनिश्चितता ने ऊर्जा की कीमतों को मजबूत कर दिया है, जिससे 2026 में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ने और मध्यम अवधि की मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं बढ़ने की उम्मीद है।

हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो गई है लेकिन कुछ प्रमुख एई में लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। अमेरिका में मुद्रास्फीति, जिसे व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है - फेडरल रिजर्व का पसंदीदा मुद्रास्फीति मीट्रिक - मोटे तौर पर स्थिर रहा है लेकिन लक्ष्य से ऊपर है। पीसीई मुद्रास्फीति में हाल के महीनों में थोड़ी वृद्धि देखी गई है, जो निरंतर सेवाओं की मुद्रास्फीति के बीच उच्च ऊर्जा कीमतों और आश्रय लागत को दर्शाती है। यूके में, हेडलाइन मुद्रास्फीति वर्ष 2025 की दूसरी छमाही के बाद से कम हो रही है, जो मुख्य रूप से धीमी मजदूरी वृद्धि के बीच सेवाओं की मुद्रास्फीति को कम करने के कारण है, हालांकि यह लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। यूरो क्षेत्र में, हेडलाइन मुद्रास्फीति वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 2.0 प्रतिशत लक्ष्य के करीब रही, जनवरी 2026 में 1.7 प्रतिशत तक गिर गई, और फिर मार्च में 2.5 प्रतिशत तक बढ़ गई, जिसका मुख्य कारण उच्च ऊर्जा मुद्रास्फीति है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी और बिजली की कीमतों में गिरावट के कारण पिछली एमपीआर के बाद से जापान में मुद्रास्फीति में आम तौर पर कमी आई है (चार्ट 1.4ए)।

पिछले एमपीआर के बाद से सीपीआई मुद्रास्फीति में आम तौर पर गिरावट आई है। ब्राजील में, पहले की गई मौद्रिक सख्ती के कारण हेडलाइन सीपीआई धीरे-धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण अफ्रीका में, परिवहन लागत में हाल ही में गिरावट के साथ हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा के भीतर बनी हुई है। रूस में, सीपीआई मुद्रास्फीति अवस्फीतिकारी पथ पर रही है। चीन की हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति सकारात्मक बनी रही, चीनी नव वर्ष से संबंधित खर्च के कारण जनवरी 2023 के बाद से फरवरी में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट I.4बी)।

पिछले एमपीआर के बाद से, सेवा मुद्रास्फीति में कमी से समर्थित कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति कम हुई है, जबकि प्रमुख उभरते बाजारों में मुद्रास्फीति नियंत्रित बनी हुई है। हालांकि, ऊर्जा की कीमतों में नए सिरे का दबाव, मुद्रास्फीति के परिदृश्य के लिए एक नए ऊर्ध्वगामी जोखिम के रूप में उभरी है।

कुल मिलाकर, हालांकि कई अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, ऊर्जा की कीमतों में हालिया वृद्धि ने ऊर्ध्वगामी जोखिमों को बढ़ाया है, जिसके लिए मौद्रिक नीति पथ के सावधानीपूर्वक समायोजन की आवश्यकता है।

चार्ट I.4: सीपीआई मुद्रास्फीति (व-द-व) – चुनिंदा अर्थव्यवस्थाएं

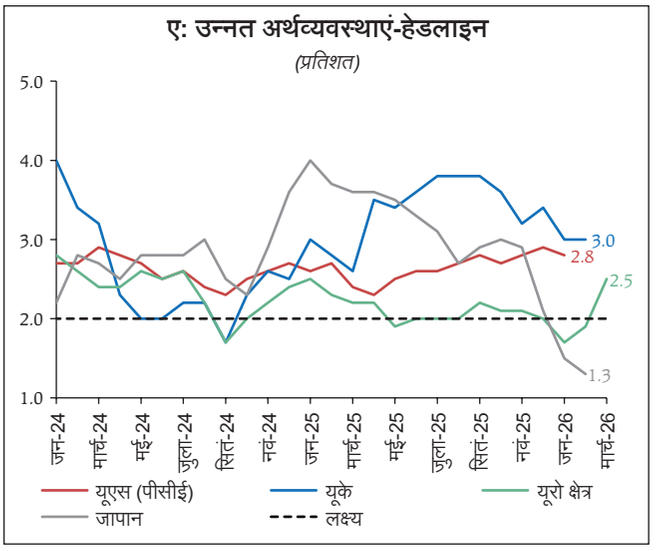

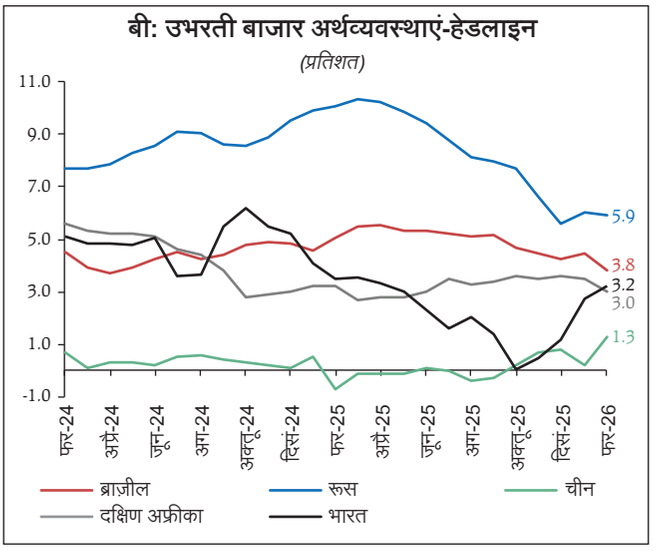

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

I.3 मौद्रिक नीति रुख

अक्टूबर 2025 से वैश्विक सुलभ चक्र धीमा हो गया है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने मुख्यत: विराम की ओर रूख किया, जबकि बैंक ऑफ जापान और ऑस्ट्रेलिया ने धीरे-धीरे सख्ती का चक्र शुरू किया है। मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण कुछ उभरते बाजारों के केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत उपायों में ढील देना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप नीतिगत दर स्थिर हो गई।

प्रमुख एई में, रोजगार पर अधोगामी जोखिमों के प्रति संतुलित प्रतिक्रिया के रूप में फेड ने अक्टूबर और दिसंबर की बैठकों में नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कमी की। इसने 2026 की पहली तिमाही में दरों को अपरिवर्तित रखा क्योंकि मुद्रास्फीति कुछ हद तक उच्च बनी रही, ताकि नीति में समायोजन करने से पहले यह आकलन किया जा सके कि पहले के कदम और तेल संकट अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। इस संबंध में, हाल की बैठकों में एफओएमसी सदस्यों के विचारों में तेजी से भिन्नता आई है। यह मुद्रास्फीति, श्रम बाजार की मजबूती और नीतिगत सहजता के समय को लेकर बढ़ती अनिश्चितता को दर्शाता है, जिसमें नीति निर्माता निरंतर मुद्रास्फीति से बचाव और अत्यधिक सख्ती की लागत से बचने के बीच विभाजित हैं (चार्ट I.5)।

सितंबर 2025 से, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सक्रिय सहजता की नीति से हटकर सतर्कतापूर्ण विराम की नीति अपनाई है जिसमें

चार्ट I.5: एफओएमसी – गवर्नर असहमति

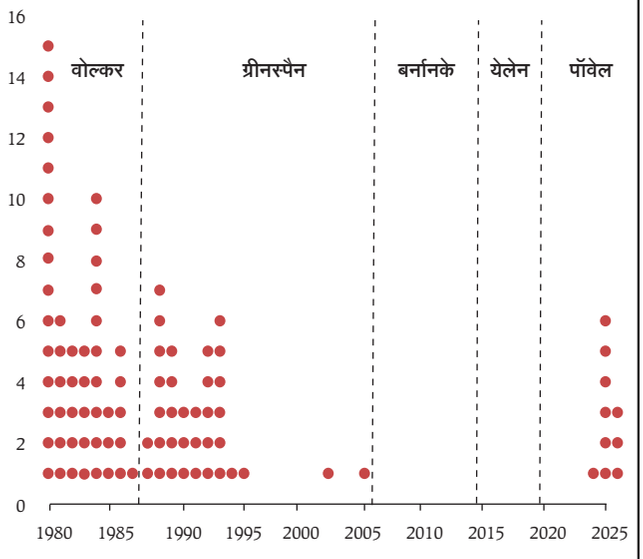

स्रोत: दि फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ सेंट लुइस।

दिसंबर में बैंक ब्याज दर में कटौती की गई, लेकिन मुद्रास्फीति के लक्ष्य की ओर बढ़ने के कारण उसके बाद विराम लाया गया। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने लचीला और डेटा पर आधारित दृष्टिकोण बनाए रखते हुए, अपनी नीतिगत सहजता का चक्र काफी हद तक पूरा कर लिया है, और निर्णय प्रत्येक बैठक के आधार पर लिए जाते हैं। पिछले एमपीआर के बाद से, बैंक ऑफ जापान (बीओजे) ने ब्याज दरों को 0.5 प्रतिशत पर स्थिर रखने के बजाय 25 आधार अंकों की वृद्धि कर 0.75 प्रतिशत कर दिया है, जो तीन दशकों में इसका उच्चतम स्तर है, क्योंकि इस बात का भरोसा बढ़ा है कि मुद्रास्फीति और मजदूरी में टिकाऊ आधार पर मजबूती आ रही है। बीओजे ने 2026 की पहली तिमाही में ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा, और आगे सख्ती करने पर विचार करने से पहले मजदूरी वृद्धि और अंतर्निहित मुद्रास्फीति के स्पष्ट प्रमाणों की प्रतीक्षा करने के साथ-साथ पश्चिम एशिया में तनाव से उत्पन्न कमजोर आर्थिक गतिविधि और तेल की कीमतों में आए झटके के प्रभाव का आकलन करने का विकल्प चुना। अन्य एई के बीच, रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया ने फरवरी और मार्च दोनों में ब्याज दरों में वृद्धि करके नीतिगत सख्ती शुरू की, ताकि श्रम बाजार में बढ़ती मुद्रास्फीति का मुकाबला किया जा सके। इसके विपरीत, बैंक ऑफ़ कनाडा ने अर्थव्यवस्था और कमजोर श्रम बाजार को सहारा देने के लिए अक्टूबर 2025 में ब्याज दर में 25 बीपीएस की कटौती की। हालांकि, टैरिफ संबंधी अनिश्चितता और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच इसने अपनी पिछली तीन बैठकों में नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा। इसी प्रकार, न्यूजीलैंड ने धीमी वृद्धि के बीच 2025 की चौथी तिमाही में दरों में कटौती करने से हटकर 2026 में अब तक नीतिगत दरों को स्थिर रखते हुए प्रतीक्षा करो और देखो की नीति अपनाई है। (चार्ट I.6ए)।

प्रमुख ईएमई में, ब्राजील के केंद्रीय बैंक ने सर्वसम्मति से मार्च में सेलिक दर में एक चौथाई अंक की कमी की, जो लगभग दो वर्षों में पहली कटौती है और यह कटौती आर्थिक गतिविधियां सुस्त बनी रहने के कारण की गई। रूस के बैंक ने आर्थिक विकास की गति अधिक संतुलित होने और मुद्रास्फीति के लक्ष्य के करीब पहुंचने के साथ ही अपनी प्रमुख दर में धीरे-धीरे कमी की है। चीन ने लगभग एक वर्ष से अपनी बेंचमार्क दर को 3.0 प्रतिशत पर स्थिर रखा है। दक्षिण अफ्रीका ने लक्ष्य सीमा से हटकर 3.0 प्रतिशत (±1 प्रतिशत बिंदु) के लक्ष्य बिंदु पर आ

चार्ट I.6: नीति दर परिवर्तन – चुनिंदा प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं

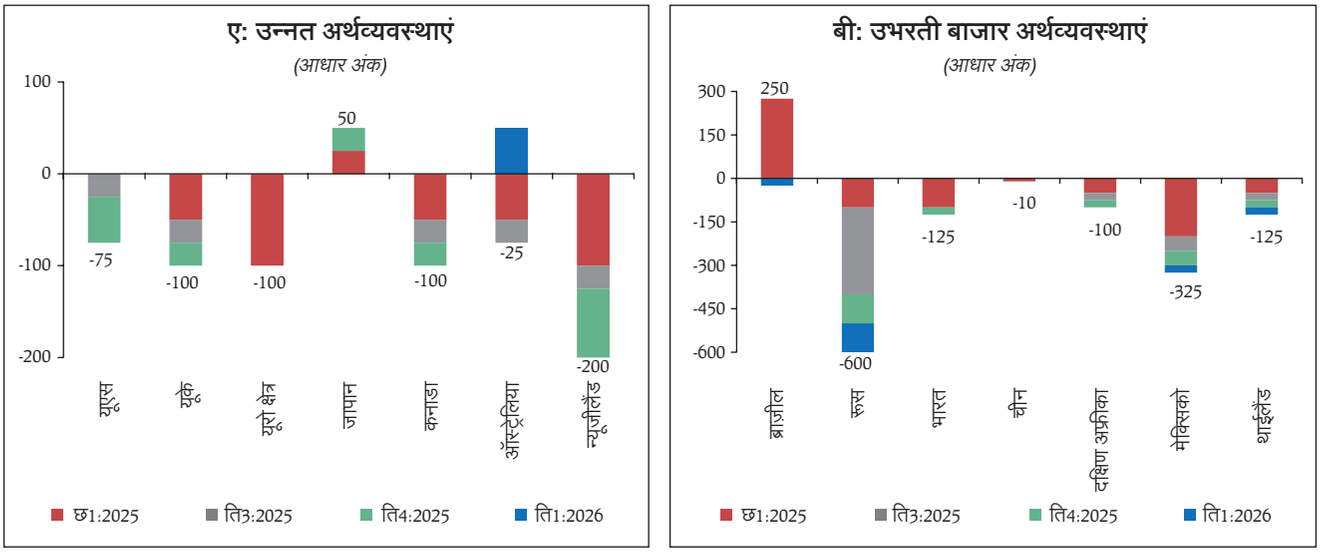

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

गया है। मुद्रास्फीति की बेहतर संभावनाओं के साथ, एमपीसी ने नवंबर में नीतिगत दर में 25 आधार अंक की कटौती करके इसे 6.75 प्रतिशत कर दिया, लेकिन मुद्रास्फीति के ऊर्ध्वगामी जोखिम के कारण 2026 में फिलहाल इसमें विराम लगा हुआ है। थाईलैंड ने कमजोर आर्थिक सुधार को समर्थन देने और ऋण बोझ को कम करने के लिए अपनी नीतिगत दर में दो बार कटौती की। मैक्सिको ने भी कुल 75 आधार अंक की दर में कमी की, क्योंकि कमजोर वृद्धि और मुद्रास्फीति के धीरे-धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने के अनुमानों ने नीतिगत सामान्यीकरण की अनुमति दी (चार्ट I.6बी)।

I.4 वित्तीय बाजार

व्यापारिक तनाव और भू-राजनीतिक अस्थिरताओं के बावजूद, 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में वैश्विक जोखिम भावना सकारात्मक बनी रही क्योंकि मुद्रास्फीति में कमी आई, मौद्रिक नीति निभावकारी बनी रही और एआई से संबंधित आशावाद कायम रहा। इसके विपरीत, मार्च 2026 में शेयरों में व्यापक गिरावट आई और जोखिम उन्मुख रुझान में बदलाव आया, क्योंकि पश्चिम एशिया में संघर्ष और मुद्रास्फीति की नई चिंताओं ने निवेशकों को जोखिम भरी संपत्तियों में निवेश कम करने के लिए प्रेरित किया। राजकोषीय चिंताओं के बीच सरकारी बांडों पर ब्याज दरें ऊंची बनी रहीं, और हाल ही में हुए पश्चिम एशिया संघर्ष ने उन पर और ऊर्ध्वगामी दबाव डाला। मुद्रा बाज़ारों में भी इस बदलाव का प्रभाव दिखा और हाल ही में सुरक्षित निवेश की मांग के चलते अमेरिकी डॉलर मज़बूत हुआ। अधिकांश विकसित और उभरते बाज़ारों की मुद्राओं पर अवमूल्यन का दबाव रहा।

वैश्विक शेयर बाजारों में 2025 की चौथी तिमाही में तेजी देखी गई, जिसमें विकसित और उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं में लाभ हुआ (चार्ट I.7ए)। मजबूत आय वृद्धि, मुद्रास्फीति के दबाव में कमी और इस उम्मीद से कि प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंक 2026 में ब्याज दरों में कमी जारी रखेंगे, शेयर बाजारों को समर्थन मिला। 2025 की चौथी तिमाही में, सबसे लंबे सरकारी शटडाउन के बावजूद, अमेरिकी शेयरों में लाभ दर्ज किया गया। तिमाही लाभ ने बाजार को लगातार तीसरे वर्ष दोहरे अंकों का रिटर्न देने में मदद की। एआई से संबंधित आशावाद, निभावकारी मौद्रिक नीति और व्यापार समझौतों में कुछ प्रगति के कारण एसएंडपी 500 इंडेक्स ने 2025 के लिए लगभग 16.0 प्रतिशत रिटर्न दिया, हालांकि निवेशक तकनीकी शेयरों के उच्च मूल्यांकन को लेकर चिंतित रहे। यूरो क्षेत्र ने भी मुद्रास्फीति में कमी और बेहतर दृष्टिकोण के कारण चौथी तिमाही में सकारात्मक लाभ दर्ज किया क्योंकि 2025 के लिए जीडीपी पूर्वानुमान को ऊपर की ओर संशोधित किया गया था। जनरेटिव एआई में मजबूत वृद्धि और उच्च रक्षा खर्च की प्रत्याशाओं के

मौद्रिक नीति वक्तव्य

चार्ट I.7: वैश्विक इक्विटी और मूल्यांकन

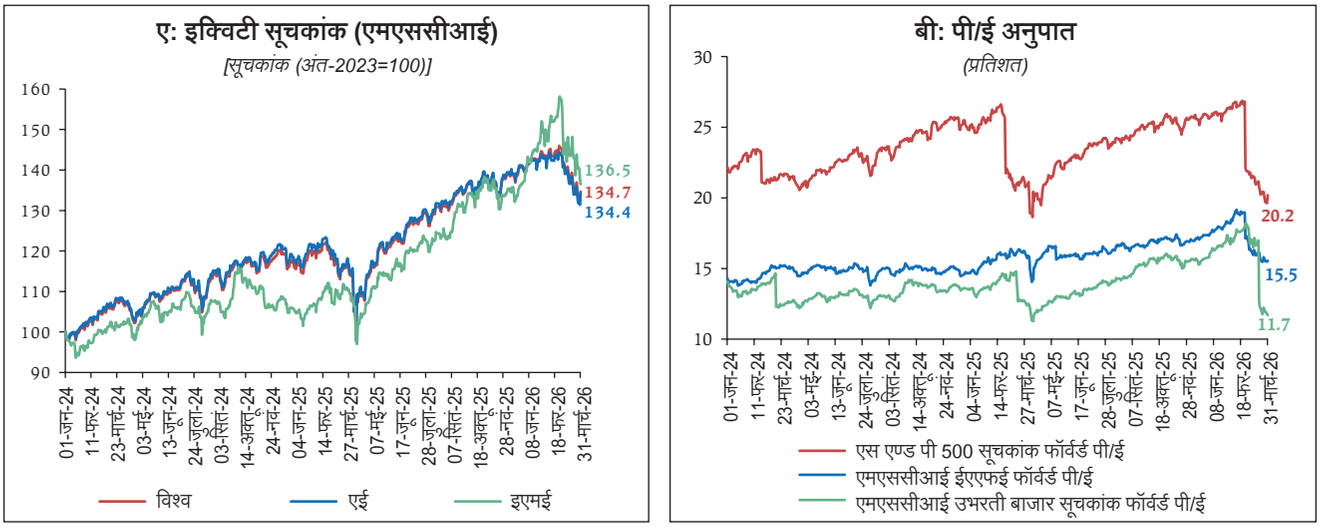

टिप्पणी: एमएससीआई ईएएफई इंडेक्स एक इक्विटी इंडेक्स है जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और सुदूर पूर्व के विकसित बाजारों के देशों में बड़ी और मध्यम आकार की कंपनियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग और आरबीआई स्टाफ गणना।

कारण जापानी शेयरों में भी चौथी तिमाही में लाभ हुआ। जापान में नई सरकार के गठन को अधिक राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने और अधिक राजकोषीय प्रोत्साहन का समर्थन करने के रूप में देखा गया।

2026 की पहली तिमाही में, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण जोखिम भावना में गिरावट आने से शेयर बाज़ारों में गिरावट आई, जिसका असर प्रमुख सूचकांकों पर पड़ा। अमेरिकी डॉलर के मज़बूत होने से जोखिम-विमुख रुझान और भी बढ़ गया, हालांकि कई देशों में निभावकारी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के चलते समग्र परिस्थितियाँ अनुकूल बनी हुई हैं। डॉलर की कमज़ोरी और देश-विशिष्ट कारकों के कारण उभरते बाज़ारों ने विकसित बाज़ारों से बेहतर प्रदर्शन किया है, भले ही राजनीतिक तनाव और ब्याज दरों में बदलाव की प्रत्याशाएं बनी हुई हों। हाल ही में, एफओएमसी के नवीनतम निर्णय और कार्यवृत्त के बाद, निवेशकों ने फेड की नीति को आक्रामक मानते हुए, प्रौद्योगिकी शेयरों के बढ़े हुए मूल्यांकन का पुनर्मूल्यांकन करते हुए और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर प्रतिक्रिया देते हुए, विकसित और उभरते दोनों बाज़ारों में बिकवाली का दबाव देखा है। घरेलू ब्याज दरों में मजबूती आने के बावजूद, जनरेटिव-एआई की मांग को लेकर आशावाद के चलते जापानी शेयरों में शुरू में तेज़ी आई, जो उच्च वृद्धि और मुद्रास्फीति के साथ-साथ राजकोषीय अनुशासन को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाती है। हालांकि, तेल की बढ़ती कीमतों ने आर्थिक परिदृश्य को धूमिल कर दिया है, जिसके चलते इक्विटी में गिरावट आई है।

उभरते बाजारों के इक्विटी बेंचमार्क आमतौर पर अमेरिकी डॉलर की नरमी, विशिष्ट क्षेत्रों में पूंजी प्रवाह और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति बेहतर दृष्टिकोण से समर्थित रहे हैं (एशिया उभरते बाजार - विशेष रूप से कोरिया और ताइवान - को चिप और मेमोरी आपूर्ति श्रृंखला में उनकी भूमिका से लाभ हुआ है)। चीन के घरेलू स्तर पर विकसित एआई मॉडल ने क्षेत्र की एआई क्षमता पर बाजार का ध्यान बनाए रखा है, भले ही मार्च में व्यापार नीति की अनिश्चितता और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने जोखिम-विमुख भावना प्रारंभ हुई, जिससे 2026 की पहली तिमाही में इक्विटी में गिरावट आई।

उभरते बाजार एसएंडपी 500 की तुलना में अभी भी कम फॉरवर्ड पी/ई अनुपात में कारोबार कर रहे हैं जो कई अर्थव्यवस्थाओं में कम मुद्रास्फीति और सामान्यत: निभावकारी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों से समर्थित है। हालांकि, पश्चिम एशिया में तनाव, अनिश्चित टैरिफ परिदृश्य और मुद्रास्फीति के भविष्य के जोखिमों के कारण वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ, अवस्फीति की प्रक्रिया के

रुकने या उलट जाने का खतरा बढ़ रहा है, जिससे मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति दोनों के परिदृश्य जटिल हो सकते हैं। (चार्ट I.7बी)

प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी ऋण का स्तर उच्च बना हुआ है, जिससे बॉन्ड प्रतिफल पर ऊर्ध्वगामी दबाव बढ़ रहा है और केंद्रीय बैंकों के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना अनिवार्य हो गया है। अधिकतर मामलों में, यह लक्ष्य या तो काफी हद तक हासिल कर लिया गया है या पूरा होने के करीब है, हालांकि ऊर्जा कीमतों में हालिया उछाल से मुद्रास्फीति के लिए ऊर्ध्वगामी जोखिम का खतरा हो गया है। अमेरिका में, अक्टूबर 2025 में शटडाउन के दौरान सुरक्षित निवेश की मांग के कारण प्रतिफल में थोड़ी नरमी आई। हालांकि, फेडरल रिजर्व के सख्त रुख, निश्चल मुद्रास्फीति प्रिंट और जापान में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के कारण प्रतिफल में जल्द ही वृद्धि हो गई। प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी बॉन्ड प्रतिफल 2025 की चौथी तिमाही में काफी हद तक सीमित दायरे में कारोबार करती रही, जो लगातार राजकोषीय दबाव और सतर्क मौद्रिक नीति के रुख को दर्शाती है।

2026 की पहली तिमाही में, तकनीकी शेयरों की बिकवाली के बाद रोटेशन के जोखिमों, बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों और अमेरिका के 2025 की चौथी तिमाही के कमजोर जीडीपी आंकड़ों के कारण फरवरी तक बॉन्ड प्रतिफल में आम तौर पर गिरावट देखी गई। जापान में स्पष्ट नीतिगत संकेतों, कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में कमी और भू-राजनीतिक तनावों तथा प्रौद्योगिकी मूल्यों के अत्यधिक मूल्यांकन को लेकर चिंताओं के कारण सुरक्षित निवेश की मांग से बाजारों को कुछ राहत मिली। हालांकि, मार्च में, पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद मुद्रास्फीति की नई चिंताओं के कारण प्रतिफल में आंशिक रूप से बदलाव आया और इसमें थोड़ी वृद्धि हुई, जिससे निवेशकों को वैश्विक ब्याज दरों और टर्म प्रीमियम के रुख का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया गया। बैंक ऑफ जापान की नीति के सामान्यीकरण, निरंतर मुद्रास्फीति और नई सरकार के तहत विस्तारवादी राजकोषीय नीति की प्रत्याशाओं के चलते जापानी सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि हुई। मार्च में, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण बॉन्ड प्रतिफल में मजबूती आई(चार्ट I.8ए)।

2025 की चौथी तिमाही और 2026 की पहली तिमाही के अधिकांश समय में उभरते बाजारों के बॉन्ड प्रतिफल में उतार-चढ़ाव देखा गया: जहां घरेलू मुद्रास्फीति में कमी और कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आसान नीति की प्रत्याशाओं ने कई बाजारों में कैरी को समर्थन दिया, वहीं अन्य जगहों पर प्रतिफल में वृद्धि हुई क्योंकि निवेशकों ने मुद्रास्फीति के जोखिमों, ब्याज दरों में कटौती की संभावित गति और पश्चिम एशिया संघर्ष के राजकोषीय और जोखिम प्रीमियम पर पड़ने वाले प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन किया। मार्च में, ऊर्जा-प्रेरित मुद्रास्फीति के नए सिरे से आशंका के बीच कई अर्थव्यवस्थाओं में प्रतिफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। (चार्ट I.8बी)।

चार्ट I.8: 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल

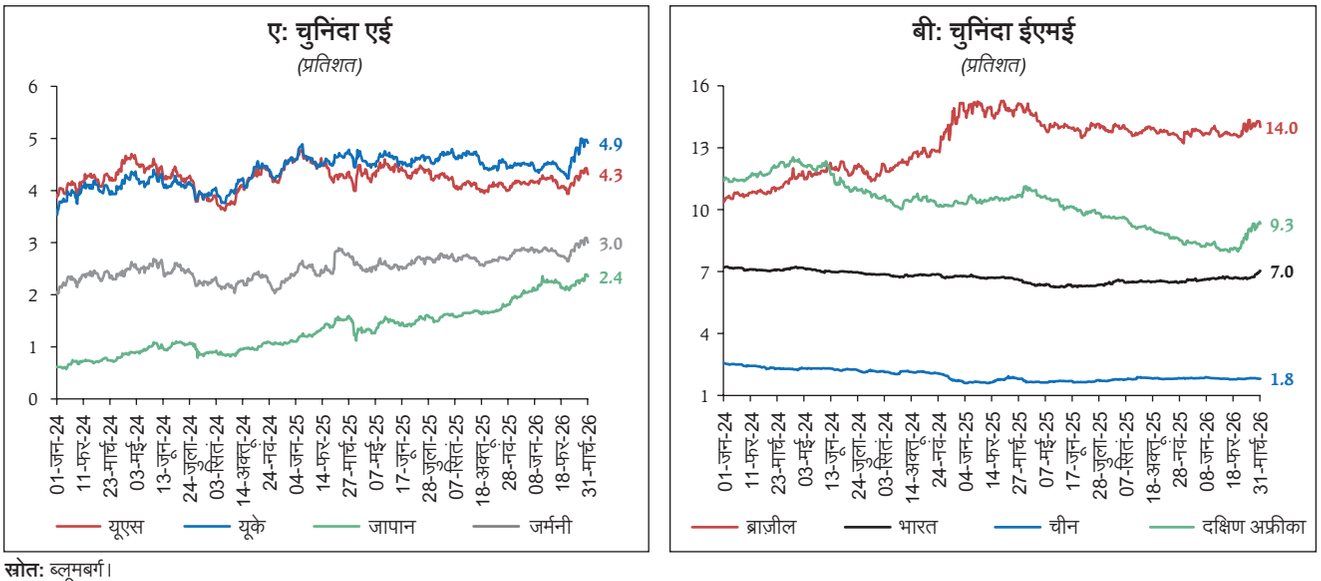

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

2025 में मुद्रा बाजार अशांत रहे, खासकर अमेरिकी डॉलर, जोखिम भावना और नीतिगत अपेक्षाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहते हुए कमजोर बना रहा; हालांकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में निवेशकों के उत्साह और परिणामस्वरूप अमेरिकी शेयरों में पूंजी प्रवाह ने डॉलर को कुछ हद तक सहारा दिया। 2025 में प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर 9.0 प्रतिशत से अधिक गिर गया, क्योंकि फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की आशंकाओं ने प्रतिफल अंतर को कम कर दिया, जबकि अमेरिकी राजकोषीय घाटे और राजनीतिक अनिश्चितता को लेकर चिंताएं बढ़ गई। 2025 की चौथी तिमाही में अमेरिकी डॉलर में व्यापक रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ जिससे फेड के कड़े रुख, मजबूत तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों के जारी होने और सुरक्षित निवेश की मांग के चलते इसमें बीच-बीच में तेजी देखी गई। इसके बाद, कमजोर आंकड़ों और बिगड़ते बाजार के माहौल के कारण इसमें गिरावट का रुझान रहा, हालांकि पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान सुरक्षित निवेश की मांग से इसे कुछ हद तक समर्थन मिला। कुल मिलाकर, 2026 की पहली तिमाही के अधिकांश समय तक सुस्त रहने के बाद, सुरक्षित निवेश की मांग और अभी भी उच्च मुद्रास्फीति के चलते तिमाही के अंत में डॉलर में मजबूती आई। जी7 मुद्राओं में उच्च विदेशी मुद्रा अस्थिरता अक्सर कमजोर अमेरिकी डॉलर के साथ मेल खाती थी, लेकिन मार्च में यह नकारात्मक सहसंबंध कम हो गया क्योंकि सुरक्षित निवेश प्रवाह और फेड की अपेक्षाओं के आक्रामक पुनर्मूल्यांकन ने हाल ही में कई सकारात्मक रीडिंग उत्पन्न की हैं, जिसमें अस्थिरता में उछाल अक्सर मजबूत डॉलर के साथ होता है (चार्ट I.9)। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट करेंसी इंडेक्स ने 2025 की चौथी तिमाही में बढ़त दर्ज की, लेकिन 2026 की पहली तिमाही में इसमें गिरावट आई, क्योंकि मार्च में पश्चिम एशिया संघर्ष ने अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के बीच मुद्रा पर नए सिरे से दबाव और पोर्टफोलियो बहिर्गमन हुआ। हालांकि एआई से संबंधित आशावाद और विस्तारवादी राजकोषीय नीतियां एक सहायक पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं, लेकिन टैरिफ अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और फेड की बदलती नीतिगत अपेक्षाओं से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के कारण पूंजी प्रवाह अस्थिर बना हुआ है। (चार्ट I.10 ए और बी)

चार्ट I.9: यूएसडी बनाम जी7 मुद्राओं में अस्थिरता

(सूचकांक (अंत-2023=100), बायां मान; मूल्य, दायां मान)

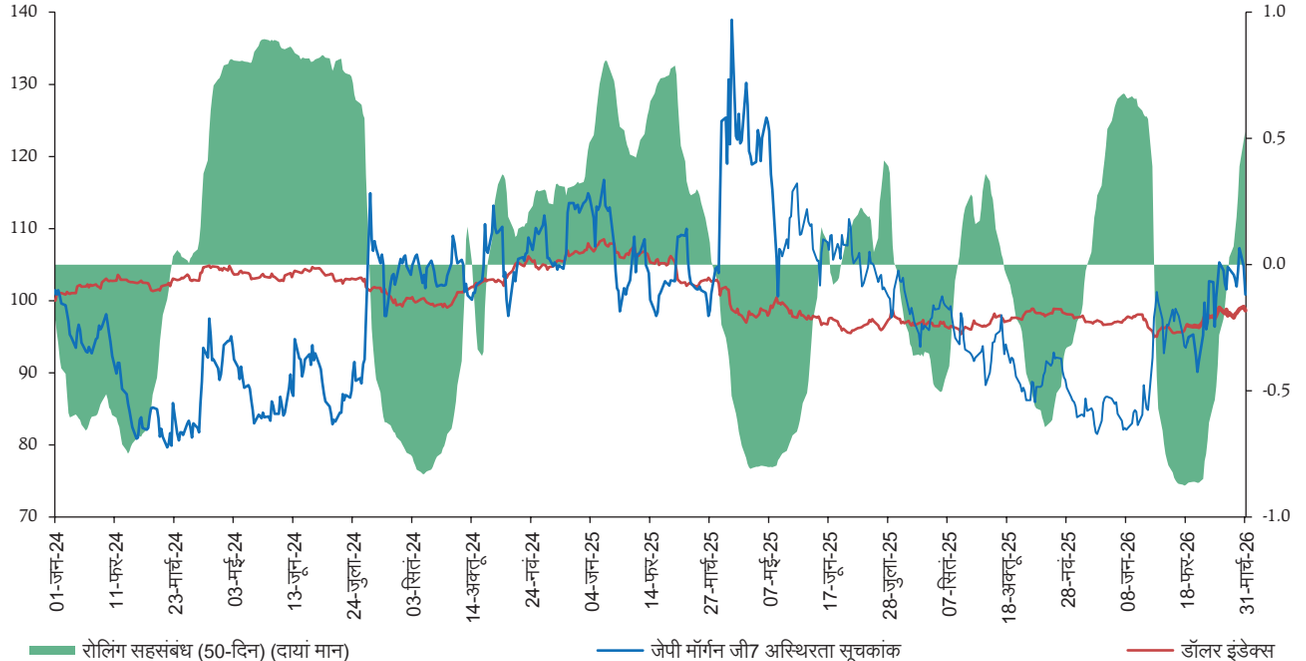

टिप्पणी: जेपी मॉर्गन जी7 अस्थिरता सूचकांक: यह एक विकल्प-आधारित माप है जो मुख्य अमेरिकी डॉलर के मुद्रा युग्मों की ईयूआर, जेपीवाई, जीबीपी, सीएचएफ, सीएडी, एयूडी और एनजेडडी के मुकाबले निहित अस्थिरता को मापती है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट I.10: मुद्रा उतार-चढ़ाव और पूंजी प्रवाह

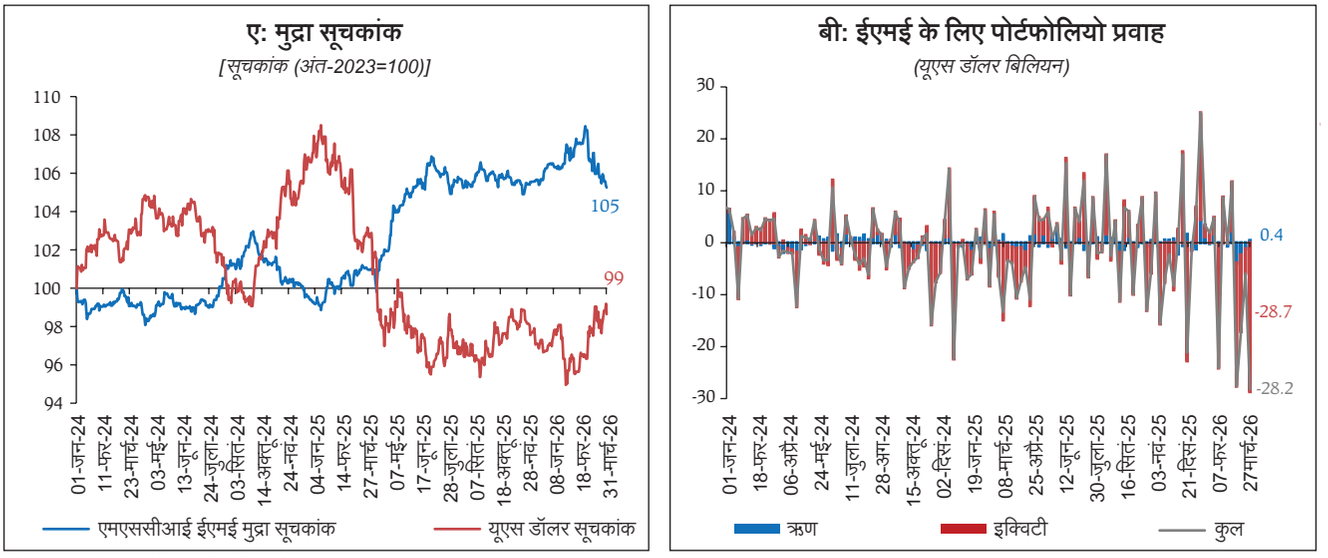

स्रोत: ब्लूमबर्ग तथा अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान।

I.5 निष्कर्ष

बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, निरंतर व्यापारिक टकराव, बढ़ते सरकारी कर्ज़ और एआई-प्रेरित इक्विटी मूल्यांकन में अस्थिरता के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक विकास सुदृढ़ रहा है, लेकिन अपने ऐतिहासिक औसत से नीचे बना हुआ है, जबकि अवस्फीति असमान है और ऊर्जा की कीमतों में हालिया वृद्धि से इसमें उलटफेर हो सकता है। कुल मिलाकर, 2026 के लिए यह परिदृश्य मामूली विस्तार का संकेत देता है और यह भू-राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव और ऊर्जा-प्रेरित मुद्रास्फीति के जोखिमों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है। परस्पर विरोधी उद्देश्यों को संतुलित करने के लिए समायोजन की लागत को कम करते हुए मौद्रिक नीति पथ के संबंध में नपे-तुले कदम उठाने की आवश्यकता होगी।

II. चलनिधि स्थितियां और वित्तीय बाजार

रिज़र्व बैंक के चलनिधि बढ़ाने के उपायों द्वारा समर्थित होने के कारण दूसरी छमाही में प्रणाली में चलनिधि अधिशेष में रही। मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता के बीच घरेलू वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के दौर दिखाई दिए। ओवरनाइट दरें मुद्रा बाजार में नीतिगत दर और विद्यमान चलनिधि स्थितियों के अनुरूप विकसित हुईं। दूसरी छमाही में उधार और जमा दरों पर इसका संचरण जारी रहा। क्षेत्रीय रुझान खंडों में ऋण वृद्धि के मजबूत होने का संकेत देते हैं।

परिचय

2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान, वैश्विक वित्तीय बाजार आम तौर पर स्थिर रहे, लेकिन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़े भू-राजनीतिक तनाव के बीच अस्थिर हो गए। वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिर पूंजी प्रवाह के बीच घरेलू वित्तीय बाजारों में रुक-रुक कर अस्थिरता देखने को मिली। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने दूसरी छमाही के दौरान नीतिगत दर में 25 आधार अंक (बीपीएस) की कमी की, जिससे फरवरी 2025 से अब तक कुल 125 आधार अंक की कमी हो गई है। दूसरी छमाही के आरंभ में प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष में आई कमी को टिकाऊ चलनिधि के सुनियोजित इंजेक्शनों के माध्यम से उलट दिया गया। ओवरनाइट मुद्रा बाजार दरें काफी हद तक बदलती चलनिधि स्थितियों के अनुरूप रहीं। दूसरी छमाही के दौरान उधार और जमा दरों में अच्छे अंतरण से मौद्रिक नीति संचरण को बल मिला। बैंक ऋण वृद्धि में सुधार जारी रहा और इससे वास्तविक आर्थिक गतिविधि को समर्थन मिला। बैंकिंग से इतर स्रोतों से वित्तपोषण में भी वृद्धि हुई।

II.1 चलनिधि स्थितियां और मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से यह अपेक्षित है कि वह मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन से संबंधित परिचालन प्रक्रिया और उसमें समय-समय पर परिवर्तनों, यदि कोई हो, को सार्वजनिक डोमेन में रखे।[1]

वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान, एमपीसी ने दिसंबर की बैठक में पॉलिसी रेपो दर में 25 आधार अंक की कमी की। इसके अलावा, एमपीसी ने जून 2025 में अपनाए गए तटस्थ नीति रुख को बनाए रखने का निर्णय लिया। रिज़र्व बैंक ने सितंबर-नवंबर 2025[2] के दौरान नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 100 बीपीएस घटाकर निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) का 3.0 प्रतिशत कर दिया। दूसरी छमाही में सीआरआर कटौतियों ने प्रणाली चलनिधि को सहारा दिया। सीआरआर रखरखाव चक्र में बदलाव के साथ बैंकों के लिए रिपोर्टिंग पखवाड़े की परिभाषा 15 दिसंबर 2025 से बदल दी गई । नई परिभाषा के अनुसार, एक रिपोर्टिंग चक्र को प्रत्येक कैलेंडर महीने के पहले दिन से पंद्रहवें दिन तक की अवधि और प्रत्येक सोलहवें दिन से कैलेंडर महीने के अंतिम दिन तक, दोनों दिन को शामिल करते हुए, परिभाषित किया गया है। रिपोर्टिंग चक्र में परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि रिज़र्व रखरखाव अवधि के भीतर रिज़र्व की मांग के संबंधित प्रभाव के साथ महीने के पहले रिपोर्टिंग चक्र (15 दिन) में दिनों की संख्या दूसरे रिपोर्टिंग चक्र (जो 13-16 दिनों का हो सकता है) से भिन्न हो सकती है। इसके अलावा, पिछली प्रणाली के 26-27 रिर्पोटिंग पखवाड़ों की तुलना में एक वर्ष में रिपोर्टिंग चक्रों की संख्या अब मानकीकृत होकर 24 हो गई है।

---

[1] संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचा 30 सितंबर 2025 से प्रचलन में है। इस ढांचे की प्रमुख विशेषताएं अक्टूबर 2025 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में दी गई हैं।

[2] यह कटौती 25 बीपीएस की चार बराबर भागों में लागू की गई थी, जो 6 सितंबर, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर 2025 से शुरू होने वाले पखवाड़े के हिसाब से प्रभावी थी।

चालक और चलनिधि का प्रबंधन

प्रणाली चलनिधि, जिसे चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत निवल शेष राशि द्वारा मापा जाता है, वर्ष की पहली छमाही में बड़े अधिशेष से वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में कमी आई (चार्ट II.1)। निवल आधार पर, एलएएफ के तहत औसत दैनिक अवशोषण पहली छमाही में ₹2.29 लाख करोड़ की तुलना में दूसरी छमाही में घटकर ₹1.43 लाख करोड़ हो गया। दूसरी छमाही में चलनिधि स्थितियों के प्रमुख चालक संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में विस्तार और अस्थिर पूंजी प्रवाह थे।

वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान प्रणाली चलनिधि अधिशेष में रही, कुछ छिट-पुट अवसरों को छोड़कर जब कर भुगतान ने बैंकिंग प्रणाली से चलनिधि की निकासी की थी। तीसरी तिमाही में प्रणाली चलनिधि में कमी आई, जो त्योहारी सीजन के दौरान संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि और रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालन को दर्शाती है। इसकी आंशिक भरपाई सीआरआर में कमी और रिज़र्व बैंक द्वारा खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीद से हुई। चौथी तिमाही में चलनिधि की स्थिति में सुधार

चार्ट II.1: चलनिधि परिचालन

(₹ लाख करोड में)

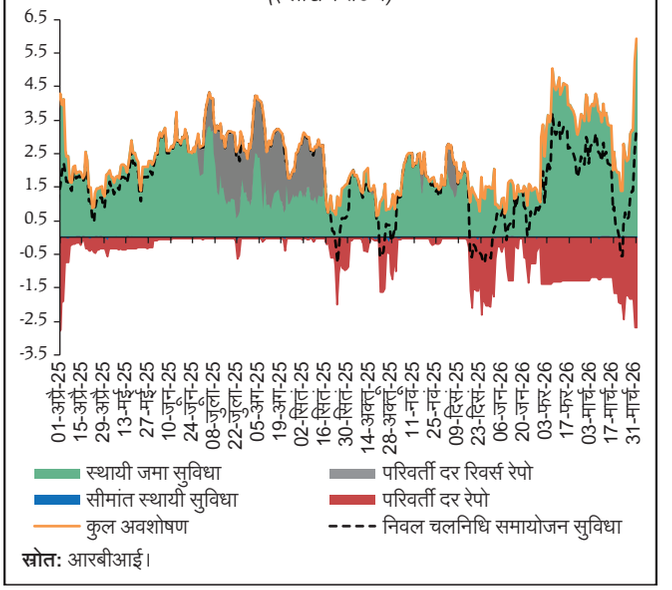

स्रोत: आरबीआई।

हुआ जब ओएमओ खरीद, दीर्घकालिक यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी और टर्म रेपो नीलामियों के माध्यम से डाली गई चलनिधि द्वारा सीआईसी में तीव्र वृद्धि की भरपाई अपेक्षा से अधिक हो गई (सारणी II.1)।

सारणी II.1: चलनिधि – प्रमुख चालक और प्रबंधन

(₹ करोड़)

	2024-25		2025-26			
	छ1	छ2	छ1	ति3	ति4*	छ2*
चालक						
(i) सीआईसी [निकासी (-) / प्रतिफल (+)]	29,247	-2,42,234	-74,052	-1,25,023	-2,08,489	-3,33,512
(ii) निवल विदेशी मुद्रा खरीद (+) / बिक्री (-)	70,402	-3,61,635	-1,41,591	-3,28,665	14,632	-3,14,033
(iii) भारत सरकार के नकद शेष [बिल्ड-अप (-) / ड्रॉडाउन (+)]	-2,04,802	2,98,531	-3,44,103	74,298	26,974	1,01,272
(iv) अतिरिक्त रिजर्व [बिल्ड-अप (-) / ड्रॉडाउन (+)]	-15,839	16,655	14,376	17,884	-6,663	11,221
प्रबंधन						
(i) निवल ओएमओ खरीद (+) / बिक्री (-)	-24,040	2,83,386	2,39,223	1,81,435	4,06,900	5,88,335
(ii) अपेक्षित रिज़र्व [एनडीटीएलऔर सीआरआर दोनों में परिवर्तन सहित]	-55,613	76,450	15,674	1,67,530	-17,776	1,49,754
(iii) आवधिक रेपो नीलामी	-	1,82,964	25,731	-	1,36,504	1,62,235
मेमो आइटम						
(i) दीर्घकालिक फ़ॉरेक्स स्वैप खरीद / बिक्री (+) / खरीद/बिक्री (-)	-	2,19,245	-	46,147	1,80,738	2,26,885
(ii) समाप्त अवधि के अनुसार निवल अवशोषण (+) / इंजेक्शन (-)	84,651	1,30,261	56,274	28,123	2,15,148	2,15,148

टिप्पणियाँ: 1. (+) / (-) चिह्न बैंकिंग प्रणाली चलनिधि में वृद्धि/कमी को दर्शाता है।
2. डेटा संबंधित अवधि के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
3. *: ति4 और छ2:2025-26 के लिए डेटा 15 मार्च 2025 तक है।
4. ^: निकटतम मूल्य।

स्रोत: आरबीआई।

[3] दूसरी छमाही में, एलएएफ के तहत शेष राशि के आधार पर मापी गई प्रणाली चलनिधि, जीएसटी से संबंधित बहिर्वाह के कारण 20 से 22 अक्टूबर के दौरान घाटे में चली गई। इसके अलावा, 16 से 29 दिसंबर, और 20 और 21 मार्च के दौरान अग्रिम कर और जीएसटी से संबंधित बहिर्वाह के संयोजन से प्रणाली चलनिधि घाटे की ओर चली गई।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

चलनिधि की स्थिति अधिशेष में रहने के कारण, वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान बैंकों द्वारा ली जा रही सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का सहारा औसतन ₹0.02 लाख करोड़ रहा जैसा कि पहली छमाही में है, वहीं, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के अंतर्गत दैनिक शेष राशि पहली छमाही में औसतन ₹1.84 लाख करोड़ से बढ़कर दूसरी छमाही में ₹2.20 लाख करोड़ हो गई। रिज़र्व बैंक ने अपने चलनिधि प्रबंधन में तेजी और सजगता से कार्य किया एवं मुद्रा बाजार में संचरण देने के लिए बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित की (बॉक्स II.1)। चलनिधि की स्थिति और परिदृश्य की संभावनाओं की समीक्षा के आधार पर, रिजर्व बैंक ने 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ चलनिधि डालने के लिए ओएमओ खरीद, खरीद/बिक्री फॉरेक्स स्वैप और दीर्घावधि के रेपो सहित कई उपाय किए (सारणी II.2)।

सारणी II.2: 2025-26 के दौरान रिज़र्व बैंक के चलनिधि उपाय

(₹ करोड़)

उपाय	छ 1:2025-26	छ 2:2025-26	वि वर्ष:2025-26
सीआरआर कटौती	62,500*	1,87,500*	2,50,000*
ओएमओ खरीद नीलामी	2,39,203	5,00,000	7,39,203
यूएसडी / आईएनआर खरीद / बिक्री स्वैप नीलामी		2,26,885*	2,26,885*
टर्म रेपो नीलामी	25,731	1,36,504	1,62,235
कुल	**3,27,434**	**10,50,889**	**13,78,323**

टिप्पणी: * अनुमानित मान दर्शाता है।
स्रोत: आरबीआई।

बॉक्स II.1: चलनिधि का इष्टतम स्तर

केंद्रीय बैंक बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि की स्थिति का सक्रिय रूप से प्रबंधन करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिचालन लक्ष्य नीतिगत दर के अनुरूप ब्याज दर कॉरिडोर के भीतर बना रहे। रिज़र्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन का मार्गदर्शी सिद्धांत, जैसा कि सितंबर 2025 के संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे में दोहराया गया है, भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) को नीतिगत रेपो दर के साथ संरेखित करना है। चलनिधि असंगति के कारण नीतिगत दर से परिचालन लक्ष्य का विचलन होता है, जिससे मौद्रिक नीति संचरण में बाधा आती है (कावेडिया और पटनायक, 2016)।

लंबी अवधि में अत्यधिक चलनिधि अधिशेष से अल्पकालिक ब्याज दर के अति-निम्न स्तर तक जाने, जोखिम धारणाओं में गडबड़ी होने और आस्ति मूल्य बुलबुले बनने का जोखिम होता है। इसके अलावा, लगातार बड़े अधिशेष चलनिधि वाली बाजार सहभागियों के व्यवहार में एक बड़ा बदलाव लाती है, जिससे वे बड़ी चलनिधि के अभ्यस्त हो जाते हैं। इसके विपरीत, बैंकिंग प्रणाली में बड़ा घाटा (कमी) बैंकों के लिए उधार लेने की लागत को बढ़ाता है, जो ऋण देने की गतिविधि को प्रतिबंधित, मौद्रिक संचरण को बाधित, और संभावित रूप से वित्तीय स्थिरता को कमजोर कर सकता है। इसलिए, मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप प्रणाली चलनिधि के इष्टतम स्तर का आकलन करना आवश्यक हो जाता है। इस पृष्ठभूमि में, बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि के पर्याप्त स्तर का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है जो रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन के मार्गदर्शी सिद्धांत, स्प्रेड (पॉलिसी रेपो दर पर भारित औसत कॉल दर) और चलनिधि स्थितियों (*एलआईक्यू*) - निवल एलएएफ के बीच संबंध के अनुरूप है।

अधिशेष और घाटे के दौर (आरबीआई, 2021) में संचरण में सुपरिचित विषमता को ध्यान में रखते हुए, जनवरी 2012 से मार्च 2026 की अवधि के दैनिक आंकड़ों के आधार पर अधिशेष और घाटे की चलनिधिवाले चरणों के लिए दो अलग-अलग अनुमान लिए गए हैं। चूंकि एक विशेष चलनिधि चरण के भीतर चलनिधि के प्रभाव की सीमा प्रारंभिक स्थितियों के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकती है, इसलिए इस विषम प्रभाव का अनुमान एक गैर-रैखिक प्रकार्य को फिट करके लगाया गया है।[4] तदनुसार,फ्रेक्शनल पोलिनोमियल मॉडल को अधिशेष और घाटे की चलनिधि स्थितियों के लिए अलग-अलग स्टैंडर्ड एट-एलिमेंट पावर्स का उपयोग करके फिट किया गया है। प्रत्येक शासन के लिए सबसे उपयुक्त मॉडल का चयन रॉयस्टन-सॉयरब्रेई बंद परीक्षण प्रक्रिया (रॉयस्टन-सॉयरब्रेई 2006) का उपयोग करके किया गया है, जो संभावना अनुपात परीक्षणों के आधार पर होता है। फिट किए गए वक्र निम्नलिखित हैं।

(जारी...)

[4] प्रथम घात का भिन्नात्मक बहुपद (FP1) $\beta_0 + \beta_1 x^p$ के रूप में होता है, जहाँ $p \in \wp$ है, और द्वितीय घात का भिन्नात्मक बहुपद (FP2) $\beta_0 + \beta_1 x^{p1} + \beta_2 x^{p2}$ के रूप में होता है, जहाँ $p_1 \leq p_2, p_i \in \wp$ है; और जहाँ $p_1 = p_2 = p$ है, वहाँ पुनरावृत्त घात FP2 बहुपद $\beta_0 + \beta_1 x^p + \beta_2 x^p \log(x)$ बन जाता है। यहाँ $\wp$={-2,-1,-0.5,0,0.5,1,2,3} और $p = 0$ का अर्थ $\log(x)$ है। अनुमान से प्रत्येक चलनिधि चरण के लिए 44 संभावित गैर-रैखिक विनिर्देश प्राप्त होते हैं।

$Spread = 0.58-0.5*\log(Liq+3.3)$; *for* $Liq < 0$ *(Deficit phase)*

$Spread = -0.03-0.07\ Liq^2 + 0.01\ Liq^3$; *for* $Liq > 0$ (*Surplus phase*)

तदनुसार, अधिशेष और घाटे की चलनिधि अवधि के लिए सबसे उपयुक्त वक्र चार्ट II.1.1 में दिया गया हैं।

संबंध से पता चलता है कि चलनिधि में वृद्धि स्प्रेड से व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंधित है; इसके अलावा, संबंध गैर-रैखिक पाया गया है। स्प्रेड पर अतिरिक्त चलनिधि का प्रभाव एक बिंदु के बाद काफी कम हो जाता है। अतिरिक्त चलनिधि बढ़ने पर वक्र सपाट हो जाता है, जो दर्शाता है कि बड़ी अतिरिक्त चलनिधि का स्प्रेड पर एक सीमा से परे कोई महत्वपूर्ण वृद्धिशील प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि, घाटे के चरण के अंतर्गत, उच्च घाटे के स्तर पर असीमित हो जाता है।

निष्कर्षों से पता चलता है कि एनडीटीएल के 0.6 से 1.1 प्रतिशत के दायरे में अधिशेष चलनिधि द्वारा स्प्रेड के रेपो दर से 5 से 10 बीपीएस नीचे रहने की संभावना है, जबकि एनडीटीएल के 0.4 से 0.7 प्रतिशत के दायरे में चलनिधि की कमी से डब्ल्यूएसीआर के रेपो दर से 5 से 10 बीपीएस ऊपर रहने की संभावना है। जैसा कि निष्कर्षों से स्पष्ट है, डब्ल्यूएसीआर को रेपो दर के अनुरूप रखने में घाटे और अधिशेष स्थितियों में चलनिधि के विभिन्न स्तर शामिल होते हैं। इसके अलावा, संरेखण की सीमा अधिशेष/घाटे के स्तर पर भी निर्भर करती है।

चार्ट II.1.1: स्प्रेड और चलनिधि स्थितियों के बीच संबंध

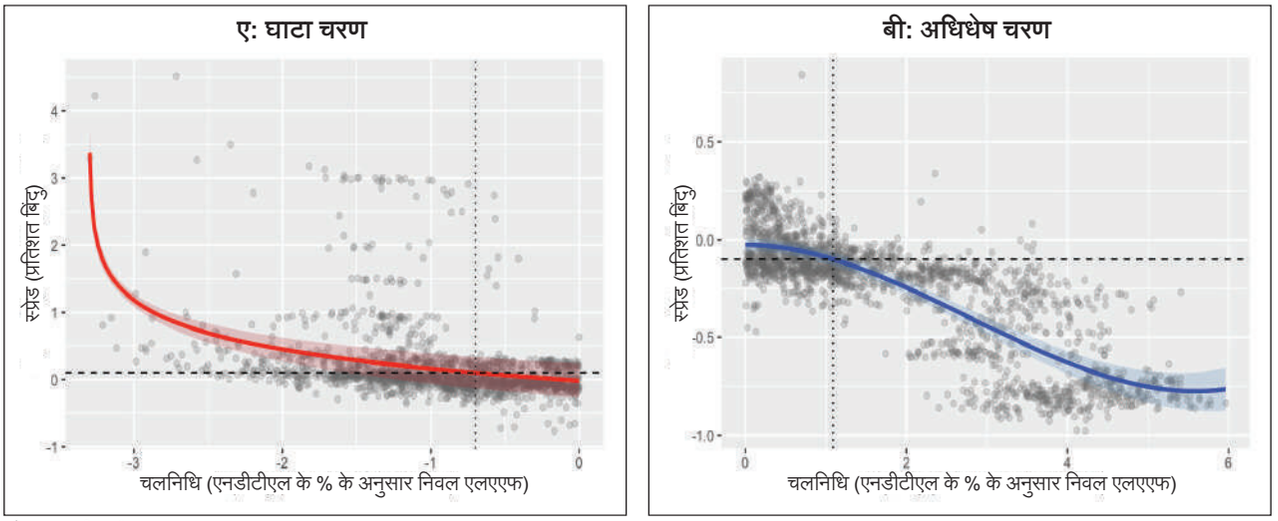

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

संदर्भ:

1. कावेडिया, आर. एंड पटनायक, एस. (2016), "ऑपरेटिंग टारगेट वोलेटिलिटी: इट्स इम्प्लीकेशन्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन", रिज़र्व बैंक ऑफ इडिया ओकेशनल पेपर्स वॉल्यूम 37, नंबर 1 और 2, 2016.
2. रिजर्व बैंक ऑफ इडिया, (2021), " मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट "।
3. रॉयस्टन, पी. और सॉरब्रेई, डब्ल्यू. (2008)। मल्टीवेरिएबल मॉडल-बिल्डिंग: ए प्रेक्टिकल अप्रोच टू रिग्रेशन एनालिसिस बेस्ट आन फ्रेक्शनल पोलीनामिनल्स फार मॉडलिंग कन्टिन्यूयस वेरियेबल्स। जॉन विले एंड संस, होबोकेन।

रिजर्व बैंक ने अस्थाई चलनिधि को नियंत्रित करने और ओवरनाइट खंडों में दरों को नीतिगत दर के अनुरूप लाने के लिए विभिन्न परिपक्वता अवधियों के कई परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) और परिवर्ती दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) संचालित किए। कुल मिलाकर, 2025 की दूसरी छमाही में 44 वीआरआर और 7 वीआरआरआर नीलामी आयोजित की गईं।

15 मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार, आरक्षित मुद्रा (एम0) में एक वर्ष पहले के 3.7 प्रतिशत की तुलना में

मौद्रिक नीति वक्तव्य

5.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में विस्तार को दर्शाती है। सीआरआर में बदलाव को समायोजित करने पर आरक्षित मुद्रा में वृद्धि 10.7 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 6.2 प्रतिशत) रही। 15 मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार, मुद्रा आपूर्ति (एम3) में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) एक वर्ष पहले के 9.4 प्रतिशत से बढ़कर 10.7 प्रतिशत हो गई, जो मुद्रा में तेजी से वृद्धि और जनता के पास मुद्रा को दर्शाती है। बढ़ते मुद्रा-जमा अनुपात के बावजूद, सीआरआर कटौती की सहायता से, मुद्रा गुणक 15 मार्च 2026 को बढ़कर 5.99 हो गया, जो एक वर्ष पहले 5.72 था।

II.2 घरेलू वित्तीय बाजार

मुद्रा बाजार की दरें प्रणाली चलनिधि और मौद्रिक नीति कार्रवाईयों के अनुरूप विकसित हुई। घरेलू और वैश्विक कारकों ने दीर्घकालिक सरकारी बॉन्ड के प्रतिफल को उच्चतर किया। अस्थिर पूंजी प्रवाह और विकसित वैश्विक जोखिम धारणाओं के बीच इक्विटी बाजारों और भारतीय रुपये ने दोतरफा उतार-चढ़ाव प्रदर्शित किए। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण मार्च में शेयर बाजारों और भारतीय रुपये दोनों पर दबाव और बढ़ गया। ऋण बाजार में, बैंक ऋण स्वस्थ गति से बढ़ा।

II.2.1 मुद्रा बाजार

2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान, मुद्रा बाजार दरें नीतिगत रेपो दर और बदलती चलनिधि स्थितियों के साथ चलती रहीं। भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - दिसंबर 2025 के पहली छमाही तक नीति रेपो दर से काफी हद तक नीचे रही। इसके पश्चात, दिसंबर और जनवरी के उत्तरार्ध में, चलनिधि अधिशेष में कमी के बीच डब्ल्यूएसीआर नीतिगत रेपो दर से ऊपर कारोबार करता रहा (चार्ट II.2ए)। रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि बढ़ाने के कई उपायों के चलते डब्ल्यूएसीआर में बाद में नरमी आई।

वर्ष 2025-26 दूसरी छमाही के दौरान डब्ल्यूएसीआर नीतिगत रेट कॉरिडोर के भीतर रही, जब इसका स्प्रेड नीतिगत रेपो दर पर अक्टूबर 2025 में (-)2 आधार अंक (बीपीएस) से बढ़कर मार्च 2026 में (+)4 बीपीएस हो गया (चार्ट II.2ए)। एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज (ईडब्ल्यूएमए)[5] द्वारा मापा जाने वाले डब्ल्यूएसीआर में अस्थिरता, फरवरी और मार्च 2026 में नरम पड़ने से पहले दिसंबर 2025 (चार्ट II.2बी) में बढ़ गई थी। दूसरी छमाही में संपार्श्विक खंड अर्थात, त्रिपक्षीय रेपो

चार्ट II.2: नीतिगत कॉरिडोर और डब्ल्यूएसीआर

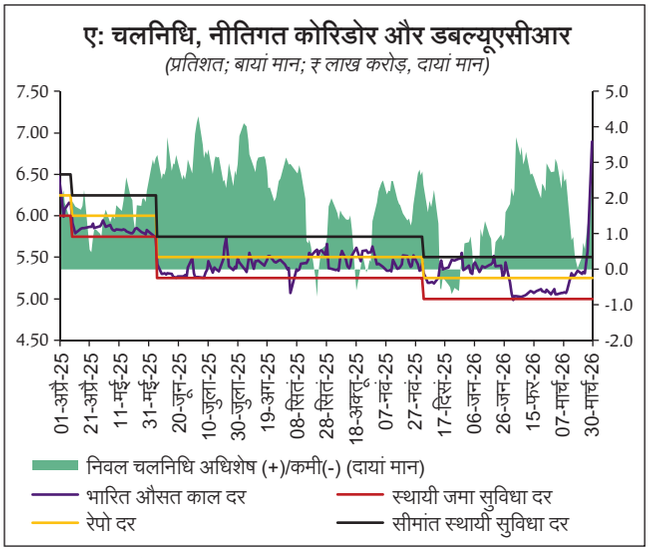

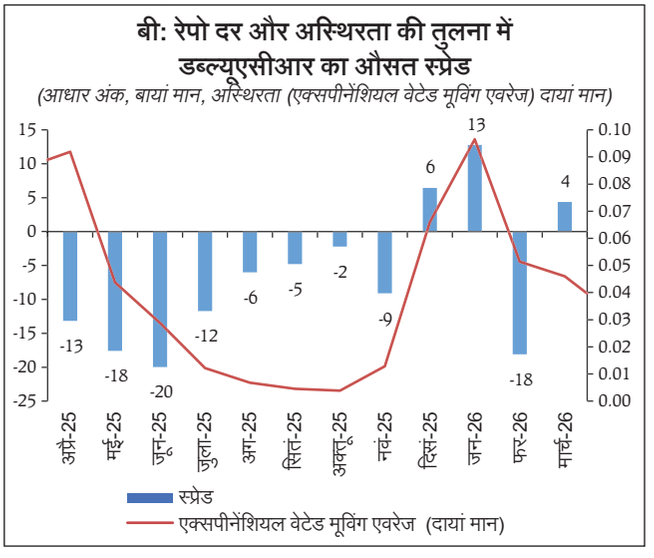

स्रोत: आरबीआई और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[5] ईडब्ल्यूएमए सरल भिन्नता की तुलना में बेहतर है क्योंकि यह हाल के अवलोकन को अधिक महत्व देता है। ईडब्ल्यूएमए अस्थिरता को पूर्व की अस्थिरता के भारित औसत के रूप में व्यक्त करता है, जिसमें हाल के अवलोकनो को अधिक महत्व दिया जाता है।

चार्ट II.3: मुद्रा बाजार दरें और नीतिगत कॉरिडोर

(प्रतिशत)

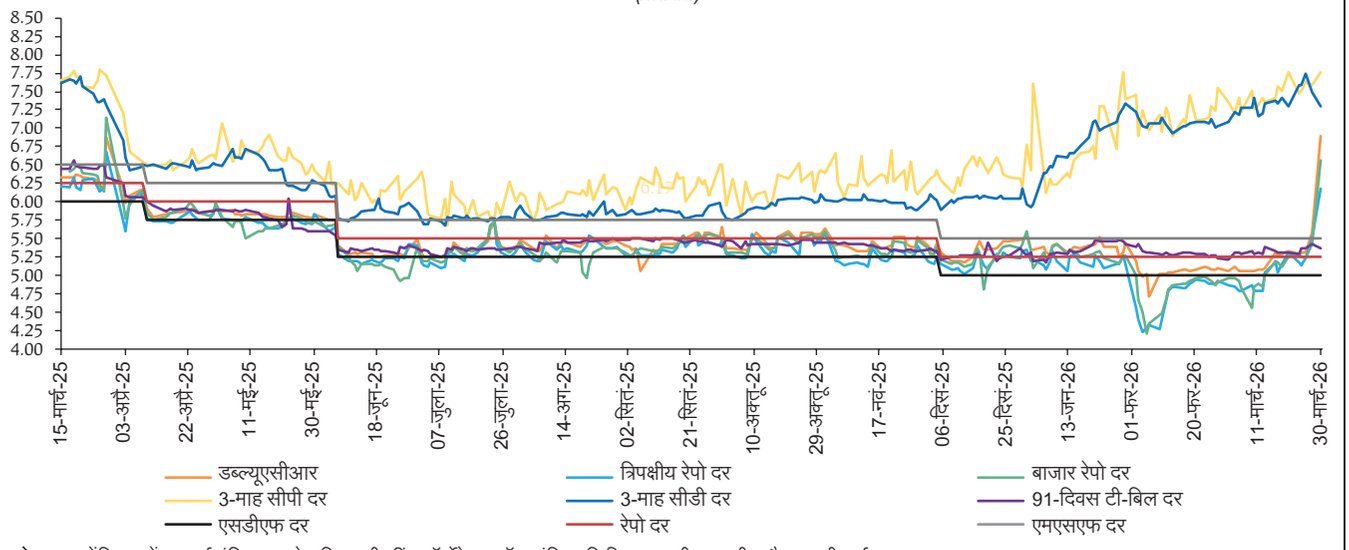

स्रोत: फ़ाइनेंसियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लि. क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि. - एफ-टीआरएसी और आरबीआई

और मार्केट रेपो में ओवरनाईट दरें, मौटे तौर पर डब्ल्यूएसीआर के साथ संरेखित रही (चार्ट II.3)।

मुद्रा बाजार की गतिविधियों में संपार्श्विक खंडो (त्रिपक्षीय और बाजार रेपो) का वर्चस्व रहा, जिसमें ओवरनाइट मुद्रा बाजार की मात्रा में उनकी हिस्सेदारी 97 प्रतिशत रही। असंपार्श्विकृत खंड का हिस्सा, अर्थात कॉल मनी मार्केट, लगभग 3 प्रतिशत पर काफी हद तक सपाट रहा (सारणी II.3)।

म्यूचुअल फंड (एमएफ) त्रिपक्षीय रेपो में प्रमुख ऋणदाता बने रहे, बावजूद इसके कि उनका हिस्सा वर्ष 2025-26 की पहली छमाही से 3 प्रतिशत अंक घटकर की दूसरी छमाही में 65 प्रतिशत हो गया। हालांकि बाजार रेपो खंड में, दूसरी छमाही में म्यूचुअल फंडो द्वारा दिए गए उधार का हिस्सा बढ़कर 48 प्रतिशत हो गया, जो पहली छमाही में 40 प्रतिशत था। बाजार रेपो में विदेशी बैंकों द्वारा दिए गए उधार का हिस्सा दूसरी छमाही में 29 प्रतिशत पर स्थिर रहा। उधार लिए जाने के मामलों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) त्रिपक्षीय रेपो में प्रमुख खिलाड़ी बने रहे, जिनकी हिस्सेदारी पहली छमाही के 28 प्रतिशत से बढ़कर दूसरी छमाही में 34 प्रतिशत हो गई, जबकि निजी बैंकों की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत से घटकर 24 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि में बाजार रेपो उधारी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत बढ़कर 8 प्रतिशत बिंदु हो गई।

सारणी II.3: ओवरनाइट मुद्रा बाजार में औसत मात्रा और हिस्सा

(₹ लाख करोड़)

	2024-25		2025-26			
	छ1	छ2	छ1	ति3	ति4	छ2
कॉल/नोटिस	0.10 (2.12)	0.11 (2.18)	0.16 (2.78)	0.16 (2.72)	0.15 (2.40)	0.16 (2.56)
त्रिपक्षीय रेपो	3.30 (68)	3.62 (70)	3.69 (66)	3.91 (66)	4.35 (70)	4.12 (68)
बाजार रेपो	1.48 (30)	1.42 (28)	1.73 (31)	1.87 (31)	1.69 (27)	1.78 (29)
कुल	**4.88** **(100)**	**5.16** **(100)**	**5.57** **(100)**	**5.94** **(100)**	**6.19** **(100)**	**6.06** **(100)**

टिप्पणियाँ: 1. कोष्टक में दिए गए आंकड़े ओवरनाइट मुद्रा बाजार के प्रत्येक खंड का हिस्सा दर्शाते है। पूर्णांकन के कारण आंकड़े कुल योग से भिन्न हो सकते हैं।
2. *: कार्यरत शनिवार तक का डेटा शामिल।

स्रोत: क्लेयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि. - एफ-टीआरएसी आरबीआई

मौद्रिक नीति वक्तव्य

सारणी II.4: सीडी निर्गमनों का अवधि वार ब्यौरा

(₹ लाख करोड़)

	2024-25		2025-26			
	छ1	छ2	छ1	ति3	ति4	छ2
91 दिवस	3.93 (73)	3.74 (57)	3.55 (73)	2.07 (62)	2.33 (44)	4.40 (51)
92-180 दिवस	0.20 (4)	0.17 (3)	0.47 (10)	0.38 (11)	0.23 (4)	0.61 (7)
181-365 दिवस	1.22 (23)	2.64 (40)	0.84 (17)	0.88 (27)	2.71 (51)	3.58 (42)
कुल	**5.35** **(100)**	**6.56** **(100)**	**4.86** **(100)**	**3.32** **(100)**	**5.27** **(100)**	**8.59** **(100)**

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक परिपक्वता खंड का हिस्सा दर्शाते है। पूर्णांकन के कारण आंकड़े कुलयोग से भिन्न हो सकते हैं।
स्रोत: क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि. . - एफ-टीआरएसी, और आरबीआई स्टाफ अनुमान

मुद्रा बाजार के अवधि खंड में ओवरनाइट मार्केट की तुलना में धीमा संचरण देखा गया, जिसका मुख्य कारण रह-रहकर चलनिधि कसाव और नीतिगत अनिश्चितता में वृद्धि थी। चौथी तिमाही में जमा प्रमाणपत्रों पर ब्याज दरें विशेष रूप से बढ़ीं, क्योंकि बैंकों ने वर्ष के अंत में वित्तपोषण की कमी को पूरा करने के लिए परिपक्व हो रहे प्रमाणपत्रों के रोलओवर और उच्च ऋण-जमा अनुपात के बीच प्रमाणपत्र जारी करना बढ़ा दिया। वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में पॉलिसी रेपो दर के ऊपर सीडी और सीपी का औसत स्प्रेड क्रमशः 116 बीपीएस और 136 बीपीएस तक बढ़ गया, जो पहली छमाही में क्रमशः 36 बीपीएस और 60 बीपीएस था। इसी तरह, पॉलिसी रेपो दर के ऊपर ट्रेजरी बिलों (टी-बिल) का औसत प्रसार ऋणात्मक से धनात्मक क्षेत्र में चला गया (चार्ट II.3)।

पहली छमाही में 4.9 लाख करोड़ रुपये से वर्ष 2025-26 दूसरी छमाही में सीडी के नए निर्गम बढ़कर 8.6 लाख करोड़ रुपये हो गए, जो जमाराशि वृद्धि और ऋण वृद्धि के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाता है। अवधि-वार, छोटी अवधि (91-दिन तक) में सीडी जारी करने के हिस्से में कमी आई, जबकि तीसरी तिमाही की तुलना में चौथी तिमाही में लंबी अवधि के निर्गम में वृद्धि हुई क्योंकि बैंकों ने बढ़ती ऋण मांग को पूरा करने के लिए लंबी अवधि के लिए निधि को सुरक्षित रखने की कोशिश की (सारणी II.4)।

प्राथमिक बाजार में सीपी का निर्गमन 2025-26 की दूसरी छमाही में घटकर 7.9 लाख करोड़ रुपये रह गया, जबकि पहली छमाही में यह 8.9 लाख करोड़ रुपये था, क्योंकि ब्याज दरों में वृद्धि के कारण बैंकों से उधार लेने की प्रवृत्ति बढ़ी (चार्ट II.4ए;

चार्ट II.4: वाणिज्यिक पत्र के प्राथमिक निर्गम

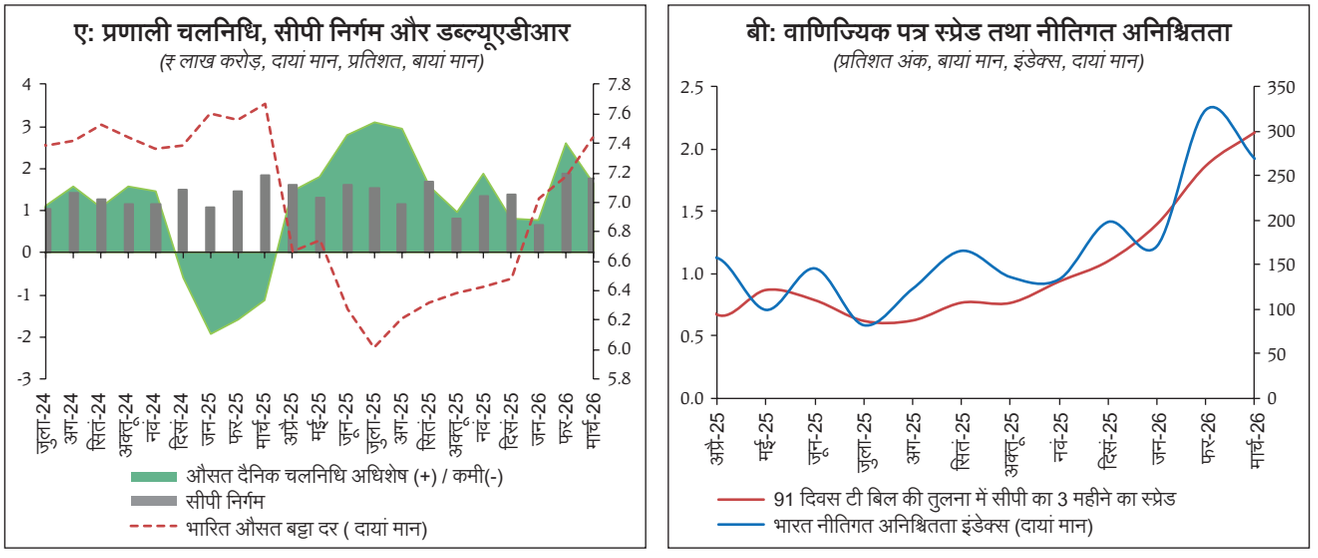

स्रोत: क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि. -एफ-टीआरएसी; www.policyuncertainty.com आरबीआई;और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.5: वाणिज्यिक पत्र जारी करने वालों का प्रोफाइल

₹ लाख करोड़

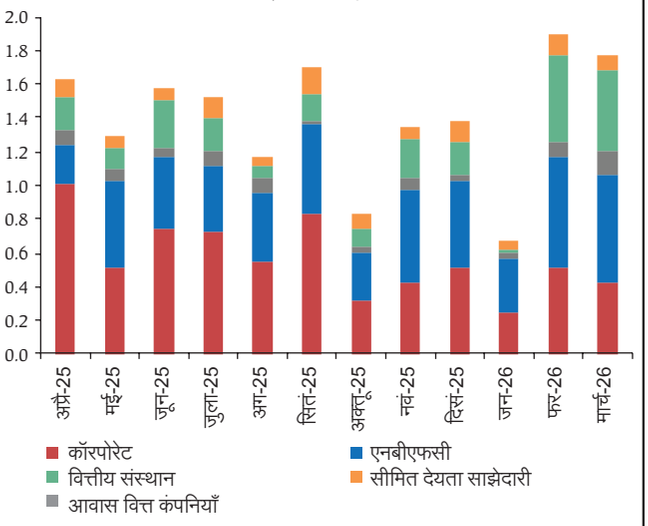

स्रोत: सीसीआईएल-एफ-टीआरएसी आरबीआई; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी II.5: सीपी निर्गमों की परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ लाख करोड़)

अवधि	छ1: 2024-25	छ2: 2024-25	छ1: 2025-26	छ2: 2025-26
7-30 दिवस	0.63 (8)	0.51 (6)	0.43 (5)	0.66 (8)
31-90 दिवस	2.35 (31)	2.33 (28)	3.10 (35)	1.87 (24)
91-180 दिवस	3.94 (52)	4.24 (52)	4.56 (51)	4.24 (53)
181-365 दिवस	0.64 (8)	1.11 (14)	0.86 (10)	1.16 (15)
कुल	**7.55 (100)**	**8.19 (100)**	**8.95 (100)**	**7.93 (100)**
बकाया (समाप्ति-अवधि के अनुसार)	3.98	4.43	4.88	4.60

टिप्पणियाँ: 1. कोष्टक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक परिपक्वता प्रोफाइल का हिस्सा दर्शाते है।
2. पूर्णांकन के कारण आंकड़ा कुल योग से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि. -एफ-टीआरएसी; और आरबीआई।

सारणी II.4)। दूसरी छमाही में नीतिगत अनिश्चितता बढ़ने के साथ-साथ जोखिम प्रीमियम (91-दिवसीय टी-बिलों पर 3 महीने की सीपी दर का स्प्रेड) में वृद्धि का रुझान देखा गया (चार्ट II.4बी)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने चालू पूंजी निर्गमों में अपना दबदबा बनाया, जिसकी औसत हिस्सेदारी दूसरी छमाही: 2025-26 के लिए 38 प्रतिशत थी। दूसरी छमाही में कंपनियों की हिस्सेदारी पहली छमाही में 49 प्रतिशत से घटकर 32 प्रतिशत रह गई (चार्ट II.5)। परिपक्वता प्रोफ़ाइल के संदर्भ में, नए सीपी जारी करने का सबसे बड़ा हिस्सा (53 प्रतिशत) 91-180 दिनों के खंड में था , इसके बाद 31-90 दिनों के खंड में (सारणी II.5)।

II.2.2 सरकारी प्रतिभूतियां (जी-सेक) बाजार

सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार में, प्रतिफल आम तौर पर वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान दबाव में रहा, जो घरेलू और वैश्विक कारकों को दर्शाता है (चार्ट II.6)। दूसरी

चार्ट II.6: 10-वर्षीय सममूल्य प्रतिफल और रेपो दर

(प्रतिशत)

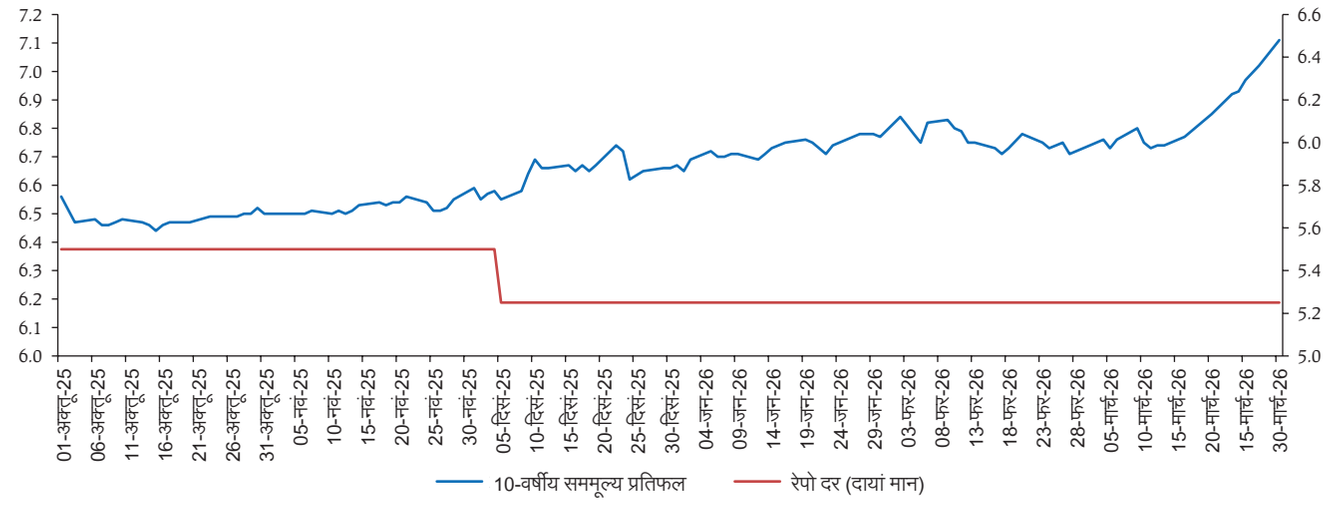

स्रोत: फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; और आरबीआई।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

छमाही की शुरुआत में, प्रतिफलों में नरमी आई, जो एमपीसी द्वारा 2025-26 और 2026-27 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई पूर्वानुमानों का अधोगामी संशोधन और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को दर्शाती है। उसके पश्चात नवंबर और दिसंबर में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, अमेरिकी प्रतिफल में मजबूती और एफपीआई बहिर्वाह में वृद्धि के कारण इसमें मजबूती आई।

जनवरी में, आरबीआई द्वारा की गई ओएमओ खरीद के जवाब में महीने के अंत में नरमी से पहले प्रतिफलों में मजबूती जारी रही। फरवरी में, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित सकल बाजार उधार के प्रत्याशा से अधिक होने के कारण प्रतिफल फिर से थोड़े समय के लिए कठोर हो गया। इसके बाद, प्रतिफल में नरमी आई क्योंकि आरबीआई ने और अधिक ओएमओ खरीद की (चार्ट II.6)। मार्च में, पश्चिम एशिया में बढ़े भू-राजनीतिक तनाव के बीच प्रतिफल फिर से मजबूत हो गया, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई और डीजल और पेट्रोल पर विशेष उत्पाद शुल्क में कटौती का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

अल्पावधि में, दिसंबर 2025 में नीतिगत दर में कटौती और टिकाऊ चलनिधि बढ़ाने के लिए आरबीआई के उपायों के कारण दूसरी 2025-26 की छमाही के दौरान प्रतिफल में नरमी आई (चार्ट II.7)।

चार्ट II.7: एफ़बीआईएल- टी-बिल बेंचमार्क

परिपक्वता पर प्रतिफल (प्रतिशत)

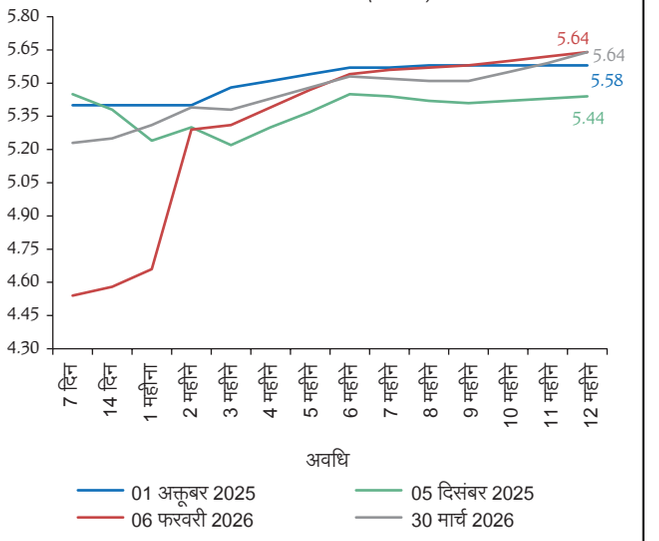

स्रोत: फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

2025-26 की दूसरी छमाही में सरकारी प्रतिभूति और टी बिल में औसत व्यापार की मात्रा पहली छमाही से कम थी (चार्ट II.8)। ट्रेड की गयी परिपक्वता पर सरकारी प्रतिभूति के लिए भारित औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) में 20 बीपीएस की वृद्धि हुई, जबकि पहली छमाही की तुलना में द्वितीय छमाही में टी-बिल के लिए इसमें 22 बीपीएस की गिरावट आई।

चार्ट II.8: ट्रेडिंग मात्रा और प्रतिफल

ए: जी-सेक

(₹ करोड़, बायां मान; प्रतिशत, दायां मान)

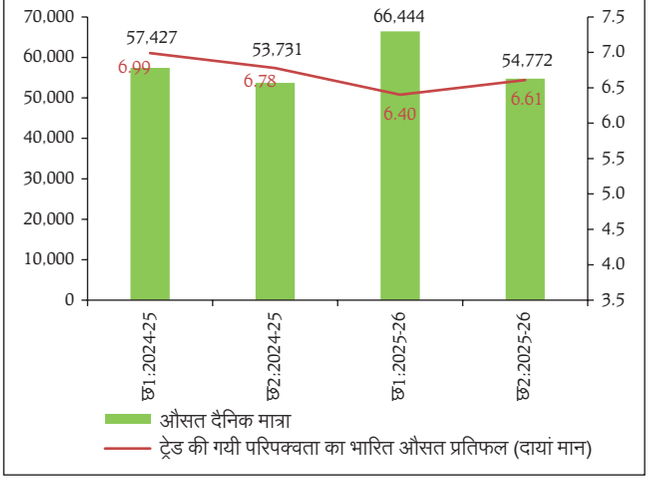

बी: टी-बिल

(₹ करोड़, बायां मान; प्रतिशत, दायां मान)

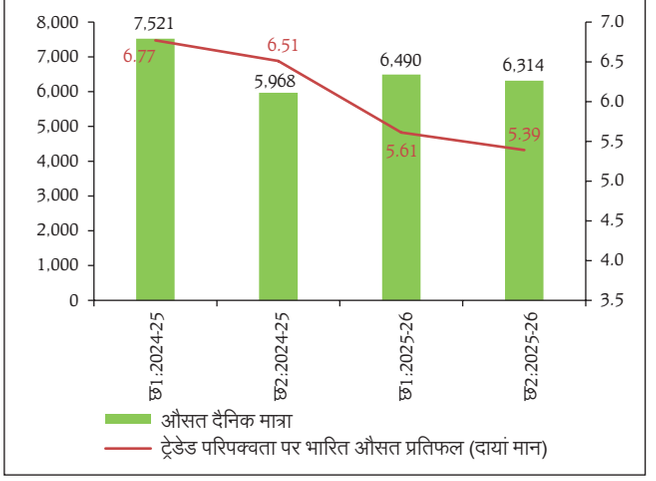

स्रोत: क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल); और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

प्रतिफल वक्र की समग्र गतिशीलता को इसके अंतर्निहित कारकों, जैसे, स्तर, ढलान और वक्रता[6] द्वारा देखा जाता है। प्रतिफल आमतौर पर दीर्घावधि में कठोर हो गए (चार्ट II.9 ए)। आंशिक रूप से इसके कारण (i) बाजार उधार में वृद्धि, (ii) लंबी अवधि की राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (एसजीएस) को जारी करने में वृद्धि, और (iii) संस्थागत निवेशकों द्वारा लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों की मांग में कमी थे।

प्रतिफल के औसत स्तर में 51 बीपीएस की वृद्धि हुई, जबकि प्रतिफल वक्र का ढलान 54 बीपीएस तक बढ़ गया, जो दीर्घावधि में मजबूती के रुझान को दर्शाता है (चार्ट II.9बी)। दूसरी ओर, वक्रता में भी 60 बीपीएस की वृद्धि हुई। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत भारतीय संदर्भ में, प्रतिफल वक्र के स्तर और वक्रता में, बाजार विभाजन और निवेशकों के पसंदीदा आवास के कारण ढलान की तुलना में भविष्य के समष्टि आर्थिक परिणामों पर अधिक जानकारी सामग्री पाई जाती है (पात्रा और अन, 2022)।[7]

सक्रिय ऋण समेकन के एक हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की ओर से वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान ₹1,45,377 करोड़ की राशि के सरकारी प्रतिभूति की सात स्विच नीलामियां आयोजित कीं। बदलती हुई मांग के स्थिति के आकलन के आधार पर दूसरी छमाही में दीर्घावधि पत्रों की आपूर्ति कम हो गयी। परिणामस्वरूप सरकारी प्रतिभूति के जारी होने की भारित औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) पहली छमाही के 19.65 वर्षों से घटकर दूसरी छमाही में 17.96 वर्ष रह गया। बकाया स्टॉक की भारित औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) सितंबर 2025 के अंत के 13.60 वर्ष से बढ़कर 20 मार्च, 2026 में 13.72 वर्ष हो गई, जबकि इसी अवधि में भारित औसत कूपन (डब्ल्यूएसी) 7.20 प्रतिशत से घटकर 7.17 प्रतिशत हो गया।

तुलनीय परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल की अपेक्षा राज्य सरकार प्रतिभूतियों (एसजीएस) पर कट-ऑफ प्रतिफल का भारित औसत प्रसार (स्प्रेड) 2025-26 की दूसरी छमाही (चार्ट II.10) में 57 बीपीएस था, जबकि यह 2025-26 की पहली छमाही में 38 बीपीएस था। 10 साल की अवधि (नए निर्गम) के एसजीएस पर कट-ऑफ प्रतिफल का औसत अंतर-राज्यीय प्रसार दूसरी छमाही में 12 बीपीएस था, जबकि पहली छमाही में 5 बीपीएस था।

चार्ट II.9 जी-सेक प्रतिफल वक्र

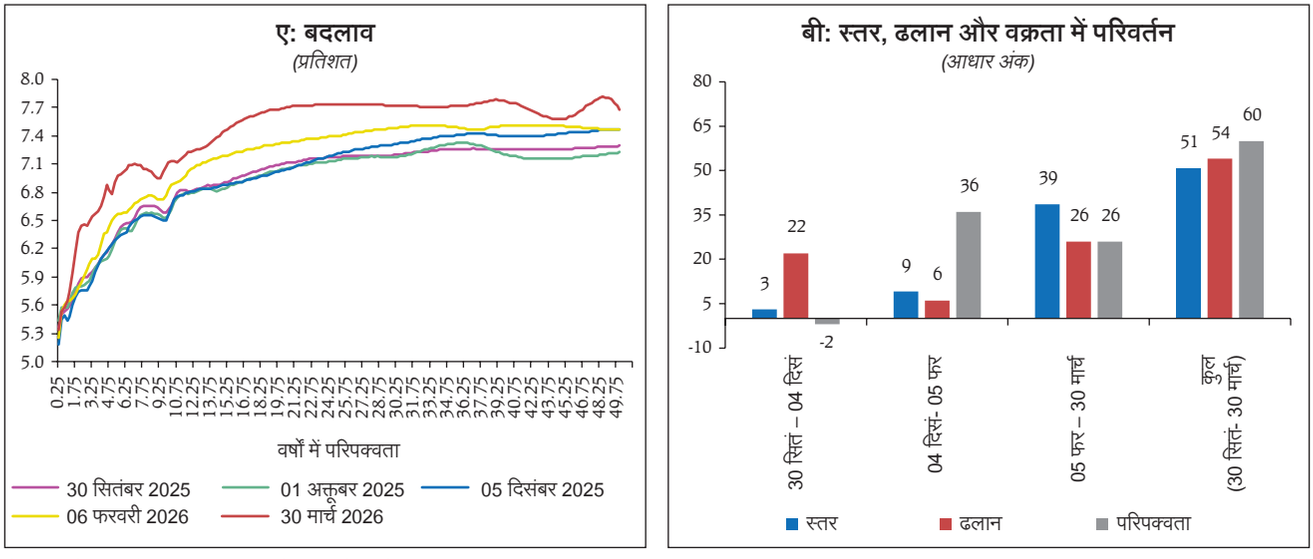

स्रोत: फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[6] यह स्तर एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित 30 साल तक की सभी अवधियों के सममूल्य प्रतिफलों और ढलान (टर्म स्प्रेड) 3 महीने और 30 साल की परिपक्वता की सममूल्य प्रतिफलों में अंतर है। वक्रता की गणना 15-वर्ष की प्रतिफल से 30-वर्ष और 3-महीने की प्रतिफल के योग से दोगुनी के रूप में की जाती है।

[7] पात्र, एमडी, जोइस, जे., कुशवाहा, केएम, और आई. भट्टाचार्य (2022), "अर्थव्यवस्था के बारे में प्रतिफल वक्र हमें क्या बता रहा है?", भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, जून।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

चार्ट II.10: एसजीएस - जुटाई गई रकम और स्प्रेड

(₹ करोड़, बायां मान; आधार अंक, दायां मान)

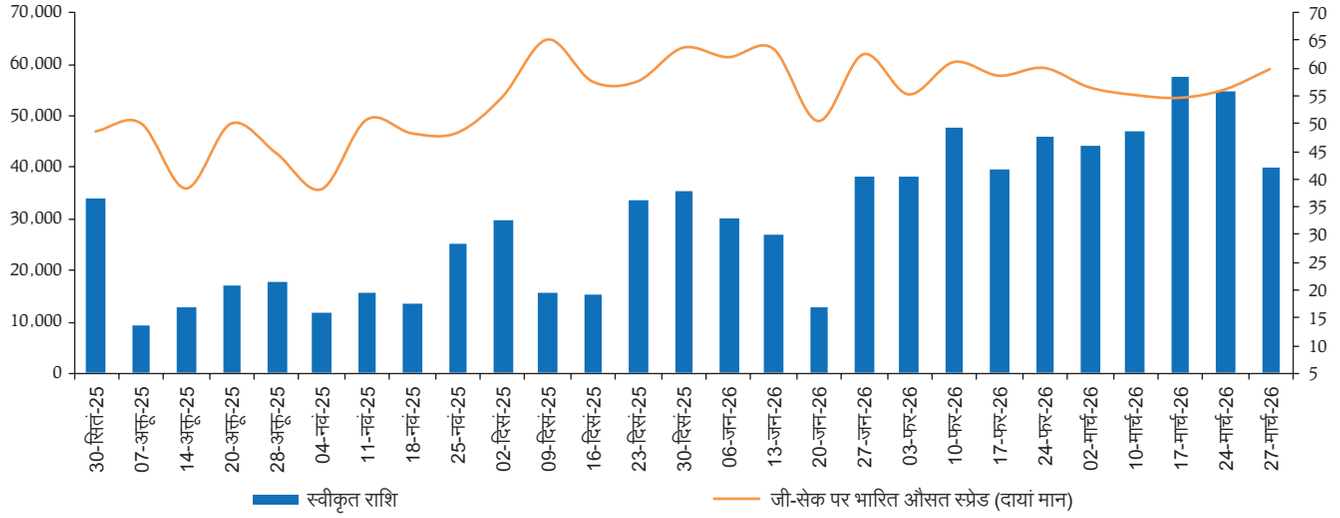

स्रोत: फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

II.2.3 कॉरपोरेट बॉण्ड मार्केट

वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में मजबूती और जोखिम प्रीमियम बढ़ने के कारण कॉरपोरेट बॉण्ड के प्रतिफल में वृद्धि हुई (चार्ट II.11ए)। उच्च एवं निम्न दर वाले बॉण्ड के लिए जोखिम प्रीमियम बढ़ गया। औसत बॉण्ड बाजार जोखिम प्रीमियम (अर्थात्, 3-वर्षीय एएए कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल और 3-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति के बीच का स्प्रेड) दूसरी तिमाही (सितंबर 2025 की तुलना में मार्च 2026) में तीसरी तिमाही में मिश्रित कॉरपोरेट कमाई के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू), वित्तीय संस्थाओं (एफ़आई) और बैंकों के लिए 80 बीपीएस से बढ़कर 109 बीपीएस, एनबीएफ़सी के लिए 107 बीपीएस से 129 बीपीएस और कॉरपोरेट्स के लिए 105 बीपीएस से 112 बीपीएस हो गया, (चार्ट II.11बी और सारणी II.6)।

चार्ट II.11: एएए-श्रेणी 3-वर्षीय कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल और स्प्रेड

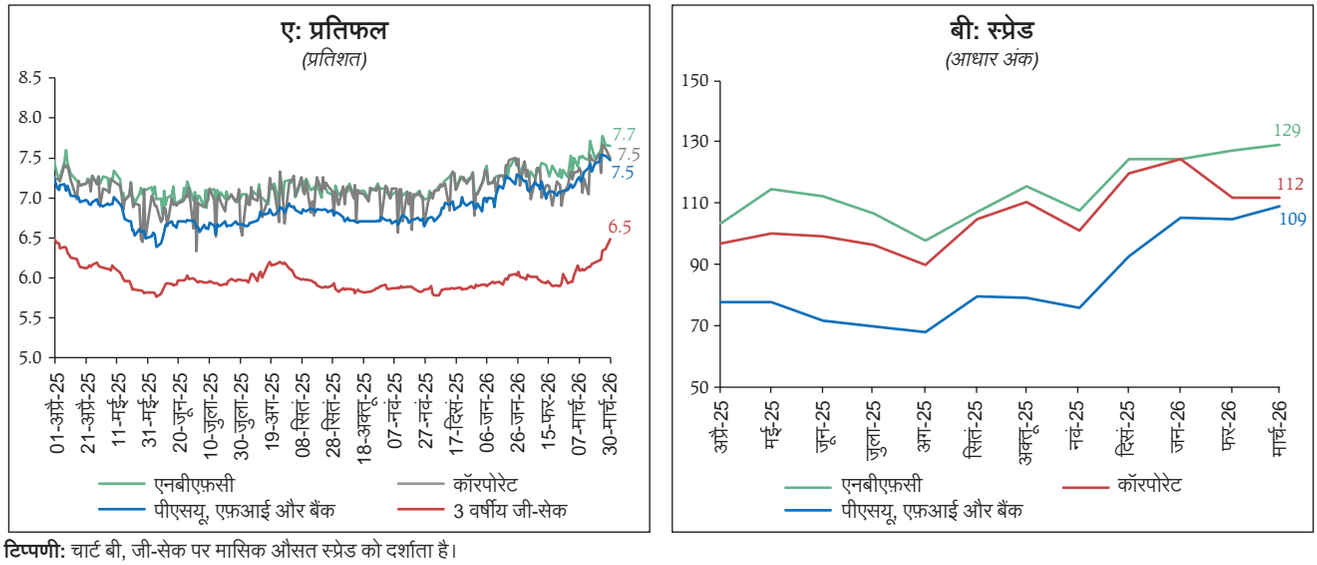

टिप्पणी: चार्ट बी, जी-सेक पर मासिक औसत स्प्रेड को दर्शाता है।
स्रोत: फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफ़आईएमएमडीए)।

सारणी II.6: द्वितीय बाजार- दरें और स्प्रेड

	ब्याज दर (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस) (तदनुरूपी जोखिम-मुक्त दर पर)		
लिखत	**मार्च 2025**	**सितंबर 2025**	**मार्च 2026**	**मार्च 2025**	**सितंबर 2025**	**मार्च 2026**
1	2	3	4	5	6	7
कॉरपोरेट बॉन्ड						
(i) एएए (1 वर्ष)	7.76	6.69	7.40	115	100	171
(ii) एएए (3 वर्ष)	7.62	7.10	7.36	98	105	112
(iii) एएए (5 वर्ष)	7.60	7.20	7.52	89	86	92
(iv) एए (3 वर्ष)	8.43	8.20	8.22	178	215	198
(v) बीबीबी माइनस (3 वर्ष)	12.09	11.88	11.92	544	583	567

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना मासिक औसत के रूप में की जाती है।

स्रोत: फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफ़आईएमएमडीए) और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही (फरवरी 2026 तक) के दौरान घरेलू बाजारों में सूचीबद्ध कॉरपोरेट बॉन्ड के प्राथमिक निर्गम घटकर ₹3.3 लाख करोड़ हो गए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान बढ़ती लागत के कारण ₹4.2 लाख करोड़ थे (चार्ट II.12ए)। दूसरी छमाही (फरवरी तक) के दौरान विदेशी निर्गम बढ़कर ₹24,568 हुए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 22,953 करोड़ रुपये थे। कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में संसाधन जुटाने का अधिकांश हिस्सा (98.7 प्रतिशत) दूसरी छमाही में निजी स्थानन के माध्यम से हुआ। कॉरपोरेट बॉण्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा बकाया निवेश

चार्ट II.12: कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार गतिविधि

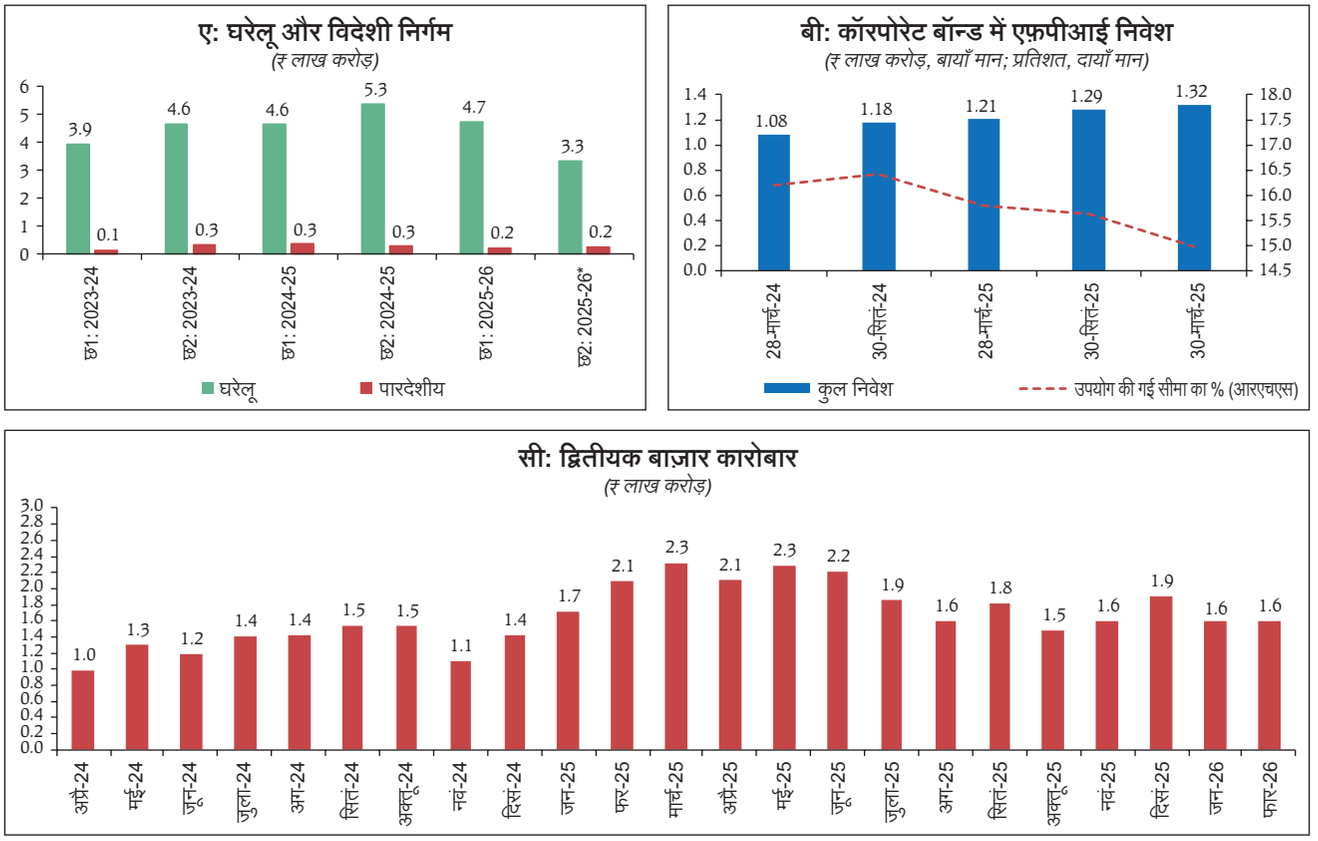

*: डेटा फरवरी 2026 तक का है।

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी); नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल); और प्राइम डेटाबेस।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

20 मार्च 2026 तक ₹1.3 लाख करोड़ था, जिसमें निवेश सीमा के उपयोग में 15.0 प्रतिशत की कमी आई (चार्ट II.12बी)। दूसरी छमाही (फरवरी 2026 तक) के दौरान द्वितीयक बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम ₹8.2 लाख करोड़ तक बढ़ गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ₹7.9 लाख करोड़ था (चार्ट II.12सी)।

II.2.4 इक्विटी बाज़ार

वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान, भारतीय इक्विटी मार्केट में द्विदिशात्मक गतिविधियां देखी गईं। अक्तूबर-नवंबर में दूसरी तिमाही के अच्छे कॉरपोरेट आय और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा नीतिगत दर में कटौती के बीच बाजार में तेजी रही। भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को लेकर बरती जा रही सावधानी के अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा नीतिगत दर में कटौती से जुड़े सकारात्मक वैश्विक संकेतों और एआई से संबंधित घटनाक्रमों पर नवीकृत आशावाद से अधिक होने के कारण दिसंबर में ये सीमाबद्ध रहे। जनवरी में अमेरिका द्वारा ताजा टैरिफ चेतावनियों और तीसरी तिमाही के लिए मिश्रित कॉरपोरेट आय के कारण आई गिरावट के बाद, भारत और उसके प्रमुख व्यापारिक भागीदारों - यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक व्यापार सौदों की घोषणा के साथ बाजारों में सुधार हुआ। हालांकि, पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के कारण फरवरी के अंत से बाजारों में तीव्र गिरावट आई है जिसने पुराने लाभों को निरस्त कर दिया।

कुल मिलाकर, व्यापक बाजार सूचकांकों ने 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान बेंचमार्क के सापेक्ष कमतर प्रदर्शन किया जिससे बाजार में सामान्यीकरण हुआ (चार्ट II.13ए)। दूसरी छमाही में इस समग्र प्रदर्शन को दर्शाते हुए, व्यापक बाजार सूचकांकों के लिए मूल्य-से-आय (पीई) अनुपात में बेंचमार्क की तुलना में अधिक गिरावट आई। बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स के लिए पीई अनुपात सितंबर 2025 के अंत में 22.2 से मार्च 2026 के अंत में 19.8 तक घट गया। इसके विपरीत, बीएसई 250 स्मॉलकैप इंडेक्स के लिए पीई अनुपात सितंबर 2025 के अंत में 34.0 से मार्च 2026 के अंत में 26.3 तक तेजी से गिर गया। बीएसई 150 मिडकैप इंडेक्स के लिए पीई अनुपात इस अवधि के दौरान 34.2 से घटकर 31.1 हो गया। भारतीय अस्थिरता सूचकांक, निफ्टी 50 की अल्पकालिक अपेक्षित अस्थिरता का एक उपाय है, जो वैश्विक टैरिफ अनिश्चितता और निरंतर भू-राजनीतिक तनाव के कारण सितंबर 2025 के 11.1 से बढ़कर मार्च 2026 में 27.9 हो गया। कीमती धातुओं की वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण धातु संबंधी शेयरों में तेजी देखी गई जबकि अन्य सभी क्षेत्रों में गिरावट आई (चार्ट II.13बी)।

चार्ट II.13: स्टॉक बाजार का प्रदर्शन

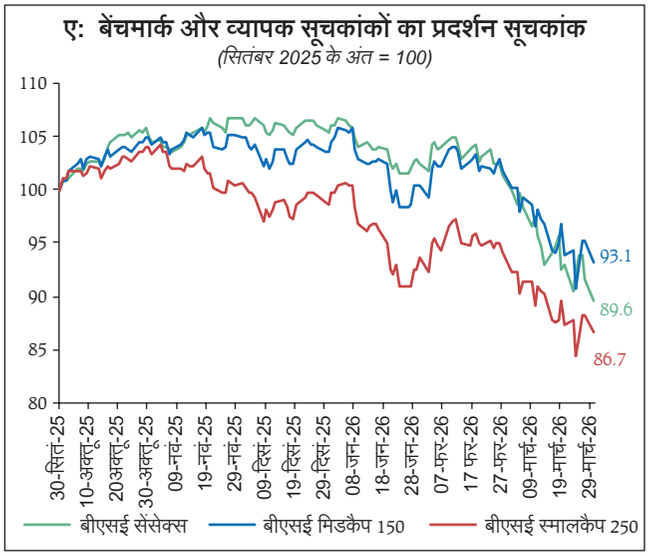

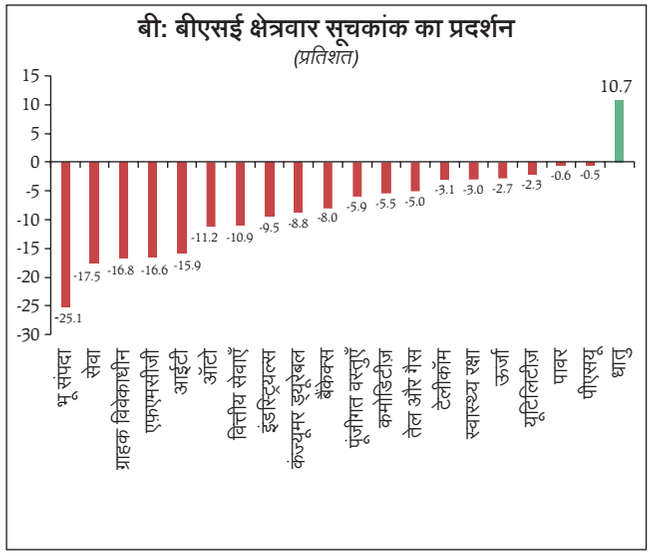

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

एफपीआई 2025-26 की दूसरी छमाही में घरेलू इक्विटी बाजार में निवल विक्रेता बने रहे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई), विशेष रूप से म्यूचुअल फंडों ने निवल खरीद के साथ एक प्रतिसंतुलन बल के रूप में काम किया और बाजारों को सुदृढ़ता प्रदान की (चार्ट II.14) । दूसरी छमाही (फरवरी 2026 तक) के दौरान प्राथमिक इक्विटी बाजारों में जुटाए गए संसाधन ₹2.3 लाख करोड़ थे, जो पहली छमाही के ₹2.0 लाख करोड़ से अधिक था (चार्ट II.15ए)। सुनियोजित निवेश योजनाओं (एसआईपी) में औसत संसाधन संग्रह में निरंतर वृद्धि देखी गई है, जो 'छोटी एसआईपी' जैसी नीतिगत पहलों द्वारा समर्थित है (चार्ट II.15बी)।

चार्ट II.14: संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय इक्विटी में निवल निवेश

(₹ करोड़)

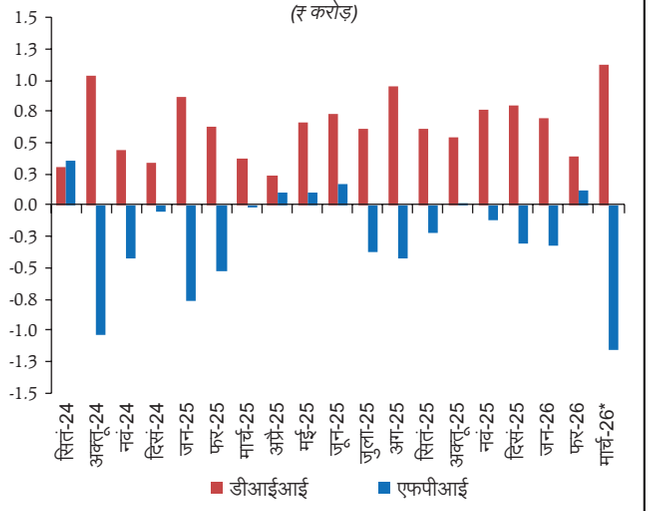

टिप्पणी: *: आंकड़े 27 मार्च 2026 तक के हैं।
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

II.2.5 विदेशी मुद्रा बाज़ार

2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान विदेशी मुद्रा बाजार अस्थिर रहा, जो बदलती अमेरिकी नीतियों, टैरिफ-संबंधित अनिश्चितता और तीव्र बढ़े हुए भू-राजनीतिक तनाव के कारण था। जनवरी तक यूएस डॉलर इंडेक्स में निरंतर गिरावट देखी गई, और यह कई वर्षों के निम्न स्तर पर आ गई, जो बढ़ते हुए अमेरिकी विकास और राजकोषीय स्थिरता को लेकर बढ़ती चिंताओं और फेडरल रिजर्व के दर-कटौती चक्र की अवधि से जुड़ी अनिश्चितता के कारण कम हो गई। फरवरी के अंत में पश्चिमी एशिया में द्वंद्व के शुरुआत के साथ, अमेरिकी डॉलर तेजी से बढ़ा, जो सुरक्षित आश्रय के मांग में वृद्धि को दर्शाता है। जनवरी 2026 तक उभरते बाजार (ईएम) की मुद्राएं अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने और विश्व भर में जोखिम उठाने की क्षमता में सुधार पर व्यापक रूप से मजबूत हुईं, लेकिन उसके बाद बढ़ती वैश्विक जोखिम-विमुख भावनाओं के बीच इसमें गिरावट आई। भारतीय रुपये (आईएनआर) ने लगातार एफ़पीआई बहिर्वाह, बढ़ी हुई

चार्ट II.15: संसाधन जुटाना और एसआईपी का प्रवाह

ए: प्राथमिक बाजार में संसाधनों का जुटाव

(₹ लाख करोड़, बायाँ मान; ₹ करोड़, दायाँ मान)

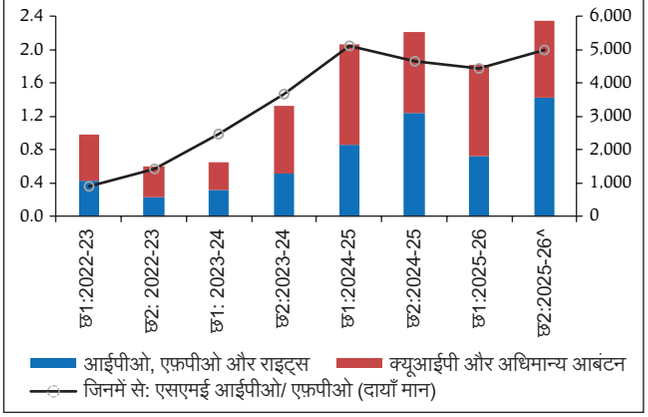

बी: एसआईपी में प्रवाह

(₹ करोड़)

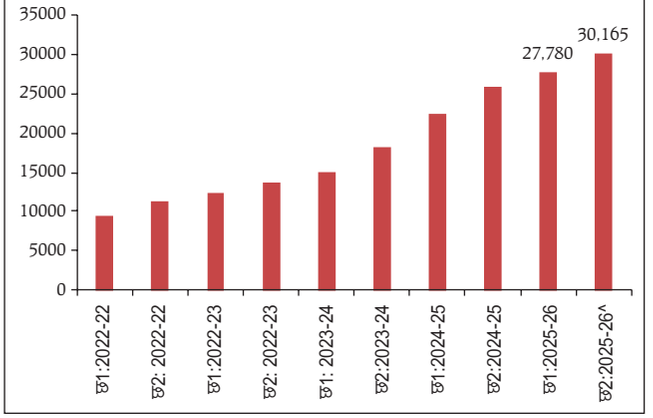

टिप्पणियाँ: 1. आईपीओ: प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। क्यूआईपी: अर्ह संस्थागत नियोजन। एफ़पीओ: अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव।
2. ^: फरवरी 2026 तक।
3. *: फरवरी 2026 तक।

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय पारस्परिक निधि संघ (एएमएफआई)।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

चार्ट II.16: भारतीय रुपया और अस्थिरता

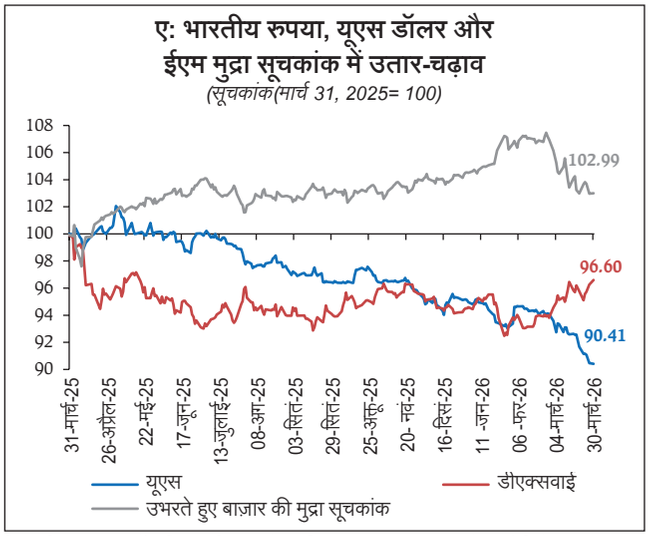

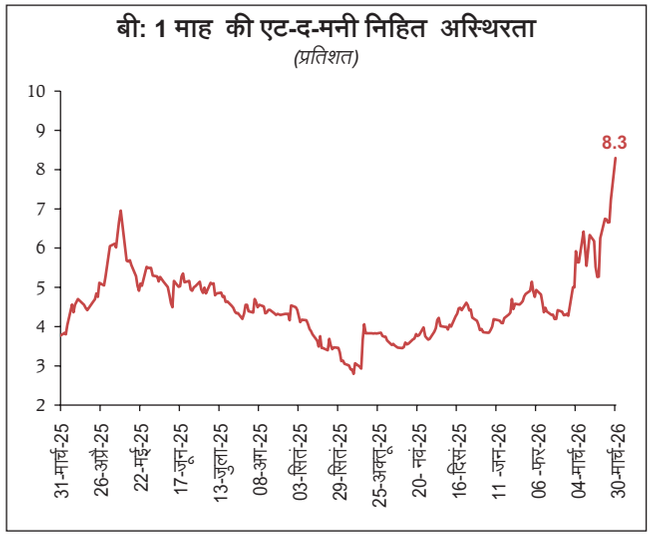

टिप्पणी: सूचकांक में वृद्धि (कमी) मुद्रा के अधिमूल्यन (अवमूल्यन) को दर्शाती है।
स्रोत: फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.; रिफिनिटिव आइकॉन; ब्लूमबर्ग और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

कॉरपोरेट डॉलर की मांग और दूसरी छमाही में वैश्विक जोखिम-बंद भावनाओं में वृद्धि के कारण मूल्यह्रास के पूर्वाग्रह के साथ दोतरफा उतार-चढ़ाव प्रदर्शित किया। अंतरिम भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा पर फरवरी 2026 की शुरुआत से भारतीय रुपए में मूल्यवृद्धि हुई पर मार्च में, पश्चिम एशिया में युद्ध बढ़ने के कारण मूल्यह्रास हुआ (चार्ट II.16ए)। दूसरी छमाही में जहां पहली छमाही की तुलना में निहित विकल्प अस्थिरता कम हो गई, पश्चिमी एशिया में चल रही जोखिम-विमुख भावनाओं और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के कारण यह उच्च बनी रही (चार्ट II.16बी)। विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्थित स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 मार्च, 2026 को एक विवेकपूर्ण उपाय पेश किया, जिसने प्रत्येक व्यावसायिक दिन के अंत में ऑनशोर डिलिवरी योग्य बाजार में अधिकृत डीलरों के आईएनआर (एनओपी-आईएनआर) में निवल खुली स्थिति को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भीतर सीमित कर दिया। इसका उद्देश्य अत्यधिक सट्टा स्थिति पर अंकुश लगाना और प्रणालीगत जोखिमों को कम करना था।

कुल मिलाकर, दूसरी छमाही में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया में 6.2 प्रतिशत की गिरावट आई, (चार्ट II.17)। तथापि, बढ़ी हुई अनिश्चितताओं के बावजूद, इस अवधि के दौरान भारतीय रुपया सबसे कम अस्थिर ईएम मुद्राओं में से एक रहा, जो मामूली चालू खाता घाटे और यह मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा समर्थित है।

फॉरवर्ड प्रीमिया ने 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान तेज उतार-चढ़ाव प्रदर्शित किए, जो ब्याज दर के अंतर में परिवर्तन और उभरती वैश्विक भावनाओं को दर्शाता है (चार्ट II.18)। दिसंबर में अल्पकालिक प्रीमियम में वृद्धि पूंजी के बहिर्वाह, वैश्विक नीतिगत अनिश्चितता में वृद्धि और उच्च हेजिंग मांग से प्रेरित थी,

चार्ट II.17: प्रमुख उभरती बाज़ार मुद्राओं में उतार-चढ़ाव (मार्च 2026 के अंत से सितंबर 2025 के अंत तक)

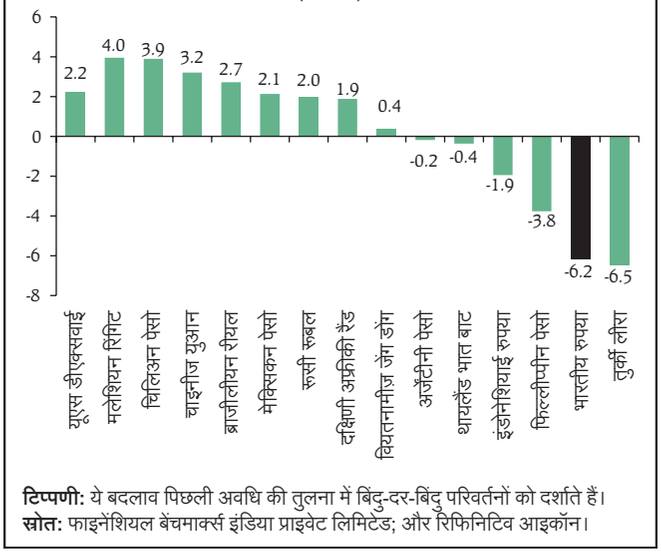

टिप्पणी: ये बदलाव पिछली अवधि की तुलना में बिंदु-दर-बिंदु परिवर्तनों को दर्शाते हैं।
स्रोत: फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; और रिफिनिटिव आइकॉन।

चार्ट II.18: भारतीय रुपए-अमेरिकी डॉलर फॉरवर्ड प्रीमियम में उतार-चढ़ाव

(प्रतिशत)

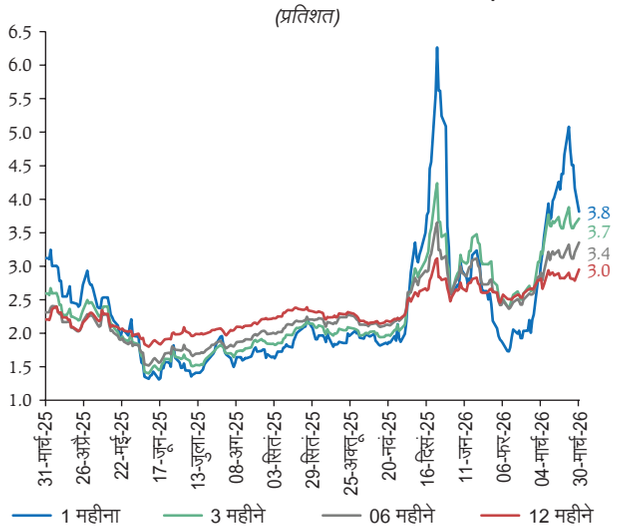

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

जिसने प्रभावी रूप से फॉरवर्ड प्रीमिया टर्म की संरचना को उलट दिया। फॉरवर्ड प्रीमिया दिसंबर की ऊँचाइयों से काफी कम हो गया क्योंकि रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि बढ़ाने के उपायों की पृष्ठभूमि में चलनिधि की स्थिति आसान हो गई, जिसमें यूएसडी/आईएनआर खरीद-बिक्री स्वैप नीलामी शामिल है। मार्च में, फॉरवर्ड प्रीमिया में वृद्धि हुई, जो पश्चिमी एशिया में बढ़ी हुई अनिश्चितता को दर्शाता है। औसतन, 1 महीने का फॉरवर्ड प्रीमियम दूसरी छमाही में बढ़कर 2.76 प्रतिशत हो गया, जो पहली छमाही में 1.95 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान 12 महीने का प्रीमिया 2.12 प्रतिशत से बढ़कर 2.54 प्रतिशत हो गया।

40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में, सितंबर 2025 और फरवरी 2026 के बीच भारतीय रुपए में 3.3 प्रतिशत की गिरावट आई, जो सांकेतिक प्रभावी विनिमय दरों में भारतीय रुपए के मूल्यह्रास से प्रेरित है (चार्ट II.19ए)। भारतीय रुपये की 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) का मूल्यह्रास मोटे तौर पर कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप था (चार्ट II.19बी)।

वित्तीय परिस्थितियां

तीसरी तिमाही में समग्र वित्तीय परिस्थितियां[8] अनुकूल रहीं। हालांकि, फरवरी 2026 के अंत में पश्चिम एशिया संकट की शुरुआत होने के साथ ही, पूरे बाज़ार में व्यापक स्तर पर सख्ती आने के कारण वित्तीय स्थितियाँ और सख्त हो गईं (चार्ट II.20)।

चार्ट II.19: वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) का रुझान

ए: भारत की 40-मुद्रा आरईईआर

(प्रतिशत, बायां मान; सूचकांक [2015-16=100] दायां मान)

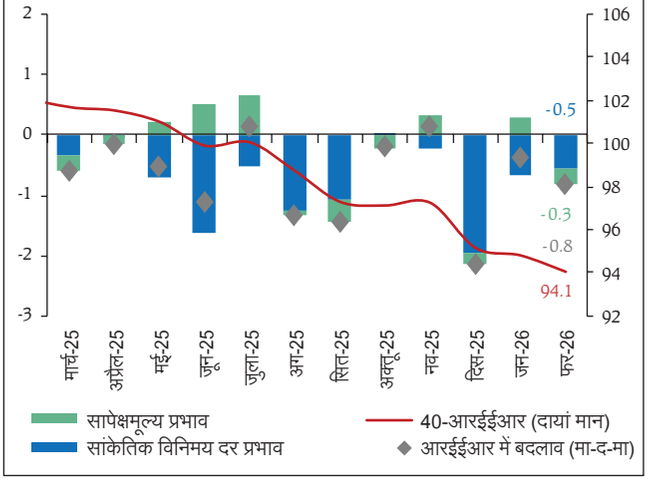

बी: आरईईआर में बहुराष्ट्रीय उतार-चढ़ाव (सितंबर 2025 की तुलना में फरवरी 2026)

(प्रतिशत)

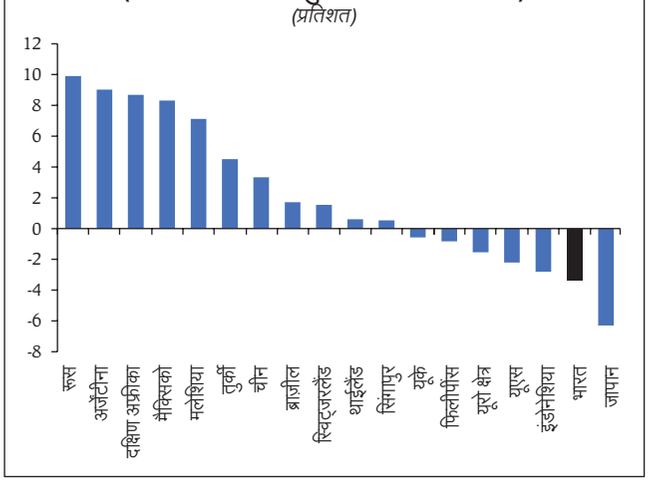

स्रोत: बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स;और आरबीआई।

[8] वित्तीय स्थिति सूचकांक दैनिक बारंबारता पर बीस भारतीय वित्तीय बाजार संकेतकों पर आधारित है। चयनित संकेतक पांच बाजार वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात् (i) मुद्रा बाजार; (ii) जी-सेक बाजार; (iii) कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार; (iv) विदेशी मुद्रा बाजार; और (v) इक्विटी बाजार। विस्तृत पद्धति के लिए, देखें बंद्योपाध्याय, पी., कुमार, ए., कुमार, पी. और भट्टाचार्य, आई. (2025), 'भारत के लिए वित्तीय स्थिति सूचकांक: उच्च-आवृत्ति दृष्टिकोण'; भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, जून। https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=23451

मौद्रिक नीति वक्तव्य

चार्ट II.20: भारत के लिए दैनिक वित्तीय स्थिति सूचकांक

(वर्ष 2012 के औसत से मानक विचलन)

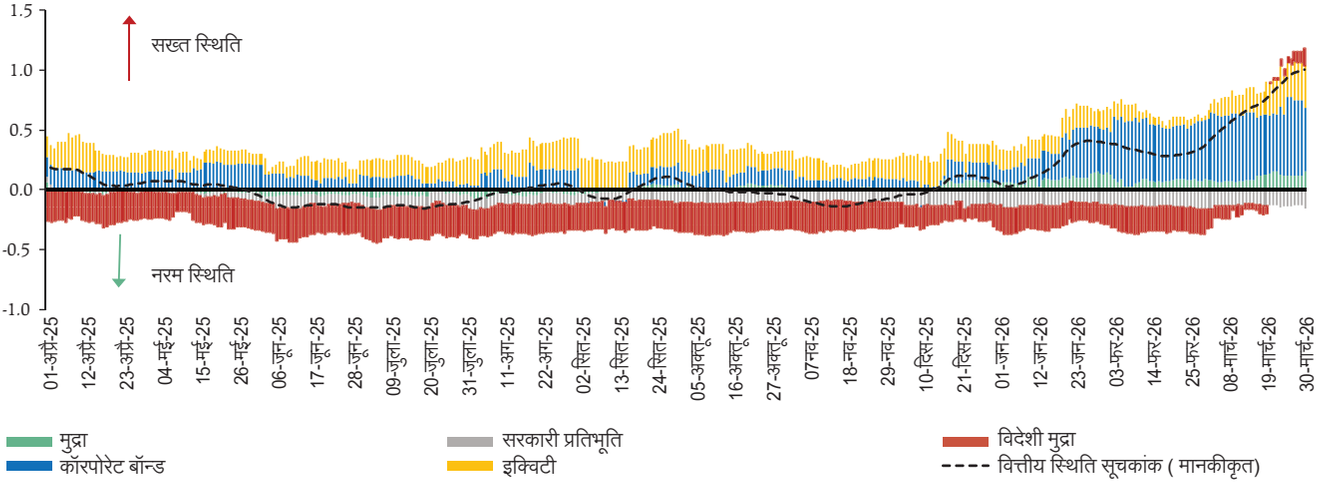

टिप्पणी: स्थिति सूचकांक अपने ऐतिहासिक औसत पर आधारित एक मीट्रिक प्रदान करता है; इस संदर्भ में, शून्य मान उस वित्तीय प्रणाली को दर्शाता है जो सूचकांक में शामिल सभी वित्तीय संकेतकों के ऐतिहासिक औसत स्तर पर कार्य कर रही है। परिणाम प्रस्तुत करने के लिए, मानकीकृत सूचकांक का उपयोग किया जाता है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

II.2.6 बैंक और गैर-बैंक ऋण

बैंक ऋण: समग्र रुझान

2025-26 की दूसरी छमाही में मौद्रिक नीति में नरमी और मज़बूत आर्थिक गतिविधियों के कारण बैंक ऋण में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंक ऋण में 15 मार्च 2026 तक 13.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) तक तेज़ वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले यह 11.0 प्रतिशत थी। बैंक समूहों में, विदेशी बैंकों की ऋण वृद्धि सबसे अधिक 14.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बनी रही, इसके पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी बैंक रहे (चार्ट II.21ए)। 15 मार्च 2026 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वृद्धिशील ऋण (वर्ष-दर-वर्ष) में सबसे बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि, हाल के महीनों में निजी बैंकों की ऋण वृद्धि तेज हुई है, जिससे वृद्धिशील ऋण में उनकी हिस्सेदारी में सुधार हुआ है (चार्ट II.21बी)।

चार्ट II.21: बैंक समूह में ऋण प्रवाह

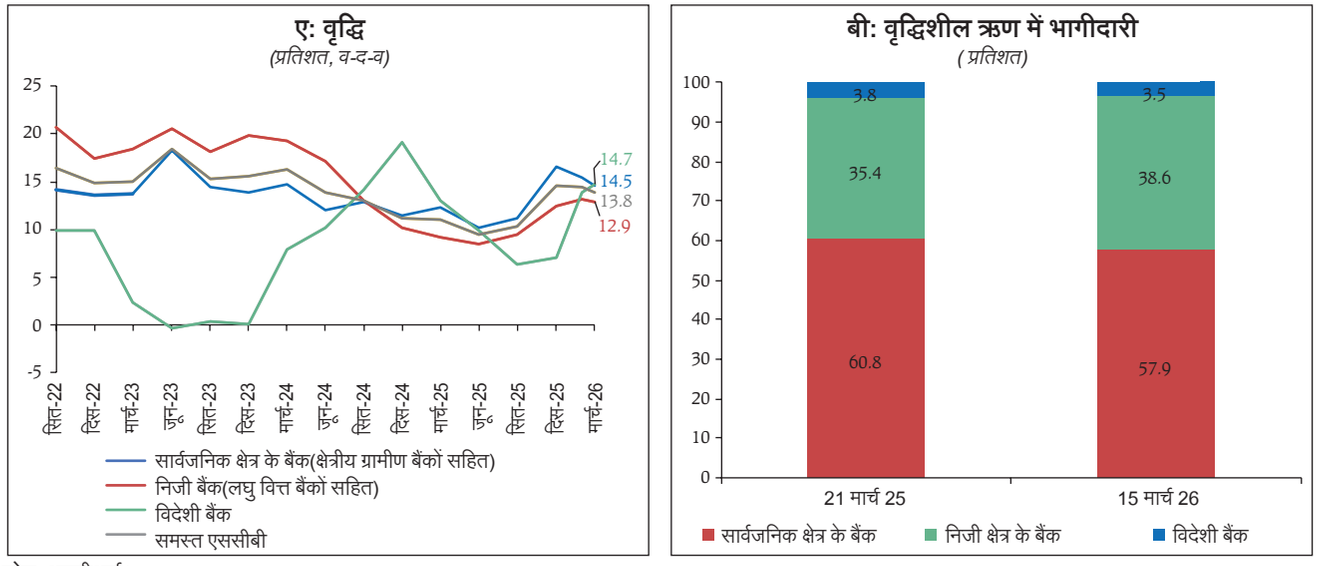

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट II.22: एससीबी की दबावग्रस्त आस्तियां और अनर्जक आस्तियां

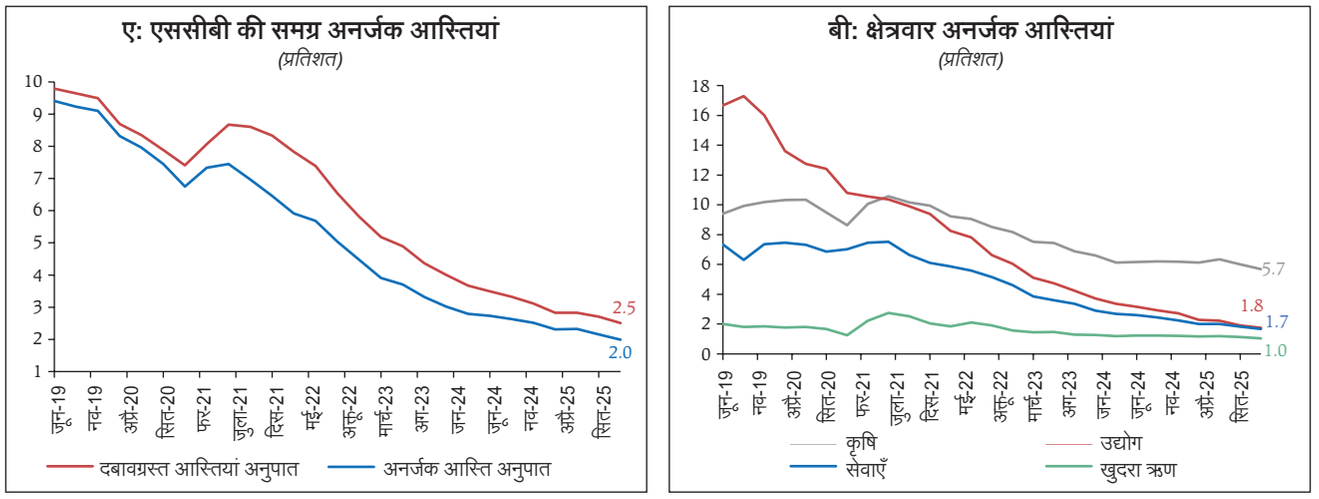

स्रोत: आरबीआई।

वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता और बेहतर हुई, समग्र सकल अनर्जक आस्ति(एनपीए) अनुपात दिसंबर 2025 में 2.0 प्रतिशत तक घट गया, जो एक वर्ष पहले 2.5 प्रतिशत था (चार्ट II.22ए)। सभी प्रमुख क्षेत्रों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ (चार्ट II.22बी)।

वाणिज्यिक पत्रों की धारिता में आई गिरावट के कारण बैंकों के गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (गैर-एसएलआर) निवेश (जिसमें सीपी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और सार्वजनिक और निजी कॉरपोरेट्स के शेयर शामिल हैं) में वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही (15 मार्च तक) के दौरान 2.7 प्रतिशत की मध्यम वृद्धि हुई (चार्ट II.23ए)। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में (15 मार्च तक) समायोजित गैर-खाद्य ऋण (गैर-खाद्य बैंक ऋण तथा बैंकों के गैर-एसएलआर निवेश का योग) में वृद्धि 13.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रही, जबकि वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में यह 10.8 प्रतिशत थी (चार्ट II.23बी)।

28 फरवरी 2026 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक बैंकों की एसएलआर प्रतिभूतियों की अतिरिक्त धारिताएं उनकी एनडीटीएल का 6.3 प्रतिशत तक कम हो गईं, जो मार्च 2025 के अंत में 7.3 प्रतिशत थी, क्योंकि बैंकों ने ऋण मांग को वित्तपोषित करने के लिए अपने निवेश पोर्टफोलियो को कम किया (चार्ट II.24)।

चार्ट II.23: गैर-एसएलआर निवेश और समायोजित गैर-खाद्य ऋण

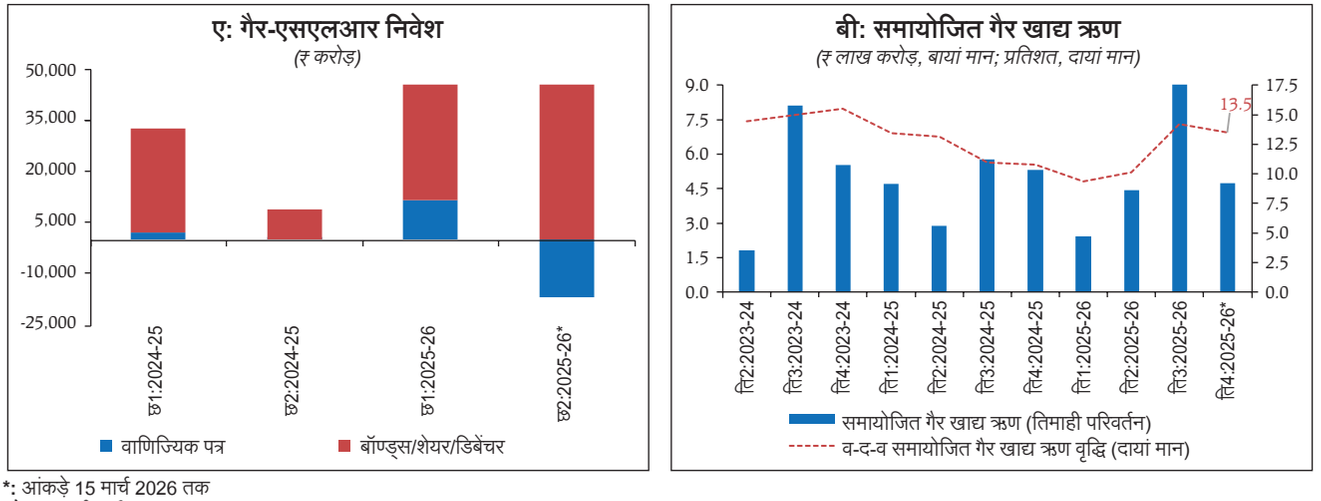

*: आंकड़े 15 मार्च 2026 तक
स्रोत: आरबीआई।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

चार्ट II.24: बैंकों का अतिरिक्त एसएलआर

(निवल मांग और मीयादी देयताओं का प्रतिशत)

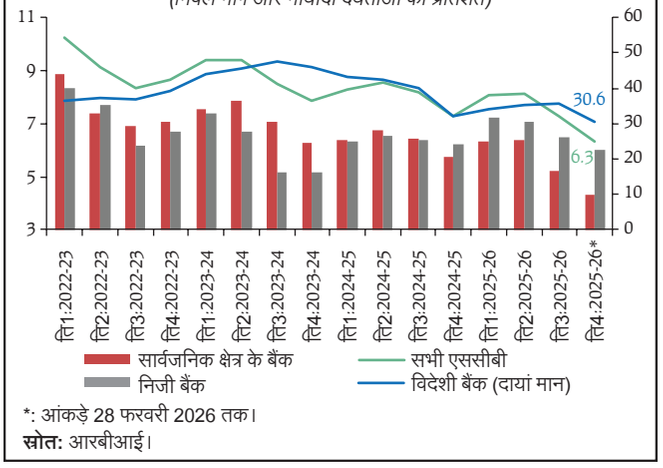

*: आंकड़े 28 फरवरी 2026 तक।

स्रोत: आरबीआई।

बैंक ऋण: एक क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

क्षेत्रीय रुझान[9] प्रमुख क्षेत्रों में ऋण वृद्धि के मजबूत होने का संकेत देते हैं। औद्योगिक ऋण वृद्धि अपने दीर्घकालिक औसत से ऊपर बनी रही, जिससे समग्र ऋण विस्तार को समर्थन मिला। हालांकि व्यक्तिगत ऋण की वृद्धि अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे रही, लेकिन हाल ही में इसमें तेजी आई है (सारणी II.7 और चार्ट II.25ए)। व्यक्तिगत ऋण और सेवा क्षेत्र को जारी ऋण ने समग्र ऋण वृद्धि को आगे बढ़ाना जारी रखा (चार्ट II.25ए और II.25बी)।

औद्योगिक क्षेत्र में, एमएसएमई[10] क्षेत्र को दिए गए ऋण में उछाल बना रहा, वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में

सारणी II.7: ऋण वृद्धि

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

क्षेत्र / उप-क्षेत्र	औसत*	कोविड के पश्चात **	नवं-23	मार्च-24	सितं-24	दिसं-24	फर-25	मार्च-25	जून-25	सितं-25	दिसं-25	जन-26	फर-26
बैंक ऋण*	**11.1**	**14.8**	**20.7**	**20.2**	**13.0**	**11.2**	**11.1**	**11.0**	**9.5**	**10.4**	**14.5**	**14.6**	**14.5**
बैंक ऋण का क्षेत्रीय परिनियोजन													
कृषि (13.0)	**11.4**	**14.2**	**18.1**	**20.0**	**16.4**	**12.5**	**11.4**	**10.4**	**6.8**	**9.0**	**12.1**	**11.4**	**12.3**
उद्योग (22.7)	**4.6**	**8.6**	**6.9**	**9.4**	**10.0**	**7.5**	**7.5**	**8.2**	**6.3**	**7.8**	**12.8**	**12.1**	**13.5**
सूक्ष्म और लघु (5.3)	9.8	17.7	17.9	15.8	14.5	9.8	9.6	8.9	19.2	22.0	30.4	31.2	30.4
मध्यम (2.2)	14.4	19.3	12.9	14.2	21.4	19.8	18.0	18.5	13.2	14.5	20.4	22.3	21.0
एमएसएमई (7.5)	10.9	18.1	16.4	15.3	16.5	12.8	12.1	11.8	17.4	19.7	27.3	28.5	27.5
बृहद (15.2)	2.8	5.3	3.7	7.2	7.5	5.5	5.6	6.9	2.0	3.0	6.9	5.5	7.8
बुनियादी अवसंरचना (7.4)	4.0	5.2	4.1	8.5	4.4	1.6	1.7	2.8	0.8	5.0	7.2	6.4	7.9
सेवाएं (29.6)	**14.1**	**17.2**	**24.5**	**22.3**	**12.4**	**11.5**	**11.7**	**12.0**	**8.8**	**9.8**	**15.4**	**15.5**	**16.3**
एनबीएफसी से इतर सेवाएं (19.7)	**12.6**	**17.6**	**27.5**	**27.3**	**14.0**	**14.1**	**13.5**	**14.4**	**11.7**	**12.7**	**15.6**	**14.4**	**14.0**
एनबीएफसी (9.9)	19.6	16.6	19.2	13.4	9.4	6.5	8.1	7.4	3.1	3.9	15.1	17.8	20.9
व्यक्तिगत ऋण (34.7)	**17.7**	**19.1**	**30.4**	**27.8**	**13.8**	**12.0**	**11.7**	**11.7**	**11.7**	**11.8**	**14.6**	**14.9**	**15.2**
अपरिवर्तित जोखिम भार के साथ व्यक्तिगत ऋण (23.6)	**17.3**	**19.2**	**32.2**	**31.5**	**13.9**	**12.9**	**13.5**	**13.5**	**13.9**	**14.1**	**17.1**	**17.5**	**17.6**
आवास (प्राथमिकता क्षेत्र आवास सहित) (16.9)	16.7	18.8	36.7	36.5	12.6	11.1	11.1	10.7	9.6	10.1	11.1	11.1	11.0
वाहन ऋण (3.7)	18.0	15.2	20.6	17.6	13.9	8.8	9.6	8.6	9.2	7.3	16.7	17.1	17.1
शिक्षा (0.8)	8.5	16.2	23.0	23.7	17.6	15.8	15.3	15.1	14.4	14.0	14.8	14.0	13.7
बढ़े हुए जोखिम भार के साथ व्यक्तिगत ऋण (11.1)	**18.8**	**19.0**	**27.1**	**21.3**	**13.5**	**10.4**	**8.4**	**8.3**	**7.5**	**7.1**	**9.8**	**10.0**	**10.4**
क्रेडिट कार्ड (1.5)	24.2	21.2	34.2	25.6	18.0	15.6	11.2	10.6	7.2	3.7	1.0	1.5	1.7
अन्य व्यक्तिगत ऋण(8.7)	20.3	18.9	27.3	22.8	13.1	8.8	7.6	7.5	7.1	7.4	11.5	11.6	12.1

टिप्पणियाँ: 1. आंकड़े अनंतिम है।
2. *: मार्च 2016 से फरवरी 2026 तक वृद्धि का सरल औसत।
3. **: अप्रैल 2022 से जनवरी 2026 तक वृद्धि का सरल औसत।
4. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए कुल गैर-खाद्य ऋण में हिस्सेदारी को दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई।

[9] गैर-खाद्य ऋण वृद्धि साप्ताहिक धारा-42 विवरणी पर आधारित है, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को शामिल करता है, जबकि क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) विवरणी पर आधारित है, जिसमें ऐसे चयनित बैंक शामिल हैं जिनके द्वारा कुल बकाया गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत ऋण प्रदत्त किया गया है। 31 दिसंबर 2025 से प्रभावी, बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत अंतिम रिपोर्टिंग पखवाड़े की परिभाषा को महीने के अंतिम दिन के रूप में बदल दिया गया है। तदनुसार, दिसंबर 2025 से आगे की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दरें चालू वर्ष के महीने के अंत के आंकड़ों और पिछले वर्ष के संबंधित महीने के लिए अंतिम रिपोर्टिंग पखवाड़े के आंकड़ों (पुरानी परिभाषा के अनुसार) पर आधारित हैं।

[10] उद्योग के भीतर सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्गों को ऋण से संबंधित है।

चार्ट II.25: बैंक ऋण का क्षेत्रीय परिनियोजन

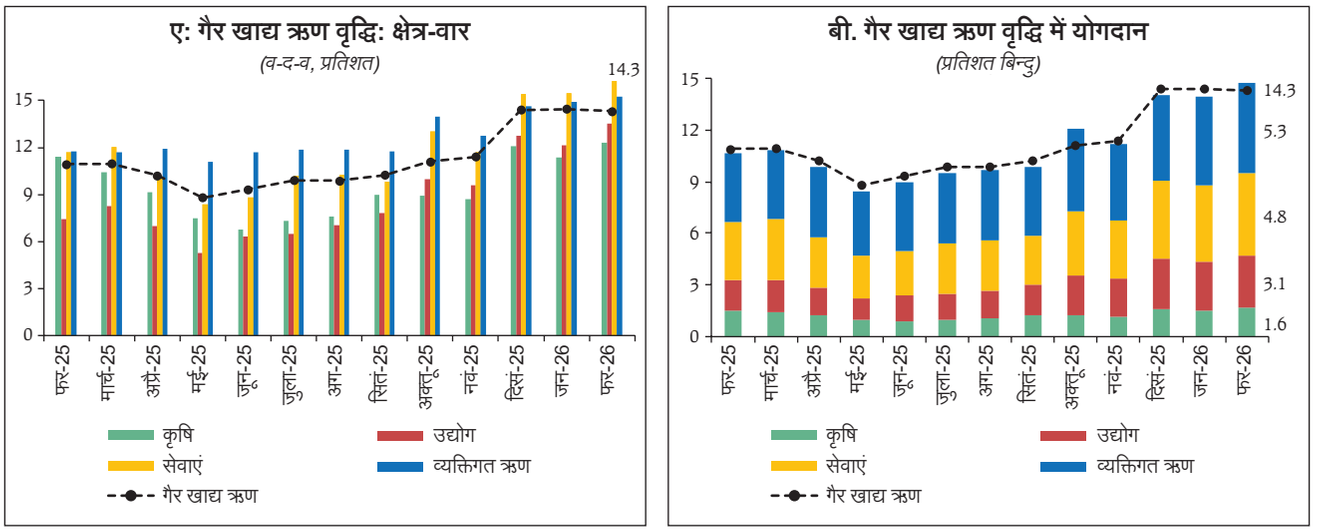

टिप्पणी: गैर-खाद्य ऋण के आंकड़े साप्ताहिक धारा-42 विवरणी पर आधारित है और क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण आंकड़े एसआईबीसी विवरणी पर आधारित हैं।
स्रोत: आरबीआई।

अब तक[11] इसमें उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई और कुल ऋण वृद्धि में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा (चार्ट II.26ए)। एमएसएमई के ऋण प्रवाह को अन्य उपायों के साथ-साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) योजना के तहत बढ़ी हुई सीमा, सूक्ष्म उद्यमों के लिए आवश्यकतानुरूप क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत, बैंकों के साथ को-लेंडिंग फ्रेमवर्क के माध्यम से डिजिटल और फिनटेक ऋण विस्तार, और एमएसएमई की अद्यतन परिभाषा सरीखे विनियामकीय उपायों द्वारा समर्थन मिला।।

मुख्य औद्योगिक उप-क्षेत्रों में, बुनियादी संरचना क्षेत्र को मिलने वाली ऋण वृद्धि हाल के महीनों में मजबूत हुई, जिसका कुल औद्योगिक ऋण विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके

चार्ट II.26: औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वृद्धि

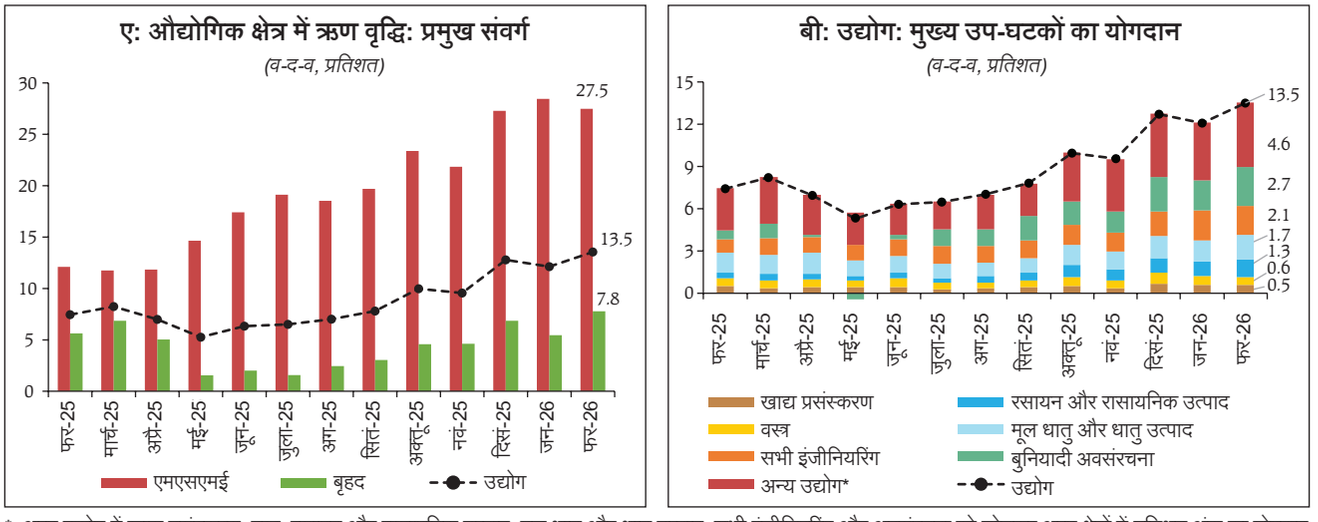

*: अन्य उद्योग में खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, रसायन और रासायनिक उत्पाद, मूल धातु और धातु उत्पाद, सभी इंजीनियरिंग और अवसंरचना को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में प्रतिशत अंक का योगदान शामिल है।
स्रोत: आरबीआई।

[11] वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के आंकड़े फरवरी 2026 तक है।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

सारणी II.8: उद्योग के प्रमुख उप-क्षेत्रों में ऋण वृद्धि

(व-द-व, प्रतिशत)

क्षेत्र	फर-25	मार्च-25	जून-25	सितं-25	दिसं-25	जन-26	फर-26
बुनियादी अवसंरचना	1.7	2.8	0.8	5.0	7.2	6.4	7.9
मूल धातु और धातु उत्पाद	13.1	12.8	11.0	9.1	14.2	13.8	15.2
वस्त्र	7.1	8.3	8.6	7.1	11.8	10.0	8.2
रसायन और रासायनिक उत्पाद	6.8	7.4	6.3	8.3	14.8	15.1	19.1
सभी इंजीनियरिंग	18.9	22.0	22.1	22.4	30.4	35.9	36.0
खाद्य प्रसंस्करण	9.3	5.1	8.1	7.7	11.7	9.6	10.2

निम्न ← → उच्च

टिप्पणी: एक पंक्ति में, गहरे हरे रंग का मतलब ऋण वृद्धि में तेजी है, जबकि लाल रंग क्रेडिट वृद्धि में धीमापन को दर्शाता है।

स्रोत: आरबीआई

अतिरिक्त मूल धातु और धातु उत्पाद, रसायन और रासायनिक उत्पाद तथा इंजीनियरिंग में ऋण वृद्धि में निरंतर सुधार दिखाई दिया (चार्ट II.26बी और सारणी II.8)।

सेवा क्षेत्र के भीतर, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफ़सी) बैंक ऋण की सबसे बड़ी प्राप्तकर्ता बनी रहीं, 01 अप्रैल 2025 से अतिरिक्त जोखिम भार को समाप्त करने के बाद एनबीएफ़सी को ऋण प्रदान करने में सुधार हुआ (चार्ट II.27)। एनबीएफ़सी के अलावा अन्य सेवाओं को मिलने वाला ऋण भी स्थिर गति से बढ़ा। वाणिज्य और व्यावसायिक रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भी मजबूत ऋण वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट II.27 और सारणी II.9)।

सारणी II.9: जोखिम भार में परिवर्तन का ऋण वृद्धि पर प्रभाव

(व-द-व, प्रतिशत)

क्षेत्र	फर-25	मार्च-25	जून-25	सितं-25	दिसं-25	जन-26	फर-26
कुल व्यक्तिगत ऋण (जोखिम भार में बदलाव के साथ)	8.4	8.3	7.5	7.1	9.8	10.0	10.4
एनबीएफसी (जोखिम भार में बदलाव के साथ)*	8.1	7.4	3.1	3.9	15.1	17.8	20.9
कुल व्यक्तिगत ऋण (जोखिम भार में कोई बदलाव नहीं)	13.5	13.5	13.9	14.1	17.1	17.5	17.6
एनबीएफसी को छोड़कर सेवाएं (जोखिम भार में कोई बदलाव नहीं)	13.5	14.4	11.7	12.7	15.6	14.4	14.0

निम्न ← → उच्च

टिप्पणियाँ: 1. *एनबीएफसी के लिए जोखिम भार अप्रैल 2025 में पुनर्स्थापित किए गए थे।
2. एक पंक्ति के भीतर, गहरे हरे रंग का अर्थ है ऋण वृद्धि में तेजी, जबकि लाल का अर्थ है ऋण वृद्धि में मंदी।

स्रोत: आरबीआई

वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान व्यक्तिगत ऋण संवर्ग में ऋण वृद्धि मुख्य रूप से आवासीय ऋण, वाहन ऋण और सोने के आभूषण की जमानत पर लिए गए ऋण के कारण रही (चार्ट II.28)। व्यक्तिगत ऋण के दोनों क्षेत्रों में, यानि जोखिम भार में परिवर्तन और बिना परिवर्तन में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई (सारणी II.9)। जोखिम भार में वृद्धि का प्रभाव प्रमुख क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों में धीरे-धीरे कम हुआ है। निरंतर आर्थिक विकास से बैंक ऋण की मांग में वृद्धि दर्ज की गई।

चार्ट II.27: सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि: प्रमुख उप-घटकों का योगदान

(प्रतिशत अंक)

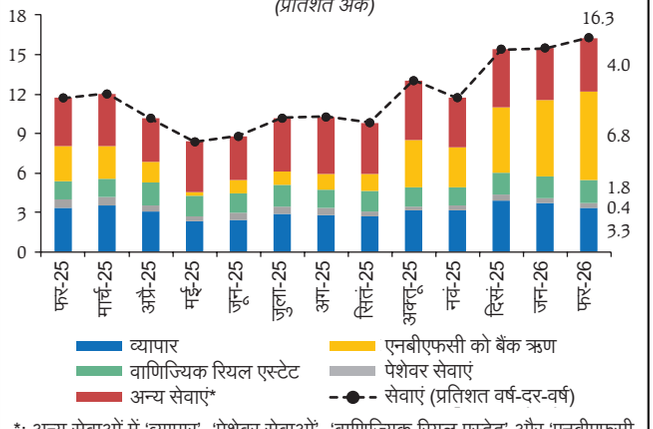

*: अन्य सेवाओं में 'व्यापार', 'पेशेवर सेवाओं', 'वाणिज्यिक रियल एस्टेट' और 'एनबीएफसी को बैंक ऋण' को छोड़कर सभी सेवाएं शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट II.28: व्यक्तिगत ऋण: प्रमुख उप-घटकों का योगदान

(प्रतिशत अंक)

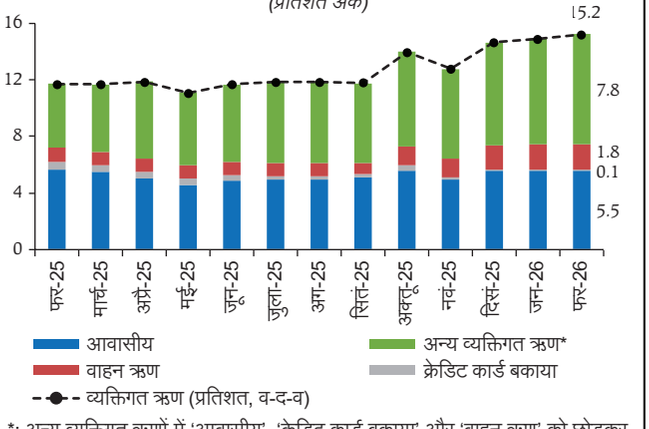

*: अन्य व्यक्तिगत ऋणों में 'आवासीय', 'क्रेडिट कार्ड बकाया' और 'वाहन ऋण' को छोड़कर सभी व्यक्तिगत ऋण शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई।

एनबीएफसी ऋण[12]

एनबीएफसी द्वारा प्रदान किया जाने वाला ऋण भी सितंबर 2025 के बाद से मजबूत हुआ है, और इसमें निरंतर दो अंकीय वृद्धि दर्ज की गई। खुदरा ऋण ने समग्र वृद्धि को बढ़ावा देना जारी रखा, जिसमें आवास और वाहन ऋण प्रमुख रहे। औद्योगिक ऋण में स्थिर वृद्धि दिखाई दी, जिसमें बुनियादी संरचना और विशेष रूप से पावर क्षेत्र को अधिक उधारी शामिल है, जो अर्थव्यवस्था में विशिष्ट क्षेत्रों को औपचारिक ऋण प्रदान करने में एनबीएफसी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही (फरवरी तक) के दौरान सेवा क्षेत्र को दिए गए एनबीएफ़सी ऋण में भी अच्छी गति से वृद्धि हुई (चार्ट II.29 और सारणी II.10)।

चार्ट II.29: एनबीएफसी ऋण वृद्धि का क्षेत्रवार योगदान

(प्रतिशत अंक)

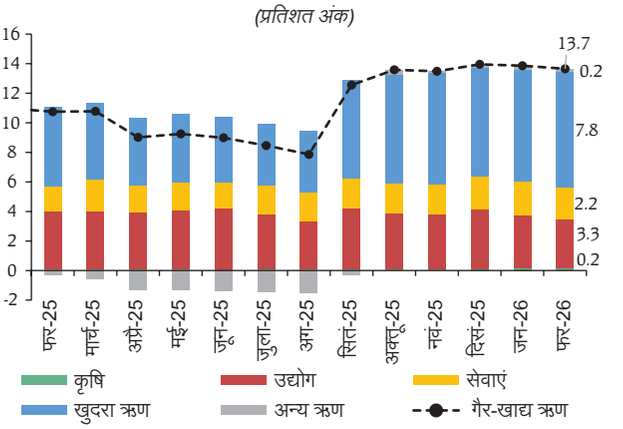

टिप्पणी: अन्य ऋणों में कृषि, उद्योग, सेवाओं, खुदरा ऋणों और एचएफसी से गैर-आवासीय ऋणों के अलावा एनबीएफसी से प्राप्त अन्य ऋण शामिल हैं।
स्रोत: राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी); और आरबीआई।

सारणी II.10: एनबीएफसी (एचएफसी सहित) द्वारा क्षेत्रवार ऋण वृद्धि

(व-द-व, प्रतिशत)

क्षेत्र	औसत*	फर-25	मार्च-25	जून-25	सितं-25	दिसं-25	जन-26	फर-26
एनबीएफसी ऋण								
कृषि और सहायक गतिविधियाँ (1.3)								
उद्योग (38.6)	**10.9**	**9.5**	**9.7**	**10.3**	**10.2**	**9.8**	**8.9**	**8.1**
जिसमें से								
बुनियादी अवसंरचना (35.4)	10.1	8.7	9.2	9.1	9.4	8.9	8.0	7.1
जिसमें से								
पावर (24.9)	12.5	12.3	12.2	13.3	11.5	10.1	9.2	7.8
सड़क (0.9)	18.3	31.4	27.7	6.7	7.6	7.6	7.7	5.4
सेवाएं (12.2)	**18.8**	**13.8**	**17.4**	**14.2**	**15.8**	**19.6**	**19.4**	**18.8**
जिसमें से								
परिवहन ऑपरेटर *(3.0)*	14.7	12.8	12.5	10.9	9.3	9.0	8.6	9.8
व्यापार (2.0)	25.9	26.9	25.1	18.3	13.3	16.2	15.7	22.3
खुदरा ऋण (42.6)	**8.7**	**13.6**	**13.1**	**11.0**	**16.6**	**18.1**	**18.7**	**19.2**
जिसमें से								
*खुदरा ऋण (14.4)***	-5.7	4.2	4.7	0.4	9.3	10.7	10.2	10.0
वाहन ऋण (10.6)	18.3	17.9	16.8	14.8	14.9	14.3	14.3	14.1
सोने के आभूषणों की जमानत पर ऋण (5.3)	27.2	29.0	32.2	40.6	50.7	61.2	68.1	71.9
टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं (1.0)	26.1	25.2	24.0	18.8	22.2	23.3	26.4	28.8
अन्य ऋण (5.3)* **	**-10.6**	**-4.8**	**-8.0**	**-19.5**	**-4.6**	**4.2**	**4.4**	**3.5**

टिप्पणियाँ: 1. अनंतिम आंकड़े।
2. जनवरी 2023 से फरवरी 2026 तक की वृद्धि का साधारण औसत।
3. **: आवासीय ऋण के आंकड़ों में आवास वित्त कंपनी (एचएफ़सी) से प्राप्त ऋण भी शामिल
4. ***: अन्य ऋणों में 'कृषि', 'उद्योग', 'सेवाएं', 'खुदरा ऋण', और एचएफसी से 'गैर-आवासीय ऋण' के इतर अन्य सभी एनबीएफसी ऋण शामिल हैं।
5. आंकड़ों में कुछ एनबीएफसी के व्यवसाय की प्रकृति में बदलाव का प्रभाव शामिल है।
6. कोष्टक में दिए गए आंकड़े कुल एनबीएफ़सी ऋण में हिस्सेदारी को दर्शाते हैं।

स्रोत: राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी); और आरबीआई।

[12] चयनित एनबीएफसी सहित एचएफसी से बकाया ऋण के क्षेत्रीय वितरण के आंकड़े प्रत्येक महीने के अंतिम दिन से संबंधित है। प्रायोगिक कार्य के रूप में, चयनित एनबीएफ़सी से मासिक क्षेत्रीय ऋण जानकारी संग्रहित करना शुरू किया गया है। 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2024-25' में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार ये एनबीएफसी, एचएफसी सहित ऊपरी और मध्यम स्तरों में सभी एनबीएफसी द्वारा प्रदान किए गए सभी ऋण का 87 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

II.3 उधार और जमा दरों में संचरण

वर्तमान नरमी के दौर (फरवरी 2025 से) में नीतिगत दर का संचरण वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में जारी रहा, जिसमें उधार और जमा दोनों ही दरें कम हुई। दिसंबर 2025 में नीतिगत दर में 25 आधार अंको (बीपीएस) की कटौती से संचयी तौर पर 125 आधार अंकों की कटौती हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की 1 वर्ष की माध्यिका 2025-26 की दूसरी छमाही में 20 आधार अंक घट गई। दूसरी छमाही में (फरवरी 2026 तक) नए रुपये आधारित ऋण पर औसत भारित उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) 5 आधार अंक बढ़ गई, जो मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में ऋण की मात्रा में संरचनात्मक बदलाव को दर्शाती है जहां अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दरें लागू होती हैं, जबकि बकाया ऋणों के लिए यह 26 आधार अंक घट गई। जमा पक्ष पर, वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में (फरवरी 2026 तक) बकाया जमा पर भारित औसत घरेलू अवधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) 20 आधार अंक घट गई, जबकि नई जमा के लिए यह 4 आधार अंक बढ़ गई (सारणी II.11)। सतत ऋण मांग और ऋण तथा जमा वृद्धि के बीच लगातार अंतर के संयोजन ने बैंकों को अपने मीयादी जमा दरों, विशेष रूप से थोक जमा दरों में वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया, ताकि हाल के महीनों में वित्तपोषण अंतर को पाटा जा सके।

मौजूदा नरमी के दौर में (फरवरी 2026 तक) बकाया ऋणों के लिए डब्ल्यूएएलआर में 87 बीपीएस की गिरावट आई। नए रुपया ऋणों के लिए, डब्ल्यूएएलआर में 89 बीपीएस की गिरावट आई। मूल्य निर्धारण का एक बेहतर पैमाना माने जाने वाले 'ब्याज दर प्रभाव' में 92 बीपीएस की गिरावट आई, जो नए ऋणों की दरों में मज़बूत संचरण को दर्शाता है। ब्याज दर प्रभाव की तुलना में डब्ल्यूएएलआर में कम नरमी, बैंकों और विभिन्न क्षेत्रों में, उच्च ब्याज दर वाले ऋणों की ओर संरचना-मिश्रण में बदलाव का संकेत देती है (बॉक्स II.2)।

एससीबी के कुल बकाया अस्थिर दर ऋण में, बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दर (ईबीएलआर) से जुड़े ऋण का हिस्सा जून 2025 के अंत में 62.9 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2025 के अंत में 65.4 प्रतिशत हो गया। इसके परिणामस्वरूप, इसी अवधि के दौरान एमसीएलआर से जुड़े ऋण का हिस्सा 33.8 प्रतिशत से घटकर 32.0 प्रतिशत रह गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों

सारणी II.11: बैंकों की जमा राशियों एवं ऋण दरों में संचरण

(आधार अंक)

अवधि	रेपो दर	मीयादी जमा दर			ऋण दर				
		डब्ल्यूएडीटीडीआर नई जमाराशियां		डब्ल्यूएडीटीडीआर (बकाया जमाराशियां)	ईबीएलआर	1-वर्षीय एमसीएलआर (माध्य)	डब्ल्यूएएलआर नए रुपया ऋण		डब्ल्यूएएलआर बकाया रुपया ऋण
		खुदरा जमाराशियां	खुदरा और थोक जमाराशियां	खुदरा और थोक जमाराशियां			समग्र प्रभाव	ब्याज दर प्रभाव#	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
सख्ती का चक्र मई 2022 से जनवरी 2025	+250	190	259	206	250	175	182	191	115
नरमी का चक्र फरवरी 2025 से मार्च 2026*	**-125**	**-77**	**-97**	**-47**	**-125**	**-60**	**-89**	**-92**	**-87**
मेमो									
छ2: 2025-26*	-25	-6	4	-20	-25	-20	5	-14	-26
दिसं – 2025	-25	-4	8	-5	-25	-5	-43	-12	-15
जन – 2026	0	-4	-1	-4	0	-5	21	3	-2
फर – 2026	0	-3	-1	-2	0	5	-5	-1	-4

टिप्पणियाँ: 1. डब्ल्यूएएलआर और डब्ल्यूएडीटीडीआर से संबंधित डेटा फरवरी 2026 तक का है। #: स्थिर भार पर।
2. ईबीएलआर से संबंधित आँकड़े 32 घरेलू बैंकों के हैं।

डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर; डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर; एमसीएलआर: निधियों की सीमांत लागत-आधारित उधार दर; ईबीएलआर : बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दर।

स्रोत: एमपीडी06 विवरणी; और आरबीआई।

बॉक्स II.2: उधार दरों तक मौद्रिक नीति संचरण का विघटन: डब्ल्यूएएलआर में कीमत और संरचना प्रभाव

भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर), जिसका उपयोग आमतौर पर मौद्रिक नीति के संचरण का आकलन करने के लिए किया जाता है, उधार दरों में होने वाले परिवर्तनों और बैंकों तथा विभिन्न क्षेत्रों में ऋण की संरचना में आए बदलावों दोनों को दर्शाती है। डब्ल्यूएएलआर को निवल मूल्य प्रभाव और ऋण के पुनर्वितरण के कारण होने वाले परिवर्तनों में विभाजित करने से नीति के प्रभाव के अधिक सटीक मूल्यांकन में सहायता मिलती है। हर्गा और स्टेक्लाकोवा (2008) एक सूचकांक संख्या-आधारित ढांचा प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कुल ब्याज दर में होने वाले बदलावों को पुनर्मूल्यांकन और संरचना प्रभावों में विभाजित किया जा सकता है। इसी अंतर्दृष्टि के आधार पर, यह विश्लेषण सूचकांक- संख्या सिद्धांत का उपयोग करके डब्ल्यूएएलआर का विश्लेषण करता है।

मान लीजिए कि महीने t में बैंक i द्वारा क्षेत्र j से ली जाने वाली उधार दर को दर्शाता है, और संबंधित ऋण राशि को दर्शाता है। संबंधित ऋण हिस्से को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

$$\theta_{i,j}^{t} = \frac{w_{i,j}^{t}}{\sum_{i,j} w_{i,j}^{t}}$$

समय t पर डब्ल्यूएएलआर इस प्रकार दिया गया है:

$$walr_t = \sum_{i,j} \theta_{i,j}^{t} * r_{i,j}^{t}$$

मौद्रिक नीति संचरण, अर्थात् अवधि 1 और 2 के बीच डब्ल्यूएएलआर में परिवर्तन को इस प्रकार लिखा जा सकता है:

$$\Delta walr = \sum_{i,j} \theta_{i,j}^{2} * r_{i,j}^{2} - \sum_{i,j} \theta_{i,j}^{1} * r_{i,j}^{1}$$

को जोड़ने और घटाने, तथा पुनर्व्यवस्थित करने पर, $\sum_{i,j} \theta_{i,j}^{1} * r_{i,j}^{2}$

इस परिवर्तन को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है:

$$\Delta walr = \sum_{i,j} \theta_{i,j}^{1} * (r_{i,j}^{2} - r_{i,j}^{1}) + \sum_{i,j} r_{i,j}^{2} * (\theta_{i,j}^{2} - \theta_{i,j}^{1})$$

पहला पद ब्याज दर प्रभाव को दर्शाता है, जो आधार अवधि (अवधि 1) में ऋण हिस्सेदारी को स्थिर रखते हुए उधार दरों में हुए परिवर्तनों के योगदान को मापता है। दूसरा पद संरचना प्रभाव को दर्शाता है, जो बैंकों और क्षेत्रों के बीच ऋण हिस्सेदारी या उत्पाद-मिश्रण में हुए बदलावों को प्रतिबिंबित करता है। यह विघटन विभिन्न स्तरों (आधार बिंदुओं) पर किया जाता है, जिससे कुल डब्ल्यूएएलआर में परिवर्तन में योगदान की सीधी व्याख्या संभव हो जाता है। इसलिए,

सारणी 1: भारित औसत उधार दरों का विघटन (फरवरी 2025 - फरवरी 2026)

	हिस्सेदारी (प्रतिशत)		डब्ल्यूएएलआर (प्रतिशत)			संचरण (बीपीएस)		
क्षेत्र	**जन-25**	**फर -26**	**जन -25**	**फर -26**	**फर -26 (स्थिर)**	**समग्र**	**ब्याज दर प्रभाव**	**भार प्रभाव**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (5)-(4)	(8)= (6)-(4)	(9)=(7)-(8)
कृषि	10.9	12.9	10.29	9.76	10.06	-53	-23	-30
बड़े उद्योग	31.0	28.6	8.08	7.04	7.00	-104	-108	4
एमएसएमई	9.7	12.7	9.94	8.76	8.83	-118	-111	-7
बुनियादी ढांचा	3.6	3.4	8.55	7.39	7.59	-116	-96	-20
व्यापार	9.8	8.5	8.38	7.57	7.48	-81	-90	9
व्यावसायिक सेवाएं	2.6	2.1	8.75	8.04	8.05	-71	-70	-1
क्रेडिट कार्ड	0.9	0.7	37.87	37.15	37.63	-72	-24	-48
शिक्षा	0.2	0.1	10.76	9.52	9.68	-124	-108	-16
वाहन	2.3	2.0	10.67	9.60	9.84	-107	-83	-24
आवास	5.6	4.9	8.70	7.61	7.63	-109	-107	-2
अन्य व्यक्तिगत ऋण	9.4	11.3	11.27	10.24	10.38	-103	-89	-14
रुपया निर्यात ऋण	2.0	1.5	8.39	7.30	7.25	-109	-114	5
अन्य	12.0	11.3	8.86	7.87	7.90	-99	-96	-3
सकल	**100.0**	**100.0**	**9.33**	**8.44**	**8.41**	**-89**	**-92**	**3**

टिप्पणियाँ: 1. भार कुल ऋणों में से ऋणों का संबंधित हिस्सा है।

2. फरवरी 2025 से फरवरी 2026 के दौरान संचरण की गणना, फरवरी 2026 के डब्ल्यूएएलआर में से जनवरी 2025 के डब्ल्यूएएलआर को घटाकर की गई है।

स्रोत: एमपीडी06 विवरणी, आरबीआई; और आरबीआई स्टाफ की गणनाएं।

(जारी...)

मौद्रिक नीति वक्तव्य

डब्ल्यूएएलआर में उतार-चढ़ाव केवल मूल्य निर्धारण व्यवहार को ही प्रतिबिंबित नहीं कर सकते; क्योंकि ऋण आवंटन में संरचनात्मक परिवर्तन प्रेक्षित संचरण को बढ़ा या घटा सकते हैं। अतः, विघटन-आधारित निदान मौद्रिक नीति संचरण और उससे संबंधित विलंबों के आकलन को बेहतर बनाते हैं।

क्षेत्रवार डब्ल्यूएएलआर की गणना बैंक-स्तरीय डेटा को इकट्ठा करके की गई है, जिसका उपयोग बाद में पूरे प्रणाली के डब्ल्यूएएलआर निकालने के लिए किया जाता है। अवधि 1 (जनवरी 2025) में डब्ल्यूएएलआर 9.33 प्रतिशत था, जो अवधि 2 (फरवरी 2026) में घटकर 8.44 प्रतिशत हो गया। इसका मतलब यह है कि भारित औसत के आधार पर, बैंकों ने पॉलिसी दर में 125 बीपीएस की कटौती के मुकाबले अपनी उधार दरों में 89 बीपीएस की कमी की है। हालाँकि, जब डब्ल्यूएएलआर में हुए बदलाव को ब्याज दर प्रभाव और मात्रा में संरचनात्मक बदलाव (भार प्रभाव) में बाँटा जाता है; तो निवल ब्याज दर संचरण (-) 92 बीपीएस होता है, जो समग्र डब्ल्यूएएलआर में आई गिरावट से अधिक है। इस प्रकार, उधार देने की प्रक्रिया में हुआ संरचनात्मक बदलाव विपरीत दिशा में काम किया और ब्याज दर प्रभाव के असर को 3 बीपीएस तक कम कर दिया।

उक्त परिणाम दर्शाते हैं कि यद्यपि सभी क्षेत्रों में उधार दरों में गिरावट आई है, फिर भी अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दर वाले क्षेत्रों की ओर उधार देने में बदलाव भार प्रभाव के माध्यम से इस कमी को आंशिक रूप से संतुलित कर सकता है। परिणामस्वरूप, डब्ल्यूएएलआर में देखा गया परिवर्तन छोटा प्रतीत हो सकता है, जो नीति के कमजोर संचरण का संकेत देता है। इसलिए, डब्ल्यूएएलआर में परिवर्तन को ब्याज दर और भार प्रभावों में विभाजित करने से संचरण का अधिक यथार्थवादी आकलन प्राप्त होता है। संक्षेप में, मौद्रिक नीति का संचरण न केवल उधार दर में परिवर्तन पर बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में संरचना मिश्रण में परिवर्तन पर भी निर्भर करता है।

संदर्भ:

हर्गा, जे. और स्टेक्लाकोवा, एल. (2008)। ब्याज दरों पर सूचकांक संख्या सिद्धांत का एक अनुप्रयोग। ईसीबी वर्किंग पेपर संख्या 939, 22 सितंबर।

(पीएसबी) के ऋण का एक बड़ा हिस्सा अभी भी एमसीएलआर से जुड़ा हुआ है (चार्ट II.30ए)। निजी बैंक (पीवीबी) अपने ऋण का एक बड़ा हिस्सा ईबीएलआर से जोड़कर` देते हैं (चार्ट II.30बी)। बाह्य बेंचमार्क-आधारित ऋणों का अधिकतर हिस्सा बेंचमार्क के तौर पर नीति रेपो दर का इस्तेमाल करता है। एमसीएलआर और अन्य पुरानी दरें – जो आंतरिक बेंचमार्क पर आधारित हैं और जिनकी पुनःस्थापन अवधि लंबी होती है – त्वरित नीति संचरण में रुकावट डालती हैं।

क्षेत्रीय रूप से, पीएसबी के पास कृषि, बड़े उद्योग, बुनियादी ढांचा और अन्य व्यक्तिगत ऋणों में एमसीएलआर संबद्ध ऋणों का उच्च हिस्सा है (चार्ट II.31ए)। पीवीबी के लिए, एमसीएलआर-

चार्ट II.30: ब्याज दर बेंचमार्क का बैंक समूह-वार हिस्सा

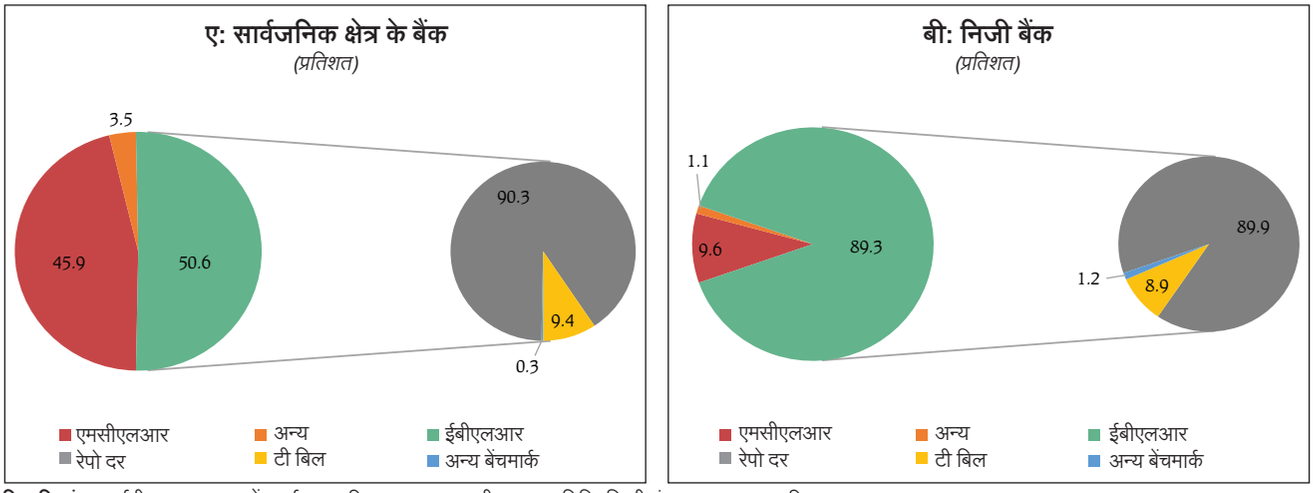

टिप्पणियां: 1. ईबीएलआर : बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दर; एमसीएलआर : निधि की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर।
2. यह डेटा दिसंबर 2025 तक के बकाया अस्थिर दर वाले रुपया ऋणों से संबंधित है।
3. 'अन्य' में बेंचमार्क मूल उधार दर, आधार दर और अन्य आंतरिक बेंचमार्क शामिल हैं।

स्रोत: *तदर्थ* सर्वेक्षण, एमपीडी।

चार्ट II.31: ब्याज दर बेंचमार्क का क्षेत्र-वार हिस्सा

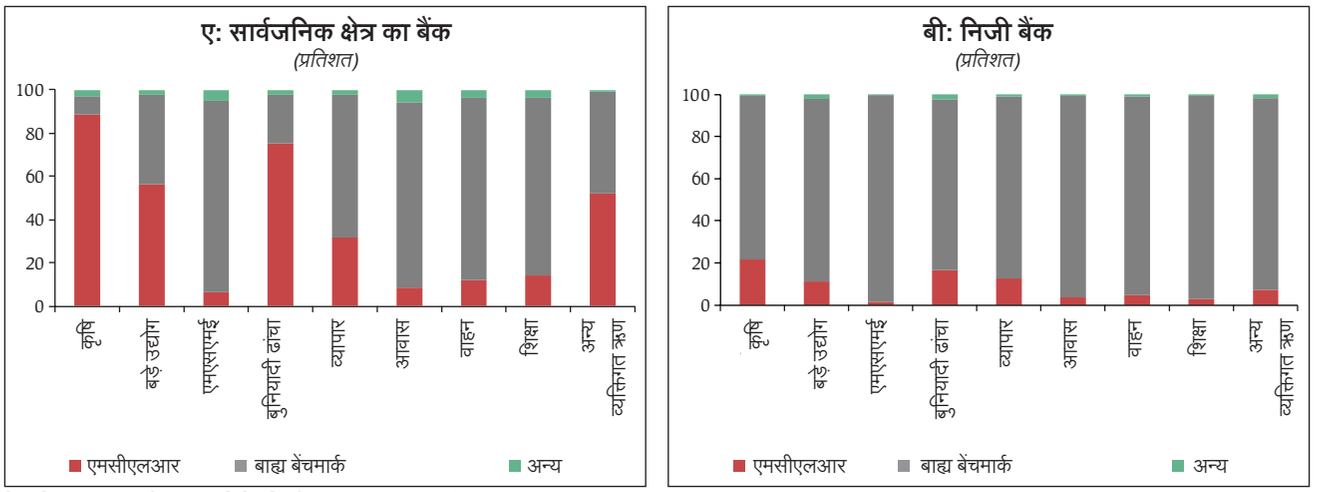

टिप्पणियां: 1. एमसीएलआर: निधि की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर।
2. यह डेटा दिसंबर 2025 के अंत तक के बकाया अस्थिर दर वाले रुपया ऋणों से संबंधित है।
3. 'अन्य' में बेंचमार्क मूल उधार दर, आधार दर और अन्य आंतरिक बेंचमार्क शामिल हैं।

स्रोत: *तदर्थ* सर्वेक्षण, एमपीडी।

संबद्ध ऋणों का हिस्सा सभी क्षेत्रों में कम है (चार्ट II.31बी)। एमसीएलआर-संबद्ध ऋणों का उच्च हिस्सा संचरण की गति को धीमा कर देता है।

बैंक समूह के अनुसार, पीवीबी के नए और बकाया रुपया ऋणों का डब्ल्यूएएलआर में संचरण पीएसबी की तुलना में अधिक था (चार्ट II.32ए)। ईबीएलआर-आधारित ऋणों के बड़े हिस्से के कारण पीवीबी में संचरण अधिक रहा। हालाँकि, पीवीबी की उधार दरें पीएसबी की दरों से ज़्यादा रहीं (चार्ट II.32बी)। उधार दरों में सबसे ज़्यादा संचरण विदेशी बैंकों में देखा गया, जो ईबीएलआर-सम्बद्ध ऋणों[13] में उनकी उच्च हिस्सेदारी को दर्शाता है।

चार्ट II.32: बैंक समूहवार उधार दरें और संचरण

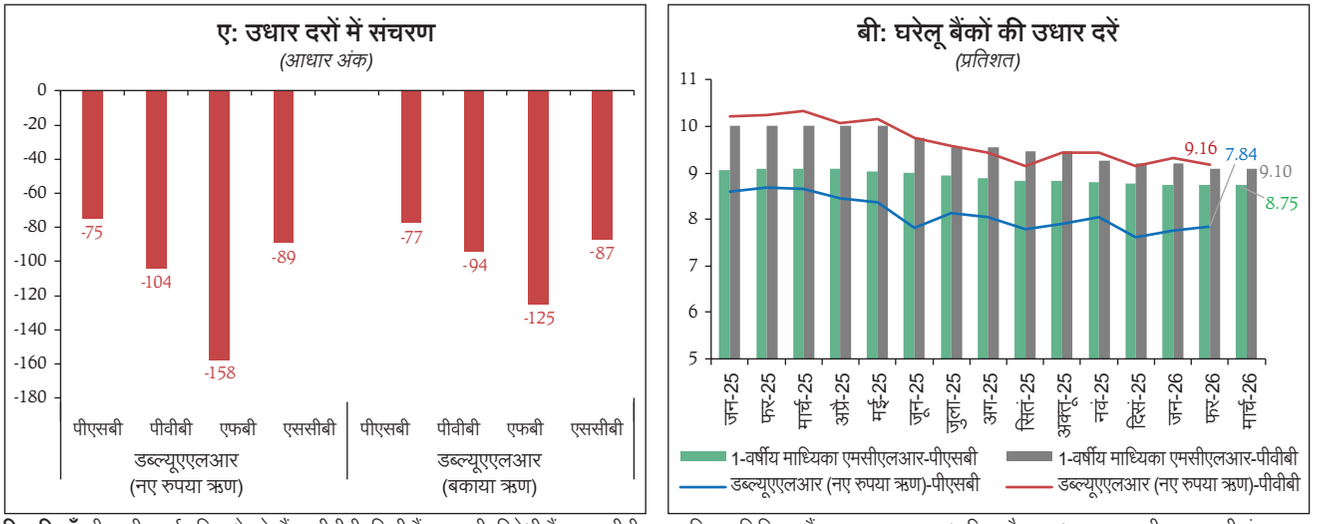

टिप्पणियाँ: पीएसबी: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक; पीवीबी: निजी बैंक; एफबी: विदेशी बैंक; एससीबी: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक; डब्ल्यूएएलआर:भारित औसत उधार दर; एमसीएलआर:सीमांत लागत आधारित उधार दर।

स्रोत: आरबीआई।

[13] दिसंबर 2025 के अंत तक, बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दर से जुड़े ऋणों का अनुपात विदेशी बैंकों (94.0 प्रतिशत) के लिए सबसे अधिक था, उसके बाद निजी बैंक (89.3 प्रतिशत) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (50.6 प्रतिशत) के लिए थे।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

चार्ट II.33: भारित औसत उधार दरों पर क्षेत्रवार संचरण

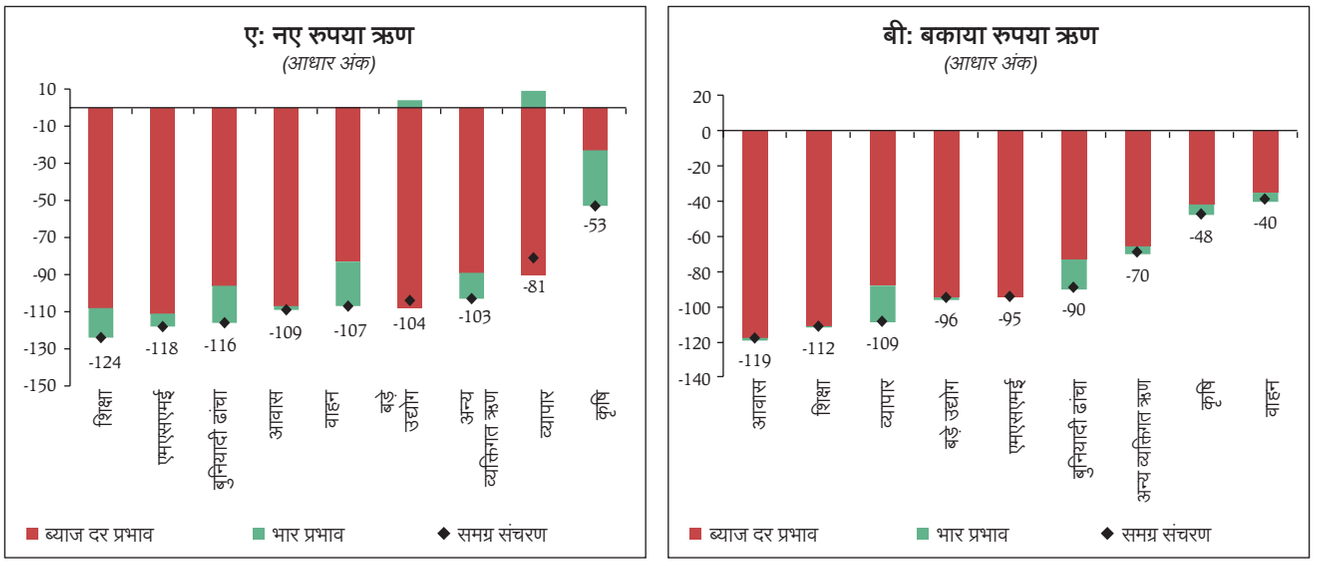

स्रोत: एमपीडी06 विवरणी, आरबीआई; और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

क्षेत्रीय विश्लेषण से पता चलता है कि नए और बकाया ऋणों पर उधार दरों का संचरण व्यापक रहा है। जैसा कि बॉक्स II.2 में चर्चा की गई है, ज़्यादा ब्याज दर वाले बैंकों की ओर मात्रा में बदलाव का प्रभाव कुल संचरण पर पड़ सकता है। इसलिए, मौजूदा नरमी के दौर में, बड़े उद्योगों और व्यापार के नए डब्ल्यूएएलआर तक संचरण, कुछ हद तक 'भार प्रभाव' से संतुलित हो गया है (चार्ट II.33)।

रेपो दर से जुड़े बाह्य बेंचमार्क ऋणों के लिए, बैंकों ने अपने स्प्रेड (नीतिगत रेपो दर के अतिरिक्त लगाया गया ब्याज दर) में वृद्धि की है, जिससे संचरण की सीमा कम हो गई है (सारणी II.12)। घरेलू बैंकों के लिए, नए रुपया ऋणों पर स्प्रेड शिक्षा ऋणों के लिए सबसे अधिक था, उसके बाद अन्य व्यक्तिगत ऋणों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ऋणों के लिए था।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये कंपनियां पहले बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों के अंतिम छोर तक ऋण पहुंचाती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में विशेष वित्तपोषण सेवाएं प्रदान करती हैं, जिससे मौद्रिक नीति संचरण के ऋण चैनल का दायरा व्यापक होता है। हालांकि, इनकी ऋण दरें आमतौर पर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक होती हैं, जिसका मुख्य कारण इनकी देयता संरचना और उधारकर्ताओं का अपेक्षाकृत उच्च जोखिम स्तर है। परिणामस्वरूप, मौद्रिक नीति संचरण की

सारणी II.12: नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दरों का स्प्रेड*

क्षेत्र	जन-25			फर-26		
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी बैंक	घरेलू बैंक	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी बैंक	घरेलू बैंक
एमएसएमई ऋण	3.43	3.12	3.20	3.31	3.28	3.29
व्यक्तिगत ऋण						
आवास	2.09	2.44	2.34	2.30	2.51	2.44
वाहन	2.63	4.03	3.07	2.81	4.43	3.17
शिक्षा	3.84	4.76	4.41	3.69	5.56	4.62
अन्य व्यक्तिगत ऋण	3.01	5.38	3.36	3.22	4.74	3.47

टिप्पणी: अन्य व्यक्तिगत ऋणों में आवास, वाहन, शिक्षा और क्रेडिट कार्ड ऋणों के अलावा अन्य ऋण शामिल हैं।
*: बाह्य बेंचमार्क से संबद्ध ऋणों के लिए रेपो दर के आधार पर गणना की गई।
स्रोत: एमपीडी 06 विवरणी; आरबीआई; और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

मात्रा एनबीएफसी और एससीबी के बीच भिन्न-भिन्न होती है (चार्ट II.34)।

मौजूदा नरमी चक्र के दौरान जमा दर में भी मजबूत संचरण देखा गया है। फरवरी 2025 से फरवरी 2026 के दौरान नए और बकाया जमाओं के लिए भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरें (डब्ल्यूएडीटीडीआर) क्रमशः 97 बीपीएस और 47 बीपीएस कम हो गईं। विभिन्न बैंक समूहों में, नए और बकाया जमा दोनों के लिए संचरण पीएसबी के लिए पीवीबी की तुलना में थोड़ा अधिक था; हालाँकि, नए खुदरा जमा के लिए, यह पीवीबी के लिए अधिक था (चार्ट II.35ए)। नए खुदरा जमाओं पर ब्याज दरें सभी अवधियों में कम हुईं, हालांकि इसका प्रभाव अलग-अलग था (चार्ट II.35बी)। कम लागत वाली चालू खाता और बचत खाता (सीएएसए) जमाओं का हिस्सा मामूली रूप से कम हुआ, हालांकि बचत जमा (कुल जमाओं का लगभग 30 प्रतिशत) पर ब्याज दर भी जून 2025 में विनियमन हटाने के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई (चार्ट II.35सी), जिससे बैंकों को अपने निवल ब्याज मार्जिन की रक्षा करने में मदद मिली है (चार्ट II.35डी)।

चार्ट II.34: एनबीएफसी और एससीबी के बकाया ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर का संचरण

(आधार अंक)

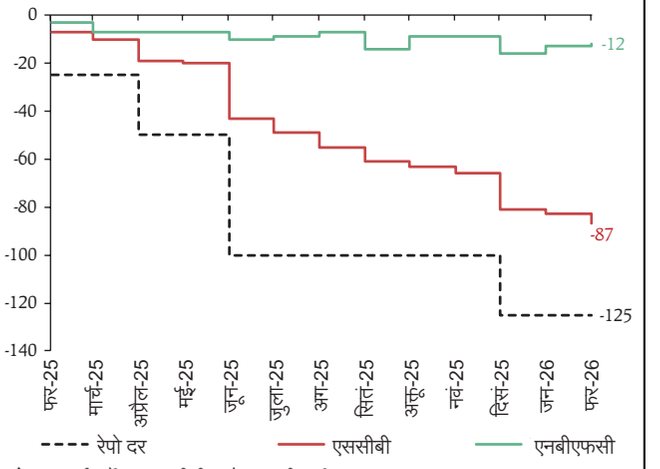

स्रोत: *तदर्थ* सर्वेक्षण, एमपीडी; और आरबीआई।

चार्ट II.35: जमा दरें और बैंकों की लाभप्रदता

ए: सावधि जमा दरों में संचरण*

(आधार अंक)

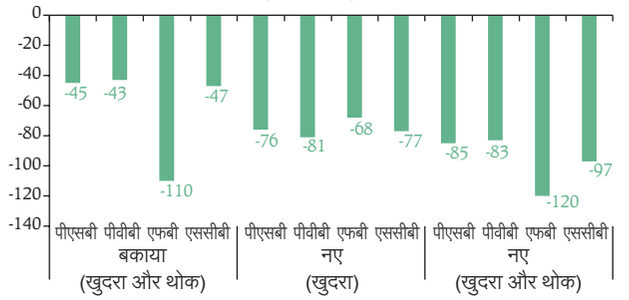

बी: नए खुदरा सावधि जमाओं में संचरण - अवधिवार*

(आधार अंक)

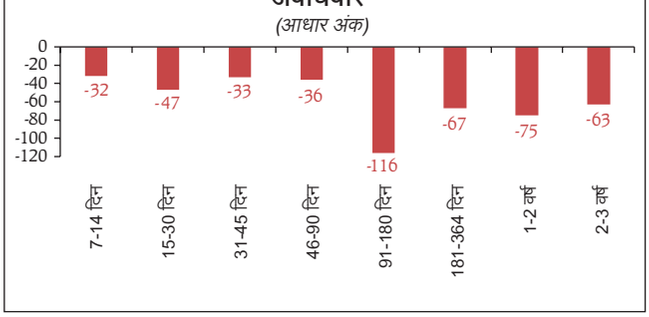

सी: एससीबी की बचत जमा दरें

(प्रतिशत)

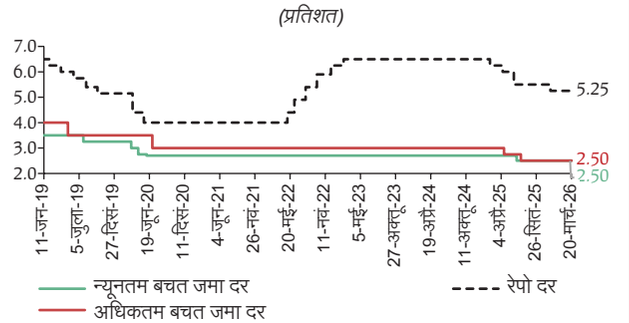

डी: एससीबी का सीएएसए हिस्सेदारी और निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)

(प्रतिशत)

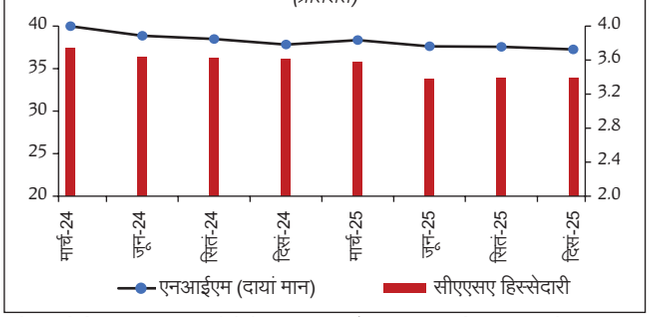

टिप्पणियाँ: पीएसबी : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक; पीवीबी:निजी बैंक; एफबी: विदेशी बैंक; एससीबी: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक; डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर; सीएएसए: चालू खाता और बचत खाता; एनआईएम: निवल ब्याज मार्जिन।

*: संचरण की गणना फरवरी 2025 से फरवरी 2026 की अवधि के लिए की गई है।

#: बचत जमा दरें पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित हैं और 1 लाख रुपये तक की खाता शेष राशि पर लागू होती हैं।

स्रोत: एमपीडी 06 विवरणी; और आरबीआई।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

सारणी II.13: लघु बचत लिखतों की ब्याज दरें – पहली तिमाही 2026-27

लघु बचत योजना	परिपक्वता (वर्षों में)	स्प्रेड$ (प्रतिशत अंक)	औसत जी-सेक प्रतिफल# (प्रतिशत)	सूत्र आधारित ब्याज दर (प्रतिशत)	भारत सरकार द्वारा घोषित ब्याज दर (प्रतिशत में)	अंतर (प्रतिशत अंक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (6)– (5)
बचत जमा	-	-			4	-
लोक भविष्य निधि	15	0.25	6.83	7.08	7.1	2
सावधि जमा						
1 वर्ष	1	0	5.49	5.49	6.9	141
2 वर्ष	2	0	5.70	5.70	7	130
3 वर्ष	3	0	5.91	5.91	7.1	119
5 वर्ष	5	0.25	6.34	6.59	7.5	91
आवर्ती जमा खाता	5	0	5.91	5.91	6.7	79
मासिक आय योजना	5	0.25	6.31	6.56	7.4	84
किसान विकास पत्र	115 महीने	0	6.83	6.83	7.5	67
एनएससी VIII अंक	5	0.25	6.50	6.75	7.7	95
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	5	1.00	6.34	7.34	8.2	86
सुकन्या समृद्धि खाता योजना	21	0.75	6.83	7.58	8.2	62

$: भारत सरकार की फरवरी 2016 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार लघु बचत ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्प्रेड।

#: दिसं 2025-फर 2026 की अवधि के लिए संबंधित परिपक्वता अवधि के जी-सेक पर अर्ध-वार्षिकीकृत प्रतिफल पर आधारित।

टिप्पणी: चक्रवृद्धि आवृत्ति विभिन्न लिखतों में भिन्न होती है।

स्रोत: भारत सरकार; फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

भारत सरकार ने विभिन्न लघु बचत लिखतों(एसएसआई) पर ब्याज दरों की समीक्षा की और उन्हें 2026-27 की पहली तिमाही के लिए अपरिवर्तित रखा। इसके परिणामस्वरूप लघु बचत लिखतों की ब्याज दरों और उनकी सूत्र-आधारित दरों के बीच अंतर बढ़ गया (सारणी II.13)। यह अंतर विशेष रूप से ब्याज दरों में नरमी के दौर में, प्रतिस्थापन प्रभाव (झा और अन्य, 2025)[14] के कारण नीतिगत दर के बैंकों की जमा दरों पर प्रभाव को सीमित कर सकता है। कुल जमा (बैंकों की खुदरा जमा और बचत जमा का योग) में छोटी बचत जमा की हिस्सेदारी जनवरी 2025 के 17.9 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी 2026 में 19.1 प्रतिशत हो गई है। इससे बैंक जमाओं का लघु बचत योजनाओं में अधिक स्थानांतरण भी प्रोत्साहित हो सकता है, जिससे बैंक-आधारित वित्तीय मध्यस्थता के लिए चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।

II.4 निष्कर्ष

दूसरी छमाही के दौरान प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष में बनी रही, सिवाय कुछ अनियमित घटनाओं के जब जीएसटी और अग्रिम कर भुगतानों के कारण बैंकिंग प्रणाली से चलनिधि कम हो गई। वैश्विक अनिश्चितता और अस्थिर पूंजी प्रवाह के कारण घरेलू वित्तीय बाजारों में दूसरी छमाही में रुक-रुक कर उतार-चढ़ाव देखा गया। मुद्रा बाजार दरें काफी हद तक प्रणालीगत चलनिधि और मौद्रिक नीतिगत कार्रवाइयों के अनुरूप विकसित हुईं। घरेलू और वैश्विक कारकों के संयोजन के कारण दीर्घकालिक सरकारी बांडों के प्रतिफल में मजबूती आई। भारतीय शेयर बाजारों ने आघात-सहनीयता दिखाई, लेकिन वैश्विक चुनौतियों और अस्थिर पूंजी प्रवाह के कारण कुछ अस्थिरता का अनुभव किया। भारतीय रुपये (आईएनआर) ने 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान मूल्यह्रास पूर्वाग्रह के साथ दोतरफा उतार-चढ़ाव का प्रदर्शन किया। पश्चिम एशिया में संघर्ष छिड़ने के बाद, मार्च में इक्विटी बाज़ार और भारतीय रुपया, दोनों पर ही दबाव काफ़ी बढ़ गया। मौजूदा आर्थिक नरमी के चक्र के दौरान बैंक ऋण दरों पर सुचारु नीतिगत संचरण ने बैंक ऋण वृद्धि को मजबूत समर्थन दिया। आगे चलकर, रिज़र्व बैंक बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय स्थिरता की रक्षा करते हुए, चलनिधि प्रबंधन कार्यों में चुस्त और सक्रिय रहेगा।

[14] झा, ए., दास, एस., और कश्यप, वाई., (2025), "लघु बचत दरों में दृढ़ता: मौद्रिक नीति संचरण के लिए निहितार्थ", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 60, अंक संख्या 52, दिसंबर।

III. मांग और उत्पादन

2025-26 की दूसरी छमाही (फरवरी तक) में आर्थिक गतिविधि लचीली रही, जो मुख्य रूप से मजबूत घरेलू मांग के कारण थी। जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और मौद्रिक सहजता से निजी खपत में अच्छी वृद्धि हुई। आधारभूत सुधारों, अनुकूल वित्तीय स्थितियों और बुनियादी ढांचे पर खर्च के कारण निवेश गतिविधि मजबूत हुई। आपूर्ति पक्ष पर, सेवाएं उत्साहजनक बनी रहीं और विनिर्माण क्षेत्र मजबूत हुआ, हालांकि मौसम की बाधाओं के कारण कृषि गतिविधि में कमी आई। भू-राजनीतिक तनाव से वैश्विक प्रतिकूल दृष्टिकोण, अस्थिर पण्य कीमतों और आपूर्ति-शृंखला व्यवधानों के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करते हैं। आगे बढ़ने के लिए सक्रिय नीतिगत कार्रवाई के लिए डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों को इनपुट आपूर्ति की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में राष्ट्रीय खाता में आधार वर्ष अद्यतन होने के साथ प्रक्रिया में सुधार और डाटा कवरेज के बढ़ने से आर्थिक गतिविधि मजबूत बनी रही जो मज़बूत घरेलू मांग के कारण हुआ। निजी उपभोग, ग्रामीण और शहरी मांग की स्थितियों में सुधार दिखा और यह जीएसटी दर के युक्तियुक्त होने और मौद्रिक नरमी के जरिए हुआ। अनुकूल वित्तीय स्थितियां और हो रहे संरचनागत सुधार के चलते निवेश गतिविधि में गति बनी हुई है। लगातार राजकोषीय सुधार के बावजूद, सरकारी उपभोग भी वृद्धि के लिए सहायक बना रहा। अनिश्चित वैश्विक माहौल में कम पण्य निर्यात ने आंशिक रूप से भरपाई की और मज़बूत सर्विसेज़ निर्यात के चलते बाह्य मांग एक जैसी नहीं रही। आपूर्ति की तरफ, उच्च मूल्य वाली सेवाओं के कारण सेवा क्षेत्र विकास के लिए मुख्य चालक बनी रहीं, वहीं मज़बूत विनिर्माण के चलते औद्योगिक गतिविधि मज़बूत हुई। मौसम से जुड़ी बाधाओं और आधार प्रभाव यह दर्शाता है कि कृषि गतिविधि में कमी आई है।

केंद्रीय बजट 2026-27 में छह सूत्री योजना का प्रस्ताव किया गया है, जो कई रणनीतिक और सीमांत क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने, पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने, चैंपियन एमएसएमई बनाने, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने और शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है। यह, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार सौदों पर आगे की प्रगति के साथ, भारत के समग्र विकास दृष्टिकोण के लिए अच्छा संकेत है। तथापि, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, पण्यों की बढ़ी हुई कीमतें और आपूर्ति-श्रृंखला में रुकावटों से पैदा होने वाली वैश्विक चुनौतियाँ, विकास के दृष्टिकोण के लिए कुछ जोखिम भी पैदा करती हैं।

III.1 समग्र मांग

अक्टूबर 2025 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) के के जारी होने के बाद से समग्र मांग मज़बूत बनी रही,। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के नए आधार वर्ष 2022-23 पर आधारित दूसरे अग्रिम अनुमानों (एसएई) के अनुसार, 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो 2024-25 के 7.1 प्रतिशत से अधिक है। इस तेज़ी का मुख्य कारण निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) और सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) रहा, जिनके क्रमशः 7.7 प्रतिशत और 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है (सारणी III.1)। निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) ने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में 4.3 प्रतिशत अंकों का योगदान दिया, जो एक साल पहले के 3.3 प्रतिशत अंकों से अधिक है।

सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) ने 2.3 प्रतिशत अंकों का योगदान दिया (2024-25 में 2.1 प्रतिशत अंक), जबकि सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) ने 0.7 प्रतिशत अंकों का योगदान दिया, जैसा कि एक वर्ष पहले था। इसके विपरीत, निवल निर्यात ने जीडीपी वृद्धि में नकारात्मक (हालांकि मामूली) रूप से काम किया (सारणी III.1 और चार्ट III.1ए)।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

सारणी III.1: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि

*(वार्षिक प्रतिशत में)^*

मद	2024-25	2025-26	भारित योगदान*		2024-25				2025-26			
	(एफआरई)	(एसएई)	2024-25	2025-26	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4#
निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई)	5.8	7.7	3.3	4.3	6.1	5.6	6.0	5.6	9.2	8.0	8.7	5.1
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई)	6.5	6.6	0.7	0.7	7.5	7.0	7.6	3.6	5.8	6.6	4.7	9.4
सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ)	6.4	7.1	2.1	2.3	6.5	6.6	6.3	6.2	4.9	8.4	7.8	7.2
निर्यात	6.6	6.5	1.5	1.5	7.3	3.1	10.5	5.4	6.6	10.2	5.6	4.0
आयात	5.3	6.4	1.3	1.5	8.3	4.6	2.9	5.5	7.4	5.9	8.6	3.6
बाजार मूल्य पर जीडीपी	**7.1**	**7.6**	**7.1**	**7.6**	**7.5**	**6.6**	**7.4**	**7.0**	**6.7**	**8.4**	**7.8**	**7.3**

टिप्पणी: * : वृद्धि के संबंध में घटक वार योगदान जो जीडीपी वृद्धि में नहीं जुड़ता क्योंकि स्टॉक, कीमती सामान और विसंगतियां शामिल नहीं हैं।
^: जब तक कुछ और न निर्दिष्ट हो, इस अध्याय में वृद्धि दर सभी चर्चाओं पर वर्ष-दर-वर्ष (वाई ओ-वाई) के आधार पर है।
एफआरई: पहला संशोधित अनुमान; एसएई : दूसरा अग्रिम अनुमान। #: निहित।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ़ अनुमान।

जीडीपी वृद्धि का तिमाही रुझान यह दर्शाता है कि अपेक्षाकृत कम होने के बाद, पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियाँ मज़बूत हुई हैं। 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान था, जो दूसरी तिमाही में बढ़कर 8.4 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 7.8 प्रतिशत हो गई, जबकि चौथी तिमाही के लिए 7.3 प्रतिशत का अंतर्निहित अनुमान था। मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दर (एसएएआर) ने भी इसी तरह का रुझान दिखाया, जिसमें चौथी तिमाही का आंकड़ा 7.1 प्रतिशत रहा (चार्ट III.1बी)। अक्तूबर 2025 की एमपीआर में, वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान दूसरी तिमाही में 7.0 प्रतिशत और तिसरी तिमाही में 6.4 प्रतिशत लगाया गया था, लेकिन दूसरी तिमाही और तिसरी तिमाही में वास्तविक वृद्धि क्रमशः 8.4 प्रतिशत और 7.8 प्रतिशत के साथ अनुमान से अधिक मजबूत रही (चार्ट III.2)। वृद्धि में यह उछाल मुख्य रूप से निजी उपभोग में उम्मीद से अधिक तेजी और निवल बाह्य मांग से कम रुकावट के कारण रहा।

कुल मिलाकर, उपलब्ध हाई-फ्रीक्वेंसी डेटा से पता चलता है कि 2025-26 में विकास दर मज़बूत बनी रही। घरेलू खपत ने मुख्य गति प्रदान की, जबकि निवेश की मांग में तेज़ी बनी रही। निवल निर्यात में अस्थिर बनी हुई है।

चार्ट III.1 जीडीपी वृद्धि और इसके घटक

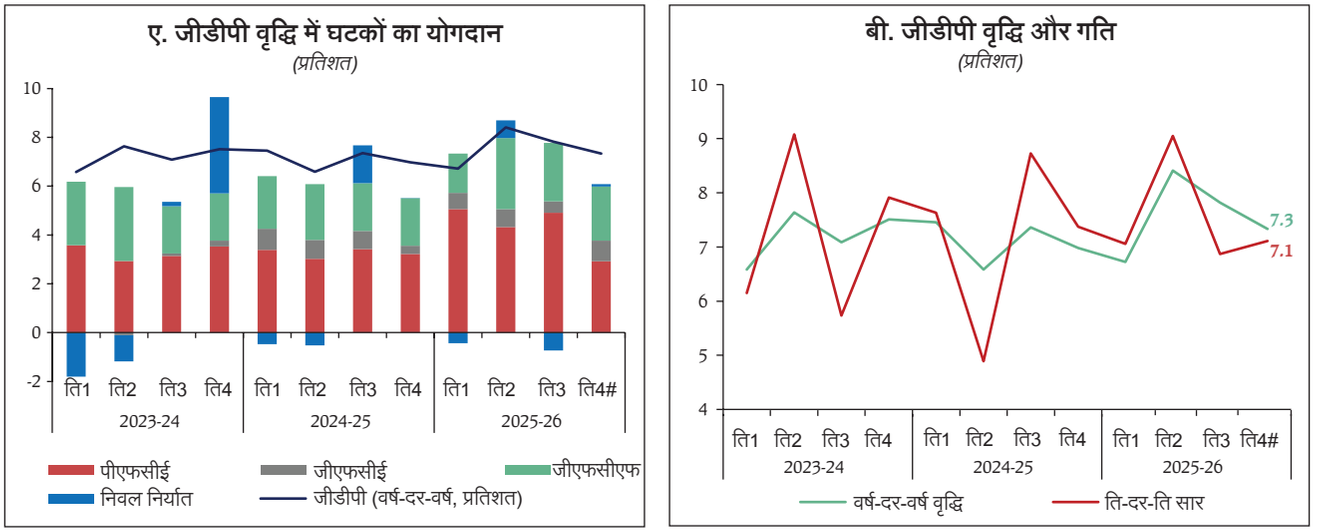

टिप्पणी: सार: मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दर। * और #, 2025-26 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमानों पर आधारित ति 4 के निहित अनुमान हैं।
स्रोत: एनएसओ, और आरबीआई स्टॉफ अनुमान।

चार्ट III.2 जीडीपी वृद्धि – अनुमान बनाम वास्तविक

(वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि प्रतिशत)

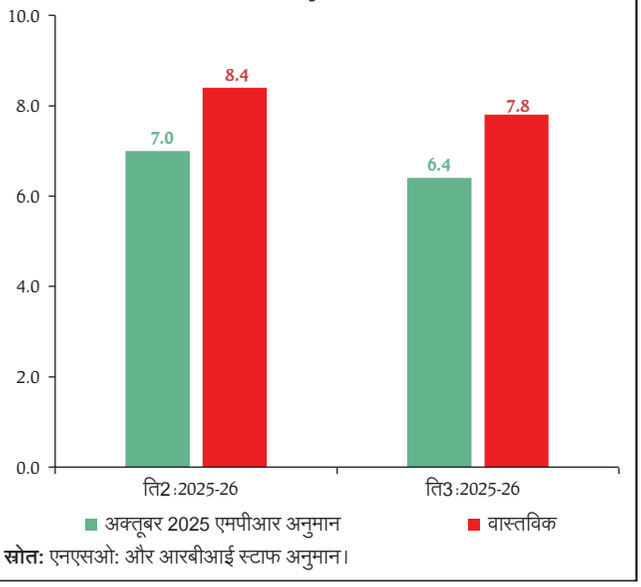

स्रोत: एनएसओ: और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

III.1.1 निजी अंतिम उपभोग व्यय

2025-26 में कुल मांग का मुख्य आधार पीएफसीई ही रहा, हालांकि नई जीडीपी सीरीज़ (आधार वर्ष 2022-23) के तहत इसका हिस्सा कम हो गया है; जो अर्थव्यवस्था में हुए संरचनात्मक बदलावों और नए डेटा स्रोतों के उपयोग को दर्शाता है (बॉक्स III.1)। एसएई के अनुसार, 2025-26 में पीएफसीई में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जो 2024-25 के 5.8 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि, पीएफसीई वृद्धि का तिमाही रुझान कुछ धीमी गति का संकेत देता है: पहली तिमाही में 9.2 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 8.0 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 8.7 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.1 प्रतिशत (सारणी III.1)।

वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में शहरी मांग के संकेतक आम तौर पर एक बेहतर स्थिति दर्शाता है (सारणी III.2)। 2025-26 तीसरी तिमाही में यात्री वाहनों की बिक्री में मज़बूत रूप से दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जो जनवरी और फरवरी 2026 में मध्यम था।। वर्ष 2025-26 के चौथी तिमाही के पहले दो महीने में विस्तार के दायरे में बना रहा। घरेलू हवाई यात्री यातायात में उतार-चढ़ाव बना रहा, लेकिन तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में, औसतन, यह विस्तार के दायरे में ही रहा। बिना किसी गारंटी वाले घरेलू ऋण की गति तेज़ हुई – तीसरी तिमाही और जनवरी -फरवरी 2026 में व्यक्तिगत ऋणों में ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि के दौरान क्रेडिट कार्ड के बकाया ऋण में वृद्धि धीमी रही।

बॉक्स III.1: राष्ट्रीय खातों की नई श्रृंखला: कार्यप्रणाली और कवरेज में सुधार

भारत की संशोधित राष्ट्रीय खातों की श्रृंखला, जिसका आधार वर्ष 2022–23 है, कार्यप्रणाली में सुधार, डेटा कवरेज में वृद्धि और उत्पादन तथा व्यय पक्षों के बीच बेहतर तालमेल के माध्यम से मापन ढांचे को मजबूत बनाती है। कार्यप्रणाली के दृष्टिकोण से, संशोधित श्रृंखला, अन्य बातों के साथ-साथ, विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में 'डबल डिफ्लेशन' (दोहरा अपस्फीति)[1] को अपनाती है, अधिक बारीक डिफ्लेटर्स का उपयोग करती है, हाल के सर्वेक्षण साक्ष्यों का उपयोग करके संकलन अनुपातों को अद्यतन करती है, एमजीटी -7/7ए वार्षिक रिटर्न फाइलिंग[2] का उपयोग करके विभिन्न गतिविधियों में कॉर्पोरेट क्षेत्र के 'मूल्य संवर्धन' के आवंटन में सुधार करती है, और त्रैमासिक अनुमानों को वार्षिक राष्ट्रीय खातों के साथ अधिक निकटता से संरेखित करती है। डेटा के संबंध में, यह सर्वेक्षणों और प्रशासनिक स्रोतों का अधिक उपयोग करती है—जिनमें एएसयूएसई, पीएलएफएस, एचसीईएस, जीएसटी, पीएफएमएस और ई- वाहन शामिल हैं—साथ ही, यह सशुल्क घरेलू सेवाओं और डिजिटल/प्लेटफ़ॉर्म गतिविधियों के कवरेज में भी सुधार करती है। इसके अलावा, 'उत्पाद संतुलन' के माध्यम से 'आपूर्ति और उपयोग सारणी' ढांचे को शामिल करने से उत्पादन- और व्यय-पक्ष के अनुमानों के बीच तालमेल मजबूत होता है, जिससे सांख्यिकीय विसंगतियों को कम करने में मदद मिलती है। प्रमुख कार्यप्रणालीगत सुधारों, डेटा कवरेज में वृद्धि और प्रणाली एकीकरण उपायों को सारणी III.1.1 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

आधार वर्ष में संशोधन, कार्यप्रणालीगत सुधारों के साथ मिलकर, भारत के राष्ट्रीय खातों में उन कई मुद्दों का समाधान करता है जिन्हें आइएमएफ की भारत पर केंद्रित 'आर्टिकल IV रिपोर्टों' में उजागर किया गया था। इसका एक महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि 2022–23 से 2024–25 की अवधि में वास्तविक जीवीए की मापी गई क्षेत्रीय संरचना में मामूली बदलाव आया है; इसमें कृषि

(जारी...)

[1] दोहरा अपस्थिति , आउटपुट और इनपुट को अलग-अलग डिफ्लेट करके वास्तविक वैल्यू एडेड का अनुमान लगाता है, जिससे वॉल्यूम में होने वाले बदलावों की माप में सुधार होता है।

[2] एमजीटी-7/7ए: कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों द्वारा भरे जाने वाले वार्षिक रिटर्न फॉर्म, जो कॉर्पोरेट संरचना और व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

सारणी III.1.1: प्रमुख कार्यप्रणालीगत सुधार, डेटा कवरेज में वृद्धि और प्रणाली एकीकरण के उपाय

	परिवर्तन		निहितार्थ
कार्यप्रणाली में सुधार	अपस्फीति कार्यनीति	दोहरी अपस्फीति और एकल एक्सट्रपलेशन का उपयोग विनिर्माण और कृषि में किया जाता है; एकल अपस्फीति बंद कर दी गई है।	कीमत और आयतन प्रभावों के पृथक्करण में सुधार करता है, और वास्तविक मूल्य संवर्धन के मापन को सुदृढ़ बनाता है।
	बारीक डिफ्लेटर	समग्र डिफ्लेटर्स के बजाय, आइटम-समूह स्तर पर सीपीआई, डब्ल्यू और इकाई मूल्य सूचकांकों का व्यापक उपयोग।	स्थिर-मूल्य अनुमानों की सटीकता और विभिन्न क्षेत्रों के बीच तुलनात्मकता को बढ़ाता है।
	अद्यतित दरें और अनुपात	हाल के सर्वेक्षणों और क्षेत्रीय अध्ययनों के आधार पर संकलन मापदंडों को संशोधित किया गया है।	क्षेत्रीय अनुमानों की प्रतिनिधिकता में सुधार करता है।
	बहु-गतिविधि कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग	एमजीटी-7/7ए फाइलिंग का उपयोग करके, वैल्यू एडेड को केवल मुख्य गतिविधि तक सीमित रखने के बजाय, सभी गतिविधियों में लगाया जाना	उद्योग वर्गीकरण और क्षेत्रीय जीवीए आबंटन में सुधार करता है।
	पीएफसीई संकलन	मिश्रित कार्यप्रणाली, जिसमें घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस), प्रशासनिक डेटा और वस्तु-प्रवाह विधियों का संयोजन किया गया है; तथा सीओआईसीओपी 2018 वर्गीकरण को अपनाया गया है।	निजी उपभोग के स्तर और संरचना को सुदृढ़ करता है, और अंतर्राष्ट्रीय तुलनीयता में सुधार लाता है।
	त्रैमासिक-वार्षिक संरेखण	त्रैमासिक संकलन ढांचा वर्गीकरण और अपस्फीति पद्धतियों के मामले में वार्षिक राष्ट्रीय खातों के साथ अधिक निकटता से संरेखित है।	यह तिमाही और वार्षिक जीडीपी अनुमानों के बीच एकरूपता में सुधार करता है, और कार्यप्रणाली संबंधी अंतरों के कारण होने वाले संशोधनों को कम करता है।
डेटा और कवरेज में सुधार	घरेलू उद्यम मापन	असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) अनौपचारिक उद्यमों के उत्पादन और मूल्य-संवर्धन के लिए प्रत्यक्ष मानक प्रदान करता है।	घरेलू/गैर-निगमित क्षेत्र के उत्पादन के मापन में सुधार करता है।
	श्रम इनपुट से संबंधित जानकारी	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोज़गार और श्रम बल से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, जिसका उपयोग श्रम-प्रधान गतिविधियों का अनुमान लगाने में किया जाता है।	घरेलू सेवाओं और अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों के अनुमान को सुदृढ़ करता है।
	प्रशासनिक डेटा एकीकरण	संकलन में जीएसटी, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएमएमएस) और ई-वाहन डेटाबेस का अधिक उपयोग।	उत्पादन और व्यय अनुमानों की समयबद्धता और क्रॉस-वैलिडेशन में सुधार करता है।
	घरेलू सेवाओं का कवरेज	जीडीपी अनुमानों में घरेलू कामगारों का स्पष्ट समावेश	जीवीए के अंतर्गत सशुल्क घरेलू सेवाओं के कवरेज का विस्तार करता है।
	डिजिटल और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था	डिजिटल, प्लेटफ़ॉर्म और गिग-इकोनॉमी से जुड़ी गतिविधियों की बेहतर रिकॉर्डिंग, जिसमें अनौपचारिक और स्वरोज़गार वाले क्षेत्र भी शामिल हैं।	उभरती सेवाओं और डिजिटल माध्यम से संचालित गतिविधियों के मापन को बेहतर बनाता है।
एकीकरण और संस्थागत खाते	एसयूटी का उपयोग	आपूर्ति और उपयोग के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु, उत्पाद-संतुलन के माध्यम से एसयूटी फ्रेमवर्क का व्यवस्थित एकीकरण।	उत्पादन और व्यय अनुमानों के बीच तालमेल को बेहतर बनाता है, और सांख्यिकीय विसंगतियों को कम करता है।
	सरकारी क्षेत्र अनुमान	बजट दस्तावेज़ों और प्रशासनिक खातों का बेहतर उपयोग; एनपीएस/ओपीएस पेंशन, एचआरए आकलन, स्थानीय निकायों की कवरेज और सब्सिडी अपस्फीति का बेहतर प्रबंधन।	सरकारी उत्पादन और व्यय की पूर्णता और मूल्यांकन में सुधार करता है।
	राज्य खाते (जीएसडीपी) का संरेखण	राज्यों को जीएसडीपी संकलन को राष्ट्रीय खातों के साथ संरेखित करने हेतु संशोधित दिशानिर्देश और कार्यप्रणाली संबंधी सहायता।	राष्ट्रीय और राज्य खातों के बीच एकरूपता को सुदृढ़ करता है और आबंटन पद्धतियों पर निर्भरता को कम करता है।

टिप्पणी: पीएमसीई: निजी अंतिम उपभोग व्यय; जीवीए: सकल मूल्य संवर्धन; जीएसडीपी: सकल राज्य घरेलू उत्पाद; एनपीएस: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली;
ओपीएस: पुरानी पेंशन योजना; एचआरए : मकान किराया भत्ता; ई-वाहन : राष्ट्रीय वाहन पंजीकरण डेटाबेस।

और संबद्ध गतिविधियों का हिस्सा बढ़ा है, जबकि उद्योग और सेवाओं का हिस्सा घटा है (चार्ट III.1.1)। कृषि के हिस्से में यह वृद्धि संभवतः फसलों और संबद्ध गतिविधियों के बेहतर मापन, अद्यतन 'इनपुट-आउटपुट' संरचनाओं, और फसलों, पशुधन तथा मत्स्य पालन के लिए मौसम-वार स्रोत डेटा के बेहतर उपयोग को दर्शाती है; इसमें कुछ त्रैमासिक अनुमानों को मौसम-वार जानकारी के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसके विपरीत, सेवाओं के हिस्से में आई कमी संशोधित शृंखला में अनौपचारिक सेवा गतिविधियों के बेहतर आकलन के अनुरूप है—जिसमें एएसयूएसई -आधारित जानकारी के माध्यम से प्राप्त डेटा भी शामिल है। पूर्ण रूप से, जीडीपी के हिस्से के तौर पर यह अंतर पिछली शृंखला में औसतन लगभग 2.0 प्रतिशत था, जबकि 2022–23 से 2025–26 के दौरान संशोधित शृंखला में यह लगभग 0.3 प्रतिशत रहा।

(जारी...)

चार्ट III.1.1: 2022-23 में जीवीए हिस्सेदारी की संरचना में परिवर्तन (नया और पुराना आधार)

(प्रतिशत)

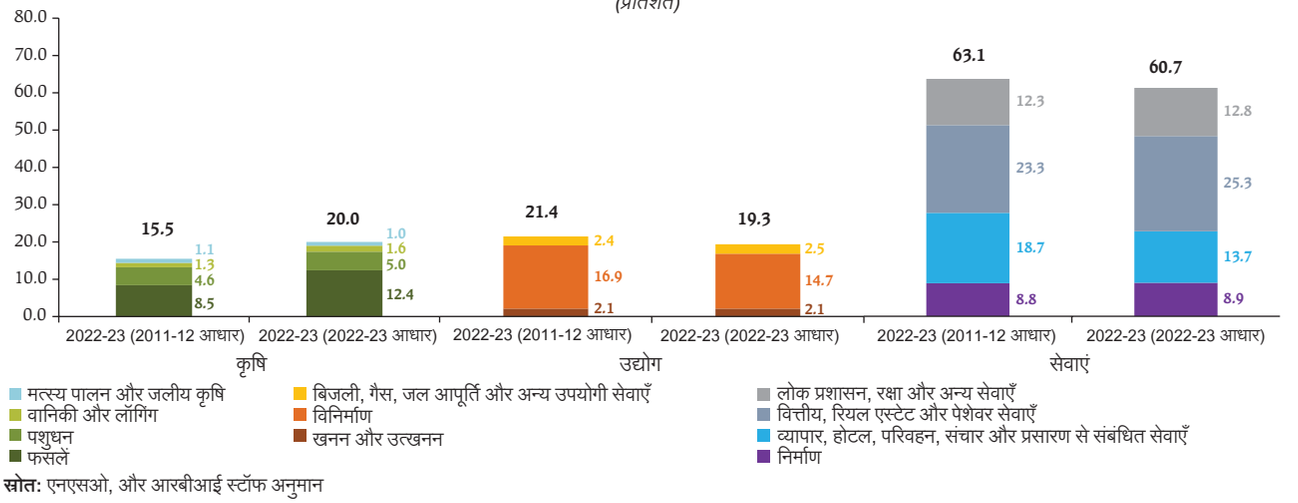

स्रोत: एनएसओ, और आरबीआई स्टॉफ अनुमान

यह इस बात का संकेत है कि खातों के उत्पादन और खर्च वाले पक्षों के बीच तालमेल बेहतर हुआ है। संशोधित शृंखला से हाल के वर्षों में बढ़त पूंजी-उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) का प्रोफ़ाइल भी कुछ हद तक ज़्यादा स्थिर नज़र आता है। यह इस बात का संकेत है कि इसके औसत स्तर में कोई बड़ा बदलाव होने के बजाय, इसमें उतार-चढ़ाव कम हुआ है (चार्ट III.1.2)।

चार्ट III.1.2: आईसीओआर: आधार वर्ष संशोधन

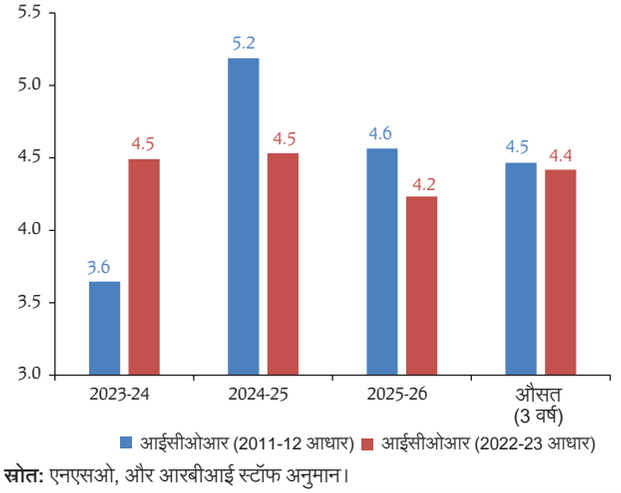

स्रोत: एनएसओ, और आरबीआई स्टॉफ अनुमान।

भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उम्मीद है कि भारत की सांख्यिकीय प्रणाली उभरते हुए अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय मानकों के अनुरूप और विकसित होगी। अगले दशक में सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स (एसएनए) 2028 से आने वाले एसएनए 2025 फ्रेमवर्क की ओर वैश्विक बदलाव के साथ, राष्ट्रीय खातों की मज़बूती और पारदर्शिता को और बेहतर बनाने के लिए कुछ और सुधारों की उम्मीद है। ये सुधार खास तौर पर डिजिटल अर्थव्यवस्था, वैश्विक उत्पादन व्यवस्थाओं और बहुराष्ट्रीय उद्यमों की गतिविधियों को मापने में, और प्रशासनिक डेटा के इस्तेमाल को और गहरा करने में किए जाएँगे।

संदर्भ:

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) (2026)। प्रेस रिलीज़: विकास को फिर से परिभाषित करना—भारत का संशोधित जीडीपी अनुमान और नया मापन फ्रेमवर्क। भारत सरकार।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) स्थिर कीमतों पर अनुमानों पर समिति की रिपोर्ट। भारत सरकार।

भारत सरकार। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)। वित्त मंत्रालय।

ग्रामीण क्षेत्रों में मांग की स्थिति में और सुधार हुआ। 2025-26 तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही के पहले दो महीनों में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की बिक्री में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। वर्ष की पहली छमाही में गिरावट में रहने के बाद तीसरी तिमाही में उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन सकारात्मक रहा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के तहत काम की मांग तीसरी तिमाही और उसके बाद के महीनों में कम ही रही, जो ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार की स्थिति में सुधार का संकेत है। तीसरी तिमाही में ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही उपभोक्ता वस्तुओं में बढ़ोतरी शहरी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा

मौद्रिक नीति वक्तव्य

सारणी III.2: उपभोग के संकेतक

t)

संकेतक	2024-25				2025-26				
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	जन	फर
शहरी मांग									
घरेलू हवाई यात्री यातायात	5.6	7.3	11.4	12.0	5.3	-1.9	1.7	3.1	-0.1
यात्री वाहनों की बिक्री	20.2	-1.3	5.1	3.6	-1.4	-1.5	20.6	8.0#	7.3#
उपभोक्ता के लिए टिकाऊ वस्तुएँ	10.7	6.6	9.0	5.9	2.6	6.9	7.3	7.2	7.3
व्यक्तिगत ऋण	25.6	13.4	12.0	11.7	11.7	11.7	14.4	14.9	15.2
वाहन ऋण	12.0	10.6	8.8	8.6	9.2	7.3	16.5	17.1	17.1
क्रेडिट कार्ड बकाया	23.3	18.0	15.6	10.6	7.2	3.7	1.0	1.5	1.7
ग्रामीण मांग									
ट्रैक्टर बिक्री	0.5	0.7	13.5	17.3	9.2	30.7	23.2	43.0	34.2
मोटर सायकल बिक्री	16.8	10.2	-1.9	-3.5	-9.2	5.0	12.0	20.3	30.8
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएँ	-0.2	-2.2	-1.6	-2.0	-1.5	-2.0	4.1	-2.3	-0.6
उर्वरक बिक्री	2.4	-7.3	0.4	-9.6	-14.7	30.6	7.5 ^		
एमजीएनआरईजीए कार्य मांग	-16.1	-16.5	1.7	6.5	1.3	-21.3	-31.8	-25.7	-14.2
एफएमसीजी बिक्री									
ग्रामीण		5.7	9.1	9.5	8.4	7.7	2.9	-0.5	-0.2
शहरी		1.9	4.0	3.5	4.1	4.0	2.3	2.4	2.4
अखिल भारत		3.5	6.2	6.1	6.0	5.5	2.6	1.1	1.3

टिप्पणी: #: इसमें टाटा मोटर्स शामिल नहीं है। ^ति3:2025-26 में उर्वरक बिक्री अक्टूबर और नवंबर 2025 के महीनों से संबंधित है।
स्रोत: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए), भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसायटी (एसआईएएम); एनएसओ; आरबीआई; रसायन और उर्वरक मंत्रालय (एमओसीएण्डएफ); ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी); नीलसेनक्यू की खुदरा लेखापरीक्षा सेवा; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

रही, लेकिन जनवरी-फरवरी 2026 में यह स्थिति उलट गई, और शहरी क्षेत्रों में मांग ग्रामीण क्षेत्रों की मांग से आगे निकल गई।

रिज़र्व बैंक के शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के जनवरी 2026 राउंड के अनुसार, मौजूदा स्थिति सूचकांक (सीएसआई) और भविष्य की उम्मीदों से संबंधित सूचकांक दोनों में पिछले राउंड की तुलना में थोडी कमी आई हालाँकि, जनवरी 2026 की तुलना में मार्च 2026 में उपभोक्ता खर्च को लेकर मौजूदा धारणाओं और एक साल आगे की उम्मीदों, दोनों में मामूली सुधार हुआ है (सारणी III.3)।

2025-26 की दूसरी छमाही में श्रम बाज़ार की स्थिति मिली-जुली रही (चार्ट III.3)। चौथी तिमाही (फरवरी 2026 तक) में श्रमिक-जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में सुधार हुआ, जबकि श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) मोटे तौर पर स्थिर रही, जिसमें महीने-दर-महीने कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिला। तीसरी तिमाही में बेरोज़गारी दर में कमी आई, जनवरी 2026 में यह थोड़ी बढ़ी, और फरवरी में इसमें फिर नरमी आई। तीसरी तिमाही में रोज़गार की संरचना में स्वरोज़गार की ओर और अधिक झुकाव देखने को मिला, और इसके साथ ही नियमित वेतनभोगी रोज़गार के हिस्से में कुछ कमी आई।

सारणी III.3: निवल प्रतिक्रियाओं पर आधारित शहरी उपभोक्ता विश्वास का सारांश

(प्रतिशत प्रतिक्रिया)

मुख्य वेरियबल्स	वर्तमान धारणाएँ		एक साल आगे अपेक्षाएँ	
	जन-26	मार्च-26	जन-26	मार्च-26
आर्थिक स्थिति	-3.5	-8.6	29.3	23.1
रोजगार	-6.3	-9.1	33.0	25.2
कीमत स्तर	-81.2	-85.2	-75.2	-76.7
आय	3.3	3.0	50.1	48.4
व्यय	78.0	78.4	80.0	81.2
उपभोक्ता विश्वास सूचकांक	98.1	95.7	123.4	120.2

टिप्पणी: 'शुद्ध प्रतिक्रिया' रिपोर्ट में आशावाद दर्शाने वाले उत्तरदाताओं और निराशावाद दर्शाने वालों के प्रतिशत के बीच का अंतर है। यह -100 और 100 के बीच होता है। शून्य से अधिक कोई भी मान विस्तार/आशावाद को इंगित करता है और शून्य से कम मान संकुचन/निराशावाद को इंगित करता है। उपभोक्ता विश्वास सूचकांक = 100 + आर्थिक स्थिति, आय, खर्च, रोजगार और मूल्य स्तर पर शुद्ध प्रतिक्रियाओं का औसत।
स्रोत: शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, आरबीआई।

चार्ट III.3: भारत में रोज़गार की स्थिति

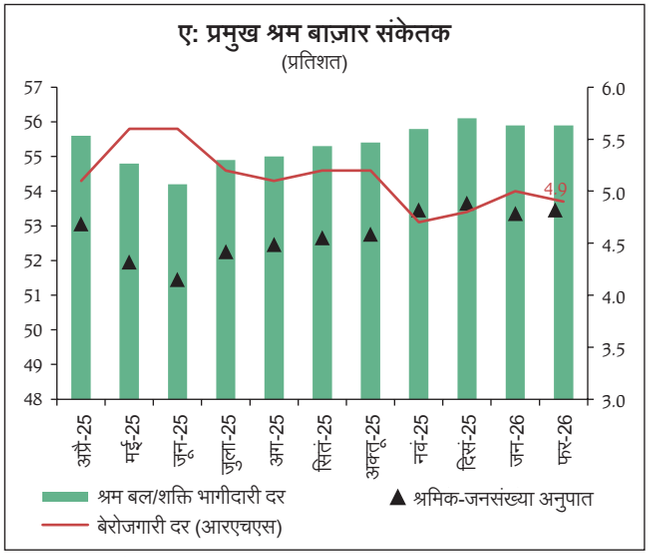

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)।

III.1.2 सकल स्थिर पूंजी निर्माण

2025-26 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) ने अपनी गति बनाए रखी। एसएई के अनुसार, जीएफसीएफ ने 2025-26 में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 2024-25 के 6.4 प्रतिशत से अधिक थी। वास्तविक जीडीपी वृद्धि में इसका दूसरा सबसे बड़ा योगदान रहा (सारणी III.1)। पहली तिमाही में थोड़ी सुस्ती के बाद, अगली तिमाहियों में निवेश गतिविधियों में तेज़ी आई; दूसरी तिमाही में जीएफसीएफ वृद्धि 8.4 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 7.8 प्रतिशत रही।

उच्च-आवृत्ति संकेतकों ने निवेश गतिविधियों के निरंतर बने रहने का संकेत दिया। 2025-26 की तीसरी तिमाही में पूंजीगत वस्तुओं के आयात में दोहरे अंकों की वृद्धि हुई और जनवरी -फरवरी 2026 में भी इसने एक स्वस्थ गति बनाए रखी (सारणी III.4)। तीसरी तिमाही में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में भी मज़बूत वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें फरवरी 2026 में उल्लेखनीय तेज़ी देखने को मिली। निर्माण-संबंधी संकेतक लगातार एक स्वस्थ/मज़बूत तस्वीर पेश करते रहे – 2025-26 की तीसरी तिमाही और जनवरी 2026 में सीमेंट उत्पादन में दोहरे अंकों की वृद्धि हुई, जबकि तीसरी तिमाही में तैयार स्टील की खपत में धीमी गति से वृद्धि हुई, हालाँकि फरवरी 2026 में इसने गति आई।

निवेश गतिविधियों में मज़बूती सर्वेक्षण और कॉर्पोरेट संकेतकों से भी ज़ाहिर होती है। हालांकि, 2025-26 की दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में मौसमी रूप से समायोजित क्षमता उपयोग में थोड़ी नरमी आई, फिर भी यह अपने 12-तिमाही मूविंग एवरेज (क्यूएमए) के करीब और अपने लंबी अवधि के औसत से ऊपर बना रहा। सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों का निवेश कवरेज

सारणी III.4: निवेश मांग के संकेतक

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

संकेतक	2024-25				2025-26				
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	जन	फर
कैपिटल वस्तुएं का आयात	10.0	11.7	6.0	7.9	14.3	8.5	11.4	7.1	19.7
आईआईपी: कैपिलटल वस्तुएं	3.0	4.9	7.4	7.0	9.8	5.6	6.8	4.1	12.5
तैयार इस्पात की खपत	15.3	12.1	8.1	11.2	7.9	8.8	4.6	4.9	12.8
सीमेंट उत्पादन	0.4	3.2	8.7	12.4	8.0	7.3	11.2	11.3	9.3

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस); एनएसओ; संयुक्त संयंत्र समिति; और आर्थिक सलाहकार कार्यालय।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

अनुपात 2025-26 की तीसरी तिमाही में सुधरकर 9.0 हो गया। सेवा क्षेत्र की कंपनियों में, गैर आई सेवा फर्मों का आईसीआर सुधरा, जबकि आईटी सेवा फर्मों का आईसीआर थोड़ा नरम पड़ा, हालांकि, यह फिर भी ऊंचे स्तर पर बना रहा।आईसीआर में सुधार कॉर्पोरेट क्षेत्र की वित्तीय मजबूती की ओर इशारा करता है, जो अनुकूल वित्तीय स्थितियों के साथ मिलकर, चल रहे निवेश चक्र को सहायता पहुंचाएगा (चार्ट III.4)।

समग्र वित्तीय मामले में, 2024-25 में बचत-निवेश का अंतर थोड़ा कम हुआ। सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) और समग्र घरेलू बचत (जीडीएस) के बीच का यह अंतर, एक साल पहले के जीडीपी का 0.8 प्रतिशत से अब घटकर 0.6 प्रतिशत हो गया है। समग्र घरेलू निवेश दर – जिसे मौजूदा कीमतों पर जीसीएफ और जीडीपी के अनुपात से मापा जाता है – पिछले साल के 33.6 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 35.5 प्रतिशत हो गया,यह पूंजी निर्माण में आई तेज़ी का संकेत है। समग्र घरेलू बचत भी एक साल पहले के 32.8 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में जीडीपी का 34.9 प्रतिशत हो गई, यह दर्शाता है कि आम सरकारी क्षेत्र द्वारा की जाने वाली कम बचत कम हुई है, और साथ ही घरेलू क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत में बढ़ोतरी हुई है (चार्ट III.5ए)।[3] ये रुझान बताते हैं कि घरेलू निवेश के लिए बाहरी बचत पर निर्भरता काफी कम हो गई है।

2024-25 के दौरान क्षेत्रीय बचत-निवेश संतुलन भी वित्तपोषण के दबावों में कमी आने का संकेत देते हैं। घरेलू क्षेत्र निधियां निवल आपूर्तिकर्ता बना रहा, जिससे वित्तपोषण की स्थितियों में स्थिरता आई। निजी गैर-वित्तीय निगमों का संसाधन अंतराल कम हुआ, जो उच्च बचत और कम निवेश को दर्शाता है, जबकि राजकोषीय सुधार ने सामान्य सरकारी अबचत को कम किया (चार्ट III.5बी)। कुल मिलाकर, समग्र संसाधन अंतराल का कम होना वित्तपोषण की स्थितियों में सुधार का संकेत देता है, जो निवेश चक्र को आधार प्रदान करता है।

III.1.3 सरकारी उपभोग

एसएई के अनुसार, 2025-26 में जीएफसीई में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के 6.5 प्रतिशत की तुलना में थोड़ी अधिक है। जीएफसीई ने 2025-26 तीसरी तिमाही में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि और चौथी तिमाही में 9.4 प्रतिशत की अंतर्निहित वृद्धि दर्ज की। केंद्र सरकार का राजस्व व्यय, ब्याज भुगतान और सब्सिडी घटाने के बाद दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान कम हुआ, जिसका आंशिक कारण राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिए जाने वाले अनुदान में कमी आना था। हालाँकि, यह उम्मीद है कि चौथी तिमाही में इसमें उच्च वृद्धि दर्ज की जाएगी ताकि पूरे वर्ष के संशोधित अनुमानों को प्राप्त किया जा सके (चार्ट III.6)। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार, 2026-27

चार्ट III.4: सर्वेक्षण और कॉर्पोरेट संकेतक

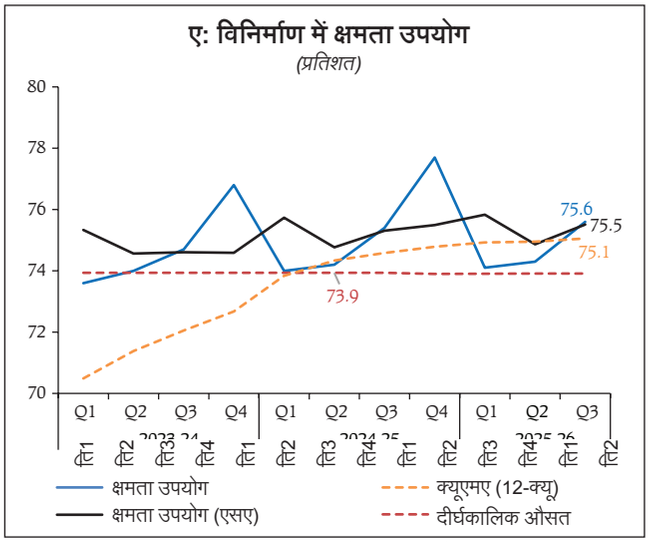

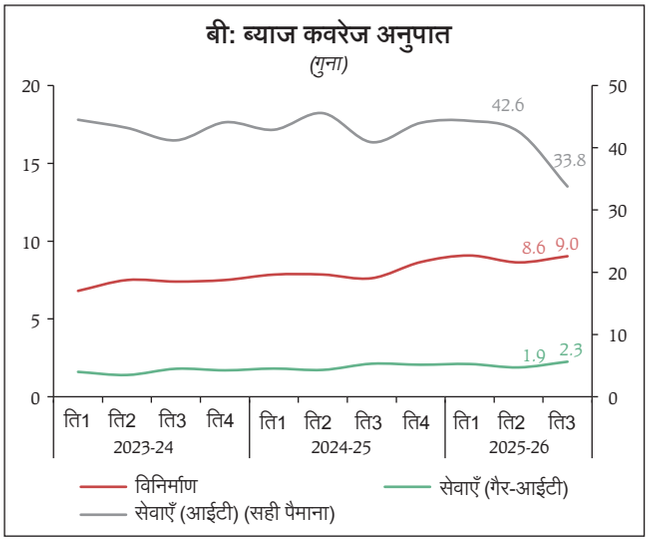

टिप्पणी: क्यूएमए (12-क्यू): 12-तिमाही मूविंग औसत; एसए: मौसमी रूप से समायोजित ।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान ।

[3] 2024-25 में परिवारों की निवल वित्तीय बचत दर जीडीपी के 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 5.9 प्रतिशत थी।

चार्ट III.5: बचत और निवेश का अंतर

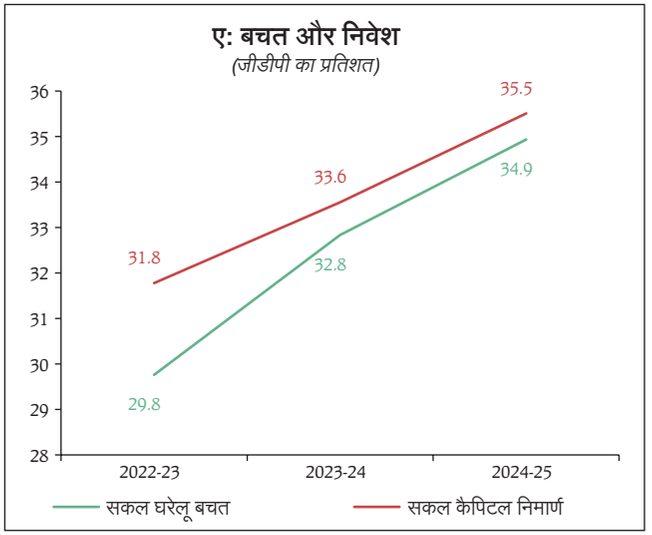

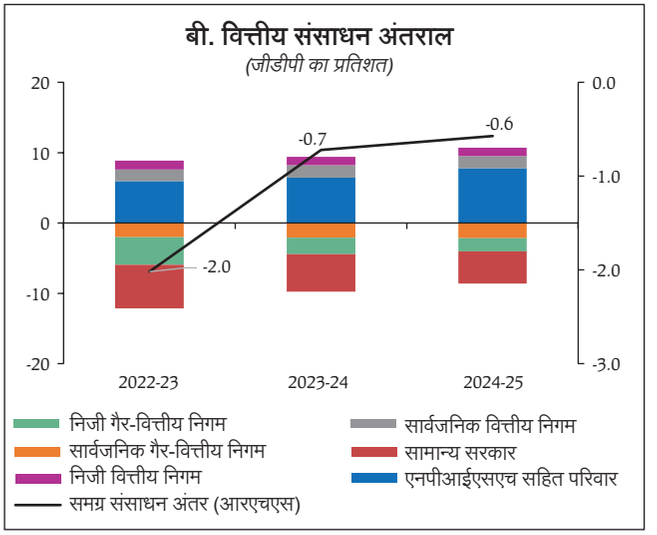

टिप्पणी: एनपीआईएसएच: परिवारों को सेवा प्रदान करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाएँ।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान

के लिए राजस्व व्यय, ब्याज भुगतान और सब्सिडी घटाने के बाद में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमानों में दर्ज 3.1 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है।

केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी)[4], 2025-26 (आरई) में जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहा। यह 2025-26 तक जीएफडी को 4.5 प्रतिशत से नीचे रखने के अपने मध्यम-अवधि के लक्ष्य के अनुरूप था (जैसा कि केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित किया गया था)। यह उपलब्धि खर्चों के युक्तिसंगत बनाने के ज़रिए हासिल की गई, जिसमें बजट में अनुमानित गैर-कर राजस्व से अधिक प्राप्ति से मदद मिली। 2026-27 (बीई) के लिए, केंद्र सरकार ने जीएफडी को जीडीपी के 4.3 प्रतिशत पर रखते हुए कम करने का बजट बनाया, जिससे राजकोषीय विवेकपूर्ण मार्ग पालन करना सुनिश्चित हुआ। आगे का राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मुख्य रूप से राजस्व व्यय को जीडीपी के 10.5 प्रतिशत तक सीमित करके (2025-26 (आरई) के 10.8 प्रतिशत से कम करके) बजट में शामिल किया गया है, जबकि पूंजीगत व्यय को जीडीपी के 3.1 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है। राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय का अनुपात[5] (आरईसीओ) जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर कम बना रहा, जो व्यय की गुणवत्ता के संरक्षण को दर्शाता है (सारणी III.5)।

2025-26 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 14.5 प्रतिशत बढ़ा, जबकि राजस्व व्यय, ब्याज भुगतान और प्रमुख सब्सिडी को छोड़कर में 6.0 प्रतिशत की कमी आई (वर्ष -दर-वर्ष)। प्राप्तियों की तरफ, सकल कर राजस्व में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण कॉर्पोरेशन

चार्ट III.6: 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार का राजस्व व्यय और पूंजी परिव्यय

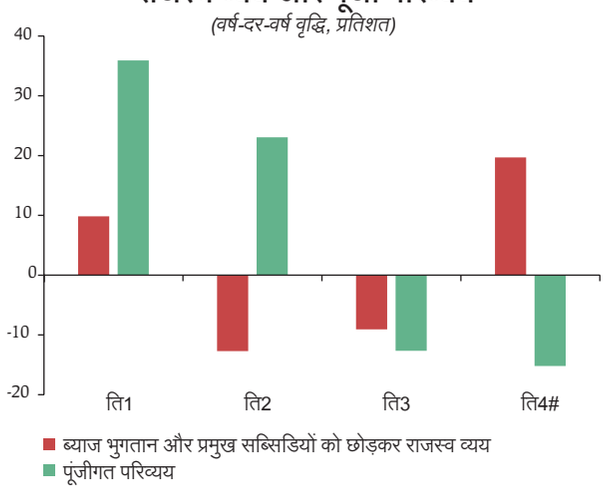

टिप्पणियाँ: #: निहित। पूंजीगत परिव्यय, ऋणों और अग्रिमों को छोड़कर किया गया पूंजीगत व्यय है।
स्रोत: महालेखा नियंत्रक (सीजीए); और केंद्रीय बजट 2026-27।

[4] इस अध्याय में, केंद्र सरकार के राजकोषीय संकेतकों की गणना जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, पुरानी जीडीपी श्रृंखला (आधार वर्ष 2011-12) का उपयोग करके की गई है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नई जीडीपी श्रृंखला (आधार वर्ष 2022-23) वर्ष 2026-27 और 2022-23 से पहले के वित्तीय वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं है।

[5] कम आरईओसी अनुपात सार्वजनिक व्यय की बेहतर गुणवत्ता को दर्शाता है।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

टैक्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क थे। प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, कॉर्पोरेशन टैक्स मे वर्ष-दर-वर्ष 12.4 प्रतिशत की मज़बूत वृद्धि दर्ज की गई; इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान इसमें 1.9 प्रतिशत की कमी आई थी। आयकर संग्रह में 2025-26 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के 22.0 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है। अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, जीएसटी संग्रह की वृद्धि दर एक साल पहले के 11.6 प्रतिशत से घटकर 5.1 प्रतिशत रह गई, जबकि सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रह में वृद्धि तेज़ हुई। 2025-26 के दौरान, मासिक जीएसटी संग्रह[6] (केंद्र + राज्य) का औसत ₹1.94 लाख करोड़ रहा (चार्ट III.7)।

राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का कुल जीएफडी, 2025–26 के लिए जीडीपी का 3.3 प्रतिशत बजट किया गया है, जो 2024-25 के अस्थायी अनुमानों के बराबर ही है (सारणी III.6)। राज्यों ने राजस्व प्राप्तियों में 23.0 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो कर और गैर-कर, दोनों तरह के राजस्व से प्रेरित है। पूंजीगत व्यय पर लगातार ज़ोर देने से राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय अनुपात में सुधार हुआ है, और 2025-26 (बीई) में पूंजीगत परिव्यय और जीडीपी अनुपात में वृद्धि हुई है (चार्ट III.8)। आगे चलकर, केंद्र द्वारा 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता' मद में ₹2 लाख करोड़ का अतिरिक्त आवंटन, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी, राज्यों के पूंजीगत व्यय को और बढ़ावा देगा।

सारणी III.5: केंद्र सरकार का वित्त

(जीडीपी का प्रतिशत)

संकेतक	2023-24	2024-25	2025-26 (आरई)	2026-27 (बीई)
1. राजस्व प्राप्तियाँ	9.1	9.2	9.4	9.0
ए. कर राजस्व (निवल)	7.7	7.6	7.5	7.3
बी. गैर-कर राजस्व	1.3	1.6	1.9	1.7
2. . गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियाँ	0.2	0.1	0.2	0.3
3. राजस्व व्यय	11.6	10.9	10.8	10.5
ए. ब्याज भुगतान	3.5	3.4	3.6	3.6
बी. प्रमुख सब्सिडी	1.4	1.2	1.2	1.0
4. राजस्व व्यय ब्याज भुगतान को छोड़कर और प्रमुख सब्सिडी	6.7	6.4	6.1	5.9
5. पूंजीगत व्यय	3.2	3.2	3.1	3.1
6. पूंजीगत परिव्यय	2.6	2.6	2.5	2.4
7. कुल व्यय	14.8	14.1	13.9	13.6
8. सकल राजकोषीय घाटा	5.5	4.8	4.4	4.3
9. राजस्व घाटा	2.5	1.7	1.5	1.5
10. प्राथमिक घाटा	2.0	1.4	0.8	0.7
ज्ञापन:				
राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय का अनुपात	4.4	4.2	4.4	4.4

नोट: आरई: संशोधित अनुमान; बीई: बजट अनुमान।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

2025-26 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान राज्यों के घाटे के संकेतक, बीई के अनुपात के रूप में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक थे (चार्ट III.9ए), जिसका मुख्य कारण राजस्व प्राप्तियों में आई कमी थी। राज्यों का वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)—जो कर राजस्व का मुख्य स्रोत है—की वृद्धि दर धीमी रही, जो कुछ हद तक जीएसटी दरों के युक्तिकरण को दर्शाती है। दूसरी ओर, राज्यों के उत्पाद शुल्क संग्रह, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में मज़बूत वृद्धि दर्ज की गई। राज्यों का राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में धीमी गति से बढ़ा, जबकि पूंजीगत व्यय में एक सकारात्मक बदलाव दर्ज किया गया (चार्ट III.9बी)।

2025-26 में केंद्र सरकार की कुल बाज़ार उधारी ₹14.61 लाख करोड़ रही, जो बजट अनुमानों ₹14.82 लाख करोड़ से थोड़ी कम थी। सक्रिय ऋण एकत्रीकरण के प्रयास में, रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार की ओर से 14 स्विच नीलामी/संचालन किए, जिनका कुल मूल्य ₹2.75 लाख करोड़ था; इसमें कम परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों को अधिक परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों से बदलने का काम शामिल था। 2025-26 के दौरान जारी की गई प्रतिभूतियों पर भारित औसत प्रतिफल 2024-25 के 7.0 प्रतिशत से घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई। उधारी की भारित औसत परिपक्वता भी पिछले वर्ष के 20.7

[6] जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह सहित।

चार्ट III.7: केंद्र सरकार का कर संग्रह

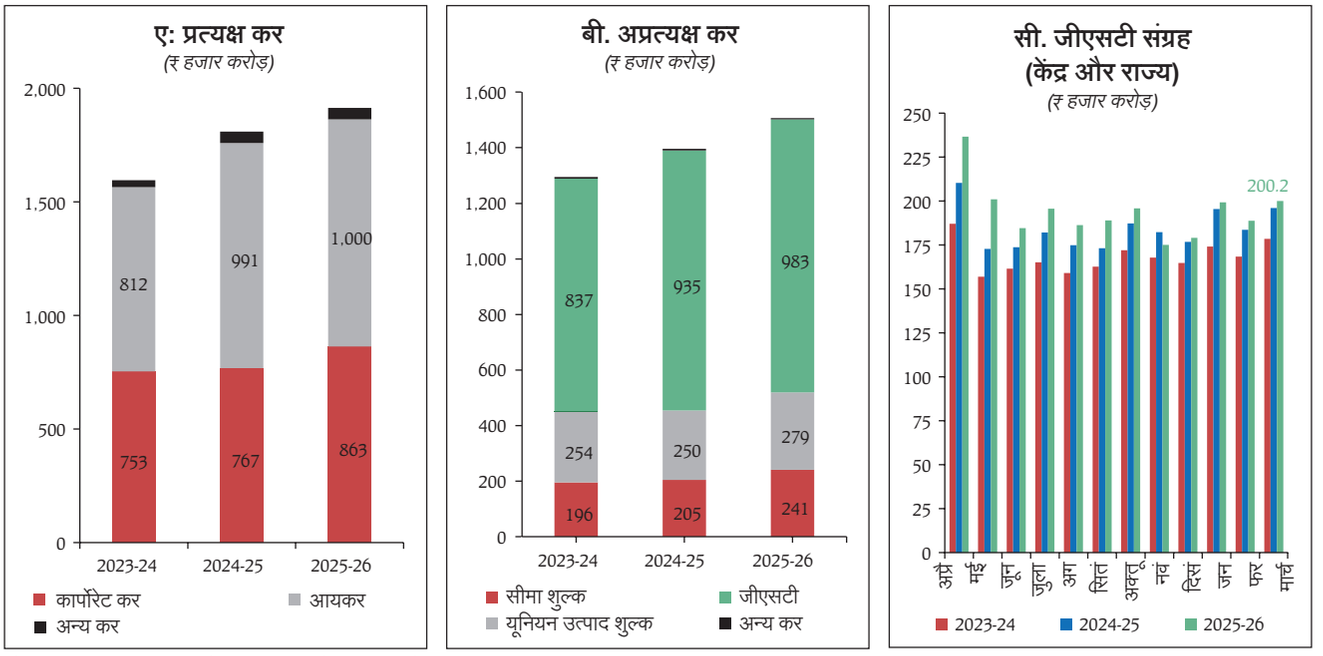

स्रोत: सीजीए; प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी); और जीएसटी पोर्टल।

वर्षों से घटकर 18.9 वर्ष हो गई। राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 2025-26 में ₹12.76 लाख करोड़ की कुल बाज़ार उधारी जुटाई, जो पिछले वर्ष में स्वीकृत कुल राशि ₹10.73 लाख करोड़ से अधिक थी [सारणी III.7]। 2026-27 के लिए केंद्र की सकल बाजार उधारी और शुद्ध उधारी का बजट क्रमशः ₹17.20 लाख करोड़ और ₹11.73 लाख करोड़ है। प्राप्तियों और भुगतानों के बीच अस्थायी विसंगतियों को पूरा करने के लिए 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार के लिए डब्ल्यूएमए की सीमा 2.5 लाख करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। जनवरी, 2026 को रिज़र्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के साथ एक समझौते के परिणामस्वरूप, जीएनसीटीडी सहित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संशोधित कुल डब्ल्यूएमए सीमा 60,118 करोड़ रुपये की मौजूदा सीमा के मुकाबले 61,008 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

सारणी III.6: राज्य सरकार का वित्त - प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी का प्रतिशत)

मद	2023-24 (ए)	2024-25 (पीए)	2025-26 (बीई)
राजस्व घाटा	0.3	0.6	0.2
सकल राजकोषीय घाटा	2.9	3.3	3.3
प्राथमिक घाटा	1.2	1.7	1.5

टिप्पणी: डेटा 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
ए: वास्तविक; पीए: अनंतिम खाते; बीई: बजट अनुमान।
स्रोत: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बजट दस्तावेज़ और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी)।

चार्ट III.8: राज्यों का पूंजीगत परिव्यय

(अनुपात, बायां मान, जीडीपी का प्रतिशत, दायां मान)

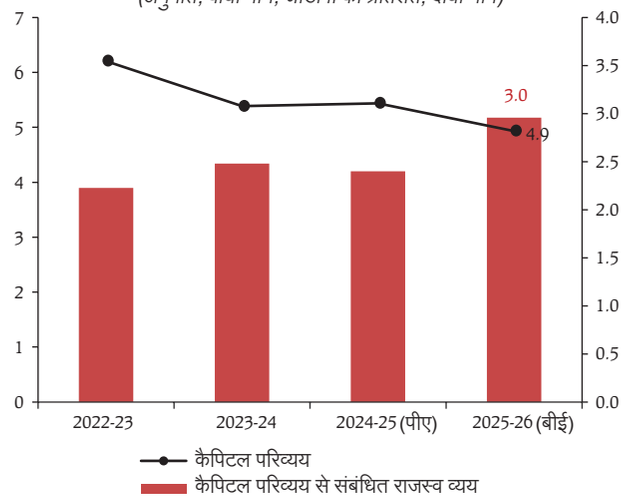

टिप्पणी: डेटा 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
पीए: अनंतिम खाते; बीई: बजट अनुमान
स्रोत: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बजट दस्तावेज़; और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

मौद्रिक नीति वक्तव्य

चार्ट III.9 राज्यों के प्रमुख राजकोषीय निष्पादन संकेतक (अप्रैल - जनवरी)

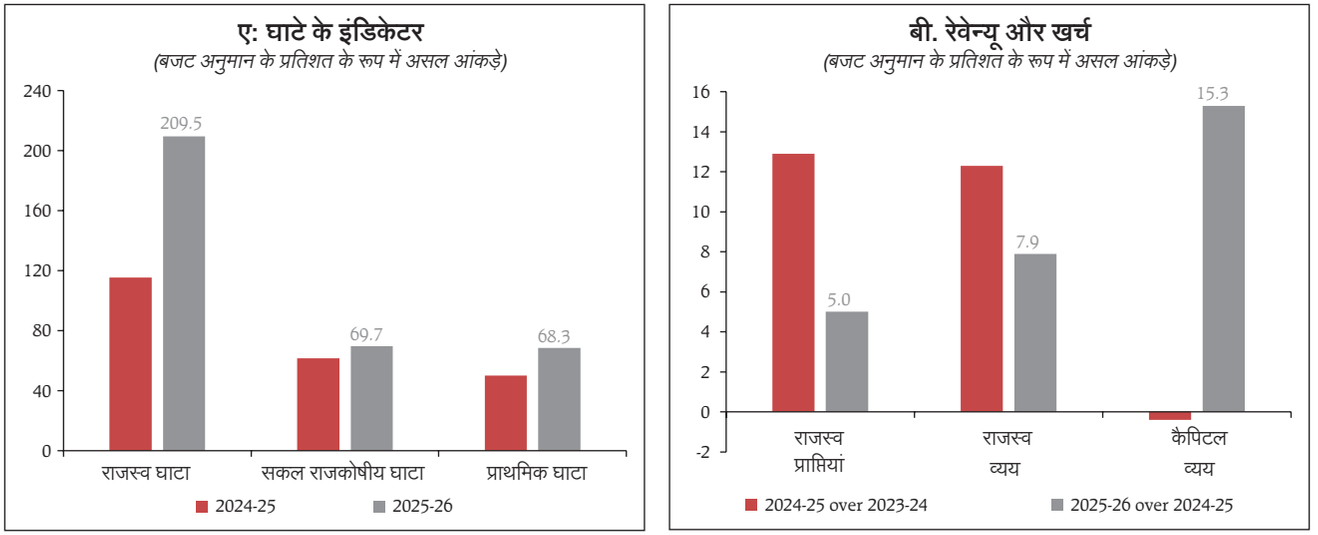

टिप्पणी: डेटा 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
स्रोत: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बजट दस्तावेज़; और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी)।

III.1.4 बाह्य मांग

2025-26 की दूसरी छमाही[7] में, बढ़ते व्यापारिक तनाव और ऊंचे टैरिफ से जुड़ी नीतिगत अनिश्चितता के बीच वैश्विक मांग की स्थितियां कमजोर पड़ गईं। चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद, वस्तुओं का निर्यात लचीला बना रहा और 2025-26 की दूसरी छमाही (अक्टूबर-फरवरी) में इसमें मामूली 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेवाओं के निर्यात में लगातार बने लचीलेपन ने भी समग्र वृद्धि को सहारा दिया। निर्यात की तुलना में पण्य आयात अधिक गति से बढ़ने के साथ, व्यापार घाटा 2025-2026 की दूसरी छमाही (अक्तूबर -फरवरी) में बढ़कर 155.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2024-25 की दूसरी छमाही (अक्तूबर -फरवरी) में 115.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट III.10)।

विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात के प्रदर्शन में भिन्न स्तर दिखे। सितंबर-फरवरी 2025-26 के दौरान पण्य निर्यात में वृद्धि मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स तथा समुद्री उत्पादों से हुई। अमेरिका को शिपमेंट में कमी से उच्च अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव स्पष्ट दिखा, विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों, जैसे रत्न और आभूषण, ऑटोमोबाइल और कुछ ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कपड़ा और रेडीमेड वस्त्र में, हालांकि अन्य बाजारों में विविधीकरण आंशिक रूप से प्रभाव की भरपाई करता रहा। कुल निर्यात में गिरावट लाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पाद, चावल, रत्न और आभूषण, वस्त्र और प्लास्टिक और लिनोलियम शामिल हैं। (चार्ट III.11)।

सारणी III.7: सरकारी बाज़ार उधार

(₹ करोड़)

	2024-25			2025-26		
	केंद्र	राज्य	कुल	केंद्र	राज्य	कुल
निवल उधार	11,62,879	7,53,345	19,16,224	11,32,834	9,03,887	20,36,721
सकल उधार केंद्र	14,00,697	10,73,310	24,74,007	14,61,000	12,76,430	27,37,430

स्रोत: भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[7] यूएसए ने अगस्त 2025 में 25 प्रतिशत के अतिरिक्त टैरिफ लगाए, जिससे भारतीय सामानों पर कुल टैरिफ बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया।

चार्ट III.10: पण्य व्यापार

(प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, बायां मान, अरब यूएस डॉलर, दायां मान)

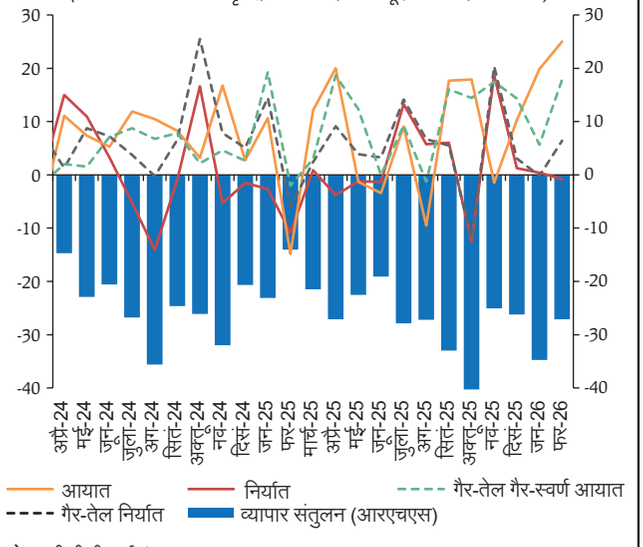

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस।

सितंबर-फरवरी 2025-26 के दौरान पण्य आयात में वृद्धि सोने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चांदी, उर्वरक और मशीनरी, इलेक्ट्रिकल और गैर-इलेक्ट्रिक वस्तुओं के उच्च आयात से प्रेरित थी। इसके विपरीत, पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद, लोहा और इस्पात, दालें, कोयला, कोक और ब्रिकेट, और रासायनिक सामग्री और उत्पादों ने नकारात्मक योगदान दिया (चार्ट III.12)। इस अवधि के दौरान सोने का आयात 78.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) तेजी से बढ़कर यूएस $ 52 बिलियन पर पहुँचा, जो कि मूल्य में तीव्र बढ़ोतरी को दर्शाता है। जबकि पेट्रोलियम, कच्चे तेल और उत्पादों में 5.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

2025-26 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान सेवा निर्यात में 8.9 प्रतिशत का अच्छा विस्तार हुआ, हालांकि पिछले साल की इसी अवधि के 13.1 प्रतिशत से यह घटा। सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं की निरंतर वैश्विक मांग के कारण, भारत 2025-26 (अप्रैल-जनवरी) में निर्यात वृद्धि के मामले में दुनिया भर में शीर्ष पांच सेवा-निर्यातक देशों में से एक बना रहा। 2025-2026 की दूसरी छमाही (अक्तूबर -फरवरी) में, सेवा निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि के 15.5 प्रतिशत की तुलना में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट III.13)। दूसरी छमाही (अक्तूबर – फरवरी) में 4.5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 2025-26 (अप्रैल -फरवरी) के दौरान सेवा आयात में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भुगतान संतुलन के आधार पर, उच्च पण्य व्यापार घाटे के कारण भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) 2025-26 की तीसरी तिमाही के दौरान बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 1.1 प्रतिशत था, जिसका कारण उच्च पण्य व्यापार घाटा रहा जबकि सेवा और विप्रेषण प्राप्तियाँ मजबूत बनी रहीं। वित्तीय खाते में निवल

चार्ट III.11: पण्य निर्यात

ए: निर्यात वृद्धि – सापेक्ष योगदान

प्रतिशत अंक, बायां मान; प्रतिशत; दायां मान

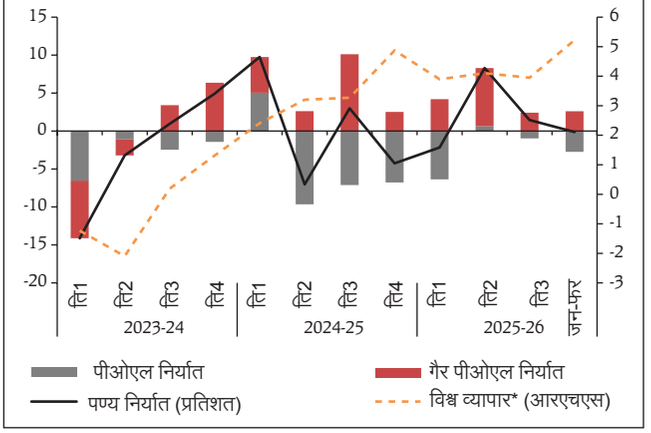

बी: 2025-26 में निर्यातों के मुख्य कारक (सितंबर -फरवरी) - सापेक्ष योगदान

(प्रतिशत अंक)

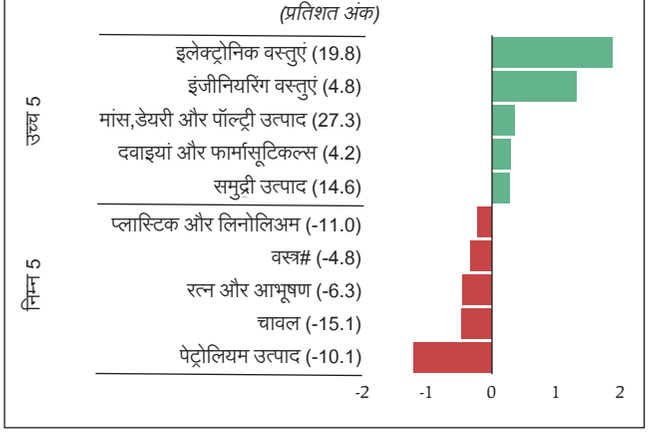

टिप्पणी: *: जनवरी 2026 तक उपलब्ध विश्व व्यापार डेटा। #: वस्त्रों में सभी वस्त्रों के आरएमजी, कपास के धागे/कपड़े/मेडअप, हाथकरघा उत्पाद आदि, जूट उत्पाद, और कालीन शामिल हैं। चार्ट बी में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उस अवधि के दौरान वस्तु के निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत परिवर्तन हैं।

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस; सीपीबी नीदरलैंडस; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

चार्ट III.12: पण्य आयात

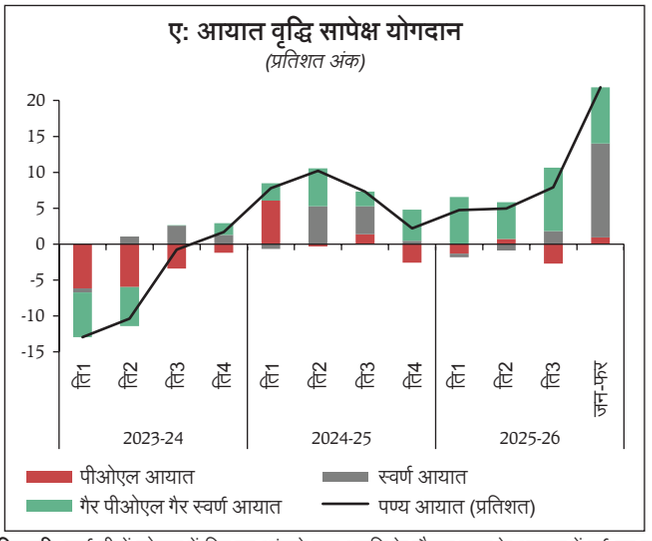

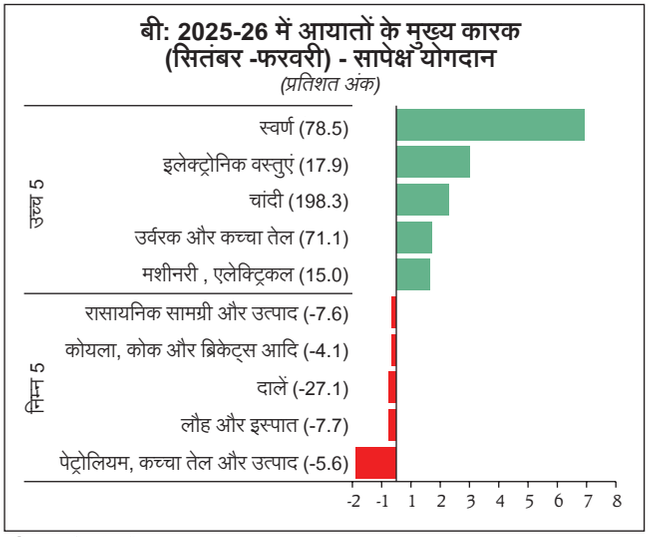

टिप्पणी: चार्ट बी में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उस अवधि के दौरान वस्तु के आयात में वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत परिवर्तन हैं।
स्रोत: डीजीसीआईएंडएस; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

पूंजी प्रवाह सीएडी से कम रहा और विदेशी मुद्रा भंडार घटा। अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान, चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.0 प्रतिशत था, जो एक साल पहले इसी अवधि के दौरान 1.3 प्रतिशत था।

भारत का सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह ने 2025-26 (अप्रैल -फरवरी) (अनंतिम) के दौरान 18.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और यह 88.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसके बाद, बढ़े हुए एफडीआई प्रत्यावर्तन और बहिर्गामी एफडीआई के बावजूद 2025-26 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान निवल एफडीआई एक साल पहले के 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 2025-26 के दौरान अब तक (फरवरी तक) कुल इक्विटी प्रवाह में विनिर्माण, कंप्यूटर सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, व्यावसायिक सेवाओं और संचार सेवाओं की हिस्सेदारी दो-तिहाई से अधिक रही है। इसके अलावा, सिंगापुर, अमेरिका, मॉरीशस, जापान और नेदरलेंड्स भारत में आवक एफडीआई के प्रमुख स्रोत देश थे, जिन्होंने कुल प्रवाह में लगभग तीन-चौथाई का योगदान दिया (सारणी III.8)।

चार्ट III.13: सेवा व्यापार

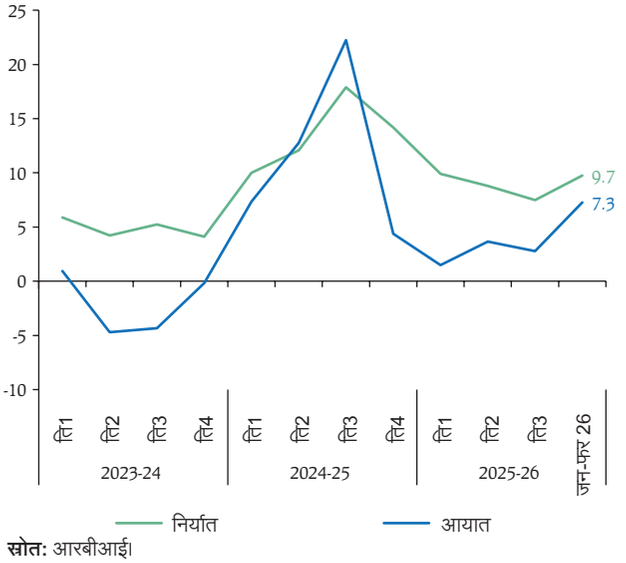

स्रोत: आरबीआई।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) ने 2025-26 के दौरान 16.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध बहिर्गमन दर्ज किया, जिसका मुख्य कारण इक्विटी खंड में बहिर्गमन था। वैश्विक व्यापार तनाव, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़ी अनिश्चितता और पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण इक्विटी खंड में एफपीआई प्रवाह नकारात्मक बने रहे। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार करार और अंतरिम भारत-अमेरिका व्यापार रूपरेखा की घोषणा के बाद विदेशी निवेशकों का मनोभाव सकारात्मक हो गया। हालांकि, पश्चिम एशिया में संघर्ष के बाद वैश्विक जोखिम

सारणी III.8: शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष एवं पोर्टफोलियो निवेश

(अरब अमेरिकी डॉलर)

	2023-24				2024-25				2025-26			
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
निवल एफडीआई	4.7	-0.8	4.0	2.3	6.2	-2.8	-2.8	0.4	4.8	1.9	-3.7	3.2@
निवल एफपीआई*	16.1	5.3	11.7	11.6	0.9	19.8	-11.4	-6.0	1.6	-5.8	0.1	-12.4

टिप्पणी: @: जनवरी 2026 के लिए डेटा। *: शुद्ध एफपीआई डेटा एनएसडीएल द्वारा प्रकाशित दैनिक डेटा से प्राप्त किया गया है; और 2025-26 के लिए डेटा 17 मार्च तक है ।
स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल); और आरबीआई।

रुख बिगड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2026 में 13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का महत्वपूर्ण निवल बहिर्वाह हुआ। 2025-26 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान, ऋण खंड के तहत 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज हुआ, जो अनिश्चित वैश्विक परिवेश में सुरक्षित संपत्तियों की पसंद को दर्शाती है। हालांकि, मार्च 2026 में, पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण ऋण खंड में एफपीआई ने भी 1.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया।

भारत का निवल बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) अंतर्वाह 2025-26 (अप्रैल -फरवरी) के दौरान घटकर 11.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 16.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ईसीबी में मंदी, मौद्रिक नीति सुलभता के बाद अनुकूल घरेलू ब्याज दरें और बढ़ती हेजिंग लागत जो ईसीबी ऋणों को महंगा बना रही हैं, को दर्शाती है। ऑन-लेंडिंग/सब-लेंडिंग के अलावा, ईसीबी का उपयोग पूर्व के ईसीबी के पुनर्वित्तपोषण, पूंजीगत माल के आयात और नई परियोजनाओं के लिए किया गया था। 2025- 26 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान लगभग 69.4 प्रतिशत नई ईसीबी[8] को हेज किया गया। गैर-निवासी जमा के तहत निवल अंतर्वाह 2025-26 [अप्रैल - फरवरी (अनंतिम)] में पिछले वर्ष के 14.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 11.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका कारण एफसीएनआर(बी) जमा राशियों के तहत निवल अंतर्वाह में गिरावट थी। 27 मार्च, 2026 तक, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 688.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो बीओपी आधार पर वार्षिकीकृत पण्य आयातों के 10.9 महीने के बराबर या दिसंबर 2025 के अंत तक बाहरी ऋण स्थिति के 89.9 प्रतिशत के बराबर था।

III.2 समग्र आपूर्ति

मूल कीमतों पर वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) द्वारा मापी जाने वाली समग्र आपूर्ति, 2025-26 में 7.7 प्रतिशत बढ़ी, जो 2024-25 में 7.3 प्रतिशत से अधिक थी। सेवा क्षेत्र की मजबूत गतिविधि और उद्योग क्षेत्र में लगातार विस्तार ने जीवीए की वृद्धि को गति दी [सारणी III.9 और चार्ट III.14].। चौथी तिमाही के लिए 7.4 प्रतिशत के निहित अनुमान के साथ 2025-26 की तीसरी तिमाही में जीवीए 7.8 प्रतिशत बढ़ा (पहली तिमाही में 7.0 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 8.6 प्रतिशत)। एसएएआर ने भी समान रुख अपनाया और चौथी तिमाही में 7.7 पर पहूंचा।

III.2.1 कृषि

2024-25 में 4.2 प्रतिशत की तुलना में 2025-26 (एसएई) में कृषि एवं सहायक गतिविधियों का वास्तविक जीवीए तीसरी तिमाही में 1.4 की धीमी गति के साथ 2.4 प्रतिशत बढ़ा । यह मंदी आंशिक रूप से पश्चिमी और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में *खरीफ* की फसल पर मौसम संबंधी बाधाओं के कारण हुई । चौथी तिमाही में, अनुकूल रबी परिस्थितियों और जलाशयों के पर्याप्त भरे हुए स्तर के कारण कृषि क्षेत्र को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

2 अप्रैल, 2026 तक, प्रमुख जलाशयों में जल स्तर पूर्ण क्षमता का 46.7 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.4 प्रतिशत अधिक और सामान्य (दशकीय) औसत से 26.7 प्रतिशत अधिक था। पूर्वी क्षेत्र के अलावा सभी क्षेत्रों में भंडारण सामान्य औसत से अधिक थे।

सरकार ने 1 अक्तूबर, 2025 को प्रमुख रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 4.0-10.1 प्रतिशत की वृद्धि

[8] ईसीबी में विदेशी मुद्रा ऋण और रुपये में मूल्यवर्गीकृत ऋण एवं बांड शामिल हैं।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

सारणी III.9: वास्तविक जीवीए वृद्धि

(वर्ष दर वर्ष, वृद्धि प्रतिशत)

क्षेत्र	2024-25	2025-26	भारित अंशदान		2024-25				2025-26			
	(एफआरई)	(एसएई)	2024-25	2025-26	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4#
कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना	**4.2**	**2.4**	**0.8**	**0.5**	**2.6**	**4.1**	**5.8**	**3.8**	**4.2**	**2.3**	**1.4**	**2.1**
उद्योग	**8.7**	**9.5**	**1.7**	**1.9**	**9.6**	**4.6**	**9.7**	**10.8**	**8.0**	**11.4**	**11.1**	**7.8**
खनन और उत्खनन	11.7	4.1	0.2	0.1	11.9	8.3	13.1	12.9	4.5	6.1	4.7	1.7
उत्पादन	9.3	11.5	1.4	1.8	9.4	4.9	10.8	11.8	10.6	13.2	13.3	9.3
बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिताओं	2.9	1.5	0.1	0.0	9.2	-0.2	0.6	2.1	-1.9	3.9	1.5	2.7
सेवाएं	**7.8**	**8.7**	**4.7**	**5.3**	**8.5**	**7.8**	**7.9**	**7.0**	**7.5**	**9.2**	**9.1**	**8.9**
निर्माण	7.3	7.1	0.7	0.6	8.7	6.1	6.4	8.0	5.4	8.7	6.6	7.6
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	6.6	10.1	0.9	1.4	6.9	6.6	6.7	6.3	9.4	10.4	11.0	9.7
वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं	10.0	9.9	2.5	2.5	10.3	10.0	11.1	8.8	8.8	9.9	11.2	9.6
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	5.0	5.8	0.6	0.7	6.9	6.0	4.4	3.2	4.3	6.9	4.5	7.5
बुनियादी कीमतों पर जीवीए	**7.3**	**7.7**	**7.3**	**7.7**	**7.6**	**6.5**	**7.8**	**7.1**	**7.0**	**8.6**	**7.8**	**7.4**

टिप्पणी: एफआरई: प्रथम संशोधित अनुमान; एसएई : द्वितीय अग्रिम अनुमान; #: अंतर्निहित।
स्रोत: एनएसओ,एमओएसपीआई; और आरबीआई कर्मचारी अनुमान।

की, जो सात वर्षों में सबसे अधिक औसत वृद्धि है। इसके बाद, 2025-26 के लिए समग्र रबी बुआई पूर्ण मौसम सामान्य क्षेत्र से 6.1 प्रतिशत अधिक और पिछले वर्ष की तुलना में 2.4 प्रतिशत अधिक रही। सभी प्रमुख फसल समूहों के अंतर्गत आने वाला पिछले वर्ष के स्तर से अधिक था। गेहूं, जो पूर्ण मौसम क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है, ने पिछले वर्ष के क्षेत्रफल से 1.9 प्रतिशत अधिक क्षेत्र बनाया; दालों में 3.7 प्रतिशत और तिलहन में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चार्ट III.14: जीवीए वृद्धि और गति

(प्रतिशत)

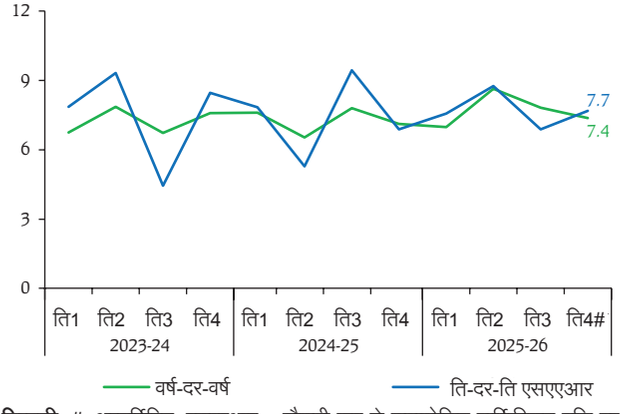

टिप्पणी: #: अन्तर्निहित; एसएएआर – मौसमी रूप से समायोजित वार्षिकीकृत वृद्धि दर (आधार संशोधन के बाद, तिमाही वास्तविक जीवीए श्रृंखला को X13 एआरआईएमए- सीट्स का उपयोग करके मौसम के अनुसार समायोजित किया गया है। जो 2011-12 और 2022-23 आधार श्रृंखला के समान तिमाहियों के माध्य स्प्लाइसिंग के माध्यम से निर्मित एक वापसी श्रृंखला पर आधारित है, और 2022-23 में आधार-स्तर परिवर्तनों और समय के अनुसार कारकों को संरेखित करने के लिए अस्थायी शिफ्ट समायोजन लागू किए गए हैं)।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

2025-26 के लिए एसएई ने खाद्यान्न उत्पादन को 3487 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर रखा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है (सारणी III.10)। प्रमुख फसलों में, चावल का उत्पादन 1.3 प्रतिशत बढ़ा, जिसमें रबी उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। गेहूं का उत्पादन 1.9 प्रतिशत बढ़कर 1,202 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। रबी दालों के उत्पादन में वृद्धि के कारण दालों का उत्पादन 3.9 प्रतिशत अधिक था, जबकि अत्यधिक मानसून के कारण खरीफ दालों का उत्पादन घटा। वाणिज्यिक फसलों में, तिलहन और कपास का उत्पादन घटा, जबकि गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा।

2025-26 में बागवानी फसलों का उत्पादन पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार 3,708 लाख टन तक पहुंच गया, जो 2024-25 के अंतिम अनुमानों की तुलना में कुछ अधिक था, जिसका मुख्य कारण केले, टमाटर और बागान फसलों के उत्पादन में वृद्धि थी।

सारणी III.10: 2025-26 में कृषि उत्पादन

(लाख टन)

फसल	2024-25		2025-26	2025-26 में अंतर (प्रतिशत)	
	एसएई	अंतिम अनुमान	एसएई	Over SAE 2024-25	Over Final 2024-25
1. अनाज	3309	3386	3487	5.4	3.0
खरीफ	1664	1695	1741	4.7	2.8
रबी	1645	1692	1745	6.1	3.2
क. चावल	1364	1389	1406	3.1	1.3
ख. गेहूं	1154	1179	1202	4.1	1.9
ग. दालें	230	230	239	3.7	3.9
2. तिलहन	417	417	410	-1.6	-1.6
3. गन्ना	4351	4546	5002	15.0	10.0
4. कपास #	294	297	291	-1.1	-2.1
5. जूट एवं मेस्ता ##	86	88	83	-3.3	-5.2

टिप्पणियाँ: #: प्रत्येक 170 किलो के लाख गांठें; ##: प्रत्येक 180 किलो के लाख गांठें।
एसएई: द्वितीय अग्रिम अनुमान।
डाटा केवल खरीफ और रबी मौसमों को कवर करता है।
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; (एमओएएफडब्ल्यू) और भारत सरकार।

चार्ट III.15: फसलों और सहायक गतिविधियों का योगदान

(प्रतिशत अंक)

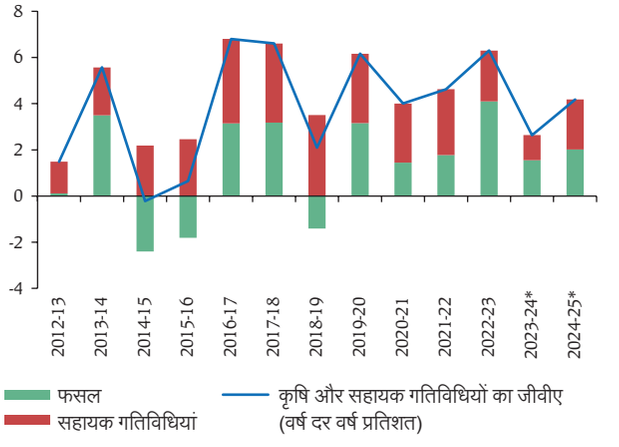

टिप्पणी: *: 2023–24 और 2024–25 के लिए आंकड़े 2011-12 के नए जीवीए आधार का उपयोग करते हैं।
स्रोत: एनएसओ: और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

पशुपालन, वानिकी और मत्स्यपालन जैसी सहायक गतिविधियों ने 2024-25 में कृषि जीवीए वृद्धि में लगभग 52 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट III.15)।

28 फरवरी, 2026 तक, 2025-26 के खरीफ बाजार सत्र के लिए चावल की खरीद 462.8 लाख टन तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.9 प्रतिशत अधिक है। चावल का भंडार 739.4 लाख टन था, जो बफर आवश्यकता का 9.7 गुना था, जबकि गेहूं का भंडार 236.2 लाख टन था, जो बफर मानक का 1.7 गुना था (चार्ट III.16)। सार्वजनिक भंडार में अच्छी स्थिति और आगामी रबी उत्पादन में आशाजनक भविष्य की संभावना को देखते हुए, सरकार ने गेहूं के लिए खुले बाजार बिक्री की घोषणा की, गेहूं के निर्यात को आंशिक रूप से फिर से खोला

चार्ट III.16: स्टॉक और प्रापण – चावल और गेहूं

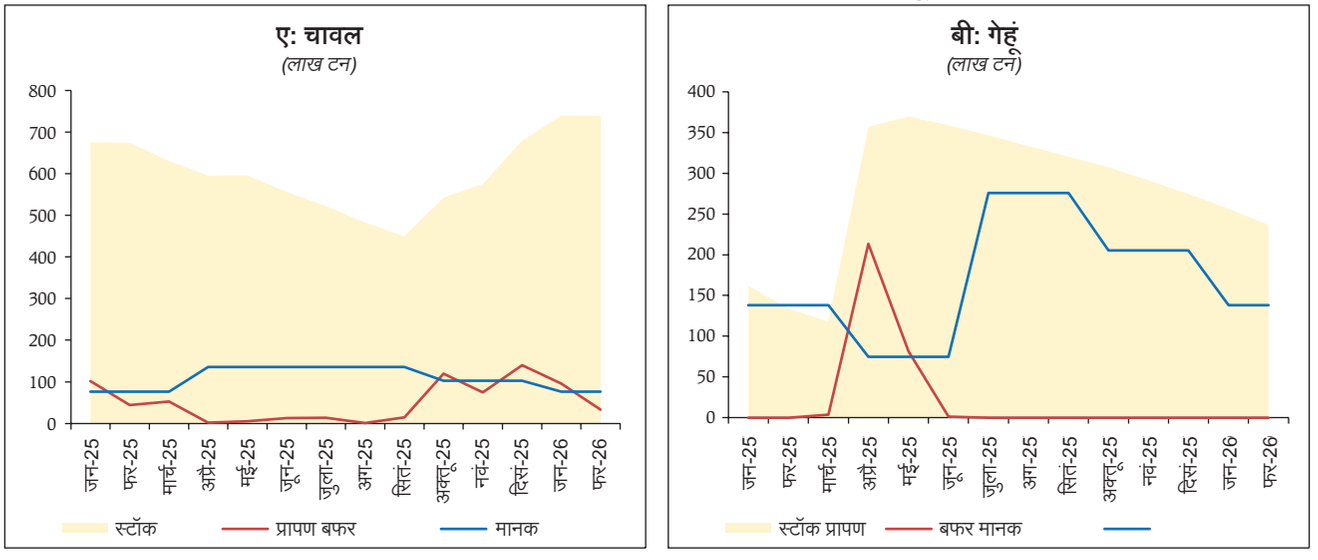

स्रोत: खाद्य निगम भारत (भारतीय खाद्य निगम ((एफसीआई)); भारत सरकार।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

और सभी गेहूं धारक इकाइयों पर स्टॉक सीमाएं हटा दीं। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम के चावल के 52 लाख टन अधिशेष को एथेनॉल उत्पादन के लिए आवंटित किया गया।

उच्च-आवृत्ति संकेतक 2025-26 की दूसरी छमाही में कृषि क्षेत्र की स्थिति को बेहतर दर्शा रहे हैं। ट्रैक्टर बिक्री (थोक) दूसरी छमाही (अक्तूबर– फरवरी) के दौरान 28.0 (वर्ष-दर-वर्ष) प्रतिशत बढ़ी, जबकि उर्वरक बिक्री 123.3 लाख टन पर उच्च बनी रही। दूसरी छमाही में (अक्तूबर–फरवरी) में कृषि एवं सहायक क्षेत्र के निर्यात 22.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर मोटे तौर पर स्थिर बने रहे। 2025-26 की दूसरी छमाही में मनरेगा के तहत रोजगार की मांग में तीव्र गिरावट आई, जो ग्रामीण श्रम बाजार की स्थिति में सुधार के अनुरूप है (सारणी III.11)।

समग्र रूप से, रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन, सामान्य से अधिक रबी बुआई, पर्याप्त जलाशय स्तर, मजबूत अनाज स्टॉक और खरीद एवं निर्यात पर सरकार के सुनियोजित हस्तक्षेप के संयोजन से निकट भविष्य में कृषि गतिविधि के लिए अनुकूल परिदृश्य बना हुआ है। पश्चिमी एशिया संघर्ष खरीफ मौसम के लिए उर्वरक उपलब्धता, विशेष रूप से यूरिया, के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, तथापि, गैस आवंटन में बढ़ौतरी और विविधीकृत आयातों की सहता से उच्च उत्पादन करते हुए स्टॉक बनाने के सरकार के प्रयास को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

III.2.2 उद्योग

एसएई के अनुसार, वर्ष 2025-26 में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि 9.5 प्रतिशत दर्ज की गई जो पिछले वर्ष के 8.7 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। औद्योगिक गतिविधि में तेजी मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत वृद्धि के कारण आई, जिसे इनपुट लागत दबाव में कमी, सूचीबद्ध विनिर्माण फर्मों की लाभप्रदता में सुधार और मजबूत घरेलू मांग ने समर्थन दिया। औद्योगिक जीवीए वृद्धि 2025-26 की तीसरी तिमाही में 11.1 प्रतिशत बढ़ी, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र ने 13.3 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर्ज की, जो लगभग दो वर्षों में सबसे मजबूत वृद्धि है। खनन एवं पत्थर कटाई की गतिविधि ने तीसरी तिमाही में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष के दो अंकों वाले विस्तार से धीमी गति है। बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं के जीवीए में तीसरी तिमाही में 1.5 प्रतिशत की हल्की वृद्धि हुई, क्योंकि बढ़े हुए मानसून की स्थितियों के कारण बिजली की मांग कम रही, जिससे ठंडक की आवश्यकता और समग्र बिजली उपभोग में कमी आई (चार्ट III.17)।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 2025-26 की तीसरी तिमाही में 5.3 प्रतिशत और चौथी तिमाही (फरवरी तक) में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई [चार्ट III.18 और सारणी III.12].। 2025-26 की पहली छमाही में संकुचन के बाद, खनन क्षेत्र ने तीसरी तिमाही में 3.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही (फरवरी तक) में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सुधार दर्शाया। हालांकि, कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में मंदी के कारण यह उछाल सीमित रहा। विनिर्माण क्षेत्र ने गति

सारणी III.11: ग्रामीण अर्थव्यवस्था - उच्च आवृत्ति संकेतक

मद	यूनिट	पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर)			दूसरी छमाही (अक्तूबर-मार्च)		
		2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26
ट्रैक्टर बिक्री	संख्या (लाख में)	4.7	4.7	5.6	3.4	3.9	5.0
दोपहिया वाहन बिक्री	संख्या (लाख में)	87.4	101.6	102.4	77.5	77.9	94.9
उर्वरक बिक्री $	लाख टन	312.9	303.5	332.0	120.2	114.7	123.3
रोजगार की मांग मनरेगा #	करोड़ परिवार	15.1	12.6	11.6	11.5	12	8.9
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के निर्यात #	बिलियन अमेरिकी डॉलर	23.3	23.4	25.5	20.0	22.7	22.6
कृषि ऋण वृद्धि	वर्ष-दर-वर्ष	16.7	16.4	9	20	11.4	12.3
बफर मानदंड के अनुपात में चावल स्टॉक*	अनुपात	3.1	3.8	4.4	7.6	8.9	9.7
बफर मानदंड के अनुपात में गेहूं स्टॉक*	अनुपात	1.2	1.2	1.6	0.7	1	1.7

टिप्पणियाँ: 2023–24 और 2024–25 के लिए डेटा 2025–26 के उलपबद्ध संगत महीनों तक प्रस्तुत किए गए हैं, ज्यादातर फरवरी तक ।
$: नवंबर; और # जनवरी तक। *28 फरवरी तक। सभी बिक्री केवल घरेलू बाजार से संबंधित हैं।
स्रोत: टीएमए; एसआईएएम; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; वाणिज्य एवं वित्त मंत्रालय; ग्रामीण विकास मंत्रालय; सीएमआईई; आरबीआई; और एफसीआई।

चार्ट III.17: औद्योगिक जीवीए वृद्धि

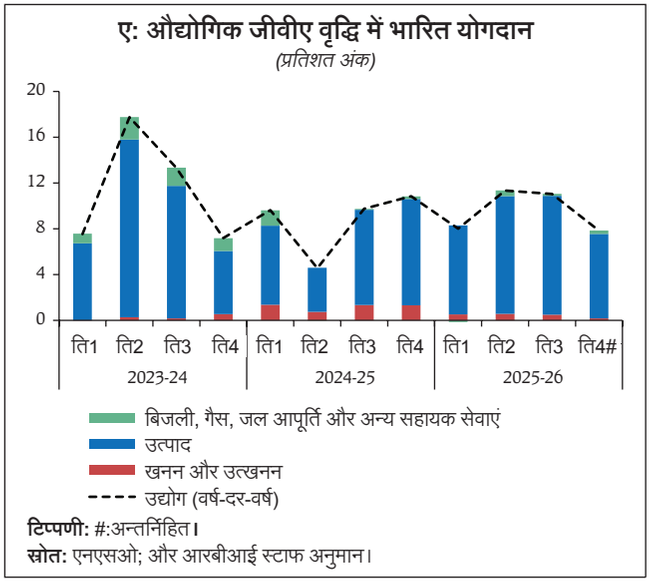

टिप्पणी: #:अन्तर्निहित।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

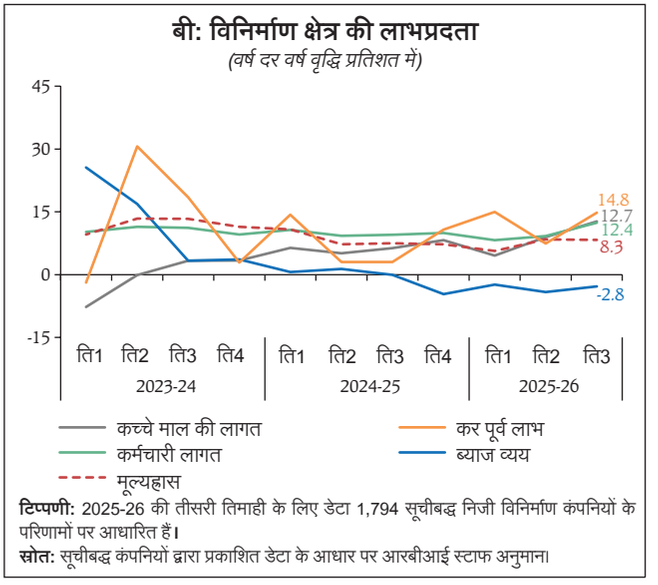

टिप्पणी: 2025-26 की तीसरी तिमाही के लिए डेटा 1,794 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों के परिणामों पर आधारित हैं।
स्रोत: सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रकाशित डेटा के आधार पर आरबीआई स्टाफ अनुमान।

बनाए रखी और तीसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत और जनवरी-फरवरी 2026 में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। विनिर्माण के अंतर्गत, दूसरी छमाही (फरवरी 2026 तक) में मूल धातुओं, मोटर वाहनों, ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर,अन्य यातायात उपकरण, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान तथा औषधीय उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि परिधान, चमड़े, मुद्रण और अन्य विनिर्मित उत्पादों के उत्पादन ने वृद्धि में बाधा के रूप में कार्य किया। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के आधार पर, दूसरी छमाही (फरवरी 2026 तक) के दौरान पूंजीगत माल, मध्यवर्ती, अवसंरचना और निर्माण सामान में गति बढ़ने के साथ सभी श्रेणियों में विस्तार देखा गया।

चार्ट III.18: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)

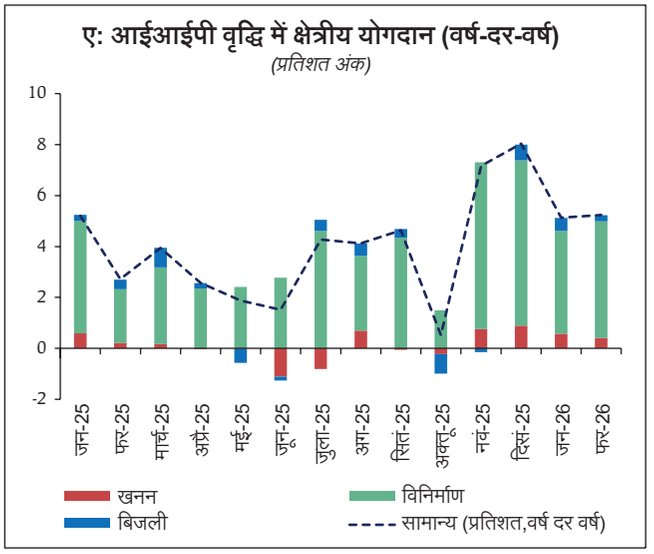

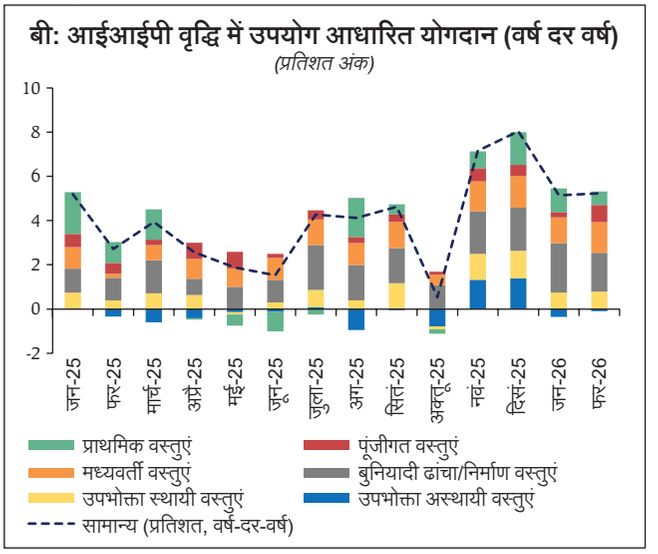

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

सारणी III.12: औद्योगिक क्षेत्र के संकेतक

(वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि प्रतिशत में)

	2025-26					
संकेतक	**ति1**	**ति2**	**ति3**	**जनवरी**	**फरवरी**	**मार्च**
1. पीएमआई: विनिर्माण (>50 पिछले महीने की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है)	58.1	58.7	56.9	55.4	56.9	53.9
2. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)	2.0	4.3	5.3	5.1	5.2	
3. आईआईपी: विनिर्माण	3.3	5.1	6.3	5.3	6.0	
4. आईआईपी: प्राथमिक वस्तुएं	-1.4	1.9	2.0	3.1	1.8	
5. आईआईपी: पूंजीगत वस्तुएं	9.8	5.6	6.8	4.1	12.5	
6. आईआईपी: मध्यवर्ती वस्तुएं	5.0	5.9	5.9	6.3	7.7	
7. आईआईपी: अवसंरचना और निर्माण वस्तुएं	6.0	11.6	11.0	14.6	11.2	
8. आईआईपी: उपभोक्ता स्थायी वस्तुएं	2.6	6.9	7.3	7.2	7.3	
9. आईआईपी: उपभोक्ता अस्थायी वस्तुएं	-1.5	-2.0	4.1	-2.3	-0.6	
10. आठ मुख्य उद्योग (ईसीआई)	1.5	4.5	2.3	4.7	2.3	
11. ईसीआई: इस्पात	7.2	14.8	7.6	11.5	7.2	
12. ईसीआई: सीमेंट	8.0	7.3	11.2	11.3	9.3	
13. बिजली की मांग	-1.5	3.3	-0.3	3.8	1.0	
ऑटोमोबाइल उत्पादन						
1. यात्री वाहन	4.9	4.2	19.1	5.6#	9.8#	
2. दो-पहिया वाहन	0.7	10.6	15.0	16.1	24.4	
3. तीन-पहिया वाहन	9.8	18.3	34.7	33.2	29.9	
4. ट्रैक्टर	12.7	14.6	31.5	14.6	80.0	

टिप्पणी: #: टाटा मोटर्स को शामिल नहीं किया गया है;
स्रोत: सीएमआईई; सीईआईसी;एचएसबीसी, एस एंड पी ग्लोबल; आर्थिक सलाहकार कार्यालय; एनएसओ;एसआईएएम; टीएमए; और आरबीआई के कर्मचारी अनुमान।

विद्युत शक्ति, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं ने दूसरी छमाही में 2.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की। नवीकरणीय, जलविद्युत और परमाणु स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन में मजबूत वृद्धि को दर्शाते हुए 2025-26 की चौथी तिमाही में विद्युत उत्पादन 3.7 प्रतिशत बढ़ा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिनका कुल उत्पादन में 15.5 प्रतिशत का हिस्सा है, तीसरी तिमाही में 20.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही (फरवरी तक) में 24.1 प्रतिशत की तीव्रता से बढ़े। क्षेत्रवार, तेसरी तिमाही में विद्युत मांग में असमानता दिखाई दी, जिसमें उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में संकुचन हुआ जबकि दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में मामूली वृद्धि हुई। सर्दियों की शुरुआत के साथ, चौथी तिमाही (फरवरी तक) में सभी क्षेत्रों में बिजली की मांग मजबूत हुई। [सारणी III.13]।

विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) तीसरी तिमाही के 56.9 से घटकर चौथी तिमाही में 55.4 हो गया, हालांकि यह विस्तार क्षेत्र में बना रहा। अच्छी मांग की स्थितियों के कारण आदेशों में मजबूती बनी रही। जैसा कि उत्पादन सूचकांक के तटस्थ स्थिति से ऊपर बने रहने में दिखा, विनिर्माण क्षेत्र में व्यावसायिक प्रत्याशाओं में उत्साह बना रहा (चार्ट III.19ए)। तथापि, पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न आपूर्ति शृंखला बाधाएं डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण इनपुट की उपलब्धता को संकुचित कर सकती हैं, जिसमें रिफाइनिंग, प्लास्टिक, उर्वरक, एल्यूमीनियम, वस्त्र, टायर, ऑटोमोटिव, रबर, रसायन और सिंथेटिक फाइबर शामिल हैं।

III.2.3 सेवाएं

2024-25 के 7.8 प्रतिशत से गति पकड़ते हुए सेवा क्षेत्र ने 2025-26 में 8.7 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना रहा, जिसने 2025-26 में

सारणी III.13: बिजली उत्पादन और खपत

(वर्ष दर वर्ष, प्रतिशत)

संकेतक	2024-25				2025-26					
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	जनवरी	फरवरी	मार्च
विद्युत उत्पादन										
तापीय	12.0	-1.4	0.0	0.3	-8.1	-1.5	-5.4	1.9	-2.9	-2.2
परमाणु	28.3	18.4	11.4	16.9	11.3	-16.6	-12.3	5.2	17.7	8.0
जलविद्युत	1.3	6.2	28.3	19.8	13.4	13.1	13.6	6.3	9.9	8.0
नवीकरणीय	7.0	7.3	17.2	22.8	24.8	22.1	20.6	22.9	25.3	
कुल	10.9	1.4	4.0	4.4	-1.7	3.5	-0.9	5.2	2.3	-1.2*
बिजली की खपत										
उत्तरी क्षेत्र	22.0	3.1	9.5	1.6	-3.0	-0.5	-3.2	5.5	0.8	
पश्चिमी क्षेत्र	5.5	-6.7	0.4	4.4	-0.3	7.0	-1.3	2.3	0.6	
दक्षिणी क्षेत्र	3.3	0.8	-2.3	3.1	-1.3	2.9	2.9	3.2	-0.2	
पूर्वी क्षेत्र	9.8	0.6	3.9	3.9	-1.7	5.9	1.8	5.6	6.2	
अखिल भारतीय	10.2	-0.7	2.6	3.2	-1.5	3.3	-0.3	3.8	1.0	

टिप्पणी: *: नवीकरणीय बिजली उत्पादन को छोड़कर।
स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए); और पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीओएसओसीओ)।

जीवीए वृद्धि में लगभग 70 प्रतिशत का योगदान दिया। 2025-26 की तीसरी तिमाही में, सेवा क्षेत्र के जीवीए ने 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (दूसरी तिमाही में 9.2 प्रतिशत), जबकि पिछले वर्ष यह 7.9 प्रतिशत थी सेवा क्षेत्र के भीतर, 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार' और 'प्रसारण; तथा वित्तीय, अचल संपत्ति और व्यावसायिक सेवाएं' जैसे खंडों में मजबूत वृद्धि से अपेक्षाकृत उच्च-मूल्य वाली सेवा गतिविधियों के बढ़ते योगदान का संकेत मिलता है (चार्ट III.20 ए)। निकटवर्ती संकेतक दिखाते हैं कि तीसरी तिमाही और जनवरी-फरवरी 2026 में निर्माण गतिविधि ने अपनी गति बनाए रखी। मानसून के बाद बढ़ी हुई मांग के कारण तीसरी तिमाही में सीमेंट उत्पादन मजबूत हुआ, जबकि तैयार इस्पात की खपत अपेक्षाकृत मध्यम दर से बढ़ी। जनवरी-फरवरी 2026 में, दोनों संकेतकों ने मजबूत वृद्धि दर्ज की। (चार्ट III.20 बी)

चार्ट III.19: पीएमआई विनिर्माण और सेवाएँ

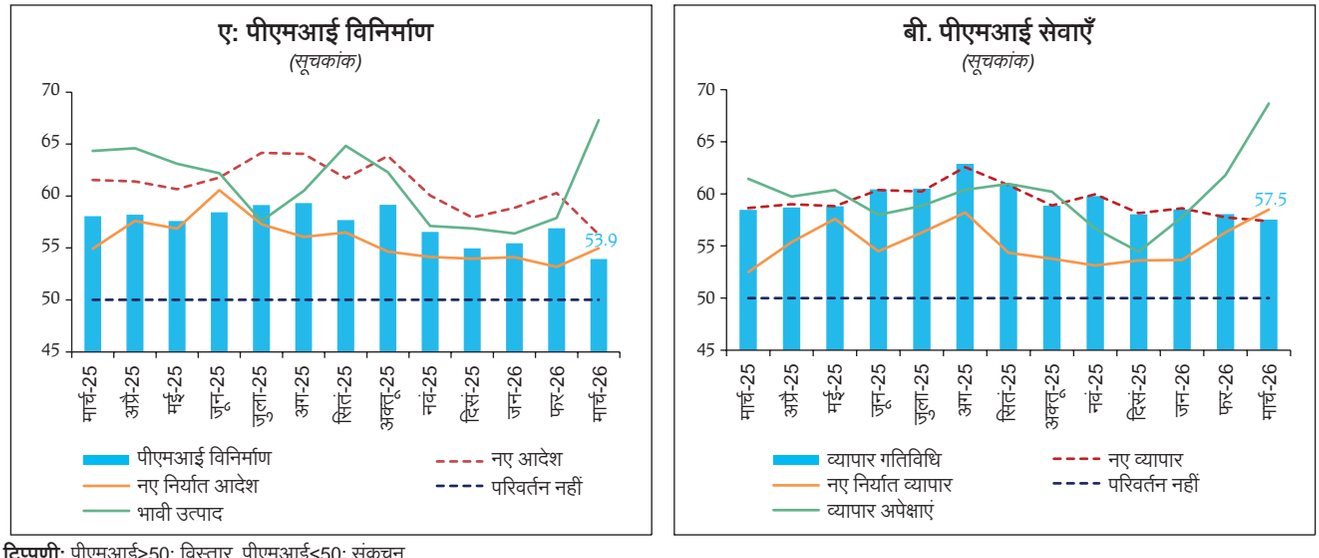

टिप्पणी: पीएमआई>50: विस्तार, पीएमआई<50: संकुचन
स्रोत: एचएसबीसी, एस एंड पी ग्लोबल।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

चार्ट III.20: सेवा क्षेत्र

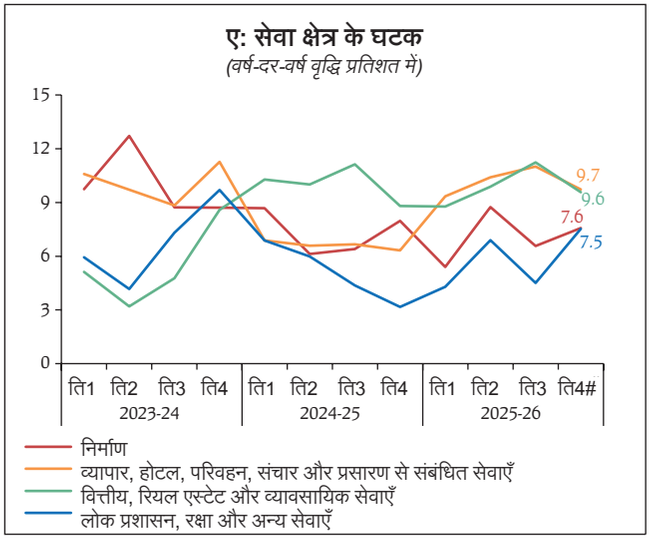

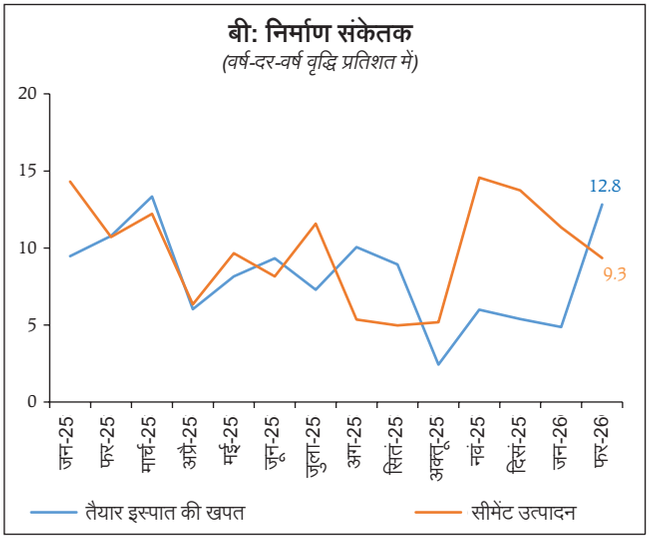

टिप्पणी: # निहित
स्रोत: एनएसओ; आर्थिक सलाहकार कार्यालय; और संयुक्त संयंत्र समिति।

व्यापार, होटल, परिवहन और संचार की जीवीए वृद्धि 2025-26 की तीसरी तिमाही में 11.0 प्रतिशत तक बढ़ी (दूसरी तिमाही में 10.4 प्रतिशत)। जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने के कारण जीएसटी संग्रह में तीसरी तिमाही में धीमापन आया, लेकिन चौथी तिमाही में सुधार हुआ, जो घरेलू व्यापार गतिविधि की मजबूत स्थिति दर्शाता है। बढ़ी हुई माल यातायात और व्यापार गतिविधि को प्रतिबिंबित करते हुए जीएसटी ई-वे बिल, बंदरगाह और विमान कार्गो यातायात ने भी 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान मजबूत वृद्धि दर्ज की। पर्यटन और व्यावसायिक यात्रा के समर्थन से घरेलू यात्री विमान यातायात ने जनवरी-फरवरी 2026 और तीसरी तिमाही में पुनरुद्धार दर्शाया। परिवहन सेवाओं के संकेतकों ने स्वस्थ वृद्धि दर्ज की – वाणिज्यिक वाहन और यात्री वाहन बिक्री की वृद्धि तीसरी तिमाही में तेज हुई। जनवरी-फरवरी (अब तक चौथी तिमाही) के लिए उपलब्ध डेटा यात्री वाहन बिक्री में निरंतर मजबूती दिखाते हैं, जो जीएसटी दर में कटौती और ब्याज दर में राहत के समर्थन से लगातार गतिमान मांग दर्शाते हैं।

वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं 2025-26 की तीसरी तिमाही में 11.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि से बढ़ीं — जो नई जीडीपी श्रृंखला (आधार वर्ष 2022–23) में दर्ज की गई सबसे अधिक वृद्धि थी — और सेवा क्षेत्र जीवीए वृद्धि (51.2 प्रतिशत) के साथ-साथ समग्र जीवीए वृद्धि (35.3 प्रतिशत) में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनी रहीं। यह गति वित्तीय मध्यस्थता में लगातार विस्तार द्वारा समर्थित थी, जिसमें मार्च 2026 में बैंक ऋण और जमा क्रमशः 13.8 प्रतिशत और 10.8 प्रतिशत बढ़े, साथ ही दूसरी छमाही (अक्तूबर–फरवरी) के दौरान जीवन और गैर-जीवन बीमा प्रीमियम में काफी वृद्धि हुई (सारणी III.14)।

गैर-आईटी सेवाओं की सांकेतिक बिक्री 2025-26 की तीसरी तिमाही में मजबूत रही, जिसने पिछली तिमाही के अनुरूप स्थिर दो अंकों की वृद्धि बनाए रखी। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आईटी क्षेत्र का कार्यनिष्पादन तीसरी तिमाही में और मजबूत हुआ (चार्ट III.21)।

मुख्य इनपुट[9] पर जीएसटी कटौती से लागत में आई कमी के परिणामस्वरूप नई आवासीय परियोजना लॉन्च में हुई वृद्धि के कारण 2025-26 की तीसरी तिमाही में रियल एस्टेट गतिविधि मजबूत रही, जबकि बिक्री स्थिर बनी रही। चूंकि लॉन्च बिक्री से अधिक हुए, तीसरी तिमाही में अविक्रित इन्वेंटरी का स्तर दूसरी

[9] नई पीढ़ी के लिए जीएसटी सुधार। विवरण https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=150302&reg=3&lang=2 पर उपलब्ध हैं:

सारणी III.14: सेवा क्षेत्र संकेतक

(वर्ष दर वर्ष, प्रतिशत)

संकेतक	2025-26					
	ति1	ति2	ति3	जनवरी	फरवरी	मार्च
1. पीएमआई: सेवाएँ (>50 पिछले महीने की तुलना में वृद्धि दर्शाता है)	59.3	61.4	58.9	58.5	58.1	57.5
निर्माण						
2. इस्पात की खपत	7.9	8.8	4.6	4.9	12.8	
3. सीमेंट उत्पादन	8.0	7.3	11.2	11.3	9.3	
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएँ						
4. वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री	-0.6	8.3	21.5			
5. घरेलू हवाई यात्री यातायात	5.3	-1.9	1.7	3.1	-0.1	
6. घरेलू हवाई माल	6.6	4.9	6.8	8.7	18.5	
7. अंतरराष्ट्रीय हवाई माल	4.7	3.6	7.3	8.4	17.5	
8. माल यातायात	2.4	4.0	3.2			
9. बंदरगाह माल	5.6	5.9	13.1	7.6	3.8	0.7
10. टोल संग्रह: मात्रा^	16.2	14.9	16.9	-1.8	-8.7	-4.0
11. पेट्रोलियम खपत	0.6	2.2	1.2	0.7	5.5	2.2
12. जीएसटी ई-वे बिल	20.5	23.1	19.4	15.8	18.8	
13. जीएसटी राजस्व*	11.8	7.7	4.7	6.2	8.1	8.8
वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ						
14. बकाया ऋण	9.5	10.4	14.5	14.6	14.5	13.8@
15. बैंक जमा	10.1	9.5	12.7	12.5	11.9	10.8@
16. जीवन बीमा प्रीमियम	4.3	10.7	24.9	21.6	18.1	
17. गैर-जीवन बीमा प्रीमियम	8.8	5.8	11.4	15.0	9.7	

टिप्पणी: @ 15 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार डाटा। ^: अनुमानों में महाराष्ट्र में विद्युत वाहनों (ईवी) की यात्राओं और अगस्त 2025 से वार्षिक पास यात्राओं के आंकड़े शामिल हैं; और *: इन आंकड़ों में क्षतिपूर्ति सेस शामिल है ।

स्रोत: सीईआईसी; एनएसओ; एचएसबीसी, एसएंडपी ग्लोबल; एमओएसपीआई; आईआरडीएआई और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

तिमाही की तुलना में बढ़ गया (चार्ट III.22ए)। मुंबई को छोड़कर सभी प्रमुख शहरों में वृद्धि के साथ अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक तीसरी तिमाही में और थोड़ा बढ़ा (चार्ट III.22बी)। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अन्य सेवाओं में उत्साहित गतिविधि के समर्थन से एक वर्ष पहले के 4.4 प्रतिशत की तुलना में सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) ने तीसरी तिमाही में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

सेवा पीएमआई 2025-26 की तीसरी तिमाही में 58.9 और चौथी तिमाही में 58.0 पर विस्तारित बना रहा, जो मजबूत मांग और नई व्यावसायिक गतिविधि से समर्थित था, हालांकि यह 2025-26 की पहली छमाही के 60.4 से धीमा हुआ (सारणी III.14)। समग्र पीएमआई सूचकांक 2025-26 की पहली छमाही में 60.9 से तीसरी तिमाही में 59.3 और फिर चौथी तिमाही में 58.1 तक घटा। तथापि, यह 50 के मार्क से सहज रूप से उच्च स्थिति में बना रहा, जो लगातार विस्तार का संकेत देता है। (चार्ट III. 19बी)

चार्ट III 21. सांकेतिक बिक्री वृद्धि

(वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रतिशत में)

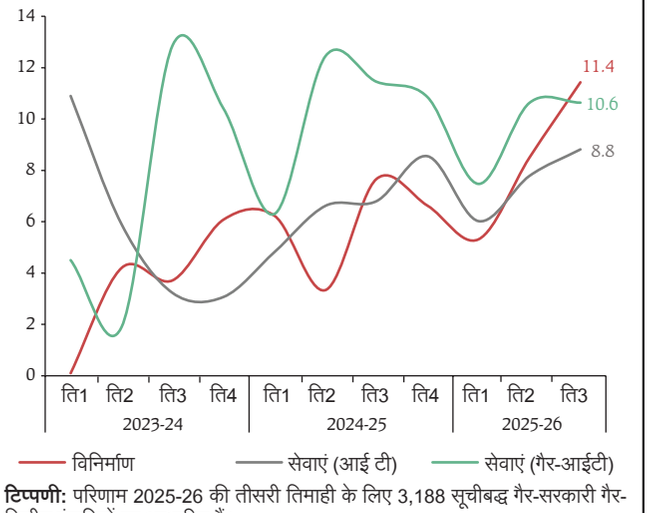

टिप्पणी: परिणाम 2025-26 की तीसरी तिमाही के लिए 3,188 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों पर आधारित हैं।

स्रोत: कैपिटलाइन; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

चार्ट III.22: आवास क्षेत्र- लॉन्च, बिक्री और कीमतें

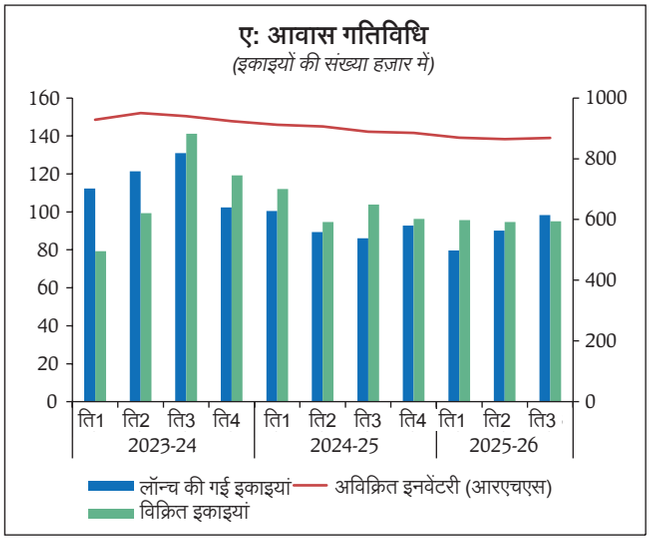

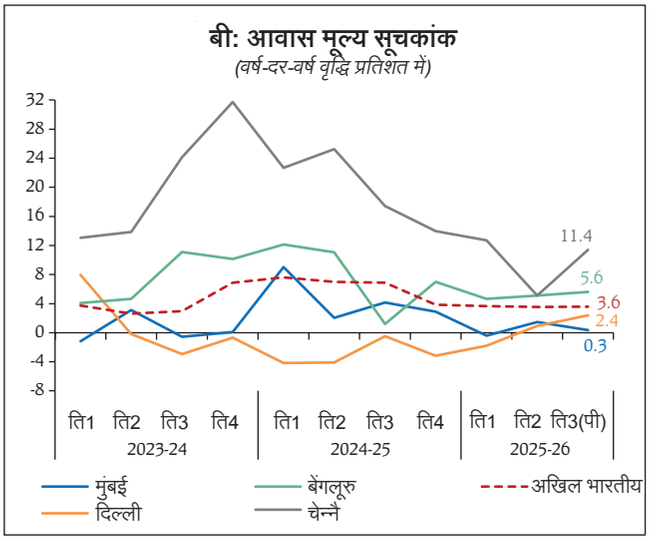

टिप्पणी: *: अनंतिम डेटा ।
स्रोत: प्रोप टाइगर और आरबीआई।

III.3 निष्कर्ष

आधार वर्ष के अद्यतनीकरण के साथ राष्ट्रीय खातों में हाल के संशोधन इसकी पुष्टि करते हैं कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से 2025-26 की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी रही। जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने, मौद्रिक नरमी, सौम्य मुद्रास्फीति परिस्थितियां, चालू संरचनात्मक सुधार और बेहतर रोजगार परिस्थितियों ने घरेलू मांग को समर्थन दिया। अनिश्चित वैश्विक परिवेश के बीच निवल बाह्य मांग पर बाधा बनी रही। आपूर्ति पक्ष की ओर, सेवा क्षेत्र में तेजी के साथ-साथ औद्योगिक गतिविधि में मजबूती ने मूल्य योगदान में वृद्धि को बढ़ावा दिया। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार समझौतों पर प्रगति भारत की संवृद्धि की संभावना के लिए अच्छी खबर है। हालांकि, भूराजनीतिक तनाव, उच्च कमोडिटी मूल्यों और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियां अधोगामी जोखिम उत्पन्न करती हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों के प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों से महत्वपूर्ण इनपुट की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए अग्रसक्रिय नीतिगत उपाय से चुनौतियों का प्रभाव कम होना अपेक्षित है।

IV. मूल्य और लागत

अक्तूबर के ऐतिहासिक निचले स्तर के बाद, मूल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति में क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई है, हालांकि यह अभी भी लक्ष्य से नीचे बनी हुई है। जनवरी 2026 से उपलब्ध नई सीपीआई शृंखला (2024=100) के आंकड़े दर्शाते हैं कि खाद्य कीमतों की स्थिति अपस्फीति से बाहर निकल आई है। कीमती धातुओं की कीमतों में उछाल के दबाव के बावजूद कोर मुद्रास्फीति नियंत्रित रही है। अंतर्निहित चालकों के संदर्भ में, वेतन का दबाव कम रहा है, जबकि मार्च में इनपुट लागत का दबाव पुनः उभर कर सामने आया है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण ऊर्जा की कीमतों में आई तेजी भविष्य में घरेलू मुद्रास्फीति के परिदृश्य के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती है।

IV.1 परिचय

पिछली मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) के जारी होने के बाद से, हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति[1], क्रमिक वृद्धि के बावजूद, लक्ष्य से नीचे बनी हुई है। अक्टूबर 2025 में मुद्रास्फीति घटकर 0.3 प्रतिशत पर आ गई थी – जो पिछली शृंखला (आधार वर्ष 2012=100) का सबसे निचला स्तर था – जिसके बाद दिसंबर में यह बढ़कर 1.3 प्रतिशत हो गई, जो इस शृंखला के अंतर्गत नवीनतम उपलब्ध आंकड़ा है। नई सीपीआई शृंखला (2024=100)[2] के अंतर्गत, मुद्रास्फीति जनवरी में बढ़कर 2.7 प्रतिशत और फरवरी 2026 में 3.2 प्रतिशत हो गई (चार्ट IV.1)। नई सीपीआई शृंखला भारत में मुद्रास्फीति के मापन में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है, जो नीति के लिए आवश्यक सूचना को और समृद्ध करती है (बॉक्स IV.1)।

अक्टूबर 2025 से मुद्रास्फीति में आई तेजी मुख्य रूप से प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण थी, जबकि इसकी गति[3] काफी धीमी बनी रही (चार्ट IV.2)।

चार्ट IV.1: सीपीआई मुद्रास्फीति

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

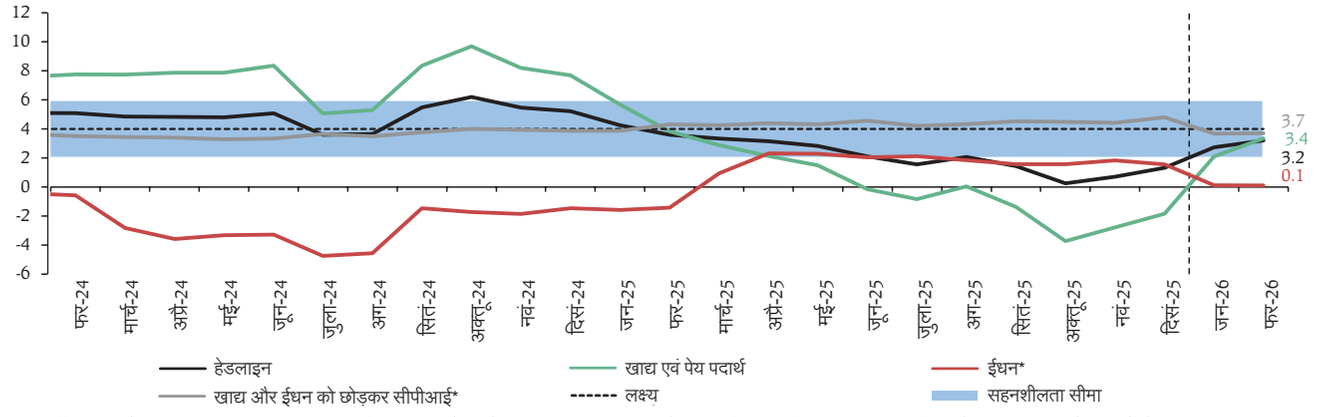

टिप्पणियाँ: 1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2024=100 की शृंखला में, विभिन्न श्रेणियों/ समूहों का भारांश इस प्रकार है: खाद्य और पेय पदार्थ – 36.8 प्रतिशत, ईंधन* – 10.2 प्रतिशत और सीपीआई (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) – 53.0 प्रतिशत। इसकी तुलना में, CPI 2012=100 की शृंखला में, ये भारांश क्रमशः खाद्य और पेय पदार्थ – 45.9 प्रतिशत, ईंधन* – 9.2 प्रतिशत और सीपीआई (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) – 45.0 प्रतिशत थे।

2. नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृंखला में 'ईंधन*' घरेलू ईंधन का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात 'आवास, जल, विद्युत, गैस और अन्य ईंधन' खंड के अंतर्गत आने वाला 'विद्युत, गैस और अन्य ईंधन' समूह; तथा परिवहन ईंधन, अर्थात 'व्यक्तिगत परिवहन उपकरणों के लिए ईंधन और स्नेहक' वर्ग, जिसमें 'पेट्रोल', 'डीजल' और 'अन्य प्राकृतिक गैस' शामिल हैं। पुरानी शृंखला में ईंधन का तात्पर्य 'ईंधन और प्रकाश' समूह तथा 'वाहनों के लिए पेट्रोल' और 'वाहनों के लिए डीजल' मदों से है। इस अध्याय में ईंधन समूह/ श्रेणी में पारिवारिक तथा परिवहन ईंधन दोनों को शामिल किया गया है।

3. ऊर्ध्वाधर डैश वाली रेखा पुरानी और नई सीपीआई शृंखला के बीच के अंतर को दर्शाती है, क्योंकि दोनों शृंखलाओं के मुद्रास्फीति आँकड़े पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ अनुमान।

[1] सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाले वार्षिक (वर्ष-दर-वर्ष) परिवर्तनों के आधार पर हेडलाइन मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है।

[2] सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने 12 फरवरी, 2026 को नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2024=100) जारी किया है, जो जनवरी 2026 से नई शृंखला के आधार पर मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रदान करता है।

[3] किसी भी दो महीनों के बीच सीपीआई वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति में बदलाव मूल्य सूचकांक (गति) में वर्तमान माह-दर-माह परिवर्तन और 12 महीने पहले मूल्य सूचकांक में माह-दर-माह परिवर्तन (आधार प्रभाव) के बीच का लगभग अंतर है। अधिक जानकारी के लिए, एमपीआर का बॉक्स I.1, सितंबर 2014 देखें।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

बॉक्स IV.1. नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृंखला: मुख्य परिवर्तन और मुद्रास्फीति पर प्रभाव

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 12 फरवरी, 2026 को जनवरी 2026 माह के लिए आधार वर्ष 2024 पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मुद्रास्फीति आँकड़े जारी किए। नई शृंखला में भारांश उपभोग के अधिक हालिया स्वरूप को दर्शाते हैं, जो पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2023-24 पर आधारित हैं (इसने सीपीआई 2012=100 शृंखला में प्रयुक्त एचसीईएस 2011-12 का स्थान लिया है)।

संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृंखला की प्रमुख विशेषताएं/ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

विस्तारित कवरेज

- ***भौगोलिक कवरेज:*** *कवर किए गए बाजारों की संख्या में 25 प्रतिशत की वृद्धि और शहरों की संख्या में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।*
- ***मदें:*** *सीपीआई 2024 वस्तु मदों में भारित वस्तुओं की संख्या 299 से बढ़कर 358 हो गई है (वस्तुएं 259 से बढ़कर 308 और सेवाओं की मदें 40 से बढ़कर 50 हो गई हैं)।*
- ***ग्रामीण कवरेज का विस्तार:*** *ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपभोग को शामिल करने के लिए 'ग्रामीण मकान किराया' को सम्मिलित किया गया है।*
- ***उपभोग बास्केट में नई वस्तुएं:*** *आधुनिक वस्तुओं का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, जिनमें ऑनलाइन मीडिया सेवाएं, स्वास्थ्य पूरक और संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) / पाइपयुक्त-प्राकृतिक गैस (पीएनजी) जैसे स्वच्छ ईंधन शामिल हैं।*
- ***वैकल्पिक डेटा स्रोतों का उपयोग:*** *डिजिटल और प्रशासनिक डेटा (जैसे दूरसंचार शुल्क, रेल और हवाई किराया, ईंधन की कीमतें, डाक शुल्क और ओवर दि टॉप (ओटीटी) सब्सक्रिप्शन) का समावेश किया गया है और 12 ऑनलाइन बाजारों को शामिल किया गया है।*

भारांश पद्धति में परिवर्तन

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2024 शृंखला में आईएमएफ़ के उद्देश्य के अनुसार व्यक्तिगत उपभोग के वर्गीकरण (सीओआईसीओपी) 2018 को अपनाया गया है। इसने 2012 की शृंखला में प्रयुक्त पूर्ववर्ती छह-समूहों वाली संरचना के स्थान पर 12 प्रभागों, 43 समूहों, 92 वर्गों और 162 उप-वर्गों का अधिक विस्तृत पदानुक्रम स्थापित किया है। प्रभाग स्तर पर भारांश संरचना को तालिका IV.1.1 में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी तुलना तालिका IV.1.2 में 2012 शृंखला के समूह/ उप-समूह स्तर के भारांश से की गई है।

तालिका IV.1.1: अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त की भारांश संरचना: 2024=100

प्रभाग	भारांश (प्रतिशत)
खाद्य और पेय पदार्थ	36.75
पान, तंबाकू और मादक द्रव्य	2.99
कपड़े और जूते	6.38
आवास, जल, विद्युत, गैस और अन्य ईंधन	17.66
साज-सज्जा, घरेलू उपकरण और नियमित घरेलू रखरखाव	4.47
स्वास्थ्य	6.10
परिवहन	8.80
सूचना और संचार	3.61
मनोरंजन, खेल और संस्कृति	1.52
शिक्षा सेवाएँ	3.33
रेस्तरां और आवास सेवाएँ	3.35
व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और विविध वस्तुएं एवं सेवाएं	5.04

तालिका IV.1.2: अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त की भारांश संरचना: 2012=100

समूह/ उप-समूह	भारांश (प्रतिशत)
खाद्य और पेय पदार्थ	45.86
पान, तंबाकू और मादक द्रव्य	2.38
कपड़े और जूते	6.53
आवास	10.07
सीपीआई ईंधन और प्रकाश	6.84
विविध	28.32
जिसमें से:	
घरेलू सामान और सेवाएं	3.80
स्वास्थ्य	5.89
परिवहन और संचार	8.59
मनोरंजन और आमोद-प्रमोद	1.68
शिक्षा	4.46
व्यक्तिगत देखभाल और वस्तुएं	3.89

वर्गीकरण में बदलाव के कारण भारांश संरचना की सीधी तुलना संभव नहीं है, फिर भी संशोधित भारांश आरेख पारिवारिक व्यय में खाद्य वस्तुओं की घटती हिस्सेदारी और आवास, सेवाओं तथा परिवहन से संबंधित मदों में हुई वृद्धि को रेखांकित करता है।

(Contd...)

मुद्रास्फीति मापन के लिए नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृंखला में किए गए परिवर्तनों के प्रभाव और नीतिगत प्रभावों का विवरण तालिका IV.1.3 में दिया गया है:

तालिका IV.1.3: नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृंखला में परिवर्तनों के प्रभाव

मुख्य परिवर्तन	नए आधार के अंतर्गत सीपीआई मुद्रास्फीति में संशोधन	मुद्रास्फीति पर प्रभाव/ मौद्रिक नीति के संबंध में निहितार्थ
भारांश संरचना में परिवर्तन	खाद्य के भारांश में कमी। 'सब्जियां', 'दालें' और 'तेल एवं वसा' जैसे उच्च मुद्रास्फीति अस्थिरता वाले उप-समूहों का भारांश कम है।	हेडलाइन मुद्रास्फीति में कम अस्थिरता की अपेक्षित है।
वस्तुओं का पुनर्वर्गीकरण	पहले की शृंखला के 'खाद्य और पेय पदार्थ' का हिस्सा 'तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि' का एक हिस्सा अब एक अलग नए वर्ग 'रेस्तरां और आवास सेवाओं' में स्थानांतरित कर दिया गया है। "व्यक्तिगत परिवहन उपकरणों के लिए ईंधन और स्नेहक" नामक एक अलग वर्ग परिवहन प्रभाग का हिस्सा है।	पिछली शृंखला में खाद्य समूह का हिस्सा रहे कुछ मद अब 'कोर' का हिस्सा होंगे। परिवहन ईंधन मदों को छोड़कर भी कोर[4] मुद्रास्फीति की गणना की जा सकती है।
मुफ्त पीडीएस वस्तुओं[5] को हटाना	पीडीएस वस्तुओं का भारांश 1.0 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत किया गया	मुफ्त पीडीएस वस्तुओं को हटाने से सूचकांक बाजार की कीमतों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करेगा।
मकान किराया कवरेज में बदलाव	नई शृंखला में नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए आवास के किराए को बाहर रखा गया है। ग्रामीण मकान किराए को शामिल किया गया है।	किराया सूचकांक के उतार-चढ़ाव से बाजार की कीमतों के बेहतर प्रतिबिंब की उम्मीद है। वेतन आयोगों के दौरान आवास के किराए के एकमुश्त संशोधनों से संबंधित समस्याओं को संबोधित किया गया है।
एकत्रीकरण	उन सभी वस्तुओं के लिए अभ्यरोपण[6] (इम्प्यूटेशन) किया जाएगा जिनका डेटा उपलब्ध नहीं है (मौसमी वस्तुओं सहित)। लुप्त मदों के मामले में भारांश का पुनर्वितरण नहीं होगा।	- नया सीपीआई लंबवत और क्षैतिज रूप से एकत्र करने योग्य है; एकत्रीकरण पूर्वाग्रह[7] की समाप्ति। - कोर मुद्रास्फीति के लिए 'अपवर्जन' और 'समावेशन' आधारित विधियां समान होंगी; संचार में सुगमता।
मकान किराया सूचकांक संकलन	हर महीने नमूने में सभी घरों को कवर करने के लिए एक सांख्यिकीय कार्यप्रणाली तैयार की गई है।	मकान किराया मुद्रास्फीति में कम अस्थिरता अपेक्षित है।
प्रारंभिक शृंखला-आधारित सूचकांक	प्रारंभिक स्तर पर जेवान्स के लघु सूचकांक फॉर्मूले[8] का उपयोग किया जाएगा, जिससे गुणवत्ता/विशिष्टता के परिवर्तनों को अपनाना आसान हो जाएगा।	नया सीपीआई अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होगा।

संदर्भ:

एन.एस.ओ. (2026ए). उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के व्यापक अद्यतनीकरण पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

एन.एस.ओ. (2026ए).आधार 2024=100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की प्रथम प्रेस विज्ञप्ति, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अक्तूबर 2025 तक मुद्रास्फीति में आई गिरावट और उसके बाद हुई वृद्धि, दोनों ही मुख्य रूप से 'खाद्य और पेय पदार्थ' समूह द्वारा संचालित थे। कुल मुद्रास्फीति में खाद्य और पेय पदार्थ घटक का योगदान, जो अक्टूबर में अत्यधिक नकारात्मक था, जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान सकारात्मक हो गया (चार्ट IV.3)। ईंधन समूह का योगदान नगण्य रहा, जबकि कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) का योगदान काफी हद तक स्थिर रहा।

[4] नई सीपीआई (2024=100) श्रृंखला में, कोर सीपीआई, अर्थात खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई की गणना 'खाद्य और पेय पदार्थ', समूह 'बिजली, गैस, अन्य ईंधन' (भार 5.4), और वर्ग 'व्यक्तिगत परिवहन उपकरण के लिए ईंधन और स्नेहक' (भार 4.8) [जिसमें 'पेट्रोल', 'डीजल' और 'अन्य प्राकृतिक गैस (सीएनजी)' शामिल हैं] को हटाकर की जाती है। पुरानी सीपीआई (2012=100) श्रृंखला में, कोर सीपीआई, यानी खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई को खाद्य और पेय पदार्थ और इंधन को छोड़कर सीपीआई को तुलनीय बनाने के लिए हेडलाइन सीपीआई से 'वाहन के लिए पेट्रोल' और 'वाहन के लिए डीजल' को समाप्त करके तैयार किया जाता है।

[5] नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2024=100) शृंखला में चावल, गेहूं और दालों जैसी मुफ्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है।

[6] अनुपलब्ध मूल्यों का अधिरोपण, उसी प्राथमिक समूह या उच्च-स्तरीय समूह के भीतर तुलनीय वस्तुओं की कीमत के उतार-चढ़ाव के आधार पर किया जाता है।

[7] उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलन में एग्रीगेशन बायस एक संभावित विकृति को दर्शाता है जो तब उत्पन्न होती है जब विभिन्न मदों के सूचकांकों को मिलाकर उच्च-स्तरीय सूचकांक प्राप्त किए जाते हैं- विशेष रूप से ऐसी स्थितियों में जहाँ कीमत उपलब्ध न हो; या गुणवत्ता अथवा विशिष्टताओं में कोई परिवर्तन हुआ हो।

[8] प्राथमिक सीपीआई संकलन के लिए जेवन्स के लघु सूचकांक सूत्र का उपयोग श्रृंखला आधारित सूचकांक पद्धति निश्चित आधार वर्ष के बजाय महीने-दर-महीने मूल्य परिवर्तन पर निर्भर करती है, इसलिए वर्तमान महीने और पिछले महीने की कीमतें समान विनिर्देशों को संदर्भित करती हैं। अधिक विवरण कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैनुअल कॉन्सेप्ट्स एण्ड मेथड्स, 2020 के अध्याय 8 में उपलब्ध हैं। https://data.imf.org/-/media/iData/External-Storage/Documents/094CFD9697F645FBA6B4F720A062A35D/en/Consumer-Price-Index-Manual.pdf

मौद्रिक नीति वक्तव्य

चार्ट IV.2: हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति: गति और आधार प्रभाव

(प्रतिशत अंकों में)

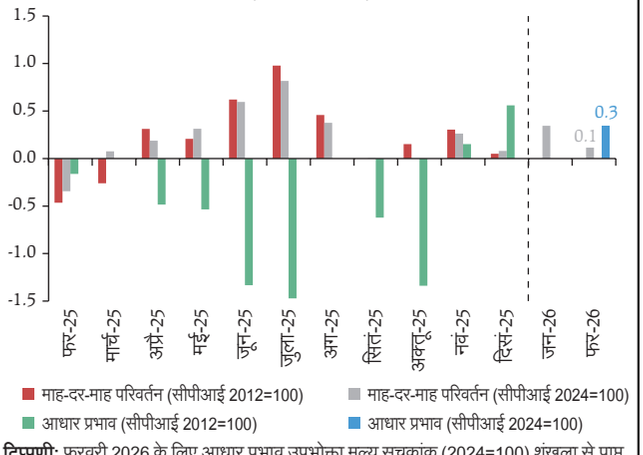

टिप्पणी: फरवरी 2026 के लिए आधार प्रभाव उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2024=100) शृंखला से प्राप्त किया गया है, जबकि जनवरी 2026 के लिए यह उपलब्ध नहीं है क्योंकि नई शृंखला का सूचकांक केवल जनवरी 2025 से शुरू होता है।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ अनुमान।

चार्ट IV.3: हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति के संचालक

(प्रतिशत अंकों में योगदान)

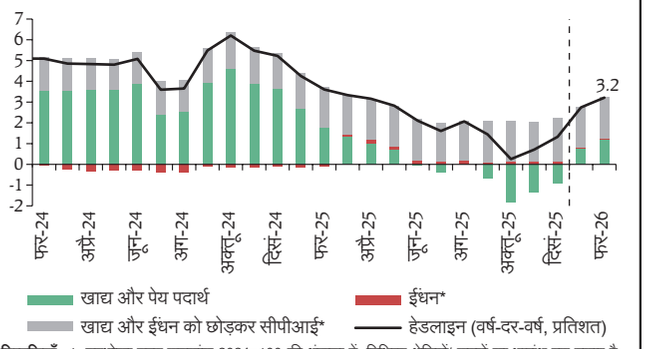

टिप्पणियाँ: 1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2024=100 की शृंखला में, विभिन्न श्रेणियों/ समूहों का भारांश इस प्रकार है: खाद्य और पेय पदार्थ – 36.8 प्रतिशत, ईंधन* – 10.2 प्रतिशत और सीमपीआई (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) – 53.0 प्रतिशत। इसकी तुलना में, सीपीआई 2012=100 की शृंखला में, इन समूहों का भारांश खाद्य और पेय पदार्थ – 45.9 प्रतिशत, ईंधन और प्रकाश* – 9.2 प्रतिशत और सीपीआई (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) – 45.0 प्रतिशत था।

2. नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2024=100) शृंखला में 'ईंधन', 'आवास, जल, विद्युत, गैस और अन्य ईंधन' | प्रभाग के अंतर्गत आने वाले 'विद्युत, गैस और अन्य ईंधन' समूह तथा 'व्यक्तिगत परिवहन उपकरणों के लिए ईंधन और स्नेहक' वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके विपरीत, पुरानी शृंखला में ईंधन के अंतर्गत 'ईंधन और प्रकाश' समूह तथा 'वाहनों के लिए पेट्रोल एवं 'वाहनों के लिए डीजल' मदों को सम्मिलित किया गया है।

3. ऊर्ध्वाधर डैश वाली रेखा पुरानी और वर्तमान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृंखलाओं के बीच के अंतर को दर्शाती है, क्योंकि दोनों शृंखलाओं के मुद्रास्फीति आँकड़े पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ अनुमान।

अक्टूबर की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में सीपीआई मुद्रास्फीति के वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में औसत 1.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था (चार्ट IV.4)।[9] वास्तविक परिणाम 2025-26 की तीसरी तिमाही और 2025-26 की चौथी तिमाही (फरवरी तक) के अनुमानों की तुलना में लगभग एक-एक प्रतिशत अंक कम रहे। तीसरी तिमाही के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई भारी गिरावट, जो सामान्य रुझान से कहीं अधिक थी, इस विचलन का मुख्य कारण रही। चौथी तिमाही में अब तक का विचलन नई सीपीआई शृंखला में कोर मुद्रास्फीति के कम रहने के कारण भी है।

चार्ट IV.4: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति: पूर्वानुमान बनाम वास्तविक

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

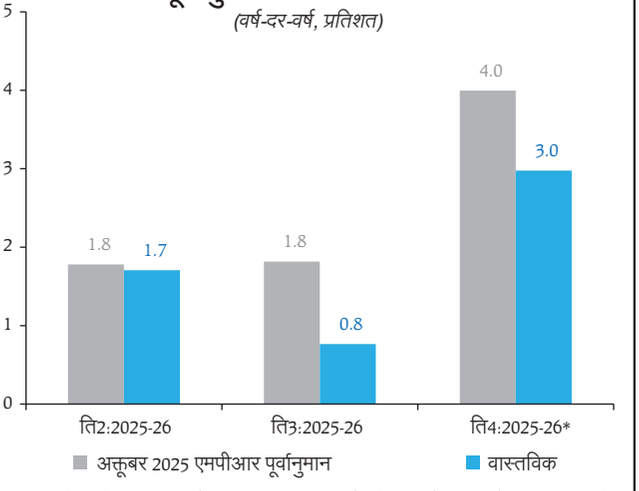

टिप्पणी: संपूर्ण ति4: 2025-26 के लिए किए गए पूर्वानुमानों की तुलना में नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2024=100) शृंखला से प्राप्त जनवरी-फरवरी 2026 की वास्तविक औसत मुद्रास्फीति।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ अनुमान।

IV.2 सीपीआई के प्रमुख घटकों में घटनाक्रम

सीपीआई खाद्य और पेय पदार्थ

सितंबर-दिसंबर 2025 के दौरान खाद्य और पेय पदार्थ[10] समूह में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अपस्फीति दर्ज की गई, क्योंकि कीमतों की गति धीमी या नकारात्मक बनी रही। हालांकि, नई शृंखला में 'खाद्य और पेय पदार्थ' वर्ग ने जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान सकारात्मक आंकड़े दर्ज किए (चार्ट IV.5)।

[9] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (2016 में संशोधित) के अंतर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए यह अनिवार्य है कि वह मुद्रास्फीति के वास्तविक परिणामों और उनके अनुमानों के बीच होने वाले किसी भी विचलन (यदि कोई हो) को प्रस्तुत करे और उसके अंतर्निहित कारणों की व्याख्या करे।

[10] मुद्रास्फीति के आंकड़े दिसंबर 2025 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100) शृंखला पर आधारित हैं, जबकि जनवरी-फरवरी 2026 के बाद के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2024=100) शृंखला पर आधारित हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100) शृंखला में, 'खाद्य और पेय पदार्थ' समूह में 'खरीदा गया पका हुआ भोजन और पका हुआ स्नेक्स' जैसी मदें शामिल थीं, हालांकि, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2024=100) शृंखला में, वे 'खाद्य और पेय पदार्थ' खंड का हिस्सा नहीं हैं।

चार्ट IV.5: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति के संचालक

(प्रतिशत अंकों में)

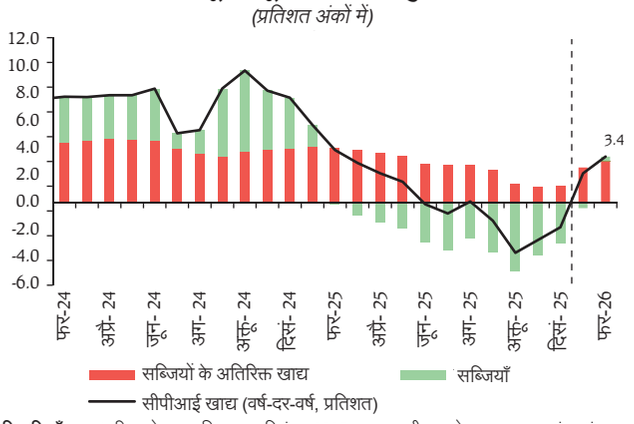

टिप्पणियाँ: 1. भारित योगदान की गणना दिसंबर 2025 तक पुरानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृंखला (2012=100) के उपयोग से की गई है। इसके बाद की अवधि के लिए, यह नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृंखला (2024=100) पर आधारित है।

2. पुरानी शृंखला में खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह का भार 45.9 प्रतिशत था। उपभोग के बदलते स्वरूप और वस्तुओं के पुनर्वर्गीकरण को दर्शाते हुए, नई शृंखला में इस भार को घटाकर 36.8 प्रतिशत कर दिया गया है।

3. ऊर्ध्वाधर डैश रेखा पुरानी और नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृंखला के बीच के अंतर को दर्शाती है, क्योंकि मुद्रास्फीति के आंकड़े इन दोनों शृंखलाओं के बीच पूरी तरह से तुलनीय नहीं हैं।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ अनुमान।

जनवरी-फरवरी 2026 में अधिकांश खाद्य समूहों में बहुत कम मुद्रास्फीति या अपस्फीति दर्ज की गई, जिसमें खाद्य तेल, मांस और मछली, तथा फल इसके अपवाद रहे (चार्ट IV.6)। खाद्य समूह के भीतर देखी गई कीमतों की वृद्धि (2012 और 2024 दोनों शृंखलाओं में), अपने ऐतिहासिक औसत की तुलना में 2025-26 के दौरान काफी कम रही है (चार्ट IV.7)।

खाद्य समूह के प्रमुख घटकों में, सब्जियों[11] की कीमतों में अप्रैल-दिसंबर 2025 में बाजार में सुदृढ़ आवक के कारण भारी अपस्फीति दर्ज की गई, (चार्ट IV.8)। नई सीपीआई शृंखला में, मुख्य रूप से प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण सब्जियां, कंद, केला तथा सब्जी वाले केला और दालें वर्ग में फरवरी 2026 में 0.1 प्रतिशत की मामूली मुद्रास्फीति दर्ज की गई, जबकि माह-दर-माह आधार पर कीमतों में गिरावट जारी रही।

चार्ट IV.6: उप-समूह/वर्ग स्तर पर खाद्य मुद्रास्फीति

(प्रतिशत)

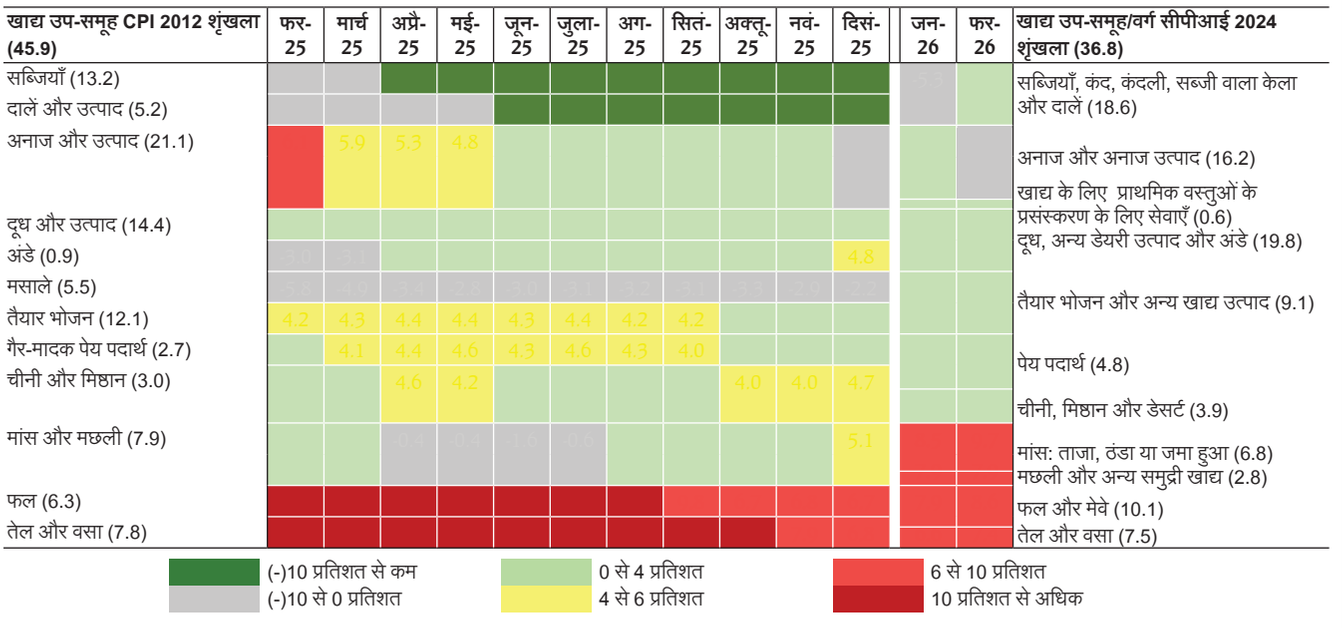

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें, बाईं ओर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100) शृंखला के लिए 'खाद्य एवं पेय पदार्थ' समूह में और दाईं ओर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2024=100) शृंखला के 'खाद्य एवं पेय पदार्थ' प्रभाग में व्यक्तिगत उप-समूहों के भारांक को दर्शाते हैं।

2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2024=100) शृंखला में, 'सब्जियाँ, कंद, कंदली, सब्जी का केला और दालें' वर्ग में दालें एवं उनके उत्पाद शामिल हैं, जबकि सीपीआई (2012=100) शृंखला में, अन्य मदों के साथ, 'दालें एवं उत्पाद' एक स्वतंत्र उप-समूह था। इसी प्रकार, सीपीआई (2024=100) शृंखला में 'दूध, अन्य डेयरी उत्पाद और अंडे' वर्ग में अंडों को शामिल किया गया है, और 'तैयार भोजन तथा अन्य खाद्य उत्पाद' वर्ग में मसालों को शामिल किया गया है। सीपीआई (2012=100) शृंखला में मौजूद 'मांस एवं मछली' उप-समूह को सीपीआई (2024=100) शृंखला में दो वर्गों—'मांस: ताजा, ठंडा या जमा हुआ' और 'मछली एवं अन्य समुद्री खाद्य'—में विभाजित किया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव 'खरीदे गए पके हुए भोजन और खरीदे गए पके हुए स्नैक्स' जैसी मदों का पुनर्वर्गीकरण है, जो सीपीआई (2012=100) शृंखला में 'तैयार भोजन, स्नैक्स, मिठाई' उप-समूह का हिस्सा थे, लेकिन अब सीपीआई (2024=100) शृंखला में इन्हें एक नए प्रभाग 'रेस्तरां और आवास सेवाएं' के अंतर्गत रखा गया है। इससे, नई शृंखला में 'खाद्य एवं पेय पदार्थ' प्रभाग के भारांक में गिरावट आई है।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ अनुमान।

[11] उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-2012=100) शृंखला के 'सब्जी' उप-समूह का सीपीआई-सी में भारांक 6.0 प्रतिशत और 'खाद्य एवं पेय पदार्थ' समूह में 13.2 प्रतिशत था। इसके विपरीत, सीपीआई (2024=100) शृंखला में तुलनीय सब्जी श्रेणी, अर्थात 'सब्जियां, कंद, केला तथा सब्जी वाले केला' (दालों को छोड़कर) वर्ग का सीपीआई-सी में भारांक 5.2 प्रतिशत और 'खाद्य एवं पेय पदार्थ' प्रभाग में 14.1 प्रतिशत है।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

चार्ट IV.7: सीपीआई-खाद्य में मूल्य वृद्धि का संचय

(प्रतिशत)

टिप्पणी: 1. मूल्य वृद्धि की गणना दिसंबर 2025 तक पुरानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृंखला (2012=100) का उपयोग करके की गई है और इसके बाद नई शृंखला (2024=100) का उपयोग किया गया है।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ अनुमान।

चार्ट IV.8: सब्जियों की बाजार आवक

[मिलियन मीट्रिक टन, बायां पैमाना; प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष), दायां मान]

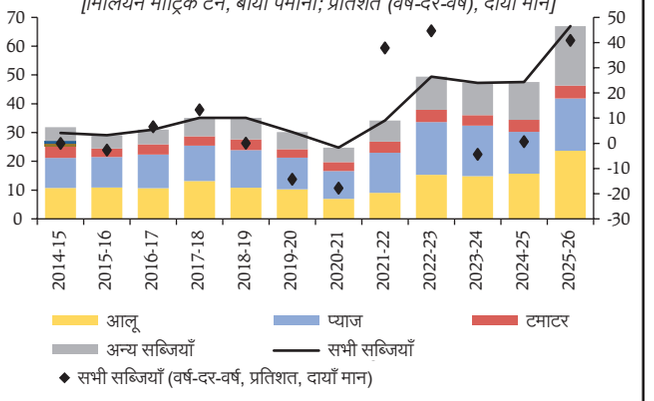

टिप्पणियाँ: 1. आंकड़े प्रत्येक वर्ष के लिए अप्रैल-फरवरी के दौरान हुई कुल आवक से संबंधित हैं। अन्य सब्जियों में बैंगन, बंदगोभी, फूलगोभी, लहसुन, हरी मिर्च, भिंडी और पालक शामिल हैं।

2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृंखला 2024=100/2012=100 में, सब्जी उप-समूह के अंतर्गत मद-वार भार (प्रतिशत में) इस प्रकार हैं: आलू 14.6/16.3, प्याज: 13.5/10.7, टमाटर: 9.6/9.5, और अन्य सब्जियां: 62.3/63.5।

स्रोत: एगमार्कनेट

सब्जी उप-समूह के भीतर, टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) तथा गैर-टीओपी सब्जियों की कीमतों के बीच एक विपरीत रुझान देखा गया है। टीओपी श्रेणी में कीमतों की वृद्धि (2012 और 2024 दोनों शृंखलाओं में), अब तक 2025-26 के दौरान ऐतिहासिक औसत से कम रही (चार्ट IV.9ए)। सितंबर-दिसंबर 2025 के दौरान आलू की कीमतें गहरी अपस्फीति में रहीं, जो 2024-25 में उच्च उत्पादन को दर्शाती हैं जिसके कारण पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहा। रबी की बंपर फसल और खरीफ की आवक में सुधार के कारण प्याज की कीमतें भी पिछले साल की तुलना में कम रहीं। हालांकि, प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में अक्टूबर 2025 में हुई स्थानीय बेमौसम बारिश के कारण टमाटर की कीमतों में तेजी आई, जिससे सर्दियों में कीमतों में होने वाली सामान्य गिरावट में देरी हुई। टीओपी सब्जियों के विपरीत, गैर-टीओपी सब्जियों में कीमतों की वृद्धि, जैसा कि सीपीआई (2024=100) शृंखला में दर्ज किया गया है, ऐतिहासिक औसत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक थी (चार्ट IV.9बी)।

चार्ट IV.9: सब्जियों में मूल्य वृद्धि का संचय

ए: टीओपी

(प्रतिशत)

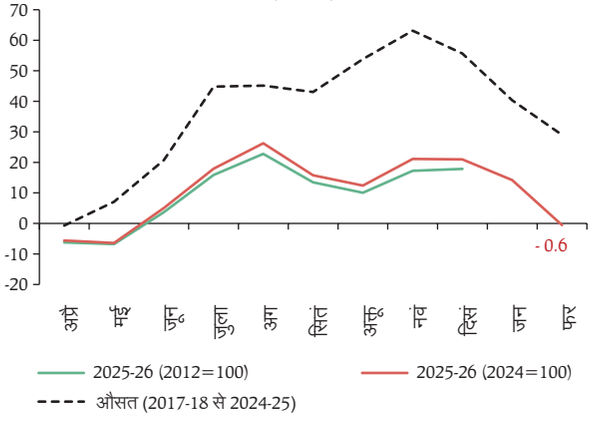

बी: गैर-टीओपी

(प्रतिशत)

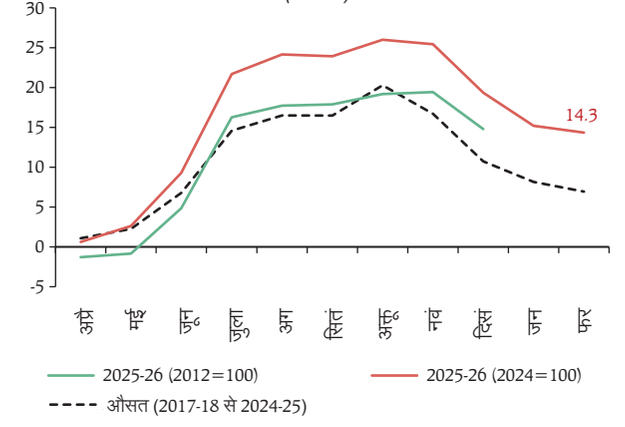

टिप्पणियाँ: 1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की (2024=100) शृंखला में, टीओपी से तात्पर्य टमाटर, प्याज और आलू से है, जिनका सब्जियों के अंतर्गत कुल भार 37.7 प्रतिशत है।

2. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पुरानी (2012=100) और नई (2024=100) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृंखला हेतु मूल्य वृद्धि को प्रस्तुत किया गया है, और इसकी तुलना पुरानी शृंखला पर आधारित औसत मूल्य वृद्धि से की गई है।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ अनुमान।

अपने ऐतिहासिक रुझान के विपरीत, दालों[12] की कीमतों में 2025-26 के दौरान अब तक गिरावट जारी रही और फरवरी 2025 से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अपस्फीति दर्ज की गई (चार्ट IV.10ए और बी)। 2024-25 और 2025-26 में उच्च घरेलू उत्पादन[13], घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रमुख दालों का आयात[14] और खुदरा बाजारों में सरकार के लक्षित हस्तक्षेपों ने कीमतों में समग्र कमी लाने में योगदान दिया। नई सीपीआई (2024=100) शृंखला से उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि दालों और उत्पादों के उप-वर्ग में अपस्फीति की स्थिति बनी रही, जिसमें जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान (-) 9.0 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष अपस्फीति दर्ज की गई।

सितंबर-दिसंबर 2025 के दौरान अनाज एवं उत्पादों की मुद्रास्फीति 0.7 प्रतिशत तक कम हो गई, जो एक वर्ष पहले समवर्ती अवधि[15] के दौरान 6.8 प्रतिशत थी। नए सीपीआई शृंखला में, चावल और गेहूं की कीमतों में गिरावट के कारण 'अनाज एवं अनाज उत्पाद' वर्ग ने फरवरी 2026 में (-)0.3 प्रतिशत की अपस्फीति दर्ज की (चार्ट IV.11)।

अनाज की कीमतों में सुधार मुख्य रूप से अनुकूल आपूर्ति स्थितियों से आया, जो मजबूत उत्पादन और पर्याप्त स्टॉक[16] के समर्थन से संभव हुआ। पर्याप्त आपूर्ति के मद्देनजर, सरकार ने फरवरी 2026 में गेहूं के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी,

चार्ट IV.10: सीपीआई-दाल और उत्पाद

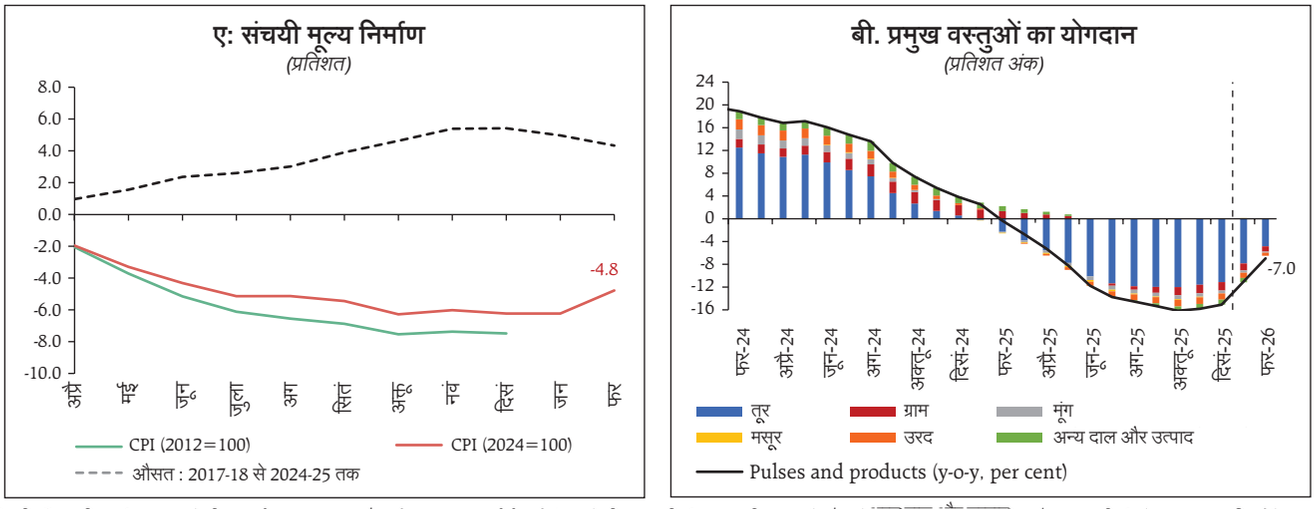

टिप्पणियाँ: 1. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पुरानी (2012=100) और नई (2024=100) सीपीआई शृंखला के लिए मूल्य निर्माण प्रस्तुत किया गया है और इसे पुरानी शृंखला पर आधारित औसत मूल्य निर्माण के साथ तुलना की गई है।

2. पुरानी CPI शृंखला में 'दालें और उत्पाद' सूचकांक के उपसमूह का हिस्सा थे। नई सीपीआई शृंखला में, उप-वर्ग 'दाल' 'सब्जियाँ, कंद, केले, सब्जी योग्य केले और दाल' के व्यापक वर्ग के अंतर्गत आता है। पुरानी शृंखला के साथ तुलना के लिए 'दालें और उत्पाद' श्रेणी को 'दालें' उप-वर्ग को उन वस्तुओं के साथ संयोजित करके तैयार किया गया है जो दाल उत्पादों से संबंधित हैं, अर्थात 'बेसन और चने के उत्पाद' तथा 'अन्य दाल उत्पाद', जो एक ही व्यापक वर्ग के अंतर्गत आते हैं।

3. सीपीआई 2024=100/2012=100 में, दालें और उत्पाद उप-वर्ग में वस्तुवार भार (प्रतिशत में) निम्नलिखित हैं: तूर: 32.4/33.4, चना: 12.4/12.3, मूंग: 14.5/14.5, मसूर: 12.3/12.7, उड़द: 11.2/11.5 तथा अन्य: 17.1/15.5।

4. ऊर्ध्वाधर डैश रेखा पुरानी और वर्तमान सीपीआई शृंखला के बीच विभाजन को दर्शाती है।

स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान

[12] सीपीआई (2012=100) शृंखला में 'दालें और उत्पाद' उपसमूह का सीपीआई में भार 2.4 प्रतिशत और 'खाद्य एवं पेय' समूह में 5.2 प्रतिशत है। सीपीआई (2024=100) शृंखला में, 'दालें' उप-वर्ग 'सब्जियाँ, कंद, केले, सब्जी योग्य केले और दालें' विस्तृत वर्ग से संबंधित है तथा सीपीआई में इसका भार 1.5 प्रतिशत और 'खाद्य एवं पेय' विभाग में 4.0 प्रतिशत है। 'बेसन और चने के उत्पाद' तथा 'अन्य दाल उत्पाद' आइटम्स के साथ मिलाकर, ये भार सीपीआई में 1.6 प्रतिशत और विभाग में 4.5 प्रतिशत तक पहुँचते हैं। फरवरी 2026 में, 'दालें' उपश्रेणी ने (-) 7.4 प्रतिशत की अपस्फीति दर्ज की, और इन दाल उत्पादों के साथ मिलाकर यह सीपीआई (2024=100) शृंखला में (-) 7.0 प्रतिशत दर्ज हुई।

[13] 2025-26 में दालों के उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2024-25 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि के बाद हुई (2025-26 के दूसरे प्रगति अनुमानों और 2024-25 के अंतिम अनुमानों के अनुसार)।

[14] वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के अनुसार, अप्रैल 2025 - जनवरी 2026 की अवधि के दौरान दालों के आयात 4.9 मिलियन मेट्रिक टन रहे, जिसके अलावा 2024-25 में रिकॉर्ड 7.3 मिलियन मेट्रिक टन दालों का आयात किया गया।

[15] सीपीआई (2012=100) शृंखला में 'अनाज और उत्पाद' उपसमूह का सीपीआई में भार 9.7 प्रतिशत और 'खाद्य एवं पेय पदार्थ' समूह में 21.1 प्रतिशत था। सीपीआई (2024=100) शृंखला में 'अनाज एवं अनाज उत्पाद' वर्ग का सीपीआई में भार 5.9 प्रतिशत तथा 'खाद्य एवं पेय पदार्थ' विभाग में 16.2 प्रतिशत है।

[16] 2024-25 में 9 प्रतिशत की वृद्धि के बाद (2024-25 के अंतिम अनुमानों के अनुसार) 2025-26 में चावल के उत्पादन में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (2025-26 के दूसरे प्रगति अनुमानों के अनुसार)। स्टॉक पर्याप्त हैं, तथा 1 मार्च, 2026 तक चावल के बफर स्टॉक नॉर्म के 9.7 गुना हैं। 2025-26 में गेहूं के उत्पादन में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार) तथा बफर स्टॉक भी 16 मार्च, 2026 तक नॉर्म के 1.7 गुना के स्तर पर पर्याप्त बने हुए हैं।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

चार्ट IV.11: अनाज मुद्रास्फीति

(वर्ष दर वर्ष, प्रतिशत)

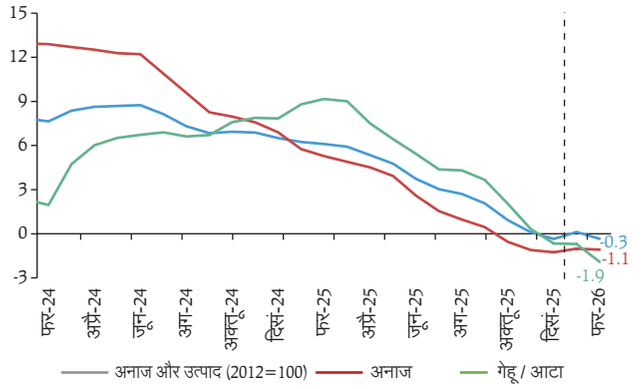

टिप्पणियाँ: 1. सीपीआई (2024=100) शृंखला में, गेहूं और गेहूं का आटा अलग-अलग वस्तुओं के रूप में माने जाते हैं, इन्हें सीपीआई (2012=100) शृंखला के साथ एक तुलनीय सूचकांक बनाने के लिए संयुक्त किया गया है।

2. ऊर्ध्वाधर डैश रेखा जनवरी 2026 के रिलीज के बाद पुरानी और वर्तमान सीपीआई शृंखला के बीच विभाजन को दर्शाती है, क्योंकि दोनों शृंखलाओं के बीच मुद्रास्फीति डेटा पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं।

स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान

जिससे गेहूं और गेहूं उत्पादों के 3 मिलियन मेट्रिक टन के निर्यात की अनुमति दी गई, ताकि प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन सुनिश्चित हो सके और तनावपूर्ण बिक्री से बचा जा सके।

तेल और वसा उप-समूह[17] में मुद्रास्फीति अगस्त में 21.2 प्रतिशत के उच्चतम प्रतिशत से दिसंबर 2025 में 6.8 प्रतिशत तक कम हो गई, जो वैश्विक पाम तेल की कीमतों में तेज गिरावट के कारण हुई (चार्ट IV.12ए)। सरसों और नारियल के घरेलू उत्पादन में कमी के कारण इस श्रेणी में मुद्रास्फीति अभी भी उच्च स्तर पर बनी रही (चार्ट IV.12बी)। वैश्विक पाम तेल की कीमतों में पलटाव के साथ, जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान 'तेल और वसा' श्रेणी में मुद्रास्फीति में वृद्धि देखी गई। मध्य पूर्व में संघर्ष के फैलने के बाद वैश्विक खाद्य वस्तुओं के मूल्यों पर लॉजिस्टिक्स लागत, विशेष रूप से भाड़ा और बीमा शुल्क में वृद्धि के कारण दबाव पड़ा है। यह स्थिति वैश्विक पाम और सोयाबीन तेल बाजार में तंगी के कारण और बिगड़ रही है, जिसमें प्रमुख उत्पादकों, जैसे अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील द्वारा खाद्य तेलों का बायोडीजल उत्पादन के लिए पुनर्निर्देशन किया जा रहा है। हालांकि, घरेलू सरसों के उत्पादन में वृद्धि[18] कुछ राहत प्रदान करने की संभावना है।

चार्ट IV.12: खाद्य तेल और वसा मुद्रास्फीति

ए: खाद्य तेल की कीमतें: घरेलू और वैश्विक

(वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन, प्रतिशत)

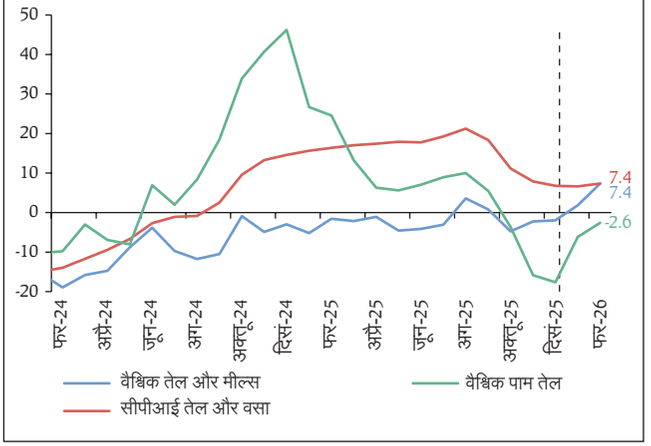

बी. सीपीआई तेल और वसा मुद्रास्फीति में योगदान

(प्रतिशत अंक)

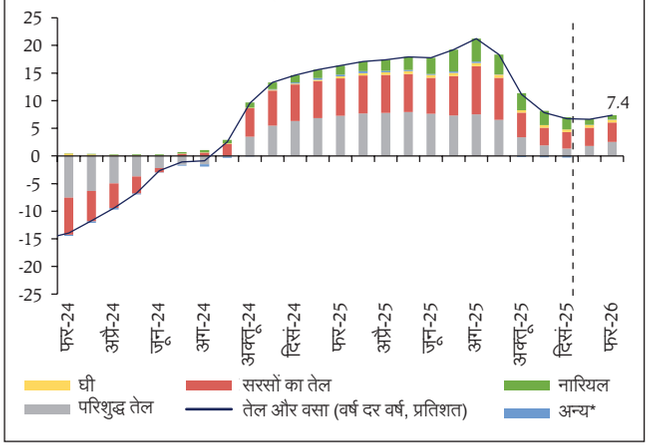

टिप्पणियाँ 1. ऊर्ध्वाधर डैश रेखा जनवरी 2026 के रिलीज़ के बाद पुरानी और वर्तमान सीपीआई शृंखला के बीच अंतर को दर्शाती है, क्योंकि दोनों शृंखलाओं के बीच मुद्रास्फीति डेटा पूर्णतः से तुलनीय नहीं हैं।

2. *: पुरानी शृंखला में, 'अन्य' में मूंगफली का तेल, मक्खन, वनस्पति और मार्जरीन शामिल थे। नई शृंखला में, इसमें मूंगफली का तेल, खाद्य तेल, मक्खन, वनस्पति और मार्जरीन शामिल हैं।

3. सीपीआई 2024=100/2012=100 में, सीपीआई-तेल और वसा उपसमूह में वस्तुओं के अनुसार भार (प्रतिशत में) निम्नलिखित हैं: सरसों का तेल: 35.0/37.3, शुद्ध तेल: 38.2/35.5, घी: 18.9/13.3, अन्य: 7.9/13.9.

[17] सीपीआई (2012=100) शृंखला में 'तेल एवं वसा' उपसमूह का सीपीआई में भार 3.6 प्रतिशत तथा 'खाद्य एवं पेय पदार्थ' समूह में 7.8 प्रतिशत है। सीपीआई (2024=100) श्रृंखला में 'तेल एवं वसा' वर्ग का सीपीआई में भार 2.7 प्रतिशत तथा 'खाद्य एवं पेय पदार्थ' विभाग में 7.5 प्रतिशत है।

[18] 18. सरसों और रेपसीड ने 2024-25 की तुलना में 2025-26 में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार)।

फलों[19] के उप-समूह में मुद्रास्फीति अप्रैल 2025 में 13.9 प्रतिशत से दिसंबर 2025 में 6.7 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई। नई शृंखला के अनुसार, 'फल और मेवे' श्रेणी में मई 2026 में मुद्रास्फीति 8.6 प्रतिशत रही। नारियल जो पिछले वर्ष से फलों की मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण रहा, ने नए रोपण चक्र में मुद्रास्फीति में नरमी दर्ज की। (चार्ट IV.13)।

सितंबर-दिसंबर 2025 के दौरान पशु आधारित प्रोटीन विशेषकर मांस, मछली और अंडे की मुद्रास्फीति मजबूत बनी रही। नई सीपीआई श्रृंखला में, 'मांस, ताजा, ठंडा या जमा हुआ' और 'मछली तथा अन्य समुद्री भोजन' श्रेणियों में जनवरी-फरवरी के दौरान क्रमशः 9.1 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत की औसत दर से उच्च मुद्रास्फीति बनी रही।

समग्र रूप से, 2025-26 के दौरान भोजन की कीमतों में सुधार अनुकूल आपूर्ति स्थितियों के कारण हुआ, जो उच्च घरेलू उत्पादन, मजबूत बाजार आवक और प्रमुख अनाज के स्टॉक में

चार्ट IV.13: सीपीआई फल और मेवों की मुद्रास्फीति के संचालक

(प्रतिशत बिंदु)

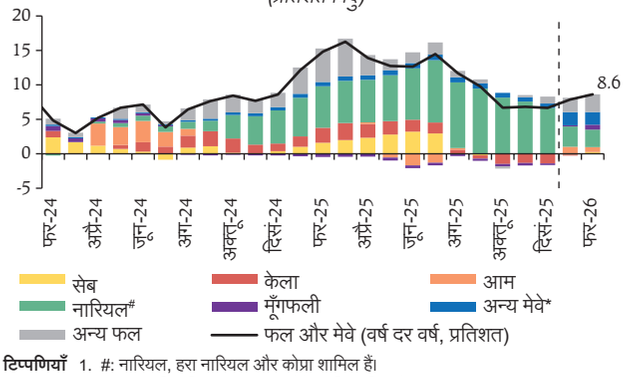

टिप्पणियाँ 1. #: नारियल, हरा नारियल और कोप्रा शामिल हैं।
2. *: खजूर, किशमिश, काजू, अन्य मेवे आदि शामिल हैं।
3. सीपीआई 2024=100/2012=100 में, सीपीआई-फल और मेवे उपसमूह में वस्तु-वार भार (प्रतिशत में) निम्नलिखित हैं: सेब: 15.2/16.3, केला: 12.6/19.4, आम: 8.3/11.1, नारियल#: 11.2/14.1, मूंगफली: 8.6/9.9, अन्य मेवे*: 19.4/8.2, अन्य फल: 24.8/21.0.
4. ऊर्ध्वाधर डैश रेखा जनवरी-2026 रिलीज़ के बाद पुरानी और वर्तमान सीपीआई शृंखला के बीच विभाजन को दर्शाती है।

स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान

पर्याप्तता से प्रतिबिंबित हुआ। चरम मौसमी घटनाओं के अभाव ने भोजन मुद्रास्फीति में अस्थिरता को सीमित करने में मदद की। जीएसटी सुधार और व्यापार नीति पहल जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों ने भी चुनिंदा खाद्य कीमतों में सुधार में योगदान दिया।

हाल में, मध्य पूर्व में संघर्ष ने कृषि इनपुट लागतों के लिए जोखिम बढ़ा दी। उर्वरकों और प्रमुख कच्चे माल — जैसे तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), अमोनिया और सल्फर — की उपलब्धता के संबंध में बढ़ती अनिश्चितताएँ वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण चिंताओं के रूप में उभर रही हैं। ये भारत के लिए भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि यह अपनी तैयार उर्वरक आवश्यकताओं का एक तिहाई और प्राकृतिक गैस का 60 प्रतिशत से अधिक आवश्यकताओं के लिए पश्चिम एशियाई देशों[20] पर निर्भर करता है। हालांकि, घरेलू उर्वरक स्थिति अल्पकाल में पर्याप्त स्टॉक के समर्थन से अपेक्षाकृत सहज बनी हुई है। 19 मार्च, 2026 तक, आगामी खरीफ मौसम के लिए सरकार के पास उर्वरक स्टॉक 180 लाख मेट्रिक टन था, जो एक वर्ष पहले[21] की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक था। यह तत्काल आपूर्ति बाधाओं के खिलाफ एक बफर प्रदान करता है, हालांकि आपूर्ति शृंखला में अधिक लंबे समय तक बाधा होने से उपलब्धता और लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सीपीआई ईंधन

जबकि 2025 के अधिकांश समय के दौरान वैश्विक तेल की कीमतें गिरती रहीं, ईंधन की कीमतों पर दबाव नियंत्रित रहा और 'सीपीआई ईंधन एवं प्रकाश' समूह की मुद्रास्फीति सितंबर-दिसंबर 2025 के दौरान 2.0-2.3 प्रतिशत के बीच सीमित रही। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रमुख टैरिफ संशोधन के अभाव में, बिजली सूचकांक में वार्षिक आधार पर मुद्रास्फीति 1.1-1.6 प्रतिशत की सीमा में नियंत्रित रही (चार्ट IV.14ए)। मिट्टी के तेल

[19] सीपीआई (2012=100) शृंखला में 'फल' उपसमूह का सीपीआई में भार 2.9 प्रतिशत तथा 'खाद्य एवं पेय' समूह में 6.3 प्रतिशत है। सीपीआई (2024=100) श्रृंखला में 'फल और मेवे' वर्ग का सीपीआई में भार 3.7 प्रतिशत तथा 'खाद्य एवं पेय' विभाग में 10.1 प्रतिशत है।

[20] भारत यूरिया और कॉम्प्लेक्स (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम (एनपीके)) में आत्मनिर्भर है, जिसमें आयात का हिस्सा 20 प्रतिशत से कम है। हालांकि, डायअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और पोटाश के म्यूरिएट (एमओपी) के मामले में, भारत निर्मित उर्वरकों और घरेलू उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल दोनों के लिए आयात पर भारी निर्भरता रखता है।

[21] https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2242656&reg=3&lang=2

मौद्रिक नीति वक्तव्य

की कीमतें अपस्फीति से बाहर आ गईं, क्योंकि अक्टूबर-दिसंबर 2025 के दौरान महानगरों[22] में सब्सिडी वाले मिट्टी के तेल की कीमतों में तीन बार वृद्धि की गई। जनवरी 2026 में कीमतों में कमी की गई, लेकिन फरवरी में फिर से वृद्धि की गई।

नए सीपीआई शृंखला (2024=100) के आधार पर, जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान ईंधन मदों[23] ने बहुत कम 0.1 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की और इसका मुख्य कारण दोनों महीनों में बिजली उपश्रेणी में (-)2.4 प्रतिशत की अपस्फीति है। यह कुछ राज्यों में मुफ्त बिजली की आपूर्ति को दर्शाता है, जिसका समग्र औसत मूल्यों पर संयमित प्रभाव पड़ा था। परिवहन ईंधन के अंतर्गत, पेट्रोल और डीजल के खुदरा कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नई शृंखला में शामिल किए गए 'अन्य प्राकृतिक गैस' (सीएनजी) ने जनवरी और फरवरी में क्रमशः 1.9 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की (चार्ट IV.14बी)।

पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक गैस की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2026 की शुरुआत में घरेलू एलपीजी की कीमतों में प्रति सिलेंडर ₹60 की वृद्धि की गई, जिसका प्रभाव आने वाले महीनों[24] के सीपीआई मुद्रास्फीति आंकड़ों में दिखाई देगा।

मार्च 2024[25] में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्यों में पिछले संशोधन के बाद से, अंतरराष्ट्रीय मानक मूल्य फरवरी 2026 तक गिरते रहे हैं। हालांकि, मार्च में वे काफी बढ़ गई, जिससे ओएमसी के लिए बड़ी घाटे की स्थिति उत्पन्न हुई (चार्ट IV.15)। इस संदर्भ में, भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में प्रति लीटर 10 रुपये की कटौती की घोषणा की, जिसका उद्देश्य घाटे को आंशिक रूप से कम करना था।

चार्ट IV.14 : सीपीआई ईंधन मुद्रास्फीति

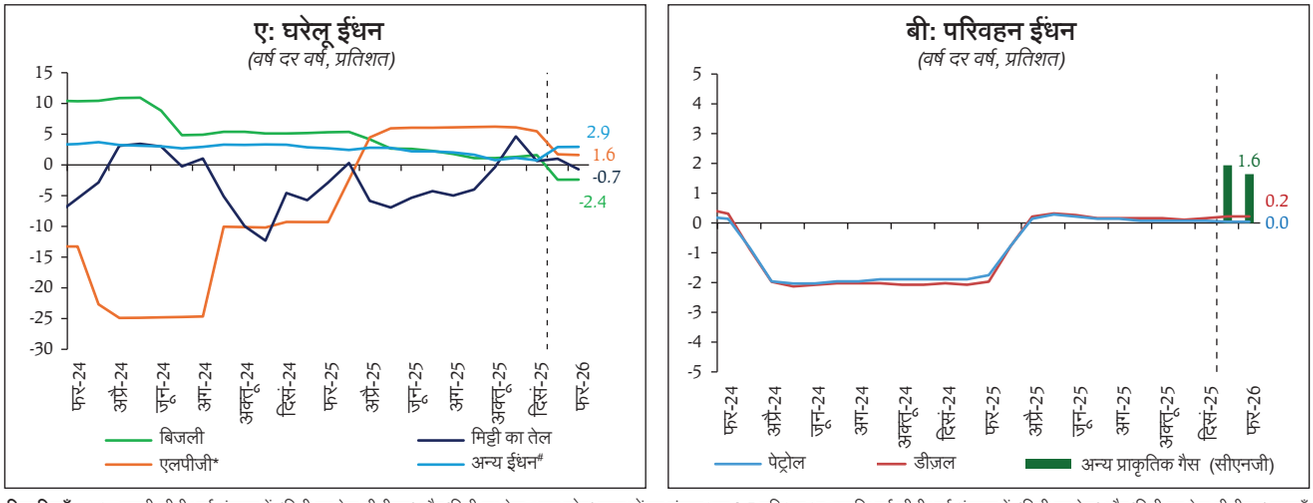

टिप्पणियाँ
1. पुरानी सीपीआई शृंखला में, 'मिट्टी का तेल-पीडीएस' और 'मिट्टी का तेल-अन्य स्रोत' वस्तुओं का संयुक्त भार 0.5 प्रतिशत था, जबकि नई सीपीआई शृंखला में, 'मिट्टी का तेल' और 'मिट्टी का तेल-पीडीएस' वस्तुएँ 'तरल ईंधन' उपवर्ग के अंतर्गत आती हैं, जिसका संयुक्त भार बहुत कम, 0.01 प्रतिशत है। पुरानी और नई सीपीआई शृंखला में बिजली का भार 2.3% पर लगभग समान रहता है, पुरानी शृंखला में 'एलपीजी' (जिसका भार 1.3 प्रतिशत था) को नई शृंखला में 'एलपीजी सिलेंडर और पाइप्ड नेचुरल गैस' मद (जिसका भार 2.0 प्रतिशत है) द्वारा प्रतिस्थापित की गई है।
2. ऊर्ध्वाधर डैश रेखा पुरानी और नई सीपीआई शृंखला के बीच विभाजन को दर्शाती है, क्योंकि मुद्रास्फीति के आंकड़े दोनों शृंखलाओं के बीच पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं।
3. *: नई शृंखला में पाइप्ड नेचुरल गैस के साथ-साथ एलपीजी शामिल है।
4. #: नई शृंखला में अन्य ईंधन में कोयला, लकड़ी और चिप्स, लकड़ी का कोयला, गोबर की ईंट, बायोगैस और गोबर गैस शामिल हैं। पुरानी शृंखला में इसमें डीजल, कोक, लकड़ी और चिप्स, कोयला, लकड़ी का कोयला, गोबर की ईंट और 'अन्य ईंधन' शामिल थे।

स्रोत : एनएसओ: और आरबीआई स्टाफ अनुमान

[22] इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) से प्राप्त आंकड़े।

[23] ईंधन से आशय घरेलू ईंधन, अर्थात् 'बिजली, गैस और अन्य ईंधन' समूह; तथा परिवहन ईंधन, अर्थात् 'व्यक्तिगत परिवहन उपकरणों के लिए ईंधन और स्नेहक' वर्ग से है, जिसमें 'पेट्रोल', 'डीजल' और 'अन्य प्राकृतिक गैस (सीएनजी)' शामिल हैं।

[24] 'एलपीजी सिलेंडर और पाइप्ड नेचुरल गैस' एक संयुक्त मद है जिसका समग्र सीपीआई (2024=100) में भार 2.0 प्रतिशत है।

[25] मार्च 2024 में, ओएमसी ने पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्यों में प्रति लीटर ₹2 की कमी की।

चार्ट IV.15: वैश्विक एवं घरेलू ईंधन मूल्य

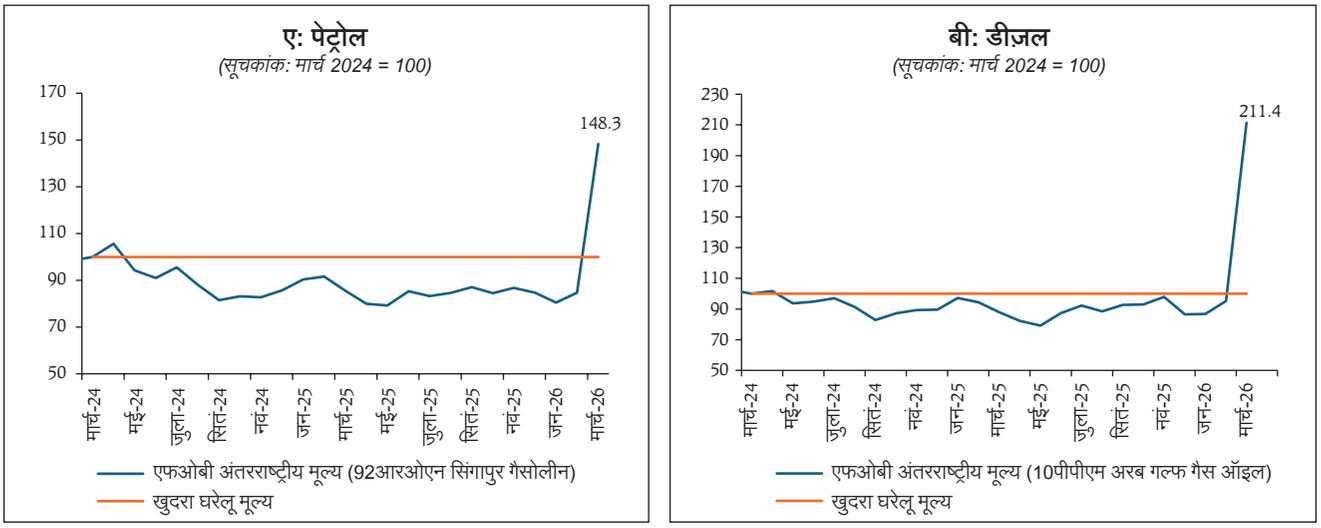

टिप्पणी: सूचकांकों की गणना मार्च 2024 = 100 आधार पर की गई है ताकि भारत में पिछले खुदरा मूल्य संशोधन के बाद से सापेक्ष गतिविधियों को दर्शाया जा सके।
स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण सेल (पीपीएसी); तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

कोर सीपीआई (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई)

सीपीआई 2012 श्रृंखला में, खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर सीपीआई की गणना 'खाद्य एवं पेय' तथा 'ईंधन एवं प्रकाश' समूहों को बाहर रखकर की गई थी। सीपीआई 2024 श्रृंखला में दो ईंधन घटक हैं, अर्थात् घरेलू ईंधन —'बिजली, गैस और अन्य ईंधन' का समूह, तथा परिवहन ईंधन —'व्यक्तिगत परिवहन उपकरणों के लिए ईंधन और स्नेहक' का वर्ग, जिसमें 'पेट्रोल', 'डीजल' और 'अन्य प्राकृतिक गैस (सीएनजी)' शामिल हैं। अतः खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर सीपीआई की गणना 'खाद्य एवं पेय समूह' तथा दोनों ईंधन घटकों को बाहर रखकर की जाती है (बॉक्स IV.2)।

सीपीआई (2012=100) शृंखला में, सितंबर-दिसंबर 2025 के दौरान कोर मुद्रास्फीति का औसत 4.6 प्रतिशत रहा, जो हेडलाइन मुद्रास्फीति से अधिक था, जिसका मुख्य कारण कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी से हुई वृद्धि रहा। सितंबर-दिसंबर 2025 के दौरान, सोने की कीमतों में 20.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे दिसंबर में कोर मुद्रास्फीति में इसका योगदान 212 आधार अंकों तक पहुँच गया। आवास और स्वास्थ्य मुख्य

बॉक्स IV.2: नई सीपीआई शृंखला में मुख्य मुद्रास्फीति: पुनर्विचार

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पारंपरिक रूप से कोर मुद्रास्फीति का एक बहिष्करण-आधारित उपाय का उपयोग करके अंतर्निहित मुद्रास्फीति दबावों का आकलन किया है। सीपीआई शृंखला (आधार 2012=100) में, कोर मुद्रास्फीति की गणना समग्र सीपीआई से 'खाद्य एवं पेय' तथा 'ईंधन एवं प्रकाश' समूहों को बाहर रखकर की जाती थी। इस दृष्टिकोण में, पेट्रोल और डीजल जैसे परिवहन ईंधन 'परिवहन एवं संचार' उप-समूह के अंतर्गत अलग मदों के रूप में बने रहे और कोर मुद्रास्फीति का हिस्सा बने रहे। परिणामस्वरूप, कोर मुद्रास्फीति का माप मूल्यों में ईंधन-संबंधी उतार-चढ़ावों को पूरी तरह से बाहर नहीं कर पाया।

नई सीपीआई शृंखला (आधार 2024=100) आईएमएफ के सीओआईसीओपी 2018 पर आधारित है, जो दो ईंधन घटकों की अलग-अलग पहचान करता है: (ए) 'आवास, जल, बिजली, गैस एवं अन्य ईंधन' प्रभाग के अंतर्गत 'बिजली, गैस एवं अन्य ईंधन'; तथा (बी) 'परिवहन' विभाग के अंतर्गत 'व्यक्तिगत परिवहन साधनों के लिए ईंधन एवं स्नेहक'। इस प्रकार, नई शृंखला में कोर मुद्रास्फीति का माप समग्र मुद्रास्फीति से 'खाद्य एवं पेय', 'बिजली,

(जारी)

मौद्रिक नीति वक्तव्य

गैस एवं अन्य ईंधन', तथा 'व्यक्तिगत परिवहन साधनों के लिए ईंधन एवं स्नेहक' को बाहर रखकर परिभाषित किया जा सकता है।

कोर मुद्रास्फीति की परिभाषा से घरेलू एवं परिवहन ईंधन दोनों को बाहर रखने से कई लाभ होते हैं। पहला, यह माप की प्रतिनिधित्व क्षमता में सुधार करता है, क्योंकि खुदरा ईंधन मूल्य मुख्य रूप से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों से प्रभावित होते हैं और मांग-पक्ष के दबावों को कम प्रतिबिंबित करते हैं। दूसरा, चूंकि खुदरा ईंधन की कीमतें अक्सर संशोधित नहीं की जाती हैं, इसलिए यदि उन्हें शामिल किया जाता है तो मुख्य माप में बड़े असतत परिवर्तन होंगे, जिससे अंतर्निहित मुद्रास्फीति के मूल्यांकन में जटिलता उत्पन्न होगी। इसके अलावा, नई सीपीआई शृंखला में परिवहन ईंधन का भार काफी बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल के भार में सीपीआई (2012 = 100) शृंखला में क्रमशः 2.2 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 2024 शृंखला में क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 0.3 प्रतिशत हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, नई शृंखला में परिवहन ईंधन के अंतर्गत 'अन्य प्राकृतिक गैस (सीएनजी)' नामक एक नई मद शामिल की गई है, जिसका भार 0.04 प्रतिशत है। समग्र रूप से, कोर मुद्रास्फीति माप से परिवहन ईंधन को बाहर रखना इसे अंतर्निहित मांग स्थितियों का एक अधिक विश्वसनीय माप बना देगा।

तालिका IV.2.1 पुरानी और नई शृंखला के तहत ईंधन और मुख्य घटकों के भारों की तुलना दोनों वर्गीकरणों का उपयोग करके करती है। दोनों वर्गीकरणों के तहत नई शृंखला में कोर घटक

तालिका IV.2.1: वैकल्पिक वर्गीकरणों के आधार पर ईंधन और कोर के भार

(प्रतिशत)

माप	वर्गीकरण	पुराने सीपीआई (2012=100)	नए सीपीआई (2024=100)	अंतर (नया घटा पुराना)
ईंधन	पुराने	6.8	5.4	-1.4
	नए	9.2	10.2	1.0
कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर)	पुराने	47.3	57.9	10.6
	नए	45.0	53.0	8.0

टिप्पणी: पुराने वर्गीकरण में ईंधन में केवल घरेलू ईंधन को शामिल करता है, जबकि नए वर्गीकरण में घरेलू तथा परिवहन ईंधन दोनों शामिल हैं।

स्रोत: एनएसओ: और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

का भार बढ़ गया है। इसी समय, नए वर्गीकरण के अनुसार ईंधन का भार अधिक है, जो परिवहन ईंधन श्रेणी के समावेश को प्रतिबिंबित करता है। घरेलू और परिवहन ईंधन दोनों को छोड़कर कोर समूह का सीपीआई (2024 = 100) शृंखला में भार 53.0 प्रतिशत है।

चार्ट IV.2.1 जनवरी और फरवरी 2026 में दोनों मापों द्वारा दर्ज मुद्रास्फीति की तुलना करता है। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार, दोनों महीनों में कोर मुद्रास्फीति 30 आधार बिंदु अधिक है (पिछले वर्ष भर में परिवहन ईंधन की खुदरा कीमतें लगभग अपरिवर्तित रही हैं; अतः इसके बाहर रखने से वार्षिक मुद्रास्फीति अधिक दर्ज हुई)। दूसरी ओर, ईंधन मुद्रास्फीति लगभग समान बनी रही।

तालिका IV.2.1: वैकल्पिक वर्गीकरणों के आधार पर ईंधन और कोर के भार

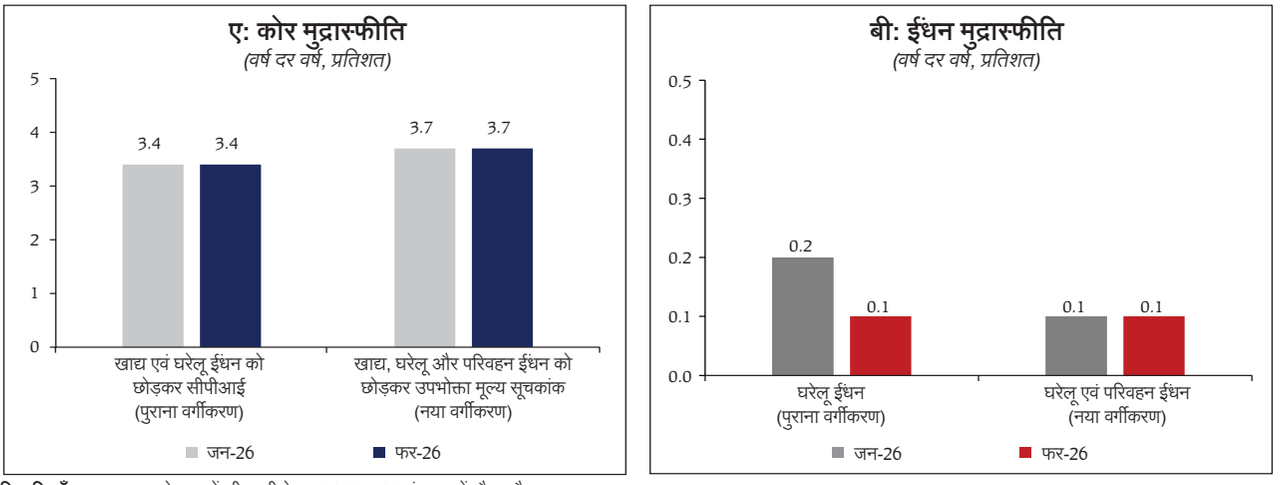

टिप्पणियाँ: 1. एक मद के रूप में सीएनजी केवल 2024=100 शृंखला में मौजूद है।
2. दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए मुद्रास्फीति सीपीआई 2012 शृंखला पर आधारित है। जनवरी और फरवरी 2026 की संख्याएँ सीपीआई 2024 शृंखला पर आधारित हैं।

स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मुद्रास्फीति में अन्य प्रमुख योगदानकर्ता बने रहे (चार्ट IV.16ए)। नई सीपीआई शृंखला (2024=100) में, जनवरी-फरवरी के दौरान कोर मुद्रास्फीति का औसत 3.7 प्रतिशत रहा, जो मुख्य रूप से आवास मुद्रास्फीति में कमी[26] और कीमती धातुओं की कीमतों में मुद्रास्फीति में कमी के कारण था, क्योंकि कीमती धातुओं की विनिर्देशन में बदलाव किया गया था जिसमें सोने के बुलियन कीमतों के बजाय आभूषण कीमतों को शामिल किया गया (चार्ट IV.16बी)।

मूल्यवान धातुओं का कोर मुद्रास्फीति पर असमानुपातिक प्रभाव कोर और 'मूल्यवान धातुओं को छोड़कर कोर' मुद्रास्फीति के बीच अंतर का कारण बना है। पुरानी सीपीआई शृंखला (2012=100) के आधार पर, दिसंबर में खाद्य, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, सोने और चांदी[27] को छोड़कर सीपीआई में मुद्रास्फीति 2.4 प्रतिशत तक कम हो गई, जो पारंपरिक कोर मुद्रास्फीति (अर्थात् खाद्य और ईंधन को छोड़कर) से 240 आधार अंक कम है। नई सीपीआई (2024=100) शृंखला में भी रुझान सामान्य रूप से समान बने हुए हैं, जहां खाद्य, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी को छोड़कर सीपीआई फरवरी 2026 में 2.1 प्रतिशत तक कम हो गया, जो पारंपरिक कोर मुद्रास्फीति (यानी, खाद्य और ईंधन को छोड़कर) से 160 आधार अंक नीचे है (तालिका IV.1)।

अंतर्निहित मुद्रास्फीति[28] की प्रवृत्तियों को उसके वस्तु और सेवा घटकों[29] में विभाजित करने से पता चलता है कि अक्टूबर-दिसंबर 2025 के दौरान वस्तु मुद्रास्फीति 2025-26 के पहले अर्ध-वर्ष में 2.9 प्रतिशत से घटकर 1.9 प्रतिशत हो गई, जिसका मुख्य कारण परिवहन और संचार समूह में अपस्फीति था। उसी

चार्ट IV.16: सीपीआई कोर मुद्रास्फीति में योगदान

(प्रतिशत अंक)

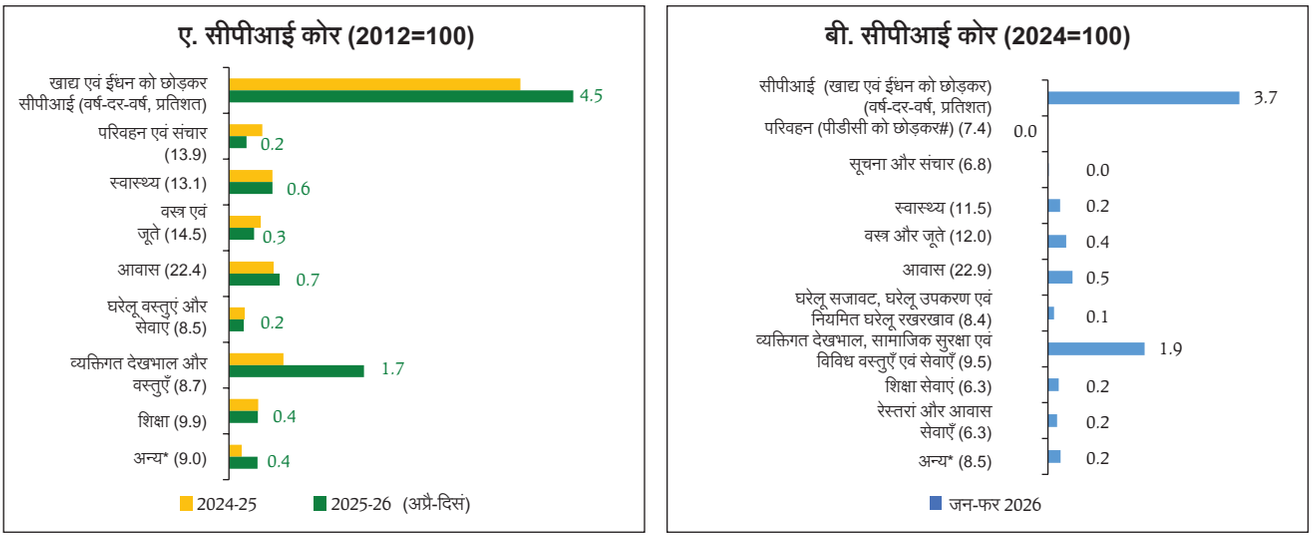

टिप्पणियाँ: 1. *: अन्य में पान, तम्बाकू और मादक पदार्थ; तथा मनोरंजन और आमोद-प्रमोद शामिल हैं।

2. पुरानी शृंखला में 3.9 प्रतिशत के भार वाला उपसमूह 'व्यक्तिगत देखभाल और वस्तुएँ' अब नई शृंखला में 5.0 प्रतिशत के भार वाला विभाग 'व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा एवं विविध वस्तुएँ और सेवाएँ' बन गया है। 'परिवहन और संचार' उपसमूह (पुरानी शृंखला में 8.6 प्रतिशत के भार के साथ) को 'सूचना और संचार' (3.6 प्रतिशत के भार के साथ) और 'परिवहन' (पुरानी शृंखला में 8.8 प्रतिशत के भार के साथ) प्रभागों में विभाजित किया गया है। 'शिक्षा' उपसमूह (पुरानी शृंखला में 4.5 प्रतिशत के भार के साथ) अब 'शिक्षा सेवाएँ' प्रभाग (3.3 प्रतिशत के भार के साथ) बन गया है।

3. # : पीडीसी : पेट्रोल, डीजल और सीएनजी।

स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[26] सीपीआई (2012=100) में, 'आवास' उपसमूह का भार 10.1 प्रतिशत था और यह केवल शहरी आवास खंड तक सीमित था, जिसमें कोई समवर्ती ग्रामीण घटक नहीं था। नई शृंखला सीपीआई (2024=100) में, 'आवास, जल, बिजली, गैस और अन्य ईंधन' प्रभाग का भार बढ़कर 17.7 प्रतिशत हो गया है, जिससे व्याप्ति में शहरी और ग्रामीण दोनों खंडों को शामिल किया गया है। नए प्रभाग में घरेलू ईंधन भी शामिल है, जिसका सीपीआई (2024=100) श्रृंखला में भार 5.4 प्रतिशत है।

[27] नई सीपीआई शृंखला (2024=100) में सोना और चांदी क्रमशः 'सोना/हीरा/प्लैटिनम आभूषण' और 'चांदी के आभूषण' को संदर्भित करते हैं।

[28] खाद्य, ईंधन, सीएनजी, सोना और चांदी को छोड़कर सीपीआई द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

[29] पुरानी सीपीआई शृंखला (2012=100) में, खाद्य, ईंधन, सोना और चांदी को छोड़कर सीपीआई में वस्तुओं के घटक का भार 20.7 प्रतिशत है, जबकि सेवाओं के घटक का समवर्ती भार 23.0 प्रतिशत है। नई सीपीआई शृंखला (2024=100) में, इन घटकों के भार क्रमशः 26.7 प्रतिशत और 25.4 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

तालिका IV.1: अपवर्जन-आधारित मुद्रास्फीति के माप (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

अवधि	सीपीआई (खाद्य और ईंधन को छोड़कर*)	सीपीआई (खाद्य, ईंधन*, सोना और चांदी को छोड़कर)
जन-25	3.9	3.2
फर-25	4.3	3.4
मार्च-25	4.3	3.3
अप्रै-25	4.4	3.5
मई-25	4.3	3.4
जून-25	4.6	3.5
जुला-25	4.2	3.2
अग-25	4.3	3.1
सितं-25	4.5	3.1
अक्तू-25	4.5	2.6
नवं-25	4.4	2.4
दिसं-25	4.8	2.4
जन-26	3.7	2.1
फर-26	3.7	2.1

टिप्पणियाँ: 1. फरवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक की मुद्रास्फीति संख्याएँ पुरानी सीपीआई (2012=100) शृंखला पर आधारित हैं, जबकि जनवरी 2026 और फरवरी 2026 के लिए ये संख्याएँ नई सीपीआई (2024=100) शृंखला पर आधारित हैं।

2. *नई सीपीआई (2024=100) शृंखला में 'ईंधन' घरेलू ईंधन, अर्थात् 'बिजली, गैस और अन्य ईंधन' समूह; और परिवहन ईंधन, अर्थात् 'व्यक्तिगत परिवहन उपकरणों के लिए ईंधन और स्नेहक' वर्ग को दर्शाता है, जिसमें 'पेट्रोल', 'डीजल' और 'अन्य प्राकृतिक गैस (सीएनजी)' शामिल हैं। पुरानी सीपीआई (2012=100) शृंखला में, 'ईंधन' समूह 'सीपीआई ईंधन और प्रकाश' तथा 'वाहन के लिए पेट्रोल' और 'वाहन के लिए डीजल' मदों को दर्शाता है।

3. खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर सीपीआई की गणना 'खाद्य एवं पेय' तथा 'ईंधन एवं प्रकाश' समूहों और 'वाहनों के लिए पेट्रोल' तथा 'वाहनों के लिए डीजल' मदों को हेडलाइन सीपीआई (2012=100) शृंखला से हटाकर की जाती है। नई सीपीआई (2024=100) शृंखला में, खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर सीपीआई की गणना 'खाद्य एवं पेय' प्रभाग, 'विद्युत, गैस, अन्य ईंधन' समूह तथा 'व्यक्तिगत परिवहन उपकरणों के लिए ईंधन और स्नेहक' वर्ग को हेडलाइन सीपीआई (2024=100) शृंखला से हटाकर की जाती है।

स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अवधि के दौरान सेवा मुद्रास्फीति भी 3.7 प्रतिशत से घटकर 3.0 प्रतिशत हो गई (चार्ट IV.17)।

IV.3 मुद्रास्फीति गतिकी को समझना

सांख्यिकीय गुण

2024-25 की तुलना में 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर 2025) में सीपीआई (2012=100) मुद्रास्फीति का वितरण, अपेक्षाकृत कम तीव्र सकारात्मक विषमता दर्शाता है, जो कीमतों के दबाव में व्यापक स्तर पर कमी को दर्शाता है। इस वितरण के दायरे में कमी भी दर्ज की गई है, जिससे पता चलता है कि उप-समूहों के बीच मुद्रास्फीति की अस्थिरता कम हुई है (चार्ट IV.18)। जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान नई शृंखला में भी इसी तरह का पैटर्न देखा गया है।

मासिक प्रक्षेपवक्र के संदर्भ में, अक्टूबर-दिसंबर 2025 (सीपीआई 2012=100) के दौरान मुद्रास्फीति के दबाव में कमी के साथ-साथ, कुछ वस्तुओं —जैसे कीमती धातुओं—के अलग-अलग हिस्सों (क्वांटाइल) में मुद्रास्फीति का अंतर भी बढ़ा है, जिनमें कीमती धातुओं में बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति दर्ज की गई है (चार्ट IV.19)। नई सीपीआई सीरीज़ (2024=100) में, मूल मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी का कारण मुद्रास्फीति के वितरण के ऊपरी हिस्सों (ऊपरी क्वांटाइल) का बढ़ना रहा है। इसकी मुख्य वजह 'निजी देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सामान और सेवाएँ' खंड है, जिसमें कीमती धातुएं शामिल हैं।

अंतर्निहित मुद्रास्फीति के सांख्यिकीय माप, जैसे कि ट्रिम्ड माध्य उपाय और भारित माध्यिका[30], खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई की तुलना में काफी कम स्तर पर बने रहे (सारणी IV.2)। प्रक्षेपवक्र के संदर्भ में, वे काफी हद तक पारंपरिक कोर मुद्रास्फीति के अनुरूप ही बने रहे।

अंतर्निहित मुद्रास्फीति की गतिशीलता को मापने का एक और तरीका उत्पादों को वस्तुओं और सेवाओं में वर्गीकृत करना है। वस्तुओं [जिनका पुराने सीपीआई (2012=100) में 76.6 प्रतिशत भार था] ने कोर मुद्रास्फीति में नकारात्मक योगदान दिया, जिससे अक्टूबर 2025 में यह अपने न्यूनतम स्तर पर पहुँच गई। इस बीच, सेवाओं (जिनका भार 23.4 प्रतिशत था) का समग्र मुद्रास्फीति में योगदान काफी हद तक स्थिर रहा (चार्ट IV.20)। नई श्रृंखला (सीपीआई 2024=100) में, वस्तुओं की मुद्रास्फीति

[30] जबकि अपवर्जन-आधारित उपाय प्रत्येक अवधि में कुछ तय अस्थिर मदों (जैसे, खाद्य और ईंधन) को हटा देते हैं, वहीं ट्रिम्ड उपाय मुद्रास्फीति वितरण की पीछे की मदों को हटाते हैं – प्रत्येक महीने कीमतों में तय सीमा से ज़्यादा बदलाव वाली मदों को हटा दिया जाता है, और हटाई गई मदें हर महीने अलग-अलग होती हैं। भारित औसत मुद्रास्फीति दर को उस मद से जुड़ी मुद्रास्फीति दर के तौर पर परिभाषित किया जाता है जो सीपीआई बास्केट के अंदर कीमतों में बदलाव के वितरण में 50वें परसेंटाइल पर आती है, जिसे सीपीआई भार का इस्तेमाल करके भारित किया जाता है।

चार्ट IV.17: खाद्य, ईंधन, सोना और चांदी को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति में योगदान

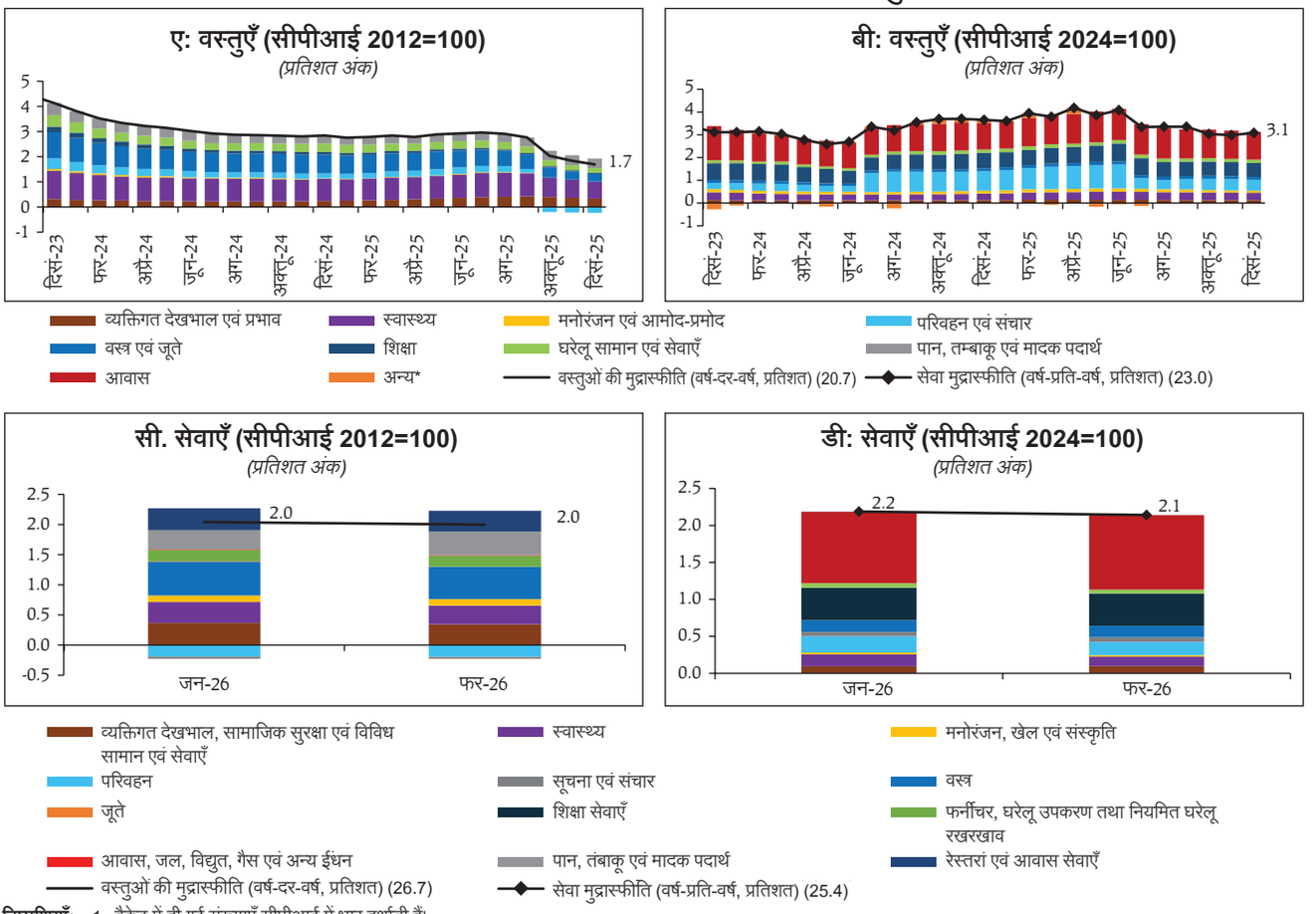

टिप्पणियाँ: 1. ब्रैकेट में दी गई संख्याएँ सीपीआई में भार दर्शाती हैं।
2. *: यह एक संतुलनकारी मद का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य ऊर्ध्वाधर रूप से समेकित सीपीआई की मद-स्तरीय सूचकांकों और प्रकाशित उप-समूह/समूह/समग्र सीपीआई सूचकांक के बीच के अंतर का मिलान करना है।

स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट IV.18: औसत सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)

(कर्नल घनत्व अनुमान)

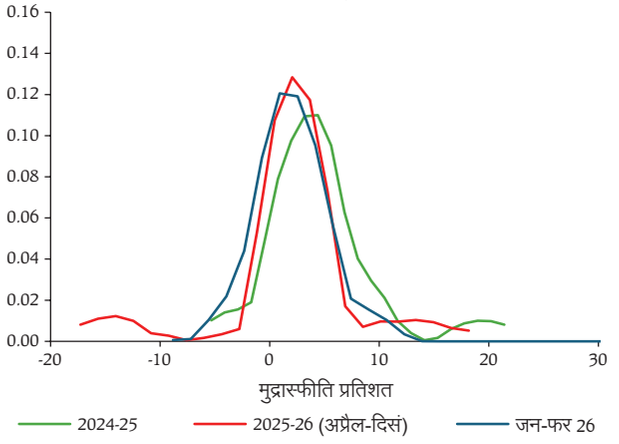

टिप्पणी: कर्नल घनत्व अनुमान (KDE) एक सांख्यिकीय तकनीक है जो प्रत्येक डेटा बिंदु पर केंद्रित स्थानीय कर्नल फ़ंक्शनों को जोड़कर डेटासेट से एक संभाव्यता घनत्व फ़ंक्शन (PDF) का एक सुचारु अनुमान तैयार करती है।

स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट IV.19: सीपीआई उप-समूह/समूह मुद्रास्फीति सीमा

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

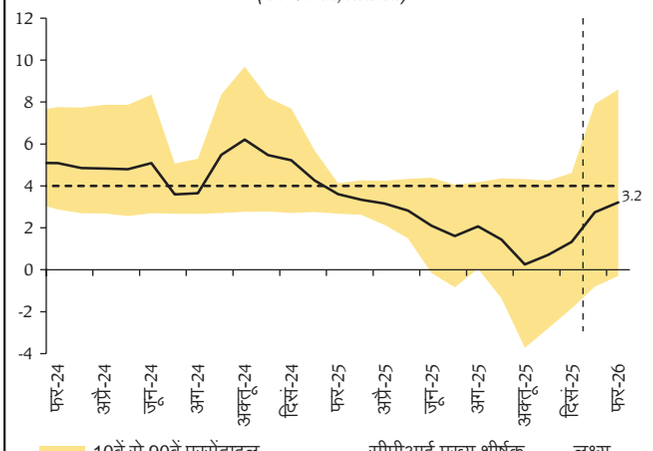

टिप्पणी: ऊर्ध्वाधर छिद्रित रेखा जनवरी 2026 के रिलीज़ के बाद पुरानी और वर्तमान CPI शृंखला के बीच अंतर को दर्शाती है, क्योंकि दोनों शृंखलाओं के बीच मुद्रास्फीति डेटा सख्ती से तुलनीय नहीं है।

स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

तालिका IV.2: अंतर्निहित मुद्रास्फीति के माप: ट्रिम्ड माध्य माप और भारित माध्य

(वर्ष दर वर्ष, प्रतिशत)

माह	5% ट्रिम्ड	10% ट्रिम्ड	25% ट्रिम्ड	भारित मीडियन
जन-25	4.1	3.7	3.4	2.9
फर-25	3.7	3.5	3.3	2.9
मार्च-25	3.6	3.4	3.2	2.9
अप्रै-25	3.3	3.4	3.3	3.0
मई-25	3.1	3.3	3.3	3.2
जून-25	2.8	3.1	3.1	3.1
जुला-25	2.7	3.0	3.1	3.0
अग-25	2.9	2.9	2.9	3.0
सितं-25	2.5	2.6	2.7	2.7
अक्तू-25	1.9	2.2	2.4	2.4
नवं-25	2.0	2.2	2.4	2.5
दिसं-25	1.8	1.9	2.1	2.1
जन-26	2.3	2.2	2.1	2.0
फर-26	2.5	2.4	2.1	2.0

टिप्पणियाँ: दिसंबर 2025 तक की मुद्रास्फीति की संख्याएँ पुरानी सीपीआई (2012=100) शृंखला पर आधारित हैं, जबकि जनवरी और फरवरी 2026 के लिए ये संख्याएँ नई CPI (2024=100) शृंखला पर आधारित हैं।
स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट IV.20: वस्तुओं और सेवाओं का योगदान

(प्रतिशत अंक)

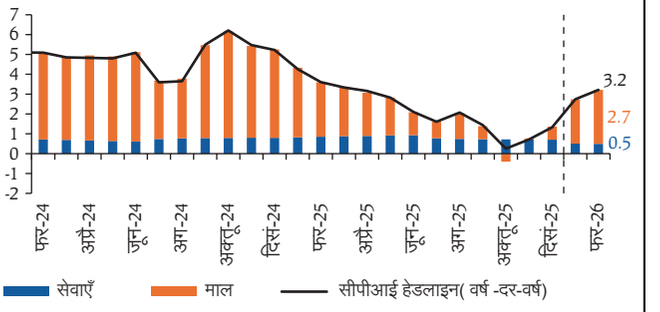

टिप्पणियाँ: 1. ऊर्ध्वाधर डैश वाली रेखा जनवरी 2026 के बाद पुराने और नए सीपीआई शृंखला के बीच ब्रेक को इंगित करती है, क्योंकि मुद्रास्फीति डेटा दोनों शृंखलाओं में पूर्णतः तुलनीय नहीं है।
2. हेडलाइन मुद्रास्फीति में वस्तुओं का भार पुराने सीपीआई (2012-100) शृंखला में 76.6 प्रतिशत से घटकर नए सीपीआई (2024-100) शृंखला में 72.0 प्रतिशत हो गया है। दूसरी ओर, सेवाओं का भार पुराने शृंखला में 23.4 प्रतिशत से बढ़कर नई शृंखला में 28.0 प्रतिशत हो गया है।
स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अधिक थी, जिसका मुख्य कारण मांस और मछली, फल और मेवे, तथा सब्जियाँ थीं।

मुद्रास्फीति में क्षेत्रीय प्रवृत्तियाँ

मार्च 2025 से सीपीआई 2012 शृंखला में ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी मुद्रास्फीति से कम रही है, क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट का ग्रामीण मुद्रास्फीति पर अधिक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इसका ग्रामीण उपभोग बास्केट में भार का हिस्सा अधिक है, जबकि कीमती धातु की बढ़ती कीमतों से शहरी मुद्रास्फीति असमान रूप से प्रभावित हुई है। इसके विपरीत, नई सीपीआई (2024 = 100) शृंखला में ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति अंतर काफी कम हो गया क्योंकि हेडलाइन और खाद्य मुद्रास्फीति के बीच विचलन कम हो गया। यह आंशिक रूप से नई सीपीआई शृंखला में ग्रामीण उपभोग बास्केट में खाद्य वस्तुओं के उच्च भार को भी दर्शाता है (चार्ट IV.21)।

अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान, अधिकांश भारतीय राज्यों ने निम्न मुद्रास्फीति ब्रैकेट में प्रवेश किया[31] - 0-2 प्रतिशत की सीमा में 18 और 2-4 प्रतिशत में 13, जो हेडलाइन मुद्रास्फीति में व्यापक आधार पर नरमी की ओर इशारा करता है (सारणी IV.3)। सीपीआई (2024=100) शृंखला में, जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान अधिकांश राज्यों में हेडलाइन मुद्रास्फीति 2-4 प्रतिशत की सीमा के भीतर रही।

IV.4 मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र के चालक

आयातित मुद्रास्फीति

2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में आयातित घटकों का योगदान मामूली रहा[32], जिसे ऊर्जा की सामान्य कीमतों से समर्थन मिला, भले ही कीमती धातुओं की वैश्विक कीमतें ऊँची रहीं (चार्ट IV.22)। खाद्य तेल की वैश्विक कीमतों में बहाली के साथ-साथ ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि तथा स्वर्ण और चांदी की

[31] 31 इस अवधि में दो राज्य, बिहार और मणिपुर, अपस्फीति में चले गए।

[32] 32 वर्ष 2025 के लिए आयातित मुद्रास्फीति का अनुमान सीपीआई शृंखला (आधार वर्ष 2012=100) के आधार पर लगाया गया है, जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्वर्ण, चांदी, रासायनिक उत्पाद, धातु उत्पाद, वस्त्र, अनाज, दुग्ध उत्पाद और सब्जियां जैसी वस्तुएं शामिल हैं (अंतरराष्ट्रीय कीमतों से होने वाले प्रभाव विस्तार के आधार पर समायोजित भार सीपीआई बास्केट में 8.4 प्रतिशत है)।

सारणी IV.3: राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में हेडलाइन मुद्रा-स्फीति का वितरण : राज्यों की संख्या[1]

हेडलाइन मुद्रा-स्फीति का दायरा (प्रतिशत)	2024-25 (अप्रैल-दिसंबर)[2]	2025-26 (अप्रैल-दिसंबर)[2]	2025-26 (जनवरी-फरवरी)[3]
Less than 0 (Deflation)	0	2	0
0 से 2.0 प्रतिशत के बीच	0	18	8
2.0 से 4.0 प्रतिशत के बीच	7	13	26
4.0 से 6.0 प्रतिशत के बीच	25	1	2
6.0 से अधिक	4	2	0

टिप्पणियाँ: 1. दमन और दीव का दादरा और नगर हवेली के साथ एकीकरण और लद्दाख के गठन को पुराने सीपीआई (2012 = 100) शृंखला में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लेखांकित किया गया।
2. अप्रैल-दिसंबर के लिए औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति के आंकड़े पुरानी सीपीआई (2012 = 100) शृंखला पर आधारित हैं।
3. 2025-26 (जनवरी-फरवरी) के लिए औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति के आंकड़े नई सीपीआई (2024=100) शृंखला पर आधारित हैं।

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

उच्च मुद्रास्फीति के कारण जनवरी-फरवरी 2026 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में आयातित घटकों का योगदान काफी अधिक रहा[33]।

लागत

औद्योगिक कच्चे माल और कृषि इनपुट में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) अपस्फीति द्वारा मापी गई इनपुट लागतें, 2025-26 की पहली तिमाही से फरवरी 2026 तक कम बनी रहीं,

चार्ट IV.22: आयातित मुद्रास्फीति का योगदान

(प्रतिशत अंक)

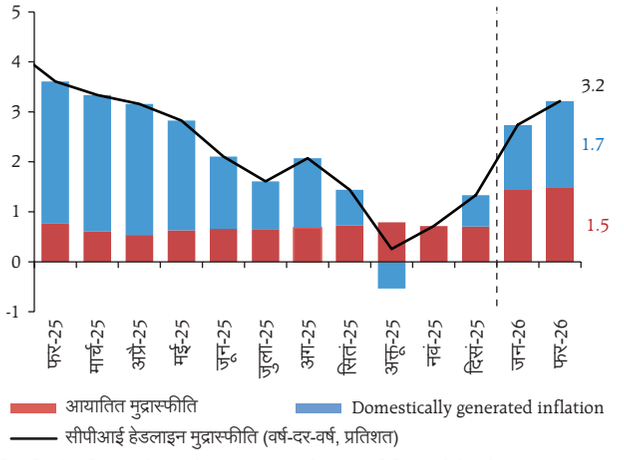

टिप्पणियाँ: चूंकि जनवरी-फरवरी-2026 से, आयातित मुद्रास्फीति नई सीपीआई (2024 = 100) पर आधारित है, ये आंकड़े सीपीआई (2012 = 100) पर आधारित 2025 के पहले के अनुमानों के साथ सीधे तुलनीय नहीं हैं, जैसा कि डैश वाली ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा दर्शाया गया है।
स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट IV.21: सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति: शहरी और ग्रामीण

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

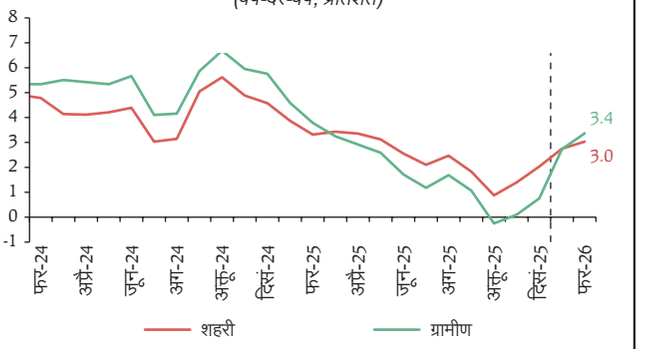

टिप्पणियाँ: 1. दिसंबर 2025 तक के मुद्रास्फीति पुरानी सीपीआई (2012 = 100) शृंखला पर आधारित है। जबकि जनवरी 26 और फरवरी 26 के मुद्रास्फीति आंकड़े नई सीपीआई (2024=100) शृंखला पर आधारित हैं जिसे ऊर्ध्वाधर डैश वाली रेखा से दर्शाया गया है।
2. डैश वाली ऊर्ध्वाधर रेखा पुरानी और वर्तमान सीपीआई शृंखला के बीच ब्रेक को इंगित करती है, क्योंकि मुद्रास्फीति डेटा दोनों शृंखलाओं में पूर्णतः तुलनीय नहीं है।

स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

जिसमें मुद्रास्फीति के दोनों घटक शामिल थे। इसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतों में नरमी आना था। 2025-26 की दूसरी तिमाही में, खनिज और गैर-खाद्य वस्तुओं के कारण औद्योगिक इनपुट मुद्रास्फीति के दायरे में आ गए। 2025-26 की तीसरी तिमाही में, हाई-स्पीड डीज़ल (एचएसडी और बिजली की कीमतों में गिरावट के कारण कृषि इनपुट में अपस्फीति और गहन हो गई, जबकि खनिज, गैर-खाद्य वस्तुओं और विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) में मुद्रास्फीति के कारण औद्योगिक इनपुट की कीमतें मज़बूत हुईं (चार्ट IV.23)।

मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधानों के परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव आया है और उर्वरक उत्पादन के लिए प्रमुख फीडस्टॉक की कमी हो गई है, जिससे संबद्ध औद्योगिक उत्पादन में प्रभाव-विस्तार बना रहा है। ओएमसी ने 20 मार्च 2026 को थोक खरीदारों (औद्योगिक उपयोग) के लिए डीजल की कीमतों में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि भी की है। वाणिज्यिक एलपीजी कीमतें दो हिस्सों में बढ़ी -पहले 115 रुपए प्रति सिलेन्डर तथा बाद में 195 रुपए प्रति सिलेन्डर। आगे चलकर, ये उच्च इनपुट लागत दबाव डाल सकते हैं।

[33] 33 जनवरी-फरवरी 2026 के लिए आयातित मुद्रास्फीति का अनुमान सीपीआई शृंखला (आधार वर्ष 2024=100) के आधार पर लगाया गया है जिसमें में पेट्रोलियम उत्पाद, स्वर्ण, चांदी, घरेलू सामान और उपकरण, कपड़े, टायर, टॉयलेटरीज़ और वनस्पति तेल जैसी वस्तुएं शामिल हैं (अंतरराष्ट्रीय कीमतों से होने वाले प्रभाव विस्तार के आधार पर समायोजित भार सीपीआई बास्केट में 9.9 प्रतिशत है)।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

चार्ट IV.23: कृषि तथा गैर-कृषि कार्य इनपुट लागत मुद्रास्फीति

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

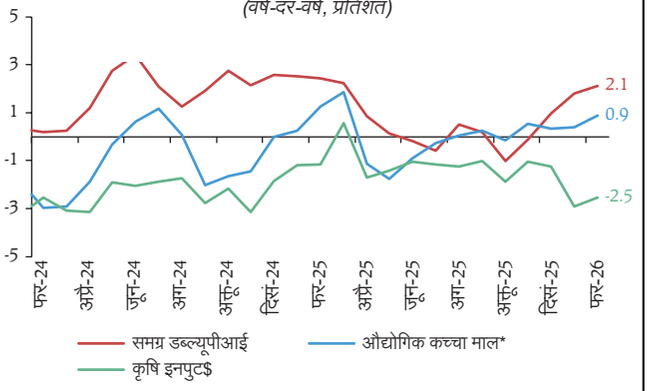

टिप्पणियाँ: *: इसमें डब्ल्यूपीआई से प्राथमिक गैर-खाद्य वस्तुएं, खनिज, कोयला, विमानन टर्बाइन ईंधन, हाई स्पीड डीजल, नैफ्था, बिटुमेन, भट्टी तेल, ल्यूब तेल, पेट्रोलियम कोक, बिजली, कपास यार्न और कागज और लुगदी शामिल हैं।

$: इसमें डब्ल्यूपीआई से उच्च गति डीजल, चारा, बिजली, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि एवं वानिकी मशीनरी शामिल हैं।

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

संगठित क्षेत्र में, 2025-26 की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान, विनिर्माण और सेवा, दोनों ही क्षेत्रों में कर्मचारियों की लागत में साल-दर-साल आधार पर तेज़ी आई (चार्ट IV.24)। नए श्रम कानूनों के लागू होने से कॉरपोरेट कर्मचारियों की लागत और लाभप्रदता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। शीर्ष 500 गैर-सरकारी, गैर-वित्तीय (NGNF)[34] सूचीबद्ध कंपनियों में से अधिकांश ने 2025-26 की तीसरी तिमाही के अपने वित्तीय परिणामों में, इन कानूनों के तहत अनिवार्य ग्रेच्युटी और अन्य सामाजिक दायित्वों के लिए एक 'असाधारण मद' के तौर पर प्रावधान[35] किए। परिणामस्वरूप , कर्मचारियों की लागत में वृद्धि (जिसमें असाधारण मदों के तहत रिपोर्ट किए गए प्रावधान भी शामिल हैं) साल-दर-साल आधार पर काफ़ी बढ़ गई, जबकि निवल लाभ कम हो गया। क्षेत्रवार देखें तो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने सबसे ज़्यादा प्रावधान किए हैं, जिनमें ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और इलेक्ट्रिकल मशीनरी क्षेत्र सबसे आगे रहे। सेवा क्षेत्र में, अगर श्रम संहिता के असर को हटा दें, तो आई टी कंपनियों का तीसरी तिमाही का निवल लाभ काफ़ी बढ़ा होता; वहीं, गैर-आई टी सेवा क्षेत्र में मार्जिन में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलता।

लागत स्थितियों के आकलन के संदर्भ में, क्रय प्रबन्धक सूचकांक (पीएमआई) के लिए सर्वेक्षण की गई विनिर्माण कंपनियों ने मार्च 2026 में निविष्टि कीमतों में भारी बढ़ोतरी की जानकारी दी (अगस्त 2022 के बाद से विस्तार की सबसे तेज़ दर), जिसका

चार्ट IV.24: विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में स्टाफ लागत

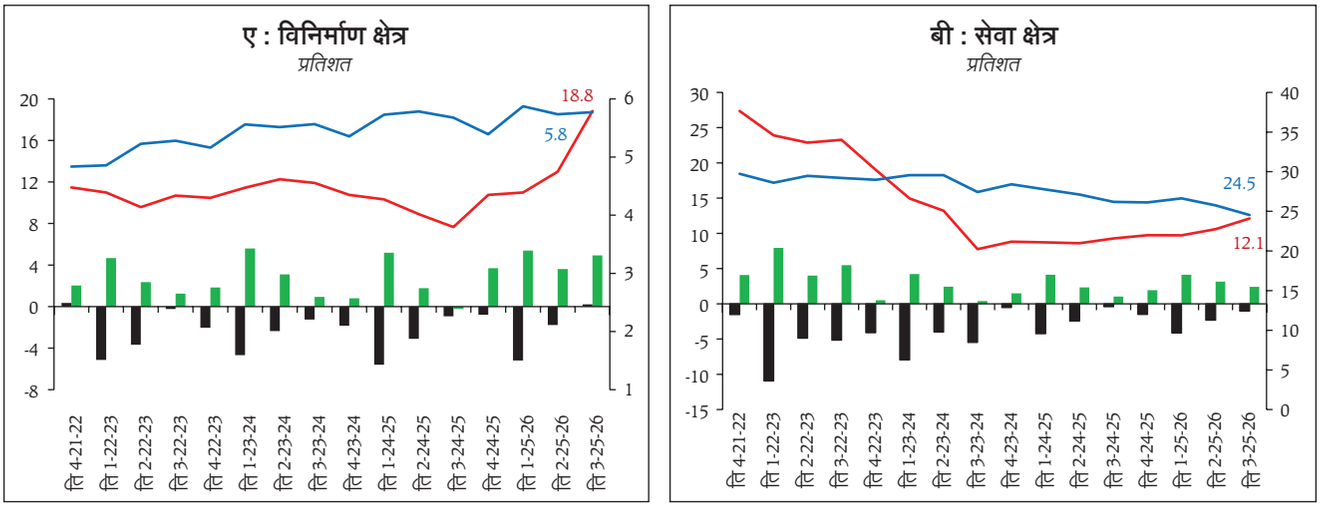

स्रोत: कैपिटलाइन डेटाबेस; और आरबीआई स्टाफ़ अनुमान।

[34] 2025-26 की तीसरी तिमाही के दौरान 3188 सूचीबद्ध एनजीएनएफ़ कंपनियों के कुल कर्मचारी खर्च में 89 प्रतिशत और कुल बिक्री में 80 प्रतिशत हिस्सा रहा।

[35] इन श्रम संहिताओं के महत्वपूर्ण प्रावधानों में गिग और संविदा कर्मचारियों सहित सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करना; मूल वेतन को कुल परिश्रमिक के कम से कम 50 प्रतिशत बढ़ाना; और ग्रेच्युटी की पात्रता अवधि को हटाकर एक वर्ष करना आदि शामिल हैं।

चार्ट IV.25: पीएमआई इनपुट-आउटपुट मूल्य अंतर

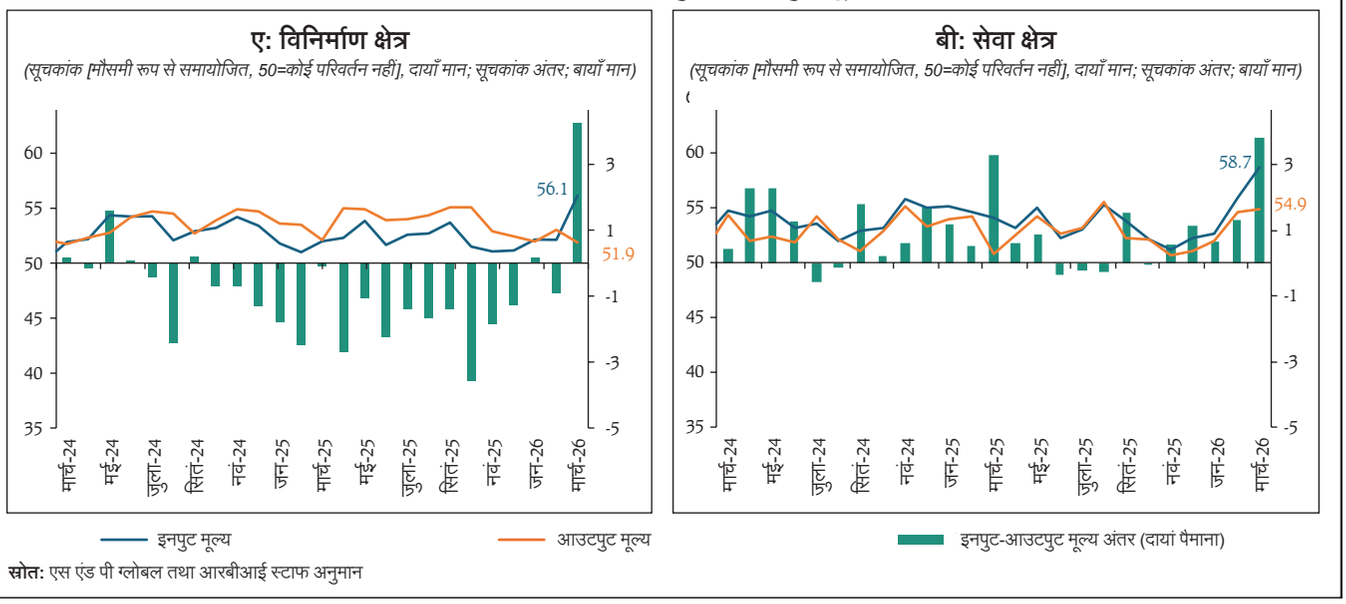

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान

कारण ईंधन, सामग्री और परिवहन पर बढ़ा हुआ खर्च था। मार्च 2026 के दौरान विनिर्माण कंपनियों के लिए उत्पादन कीमतों में केवल मामूली बढ़ोतरी हुई। यह फरवरी तक के पिछले रुझान के विपरीत है, जब कंपनियों द्वारा ली जाने वाली आउटपुट कीमतें इनपुट कीमतों से ज़्यादा थीं। सेवा क्षेत्र में भी, मार्च में इनपुट की कीमतें करीब चार वर्षों में सबसे तेज बढ़ीं। फरवरी तक फर्मों द्वारा ली जाने वाली कीमतें इनपुट की कीमतों के साथ-साथ बढ़ीं (चार्ट IV.25)

चार्ट IV.26: लागत और मूल्य स्थितियों संबंधी प्रत्याशाएं

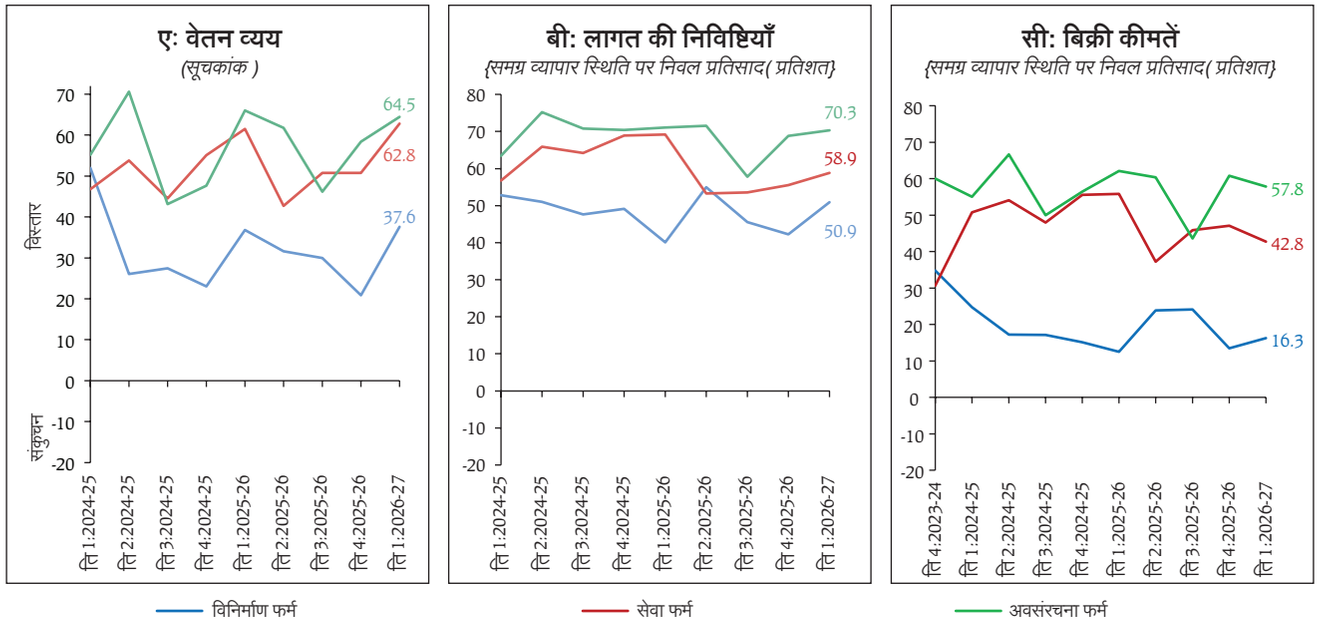

टिप्पणी : 'निवल प्रतिसाद' मूल्यों में वृद्धि बताने वाले और कमी बताने वाले उत्तरदाताओं के प्रतिशत के बीच का अंतर है।
स्रोत : रिजर्व बैंक का औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण; सेवा और आधारभूत संरचना परिदृश्य का सर्वेक्षण; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

लागत स्थितियों के आकलन और दृष्टिकोण पर, रिज़र्व बैंक के एंटरप्राइज सर्वे[36] में शामिल फर्मों के अनुसार, 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान सभी क्षेत्रों में वेतन खर्च और इनपुट लागत दोनों के दबाव बढ़ने की उम्मीद है। 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र में बिक्री कीमत के दवाव बढ़ने की उम्मीद है, जबकि अवसंरचना और सेवा दोनों ही फर्मों में इसके कम होने की उम्मीद है (चार्ट IV.26)।

मार्जिन

समग्र रूप से, खाद्य कीमत मार्जिन में उतार-चढ़ाव सीमाबद्ध रहा, और कुछ चुनिंदा चीज़ों की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई। अनाज की खुदरा मूल्य मार्जिन[37] में अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 के दौरान धीरे-धीरे बढ़ोतरी हुई, और फिर मार्च 2026 में इनमें कुछ नरमी देखी गयी। दलहन के मामले में, अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के दौरान कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। टीओपी (टमाटर,आलू, प्याज) सब्जियों की खुदरा कीमतों में भी अक्टूबर

चार्ट IV.27: खुदरा, थोक मूल्य और मार्जिन

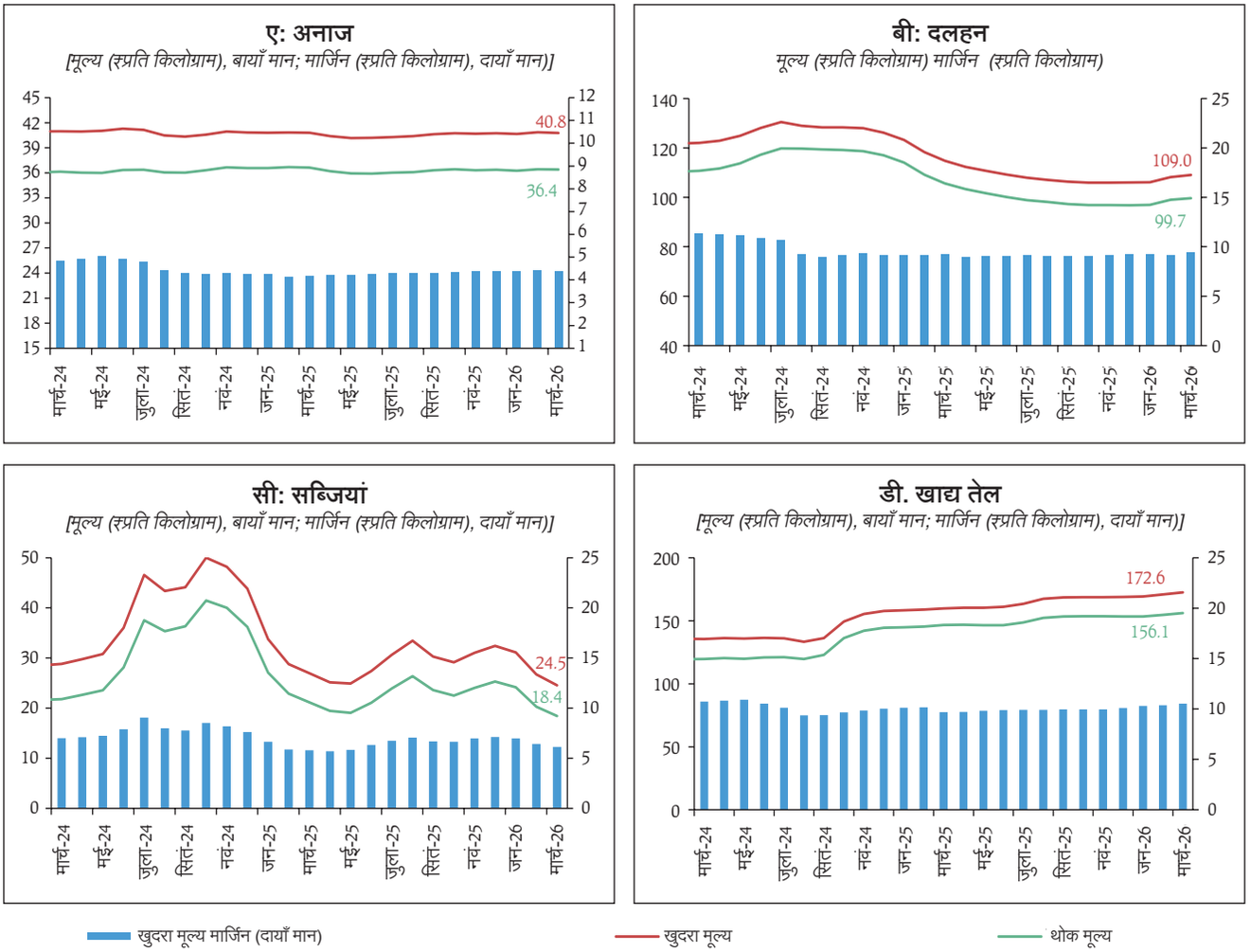

स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[36] औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण; तथा सेवाएं और आधारभूत संरचना परिदृश्य का सर्वेक्षण।

[37] उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए) से प्राप्त खुदरा और थोक कीमतों के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित 'पूर्ण खुदरा मूल्य मार्जिन' का विश्लेषण चार प्रमुख उप-समूहों के लिए किया गया। वस्तु-स्तर की खुदरा और थोक कीमतों को, वस्तु-स्तर के सीपीआई भारों का उपयोग करके, संबंधित उप-समूह में समेकित किया जाता है। फरवरी 2026 के लिए वस्तु-स्तर की खुदरा और थोक कीमतें, 23 फरवरी 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हैं।

चार्ट IV.28: सीपीआई मुद्रास्फीति का अपघट

(प्रतिशत अंक, बायाँमान,प्रतिशत ,दायाँ मान)

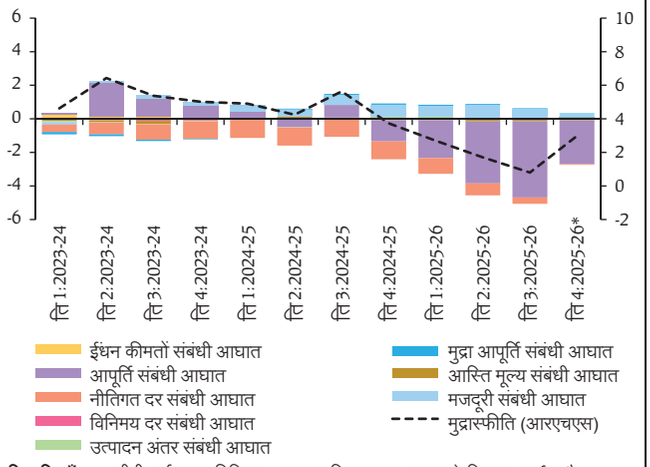

टिप्पणियाँ: 1. सीपीआई मुद्रास्फीति का अपघटन नियतात्मक रुझान से विचलन दर्शाता है।
2. *: 2025-26 की चौथी तिमाही नई सीपीआई शृंखला (2024=100) के आधार पर जनवरी और फरवरी 2026 का औसत है, जबकि तीसरी तिमाही तक का डेटा पुरानी सीपीआई शृंखला (2012=100) पर आधारित है।

स्रोत: एनएसओ; आरबीआई; पीपीएसी; बीएसई; श्रम ब्यूरो; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

से दिसंबर 2025 के दौरान कुछ सख्ती देखी गई, और उसके बाद मार्च 2026 तक इनमें गिरावट आई। खाद्य तेलों के मामले में, अक्टूबर 2025 से खुदरा कीमतों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखी गई, जिसकी वजह सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों और रिफाइंड तेलों की कीमतों में आई मजबूती थी (चार्ट IV.27)।

कुल मिलाकर, वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (वीएआर)[38] मॉडल का उपयोग करके मुद्रास्फीति का ऐतिहासिक विश्लेषण यह दर्शाता है कि 2025-26 के दौरान मुद्रास्फीति में जो नरमी देखी गई, उसका मुख्य कारण अनुकूल आपूर्ति आघात थे (चार्ट IV.28)।

IV.5 *निष्कर्ष*

2025-26 के दौरान फरवरी 2026 तक, हेडलाइन मुद्रास्फीति दर तय लक्ष्य से नीचे रही है। इसकी मुख्य वजह खाद्य वस्तुओं की कम कीमतें और सौम्य अंतर्निहित मुद्रास्फीति का काबू में रहना है। सोने की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से दबाव पड़ने के बावजूद, कोर मुद्रास्फीति दर काफी हद तक नियंत्रण में रही। आगे चलकर, जलाशयों में पानी के रिकॉर्ड स्तर की मदद से फ़सलों का उत्पादन बढ़ने से खाद्य मुद्रास्फीति पर काबू पाया जा सकता है। हालाँकि, कुछ जोखिम भी हैं; जैसे ग्रीष्मऋतु में तापमान का सामान्य से अधिक होना और अल नीनो की स्थिति का दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पर नकारात्मक असर पड़ना। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतों में हाल ही में आई तेज़ी, मुद्रास्फीति के प्रक्षेपमार्ग का एक बड़ा जोखिम पैदा करती है।

[38] ऐतिहासिक अपघटन नमूना अवधि (2010-11 की चौथी तिमाही से 2025-26 की चौथी तिमाही तक) के दौरान मुद्रास्फीति में होने वाले उतार-चढ़ावों में प्रत्येक आघात के योगदान का अनुमान लगाता है। यह अनुमान निम्नलिखित चरों (जिन्हें वेक्टर Yt के रूप में दर्शाया गया है) – कच्चे तेल की कीमतें (यूएस$ प्रति बैरल); विनिमय दर (भारतीय रुपया प्रति यूएस$); आस्ति मूल्य (बीएसई सेंसेक्स); सीपीआई; उत्पादन अंतराल; ग्रामीण मजदूरी; नीतिगत रेपो दर; और मुद्रा आपूर्ति (एम3) पर आधारित वीएआर मॉडल का उपयोग करके लगाया जाता है । नीतिगत रेपो दर के अलावा अन्य सभी चर वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दरें हैं। वीएआर को संक्षिप्त रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है: Yt = c + A Yt–1 + et; जहाँ et आघातों के एक वेक्टर को दर्शाता है। वोल्ड (Wold) अपघटन का उपयोग करते हुए, Yt को उसके नियतात्मक रुझान और सभी आघातों et के योग के एक फलन के रूप में दर्शाया जा सकता है।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

V. समष्टि-आर्थिक परिदृश्य

लगातार चल रहे भू-राजनीतिक तनावों, व्यापारिक टकरावों और अस्थिर वैश्विक वित्तीय स्थितियों के बीच, भारत की आर्थिक गतिविधियां सुदृढ़ बनी हुई हैं। घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है, जिसे स्थिर निजी उपभोग, लगातार निवेश और मजबूत समष्टि-आर्थिक आधार से समर्थन मिल रहा है, हालांकि, पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष गिरावट का जोखिम पैदा करता है। मुद्रास्फीति के धीरे-धीरे बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि आधार प्रभाव कम हो रहे हैं, और आपूर्ति शृंखला में रुकावटों के कारण निकट काल में उसका स्तर कुछ ऊपर रह सकता है, लेकिन मध्यम अवधि में यह सहन सीमा के भीतर ही रहेगा। जैसे-जैसे मौद्रिक नीति बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच आगे बढ़ रही है, वह विकास का समर्थन करते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है।

V.1 अक्टूबर 2025 एमपीआर से अब तक के प्रमुख घटनाक्रम

अक्टूबर 2025 में मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) जारी होने के बाद से, वैश्विक समष्टि-आर्थिक परिवेश, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनावों के काफी बढ़ने से और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है। पश्चिम एशिया में हालिया संघर्ष के बिना, वैश्विक विकास की संभावनाएं बेहतर होतीं, जिन्हें लगातार जारी अवस्फीति की गति, स्थिर मांग की स्थितियों, व्यापारिक रुकावटों में कमी, और डिजिटलीकरण तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को अपनाने से होने वाले दक्षता लाभों का समर्थन मिलता। हालांकि, जारी संघर्ष के परिणामी प्रभावों के कारण, जिनमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से शिपिंग में रुकावटें और क्षेत्रीय ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर को नुकसान शामिल हैं, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति सीमित हो गई है और ऊर्जा की कीमत में वृद्धि का दबाव पड़ा है। नतीजतन, निकट-अवधि का परिदृश्य बढ़ी हुई अनिश्चितता से घिरा हुआ है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ने का जोखिम और विकास घटने का जोखिम पैदा हो गया है। ओईसीडी ने अपने मार्च 2026 के इकोनॉमिक आउटलुक में अनुमान लगाया है कि वैश्विक विकास 2025 के 3.3 प्रतिशत से कम होकर 2026 में 2.9 प्रतिशत हो जाएगी।

अक्टूबर 2025 से, अलग-अलग अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के रुख अलग-अलग रहे हैं, जिसमें कुछ केंद्रीय बैंकों ने घटती मुद्रास्फीति के बीच ब्याज दरें कम की हैं, जबकि दूसरों ने घरेलू स्थितियों के आधार पर दरों को स्थिर रखा है या बढ़ाया है। वैश्विक इक्विटी बाज़ार काफी हद तक मजबूत रहे, जो मौजूदा समष्टि-आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी स्टॉक से प्रेरित थे, जबकि बॉण्ड प्रतिफल ऊंचे बने रहे। कमोडिटी बाज़ार अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़े : औद्योगिक धातुएं एक सीमित दायरे में रहीं, कृषि उत्पादों की कीमतें नरम हुईं, जबकि कच्चे तेल की कीमतें पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन प्लस (ओपेक+) द्वारा लिए गए नए निर्णयों और बदलते भू-राजनीतिक नज़रिए के कारण अस्थिर बनी रहीं।

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण शुरू में निवेशकों ने सुरक्षित निवेश की ओर रुख किया इस दौरान सोने और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के सॉवरेन बॉण्ड की कीमतों में तेजी आई, लेकिन बढ़ती मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं और मजबूत होते अमेरिकी डॉलर की वजह से बाद में इनमें कुछ गिरावट भी देखने को मिली। इक्विटी बाज़ारों ने अपनी पिछली बढ़त का एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया, जिसके चलते 2026 की पहली तिमाही में उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। वहीं, पूंजी बहिर्वाह के कारण प्रमुख विकसित और उभरती बाज़ार वाली अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय दर का दबाव बढ़ गया। मौद्रिक नीति प्रत्याशाओं ने नीतिगत बदलाव का संकेत दिया, जिसमें निवेशक यह मानकर चल रहे थे कि प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंक, पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। नतीजतन, वैश्विक वित्तीय बाज़ार अत्यधिक अस्थिर बने रहे।

कुल मिलाकर, वैश्विक परिदृश्य 2026 की शुरुआत में देखी गई स्थिर वृद्धि से हटकर, अब अधिक सतर्क और चौकस हो गया है। आगे चलकर, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की अवधि, तीव्रता और भौगोलिक विस्तार वैश्विक विकास, मुद्रास्फीति के रुझानों और वित्तीय स्थिरता को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कारक साबित होंगे।

इस पृष्ठभूमि में, भारत का समष्टि-आर्थिक परिदृश्य सुदृढ़ बना हुआ है, जिसे मजबूत घरेलू मांग और लगातार राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का समर्थन प्राप्त है। प्रमुख समष्टि-आर्थिक संकेतकों

की आधार अवधि में हाल ही में किए गए अपडेट्स ने सांख्यिकीय ढांचे को और अधिक सुदृढ़ किया है, जिससे समष्टि-आर्थिक मूल्यांकन में सुधार हुआ है। आधार वर्ष 2024=100 वाली नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) शृंखला 12 फरवरी 2026 को जारी की गई थी। इसमें उपभोग के अद्यतन पैटर्न और व्यय के संशोधित भार को शामिल किया गया है, जो मौजूदा मूल्य गतिकी को बेहतर ढंग से दर्शाता है। इसके बाद, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 27 फरवरी 2026 को आधार वर्ष 2022–23 के साथ संशोधित राष्ट्रीय लेखा शृंखला जारी की। इसमें बेहतर डेटा स्रोतों, विस्तारित क्षेत्रीय कवरेज और विकसित हो रही आर्थिक संरचनाओं के अनुरूप कार्यप्रणाली में किए गए सुधारों को एकीकृत किया गया है। इन परिवर्तनों ने नीतिगत उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले मुद्रास्फीति और विकास के आंकड़ों की प्रतिनिधित्व क्षमता, तुलनीयता और विश्लेषणात्मक सुसंगतता को बढ़ाया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों (एसएई) के अनुसार, 2025–26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.6 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि पिछले वर्ष यह 7.1 प्रतिशत थी। इस वृद्धि को मजबूत निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) और सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में लगातार विस्तार से समर्थन मिला। आपूर्ति पक्ष पर, वास्तविक योजित सकल मूल्य (जीवीए) में 7.7 प्रतिशत का विस्तार हुआ, जिसका मुख्य कारण सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि थी, वहीं कृषि और संबद्ध गतिविधियों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई।

हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति, जो 2025-26 के अधिकांश समय तक कम बनी रही थी, जनवरी 2026 के 2.7 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2026 में 3.2 प्रतिशत हो गई, जो प्रतिकूल आधार प्रभावों और कीमतों में कुछ सकारात्मक गति के मेल को दर्शाता है। खाद्य मुद्रास्फीति, जो पिछली शृंखला के तहत 2025 के अंत में कम रही थी और यहां तक कि ऋणात्मक भी हो गई थी, जनवरी के 2.1 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी में 3.4 प्रतिशत हो गई और इस प्रकार हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि में योगदान दिया। कोर मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य पदार्थ, परिवार और परिवहन ईंधन शामिल नहीं हैं (विवरण के लिए, बॉक्स IV.2 देखें), 3.7 प्रतिशत पर स्थिर रही, जो दर्शाता है कि कीमतों पर अंतर्निहित दबाव नियंत्रित थे, भले ही मूल्यवान धातुओं की कीमतें कुछ बढ़ी हों, साथ ही सोने और चांदी को छोड़कर कोर मुद्रास्फीति फरवरी 2026 में 2.1 प्रतिशत पर कम बनी रही। ईंधन मुद्रास्फीति भी कम बनी रही।

इस मोटे तौर पर मजबूत पृष्ठभूमि के बावजूद, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के परिणामी प्रभाव से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई तरीकों से प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऊर्जा की ऊंची और अस्थिर कीमतें, आयात बिल में बढ़ोतरी के जरिए, चालू खाता घाटे पर असर डाल सकती हैं और आयातित मुद्रास्फीति का दबाव डाल सकती हैं, जिसमें संभावित दूसरे दौर के प्रभाव भी शामिल हैं। बढ़ती अनिश्चितता, जोखिम से बचने की बढ़ती प्रवृत्ति और सुरक्षित निवेश की मांग के कारण पूंजी का बहिर्वाह हो सकता है, जिससे विनिमय दर पर लगातार गिरावट का दबाव पड़ सकता है। भारत के निर्यात में आयात की उच्च हिस्सेदारी को देखते हुए, इनपुट की ऊंची कीमतें और मुद्रा की गिरती कीमत मिलकर निर्यात के उत्पादन की लागत बढ़ा सकती हैं। यदि यह बढ़ी हुई लागत अंतिम उत्पाद की कीमतों में जोड़ दी जाती है, तो यह टर्म्स ऑफ़ ट्रेड के लिए एक झटके के रूप में काम कर सकती है। वैश्विक आर्थिक विकास की कमजोर संभावनाओं से बाहरी मांग कम हो सकती है और धन-प्रेषण का प्रवाह घट सकता है। इसके अलावा, ऊर्जा बाज़ारों और उर्वरकों में आने वाली बाधाएं उद्योग और कृषि के उत्पादन पर असर डाल सकती हैं, जिससे घरेलू मांग कम हो सकती है। अंत में, वैश्विक वित्तीय बाज़ारों से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के कारण घरेलू वित्तीय स्थितियां तंग हो सकती हैं और उधार लेने की लागत बढ़ सकती है। कुल मिलाकर, जो स्थिति ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स में रुकावटों के कारण आपूर्ति में आघात के रूप में शुरू होती है, उसमें मध्यम अवधि में मांग में कमी में बदलने की क्षमता है, बशर्ते यह संघर्ष लंबा खिंच जाए और आपूर्ति शृंखला की बहाली में देरी हो।

2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान, मौद्रिक नीति समिति ने दिसंबर 2025 में नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की, जो 2024-25 की चौथी तिमाही और 2025-26 की पहली छमाही के दौरान की गई कुल 100 आधार अंकों की कटौती के अतिरिक्त थी, जिसे बदलते मुद्रास्फीति और विकास के परिदृश्य को देखते हुए किया गया था। सितंबर-नवंबर 2025 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 100 आधार अंकों की चरणबद्ध कटौती ने प्रणालीगत चलनिधि को सहारा दिया था। एमपीसी ने भविष्य की

मौद्रिक नीति वक्तव्य

नीतिगत कार्रवाइयों को निर्धारित करते समय, डेटा पर आधारित रहने और बदलती समष्टि-आर्थिक स्थितियों के प्रति सतर्क रहने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। ।

मौद्रिक नीति समिति की बैठकें : अक्टूबर 2025 - मार्च 2026

अक्टूबर 2025

जब अक्टूबर 2025 में एमपीसी की बैठक हुई, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था उम्मीद से कहीं ज्यादा सुदृढ़ नज़र आई, हालांकि नीतिगत अनिश्चितताओं के कारण परिदृश्य अभी भी धुंधली बनी हुई थी। कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई लक्ष्य से ऊपर बनी रही, जिससे केंद्रीय बैंकों के लिए विकास और मुद्रास्फीति के बीच बदलते संतुलन को साधने में चुनौतियां खड़ी हो गईं। घरेलू स्तर पर, 2025-26[1] की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही, जिसका मुख्य कारण निजी उपभोग और निवेश था। सामान्य से बेहतर मॉनसून, खरीफ की बुवाई में स्थिरता और जलाशयों में पानी का पर्याप्त स्तर होने से कृषि और ग्रामीण मांग की संभावनाएं बेहतर हुई हैं।

सेवाओं से जुड़ी मजबूत गतिविधियों और रोजगार में स्थिरता ने मांग को सहारा दिया, और जीएसटी को तर्कसंगत बनाने से इसे और गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में अस्थिरता से विकास के लिए गिरावट के जोखिम पैदा होते हैं। तदनुसार, 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई भारी गिरावट के कारण नियंत्रण में रही, और जीएसटी को तर्कसंगत बनाने तथा खाद्य पदार्थों की कीमतों के स्थिर रहने के कारण, पूरे वर्ष के लिए इसके पहले के अनुमानों की तुलना में और भी कम रहने की उम्मीद है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 2.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। एमपीसी ने यह पाया कि जहां एक ओर समष्टि-आर्थिक स्थितियां और परिदृश्य विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों के लिए गुंजाइश बनाते हैं, वहीं नीतिगत दरों में बदलाव करने से पहले, शुरुआती दौर में की गई मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाइयों और जीएसटी दरों में किए गए समायोजनों के प्रभावों के सामने आने का इंतज़ार करना तथा व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं के घटनाक्रम पर अधिक स्पष्टता प्राप्त करना ही समझदारी होगी। परिणामस्वरूप, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 5.50 प्रतिशत पर ही अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। एमपीसी ने अपना तटस्थ रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया, हालांकि दो सदस्य नरम रुख अपनाने के पक्ष में थे।

दिसंबर 2025

दिसंबर 2025 में, वैश्विक विकास अपेक्षाकृत मजबूत बना रहा, हालांकि बदलते भू-राजनीतिक और व्यापारिक समीकरणों ने परिदृश्य को अनिश्चित बनाए रखा। घरेलू वास्तविक जीडीपी वृद्धि, जो पहले की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा रही, 2025-26 की दूसरी तिमाही (आधार वर्ष: 2011-12) में छह तिमाहियों के उच्चतम स्तर अर्थात, 8.2 प्रतिशत पर पहुंच गई, जिसका मुख्य कारण मजबूत घरेलू मांग था। आगे चलकर, अनुकूल घरेलू परिस्थितियां, जिनमें कृषि की अच्छी संभावनाएं, जीएसटी को तर्कसंगत बनाने से मिलने वाला लगातार प्रोत्साहन और नियंत्रित मुद्रास्फीति शामिल हैं, आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने में सहायक होने की उम्मीद थी। तदनुसार, 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि के अनुमान में संशोधन करते हुए उसे बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया गया। अक्टूबर 2025 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई, जो उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से गिरी, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में और अधिक कमी आना था। खाद्य आपूर्ति की बेहतर संभावनाएं, जिन्हें खरीफ की अधिक पैदावार और रबी की अच्छी बुवाई से बल मिला, मुद्रास्फीति को पहले के अनुमानों की तुलना में कम स्तर पर बनाए रखने में सहायक होने की उम्मीद थी। इन सभी कारकों को देखते हुए, 2025-26 के लिए सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति के अनुमान में संशोधन करते हुए उसे घटाकर 2.0 प्रतिशत कर दिया गया। यहां तक कि कोर मुद्रास्फीति भी, जो 2024-25 की पहली तिमाही से लगातार बढ़ रही थी, 2025-26 की दूसरी तिमाही में थोड़ी कम हुई और उम्मीद थी कि आने वाले समय में यह स्थिर बनी रहेगी। मुद्रास्फीति के परिदृश्य से नीति में अत्यधिक गुंजाइश के पैदा होने से एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक घटाकर 5.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। समिति ने तटस्थ रुख को जारी रखने का भी निर्णय लिया, सिवाय एक सदस्य के, जिन्होंने नरम रुख अपनाने का सुझाव दिया था।

फरवरी 2026

फरवरी की बैठक से पहले, यह उम्मीद थी कि 2026 में वैश्विक विकास मजबूत होगा, जिसे प्रौद्योगिकी में निवेश और

[1] एनएसओ के पिछली शृंखला (आधार वर्ष: 2011-12) के वास्तविक जीडीपी वृद्धि के अनुमानों के अनुसार, जो उस समय उपलब्ध थे।

अनुकूल वित्तीय स्थितियों से बढ़ावा मिलेगा। अलग-अलग क्षेत्रों में मुद्रास्फीति का स्तर एक जैसा नहीं रहा और अधिकांश प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में यह लक्ष्य से ऊपर बनी रही। घरेलू स्तर पर, 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान था, जिसे निजी उपभोग और स्थिर निवेश से समर्थन मिला। कृषि की बेहतर स्थिति और ग्रामीण श्रम बाज़ार की मजबूत स्थितियों से इस वृद्धि को और बल मिलने की उम्मीद थी। इसके अलावा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार समझौतों में हुई प्रगति ने बाहरी क्षेत्र के परिदृश्य को काफी हद तक बेहतर बनाया। तदनुसार, 2026-27 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्रमशः 6.9 और 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। नवंबर और दिसंबर में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति, अक्टूबर के 0.3 प्रतिशत के ऐतिहासिक निचले स्तर से थोड़ी बढ़ी, लेकिन यह निचली सहन-सीमा से नीचे ही रही। 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति में संशोधन करते हुए उसे थोड़ा बढ़ाकर 2.1 प्रतिशत कर दिया गया, जो मूल्यवान धातुओं की कीमतों में हुई वृद्धि को दर्शाता है। एमपीसी ने यह पाया कि व्यापार सौदों/समझौतों (यूरोपीय संघ, न्यूज़ीलैंड, ओमान के साथ, और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार सौदे की घोषणा) का सफल समापन समग्र परिदृश्य के लिए शुभ संकेत है। इसके मद्देनज़र, एमपीसी ने नीतिगत दर को उचित माना और सर्वसम्मति से इसे 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के पक्ष में मतदान किया। समिति ने तटस्थ रुख भी जारी रखा, हालांकि एक सदस्य नरम रुख अपनाने के पक्ष में थे।

25 मार्च 2026 को भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के परामर्श से, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए मुद्रास्फीति के लक्ष्य को +/-2 प्रतिशत की सहन-सीमा के साथ 4 प्रतिशत पर बनाए रखने की अधिसूचना जारी की। यह निर्णय, जो 21 अगस्त 2025 को जारी मौद्रिक नीति ढांचे पर चर्चा पत्र पर प्राप्त प्रतिक्रिया के भी अनुरूप है, अस्थिर वैश्विक परिवेश के बीच निरंतरता को दर्शाता है और और विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है। 4 प्रतिशत का लक्ष्य, समष्टि-आर्थिक स्थिरता के अनुरूप एक उचित स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सहन-सीमा अस्थायी झटकों को समायोजित करने के लिए लचीलापन प्रदान करती है, जिससे बार-बार नीतिगत समायोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

वैश्विक स्तर पर, अलग-अलग क्षेत्रों में मुद्रास्फीति के नतीजों में अंतर आने और प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एईज़) में इसके लक्ष्य से ऊपर बने रहने के कारण, केंद्रीय बैंकों को कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ा। कुछ अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी ढील देने के सिलसिले को धीमा कर दिया या रोक दिया, और कुछ ने मुद्रास्फीति के ऊंचे अनुमानों के जवाब में ब्याज दरें बढ़ा दीं। एईज़ में, जापान ने कई बार विराम लेने के बाद अपनी नीतिगत दर बढ़ाई, वहीं, ईएमईज़ में, कोलंबिया ने इस कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से ही अपनी नीतिगत दर में बढ़ोतरी कर दी (सारणी V.1)। नीतिगत प्रतिक्रियाओं में यह विविधता, मौजूदा नरमी के दौर में बढ़ी हुई अनिश्चितता के बीच, मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया कार्यप्रणालियों में आए एक बुनियादी बदलाव को दर्शाती है (बॉक्स V.1)।

सारणी V.1 मौद्रिक नीति समितियां और नीति दर मतदान स्वरूप

देश	नीतिगत बैठकें : अक्टूबर 2025 – मार्च 2026			
	कुल बैठकें	पूर्ण सहमति वाली बैठकें	बगैर पूर्ण सहमति की बैठकें	नीतिगत दर में बदलाव (आधार अंक)
ब्राजील	4	4	0	-25
चिली	4	4	0	-25
कोलंबिया	4	0	4	200
चेक गणराज्य	4	4	0	0
हंगरी*	6	5	0	-25
भारत	3	3	0	-25
जापान	4	1	3	25
दक्षिण अफ्रीका	3	2	1	-25
स्वीडन	4	4	0	0
थाईलैंड	3	1	2	-50
यूके	4	1	3	-25
यूएस	4	0	4	-50

टिप्पणी : 1. माइनस चिह्न नीतिगत दर में कटौती को दर्शाता है।
2. *: कुल छह बैठकें हुईं। हालांकि, पिछली बैठक (24 मार्च 2026) का कार्यवृत्त अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है।

स्रोत : केंद्रीय बैंक की वेबसाइटें।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

बॉक्स V.1: क्या नरमी के मौजूदा दौर में मौद्रिक नीति का व्यवहार भिन्न है? एक अंतर-देशीय विश्लेषण

मौजूदा वैश्विक मौद्रिक नरमी का दौर, जो 2024 में शुरू हुआ, 2013 के बाद के दौर से अलग है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने और आपूर्ति को लगातार आघात पहुंचने के बीच, मौद्रिक नीति के प्रतिक्रिया देने के तरीकों में बदलाव आया है। मौजूदा दौर में, मुद्रास्फीति भले ही कुछ कम हो रही हो, लेकिन कई अर्थव्यवस्थाओं में यह अभी भी लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है; फिर भी, इस उम्मीद में नीति में ढील देना शुरू कर दिया गया है कि मध्यम अवधि में मुद्रास्फीति घटकर लक्ष्य के स्तर पर आ जाएगी। जोखिम प्रबंधन का यह भविष्योन्मुखी नज़रिया आर्थिक विकास और रोजगार को प्राथमिकता देता है। इसके तहत, मौजूदा मुद्रास्फीति में विचलन के लिए कम सख़्त रुख अपनाया जाता है ताकि आउटपुट में होने वाले नुकसान से बचा जा सके।

नीतिगत दरों की संवेदनशीलता का पता लगाने के उद्देश्य से कि वे मुद्रास्फीति के अपने लक्षित स्तरों से विचलन के प्रति कितनी संवेदनशील हैं और क्लैरिडा और अन्य (2000)[2] की कार्यप्रणाली का अनुसरण करते हुए, हालिया 2024-25 के नरमी के दौर की तुलना 2013 से चली आ रही एक लंबी अवधि से की गई है, ताकि यह जांचा जा सके कि क्या मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाने वाले देशों के लिए टेलर नियम मौजूदा आर्थिक झटकों के बावजूद बदल गया है। पूरे सैम्पल अवधि (2013–2025) के दौरान भविष्योन्मुखी टेलर नियम के अनुमान एक मजबूत मुद्रास्फीति प्रतिक्रिया (1.6) और एक सार्थक उत्पादन स्थिरीकरण गुणांक (0.6) को दर्शाते हैं। ये परिणाम काफी हद तक मूल टेलर नियम से मेल खाते हैं, जिसके अनुसार सांकेतिक ब्याज दर को मुद्रास्फीति के प्रति 1.5 के गुणांक के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जब मुद्रास्फीति अपने लक्ष्य से अधिक हो जाए तो वास्तविक दर में वृद्धि हो, साथ ही, 0.5 के उत्पादन गुणांक के साथ विकास की स्थितियों के प्रति संवेदनशीलता भी बनी रहे। हालांकि, 2024–25 के नरमी के दौर में किए गए पुनर्मूल्यांकन से एक भिन्न नीतिगत बर्ताव सामने आता है, जिसके अनुसार मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशीलता घटकर 1.2 रह जाती है और उत्पादन गुणांक में भी मामूली कमी आती है (चार्ट V.1.1)। यद्यपि ये दोनों गुणांक, साहित्य में उपलब्ध टेलर नियम के अनुमानों के साथ मोटे तौर पर सुसंगत बने रहते हैं, फिर भी प्रतिक्रिया की तीव्रता कुछ नरम पड़ी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि मौजूदा नरमी के दौर में, केंद्रीय बैंक कोर मैक्रो वेरिअबल्स पर अपेक्षाकृत कम जोर दे रहे हैं। दोनों ही विशिष्टताओं में ब्याज दर को समतल करने का पैरामीटर उच्च बना रहता है (ρ = 0.8 से 0.9), जो इस बात को रेखांकित करता है कि केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों को समायोजित करते समय एक सतर्क किंतु क्रमिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, ताकि नीतिगत पूर्वानुमान की सुनिश्चितता बनी रहे।

चार्ट I. टेलर नियम गुणांक प्लॉट्स

(मान)

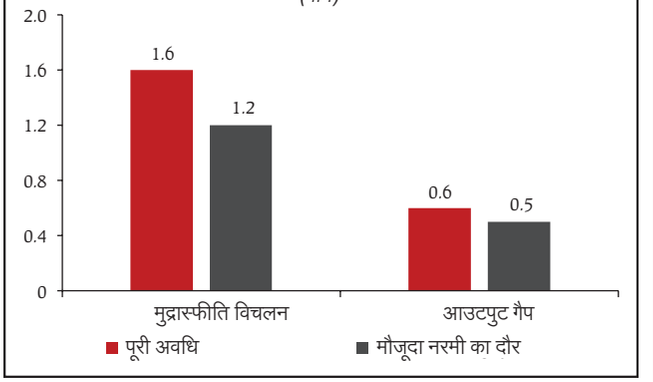

यह बदलाव इस बात का संकेत है कि बढ़ती अनिश्चितता और महामारी के बाद प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर भारी कर्ज़ के स्तर के बीच, मौद्रिक अधिकारी पारंपरिक मुद्रास्फीति-उत्पादन अंतर के तालमेल से परे, कुछ व्यापक संकेतकों पर विचार कर रहे हैं। वे इन अनिश्चित समयों में अधिक सतर्क और कम प्रतिक्रियाशील होकर नीतिगत दांव-पेच की गुंजाइश को सुरक्षित रख रहे हैं, नतीजतन वे 'अवस्फीति का अंतिम चर स्थिरता के साथ तय कर रहे हैं' (बीआईएस, 2024)। यह नपा-तुला दृष्टिकोण लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचों के अनुरूप है, जो मध्यम-अवधि की स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं जब प्रत्याशाएं स्थिर बनी रहती हैं (हॉफमैन और अन्य, 2024)।

संदर्भ :

बीआईएस (2024) । वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट।

क्लेरिडा, आर., गैली, जे., एंड गर्टलर, एम. (2000). मौद्रिक नीति के नियम और समष्टि-आर्थिक स्थिरता: प्रमाण और कुछ सिद्धांत। द *क्वॉर्टर्ली जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स*, 115(1), 147–180.

हॉफमैन, बी., मानेआ, सी., एंड मोजोन, बी. (2024). लक्षित टेलर नियम : मांग- और आपूर्ति-जनित मुद्रास्फीति के प्रति मौद्रिक नीति की प्रतिक्रियाएं। *बीआईएस क्वॉर्टर्ली रिव्यू, दिसंबर।*

[2] 2013 की पहली तिमाही से 2025 की तीसरी तिमाही तक की अवधि के लिए, मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाने वाले 16 देशों के एक क्रॉस-कंट्री पैनल के लिए, निम्नलिखित भविष्योन्मुखी टेलर-नियम समीकरण का अनुमान लगाया गया है :

$$i_{i,t} = \alpha + \rho i_{i,t-1} + \beta_{\pi} \text{InfDev}_{i,t+1} + \beta_{y} \text{Output Gap}_{i,t} + u_{i,t}$$

यहाँ $i_{i,t}$ सांकेतिक नीतिगत ब्याज दर है, α एक स्थिरांक है, ρ नीतिगत जड़ता है, β_{π} मुद्रास्फीति प्रतिक्रिया गुणांक है, $\text{InfDev}_{i,t+1}$ भविष्योन्मुखी मुद्रास्फीति विचलन है, β_{y} उत्पादन स्थिरीकरण गुणांक है, $\text{Output Gap}_{i,t}$ उत्पादन अंतराल है, और $u_{i,t}$ त्रुटि पद है।

चूंकि अपेक्षित भावी मुद्रास्फीति और उत्पादन अंतराल प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने योग्य नहीं हैं, इसलिए इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स के साथ टू-स्टेज जीएमएम अनुमान विधि का उपयोग किया जाता है। इन इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स में नीतिगत दर के लैग्स में लक्ष्य से एक तिमाही आगे का मुद्रास्फीति विचलन, उत्पादन अंतराल, कमोडिटी मूल्य मुद्रास्फीति, और यील्ड स्प्रेड्स शामिल हैं, साथ ही, दोनों रिग्रेशन विशिष्टताओं में अनिश्चितता को भी नियंत्रित किया जाता है। मुद्रास्फीति विचलन और उत्पादन अंतराल के दीर्घकालिक गुणांकों का निर्माण अनुमानित अल्पकालिक गुणांकों से किया जाता है, जिसके लिए संबंधित गुणांकों को $(1 - \rho)$ से विभाजित किया जाता है, यहां ρ एक स्मूथिंग पैरामीटर है।

भारत की अनुकूल वृद्धि-मुद्रास्फीति गतिशीलता को दर्शाते हुए, एमपीसी के मतदान स्वरूप में पिछली तीन नीतियों के दौरान पूर्ण एकमतता देखने को मिली, जो कुछ प्रमुख एईज़ के बिलकुल विपरीत है, जहां मतदान स्वरूप, मुख्य रूप से विभिन्न आर्थिक संकेतकों से मिले-जुले संकेतों के आधार पर, अलग-अलग सदस्यों के आकलन, अपेक्षाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं में मौजूद विविधता को दर्शाता है।

समष्टि-आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित करने वाले कारक

2025-26 की चौथी तिमाही के अंत में पश्चिम एशिया में संघर्ष छिड़ने से आपूर्ति में भारी रुकावटें आई हैं और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा की कीमतों में तेजी आई है। अगर इस संघर्ष का भौगोलिक दायरा धीरे-धीरे बढ़ता रहा और इसकी तीव्रता और अवधि बनी रही, तो इससे न केवल भारत की, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी विकास घटने का जोखिम और मुद्रास्फीति बढ़ने का जोखिम पैदा हो जाएगा। ऐसे माहौल में, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रण में रखने और विकास को बढ़ावा देने के बीच नीतिगत संतुलन बनाना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह इस आकलन पर निर्भर करता है कि यह आघात स्थायी है या अस्थायी। हालांकि, आपूर्ति शृंखला में आई रुकावट के निकट-काल के असर को, समय के साथ तैयार किए गए घरेलू बफर से संभाला जा सकता है, लेकिन अगर यह रुकावट लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा।

अध्याय III और IV में 2025-26 की दूसरी छमाही (अक्टूबर 2025-मार्च 2026) के दौरान आर्थिक गतिविधि और मुद्रास्फीति से संबंधित घरेलू समष्टि-आर्थिक घटनाक्रमों का विश्लेषण किया गया है। आगे चलकर, परिदृश्य कुछ आधारभूत अनुमान पर आधारित है।

सबसे पहले, कच्चे तेल की कीमत के लिए आधारभूत अनुमान को 2026-27 के लिए 85 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल और 2027-28 के लिए 75 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रखा गया है, जो औसत ब्रेंट फ्यूचर कीमतों के अनुरूप है (सारणी V.2 और चार्ट V.1ए)। अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 के दौरान अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का रुख देखा गया, और ये घटकर लगभग 63 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक आ गईं, जिसकी वजह ओपेक+ की वे घोषणाएं थीं जिनसे वैश्विक तेल बाज़ार में आपूर्ति बढ़ गई थी। मार्च 2026 में यह रुख तेजी से बदल गया, और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण कीमतें नवंबर 2022 के बाद पहली बार 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गईं। 2025-26 की दूसरी तिमाही से कच्चे तेल के भंडार में जो बढ़ोतरी हुई थी, जो आपूर्ति की अनुकूल स्थितियों को दर्शाती थी, वह अब उलट गई है। परिचालन और शिपिंग संबंधी बाधाओं के कारण उत्पादन में काफी रुकावटें आई हैं, जिससे आपूर्ति की स्थिति तंग हो गई है, वहीं, रिकॉर्ड स्तर पर भंडार निकाले जाने के कारण इन्वेंट्री बफ़र्स पर भी भारी दबाव पड़ा है, और उम्मीद है कि 2026 तक यह दबाव बना रहेगा।

दूसरा, भारतीय रुपये (₹) की सांकेतिक विनिमय दर अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के दौरान ₹87-92 प्रति अमेरिकी डॉलर की सीमा में थी। अक्टूबर 2025 से लेकर नवंबर के पहले पखवाड़े तक, रुपया स्थिर रहा और लगभग ₹88 प्रति अमेरिकी डॉलर के आसपास कारोबार करता रहा (चार्ट V.1बी)। नवंबर के अंत में,

सारणी V.2 : अनुमान हेतु आधारभूत धारणाएं

संकेतक	एमपीआर अक्टूबर 2025	एमपीआर अप्रैल 2026
कच्चा तेल	छ2:2025-26 के दौरान यूएस$ 70 प्रति बैरल	2026-27 के दौरान यूएस$ 85 प्रति बैरल और 2027-28 के दौरान यूएस$ 75 प्रति बैरल
विनिमय दर	छ2:2025-26 के दौरान ₹88/यूएस$	2026-27 के दौरान ₹94/ यूएस$
मॉनसून	2026-27 के लिए सामान्य	2026-27 और 2027-28 के लिए सामान्य
वैश्विक वृद्धि	2025 में 3.0 प्रतिशत 2026 में 3.1 प्रतिशत	2026 में 2.9 प्रतिशत 2027 में 3.0 प्रतिशत
राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	बीई 2025-26 के भीतर बना रहेगा केंद्र : 4.4 संयुक्त : 7.4	बीई 2026-27 के भीतर बना रहेगा केंद्र : 4.3 संयुक्त : 6.8
पूर्वानुमान की अवधि के दौरान घरेलू समष्टि-आर्थिक / संरचनात्मक नीतियां	जीएसटी तर्कसंगत किया गया	कोई बड़ा परिवर्तन नहीं

टिप्पणियां: 1. तेल के संबंध में यह अनुमान ब्रेंट क्रूड पर आधारित है।
2. यहां माना गया विनिमय दर पथ आधारभूत अनुमान तैयार करने के उद्देश्य से है और विनिमय दर के स्तर के संबंध में किसी भी 'राय' को इंगित नहीं करता है। रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निर्देशित होता है और न कि विनिमय दर के किसी विशिष्ट स्तर और/या उसके आस-पास के किसी दायरे से।
3. बीई : बजट अनुमान।
4. संयुक्त राजकोषीय घाटे से तात्पर्य केन्द्र और राज्यों की सम्मिलित राजकोषीय घाटे से है।

स्रोत : आरबीआई अनुमान; बजट दस्तावेज; अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी)।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

चार्ट V.1: कच्चे तेल की कीमतें और विनिमय दर की गतिशीलता

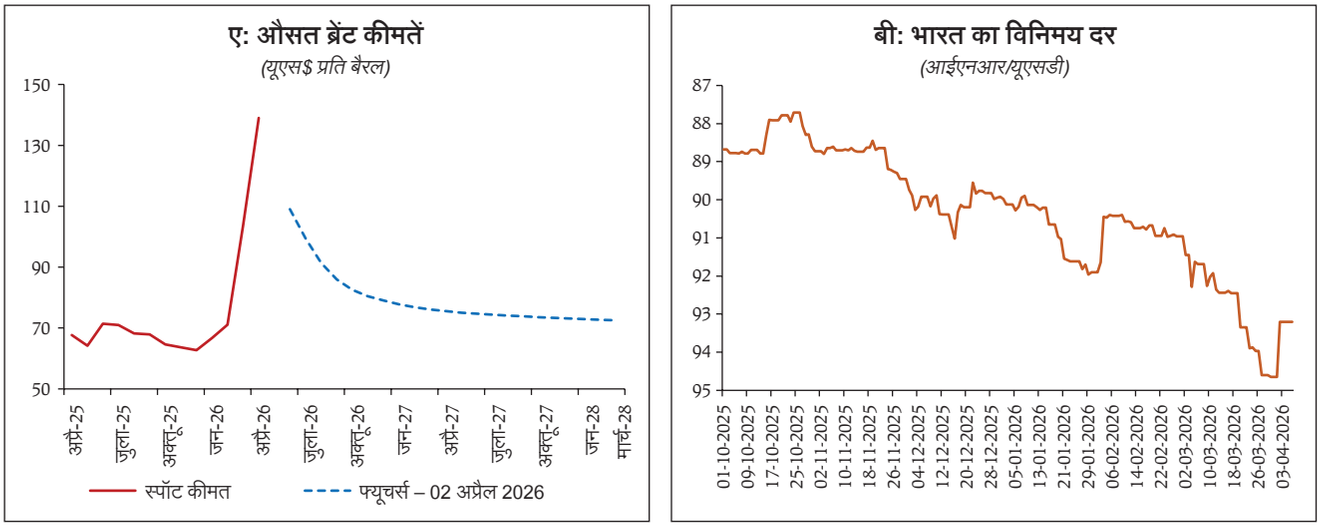

टिप्पणी : चार्ट V.1बी में, विनिमय दर शृंखला को इन्वर्टेड स्केल पर प्लाट किया गया है।
स्रोत : ब्लूमबर्ग।

आईएनआर में गिरावट का रुझान दिखा और यह अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, जो जनवरी 2026 के दूसरे पखवाड़े में लगभग ₹92 प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर को छू गया। इसकी मुख्य वजह पोर्टफोलियो बहिर्वाह, डॉलर की लगातार मांग और वैश्विक वित्तीय स्थितियों का तंग होना था। हालांकि, ईयू और यूएस के बीच व्यापार समझौते की घोषणा के बाद, रुपये में कुछ सुधार हुआ और यह ₹90 प्रति अमेरिकी डॉलर के आसपास सीमित दायरे में बना रहा। मार्च में, पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर चिंताओं के बीच, रुपये पर गिरावट का दबाव और बढ़ गया, जिससे आईएनआर एक ही दिन में ₹95 प्रति अमेरिकी डॉलर को पार कर गया और अपने पिछले सभी रिकॉर्ड निचले स्तरों को तोड़ दिया। इसका एक मुख्य कारण पोर्टफोलियो का लगातार बहिर्वाह, जो वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने के बीच उभरते बाजारों के प्रति जोखिम से बचने की भावना को दर्शाता है। अमेरिकी डॉलर में अस्थिरता और वैश्विक पूंजी प्रवाह में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, विनिमय दर के लिए आधारभूत अनुमान को संशोधित करके ₹94 प्रति अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है, जबकि अक्टूबर 2025 की एमपीआर में यह ₹88 था।

तीसरा, जहां 2025 में टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता का सामना करने में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने सुदृढ़ता दिखाई, वहीं 2026 का परिदृश्य पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण मुश्किलों से घिरा हुआ है। अपने आर्थिक परिदृश्य (मार्च 2026) में, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक विकास दर 2025 के 3.3 प्रतिशत से घटकर 2026 में 2.9 प्रतिशत रह जाएगी, जिसकी वजह यह है कि ऊर्जा की कीमतों में उछाल और चल रहे संघर्ष की अनिश्चित प्रकृति के कारण लागत बढ़ेगी और मांग कम होगी, जिससे मजबूत प्रौद्योगिकी-संबंधी निवेश और उत्पादन, कम प्रभावी टैरिफ दरें और 2025 से मिली गति की अनुकूल परिस्थितियों का असर खत्म हो जाएगा। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बाद, वैश्विक विकास पर गिरावट का जोखिम है, जबकि वैश्विक मुद्रास्फीति पर बढ़ोतरी का जोखिम है, जो बढ़ती अनिश्चितता, बाज़ारों में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति शृंखला में लंबे समय तक बनी रहने वाली बाधाओं और मुद्रास्फीति में अचानक आई तेजी के कारण मौद्रिक नीति को उम्मीद से पहले ही सख़्त करने से पैदा हुई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से होने वाली शिपमेंट का लगभग पूरी तरह से बंद हो जाना और महत्वपूर्ण ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान ने वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं और उर्वरक जैसी संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित कर दिया है, साथ ही, वित्तीय बाज़ारों में, विशेष रूप से ऊर्जा पर निर्भर कुछ एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में, उतार-चढ़ाव भी बढ़ गया है। इस मोड़ पर, यह कहना बेहद अनिश्चित है कि उत्पादकता में वृद्धि और एआई सहित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ते निवेश की अनुकूल परिस्थितियों से इन विपरीत परिस्थितियों की भरपाई

किस हद तक हो पाएगी, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लचीलेपन की कड़ी परीक्षा ले रही है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुमान के अनुसार, वैश्विक पण्य व्यापार की मात्रा में वृद्धि 2025 के 4.6 प्रतिशत से घटकर 2026 में 1.9 प्रतिशत और फिर 2027 में बढ़कर 2.6 प्रतिशत होने की उम्मीद है; वहीं, सेवाओं के व्यापार की मात्रा 2025 के 5.3 प्रतिशत से घटकर 2026 में 4.8 प्रतिशत और फिर 2027 में सुधरकर 5.1 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

V.2 मुद्रास्फीति परिदृश्य

फरवरी 2026 में, खाद्य और पेय पदार्थों की वजह से घरेलू हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गई। कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) मुद्रास्फीति 3.7 प्रतिशत पर स्थिर रही। हालांकि, संघर्ष का असर जरूरी वस्तुओं की कीमतों और उनकी उपलब्धता पर पड़ा है जो मौजूदा समय में मुद्रास्फीति के लिए सबसे बड़ा जोखिम बनकर उभरा है। ऊर्जा की कीमतें उस स्तर तक पहुंच गई हैं जो आखिरी बार 2022 के रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान देखी गई थीं, तथा माल ढुलाई और बीमा की लागत बढ़ने की वजह से कई दूसरी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ गई हैं। घरेलू खुदरा कीमतों पर काफी ज्यादा दबाव डालने के अलावा, ये लागतें कई उत्पादों के इनपुट कॉस्ट में भी जुड़ जाती हैं, जिससे कॉस्ट-पुश मुद्रास्फीति का जोखिम पैदा हो जाता है। उर्वरकों जैसे जरूरी इनपुट की आपूर्ति में कमी, अगर लंबे समय तक बनी रहती है, तो इससे उत्पादन लागत में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे मुद्रास्फीति के परिदृश्य के लिए जोखिम और भी बढ़ जाएगा।

शहरी परिवारों की अगले तीन महीनों की मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाएं 60 बीपीएस बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गईं, जबकि एक साल आगे के लिए रिज़र्व बैंक के द्विमासिक परिवारों के सर्वेक्षण[3] के नवीनतम सर्वेक्षण दौर (मार्च 2026) में 20 बीपीएस की मामूली बढ़ोतरी के साथ यह 8.8 प्रतिशत हो गई। लगातार दूसरे दौर में, मुद्रास्फीति बढ़ने की उम्मीद करने वाले उत्तरदाताओं का हिस्सा, निकट काल और एक साल आगे, दोनों के लिए बढ़ा है (चार्ट V.2ए)। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक के हालिया द्विमासिक ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (आरसीसीएस)[4] के अनुसार, ग्रामीण और अर्ध-शहरी परिवारों की वार्षिक मुद्रास्फीति के बारे में मौजूदा सोच पिछले दौर के मुकाबले मार्च 2026 में 50 आधार अंक (बीपीएस) बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गई। साथ ही, उनकी एक साल

चार्ट V.2: परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं

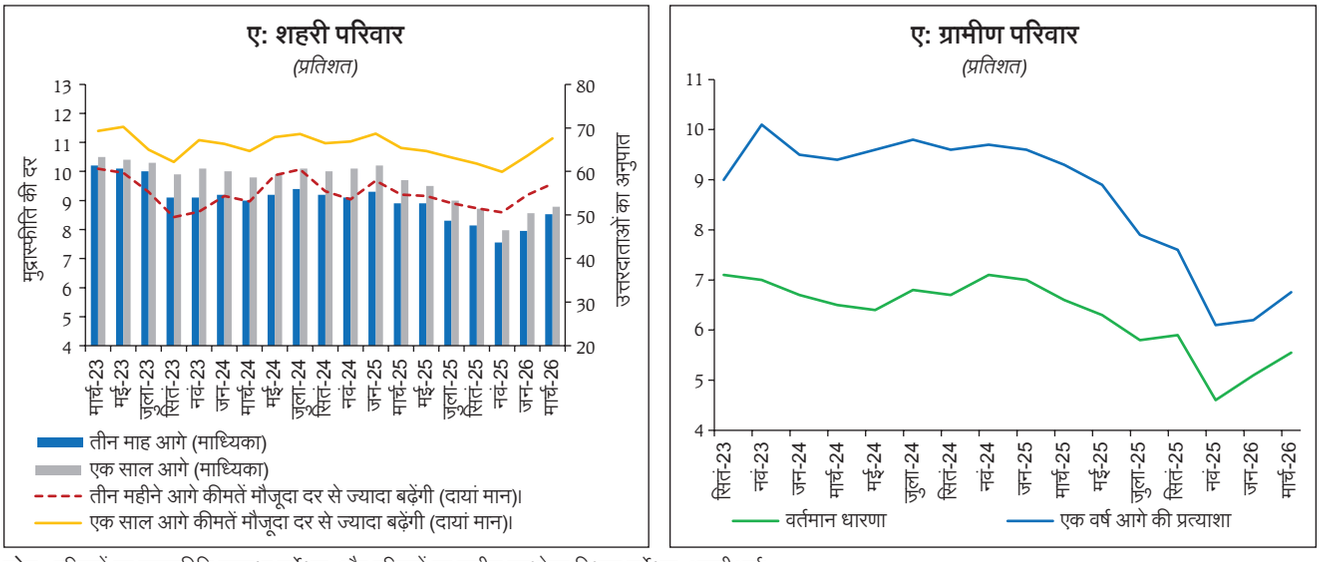

स्रोत : परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण; और परिवारों का ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, आरबीआई।

[3] रिज़र्व बैंक का मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी परिवारों का सर्वेक्षण मार्च 2021 से 19 शहरों (पिछले दौर में 18 शहरों) में किया जा रहा है और मार्च 2026 दौर के परिणाम 6,075 परिवारों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।

[4] रिज़र्व बैंक का ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण सितंबर 2023 से भारत के सभी राज्यों और तीन प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जा रहा है, और मार्च 2026 के दौर के परिणाम 8,928 उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

आगे की प्रत्याशाएं भी 60 बीपीएस बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गईं (चार्ट V.2बी)।

रिज़र्व बैंक के तिमाही औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण के जनवरी-मार्च 2026 के दौर में सर्वेक्षण की गई विनिर्माण फर्मों को 2026-27 की पहली तिमाही में कच्चे माल की लागत से बढ़ते दबाव की उम्मीद है। पिछली तिमाही की तुलना में बिक्री कीमतों में वृद्धि के भी बढ़ने की उम्मीद है (चार्ट V.3ए)।[5] सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्मों को 2026-27 की पहली तिमाही में इनपुट लागत के दबाव में वृद्धि, लेकिन बिक्री कीमतों में कम वृद्धि की उम्मीद है (चार्ट V.3बी और चार्ट V.3सी)।[6]

मार्च 2026 में रिज़र्व बैंक द्वारा सर्वेक्षण किए गए पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं ने सीपीआई मुद्रास्फीति 2025-26 की चौथी तिमाही में 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इसके धीरे-धीरे और बढ़कर 2026-27 की पहली तिमाही में 4.1 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 4.4 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 4.7 प्रतिशत तक पहुंचने तथा उसके बाद 2026-27 की चौथी तिमाही में कम होकर 4.2 प्रतिशत पर आने की उम्मीद है (चार्ट V.4ए और सारणी V.3)।[7] सीपीआई मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य और पेय पदार्थ, पान, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ, तथा ईंधन और बिजली शामिल नहीं हैं, 2025-26 की चौथी तिमाही में 3.5 प्रतिशत पर रहने और उसके बाद 2026-27 की चौथी तिमाही तक लगभग 4.0-4.3 प्रतिशत के आसपास बने रहने की उम्मीद है।

पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं की दीर्घकालिक मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं – जिन्हें उनके पांच और दस साल के नज़रिए से मापा गया है – मौजूदा दौर में क्रमशः 4.0 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत हैं (चार्ट V.4बी)।

प्रारंभिक स्थितियों, भविष्योन्मुखी सर्वेक्षणों से मिले संकेतों एवं समय-शृंखला और संरचनात्मक मॉडल[8] से मिले अनुमानों को देखते हुए, सीपीआई मुद्रास्फीति का औसत 2026-27 में 4.6 प्रतिशत - पहली तिमाही में 4.0 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 4.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.2 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें जोखिम बढ़ने की आशंका है।

चार्ट V.3: कच्चे माल/इनपुट की लागत और बिक्री कीमत संबंधी प्रत्याशाएं

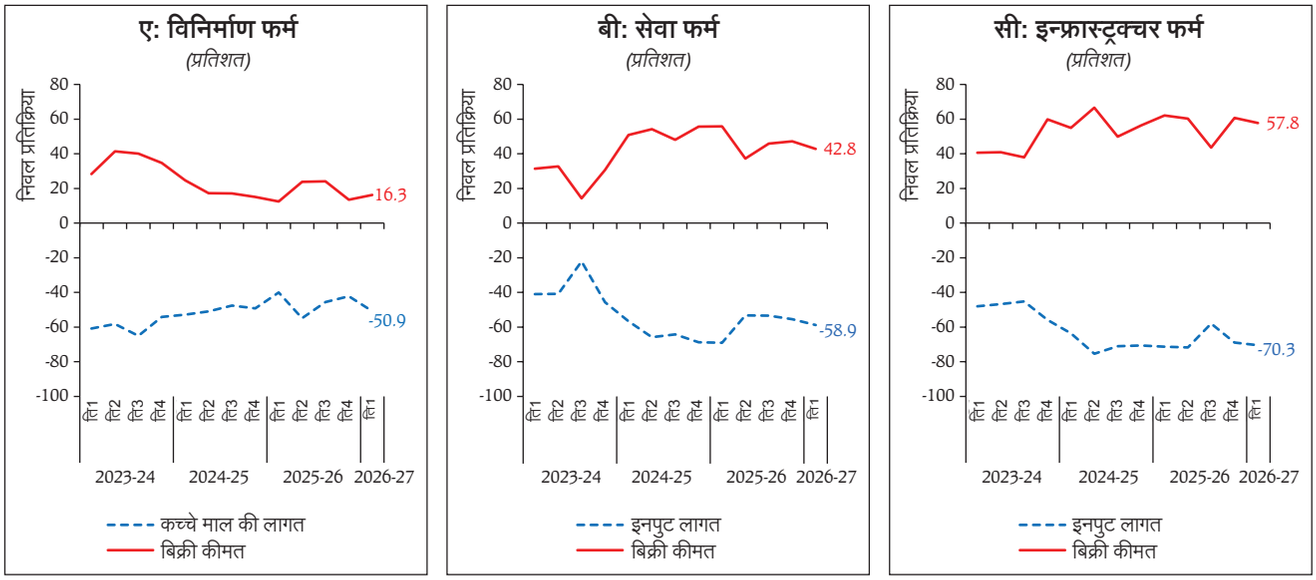

टिप्पणी : निवल प्रतिक्रिया, उन उत्तरदाताओं के योग के बीच का अंतर है, जो आशावादी हैं और जो निराशावादी हैं। इसकी रेंज -100 से 100 तक होती है।
स्रोत : औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण एवं सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर परिदृश्य सर्वेक्षण, आरबीआई।

5 औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण के जनवरी-मार्च 2026 दौर के परिणाम 1,256 कंपनियों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।

6 सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर परिदृश्य सर्वेक्षण के जनवरी-मार्च 2026 दौर में शामिल 712 सेवा कंपनियों और 123 इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्मों पर आधारित।

7 रिज़र्व बैंक के पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के सर्वेक्षण के मार्च 2026 दौर में छियालीस पैनलिस्टों ने भाग लिया।

8 जोइस जॉन, दीपक कुमार, आशिष थॉमस जॉर्ज, प्रतीक मित्रा, मनीष कपूर और माइकल देवब्रत पात्र (2023), "अ रीकैलिब्रेटेड क्वार्टरली प्रोजेक्शन मॉडल (क्यूपीएम 2.0) फार इंडिया", भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, फरवरी खंड LXXVII(2), पीपी.59-77.

चार्ट V.4: सीपीआई मुद्रास्फीति के संबंध में पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं की प्रत्याशाएं

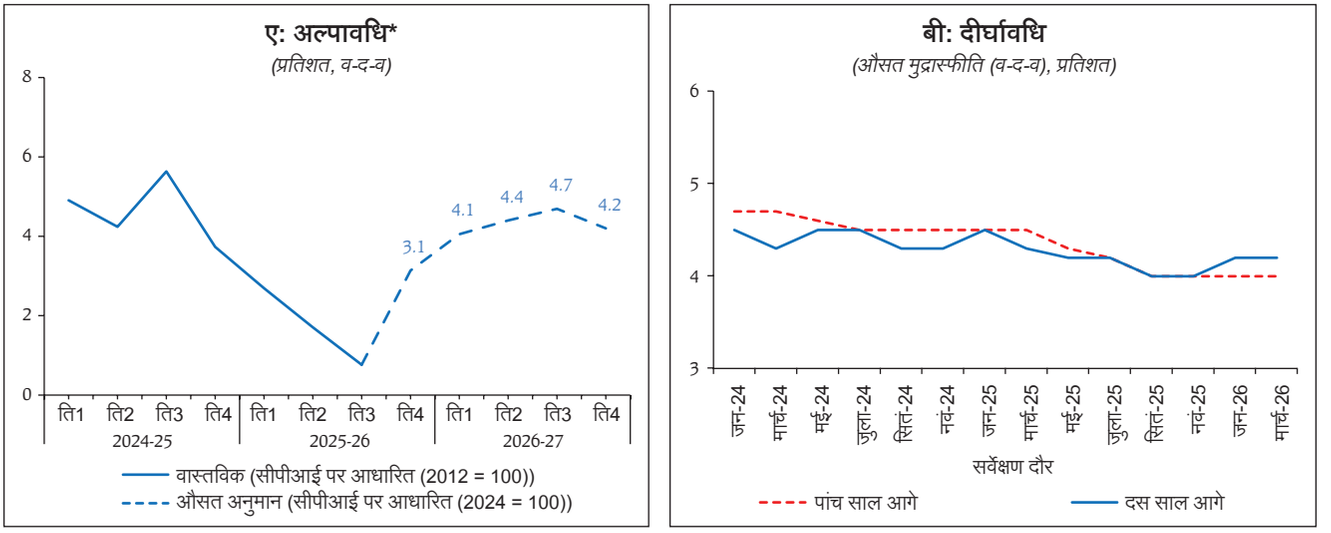

*: मार्च 2026 में पांच तिमाही आगे की प्रत्याशाएं।
स्रोत : पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण, आरबीआई; और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति के लिए 50 प्रतिशत और 70 प्रतिशत विश्वास अंतराल क्रमशः 3.6-7.9 प्रतिशत और 3.0-9.6 प्रतिशत हैं (चार्ट V.5 और सारणी V.3)। यह मानते हुए कि मानसून सामान्य रहेगा और आगे कोई बाह्य या नीतिगत आघात नहीं लगेगा, संरचनात्मक मॉडल अनुमानों से संकेत मिलता है कि मुद्रास्फीति का औसत 2027-28 में 4.6 प्रतिशत रहेगा। वर्ष 2027-28 की चौथी तिमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति के लिए 50 प्रतिशत और 70 प्रतिशत विश्वास अंतराल

चार्ट V.5: सीपीआई मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान (व-द-व)

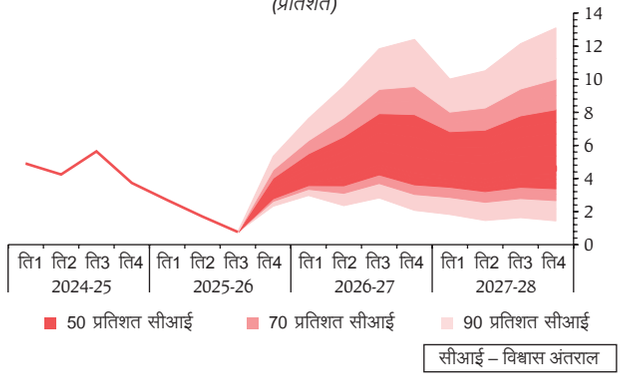

टिप्पणी : फैन चार्ट आधारभूत अनुमान पथ के आसपास अनिश्चितता को दर्शाता है। आधारभूत अनुमान सारणी V.2 में निर्धारित धारणाओं पर आधारित हैं। गहरा लाल छायांकित क्षेत्र 50 प्रतिशत विश्वास अंतराल को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि 50 प्रतिशत संभावना है कि वास्तविक परिणाम गहरे लाल छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाई गई सीमा के भीतर होगा। इसी तरह, 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत विश्वास अंतराल के लिए, क्रमशः 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत संभावना है कि वास्तविक परिणाम संबंधित छायांकित क्षेत्रों द्वारा दर्शाई गई सीमा में होंगे।
स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी V.3: अनुमान – रिज़र्व बैंक और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता

(प्रतिशत)

	2025-26	2026-27	2027-28
रिज़र्व बैंक का आधारभूत अनुमान			
मुद्रास्फीति	1.9#	4.6	4.6
वास्तविक जीडीपी वृद्धि	7.6@	6.9	6.6
रिज़र्व बैंक के परिदृश्य संबंधी अनुमान*			
मुद्रास्फीति	1.9#	5.0	5.1
वास्तविक जीडीपी वृद्धि	7.6@	6.7	6.4
पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के औसत अनुमान			
मुद्रास्फीति, ति4 (व-द-व)	3.1	4.2	-
वास्तविक जीडीपी वृद्धि	7.6	6.9	7.0
सकल घरेलू बचत (जीएनडीआई का प्रतिशत)	33.4	32.9	32.8
सकल पूंजी निर्माण (जीडीपी का प्रतिशत)	34.6	34.5	34.7
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि	13.5	13.0	12.0
संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	7.6	7.5	7.2
केंद्र सरकार सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	4.4	4.4	4.4
रेपो दर (समाप्त-अवधि)	-	5.25	-
91-दिनों के ट्रेजरी बिलों पर प्रतिफल (समाप्त-अवधि)	5.4	5.8	6.2
10-वर्षीय केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिफल (समाप्त-अवधि)	6.8	7.0	6.9
पण्य निर्यात वृद्धि	1.5	4.0	5.0
पण्य आयात वृद्धि	7.9	8.3	5.4
चालू खाता शेष (जीडीपी का प्रतिशत)	-1.0	-1.5	-1.2

*: यह परिदृश्य 2026-27 के दौरान यूएस$ 95 प्रति बैरल और 2027-28 के दौरान यूएस$ 85 प्रति बैरल कच्चे तेल की धारणा पर आधारित है।
#: 2025-26 में औसत सीपीआई मुद्रास्फीति (फरवरी तक)। अप्रैल-दिसंबर 2025 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 2012 शृंखला आधारित है। जनवरी-फरवरी 2026 के लिए मुद्रास्फीति सीपीआई की नई आधार शृंखला (2024=100) पर आधारित है।
@: एनएसओ द्वितीय अग्रिम अनुमान (नए आधार वर्ष 2022-23 के अनुसार)।
टिप्पणी : जीएनडीआई: सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय।
स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान; और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण (मार्च 2026)।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

क्रमशः 3.4-8.2 प्रतिशत और 2.7-10.0 प्रतिशत हैं। वैश्विक समष्टि-आर्थिक स्थितियों में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, हेडलाइन मुद्रास्फीति का औसत 2026-27 में 5.0 प्रतिशत और 2027-28 में 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो बेसलाइन की तुलना में कच्चे तेल की कीमतों के ऊंचे रहने की धारणा पर आधारित है (सारणी V.3)।

आधारभूत अनुमान कई जोखिमों के बढ़ने और घटने पर निर्भर हैं। जोखिम में वृद्धि मौसम से जुड़े झटकों के कारण आपूर्ति में रुकावटों और लंबे समय तक चलने वाले भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों से पैदा होते हैं। जोखिम में गिरावट भू-राजनीतिक संघर्षों के जल्द समाधान से पैदा हो सकते हैं।

V.3 वृद्धि परिदृश्य

घरेलू आर्थिक गतिविधियां निजी उपभोग और स्थिर निवेश के सहारे मजबूत बनी हुई हैं। उच्च क्षमता उपयोग, बैंकों द्वारा ऋण देने में मजबूत वृद्धि, अनुकूल वित्तीय स्थितियां और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का लगातार जोर निवेश गतिविधियों को बढ़ावा देने की उम्मीद है। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित कई उपाय भी विकास को बढ़ावा देने वाले हैं। हालांकि, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों और व्यापार की गतिशीलता में उतार-चढ़ाव से पड़ने वाले प्रभावों के कारण विकास के परिदृश्य के लिए गिरावट के जोखिम भी मौजूद हैं।

भविष्योन्मुखी सर्वेक्षणों से अतिरिक्त जानकारियां भी मिलती हैं। शहरी परिवारों के लिए द्वि-मासिक उपभोक्ता विश्वास (वर्तमान स्थिति सूचकांक) पिछले दौर की तुलना में मार्च 2026 में और भी अधिक निराशावादी क्षेत्र में चला गया। मार्च 2026 के सर्वेक्षण दौर में ग्रामीण परिवारों का उपभोक्ता विश्वास भी कम हो गया, जो तटस्थ स्तर के आसपास छह लगातार दौरों तक अपेक्षाकृत स्थिर रहने के बाद अब निराशावादी क्षेत्र में चला गया है (चार्ट V.6)।

भावी प्रत्याशा सूचकांक द्वारा मापा गया, आगामी वर्ष के लिए उपभोक्ताओं का आशावाद अभी भी सकारात्मक दायरे में बना हुआ है, हालांकि, हाल के सर्वेक्षण दौर में शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों के लिए इसमें गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण सर्वेक्षण के अधिकांश पैमानों के संबंध में प्रत्याशाओं में कमी का होना है (चार्ट V.6)।

रिज़र्व बैंक के जनवरी-मार्च 2026 के तिमाही औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण में, विनिर्माण फर्म 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान अपनी कारोबार स्थितियों (बीएआई/बीईआई)[9] के संबंध

चार्ट V.6: उपभोक्ता विश्वास

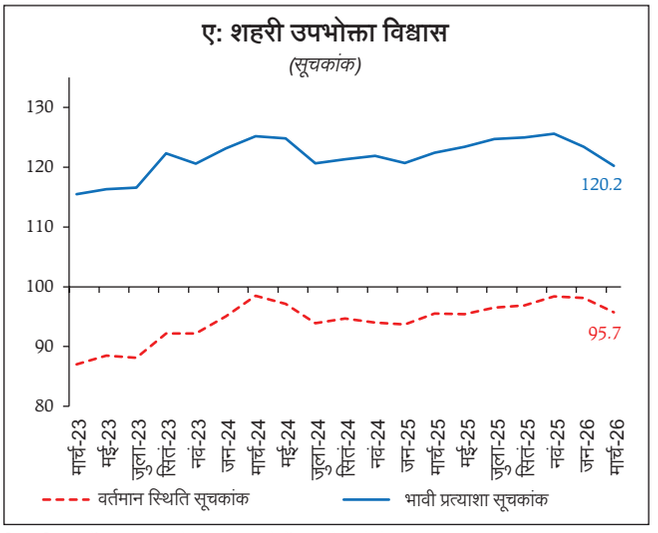

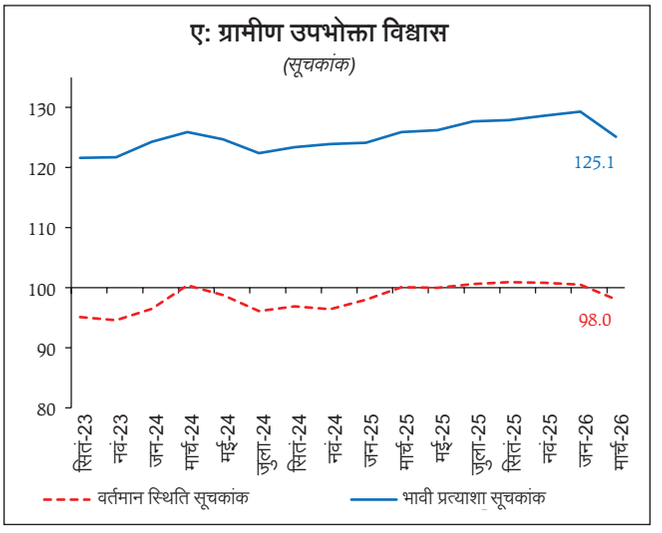

टिप्पणी : दोनों सूचकांक 0 से 200 के दायरे में बदलते रहते हैं।
स्रोत : शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण; और ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, आरबीआई।

[9] कारोबार मूल्यांकन सूचकांक (बीएआई)/कारोबार प्रत्याशा सूचकांक (बीईआई) (0 से 200 के दायरे में) विनिर्माण क्षेत्र में मांग की स्थितियों की एक झलक देता है। यह नौ पैरामीटर्स को मिलाकर बनाया जाता है – (i) समग्र कारोबार स्थिति, (ii) उत्पादन, (iii) ऑर्डर बही, (iv) कच्चे माल का स्टॉक, (v) तैयार माल का स्टॉक, (vi) लाभ मार्जिन, (vii) रोजगार, (viii) निर्यात और (ix) क्षमता उपयोग। 100 से ज्यादा का मान समग्र कारोबार गतिविधियों में विस्तार को दर्शाता है, जबकि 100 से कम का मान संकुचन को दर्शाता है।

चार्ट V.7: कारोबार मूल्यांकन और प्रत्याशाएं

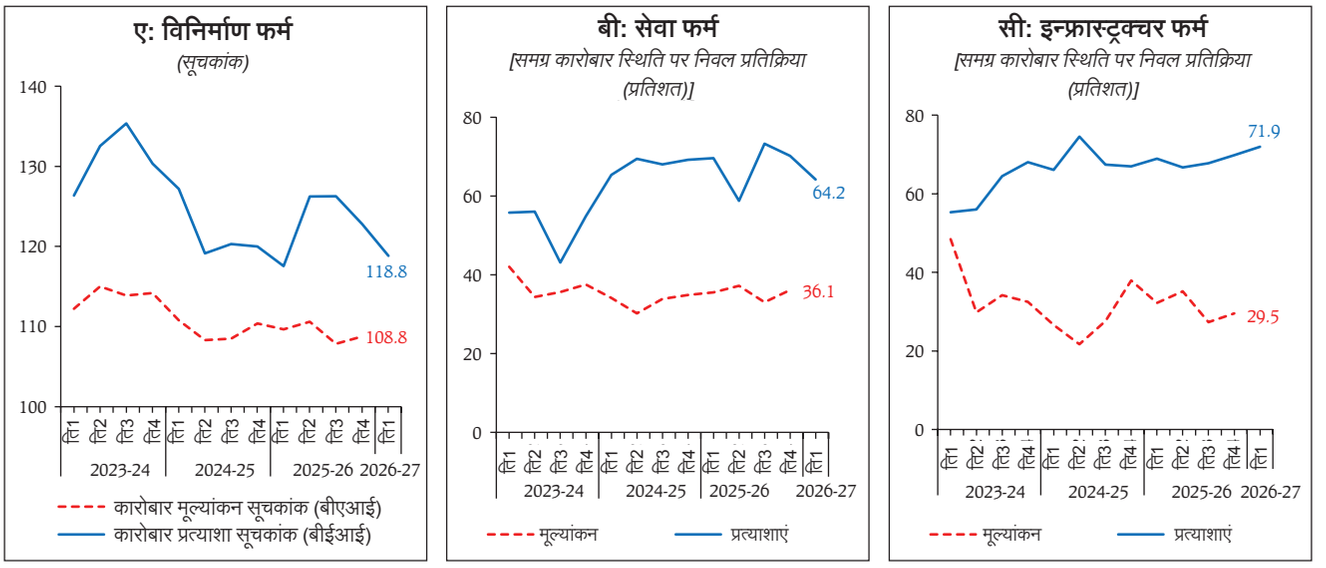

टिप्पणी : निवल प्रतिक्रिया (एनआर), उन उत्तरदाताओं के प्रतिशत के बीच का अंतर है, जो आशावादी हैं और जो निराशावादी हैं। यह -100 से 100 के बीच होती है।
स्रोत : औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण; एवं सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर परिदृश्य सर्वेक्षण, आरबीआई।

में आशावादी बनी रहीं, हालांकि इसमें कुछ नरमी देखी गई (चार्ट V.7ए)। सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियां भी 2026-27 की पहली तिमाही में समग्र कारोबार स्थिति के संबंध में आशावादी बनी रहीं (चार्ट V.7बी और V.7सी)।

रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षण के मार्च 2026 के दौर में शामिल पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं ने 2025-26 की चौथी तिमाही के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। इसके बाद की चार तिमाहियों के दौरान वृद्धि लगभग 6.8-7.0 प्रतिशत रहने की उम्मीद है (चार्ट V.8)।

नई जीडीपी सीरीज़ (आधार वर्ष 2022–23) के अनुसार, 2025-26 की तीसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही, जबकि 2025-26 की दूसरी तिमाही में यह 8.4 प्रतिशत थी। यह निजी खपत और मजबूत स्थिर निवेश के सहारे घरेलू आर्थिक गतिविधियों में लगातार मजबूती को दर्शाता है। आधारभूत अनुमानों, सर्वेक्षण संकेतकों और मॉडल अनुमानों को ध्यान में रखते हुए, 2026-27 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.9 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो पहली तिमाही में 6.8 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 7.0 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें आधारभूत पथ के आसपास जोखिम नीचे की ओर झुके हुए हैं (चार्ट V.9 और सारणी V.3)। यह मानते हुए कि मॉनसून सामान्य रहेगा और कोई बड़े बाहरी या नीतिगत आघात नहीं पहुंचेगे, 2027-28 के लिए संरचनात्मक मॉडल के अनुमान वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.6 प्रतिशत रहने का संकेत देते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के परिदृश्य में, 2026-27 और 2027-28

चार्ट V.8: पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का वास्तविक जीडीपी वृद्धि संबंधी अनुमान
(प्रतिशत, व-द-व)

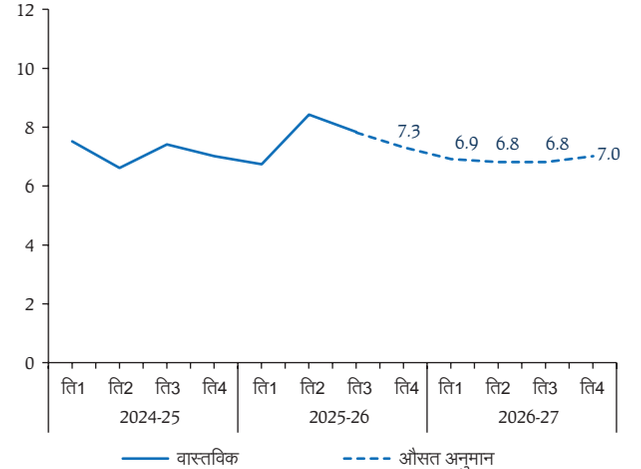

टिप्पणी : वास्तविक और अनुमान संशोधित आधार वर्ष (2022-23) के आंकड़ों पर आधारित हैं।
स्रोत : पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण, आरबीआई और राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

चार्ट V.9: वास्तविक जीडीपी में वृद्धि का अनुमान (व-द-व)

(प्रतिशत)

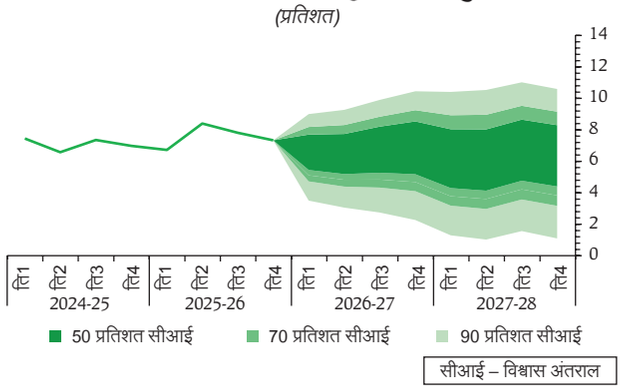

टिप्पणी : फैन चार्ट आधारभूत अनुमान पथ के आसपास अनिश्चितता को दर्शाता है। आधारभूत अनुमान सारणी V.2 में निर्धारित धारणाओं पर आधारित हैं। गहरा हरा छायांकित क्षेत्र 50 प्रतिशत विश्वास अंतराल को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि 50 प्रतिशत संभावना है कि वास्तविक परिणाम गहरे हरे छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाई गई सीमा के भीतर होगा। इसी तरह, 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत विश्वास अंतराल के लिए, क्रमशः 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत संभावना है कि वास्तविक परिणाम संबंधित छायांकित क्षेत्रों द्वारा दर्शाई गई सीमा में होंगे।

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्रमशः 6.7 प्रतिशत और 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है (सारणी V.3)।

बेसलाइन वृद्धि के पथ में अपसाइड और डाउनसाइड जोखिम हैं। अपसाइड जोखिम बेहतर होते कॉर्पोरेट कार्य-निष्पादन, निजी निवेश में तेजी से हो रही वापसी, और पश्चिम एशिया संघर्ष के जल्द समाधान से पैदा होते हैं। दूसरी ओर, लंबे समय तक चलने वाले भू-राजनीतिक संघर्ष के दुष्प्रभाव, वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव, बदलते व्यापारिक तौर-तरीके और जलवायु से जुड़े झटके आधारभूत विकास पथ के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

V.4 जोखिम संतुलन

वृद्धि और मुद्रास्फीति के आधारभूत अनुमान, प्रमुख घरेलू और वैश्विक समष्टि-आर्थिक वेरिअबल्स से संबंधित उन धारणाओं पर आधारित हैं, जिन्हें सारणी V.2 में दर्शाया गया है। ये मूल धारणाएं वैश्विक व्यापार के परिदृश्य में हो रहे बदलावों, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनावों, वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में अस्थिरता और घरेलू मौसम-संबंधी जोखिमों से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितताओं के अधीन हैं। इस पृष्ठभूमि में, यह खंड संभावित वैकल्पिक परिदृश्यों के तहत, मुद्रास्फीति और वृद्धि के आधारभूत अनुमानों के इर्द-गिर्द मौजूद जोखिमों के संतुलन की जांच करता है।

(i) वैश्विक वृद्धि संबंधी अनिश्चितताएं

वैश्विक आर्थिक गतिविधियां 2025 की दूसरी छमाही में और 2026 की शुरुआत तक मोटे तौर पर सुदृढ़ बनी रही हैं, जिस वजह से आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के जनवरी 2026 के अपडेट में 2026 के लिए वैश्विक वृद्धि के अनुमान को थोड़ा बढ़ाकर 3.3 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, यह सुदृढ़ता कुछ खास क्षेत्रों और इलाकों तक ही सीमित है, जो मुख्य रूप से प्रोद्योगिकी से जुड़े निवेश, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर से प्रेरित है, और इसका ज्यादातर हिस्सा उत्तरी अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में केंद्रित है, न कि यह व्यापक स्तर पर मांग में सुधार को दर्शाता है। ओईसीडी ने मार्च 2026 में जारी अपनी इकोनॉमिक आउटलुक अंतरिम रिपोर्ट में, 2026 और 2027 के दौरान वैश्विक वृद्धि क्रमशः 2.9 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

इस पृष्ठभूमि में, वैश्विक परिदृश्य के लिए गिरावट के जोखिम काफी बने हुए हैं। लगातार जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण परिदृश्य अस्पष्ट बना हुआ है। पश्चिम एशिया में चल रहा मौजूदा संघर्ष और तेज हो गया है, जिसके तहत खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचों पर हमले हुए हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को चुनिंदा रूप से बंद किए जाने से खाड़ी क्षेत्र में व्यापार पर गंभीर असर पड़ा है। कुल मिलाकर, इस संघर्ष ने वैश्विक व्यापार और विकास के निकट-अवधि के परिदृश्य को काफी हद तक खराब कर दिया है।

बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते राजकोषीय असंतुलन से दीर्घकालिक ब्याज दरें बढ़ सकती हैं और वैश्विक वित्तीय स्थितियां तंग हो सकती हैं, जिसका ईएमईज़ पर पूंजी के बहिर्वाह के रूप में बुरा असर पड़ सकता है। डाउनसाइड जोखिम का एक नया स्रोत एआई से जुड़ी संपत्तियों के मूल्यांकन में अचानक भारी गिरावट की संभावना से जुड़ा है, यदि कॉर्पोरेट आय, टेक्नोलॉजी क्षेत्र के ऊंचे मूल्यांकन को सही साबित करने में विफल रहती है। ऐसी गिरावट से वित्तीय स्थितियां और तंग हो सकती हैं, जो मुख्य रूप

से टेक-प्रधान क्षेत्रों में दिखेगा, लेकिन इसके व्यापक रूप से फैलने का भी खतरा बना रहेगा।

अपसाइड जोखिम की बात करें तो, व्यापारिक तनाव और पश्चिम एशिया संकट का अधिक रचनात्मक और स्थायी समाधान, साथ ही एआई-प्रेरित उत्पादकता लाभ, वैश्विक विकास को बेसलाइन से ऊपर ले जा सकते हैं।

यदि वैश्विक वृद्धि बेसलाइन से 100 बीपीएस कम रहती है, तो घरेलू वृद्धि और मुद्रास्फीति क्रमशः लगभग 30 बीपीएस और 15 बीपीएस[10] कम हो सकती है। इसके विपरीत, यदि वैश्विक वृद्धि बेसलाइन की तुलना में 50 बीपीएस अधिक रहती है, तो घरेलू वृद्धि और मुद्रास्फीति क्रमशः लगभग 15 बीपीएस और 7 बीपीएस अधिक हो सकती है (चार्ट V.10ए और V.11ए)।

(ii) कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें

मार्च 2026 में, पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग 103 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं। इस संघर्ष की तीव्रता के कारण वैश्विक तेल बाज़ार को आपूर्ति में भारी बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के रास्ते तेल और तेल उत्पादों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) ने मार्च 2026 में जारी अपनी ऑयल मार्केट रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि 2026 में वैश्विक तेल आपूर्ति औसतन 1.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन (एमबी/डी) कम हो जाएगी, जिसका मुख्य कारण ओपेक+ से इतर के उत्पादक देशों द्वारा उत्पादन में वृद्धि है। आईईए के सदस्य देशों ने 11 मार्च 2026 को अपने आपातकालीन भंडारों से 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने पर सहमति जताई है। भविष्य को देखते हुए, तेल की कीमतों का संरचनागत परिदृश्य अभी भी ऊपर की ओर झुका हुआ है, क्योंकि खाड़ी देशों में तेल के इन्फ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान के कारण वैश्विक तेल उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है। यू.एस. एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (ईआईए) ने मार्च 2026 में जारी अपने पूर्वानुमान में अनुमान लगाया है कि पूरे वर्ष 2026 के दौरान ब्रेंट क्रूड का औसत लगभग 79 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रहेगा, जो पिछले महीने अनुमानित 58 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से काफी अधिक है। इस बेसलाइन के मुकाबले, पश्चिम एशिया में लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष, प्रमुख तेल उत्पादकों पर लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों, या वैश्विक मांग में उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से होने वाली वापसी की वजह से आपूर्ति में होने वाली भारी बाधाएं तेल की कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव डाल सकती हैं। यदि कच्चे तेल की कीमतें बेसलाइन से 10 प्रतिशत ज्यादा हो जाती हैं, और यह मान लिया जाए कि इसका पूरा असर घरेलू उत्पादों की कीमतों पर पड़ेगा, तो मुद्रास्फीति लगभग 50 बीपीएस बढ़ सकती है और वृद्धि लगभग 15 बीपीएस कम हो सकती है। इसके विपरीत, वैश्विक मांग में कमी, ओपेक+ द्वारा आपूर्ति में की गई कटौती को व्यवस्थित तरीके से वापस लेना, और पश्चिम एशिया संघर्ष का जल्द समाधान होने से कीमतों में नरमी आ सकती है। यदि कच्चे तेल की कीमतें बेसलाइन के मुकाबले 10 प्रतिशत कम हो जाती हैं, तो मुद्रास्फीति लगभग 50 बीपीएस कम हो सकती है और जीडीपी वृद्धि 15 बीपीएस ज्यादा हो सकती है (चार्ट V.10ए और V.11ए)।

(iii) विनिमय दर

भारतीय रुपया (आईएनआर) 2025 के बाद के हिस्से में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रहा, और मार्च 2026 में यह ₹91.5–₹94.7 प्रति अमेरिकी डॉलर के दायरे में रहा। इस गिरावट की मुख्य वजह वैश्विक स्तर पर जोखिम से बचने की भावना और पोर्टफोलियो इक्विटी से से भारी मात्रा में बहिर्वाह था।

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का वैश्विक आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति पर असर न केवल भौतिक आपूर्ति में रुकावटों के जरिए, बल्कि वित्तीय माध्यमों से भी पड़ सकता है। बढ़ती वित्तीय अनिश्चितता निवेशकों को सुरक्षित निवेश की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कुल वित्तीय स्थितियां और सख्त हो सकती हैं। इससे कर्ज़ लेने की लागत बढ़ सकती है, निजी निवेश में रुकावट आ सकती है और कुल आर्थिक वृद्धि धीमी हो सकती है। चालू खाता घाटे का और बढ़ना

[10] सीपीआई (2024=100) और जीडीपी (2022-23) दोनों के लिए बनाई गई बैक सीरीज़ का उपयोग करके, नई सीपीआई सीरीज़ के अनुसार वेटिंग डायग्राम का उपयोग करते हुए, इंपल्स रिस्पॉन्स फंक्शन तैयार किए गए हैं। मॉडल के पैरामीटर 2019-20 की तीसरी तिमाही तक के डेटा का उपयोग करके जांचे गए हैं।

मौद्रिक नीति वक्तव्य

चार्ट V.10: आधारभूत मुद्रास्फीति पथ पर जोखिम परिदृश्यों का प्रभाव

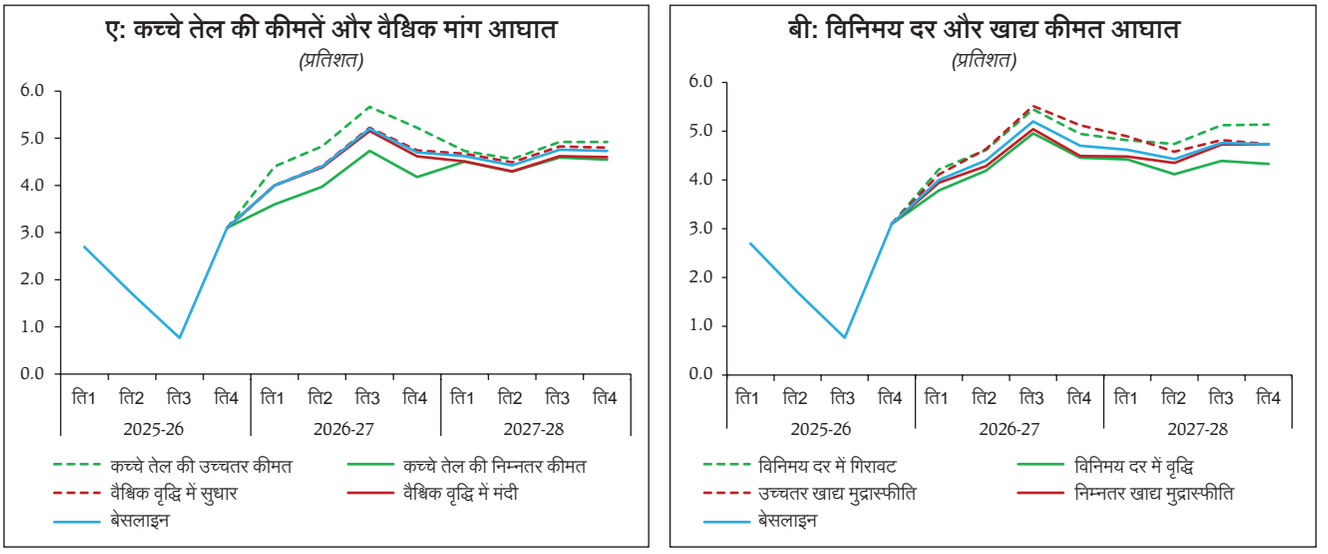

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

एवं पूंजी बहिर्वाह उभरते बाज़ारों में मुद्रा की कीमत में गिरावट का कारण बन सकता है, जिससे आयात की कीमतें बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति का दबाव और बढ़ सकता है। बढ़ी हुई अनिश्चितता के कारण विभिन्न वित्तीय आस्तियों के रिस्क प्रीमियम भी बढ़ने के दबाव पैदा हो सकते हैं।

आगे देखें तो, रुपये को एक अपेक्षाकृत मजबूत डॉलर, पूंजी अंतर्वाह की मात्रा और संरचना के संबंध में अनिश्चितता, और बढ़ती आयात लागतों से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भू-राजनीतिक तनावों के बढ़ने से ईएमई आस्ति बाज़ारों में व्यापक स्तर पर जोखिम से बचने की प्रवृत्ति पैदा होने, या प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा वर्तमान में अनुमानित से कहीं अधिक आक्रामक मौद्रिक सख्ती किए जाने से, रुपये पर फिर से अवमूल्यन का दबाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार ढांचे को अंतिम रूप दिए जाने से भारतीय वस्तुओं पर

चार्ट V.11: आधारभूत वृद्धि पथ पर जोखिम परिदृश्यों का प्रभाव

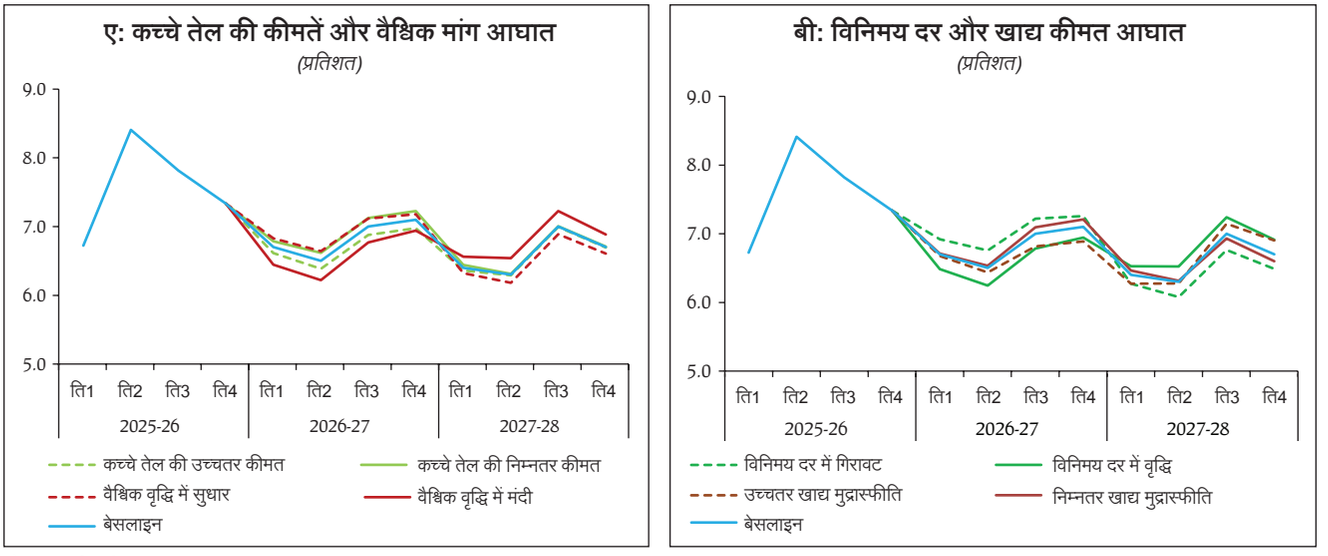

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

लगने वाले आपसी शुल्क कम हो सकते हैं, जिससे सेवाओं के निर्यात में मजबूती के साथ-साथ आईएनआर को स्थिरता मिल सकती है। ऐसे परिदृश्य में, जहां आईएनआर अपने बेसलाइन से 5 प्रतिशत तक गिर जाता है, मुद्रास्फीति लगभग 40 बीपीएस तक बढ़ सकती है, जबकि सामान्य समष्टि-आर्थिक परिस्थितियों में, निर्यात के माध्यम से जीडीपी वृद्धि को अल्पावधि में लगभग 25 बीपीएस का लाभ मिल सकता है। इसके विपरीत, बेसलाइन के मुकाबले आईएनआर में 5 प्रतिशत मूल्यवृद्धि होने से मुद्रास्फीति और जीडीपी वृद्धि दोनों में क्रमशः लगभग 40 बीपीएस और 25 बीपीएस की कमी आ सकती है (चार्ट V.10बी और V.11बी)।

(iv) खाद्य मुद्रास्फीति

2025 की दूसरी छमाही के दौरान खाद्य कीमतों में तेजी से गिरावट आई। इसका हेडलाइन सीपीआई (2012=100) पर काफी असर पड़ा, और अक्टूबर 2025 में मुद्रास्फीति ऐतिहासिक रूप से घटकर 0.25 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंच गई, जो आरबीआई की सहन सीमा के निचले स्तर से भी काफी नीचे थी। खाद्य पदार्थों में अपस्फीति काफी व्यापक थी, जिसमें सब्ज़ियां, दालें, मसाले और चावल सभी शामिल थे, जो खरीफ़ और रबी की फसलों की अच्छी पैदावार, सरकार द्वारा आपूर्ति-पक्ष का प्रभावी प्रबंधन और बेस इफ़ेक्ट के अनुकूल होने की वजह से थी। तब से खाद्य मुद्रास्फीति सामान्य होने लगी है जो किसी व्यापक मांग-जनित बढ़ते दबाव के बजाय, सब्जियों की कीमतों में आई भारी गिरावट के नरम पड़ने और अनुकूल आधार प्रभाव के कमजोर पड़ने को दर्शाता है।

आगे चलकर, फसलों के अनुमानित अधिक उत्पादन और पर्याप्त खाद्य भंडार से आपूर्ति की संभावनाएं बेहतर हुई हैं, हालांकि मौसम से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण खाद्य मुद्रास्फीति का जोखिम बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मौसम एजेंसियों ने भी दक्षिण-पश्चिम मानसून के दूसरे चरण के दौरान अल नीनो के शुरू होने की अधिक संभावना जताई है, जिसका असर बारिश पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। इसके अलावा, यदि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण आपूर्ति में कमी आती है और उर्वरक तथा कीटनाशकों जैसी जरूरी चीज़ों की उपलब्धता और लागत प्रभावित होती है, तो खाद्य पदार्थों की कीमतें भी दबाव में आ सकती हैं।

ये सभी कारक खाद्य मुद्रास्फीति को और बढ़ा सकते हैं, नतीजतन हेडलाइन मुद्रास्फीति बेसलाइन के मुकाबले 40 बीपीएस ज्यादा हो सकती है। दूसरी ओर, खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी, और साथ में बेस इफ़ेक्ट, हेडलाइन मुद्रास्फीति को बेसलाइन के मुकाबले लगभग 20 बीपीएस तक कम कर सकते हैं (चार्ट V.10बी और V.11बी)।

V.5 निष्कर्ष

घरेलू आर्थिक गतिविधियां सुदृढ़ बनी हुई हैं, जिन्हें मजबूत निजी उपभोग और स्थिर निवेश में लगातार हो रहे विस्तार से समर्थन मिल रहा है, भले ही बाह्य परिवेश अनिश्चित बना हुआ है। कृषि क्षेत्र की अनुकूल संभावनाएं, सेवाओं में स्थिर गतिविधियां, उच्च क्षमता उपयोग और कॉर्पोरेट व बैंकों की मजबूत बैलेंस शीट भविष्य में वृद्धि को आधार प्रदान करने की संभावना रखते हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर में लगातार हो रहा सरकारी निवेश और हाल ही में संपन्न हुए व्यापार समझौते भी मध्यम-अवधि की वृद्धि संभावनाओं के लिए अनुकूल रहने की उम्मीद है।

हेडलाइन मुद्रास्फीति, जो 2025 की दूसरी छमाही में खाद्य पदार्थों की कीमतों में अपस्फीति की वजह से तेजी से कम हो गई थी, अब संशोधित सीपीआई सीरीज़ के तहत सामान्य होने लगी है। कोर मुद्रास्फीति कम बनी हुई है, जो दर्शाती है कि कीमत संबंधी अंतर्निहित दबाव नियंत्रण में हैं। अनुमान है कि 2026-27 के दौरान मुद्रास्फीति धीरे-धीरे बढ़ेगी, क्योंकि बेस इफ़ेक्ट कम होंगे और खाद्य पदार्थों की कीमतें सामान्य हो जाएंगी, हालांकि, मध्यम अवधि में यह सहन सीमा के भीतर ही रहेगी। पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं की दीर्घकालिक मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाएं लगभग 4 प्रतिशत पर स्थिर बनी हुई हैं।

इसके साथ ही, परिदृश्य के संबंध में जोखिम बने हुए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और विनिमय दर में होने वाले बदलावों पर लगातार नज़र रखने की जरूरत है। भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में अस्थिरता, वैश्विक व्यापार नीतियों के बारे में अनिश्चितता और मौसम से जुड़ी बाधाएं वृद्धि और मुद्रास्फीति के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का प्रतिकूल प्रभाव वृद्धि और मुद्रास्फीति के अनुमानों में दिखाई देता है – जहां एक ओर मुद्रास्फीति के

मौद्रिक नीति वक्तव्य

बढ़ने का अनुमान है, हालांकि यह तय सीमा के भीतर ही रहेगी, वहीं दूसरी ओर वृद्धि के धीमा पड़ने की उम्मीद है। मध्यम अवधि में, वृद्धि और मुद्रास्फीति की गति इस बात पर निर्भर करेगी कि आपूर्ति शृंखला पूरी तरह से कब तक बहाल हो पाती है, और पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त होने के बाद ऊर्जा की कीमतें किस स्तर पर स्थिर होती हैं। मौजूदा हालात में स्थिति बेहद अनिश्चित है और उचित नीतिगत प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए घटनाक्रमों का लगातार मूल्यांकन करते रहने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर, भारत के मजबूत समष्टि-आर्थिक आधार और मौजूदा बफर अस्थिर करने वाली भू-राजनीतिक घटनाओं और बढ़ती अनिश्चितताओं का सामना करने में देश को मजबूती प्रदान करते हैं।

भाषण

भारत की विकास यात्रा और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में RBI की भूमिका
श्री संजय मल्होत्रा

वित्त में एआई: क्या बदल सकता है, क्या कभी नहीं बदलना चाहिए
श्री स्वामीनाथन जे.

*भारत के विकास और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका**

श्री संजय मल्होत्रा

सुप्रभात।

मुझे आपके साथ अपने विचार साझा करने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात रखता हूं। आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों के बीच यहां उपस्थित होना वास्तव में खुशी की बात है।

मुझे 2008-09 में यहां बिताए गए 11 महीने याद हैं: एंटी-ट्रस्ट इकोनॉमिक्स पर बॉब विलिग के पाठ्यक्रमों के साथ अर्थशास्त्र की मूल बातें (भगवान उनकी आत्मा को आशीर्वाद दें), एंगस डीटन, एलन ब्लाइंडर (जिन्होंने सोचा था कि मौद्रिक नीति और संचार पर उनकी सीख आगे चलकर बहुत काम आएंगे!) और ग्रॉसमैन, छोटे और एकजुट एमपीपी बैच के जीवंत सौहार्द तक, पतझड़ और वसंत में खूबसूरत ग्रामीण इलाकों में परिवार की सैर, और प्रिंसटन-हार्वर्ड फुटबॉल प्रतिद्वंद्विता, सभी स्मृति में स्पष्ट रूप से अंकित हैं।

पिछले एक दशक में भारत की कितनी बड़ी विकास गाथा रही है, उससे आप सभी परिचित हैं। हम औसतन 6.1% प्रति वर्ष की दर से बढ़े हैं,[1] जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.2% की वृद्धि हुई है और चीन जैसे हमारे निकटतम समकक्षों में 5.6% और इंडोनेशिया में 4.2% की वृद्धि हुई है।[2] मैं विकास के मुख्य चालकों - उपभोग, निवेश, सेवाओं आदि पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं उन सक्षमकर्ताओं के बारे में बात करूंगा जो पृष्ठभूमि में काम करते हैं जो मुख्य कारकों के लिए एक सुविधाजनक वातावरण बनाते हैं।

मैं इस सुविधाजनक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदान करने में आरबीआई की भूमिका के बारे में बात करूंगा। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि कई केंद्रीय बैंकों के विपरीत, आरबीआई, एक पूर्ण-विकसित, पूर्ण-सेवा प्रदाता केंद्रीय बैंक है, जिसके पास मौद्रिक नीति, मुद्रा प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण से लेकर विविध जिम्मेदारियां हैं। बैंको के बैंक होने के अलावा, यह केंद्र और राज्य सरकारों का बैंक एवं ऋण प्रबंधक है। इसके अलावा, आरबीआई की भी विकासात्मक भूमिका है। हालांकि, मैं रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्यों पर संक्षेप में बात करूंगा, जो परिवारों, व्यवसायों और सरकारों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं।

I. मूल्य स्थिरता

पहला मूल्य स्थिरता है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसका पालन सभी केंद्रीय बैंक करते हैं – ऐसा न केवल इसलिए कि मुद्रास्फीति एक प्रतिगामी कर है, जो सबसे गरीब को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, बल्कि इसलिए भी कि व्यवसायों और परिवारों के लिए आत्मविश्वास से योजना बनाने और निवेश करने के लिए मूल्य स्थिरता महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देशों के विपरीत, जिनके पास स्पष्ट दोहरा अधिदेश है और न्यूजीलैंड जैसे अन्य देश, जिनके पास स्पष्ट रूप से एकल अधिदेश है, हमारे पास विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक अधिदेश के रूप में मूल्य स्थिरता है।

हमने 2016 में औपचारिक रूप से इस अधिदेश को अपनाया। हमारे पास एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग (एफआईटी) फ्रेमवर्क है। यह लचीला है क्योंकि, जबकि हमारे पास एक पॉइंट टार्गेट (4%) है, जिसमें दोनों तरफ 2% का एक बैंड है। आंतरिक और साथ ही बाहरी, सीपीआई बास्केट में भोजन और ईंधन (आपूर्ति पक्ष कारक) के बड़ी भारिता को देखते हुए, लक्ष्य के चारों ओर अपेक्षाकृत व्यापक आघात सहनीयता बैंड हमें आपूर्ति के आघातों को नेविगेट करने देता है।

हम मौद्रिक नीति का संचालन कैसे करते हैं, विशेष रूप से इस तरह की उच्च अनिश्चितता पैदा करने वाली वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में? मुझे याद आ रहा है कि एलन ग्रीनस्पैन ने एक बार कहा था कि अनिश्चितता केवल मौद्रिक नीति परिदृश्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है; अपितु यह एक पारिभाषिक विशेषता है। दूसरे शब्दों में, केंद्रीय बैंकिंग में, आपके पास जो एकमात्र निश्चितता वह अनिश्चितता है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि कम अनिश्चितता और अस्थिरता के समय में भी, अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति संचरण जटिल

---

* 18 अप्रैल, 2026 को प्रिंसटन विश्वविद्यालय, यूएसए में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा का संबोधन।

[1] राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के आधार पर 2015-16 से 2024-25 की अवधि से संबंधित है।

[2] आईएमएफ डेटा के आधार पर 2016-2025 की अवधि से संबंधित है।

और निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं। वर्षों से अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न व्यापक आर्थिक चर और निर्मित मॉडल के बीच संबंधों को समझने की कोशिश की है। हालांकि, हर मॉडल, चाहे वह कितना भी विस्तृत हो या वैचारिक और अनुभवजन्य रूप से कितनी भी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया हो, वह हमारे द्वारा दैनिक आधार पर अनुभव किए गए सभी पेचीदगियों के साथ दुनिया का एक बेहद सरलीकृत प्रतिनिधित्व है। उदाहरण के लिए, फिलिप्स वक्र का स्लोप या ब्याज की प्राकृतिक दर अनिश्चित है। यह अपने आप में नीति निर्माण में अनिश्चितता का परिचय देता है। डेटा को लेकर भी अनिश्चितता है। अनिश्चितता के साथ-साथ, जहां हम किसी परिणाम की संभावना की भविष्यवाणी करने में असमर्थ हैं, हमारे पास अब अप्रत्याशितता भी है, जहां परिणामों की भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती है। इससे मौद्रिक नीति बनाना और भी कठिन हो जाता है।

चूंकि, अनिश्चितता मौद्रिक नीति के लिए प्रमुख मद है, इसलिए हमारे नीति-निर्माण के व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं बदलते हैं। यह केवल उनका प्रयोग है, जो बदलता है।

पहला सिद्धांत **इष्टतमता की तुलना में सुदृढ़ता को प्राथमिकता देना है**। इसमें जोखिम प्रबंधन शामिल है। हम अनिश्चितताओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी संभावनाओं का आकलन करते हैं, उनके प्रभाव को मापते हैं और फिर एक ऐसी नीति तैयार करते हैं जो मूल्य स्थिरता और विकास के सर्वोत्तम नीतिगत परिणामों को बेहतर बनाती है।

इसके अतिरिक्त ध्यान में रखा जाने वाला एक अन्य सिद्धांत है **ब्रेनार्ड का क्षीणन का सिद्धांत**। यदि केंद्रीय बैंक अपने साधनों में परिवर्तन के प्रभाव के परिमाण के बारे में अनिश्चित है, तो उसे निश्चित परिणाम की तुलना में उस साधन को कम बदलना चाहेगा। दूसरे शब्दों में, यह क्रमिकता की नीति है। हालांकि, इस नियम के अपवाद हैं जैसा कि मुद्रास्फीति की दृढ़ता के मामले में होता है।

ब्रेनार्ड के सिद्धांत का एक परिणाम है। यदि ब्रेनार्ड सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय बैंक अनिश्चितता के दौरान प्रतिक्रिया नहीं करते हैं या धीरे-धीरे प्रतिक्रिया करते हैं, तो मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को प्रबंधित करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए, **मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को स्थिर करना** आवश्यक हो जाता है, जो एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसे हम भविष्य के लिए गाइडेंस प्रदान करने सहित विभिन्न साधनों के माध्यम से प्राप्त करते हैं।

हमारा चौथा मार्गदर्शी सिद्धांत **पारदर्शिता** है, जो पूर्वानुमेयता और विश्वसनीयता प्रदान करता है, और इस तरह प्रभावशीलता को बढ़ाता है। यह आर्थिक एजेंटों के मन से अनिश्चितता को भी दूर करता है।

अंत में, केंद्रीय बैंक की रणनीति और नीतिगत निर्णयों का **स्पष्ट संचार**, मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली आधार है। यह दृष्टिकोण की स्पष्टता लाता है और इस प्रकार पारदर्शिता को बेहतर बनाने और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को स्थिर करने में मदद करता है।

वर्तमान संकट की बात करें तो यह हमें विशेष रूप से प्रभावित करता है क्योंकि पश्चिम एशिया हमारे निर्यात का लगभग छठा हिस्सा, हमारे आयात का पांचवां हिस्सा, कच्चे तेल के आयात का आधा, हमारे उर्वरकों के आयात का दो-पांचवां हिस्सा और हमारे आवक विप्रेषण का लगभग दो-पांचवां हिस्सा देता है। इस तरह की आपूर्ति के आघातों के लिए उचित मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया पहले दौर के प्रभाव को इस हद तक देखना है कि यह दूसरे दौर की गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता हो। दूसरे दौर के प्रभाव वास्तविक चिंता का विषय हैं। यदि आपूर्ति शृंखला में व्यवधान लंबे समय तक जारी रहता है तो वे अमल में लाए जा सकते हैं। फिर, आपूर्ति के आघातों के रूप में जो शुरू हुआ वह सामान्य मूल्य स्तर में अंतर्निहित हो सकता है। ऐसे में मौद्रिक नीति की प्राथमिक भूमिका कुंद मांग संपीड़न के बजाय मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं पर इसके प्रभाव के माध्यम से इस अवरोध को रोकना है ।

इसके अलावा, इस तरह के अनिश्चित समय में, **चुस्त और फुर्तीला होना, व्यापक नीतिगत रुख बनाए रखना** और नीति के भविष्य के मार्ग की दृढ़ प्रतिबद्धताएं बनाने से बचना महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थितियों में, हमारा व्यापक दृष्टिकोण और भी अधिक डेटा पर निर्भर होना और जोखिमों के संतुलन का लगातार पुनर्मूल्यांकन करना रहा है। इसलिए हम अब वेट एंड वॉच मोड में हैं। इसके अलावा, हम पिछले कुछ नीतिगत समीक्षाओं से तटस्थ रुख बनाए हुए हैं। यह मुद्रास्फीति-वृद्धि की गतिशीलता के विकसित होने पर प्रतिक्रिया करने के लिए लचीलेपन को संरक्षित करता है।

महामारी से लेकर यूक्रेन युद्ध तक लगातार आघातों से निपटने में एफआईटी के साथ हमारा एक दशक का अनुभव बताता है कि इसने हमारी अच्छी सेवा की है।

जब से हमने एफआईटी को अपनाया है, हमारी औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.7% (सितंबर 2016 से दिसंबर 2025) तक गिर गई है, जो पिछले वर्षों (अप्रैल 2012 से अगस्त 2016) में 7.4% से कम है।

इसके अलावा, हेडलाइन मुद्रास्फीति की अस्थिरता उसी अवधि में 2.4% से 1.7% तक कम हो गई।

मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएँ बेहतर रूप से सुदृढ़ और कम अस्थिर हैं।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में भी, एफआईटी ढांचा सफल रहा है। 2006-2015 के दौरान एई और ईएमडीई दोनों के बीच उच्चतम औसत मुद्रास्फीति से, भारत में मुद्रास्फीति पिछले दशक के दौरान ईएमडीई के औसत से नीचे आ गई है।

यह उल्लेख करना भी उचित है कि कोविड और यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के बाद, भारत में मुद्रास्फीति कई उन्नत देशों की तुलना में तेजी से लक्षित हो गई।

मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने में राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय की भूमिका

यद्यपि हम मूल्य स्थिरता में सुधार के लिए मौद्रिक नीति और लोचनीय मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को श्रेय देते हैं, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस संबंध में राजकोषीय नीति की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। यह विशेष रूप से हमारे जैसे देश में है, जहां आपूर्ति पक्ष के कारक मुद्रास्फीति में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं।

सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कीमतों के दबाव को रोकने के लिए आपूर्ति पक्ष के उपायों के साथ मौद्रिक नीति कार्रवाइयों को जोड़ा है। पहला, सरकार ने कृषि में सुदृढ़ता स्थापित करने और बरसाती तथा फसल रोगों की अनिश्चितताओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को कम करने को प्राथमिकता दी है। यह सिंचाई के तहत अधिक भूमि, बेहतर बीज; फसल प्रबंधन और कटाई के बाद की प्रथाओं को शामिल करके प्राप्त किया गया है। दूसरा, सरकार ने कीमतों के दबाव के समय में उपयोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के लिए खुदरा वितरण नेटवर्क बनाने के अलावा, भंडारण और आपूर्ति शृंखला के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। तीसरा, इसने ईंधन की कीमतों की अस्थिरता को कम करने के लिए तेल पर उत्पाद शुल्क का उपयोग एक साधन के रूप में किया है।

मौजूदा संकट के दौरान तेल और गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। आयात के स्रोतों में विविधता लाई जा रही है। हालांकि तेल की कोई कमी नहीं है, हमारे द्वारा बनाए गए भंडार को देखते हुए, औद्योगिक प्रयोजनों के लिए गैस की कुछ राशनिंग की गई है। तेल विपणन कंपनियों और सरकार ने उपभोक्ताओं पर गैस पर कुछ मूल्य दबावों को डालते हुए तेल में मूल्य दबावों को अवशोषित कर लिया है।

इसके अलावा, हाल के वर्षों में कर संग्रह में बढ़ी हुई दक्षता और व्यय की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से राजकोषीय समेकन में लगातार प्रगति हुई है।

राजस्व पक्ष पर, जीएसटी को अपनाने और डिजिटलीकरण, सरलीकरण, युक्तिकरण और कर मूल्यांकन तथा संग्रह में मानव इंटरफ़ेस को कम करने सहित आयकर में व्यापक सुधारों ने कर वृद्धि में सुधार करने में मदद की है।[3] 2018-19 से 2025-26 तक जीएसटी के बाद आठ साल की अवधि में सकल जीएसटी वृद्धि (केंद्र और राज्य राजस्व) 1.23 है। कॉरपोरेट कर की दर कम होने और व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि के बाद से कॉरपोरेट कर में वृद्धि आम तौर पर एक से अधिक रहा है और पिछले पांच वर्षों में व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि औसतन 1.7 रहा है।

व्यय पक्ष पर भी, सरकारी खर्च को बेहतर लक्षित किया जाता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जिससे लगभग 50 बिलियन अमरीकी डालर (मार्च 2024 तक)[4] की बचत होने का अनुमान है; सार्वजनिक वितरण योजना जैसे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का डिजिटलीकरण; और राज्य सरकारों को निधियों का समय पर प्रवाह व्यय दक्षता बढ़ाने के कुछ उदाहरण हैं। महामारी के प्रति इसका दृष्टिकोण एक उदाहरण

[3] कर वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत परिवर्तन के सापेक्ष कर राजस्व में % परिवर्तन के अनुपात के रूप में मापा जाता है।

[4] https://dbtbharat.gov.in/static-page-content/spagecont?id=18

[5] आईएमएफ राजकोषीय मॉनिटर, अप्रैल 2026।

है। फ्रंट-लोडिंग प्रोत्साहन पैकेजों के बजाय, जैसा कि अधिकांश देशों ने किया था, भारत ने समाज के कमजोर वर्गों और छोटी फर्मों का समर्थन करने के लिए एक लोचनीय और चुस्त दृष्टिकोण अपनाया।

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 2021-22 में 13.6% से घटकर 2025-26 (आरई) में 10.8% हो गया। इसके विपरीत, पूंजीगत व्यय में भारी वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2019-20 में 1.7% से बढ़कर 2025-26 (आरई) में 3.1% हो गया है। राज्यों को सहायता में पूंजीगत अनुदान को शामिल करते हुए, यह बढ़कर 3.9% (आरई) हो गया है।

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा और जीडीपी अनुपात 2020-21 में 9.2% से घटकर 2025-26 (आरई) में 4.4% हो गया है। भारत का सामान्य सरकारी ऋण जीडीपी अनुपात 81.1% (2024-25 में) उचित है, जर्मनी और रूस[5] के अलावा दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं (यूएसडी में नाममात्र जीडीपी के संदर्भ में) में भारत की तुलना में अधिक ऋण अनुपात है।

II. वित्तीय स्थिरता

अब मैं वित्तीय स्थिरता पर आता हूं। यह वह आधार है जिस पर अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है और स्थायी रूप से बढ़ती है।

वित्तीय स्थिरता से जुड़ा हमारा निहितार्थ हमारे व्यापक नियामक ढांचे में विधिवत परिलक्षित होता है। हम दीर्घकालिक विकास के लिए कुछ अल्पकालिक लाभ का त्याग करने के लिए तैयार हैं। जबकि कुछ लोग इसे रूढ़िवाद के रूप में मानते हैं, हम मानते हैं कि यह विवेकपूर्ण है। यह विभिन्न संकटों के दौरान हमारी सुदृढ़ता से स्पष्ट होता है। मैं इसे कुछ उदाहरणों के साथ उजागर करूंगा।

जब 1997-98 में एशियाई वित्तीय संकट इस क्षेत्र में फैल गया, तो इसने उन मुद्राओं और अर्थव्यवस्थाओं को नीचे ला दिया, जिसे केवल महीनों पहले निर्यात के बढ़ावा देने वाले विकास के मॉडल के रूप में समझा जा रहा था। भारत ने तुलनात्मक स्थिरता की स्थिति से इसे देखा और इसके कारण आकस्मिक नहीं थे।

आरबीआई ने पूंजी खाते पर नियंत्रण बनाए रखा था, विशेष रूप से निवासियों के लिए। अल्पकालिक विदेशी ऋण को विदेशी मुद्रा भंडार से काफी नीचे के स्तर पर बनाए रखा गया था, जो आसानी से कवर कर सकता था। इसने उस तरह के अल्पकालिक विदेशी मुद्रा उधार की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसने हमारे क्षेत्रीय पड़ोसियों को अचानक इस भावना का सामना करना पड़ा। जब विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, तो आरबीआई ने कार्रवाई की - लेकिन इसने किसी ऐसी व्यवस्था को नहीं अपनाया जिसका बचाव करना मुश्किल हो। भारत का चालू खाता घाटा प्रबंधनीय था और विदेशी मुद्रा का जोखिम बना हुआ था। सबक यह है कि भारत के विकास के चरण में एक देश के लिए, पूंजी खाता उदारीकरण का अनुक्रमण कोई तकनीकी नहीं है – यह व्यापक आर्थिक संप्रभुता का पहला प्रश्न है।

यदि एशियाई संकट ने बाहरी अनुशासन के महत्व को प्रदर्शित किया, तो 2007-08 के सबप्राइम संकट ने आंतरिक अनुशासन बनाए रखने के महत्व को दर्शाया। वैश्विक वित्तीय प्रणाली 2000 के दशक के मध्य में अधिक विस्तृत और जटिल वित्तीय संरचना विकसित कर रही थी, आरबीआई कुछ ऐसा कर रहा था जो प्रचलित मानकों के आधार पर अलोकप्रिय लग रहा था। जब 2002 में, ब्याज दरें गिर रही थीं और बैंकों के पास वापसी की उम्मीद करने का कोई कारण नहीं था, तो आरबीआई ने उनसे ठीक उसी स्थिति के बदले निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व नामक एक काउंटर-साइक्लिकल बफर बनाने की मांग की। बाद में, वर्ष 2005-07 के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए जोखिम भारिता और प्रावधान संबंधी अपेक्षाएं बढ़ाई गई थीं। प्रतिभूतिकरण हेतु लाभ की मान्यता को प्रतिभूतियों की अवधि पर विस्तारित करना आवश्यक था। इसके अलावा, उस समय के लेखांकन मानकों ने अप्राप्त लाभ की मान्यता की अनुमति नहीं दी थी।

इनमें से कोई भी उस समय विशेष रूप से लोकप्रिय नहीं था। लेकिन जब वैश्विक वित्तीय प्रणाली दबाव में आ गई, तो इन उपायों को महत्व मिला। भारतीय बैंक अपेक्षाकृत सुदृढ़ तुलन पत्र के कारण संकट से बाहर आए।

हम वित्तीय स्थिरता को महत्व देना जारी रखते हैं। पिछले दशक में कई उपाय किए गए हैं। 2015 में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016; वैश्विक मानकों के अनुरूप विवेकपूर्ण मानदंडों का संरेखण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अभिशासन सुधार उनमें से कुछ हैं।

इनके कारण, हमारी वित्तीय प्रणाली आज बहुत मजबूत और आघात-सहनीय है, जिससे आर्थिक विकास का समर्थन होता है।

III. विकासात्मक भूमिका

मूल्य और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना अधिकांश केंद्रीय बैंकों के मुख्य दायित्व हैं लेकिन आरबीआई की भूमिका इन सीमाओं से परे है। हमारी विकासात्मक भूमिका बड़ी है।

आरबीआई ने वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने जन धन कार्यक्रम के लिए सरकार के साथ सहयोग किया, जिसे 2014 में मिशन मोड पर लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत आधार नामक डिजिटल पहचान और मोबाइल पहुँच का लाभ उठाते हुए, भारत ने पिछले दशक में मानव इतिहास में सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन अभियान चलाया। 570 मिलियन से अधिक बैंक खाते उन लोगों के लिए खोले गए जिनके पास कभी एक भी नहीं था। आज लगभग हर किसी के पास बैंक खाता है। इसने सरकारों से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सक्षम बनाया, जिसने बिचौलियों को दरकिनार कर दिया। इसने लीकेज को खत्म कर दिया। इस क्रांति ने लोगों को चुपचाप सशक्त बनाया।

RBI ने UPI के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बिना किसी समानता के एक सफलता की कहानी है। आज, दुनिया के वास्तविक समय के डिजिटल भुगतान की मात्रा में भारत की हिस्सेदारी लगभग आधी है। यूपीआई ने इस साल मार्च में 22 अरब से अधिक लेनदेन किए। आरबीआई के विकासात्मक जनादेश, एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, व्यापक मोबाइल स्वामित्व और कम लागत वाली डेटा पहुंच के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी उपस्थिति ने भारत को डिजिटल भुगतान में छलांग लगाने में मदद की। हम पहले ही यूपीआई को 8 देशों में स्वीकृति के साथ वैश्विक स्तर पर ले चुके हैं और अब इसे यूरोपीय सेंट्रल बैंक के टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम (टिप्स) सहित कई और देशों से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं।

हम वर्तमान में उधारदाताओं को डेटा तक तत्काल डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) का निर्माण कर रहे हैं, जिससे उन्हें छोटे किसानों और व्यवसाय मालिकों के लिए मिनटों के भीतर क्रेडिट योग्यता का आकलन करने की अनुमति मिलती है जिनके पास पहले दिखाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं थे या उन्हें बैंक में काफी समय और प्रयास खर्च करना पड़ता था।

हम अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) के साथ सीमाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें सीमा पार भुगतान को तेज और सस्ता करने की क्षमता है। हम विशिष्ट उपयोगों और उद्देश्यों के लिए भुगतान को निर्देशित करने के लिए प्रोग्रामेबिलिटी का भी परीक्षण कर रहे हैं।

हमारा विकासात्मक जनादेश समावेशी विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य में मदद करता है।

V. निष्कर्ष

अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन संयोग से नहीं है। यह मजबूत नीतिगत ढांचे के कारण है जिसे सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। यह मजबूत और विश्वसनीय संस्थानों के कारण है जिन्हें परिश्रमपूर्वक बनाया गया है। यह पिछले कुछ वर्षों में लगातार किए गए विभिन्न सुधारों के कारण है। यह स्थिरता और समावेशन की नींव पर टिका हुआ है।

इन शब्दों के साथ, मैं आप सभी को आपके धैर्यवान दर्शकों के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे प्रश्नों का उत्तर देने में खुशी होगी, यदि कोई हो।

*वित्त में एआई: क्या बदल सकता है, क्या कभी नहीं बदलना चाहिए**

श्री स्वामीनाथन जे.

शास्त्रा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस. वैद्यसुब्रमण्यम, सिटी यूनियन बैंक के बोर्ड के अध्यक्ष श्री जी. महालिंगम, सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ डॉ. एन. कामाकोडी, विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित संकाय सदस्य, कर्मचारी और प्रिय छात्रों, देवियों और सज्जनो। आप सभी को सुप्रभात।

शास्त्रा विश्वविद्यालय में श्री वी. नारायणन स्मृति व्याख्यान देना वास्तव में एक सम्मान की बात है। यह व्याख्यान श्रृंखला विशेष है क्योंकि यह न केवल एक व्यक्ति की याद दिलाती है, बल्कि बैंकिंग की एक समृद्ध परंपरा का उदाहरण है।

श्री वी. नारायणन को 1904 में कुंभकोणम में स्थापित सिटी यूनियन बैंक के एक परिवर्तनकारी नेता के रूप में याद किया जाता है, एक ऐसा शहर जिसके साथ मेरा भी व्यक्तिगत संबंध है। अक्सर एक 'स्टेट्समैन बैंकर' के रूप में वर्णित, उन्होंने संस्थागत दृष्टि को व्यक्तिगत गर्मजोशी के साथ, प्रगति के साथ विवेक और महत्वाकांक्षा को अपनी जड़ों के साथ जोड़ा।

उनके नेतृत्व में, सिटी यूनियन बैंक बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय संस्थान से व्यापक राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ विकसित हुआ। उन्होंने कर्मचारियों के विकास में निवेश किया, प्रणालियों को मजबूत किया, छोटे और मध्यम उद्यमों का दृढ़ता से समर्थन किया, और प्रौद्योगिकी को अपने समय से पहले बैंकिंग में ले कर आए।

फिर भी, परिवर्तन को अपनाते हुए भी, उन्होंने कभी भी बैंकिंग को अवैयक्तिक नहीं बनने दिया। मेरे विचार से, यही उनकी विरासत को हमारे समय के लिए इतना प्रासंगिक बनाता है।

हम वित्त में गहन बदलाव के एक और क्षण से गुजर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों की सेवा करने, दस्तावेजों को संसाधित करने, क्रेडिट का आकलन करने, जोखिमों की निगरानी करने और निरीक्षण को मजबूत करने के तरीके को नया आकार देना शुरू कर दिया है। उस परिवर्तन की गति उल्लेखनीय है। हमारे सामने असली सवाल यह नहीं है कि क्या वित्त अधिक बुद्धिमान हो जाएगा, बल्कि यह है कि क्या यह निष्पक्ष, जवाबदेह, समावेशी और मानवीय बना रहेगा।

इसलिए मैंने आज इस विषय पर बोलना उचित समझा: वित्त में एआई: क्या बदल सकता है, क्या कभी नहीं बदलना चाहिए। यह इस अवसर के लिए एक उपयुक्त विषय है।

यह सबसे पहले उपयुक्त है, क्योंकि शास्त्रा सहयोग, अनुसंधान और व्यावहारिक जुड़ाव के माध्यम से इस क्षेत्र में सचेत रूप से क्षमताओं का निर्माण कर रहा है। यह सामयिक और महत्वपूर्ण दोनों है। एक देश के रूप में, हमें अपनी अर्थव्यवस्था और समाज के अनुकूल एआई सिस्टम को डिजाइन, परीक्षण और नियंत्रित करने के लिए अपनी प्रतिभा, अपनी संस्थागत क्षमता और हमारे अपने नैतिक निर्णय की आवश्यकता होगी।

यह उचित है, दूसरा, क्योंकि श्री वी नारायणन, जिनकी स्मृति में आज हम एकत्र हुए हैं, प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग में विश्वास करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि प्रगति सही निर्णय पर टिकी रहे।

इसलिए, शास्त्रा जैसे संस्थानों की जिम्मेदारी केवल इंजीनियरों और पेशेवरों को तैयार करने के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य के जिम्मेदार बिल्डरों को आकार देने में मदद करने के लिए है।

एआई में अवसर

मैं उस अवसर से शुरुआत करता हूं जो वित्त के संबंध में एआई उपलब्ध कराता है। शुरुआत में, हालांकि, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस व्याख्यान का उद्देश्य एक तकनीकी प्रतिपादन नहीं है, जिसके लिए इस विश्वविद्यालय में निस्संदेह पर्याप्त प्रतिभा है। इसके बजाय मैं उन व्यापक प्रश्नों पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं जो एआई एक वित्तीय क्षेत्र के व्यवसायी के दृष्टिकोण से उठाता है।

वित्त, अपने सबसे अच्छे रूप में, अनिश्चितता को कम करता है और अवसर का विस्तार करता है। यह परिवारों को बचाने में मदद करता है, व्यवसायों को बढ़ाता है, किसानों को निवेश करता कराने

* XX CUB श्री वी. नारायणन स्मृति व्याख्यान, 11 अप्रैल, 2026, शनिवार को शास्त्रा विश्वविद्यालय, तंजावुर में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर स्वामीनाथन जे द्वारा दिया गया भाषण।

में, छात्रों को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में और उद्यमियों को थोड़ा बड़ा सपना देखने में मदद करता है।

फिर भी वित्त की भी अपनी बाधाएं हैं। यह भारी, भारी-दस्तावेजीकरण, भाषा-से बंधा हुआ और कभी-कभी पहुँच से दूर हो सकता है। भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में, प्रौद्योगिकी इनमें से कई कठिनाइयों को कम करने में मदद कर सकती है।

एआई-सक्षम सिस्टम ग्राहक संपर्क को सरल, अधिक सहज और अधिक प्रतिक्रियाशील बना सकते हैं। बहुभाषी चैटबॉट और आवाज-आधारित इंटरफेस उन ग्राहकों की मदद कर सकते हैं जो औपचारिक कागजी कार्रवाई या अंग्रेजी-भाषा इंटरफेस के साथ सहज नहीं हैं। नियमित प्रश्नों का उत्तर तेजी से दिया जा सकता है। शिकायतों को बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। जानकारी को अधिक स्पष्ट रूप से वितरित की जा सकती है। कई लोगों के लिए, यह औपचारिक वित्त सुलभता और अनजानेपन के एहसास के बीच के अंतर को कम कर सकता है।

एआई क्रेडिट डिलीवरी को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। पारंपरिक वित्त संपार्श्विक, वित्तीय विवरणों और मानकीकृत क्रेडिट टेम्पलेट्स पर निर्भर है। ये महत्वपूर्ण बने रहेंगे और जारी रहेंगे। हालांकि, वे हमेशा एक उधारकर्ता की पूरी कहानी नहीं दर्शाते हैं, विशेष रूप से छोटे व्यवसायों, अनौपचारिक उद्यमों, पहली बार उधार लेने वालों और अन्य लोग जिनका कम औपचारिक क्रेडिट इतिहास उपलब्ध है।

यदि एआई का जिम्मेदारी से उपयोग किया जाता है तो यह लेनदेन व्यवहार, पुनर्भुगतान प्रवाह और व्यावसायिक गतिविधि में पैटर्न के व्यापक सेट से अंतर्दृष्टि प्राप्त करके पारंपरिक तरीकों का पूरक हो सकता है। इससे व्यवहार्य उधारकर्ताओं की पहचान करने में मदद मिल सकती है जो अन्यथा बहिष्कृत रह सकते हैं। समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध देश के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है।

एआई धोखाधड़ी का पता लगाने और जोखिम प्रबंधन में भी सार्थक योगदान दे सकता है। आधुनिक वित्तीय प्रणालियाँ बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न करती हैं। एआई असामान्य पैटर्न की पहचान करने, संदिग्ध गतिविधि को चिह्नित करने और तेजी से हस्तक्षेप का समर्थन करने में मदद कर सकती है। यह भुगतान में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां जनता का विश्वास सुविधा और सुरक्षा दोनों पर निर्भर करता है। इस अर्थ में, एआई न केवल गति में, बल्कि सुरक्षा में भी योगदान दे सकती है।

अनुपालन और पर्यवेक्षण में एआई की भी भूमिका है। वित्तीय पर्यवेक्षण आज केवल आवधिक रिपोर्टिंग और पिछड़े दिखने वाले आकलन पर निर्भर नहीं हो सकता है। बुद्धिमान उपकरण बड़ी मात्रा में जानकारी का विश्लेषण करने, पैटर्न की पहचान करने, विसंगतियों पर ध्यान आकर्षित करने और प्रारंभिक चेतावनी का समर्थन करने में सहायता कर सकते हैं। अच्छी तरह से उपयोग किए जाने पर, ऐसे उपकरण संस्थानों को जोखिम को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं और पर्यवेक्षकों को उभरते मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बना सकते हैं।

चिंताएं

तो, वादा वास्तविक है। लेकिन, जैसा कि इतिहास ने साबित किया है, हर शक्तिशाली तकनीक एक दोधारी उपकरण है।

यदि एआई को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना अपनाया जाता है, तो यह मौजूदा कमजोरियों को बढ़ा सकता है और नुकसान के पूरी तरह से नए रूप पैदा कर सकता है। इसलिए, वित्त में एआई के बारे में बातचीत संतुलित होनी चाहिए। हमें न तो तकनीकी प्रचार में लिया जाना चाहिए और न ही रक्षात्मक होने के लिए पीछे हटना चाहिए।

मैं संक्षेप में पांच प्रमुख चिंताओं पर प्रकाश डालता हूं।

(i) पूर्वाग्रह और अनुचित परिणाम

पहला पूर्वाग्रह और अनुचित परिणाम है। एआई सिस्टम डेटा से सीखते हैं। लेकिन डेटा निर्वात से नहीं निकलता है। यह पिछले व्यवहार, मौजूदा असमानताओं और संरचनात्मक बहिष्करणों की छाप रखता है। यदि इन विकृतियों को डेटा में एम्बेडेड किया जाता है, तो उन्हें मॉडल द्वारा पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है, कभी-कभी और भी अधिक दक्षता और पैमाने के साथ।

क्रेडिट मूल्यांकन में, यह ऐसे परिणाम पैदा कर सकता है जिन्हें उचित ठहराना मुश्किल है और इसका पता लगाना कठिन है। सतह पर जो वस्तुनिष्ठ प्रतीत होता है, वह वास्तव में, सतह के नीचे अनुचितता का पोषण कर सकता है। वित्त में, यह केवल

एक तकनीकी चिंता नहीं है। यह उपभोक्ता संरक्षण, समावेशन और समानता का प्रश्न है।

(ii) कुछ प्रणालियों की ब्लैक बॉक्स प्रकृति

दूसरा है अस्पष्टता। कई उन्नत प्रणालियाँ ब्लैक बॉक्स की तरह काम करती हैं। वे एक आउटपुट का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इस तरह से नहीं जो एक ग्राहक, एक प्रबंधक या यहां तक कि एक नियामक के लिए समझ में आता है। लेकिन वित्त ब्लैक बॉक्स नहीं बन सकता। यदि किसी व्यक्ति को क्रेडिट से वंचित कर दिया जाता है, एक खाता फ्रीज कर दिया जाता है, एक लेनदेन गलत तरीके से चिह्नित किया जाता है, या एक उत्पाद को गलत तरीके से ग्राहक को धकेल दिया जाता है, तो संस्था को उस निर्णय के आधार की व्याख्या करने में सक्षम होना चाहिए। एक निर्णय जो किसी नागरिक के आर्थिक जीवन को भौतिक रूप से प्रभावित करता है, उसका बचाव यह कहकर नहीं किया जा सकता है, "मशीन ने फैसला किया।

(iii) डाटा गोपनीयता और दुरुपयोग।

तीसरी चिंता डेटा की गोपनीयता और दुरुपयोग है। एआई सिस्टम बड़ी मात्रा में डेटा पर निर्भर करते हैं, और वित्तीय डेटा व्यक्तिगत जानकारी के सबसे संवेदनशील रूपों में से एक है। इसलिए संस्थानों को सहमति, भंडारण, साझाकरण, अभिगम नियंत्रण और उद्देश्य सीमा के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। डेटा गवर्नेंस को एक साइड इश्यू के रूप में नहीं माना जा सकता है। एआई के युग में, विश्वास केंद्रीय हो जाता है।

(iv) मॉडल जोखिम

चौथी चिंता मॉडल जोखिम और एकाग्रता जोखिम है। पहले के युग में, एक कार्यालय में एक कमजोर निर्णय सीमित संख्या में खातों को प्रभावित कर सकता है। एआई युग में, एक त्रुटिपूर्ण मॉडल लाखों ग्राहकों के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, यदि कई संस्थान समान मॉडल, सामान्य डेटासेट, विक्रेताओं के एक छोटे से सेट या साझा बुनियादी ढांचे पर भरोसा करते हैं, तो व्यक्तिगत कमजोरियां सहसंबद्ध कमजोरियां बन सकती हैं। यह वह जगह है जहां एक स्थानीय कमजोरी भी व्यापक प्रणालीगत महत्व प्राप्त कर सकती है।

(v) साइबर जोखिम

पांचवीं चिंता साइबर जोखिम है। एआई सुरक्षा को मजबूत कर सकता है, लेकिन यह हमलावरों को भी लैस कर सकता है। धोखेबाज और बुरे काम करने वाले लोग एआई का उपयोग अधिक ठोस फ़िशिंग प्रयासों को तैयार करने, डीपफेक बनाने, सिस्टम की अधिक प्रभावी ढंग से जांच करने और दुर्भावनापूर्ण गतिविधि को स्वचालित करने के लिए कर सकते हैं। जैसे-जैसे वित्त अधिक डिजिटल और अधिक परस्पर जुड़ा हुआ होता है, लचीलापन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

मार्गदर्शक सिद्धांत

फिर हमारा मार्गदर्शन किसे करना चाहिए, क्योंकि हम पूर्ण पैमाने पर एआई अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? मेरे विचार में, पांच व्यापक सिद्धांतों को वित्त में एआई के जिम्मेदार उपयोग को आकार देना चाहिए:

सबसे पहले, मानवीय जिम्मेदारी केंद्रीय रहनी चाहिए। एआई निर्णय लेने में सहायता कर सकता है, लेकिन जवाबदेही मनुष्यों और संस्थानों के साथ रहनी चाहिए। एक बैंक या एनबीएफसी एक एल्गोरिदम, एक विक्रेता या एक प्लेटफॉर्म को जिम्मेदारी आउटसोर्स नहीं कर सकता है। प्रौद्योगिकी गति और पैमाने पर जानकारी को संसाधित करने में मदद कर सकती है, लेकिन निर्णय और जिम्मेदारी को वहीं रहना चाहिए जहां वे हैं।

दूसरा, निष्पक्षता और व्याख्या को शुरू से ही सिस्टम में बनाया जाना चाहिए। उन्हें वैकल्पिक अतिरिक्त चीज के रूप में नहीं माना जा सकता है। विभिन्न हितधारकों को विभिन्न प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है।

ग्राहक एक महत्वपूर्ण निर्णय के लिए एक स्पष्ट और समझने योग्य कारण का हकदार है। प्रबंधन को यह समझने की जरूरत है कि मॉडल कैसे व्यवहार करता है, इसकी सीमाएं कहां हैं और कौन सी धारणाएं इसे चलाती हैं। पर्यवेक्षकों को विश्वास की आवश्यकता होती है कि सिस्टम मजबूत, ऑडिट योग्य और अच्छी तरह से शासित हैं। मुद्दा हर मॉडल को सरल बनाने का नहीं है। मुद्दा यह सुनिश्चित करना है कि यह उचित स्तर पर समझ में आता रहे।

तीसरा, मजबूत डेटा गवर्नेंस आवश्यक है। संस्थानों को डेटा के पूर्ण जीवनचक्र के बारे में ध्यान से सोचना चाहिए: इसे कैसे एकत्र किया जाता है, इसका उपयोग किस आधार पर किया जाता है, इसे कितने समय तक बनाए रखा जाता है, इसे कौन एक्सेस कर सकता है और इसे कैसे संरक्षित किया जाता है। गोपनीयता और नवाचार को पारस्परिक रूप से विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जो संस्थाएं टिकी हैं, वे ऐसी संस्थाएं होंगी जो दोनों में सामंजस्य बिठाना सीखती हैं।

चौथा, संस्थागत क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए। वित्त में एआई केवल एक प्रौद्योगिकी चुनौती नहीं है। यह एक शासन, क्षमता और सांस्कृतिक चुनौती भी है। बोर्डों और वरिष्ठ प्रबंधन को सही प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त समझने की आवश्यकता है। जोखिम प्रबंधकों को यह जानने की जरूरत है कि क्या मान्य करना है। पर्यवेक्षकों को एआई-सक्षम प्रणालियों की बुद्धिमानी से जांच करने की क्षमता की आवश्यकता होती है और विश्वविद्यालयों को ऐसे स्नातकों का उत्पादन करने की आवश्यकता है जो न केवल तकनीकी रूप से सक्षम हों, बल्कि नैतिकता, विनियमन और सार्वजनिक उद्देश्य के प्रश्नों के प्रति भी जीवित हों।

पांचवां, समावेशन का एक डिजाइन उद्देश्य होना चाहिए, न कि एक आकस्मिक उप-उत्पाद। पैमाने का मतलब अपने आप में समावेशन नहीं है। हमें एक कठिन प्रश्न पूछना चाहिए: कौन अभी भी छूटा हुआ है? सबसे अच्छा नवाचार वह नहीं है जो पहले से ही अच्छी तरह से सेवा करने वालों को चकाचौंध कर दे। सबसे अच्छा नवाचार वह है जो भूगोल, भाषा, साक्षरता, आयु या आय के कारण औपचारिक वित्त को सरल, सुरक्षित और उन लोगों के लिए अधिक उपयोगी बनाता है जो हाशिए पर हैं। यदि एआई उन अंतरालों को पाटने में मदद करता है, तो यह समावेशन को आगे बढ़ाता है। यदि यह चुपचाप बहिष्करण को गहरा करता है, तो हम इसके डिजाइन में विफल हो जाते। जैसा कि मैंने पहले कहा है, समावेशन नवाचार का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए[1]।

भारत में, वित्त में एआई के वास्तविक मूल्य को तीन परीक्षणों द्वारा आंका जाना चाहिए।

i. क्या यह समावेशन को आगे बढ़ाता है?

ii. क्या यह दक्षता में सुधार करता है?

iii. क्या यह विश्वास को मजबूत करता है?

यदि यह इन तीन चीजों को सकारात्मक रूप से करता है, तो यह एक सार्थक सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो केवल इसके परिष्कार से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए।

श्री नारायणन से सबक

इस बिंदु पर, मैं श्री वी नारायणन पर दुबारा बात करूंगा।

जो लोग उन्हें जानते थे वे याद करते हैं कि उन्होंने अपने समय से आगे के बारे में सोचा था। उन्होंने कई तुलनीय संस्थानों की तुलना में बैंकिंग में प्रौद्योगिकी को पहले ही लाया। फिर भी उन्होंने एक मानवीय स्पर्श भी बनाए रखा, खासकर छोटे और मध्यम उद्यमों के साथ संबंधों को उधार देने में। वह संयोजन गहराई से शिक्षाप्रद है। वह तकनीक और रिश्तों के बीच चयन नहीं कर रहा था। वह दिखा रहा था कि प्रगति और मानवीय निर्णय को कैसे एक साथ चलना चाहिए।

उनके साथ अक्सर जुड़ी एक पंक्ति इसे खूबसूरती से दर्शाती है: "बैंक का ख्याल रखें; बैंक आपका ख्याल रखेगा। यह एक सरल कथन है, लेकिन इसमें एक गहन संस्थागत नैतिकता शामिल है। यह प्रबंधन की बात करता है। यह हमें याद दिलाता है कि संस्थान तब फलते-फूलते हैं जब लोग उन्हें न केवल लेनदेन या रोजगार के स्थलों के रूप में मानते हैं, बल्कि विश्वास के भंडार के रूप में भी मानते हैं। यह अंतर्दृष्टि एआई के युग में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी बहीखातों और शाखा के रजिस्टरों के युग में थी।

श्री नारायणन के जीवन से यह सबक मिलता है कि वित्त में तकनीकी परिवर्तन को प्रबंधन, विश्वास और जिम्मेदारी पर आधारित रहना चाहिए।

बैंकिंग, मूल रूप से विश्वास का व्यवसाय है। एक वित्तीय संस्थान एक कठिन तिमाही, एक परिचालनगत गलती या यहां तक कि एक रणनीतिक झटके से भी बच सकता है। लेकिन यह विश्वास की हानि से आसानी से बच नहीं सकता। यही कारण है कि वित्त में नवाचार को हमेशा ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही के अधीन रहना चाहिए।

छात्रों की भूमिका

इस हॉल में छात्रों के लिए, यह कोई दूर का मुद्दा नहीं है। जब तक आप में से कई लोग करियर के मध्य में होंगे, तब तक एआई वित्तीय दुनिया के लगभग हर हिस्से में बुना जा चुका होगा।

मेरा सुझाव है कि आप इन उपकरणों को गहराई से सीखें। तकनीक को गंभीरता से समझें। कठोरता और जिज्ञासा के साथ तकनीकी क्षमता का निर्माण करें। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने साथ नैतिकता, पारदर्शिता और सार्वजनिक हित के लिए समान रूप से गहरी प्रतिबद्धता भी लेकर चलें।

[1] स्वामीनाथन जे, "समावेशन नवाचार का सर्वोच्च उद्देश्य है: भारत से सबक," भारतीय रिजर्व बैंक, 15 अक्टूबर 2025, https://rbi.org.in/scripts/BS_SpeechesView.

एआई द्वारा आकार दी गई दुनिया में, नैतिकता के बिना तकनीकी उत्कृष्टता बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आपकी पीढ़ी की असली परीक्षा यह नहीं होगी कि आप शक्तिशाली सिस्टम बना सकते हैं या नहीं। यह होगा कि क्या आप जनता के विश्वास के योग्य सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं।

यदि भारत अपनी डिजिटल ताकत, उद्यमशीलता ऊर्जा, वैज्ञानिक प्रतिभा और संस्थागत ज्ञान को जोड़ सकता है, तो हम एक ऐसे वित्तीय क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल अधिक कुशल हो, बल्कि अधिक समावेशी, अधिक लचीला और अधिक भरोसेमंद भी हो। यही हमारी आकांक्षा होनी चाहिए। हमें अपने लिए प्रौद्योगिकी का अनुसरण नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे लोगों की सेवा में उपयोग करना चाहिए।

जवाबदेही के बिना बुद्धि अच्छे परिणाम नहीं लाएगी; इसे बेहतर और नैतिक निर्णय द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। इसलिए, हमारा प्रयास नवाचार को बढ़ावा देना होना चाहिए जो संस्थानों को लंबी अवधि के लिए मजबूत करता है।

निष्कर्ष

मैं इस विचार के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा।

हर पीढ़ी को कुछ शक्तिशाली उपकरण प्राप्त होते हैं। यह पीढ़ी डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बड़ी हुई है। इतिहास समाजों को उनके पास मौजूद उपकरणों के परिष्कार से नहीं, बल्कि उन मूल्यों से आंकता है जो उनके उपयोग को निर्देशित करते हैं।

यदि एआई अवसर को व्यापक बनाने, पहुंच में सुधार करने, विवेक को मजबूत करने, ग्राहकों की रक्षा करने और विश्वास को गहरा करने में मदद करता है, तो यह एक महान उद्देश्य की पूर्ति करेगा। दूसरी ओर, यदि यह जवाबदेही को कमजोर करता है, निर्णयों को अस्पष्ट करता है, कमजोर लोगों को बाहर करता है या वित्त को एक अवैयक्तिक ब्लैक बॉक्स में बदल देता है, तो यह हमें उन आदर्शों से दूर ले जाएगा जिनके लिए श्री वी. नारायणन जैसे बैंकर खड़े थे।

इसलिए, स्थायी कार्य वित्त को कम मानवीय बनाए बिना, अधिक बुद्धिमान बनाना है; इसे कम जवाबदेह बनाए बिना, इसे और अधिक डिजिटल बनाने के लिए; और इसे कम विवेकपूर्ण बनाए बिना, इसे और अधिक समावेशी बनाना है। संक्षेप में, यह वह है जो बदल सकता है और जिसे कभी नहीं बदलना चाहिए।

इस अवसर के लिए मैं आयोजकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं शास्त्रा, इसके संकाय और इसके छात्रों को उनके सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने में भगवान आपका मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जय हिंद।

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

*अर्थव्यवस्था की स्थिति**

पश्चिम एशिया में संघर्ष ने मार्च में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव को तीव्र कर दिया, हालांकि अप्रैल की पहली छमाही में कुछ राहत देखी गई। घरेलू आर्थिक गतिविधि ने कई खंडों में सुदृढ़ता दिखाई, जबकि कुछ अन्य खंडों में धीमी गति रही। ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों से संचालित सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च में थोड़ी बढ़ी। पश्चिम एशिया में अस्थायी युद्धविराम के बाद मुद्रा बाजार और बॉण्ड प्रतिफल में नरमी आई। आयात में धीमी गति और निर्यात में विस्तार के कारण व्यापार घाटा घटकर नौ महीने के निचले स्तर पर आ गया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के प्रवाह में उतार-चढ़ाव बना रहा, हालांकि फरवरी में निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) सकारात्मक हो गया ।

परिचय

पश्चिम एशिया में संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता की परीक्षा लेनी शुरू कर दी है, जो पहले से ही व्यापारिक तनावों से प्रभावित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से टैंकरों की आवाजाही पर लगभग पूर्ण विराम ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव को और बढ़ा दिया है। संघर्ष की अवधि और तीव्रता ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यापक व्यवधानों और ऊर्जा की ऊंची कीमतों के मध्य वैश्विक विकास की संभावनाओं के लिए काफी अनिश्चितता पैदा कर दी है।

वैश्विक आर्थिक गतिविधि मंद पड़कर 11 महीने के निचले स्तर पर आ गई, क्योंकि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में गति कमजोर पड़ गई। कीमती धातुओं को छोड़कर, वैश्विक पण्य कीमतों में तेजी से उछाल आया और यह तेजी व्यापक स्तर पर देखी गई। कच्चे तेल के मूल्य 31 मार्च को बहु-वर्षीय उच्च स्तर 118.4 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल को छू गए और उच्च बने हुए हैं।[1] हाल ही में, अप्रैल की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह का युद्धविराम हुआ, जिससे तनाव कुछ हद तक कम हुआ और वस्तु मूल्य अपने हाल के शिखर स्तर से नीचे आए, हालांकि वे अभी भी ऊंचे बने हुए हैं। उच्च कीमतों द्वारा क्रय क्षमता के ह्रास और आस्ति मूल्यों में कमजोरी को लेकर चिंताओं के कारण उपभोक्ता के रुख में भारी गिरावट आई हैं।[2] व्यापारिक आशावाद भी मार्च में पांच महीने के निचले स्तर पर गिर गया, जो 2020 में महामारी के बाद से इसके सबसे कमजोर स्तरों में से एक है।[3] अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2026 में वैश्विक विकास में मंदी और मुद्रास्फीति में वृद्धि का अनुमान लगाया है। विकास में यह गिरावट और मुद्रास्फीति का दबाव उभरती बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है।[4]

वित्तीय बाजारों ने इन उथल-पुथल भरे विकासक्रमों को पर्याप्त रूप से समाहित कर लिया है। बढ़ी हुई अनिश्चितता के बीच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक इक्विटी सूचकांक गिरे हैं। अस्थायी युद्धविराम के कारण अप्रैल की शुरुआत में कुछ हद तक सुधार देखा गया। लगातार बनी हुई मुद्रास्फीति की चिंताओं के कारण मार्च में बॉण्ड प्रतिफल, विशेष रूप से अमेरिका में बढ़े , जबकि उभरते बाजारों में बॉण्ड प्रतिफल स्प्रेड में बढ़ोतरी हुई। मार्च में उभरते बाजारों में पूंजी प्रवाह में तेज गिरावट दर्ज की गई, जो महामारी के बाद से सबसे बड़ा बहिर्वाह है। मार्च में प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में मुद्रास्फीति का दबाव मजबूत हुआ और बढ़ी हुई अनिश्चितता के मद्देनजर केंद्रीय बैंकों ने मुख्य रूप से ब्याज दरों को यथावत रखा।

मार्च के लिए घरेलू उच्च-आवृत्ति संकेतक सामान्यतः वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आ रहे अवरोधों के प्रतिकूल प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा कुछ प्रमुख जोखिमों को नियंत्रित कर लिया गया है, जिससे पूरे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। समग्र मांग की स्थितियां सुदृढ़ बनी रहीं, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। जीएसटी राहत के प्रभाव के चलते ऑटोमोबाइल बिक्री और वाहन पंजीकरण मजबूत बने रहे। महीने के दौरान ई-वे बिल बनाने और

^ यह लेख राजीब दास, राधेश्याम वर्मा, शशि कांत, रजनी दहिया, श्रेया कंसल, ऊर्जा यादव, यामिनी झांब, विकास आनंद, भाग्यश्री चट्टोपाध्याय, नीलवा दास, गौतम, अनुपम कुमार, अमृता बसु, रागिनी, लव कुमार शांडिल्य, सिद्धार्थ आर्य, डी. सुगंथी, शिवम, अमन तिवारी, अमर जोश डुंगडुंग, विशाल मौर्य, अमित पवार, सुप्रियो मंडल, समृद्धि, अथिरा सी ए, पलक गोयल और सौरभ शर्मा द्वारा तैयार किया गया है। उप गवर्नर डॉ. पूनम गुप्ता द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन और टिप्पणियों को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाता है। आशीष थॉमस जॉर्ज, पी. बृजेश और सुब्रत कुमार सीत द्वारा सहकर्मी समीक्षा को भी स्वीकार किया जाता है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] 17 अप्रैल, 2026 तक ब्रेंट क्रूड जेनेरिक 1st फ्यूचर्स दैनिक क्लोजिंग कीमतों के आधार पर।

[2] यूनाइटेड स्टेट्स मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट, अप्रैल 2026।

[3] जेपी मॉर्गन ग्लोबल कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई), मार्च 2026।

[4] आईएमएफ का विश्व आर्थिक आउटलुक, अप्रैल 2026।

पेट्रोल व डीजल की खपत जैसे लॉजिस्टिक्स संकेतकों में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।

हालांकि, बंदरगाह माल ढुलाई, वायु यात्री यातायात और क्रय प्रबंधकों के दृष्टिकोण जैसे चुनिंदा संकेतकों में मंदी के प्रारंभिक संकेत स्पष्ट हैं। विनिर्माण पीएमआई, यद्यपि विस्तार के क्षेत्र में बना हुआ है, लेकिन लगभग चार वर्षों के निचले स्तर पर गिर गया है। लागत संबंधी दबावों और अनिश्चितताओं का असर नए आदेशों और उत्पादन पर पड़ा, जो 2022 के मध्य से सबसे धीमी दर से बढ़े हैं। सेवा क्षेत्र पीएमआई ने सुदृढ़ता दिखाई, हालांकि, विस्तार की गति 14 महीनों के निचले स्तर पर धीमी हो गई, जो नए कारोबार में नरमी को दर्शाती है। आठ कोर उद्योगों का सूचकांक भी गिरा, जो उर्वरकों, कच्चे तेल, कोयले और बिजली के उत्पादन में गिरावट के कारण 19 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया है।

कृषि के संबंध में, पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद निविष्टि आपूर्तियों को लेकर चिंताओं के बावजूद, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के लिए अनुकूल ग्रीष्मकालीन बुवाई ने धान की बुवाई में आई गिरावट की भरपाई कर दी है। चालू ग्रीष्मकाल के लिए जलाशयों में भंडारण स्तर पर्याप्त बने हुए हैं। वर्तमान में सार्वजनिक खाद्यान्न स्टॉक भी किसी भी आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए बफर मानदंडों से काफी ऊपर हैं। हालांकि, संभावित एल नीनो की स्थितियों के कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून में सामान्य से कम वर्षा की संभावना कृषि उत्पादन के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करती है।

मार्च में व्यापार घाटा संकुचित होकर नौ महीने के निम्नतम स्तर पर आ गया। क्रमिक आधार पर, मार्च 2026 में निर्यात में विस्तार हुआ, जबकि आयात में संकुचन दर्ज किया गया। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उस क्षेत्र से होने वाले निर्यात और आयात दोनों में गिरावट आई।

पश्चिम एशिया से आई ऊर्जा आघात के बावजूद, मार्च में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की समग्र मुद्रास्फीति में केवल मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जिसके साथ घरेलू एलपीजी की कीमतों में वृद्धि और खाद्य मुद्रास्फीति में तेजी के कारण ईंधन मुद्रास्फीति में भी इजाफा हुआ। ईंधन और बिजली की बढ़ती लागतों से संचालित थोक मुद्रास्फीति भी मार्च में पांचवें लगातार महीने बढ़ी। आपूर्ति पक्ष की बाधाओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा की गई त्वरित आपूर्ति प्रबंधन कार्रवाई ने मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित करने में सहायता की।[5]

तेजी से विकसित हो रही पृष्ठभूमि में, मौद्रिक नीति समिति ने अपनी अप्रैल 2026 की बैठक में नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखा और आने वाले आंकड़ों का जवाब देने के लिए लोचनीयता बनाए रखने के लिए "तटस्थ" रुख बनाए रखा।

मार्च की दूसरी छमाही में कर बहिर्वाह के कारण प्रणालीगत चलनिधि में कमी आई थी, हालाँकि अप्रैल में कर बहिर्वाह का दबाव कम होने और सरकारी व्यय में वृद्धि होने के साथ चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ। चलनिधि की इन स्थितियों के प्रतिबिंब के रूप में अप्रैल में भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) रेपो दर से नीचे चली गई। मार्च की दूसरी छमाही में कुछ बढ़ने के बाद अप्रैल में खजाना बिलों की प्रतिफल में नरमी आई। मार्च माह में वाणिज्यिक पत्रों पर प्रतिफल और जमा प्रमाणपत्रों पर ब्याज दरें ऊंची बनी रहीं, जिसके बाद अप्रैल में इनमें उल्लेखनीय नरमी आई। पश्चिम एशिया में संघर्ष छिड़ने के बाद वैश्विक रुझानों के आंशिक प्रतिबिंब के रूप में, मार्च में निर्धारित अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में वृद्धि हुई और अप्रैल में भी ये ऊंचे स्तर पर बनी रहीं। मौजूदा नरमी चक्र में ब्याज दरों तक बेहतर संचरण के साथ बैंक ऋण में वृद्धि उच्च रही है। वर्ष 2025-26 के दौरान, वाणिज्यिक क्षेत्र को कुल वित्तीय संसाधनों के प्रवाह में वृद्धि हुई, जिसमें सामान्य तौर पर ऋण प्रवाह में तेजी लाने में बैंक और गैर-बैंक दोनों स्रोतों का योगदान रहा।

मार्च में लगातार अनिश्चितता और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा बिकवाली के दबाव के बीच भारतीय इक्विटी बाजारों में गिरावट आई, हालांकि अस्थायी युद्धविराम की घोषणा और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने के बाद अप्रैल

[5] सरकार द्वारा किए गए कुछ आपूर्ति प्रबंधन उपायों में घरेलू और आवश्यक आवश्यकताओं के लिए एलपीजी वितरण को प्राथमिकता देना, रिफाइनरी उत्पादन में वृद्धि करना और घरेलू और वाणिज्यिक दोनों उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शनों को आसान बनाना शामिल है। पेट्रोल और डीजल के पंपों पर खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने 27 मार्च, 2026 से दोनों वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है।

में इनमें मध्यम सुधार हुआ। मार्च में निवल एफपीआई बहिर्वाह में तेजी से वृद्धि हुई और अप्रैल में भी निवल बिकवाली जारी रही। भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय आस्तियों में वृद्धि के समर्थन से 2025-26 की तीसरी तिमाही के दौरान भारत की निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) में सुधार हुआ।

मार्च में रुपये का मूल्यह्रास हुआ, लेकिन अस्थायी संघर्ष विराम की घोषणा और तटवर्ती और अपतटीय बाजारों के बीच सट्टा मध्यस्थता की स्थिति को कम करने के उद्देश्य से आरबीआई के उपायों ने अप्रैल की शुरुआत में मुद्रा को कुछ समर्थन प्रदान किया। भारत के प्रमुख बाहरी क्षेत्र के भेद्यता संकेतक दिसंबर 2025 के अंत तक नियंत्रित रहे और विदेशी मुद्रा भंडार 10 अप्रैल, 2026 तक अनुकूल बना रहा।

इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर, लेख के शेष भाग को चार खंडों में विभाजित किया गया है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे विकासों को कवर करता है। खंड III घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन प्रस्तुत करता है। खंड IV भारत में वित्तीय स्थितियों का सारांश प्रस्तुत करता है, जबकि खंड V निष्कर्षात्मक अवलोकन प्रस्तुत करता है।

II. वैश्विक परिस्थिति

पश्चिम एशिया में लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की स्थिति में, जो गंभीर आपूर्ति कमी से चिह्नित थी, वैश्विक विकास की संभावनाएं अनिश्चित बनी रहीं। अपने नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2026) में आईएमएफ ने संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाते हुए 2026 में वैश्विक विकास में कमी का अनुमान लगाया (सारणी II.1)। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद आपूर्ति में व्यवधान के बीच ऊर्जा की ऊंची कीमतों द्वारा संचालित, मुद्रास्फीति के अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित किया गया। विकास में धीमी गति और बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यस्थाओं (ईएमडीई) में अधिक स्पष्ट होने का अनुमान लगाया गया। साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से उत्पादकता लाभों के तेजी से साकार होने और व्यापार तनावों में निरंतर कमी के साथ विकास की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं।

सारणी II.1: आईएमएफ का जीडीपी वृद्धि अनुमान – चुनिंदा एई और ईएमडीई

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

के लिए अनुमान	2026		2027	
अनुमान का महीना	**जनवरी 2026**	**अप्रैल 2026**	**जनवरी 2026**	**अप्रैल 2026**
विश्व	**3.3**	**3.1**	**3.2**	**3.2**
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	**1.8**	**1.8**	**1.7**	**1.7**
अमेरिका	2.4	2.3	2.0	2.1
यूके	1.3	0.8	1.5	1.3
यूरो क्षेत्र	1.3	1.1	1.4	1.2
जापान	0.7	0.7	0.6	0.6
उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	**4.2**	**3.9**	**4.1**	**4.2**
रूस		1.1	1.0	1.1
उभरता और विकासशील एशिया	**5.0**	**4.9**	**4.8**	**4.8**
भारत#			6.4	6.5
चीन	4.5	4.4	4.0	4.0
लैटिन अमेरिका और कैरिबियन	**2.2**	**2.3**	**2.7**	**2.7**
मेक्सिको			2.1	2.2
ब्राज़ील	1.6	1.9	2.3	2.0
मध्य पूर्व और मध्य एशिया	**3.9**	**1.9**	**4.0**	**4.6**
सब-सहारा अफ्रीका	**4.6**	**4.3**	**4.6**	**4.4**
दक्षिण अफ्रीका	1.4	1.0	1.5	1.3

टिप्पणी : #: भारत का डेटा वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के आधार पर है, जबकि अन्य सभी देशों के लिए यह कैलेंडर वर्ष के आधार पर है।
स्रोत : आईएमएफ का विश्व आर्थिक परिदृश्य, अप्रैल 2026।

जैसे-जैसे अमेरिका-ईरान युद्ध एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में फैलता गया, मार्च में भू-राजनीतिक जोखिम में तेजी से वृद्धि हुई (चार्ट II.1ए)। संघर्ष के तीव्र होने के बाद, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता मार्च के दौरान 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, हालांकि अस्थायी युद्धविराम की खबरों पर अप्रैल में इसमें कमी आई (चार्ट II.1बी)। साथ ही, माल ढुलाई और शिपिंग मार्गों में व्यवधान, विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के कारण समुद्री यातायात लगभग ठप हो गया, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला दबाव जनवरी 2023 के बाद से अपने सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गए (चार्ट II.1सी)।

वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) मार्च में गिरकर 11 महीने के निचले स्तर पर आ गया, जो कमजोर व्यावसायिक अनुकूलता और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान को दर्शाता है। विनिर्माण और सेवा दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन विस्तार

चार्ट II.1: मार्च में भू-राजनीतिक जोखिम और आपूर्ति शृंखला दबाव में वृद्धि हुई

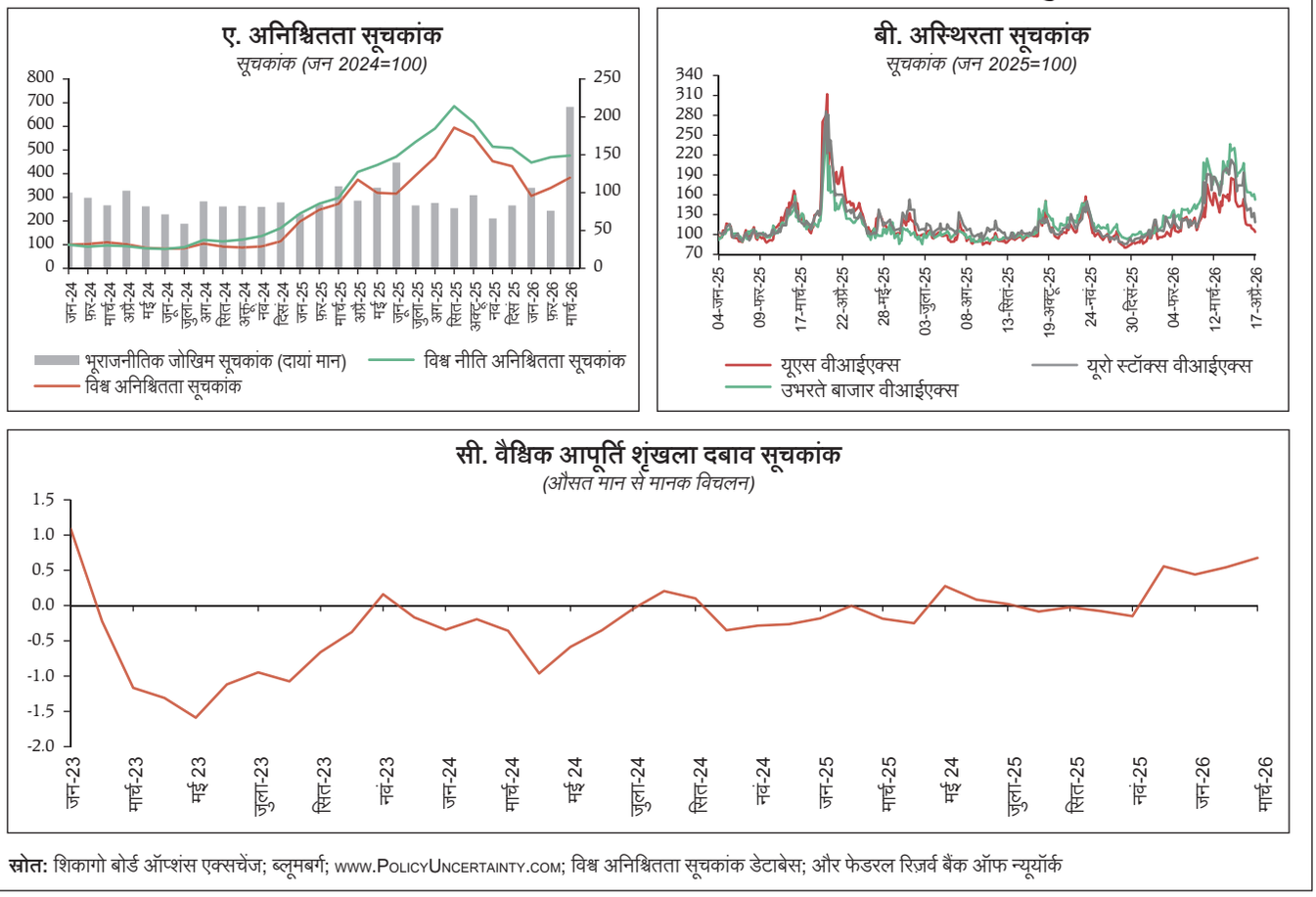

स्रोत: शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज; ब्लूमबर्ग; www.PolicyUncertainty.com; विश्व अनिश्चितता सूचकांक डेटाबेस; और फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क

की गति में कमी आई। निर्यात के नए आदेश अप्रैल 2025 के बाद पहली बार फरवरी 2026 में विस्तार दर्ज करने के उपरांत, मार्च में पुनः संकुचन में लौट आए (सारणी II.2)।

प्रमुख एई और ईएमडीई में व्यावसायिक गतिविधियों में व्यापक स्तर पर मंदी देखी गई (चार्ट II.2ए)। नए निर्यात आदेशों में रुझान क्षेत्रों के अनुसार भिन्न-भिन्न रहे, जहाँ अधिकांश एई में

सारणी II.2: मार्च में वैश्विक समग्र पीएमआई में नरमी आई

	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सितं-25	अक्टू-25	नवं-25	दिसं-25	जन-26	फर-26	मार्च-26
पीएमआई समग्र	52.1	50.8	51.2	51.7	52.5	52.9	52.5	53	52.7	52.0	52.5	53.3	51.0
पीएमआई विनिर्माण	50.3	49.8	49.5	50.4	49.7	50.9	50.7	50.9	50.5	50.4	50.9	51.9	51.3
पीएमआई सेवाएं	52.7	50.8	52	51.8	53.5	53.3	52.9	53.5	53.2	52.4	52.7	53.4	50.8
पीएमआई निर्यात आदेश	50.1	47.5	48.0	49.1	48.5	48.9	49.7	48.6	50.0	49.2	49.7	51.2	49.7
पीएमआई निर्यात आदेश : विनिर्माण	50.1	47.3	48.0	49.2	48.2	48.7	49.5	48.3	49.9	49.1	49.9	51.4	50.1
पीएमआई निर्यात आदेश : सेवाएं	50.1	48.2	47.9	48.7	49.4	49.3	50.2	49.4	50.2	49.6	49.0	50.6	48.3

50

<<<<<< संकुचन---------- विस्तार >>>>>>

टिप्पणीयाँ: 1. पीएमआई, एक प्रसार सूचकांक है, जो पिछले माह की तुलना में प्रत्येक चर में हुए परिवर्तन को दर्शाता है, यह बताते हुए कि प्रत्येक बढ़ा/सुधरा है, घटा/बिगड़ा है या अपरिवर्तित रहा है। 50 से अधिक का पीएमआई मान विस्तार को दर्शाता है; 50 से कम संकुचन को दर्शाता है; और 50 के बराबर 'कोई परिवर्तन नहीं' को दर्शाता है।

2. अप्रैल 2023 के बाद के आंकड़ों पर हीट मैप लागू किया गया है। इस मानचित्र में रंग कोड का प्रयोग किया गया है–लाल रंग प्रत्येक पीएमआई श्रृंखला में सबसे कम मान को दर्शाता है, पीला रंग 50 (या कोई परिवर्तन नहीं वाले मान) को दर्शाता है, और हरा रंग सबसे उच्च मान को दर्शाता है।

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल.

चार्ट II.2: पीएमआई: अधिकार-क्षेत्रों के बीच तुलना

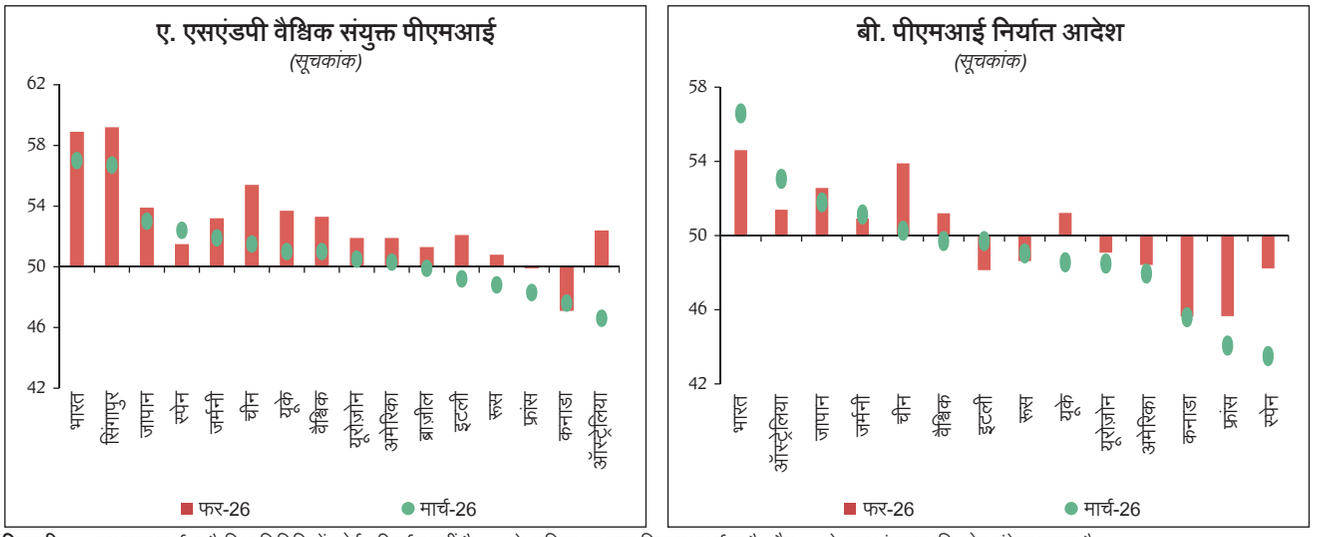

टिप्पणी: 50 का स्तर दर्शाता है कि गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं है, 50 से अधिक का मान विस्तार दर्शाता है और 50 से कम संकुचन की ओर संकेत करता है।
स्रोत: एस&पी ग्लोबल

आदेशों में संकुचन दर्ज किया गया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया, जापान और जर्मनी इसमें उल्लेखनीय अपवाद रहे। प्रमुख ईएमडीई में, भारत में निर्यात आदेशों में मजबूत गति से विस्तार हुआ, जबकि रूस में इनमें संकुचन देखी गई (चार्ट II.2बी)।

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टैंकर यातायात के रुकने से मार्च में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न हुआ। विश्व बैंक के वस्तु मूल्य सूचकांक में ऊर्जा और उर्वरक की कीमतों में वृद्धि के कारण तेज़ी से उछाल आया। खाद्य और कृषि संगठन के खाद्य मूल्य सूचकांक में प्रमुख वस्तु समूहों में व्यापक स्तर पर मुद्रास्फीति देखी गई (चार्ट II.3ए)। हालाँकि, मार्च में सोने की कीमतों में नरमी आई, क्योंकि बढ़े हुए मुद्रास्फीति के जोखिमों ने मौद्रिक नीति में ढील की उम्मीदों को मंद कर दिया और सुरक्षित निवेश की मांग अमेरिकी डॉलर और स्थिर आय वाली संपत्तियों की ओर स्थानांतरित हो गई। अप्रैल में, पश्चिम एशिया में हो रही घटनाओं के मद्देनज़र नीतिगत ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीदों के कारण सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रहा (चार्ट II.3बी)।

चार्ट II.3: मार्च में सामान्य तौर पर पण्य/खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज़ी आई

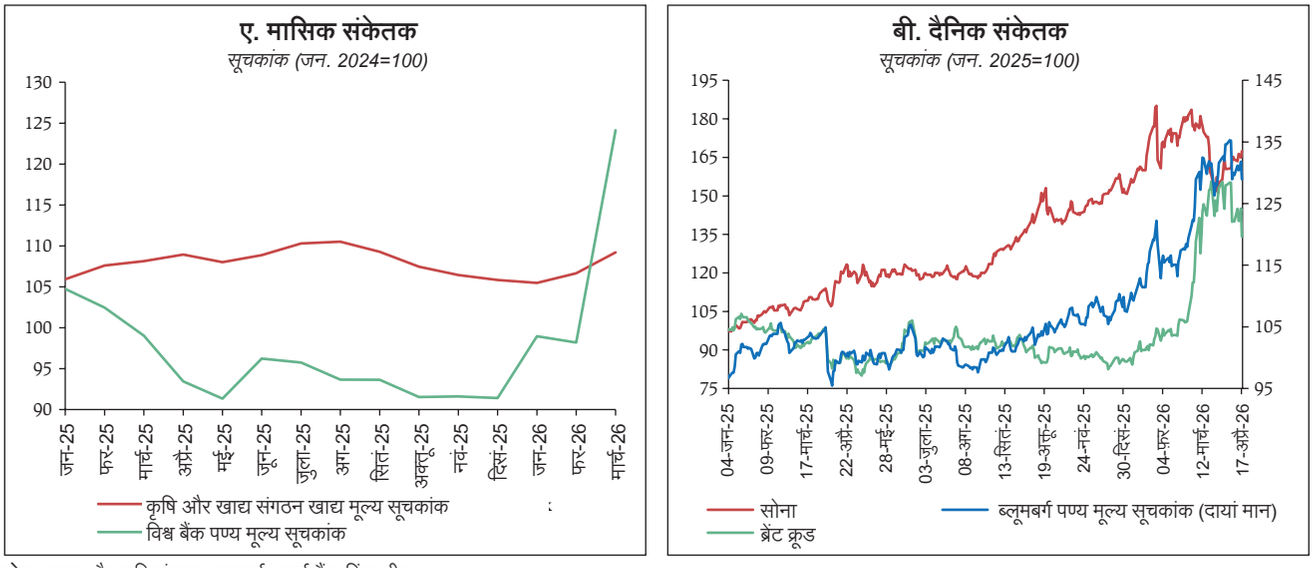

स्रोत: खाद्य और कृषि संगठन; ब्लूमबर्ग; वर्ल्ड बैंक पिंक शीट।

बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर, पश्चिम एशिया में संघर्ष में तेजी के मद्देनजर वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगीं और यह तेजी व्यापक स्तर पर देखी गई। ऊर्जा की कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि के कारण मार्च में ब्लूमबर्ग वस्तु सूचकांक में भारी उछाल आया और अप्रैल की शुरुआत तक यह ऊंचे स्तर पर बना रहा, हालांकि अस्थायी युद्धविराम के बाद इसमें कुछ कमी देखी गई। 31 मार्च को ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें चार साल के उच्चतम स्तर 118.4 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं और युद्धविराम के बावजूद कुछ गिरावट के बाद भी ऊंचे स्तर पर बनी रहीं (चार्ट II.3बी)। क्षेत्र में एल्युमीनियम स्मेल्टरों पर हमलों के कारण आपूर्ति की कमी के कारण एल्युमीनियम की कीमतों में वृद्धि हुई। गैसोलीन और एलपीजी की कीमतों में तेज वृद्धि के साथ-साथ विमानन ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई, जो आंशिक रूप से रिफाइनरी के कामकाज में रुकावट को दर्शाती है। अप्रैल में, विमान ईंधन और गैसोलीन की कीमतें ऊंची रहीं, हालांकि एलपीजी की कीमतें अपने चरम से कम हो गईं। पश्चिम एशिया सल्फर और यूरिया का प्रमुख उत्पादक होने के नाते, इस क्षेत्र में आपूर्ति में व्यवधान के कारण उर्वरक की कीमतों में वृद्धि हुई (चार्ट II.4)।

मार्च में, प्रमुख एई में हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, क्योंकि प्रमुख शिपिंग मार्गों में व्यवधान और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि ने आपूर्ति-पक्ष के दबावों को नवीनीकृत किया। प्रमुख एई में, अमेरिका और यूरो क्षेत्र में मुद्रास्फीति में तेजी आई, जो बड़े पैमाने पर उच्च ऊर्जा कीमतों से प्रेरित थी(चार्ट II.5ए)। प्रमुख ईएमडीई में, मुद्रास्फीति के रुझान मिश्रित रहे। चीन में मुद्रास्फीति कम हो गई, जबकि ब्राजील में ईंधन की ऊंची कीमतों के कारण इसमें वृद्धि हुई (चार्ट II.5बी)।

मार्च में, संघर्ष को लेकर बढ़ी हुई अनिश्चितता और नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की कम होती उम्मीदों के बीच, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक इक्विटी बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। विशेष रूप से, जापान में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई, जहां एआई से जुड़े सकारात्मक रुख से पहले जो लाभ हुए थे, वे लाभ बुकिंग

चार्ट II.4: पश्चिम एशिया में लगातार तनाव के बीच पण्य की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहीं

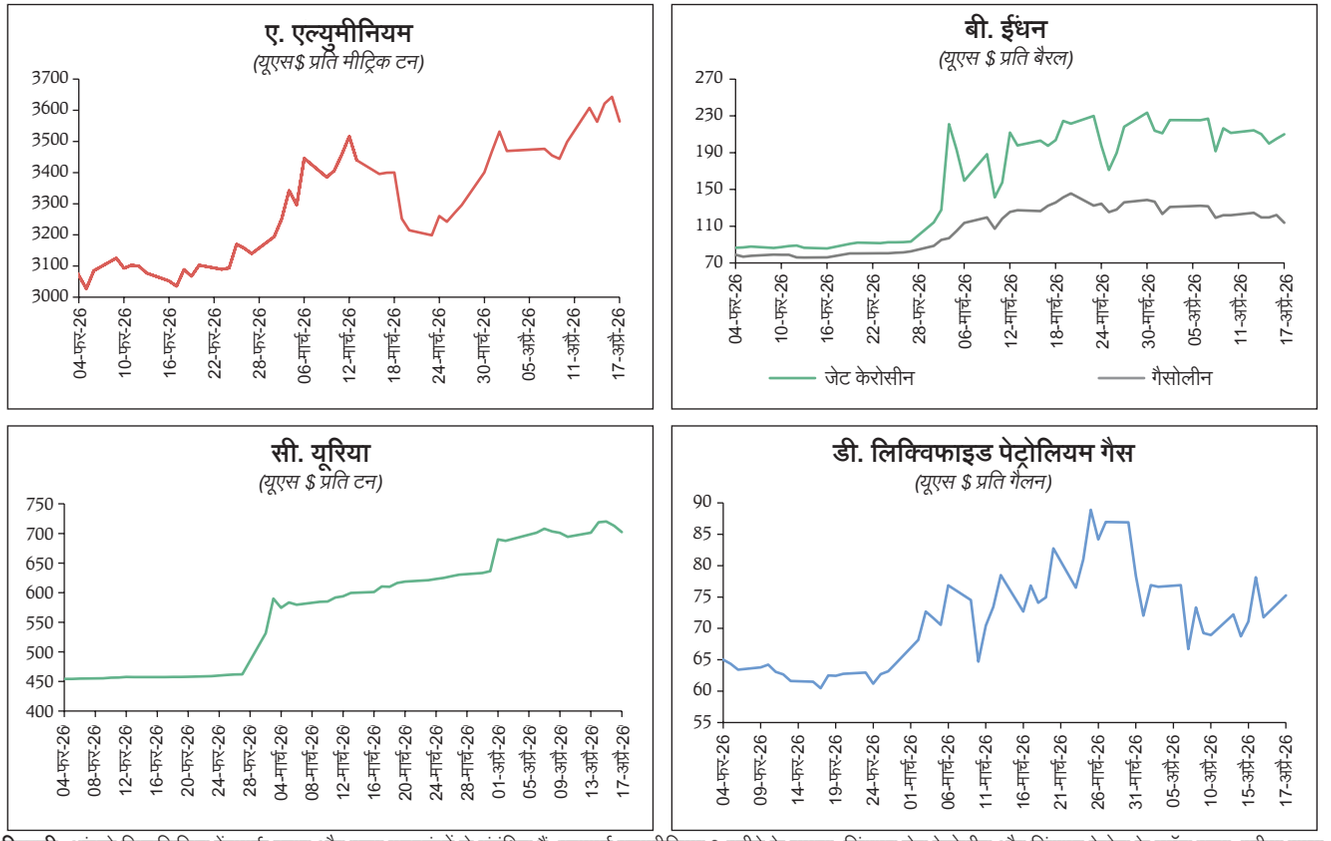

टिप्पणी: आंकड़े निम्नलिखित बेंचमार्क करार और मूल्य सूचकांकों से संबंधित हैं: एलएमई एल्युमीनियम 3-महीने के वायदा; सिंगापुर जेट केरोसीन और सिंगापुर पेट्रोल के स्पॉट मूल्य; यूरीया यूएस गल्फ वायदा; और मोंट बेल्वियू प्रोपेन निश्चित मूल्य वायदा (एलपीजी)।
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट II.5: प्रमुख एई और ईएमडीई में हेडलाइन मुद्रास्फीति

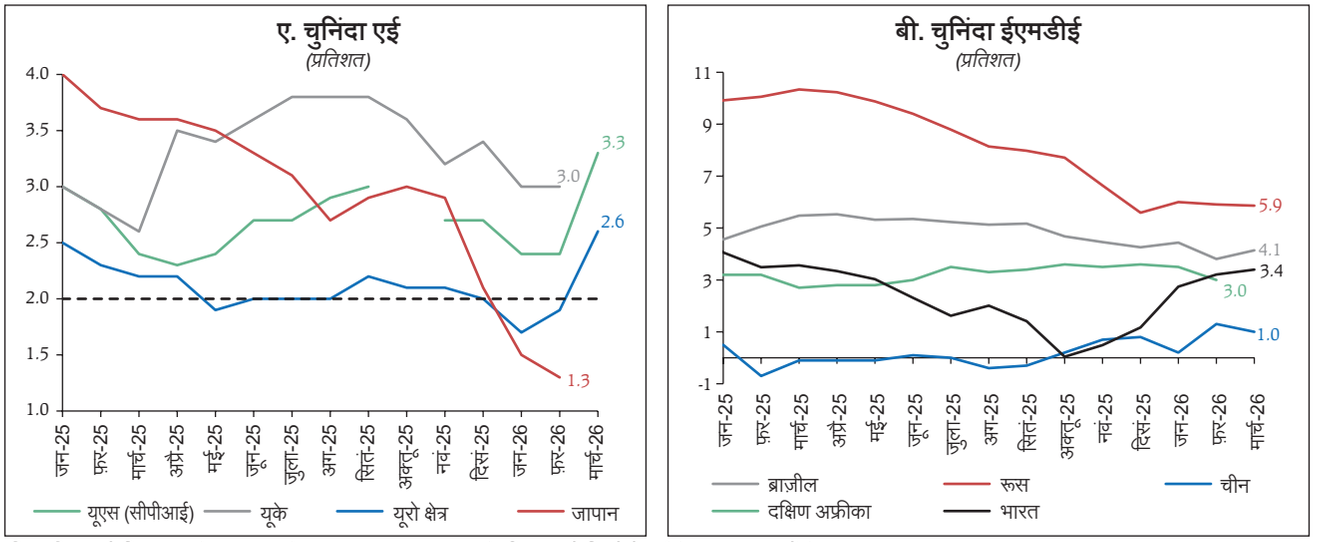

टिप्पणी: अमरीकी सरकार के शटडाउन के कारण अक्तूबर-25 2025 के लिए अमरीकी सीपीआई डेटा उपलब्ध नहीं है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग: और ओईसीडी ।

और बढ़ते वैश्विक जोखिम से बचने के रुझान के कारण आंशिक रूप से समाप्त हो गए। अप्रैल में अब तक, संघर्ष में कमी के संकेतों के बीच बाजारों ने अपनी पिछली हानि का कुछ हिस्सा वापस पा लिया है (चार्ट II.6ए)।

चार्ट II.6: वैश्विक वित्तीय बाज़ार

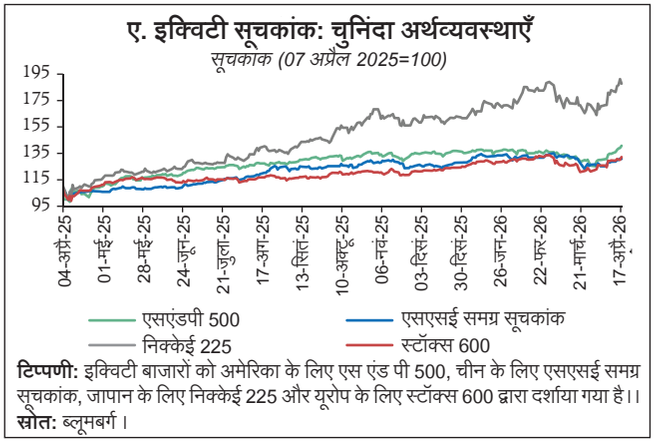

टिप्पणी: इक्विटी बाजारों को अमेरिका के लिए एस एंड पी 500, चीन के लिए एसएसई समग्र सूचकांक, जापान के लिए निक्केई 225 और यूरोप के लिए स्टॉक्स 600 द्वारा दर्शाया गया है।।
स्रोत: ब्लूमबर्ग ।

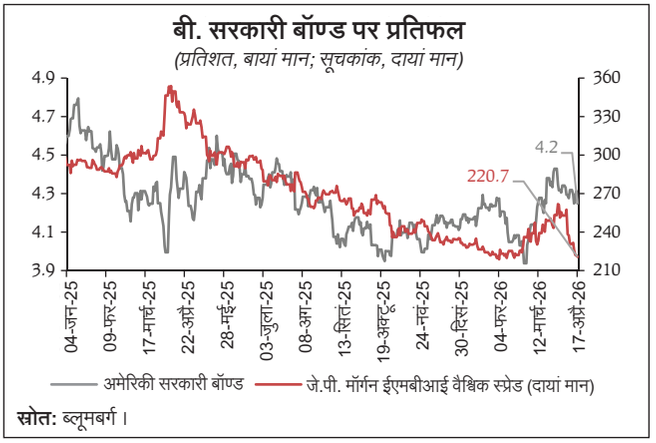

स्रोत: ब्लूमबर्ग ।

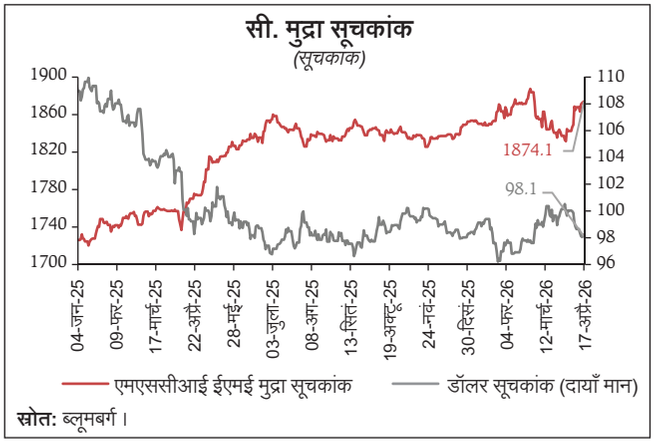

स्रोत: ब्लूमबर्ग ।

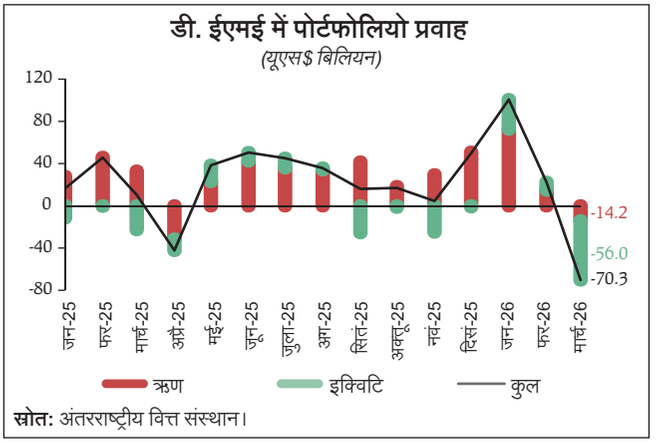

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान।

मार्च में, बढ़ती मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कम होने के कारण, सुरक्षित निवेश की मांग के बावजूद अमेरिकी 10-वर्षीय खजाना बॉण्ड की प्रतिफल में वृद्धि हुई। अप्रैल में, भू-राजनीतिक तनाव में कमी और अमेरिका-ईरान वार्ता की नई उम्मीदों के कारण मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएं कम हुईं, जिससे प्रतिफल में नरमी आई। उभरते बाजारों के बॉण्ड प्रतिफल में स्प्रेड बढ़ गया, क्योंकि जोखिम से बचने की रुख और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कारण निवेशकों ने जोखिम के लिए उच्चतर प्रतिफल की मांग की। अप्रैल में, भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच यह अंतर संकुचित हुआ (चार्ट II.6बी)। मार्च में, सुरक्षित निवेश की मजबूत मांग और ब्याज दरों में वृद्धि की उम्मीदों के कारण अमेरिकी डॉलर सूचकांक में मजबूती आई; इसे तेल की कीमतों में उछाल के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका के कम जोखिम वाले संपर्क से भी अतिरिक्त समर्थन मिला। अप्रैल में, वैश्विक जोखिम भावना में सुधार के बीच यह सूचकांक नरम पड़ा (चार्ट II.6सी)। मार्च में, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के मद्देनजर निवेशक का रुख खराब होने के कारण उभरते बाजारों में पोर्टफोलियो प्रवाह कमजोर हो गया (चार्ट II.6डी)।

मार्च में, अधिकांश प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा, जो मुद्रास्फीति के लिए ऊपर के जोखिमों और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच सावधानी को दर्शाता है (चार्ट II.7)। एई में, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरो क्षेत्र, जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और कनाडा ने दरों को स्थिर रखा क्योंकि बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागत ने मुद्रास्फीति और विकास के दृष्टिकोण को धुंधला कर दिया। इसके विपरीत, ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दूसरी बैठक के लिए अपनी बेंचमार्क दर बढ़ाई, क्योंकि मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड से ऊपर रही। प्रमुख ईएमडीई में, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका ने अपनी नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा, जबकि रूस, मैक्सिको और ब्राजील ने दरों में कटौती की। अप्रैल में अब तक चीन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया ने अपनी नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

III. घरेलू विकास

भारतीय अर्थव्यवस्था पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण आए प्रमुख आपूर्ति आघात के बावजूद मजबूती बनाए हुए है।। मार्च में, आर्थिक गतिविधि के उपलब्ध उच्च-आवृत्ति

चार्ट II.7: मार्च-अप्रैल में अधिकांश प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा

प्रकार	देश	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सितं-25	अक्टू-25	नवं-25	दिसं-25	जन-26	फर-26	मार्च-26	19.04.2026
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	ऑस्ट्रेलिया													
	कनाडा													
	यूरो क्षेत्र													
	जापान													
	न्यूजीलैंड													
	दक्षिण कोरिया													
	स्वीडन													
	स्विट्जरलैंड													
	यूनाइटेड किंगडम													
	संयुक्त राज्य अमेरिका													
उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएं	ब्राज़ील													
	चीन													
	भारत													
	इंडोनेशिया													
	मलेशिया													
	मेक्सिको													
	फिलीपींस													
	रूस													
	सऊदी अरब													
	दक्षिण अफ्रीका													
	थाईलैंड													

दर परिवर्तन < -0.75 | -0.75 to -0.50 | -0.50 to -0.25 | -0.25 to <0 | 0 (No change) | >0 to 0.25 | 0.25 to 0.50 | 0.50 to 0.75 | > 0.75

रंग

टिप्पणी : सफेद रंग के ब्लॉक नीति-विरुद्ध माह को दर्शाते हैं।

स्रोत : ब्लूमबर्ग।

संकेतकों ने अलग-अलग रुझानों को प्रदर्शित किया : आर्थिक गति में मंदी के कुछ क्षेत्रों के बावजूद, मांग की स्थिति सुदृढ़ बनी रही। आरबीआई के भविष्योन्मुखी सर्वेक्षणों ने वर्तमान स्थिति पर उपभोक्ता विश्वास को कम करने और लागत के दबाव के निर्माण के साथ-साथ व्यापार आशावाद में कमी की ओर इशारा किया।[6]

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अप्रैल 2026 की अपनी द्विमासिक समीक्षा में सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया। एमपीसी ने तटस्थ रुख जारी रखने का भी फैसला किया, आने वाली सूचनाओं पर विवेकपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया देने की लोचनीयता को बरकरार रखा। यह निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत बुनियादी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित था, जिसने इसे बाहरी आघातों का सामना करने के लिए अधिक सुदृढ़ता प्रदान किया।

कुल मांग

आर्थिक गतिविधि के उच्च-आवृत्ति संकेतकों ने मार्च में मिश्रित प्रदर्शन प्रदर्शित किया। ई-वे बिलों में जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने के समर्थन से दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जो माल की मजबूत आवाजाही को दर्शाता है। जीएसटी राजस्व में वृद्धि हुई, जो निरंतर खपत और बेहतर अनुपालन को दर्शाती है।[7] आपूर्ति बाधित होने की आशंका के बीच आंशिक रूप से खरीदारी से पेट्रोल और डीजल की खपत में तेजी देखी गई। तथापि, समग्र पेट्रोलियम खपत में कमी आई, जिसका मुख्य कारण पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद व्यापक उड़ान निलंबन के कारण विमानन टरबाइन ईंधन की मांग में तीव्र गिरावट आई। डिजिटल भुगतान ने लेनदेन मूल्य और मात्रा दोनों के संदर्भ में मजबूत वृद्धि दर्ज करना जारी रखा। हालांकि, बिजली की मांग मध्यम रही, मुख्य रूप से मार्च के पहले 25 दिनों में सामान्य से अधिक बारिश के कारण, जिससे शीतलन की आवश्यकता कम हो गई। टोल संग्रह में गिरावट का रुझान जारी रहा, जो अगस्त 2025 में फास्टैग वार्षिक पास योजना के शुरू किए जाने को दर्शाता है[8] (सारणी III.1)।

सारणी III.1: मार्च में आर्थिक गतिविधि ने मिश्रित प्रदर्शन दिखाया

संकेतक	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सितं-25	अक्टू-25	नवं-25	दिसं-25	जन-26	फर-26	मार्च-26
जीएसटी ई-वे बिल	20.2	23.4	18.9	19.3	25.8	22.4	21.0	8.2	27.6	23.5	15.8	18.8	12.9
जीएसटी राजस्व	10.6	13.3	17.3	6.5	8.2	6.9	10.0	7.6	0.7	6.1	6.2	8.1	8.8
टोल संग्रह	11.9	16.6	16.4	15.5	14.8	12.7	4.5	4.6	2.9	0.4	-1.8	-8.7	-4.0
बिजली मांग	5.7	2.8	-4.8	-2.3	2.6	3.8	3.5	-5.8	-0.6	5.8	3.8	1.0	1.7
पेट्रोलियम खपत	-3.1	0.2	1.1	0.5	-4.4	4.8	7.0	-1.5	0.6	4.5	0.7	5.5	2.2
जिसमें शामिल हैं: पेट्रोल	5.7	5.0	9.2	6.8	5.9	5.5	8.0	7.4	2.6	7.1	6.1	6.1	7.6
डीजल	0.9	4.2	2.1	1.5	2.4	1.2	6.5	-0.3	4.8	5.2	3.3	4.3	8.0
एविएशन टरबाइन ईंधन	5.7	3.9	4.4	3.3	-2.3	-2.9	-0.8	2.1	5.4	0.3	5.5	4.0	0.7
डिजिटल भुगतान – मात्रा*		30.0	29.2	28.3	30.9	31.1	28.1	21.5	30.2	26.8	22.3	23.5	18.5
डिजिटल भुगतान – मूल्य*		18.4	12.6	17.4	16.6	5.3	13.4	8.8	14.7	15.2	11.5	17.9	12.8

<<<<<< संकुचन---------- विस्तार >>>>>>

टिप्पणियां : 1. सभी संकेतकों के लिए वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
2. हीट-मैप अप्रैल 2023 से लेकर उस नवीनतम माह तक के आंकड़ों पर लागू किया गया है, जिनके लिए डेटा उपलब्ध है।
3. डिजिटल भुगतान के लिए, हीट-मैप अप्रैल 2024 से लेकर उस नवीनतम माह तक के आंकड़ों पर लागू किया गया है, जिनके लिए डेटा उपलब्ध है।
4. *मार्च 2026 के लिए डिजिटल भुगतान का डेटा अनंतिम है, क्योंकि कार्ड भुगतान से संबंधित आंकड़ों में संशोधन संभव है।
5. हीट-मैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा की सीमा को एक रंग ग्रेडिएंट योजना में अनुवाद करता है, जिसमें लाल रंग संबंधित डेटा श्रृंखला के न्यूनतम मानों को दर्शाता है और हरा रंग उच्चतम मानों के अनुरूप होता है।

स्रोत: माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन); आरबीआई; केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए); भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई); और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार।

6 आरबीआई के भविष्योन्मुखी सर्वेक्षणों के परिणाम, अप्रैल 2026

7 सकल जीएसटी राजस्व में तीन घटक शामिल हैं - आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। भारत का जीएसटी संग्रह पिछले साल के इसी महीने की तुलना में मार्च में बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।

8 वार्षिक पास उपयोगकर्ताओं को एक निश्चित शुल्क पर एक वर्ष के लिए 200 यात्राएं करने या यात्रा करने की अनुमति देता है, जिससे प्लाजा में प्रति ट्रिप टोल राजस्व कम हो जाता है।

सारणी III.2: मांग की स्थितियां सुदृढ़ बनी रहीं

	संकेतक	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सितं-25	अक्टू-25	नवं-25	दिसं-25	जन-26	फर-26	मार्च-26
शहरी मांग	घरेलू हवाई यात्री यातायात	9.9	9.7	2.6	3.7	-2.5	-0.5	-2.5	3.5	7.0	-4.9	3.1	-0.1	-1.5
	खुदरा यात्री वाहन बिक्री	6.3	1.6	-3.1	2.5	-0.8	0.9	5.8	10.7	20.4	26.6	7.2	26.1	21.5
ग्रामीण मांग	खुदरा ऑटोमोबाइल बिक्री		2.9	5.4	4.8	-4.3	2.8	5.2	40.5	2.1	14.6	17.6	25.6	25.3
	खुदरा ट्रैक्टर बिक्री		7.6	2.8	8.7	11.0	30.1	3.6	14.2	56.5	15.8	22.9	36.4	10.9
	खुदरा दो-पहिया वाहन बिक्री	-1.8	2.3	7.3	4.7	-6.5	2.2	6.5	51.8	-3.1	9.5	20.8	25.0	28.7

<<<<<< संकुचन---------- विस्तार >>>>>>

टिप्पणियां: 1. सभी संकेतकों के लिए वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
2. हीट-मैप अप्रैल 2023 से लेकर उस नवीनतम माह तक के आंकड़ों पर लागू किया गया है, जिनके लिए डेटा उपलब्ध है।
3. हीट-मैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा की सीमा को एक रंग ग्रेडिएंट योजना में अनुवाद करता है, जिसमें लाल रंग संबंधित डेटा श्रृंखला के न्यूनतम मानों को दर्शाता है और हरा रंग उच्चतम मानों के अनुरूप होता है।
4. खुदरा ऑटोमोबाइल बिक्री के आंकड़ों में दो पहिया वाहनों, तीन पहिया वाहनों, यात्री वाहनों, ट्रैक्टरों और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री शामिल है।
5. मार्च 2026 के लिए घरेलू हवाई यात्री यातायात की वृद्धि दर की गणना दैनिक आंकड़ों को एकत्रित करके की गई है।

स्रोत: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (एफएडीए); और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने मार्च में मांग में सुदृढ़ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाहनों की बिक्री में वृद्धि जीएसटी के बाद की गति से समर्थित मजबूत खुदरा मांग से प्रेरित थी। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की मांग में वृद्धि, विशेष रूप से दोपहिया खंड में, ने भी समग्र गति में योगदान दिया (सारणी III.2)।

2024 की तुलना में 2025 के दौरान श्रम बाजार की स्थितियों में सुधार हुआ।[9] अखिल भारतीय बेरोजगारी दर (सामान्य स्थिति के आधार पर) 2024 में 3.2 प्रतिशत से घटकर 2025 में 3.1 प्रतिशत हो गई, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कमी देखी गई। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि के साथ-साथ श्रम बल भागीदारी दर में स्थिरीकरण देखा गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों मापदंडों में गिरावट देखी गई। रोजगार की गुणवत्ता में सुधार देखा गया, जिसमें नियत मजदूरी/वेतनभोगी श्रमिकों का अनुपात बढ़ा; यह औपचारिक रोजगार की ओर हुए बदलाव को दर्शाता है। क्षेत्रीय वियोजन से पता चलता है कि कुल रोजगार में कृषि का हिस्सा घटता रहा, जबकि विनिर्माण और अन्य सेवाओं—जिनमें व्यापार और वित्तीय सेवाएं, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन शामिल हैं—का हिस्सा बढ़ा।

मार्च में, चालू साप्ताहिक स्थिति द्वारा मापे गए अखिल भारतीय बेरोजगारी दर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई[10]। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में गिरावट आई, जबकि वे शहरी क्षेत्रों में मोटे तौर पर स्थिर रहे। मार्च 2026 में विनिर्माण और सेवाओं के लिए पीएमआई रोजगार क्रमशः सात महीने और नौ महीने के शिखर पर पहुंच गया। नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स ने हॉस्पिटैलिटी, बीपीओ/आईटीईएस और शिक्षा के नेतृत्व में व्हाइट-कॉलर भर्तियों में भी मजबूत वृद्धि दिखाई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत काम की मांग में लगातार नौवें महीने गिरावट जारी रही, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दर्शाता है (सारणी III.3)।

अप्रैल-फरवरी 2025-26 के दौरान, संशोधित अनुमानों (आरई) के प्रतिशत के रूप में केंद्र के सभी प्रमुख घाटा संकेतक पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कम रहे (चार्ट III.1ए)। घटते राजकोषीय घाटे का कारण कर राजस्व में वृद्धि और राजस्व व्यय में मामूली वृद्धि थी।[11] निवल कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप

[9] आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2025।

[10] पीएलएफएस मासिक बुलेटिन मार्च 2026।

[11] अप्रैल-फरवरी 2025-26 के दौरान, निवल कर राजस्व और राजस्व व्यय में क्रमशः 6.4 प्रतिशत और 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में क्रमशः 9.0 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

सारणी III.3: रोज़गार से संबंधित उच्च आवृत्ति वाले संकेतक स्थिर बने रहे

संकेतक	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सितं-25	अक्टू-25	नवं-25	दिसं-25	जन-26	फर-26	मार्च-26
बेरोजगारी दर (पीएलएफएस: अखिल भारत)		5.1	5.6	5.6	5.2	5.1	5.2	5.2	4.7	4.8	5.0	4.9	5.1
बेरोजगारी दर (पीएलएफएस: ग्रामीण)		4.5	5.1	4.9	4.4	4.3	4.6	4.4	3.9	3.9	4.2	4.2	4.3
बेरोजगारी दर (पीएलएफएस: शहरी)		6.5	6.9	7.1	7.2	6.7	6.8	7.0	6.5	6.7	7.0	6.6	6.8
नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स	-1.5	8.9	0.3	10.5	6.8	3.4	10.1	-9.3	23.5	13.2	3.4	11.9	9.2
पीएमआई रोज़गार: विनिर्माण	53.4	54.2	54.9	55.1	53.3	53.1	52.1	52.4	50.9	50.5	51.1	51.5	52.6
पीएमआई रोज़गार: सेवाएं	52.5	53.9	57.1	55.1	51.4	52.2	51.9	51.4	51.6	49.8	50.8	51.6	52.7
मनरेगा(एमजीएनआरईजीएस) : कार्य मांग	2.2	-6.5	4.4	4.4	-12.3	-26.2	-27.1	-35.1	-32.0	-28.9	-25.7	-14.1	-23.2

<<<<<< संकुचन---------- विस्तार >>>>>>

टिप्पणियां:
1. सभी पीएलएफएस संकेतक चालू साप्ताहिक स्थिति को दर्शाते हैं और ये 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए हैं।
2. नौकरी सूचकांक और मनरेगा के तहत कार्य मांग के लिए वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
3. हीटमैप अप्रैल 2023 से मार्च 2026 तक के आंकड़ों पर लागू किया गया है।
4. हीटमैप प्रत्येक संकेतक के लिए आंकड़ों की सीमा को एक रंग ढाल योजना में परिवर्तित करता है, जिसमें लाल रंग न्यूनतम मानों को और हरा रंग संबंधित आंकड़ा श्रृंखला के उच्चतम मानों को दर्शाता है।
5. सभी पीएमआई मान सूचकांक के रूप में रिपोर्ट किए गए हैं। 50 से अधिक का पीएमआई मान विस्तार को, 50 से कम का मान संकुचन को और 50 के बराबर का मान 'कोई बदलाव नहीं' को दर्शाता है। पीएमआई हीटमैप में, लाल रंग प्रत्येक पीएमआई श्रृंखला में न्यूनतम मान को, पीला रंग 50 (या कोई बदलाव नहीं वाला मान) को, और हरा रंग उच्चतम मान को दर्शाता है।
6. मनरेगा को व्युत्क्रम पैमाने में दिखाया गया है - न्यूनतम मान को हरे रंग से और उच्चतम मान को लाल रंग से चिह्नित किया गया है।

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार; इन्फो एज; और एस एंड पी ग्लोबल।

से निगम कर, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में दोहरे अंकों की वृद्धि द्वारा संचालित थी।[12] पूंजीगत व्यय में मजबूत वृद्धि दर्ज करना जारी रहा, जो व्यय की गुणवत्ता में सुधार पर सरकार के जोर को दर्शाता है।[13]

राज्यों के घाटा संकेतक अप्रैल-फरवरी 2025-26 के दौरान, वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों के अनुपात के रूप में, पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में उच्च थे (चार्ट III.1बी)। उच्च घाटा मुख्य रूप से बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों

चार्ट III.1: सरकारी घाटे के संकेतक (अप्रैल – फरवरी)

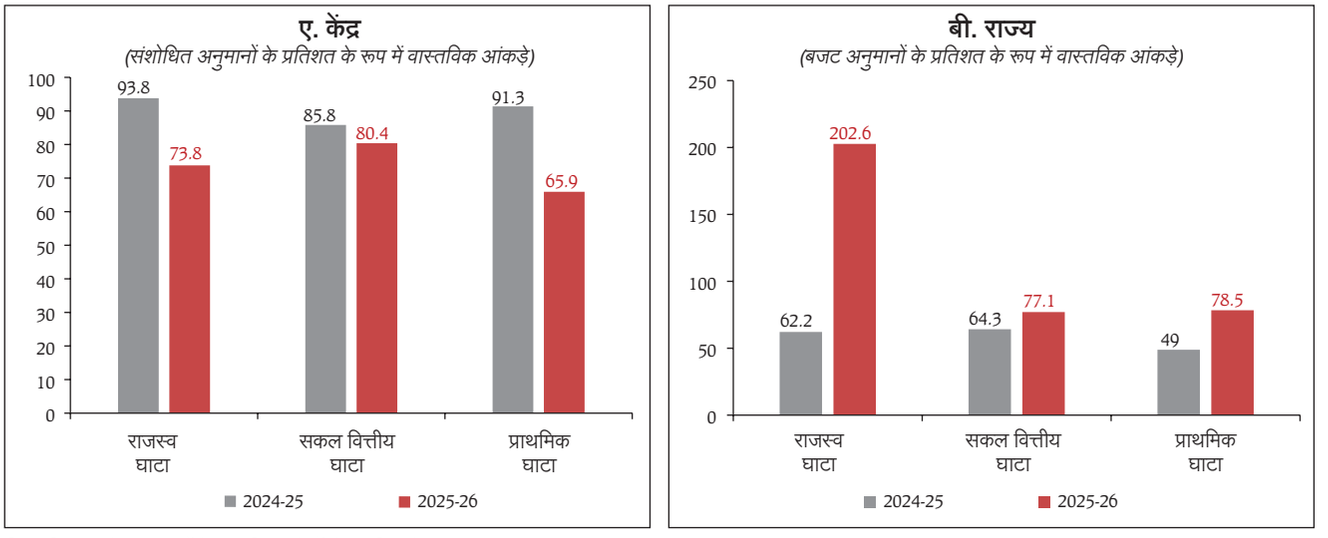

टिप्पणी: आंकड़े 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं।
स्रोत: महालेखा नियंत्रक (सीजीए); भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; और केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

[12] अप्रैल-फरवरी 2025-26 के दौरान, निगम कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क संग्रह में क्रमशः 12.4, 11.3 और 18.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में क्रमशः 1.9, (-)1.4 और 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

[13] अप्रैल-फरवरी 2025-26 के दौरान पूंजीगत व्यय में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 0.8 प्रतिशत थी।

में कमी द्वारा संचालित था। राजस्व प्राप्तियों के भीतर, राज्यों के वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) में वृद्धि धीमी हुई, जबकि राज्य उत्पाद शुल्क और स्टाम्प शुल्क मजबूत रहे। व्यय की ओर, राज्यों के राजस्व व्यय में वृद्धि धीमी हुई, जबकि पूंजीगत व्यय में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।

व्यापार

2025-26 के दौरान, वस्तु व्यापार घाटा पिछले वर्ष की तुलना में उच्च रहा, जो मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों, सोने और इलेक्ट्रॉनिक सामान द्वारा संचालित था।[14] इस वर्ष के दौरान वस्तु निर्यात और आयात दोनों में वृद्धि दर्ज की गई।[15] शुल्क संबंधी अनिश्चितताओं के बने रहने के बावजूद, 2025-26 में अमेरिका को निर्यात में विस्तार हुआ।[16] एक प्रमुख व्यापार पुनर्गठन में, चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया।[17]

मार्च 2026 में, वस्तु व्यापार घाटा क्रमिक और वर्ष-दर-वर्ष दोनों आधारों पर संकुचित हुआ (चार्ट III.2)। माह-दर-माह आधार पर, निर्यात में विस्तार हुआ जबकि आयात में संकुचन दर्ज किया गया। हालाँकि, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, निर्यात और आयात दोनों में गिरावट आई, जिसमें निर्यात में हुई गिरावट आयात की तुलना में अधिक थी। जबकि निर्यात में गिरावट (वर्ष-दर-वर्ष) अपेक्षाकृत व्यापक आधार वाली थी, वहीं आयात में गिरावट (वर्ष-दर-वर्ष) मुख्य रूप से पेट्रोलियम आयात में दोहरे अंकों की कमी से संचालित थी।[18] सोने के आयात में भी संकुचन देखा गया, जो

चार्ट III.2: भारत का वस्तु व्यापार घाटा कम हुआ

स्रोत: पीआईबी; और डीजीसीआई एंड एस ।

[14] 2025-26 में वस्तु व्यापार घाटा 333.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2024-25 में 283.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था।

[15] वर्ष 2025-26 में 30 प्रमुख वस्तुओं में से 14 (2025-26 में निर्यात बास्केट का 54.0 प्रतिशत हिस्सा) और 30 प्रमुख वस्तुओं में से 20 (2025-26 में आयात बास्केट का 60.9 प्रतिशत हिस्सा) में विस्तार दर्ज किया गया।

[16] अमेरिका को निर्यात 2025-26 में 0.9 प्रतिशत बढ़ा, जो 2024-25 में 11.6 प्रतिशत से कम था।

[17] वर्ष 2025-26 में चीन और अमेरिका के साथ भारत का कुल पण्य व्यापार क्रमशः 151.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 140.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अमेरिका 2021-22 से 2024-25 के दौरान सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। चीन के साथ पण्य व्यापार घाटा 2024-25 में 99.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 112.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

[18] पण्य व्यापार घाटा मार्च 2025 में 21.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और फरवरी 2026 में 27.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर मार्च 2026 में 20.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। मार्च 2026 में पण्य निर्यात 38.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था [7.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की कमी], हालांकि, फरवरी 2026 में 36.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण, रेडीमेड वस्त्र, चावल, और प्लास्टिक तथा लिनोलियम जैसे प्रमुख क्षेत्रों के कारण निर्यात में गिरावट हुई, जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, अभ्रक, कोयला, अन्य अयस्क और खनिज; अन्य अनाज, और हस्तनिर्मित कालीन को छोड़कर हस्तशिल्प ने निर्यात को बढ़ाया। अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड सहित अनुबंधित शीर्ष 20 प्रमुख गंतव्यों में से 10 को निर्यात में गिरावट हुआ, जबकि चीन, सिंगापुर और जर्मनी में बढ़ोतरी हुआ है। मार्च 2026 में पण्य आयात 59.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा [वर्ष-दर-वर्ष और अनुक्रमिक आधार दोनों पर 6.5 प्रतिशत का संकुचन]। कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद; सोना; परिवहन उपकरण; मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर; और लोहा तथा इस्पात के कारण आयात में गिरावट आई, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी-इलेक्ट्रिकल और गैर-इलेक्ट्रिकल; चांदी, कोयला, कोक और ब्रिकेट; तथा वनस्पति तेल ने महीने के दौरान आयात में सकारात्मक योगदान दिया। संयुक्त अरब अमीरात, रूस और सऊदी अरब सहित 20 प्रमुख गंतव्यों में से 8 से आयात में गिरावट हुआ, जबकि चीन, अमेरिका और हांगकांग से विस्तार हुआ।

चल रही भू-राजनीतिक तनावों के बीच सोने की कीमतों में गिरावट के कारण हुआ।[19]

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, क्योंकि भारत खाड़ी शिपिंग मार्गों पर भारी रूप से निर्भर है। इस संघर्ष के कारण मार्च में पश्चिम एशिया से निर्यात और आयात में औसतन 54 प्रतिशत की गिरावट आई।[20] रूस से आयात में क्रमिक वृद्धि देखी गई।[21]

फरवरी में निवल सेवा निर्यात में वृद्धि धीमी हुई, जिसमें निर्यात की तुलना में आयात तेजी से बढ़ा (चार्ट III.3)।[22] व्यापार, सॉफ्टवेयर और यात्रा सेवाओं के दोनों निर्यात और आयात में वृद्धि देखी गई।

कुल आपूर्ति

कृषि

ग्रीष्मकालीन (ज़ायद) मौसम में बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से अधिक रही है। पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद निविष्टि आपूर्तियों को लेकर चिंताओं के बीच, चावल के क्षेत्रफल में आई तेज गिरावट की भरपाई दलहन, मोटे अनाज और तिलहन के बढ़े हुए क्षेत्रफल से हुई है (चार्ट III.4)।[23]

औद्योगिक गतिविधि के मासिक संकेतक

फरवरी में, विनिर्माण और पूंजीगत वस्तुओं में मजबूती के कारण, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन के रूप में मापी गई औद्योगिक गतिविधि में वृद्धि दर में थोड़ी वृद्धि हुई। निवेश से जुड़े खंडों में लगातार मजबूती देखी गई, जिसमें बुनियादी ढांचे और निर्माण संबंधी वस्तुएं सबसे प्रमुख योगदानकर्ता बनी रहीं। मार्च में आठ कोर उद्योगों का सूचकांक संकुचित हुआ, जो 19 महीने का निचला स्तर है, और यह मुख्य रूप से उर्वरकों, कच्चे तेल, कोयले और बिजली के उत्पादन में गिरावट के कारण हुआ।

मार्च माह में औद्योगिक गतिविधियों के उच्च आवृत्ति वाले संकेतकों ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण गति में मंदी की ओर संकेत किया। नए आदेशों और उत्पादन वृद्धि में धीमी

चार्ट III.3: फरवरी में सकल सेवा निर्यात वृद्धि में मंदी

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत में)

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट III.4: साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन *(ज़ायद)* बुवाई अब तक अधिक

(लाख हेक्टेयर)

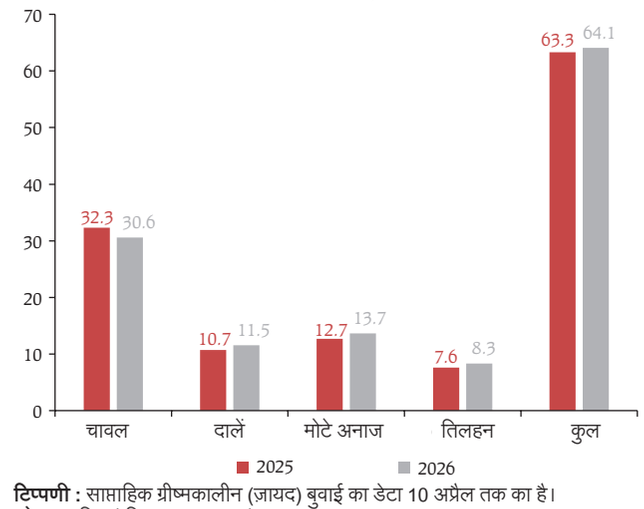

टिप्पणी : साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन (ज़ायद) बुवाई का डेटा 10 अप्रैल तक का है।
स्रोत : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

[19] मार्च 2026 में सोने के आयात में 31.6 प्रतिशत (y-o-y) की गिरावट आई।

[20] शीर्ष 20 निर्यात गंतव्यों में से, मार्च 2026 के लिए दो पश्चिम एशियाई देशों; संयुक्त अरब अमीरात (-61.9 प्रतिशत y-o-y), और सऊदी अरब (-45.7 प्रतिशत y-o-y) के लिए निर्यात वृद्धि पर डेटा उपलब्ध हैं। शीर्ष 20 आयात भागीदारों में, मार्च 2026 के लिए चार पश्चिम एशियाई देशों -संयुक्त अरब अमीरात (-66.3 प्रतिशत साल-दर-साल), सऊदी अरब (-37.3 प्रतिशत साल-दर-साल), इराक (-64.3 प्रतिशत साल-दर-साल), और कतर (-47.9 प्रतिशत साल-दर-साल) के लिए आयात वृद्धि पर डेटा उपलब्ध है।

[21] मार्च 2026 में रूस से आयात में क्रमिक रूप से 25.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[22] सेवाओं का निवल निर्यात फरवरी 2025 में 17.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर फरवरी 2026 में 17.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अप्रैल 2025 - फरवरी 2026 के दौरान, संचयी सेवाओं का निवल निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 170.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 195.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

[23] ग्रीष्मकालीन फसलों के तहत बोया गया क्षेत्र (10 अप्रैल, 2026 तक) 64.1 लाख हेक्टेयर है, जो पूरे मौसम के लिए सामान्य रकबे का 85.1 प्रतिशत है। इसके अलावा, यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.2 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, चावल (प्रमुख ग्रीष्मकालीन फसल) के तहत क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में 5.3 प्रतिशत कम है।

गति आने के कारण विनिर्माण पीएमआई जून 2022 के बाद अपने निम्नतम स्तर पर आ गया। हालांकि, प्रमुख खंडों में ऑटोमोबाइल उत्पादन मजबूत वृद्धि दर्ज करता रहा (सारणी III.4)।

भारत जलवायु सुदृढ़ता की दिशा में प्रगति कर रहा है। मार्च में, सरकार ने उत्सर्जन में कमी, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बढ़ी हुई विद्युत शक्ति क्षमता और कार्बन सिंक को बढ़ावा देने के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को अद्यतन किया है।[24] भारत ने अद्यतन एनडीसी लक्ष्यों की व्यवहार्यता को मान्य करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। यह कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है और गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के 53 प्रतिशत से अधिक तक पहुंच गया है (चार्ट III.5)।[25] नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के निरंतर विस्तार, ग्रिड एकीकरण और पूरक जलवायु कार्यों के माध्यम से इस गति को बनाए रखना अद्यतन प्रतिबद्धताओं को विश्वसनीय परिणामों में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है।

सेवा गतिविधि के मासिक संकेतक

भारत के सेवा क्षेत्र ने मार्च में कुछ गिरावट दिखाई, जबकि सेवाओं पीएमआई में निरंतर विस्तार प्रदर्शित किया। जबकि नए निर्यात आदेशों के नेतृत्व में मांग सुदृढ़ बनी रही, उत्पादन पश्चिम

सारणी III.4: उद्योग के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक मंद पड़े

संकेतक	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सितं-25	अक्टू-25	नवं-25	दिसं-25	जन-26	फर-26	मार्च-26
आईआईपी-शीर्षक स्तर	3.9	2.6	1.9	1.5	4.3	4.1	4.6	0.5	7.2	8.0	5.1	5.2	
आईआईपी-विनिर्माण	4.0	3.1	3.2	3.7	6.0	3.8	5.6	2.0	8.5	8.4	5.3	6.0	
आईआईपी-पूंजीगत वस्तुएं	3.6	14.0	13.3	3.0	6.8	4.5	5.4	2.1	10.1	8.3	4.1	12.5	
पीएमआई-विनिर्माण	58.1	58.2	57.6	58.4	59.1	59.3	57.7	59.2	56.6	55.0	55.4	56.9	53.9
पीएमआई-निर्यात आदेश	54.9	57.6	56.9	60.6	57.3	56.1	56.5	54.7	54.1	54.0	54.1	53.2	55
पीएमआई-विनिर्माण: भावी उत्पादन	64.4	64.6	63.1	62.2	57.6	60.5	64.8	62.3	57.1	56.9	56.4	57.9	67.3
आठ कोर उद्योगों का सूचकांक	4.5	1.0	1.2	2.2	3.7	6.5	3.3	-0.1	2.1	4.7	4.7	2.8	-0.4
बिजली उत्पादन: पारंपरिक	4.8	-1.8	-8.2	-6.1	-0.8	1.0	0.8	-10.6	-5.0	4.4	2.2	-1.6	-1.2
बिजली उत्पादन: नवीकरणीय	25.2	28.0	18.2	28.7	26.4	22.7	16.4	21.4	22.9	18.0	22.9	25.3	
ऑटोमोबाइल उत्पादन	6.5	-1.7	5.2	1.2	10.7	8.1	10.8	-2.8	22.3	37.1	15.0	22.1	20.2
यात्री वाहन उत्पादन	11.2	10.8	5.4	-1.8	0.1	-4.1	16.1	9.8	22.8	23.1	5.6	9.8	9.0
ट्रैक्टर उत्पादन	18.5	20.5	9.1	9.8	11.5	9.4	23.0	13.0	37.5	57.9	14.6	80.0	28.6
दोपहिया वाहन उत्पादन	5.6	-4.1	4.7	1.4	12.3	10.0	9.8	-5.6	20.9	39.9	16.1	24.4	22.0
तीपहिया वाहन उत्पादन	6.0	4.1	16.9	8.6	24.0	15.8	15.9	15.9	55.4	39.6	33.2	29.9	34.0
कच्चा इस्पात उत्पादन	8.5	9.3	11.0	12.6	13.8	12.8	13.7	8.9	11.1	10.8	10.5	10.2	3.8
तैयार इस्पात उत्पादन	10.0	6.6	7.0	10.9	13.8	13.8	14.0	7.2	12.4	10.9	11.0	8.0	1.2
पूंजीगत वस्तुओं का आयात	8.6	24.5	15.7	3.4	13.3	0.2	12.7	8.5	12.8	13.0	7.1	19.7	11.7

<<<<<< संकुचन---------- विस्तार >>>>>>

टिप्पणियां:
1. सभी संकेतकों (पीएमआई को छोड़कर) के लिए वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
2. हीट-मैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा श्रृंखला को एक रंग ग्रेडिएंट योजना में अनुवाद करता है, जिसमें लाल रंग संबंधित डेटा श्रृंखला के न्यूनतम मानों को और हरा रंग उच्चतम मानों को दर्शाता है।
3. हीट-मैप अप्रैल 2023 से लेकर उस नवीनतम माह तक के डेटा पर लागू किया गया है जिसके लिए डेटा उपलब्ध है।
4. सभी पीएमआई मान सूचकांक के रूप में रिपोर्ट किए गए हैं। 50 से अधिक का पीएमआई मान विस्तार को, 50 से कम का मान संकुचन को और 50 के बराबर का मान 'कोई बदलाव नहीं' को दर्शाता है। पीएमआई हीट-मैप में, लाल रंग प्रत्येक पीएमआई श्रृंखला में न्यूनतम मान को, पीला रंग 50 (या कोई बदलाव नहीं वाले मान) को, और हरा रंग उच्चतम मान को दर्शाता है।

स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई); एस एंड पी ग्लोबल; केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), बिजली मंत्रालय; सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम); आर्थिक सलाहकार कार्यालय, भारत सरकार; संयुक्त संयंत्र समिति; वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय; और ट्रैक्टर और मैकेनाइजेशन एसोसिएशन।

[24] एनडीसी में किए गए तीन प्रमुख संशोधनों में 2005 के स्तर से 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 47 प्रतिशत की कमी, 2035 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 60 प्रतिशत विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता प्राप्त करना और 2005 के स्तर से 2035 तक वन कार्बन सिंक को 35-40 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर बढ़ाना और वृक्षों के आवरण को बढ़ाना शामिल है।

[25] आईआरईएनए (2026), नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2026, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी।

चार्ट III.5: कुल स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन की बढ़ती हिस्सेदारी

(प्रतिशत में)

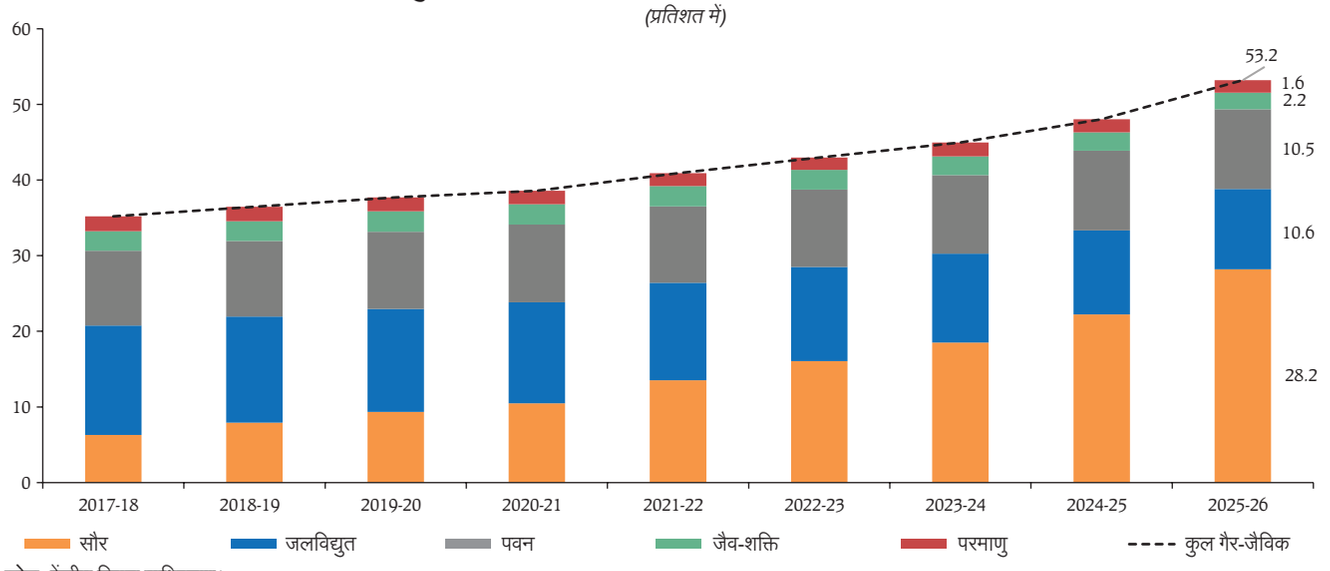

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण।

एशिया संघर्ष के प्रभाव से बाधित था। बुनियादी ढांचे से संबंधित वस्तुओं की आवाजाही और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के उच्च स्तर के समर्थन से खुदरा वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण व्यापार में व्यवधान के कारण पोर्ट कार्गो में नरमी रही। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के व्यापक रद्दीकरण और व्यवधानों के कारण अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात में तेज गिरावट देखी गई (सारणी III.5)।

सारणी III.5: सेवा क्षेत्र के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक मंद पड़े

संकेतक	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला -25	अग-25	सितं-25	अक्टू-25	नवं-25	दिसं-25	जन-26	फर-26	मार्च-26
पीएमआई सेवाएं	58.5	58.7	58.8	60.4	60.5	62.9	60.9	58.9	59.8	58.0	58.5	58.1	57.5
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	6.8	13.0	5.0	3.4	5.5	7.7	7.3	9.7	7.5	6.0	7.1	3.0	-17.8
घरेलू हवाई कार्गो	4.9	16.6	2.3	2.6	4.8	7.1	2.8	-2.3	20.5	4.3	8.7	18.5	
अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो	3.3	8.6	6.8	-1.2	4.2	4.5	2.3	-2.3	12.7	12.6	8.4	17.5	
बंदरगाह कार्गो यातायात	13.3	7.0	4.3	5.6	4.0	2.5	11.5	11.9	14.5	12.8	7.6	5.1	0.7
खुदरा वाणिज्यिक वाहन बिक्री	2.7	-1.0	-3.7	6.6	0.2	8.6	2.7	21.1	17.0	24.6	15.1	28.9	15.1
इस्पात खपत	13.3	6.0	8.1	9.3	7.3	10.0	8.9	2.4	6.0	5.4	4.9	10.9	10.6
सीमेंट उत्पादन	12.2	6.3	9.7	8.2	11.6	5.4	5.0	5.2	14.6	13.7	11.3	9.3	

<<<<<< संकुचन---------- विस्तार >>>>>>

टिप्पणियां:
1. सभी संकेतकों (पीएमआई को छोड़कर) के लिए वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
2. हीटमैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा श्रृंखला को एक रंग ग्रेडियेंट योजना में अनुवाद करता है, जिसमें लाल रंग संबंधित डेटा श्रृंखला के न्यूनतम मानों को दर्शाता है और हरा रंग उच्चतम मानों को दर्शाता है।
3. हीटमैप अप्रैल 2023 से लेकर उस नवीनतम महीने तक के डेटा पर लागू किया गया है जिसके लिए डेटा उपलब्ध है।
4. सभी पीएमआई मान सूचकांक रूप में रिपोर्ट किए गए हैं। 50 से अधिक का पीएमआई मान विस्तार को दर्शाता है, 50 से कम संकुचन को दर्शाता है, और 50 के बराबर 'कोई बदलाव नहीं' को दर्शाता है। पीएमआई हीटमैप में, लाल रंग प्रत्येक पीएमआई श्रृंखला में न्यूनतम मान को दर्शाता है, पीला रंग 50 (या कोई बदलाव नहीं वाला मान) को दर्शाता है, और हरा रंग उच्चतम मान को दर्शाता है।
5. मार्च 2026 के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात पर डेटा की वृद्धि दर की गणना दैनिक डेटा को एकत्रित करके की गई है।

स्रोत : ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन महासंघ (एफएडीए); भारतीय बंदरगाह संघ; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; संयुक्त संयंत्र समिति; आर्थिक सलाहकार कार्यालय; और एस एंड पी ग्लोबल।

मुद्रास्फीति

सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति[26] फरवरी में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च में 3.4 प्रतिशत हो गई, जो मुख्यतः खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति[27] में वृद्धि के कारण हुई। कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई[28]) स्थिर बनी रही, जो अंतर्निहित मुद्रास्फीति दबावों के व्यापक नियंत्रण को दर्शाती है। कीमती धातुएं मुख्य मुद्रास्फीति का एक प्रमुख चालक बनी रहीं। कीमती धातुओं को छोड़कर मुख्य मुद्रास्फीति भी मध्यम स्तर पर स्थिर रही। एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के कारण सीपीआई ईंधन मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, जो आंशिक रूप से अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि को दर्शाती है (चार्ट III.6)।

बारह में से सात प्रभागों में मुद्रास्फीति दर में क्रमिक वृद्धि देखी गई (चार्ट III.7)। तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू होने और 01 फरवरी, 2026 से संशोधित जीएसटी दर संरचना के बाद 'पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ' प्रभाग में लगातार दूसरे महीने वृद्धि दर्ज की गई। 'व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और विविध वस्तुओं एवं सेवाओं' वर्ग में मुद्रास्फीति, बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में नरमी आने के बावजूद, सर्वोच्च बनी रही।

मार्च 2026 में खाद्य मुद्रास्फीति सकारात्मक गति और प्रतिकूल आधार प्रभाव दोनों से प्रेरित थी। मांस और मछली, फल और मेवे, और तेल और वसा ने उच्च कीमतों में योगदान दिया।

स्थानिक वितरण के संदर्भ में, मार्च में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़ गई। कुल मिलाकर, मुद्रास्फीति 0.7 प्रतिशत से 5.8 प्रतिशत तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में देखी गई। हालांकि, अधिकांश राज्यों में मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से नीचे रही (चार्ट III.8)।

चार्ट III.6: मार्च में समग्र सीपीआई मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि

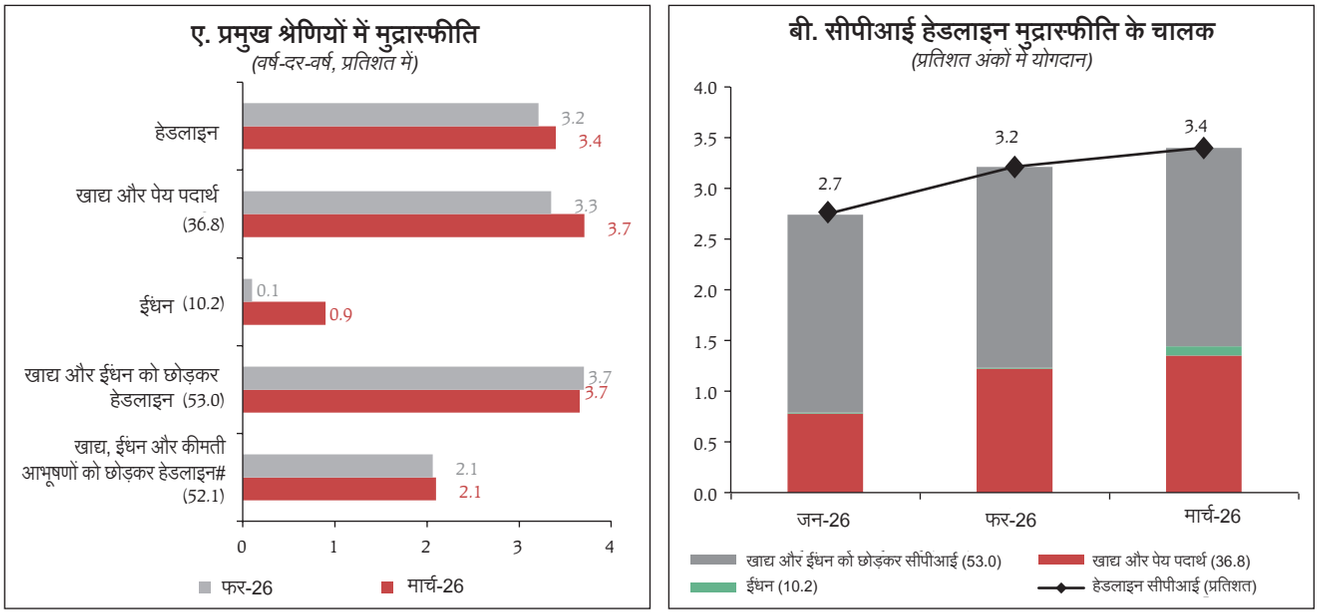

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दी गई संख्याएं समग्र सीपीआई श्रृंखला (2024=100) में भार को दर्शाती हैं।
2. #: कीमती आभूषणों में 'सोने/हीरे/प्लैटिनम के आभूषण' और 'चांदी के आभूषण' शामिल हैं।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)।

[26] राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 13 अप्रैल, 2026 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

[27] माह दर माह आधार पर, मार्च में समग्र सूचकांक में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सभी तीन घटकों, अर्थात् खाद्य और पेय पदार्थ, ईंधन और कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) में वृद्धि दर्ज की गई।

[28] ईंधन समूह 'बिजली, गैस और अन्य ईंधन' और एक वर्ग, 'व्यक्तिगत परिवहन उपकरण के लिए ईंधन और स्नेहक' [जिसमें डीजल, पेट्रोल और अन्य प्राकृतिक गैस (संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) शामिल हैं) का प्रतिनिधित्व करता है]। अधिक जानकारी के लिए मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अप्रैल 2026 के मूल्य और लागत अध्याय में बॉक्स IV.2 देखें।

चार्ट III.7: प्रभाग-वार मुद्रास्फीति दरों में परिवर्तन

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत में)

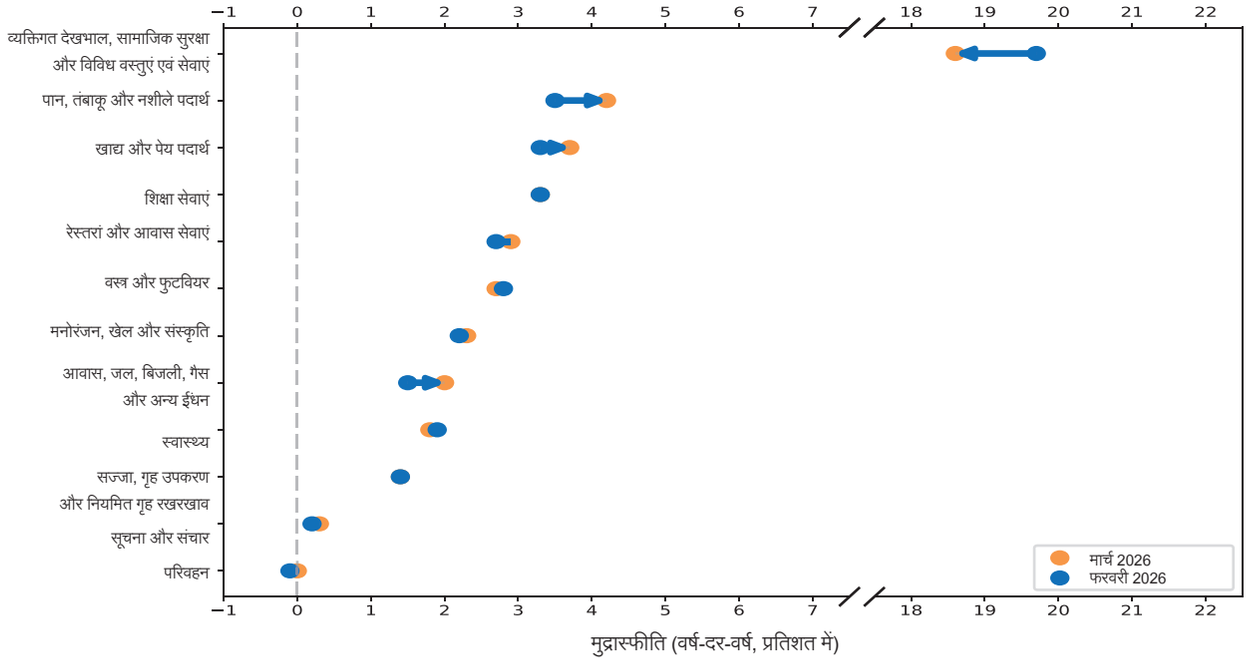

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ की गणनाएं।

16 अप्रैल तक के उच्च-आवृत्ति वाले आंकड़े चावल और गेहूं की कीमतों में नरमी की ओर संकेत करते हैं। दालों के भीतर, अरहर की कीमतों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जबकि चने की कीमतों में गिरावट आई। खाद्य तेलों की कीमतों में व्यापक वृद्धि देखी गई। अप्रैल में अब तक सभी प्रमुख सब्जियों, यथा आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में नरमी आई है (चार्ट III.9)।

चार्ट III.8: मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण : मार्च 2026

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत में)

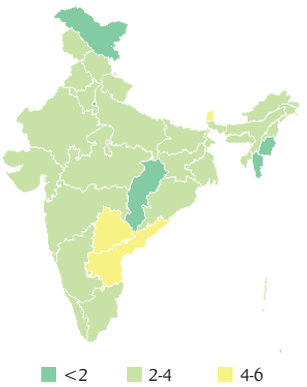

मुद्रास्फीति दायरा	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या
<2	5
2-4	27
4-6	4

मुद्रास्फीति प्रवृत्ति	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या
गिरावट या स्थिर :	12
वृद्धि	24

टिप्पणियां : 1. मानचित्र केवल उदाहरण प्रयोजनों के लिए है।
2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में मुद्रास्फीति क्रमशः 3.4 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत अनुभव की गई।

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ की गणनाएं।

अप्रैल में (16 तारीख तक) एलपीजी की खुदरा विक्रय कीमतों में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की कीमतें अपरिवर्तित रहीं (सारणी III.6)।

मार्च के पीएमआई आंकड़ों से पता चलता है कि विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों की कंपनियों में निविष्टि लागत के दबाव तीव्र हुए हैं। हालांकि, विनिर्माण कंपनियों द्वारा निर्धारित उत्पादन कीमतों में वृद्धि में कमी आई है, जो ग्राहकों को बनाए रखने और

सारणी III.6: पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

वस्तु	इकाई	घरेलू मूल्य			माह-दर-माह (प्रतिशत में)	
		अप्रै-25	मार्च-26	अप्रै-26^	मार्च-26	अप्रै-26^
पेट्रोल	₹/लीटर	101.0	101.2	101.2	0.0	0.0
डीजल	₹/लीटर	90.5	90.5	90.5	0.0	0.0
केरोसिन (सब्सिडी वाला)	₹/लीटर	43.5	46.8	46.8	6.2	0.0
एलपीजी (बिना सब्सिडी वाला)	₹/सिलेंडर	863.3	911.6	923.3	5.6	7.0

^: अवधि 1-16 अप्रैल, 2026 के लिए।

टिप्पणी: केरोसिन को छोड़कर, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। केरोसिन के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी वाली कीमतों का औसत दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ की गणनाएं।

चार्ट III.9: अप्रैल में खाद्य तेलों को छोड़कर खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट

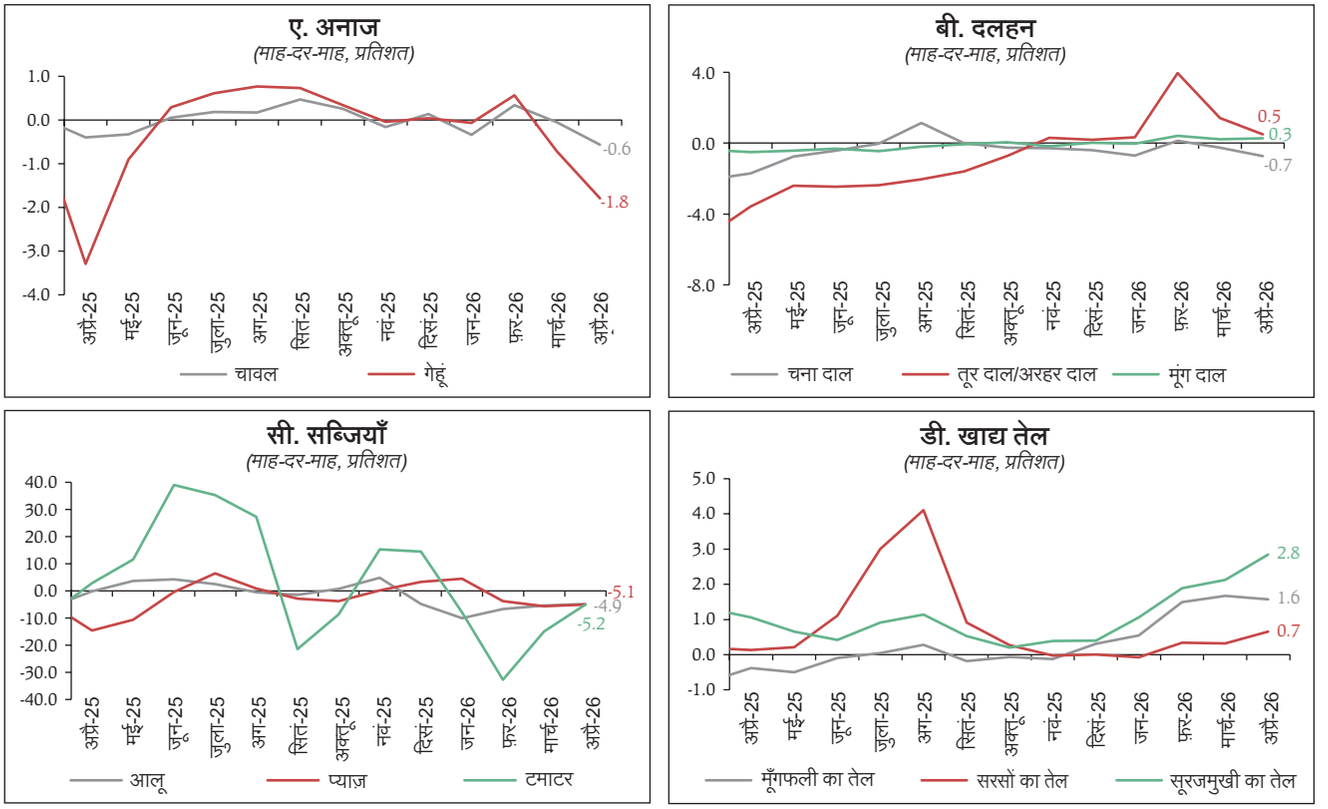

टिप्पणी: आंकड़े 1-16 अप्रैल, 2026 की अवधि से संबंधित हैं और पिछले महीने की संगत अवधि की तुलना में औसत कीमतों में माह-दर-माह परिवर्तन को दर्शाते हैं।
स्रोत : उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ की गणनाएं।

नए ग्राहकों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बढ़ी प्रतियोगिता तथा नए आदेशों में आई नरमी को दर्शाती है। इसके विपरीत, सेवा क्षेत्र की कंपनियों द्वारा वसूली जाने वाली कीमतों में वृद्धि जारी रही, जिसमें घरेलू व्यवसायिक गतिविधियों में आई धीमी गति की पूर्ति अंतरराष्ट्रीय आदेशों में लगभग रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि ने की (चार्ट III.10)।

चार्ट III.10: मार्च में इनपुट कीमतों में आई तेज़ी

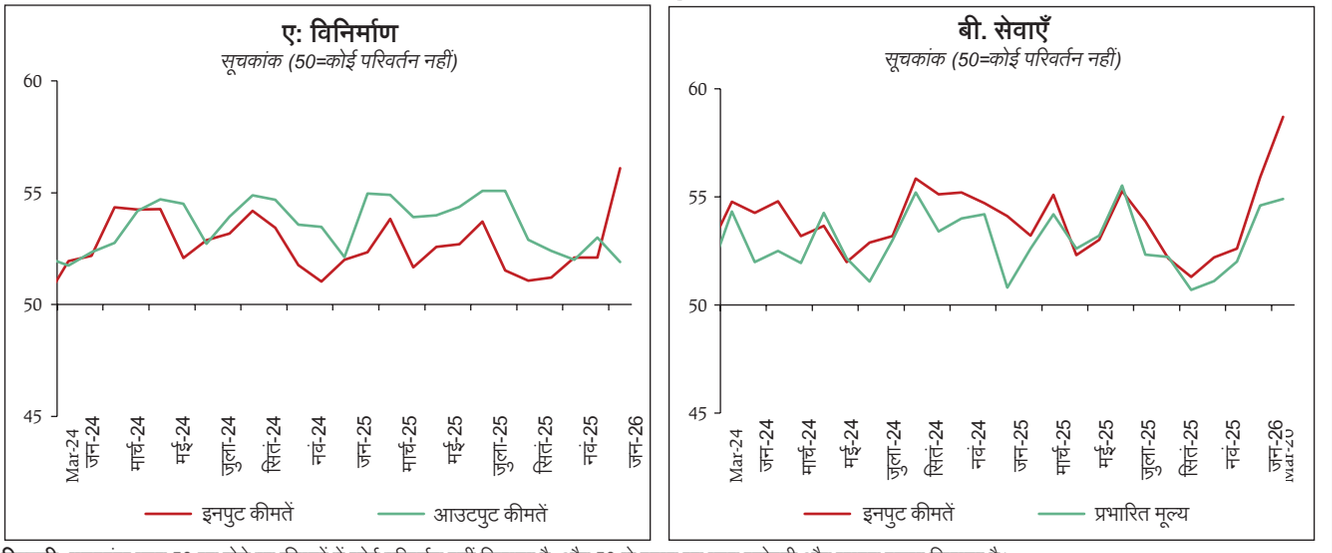

टिप्पणी: सूचकांक स्तर 50 का होने पर कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं दिखाता है, और 50 से ऊपर का स्तर बढ़ोतरी और इसका उल्टा दिखाता है।
स्रोत: एसएंडपी ।

IV. वित्तीय स्थितियां

विदेशी मुद्रा और कॉरपोरेट बॉण्ड बाजारों में अपेक्षाकृत अनुकूल स्थितियों के कारण मार्च की तुलना में अप्रैल में समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ (चार्ट IV.1)।

मार्च में एक पर्याप्त अधिशेष के कारण अप्रैल माह (16 अप्रैल तक) में प्रणालीगत चलनिधि[29] में काफी सुधार हुआ (चार्ट IV.2)।[30] मार्च के पहले पखवाड़े के दौरान, आरबीआई के खुले बाजार परिचालनों (ओएमओ) द्वारा समर्थित प्रणालीगत नकदी की स्थिति संतोषजनक रही।[31] हालांकि, मार्च के दूसरे पखवाड़े में कर और जीएसटी से संबंधित बहिर्वाह के कारण चलनिधि अधिशेष में कमी आई।[32] अप्रैल में चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ क्योंकि तेजी से सरकारी खर्च के साथ-साथ कर बहिर्वाह से उत्पन्न दबाव कम हो गया।

नकदी की स्थिति में सुधार को दर्शाते हुए, मार्च की तुलना में अप्रैल में बैंकों द्वारा स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) का उपयोग उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का उपयोग स्थिर रहा, जिससे पता चलता है कि दैनिक चलनिधि असंतुलन सुप्रबंधित थे।[33]

मुद्रा बाजार

मार्च की पहली छमाही के दौरान भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) नीतिगत गलियारे के निचले आधे हिस्से में बना रहा, किन्तु बाद में यह बढ़ गया और दूसरी छमाही के दौरान रेपो रेट से ऊपर पहुँच गया, जो कर बहिर्वाह को दर्शाता है।[34]

चार्ट IV.1: अप्रैल में वित्तीय स्थितियाँ अच्छी हुई

(2012 से औसत से मानक विचलन)

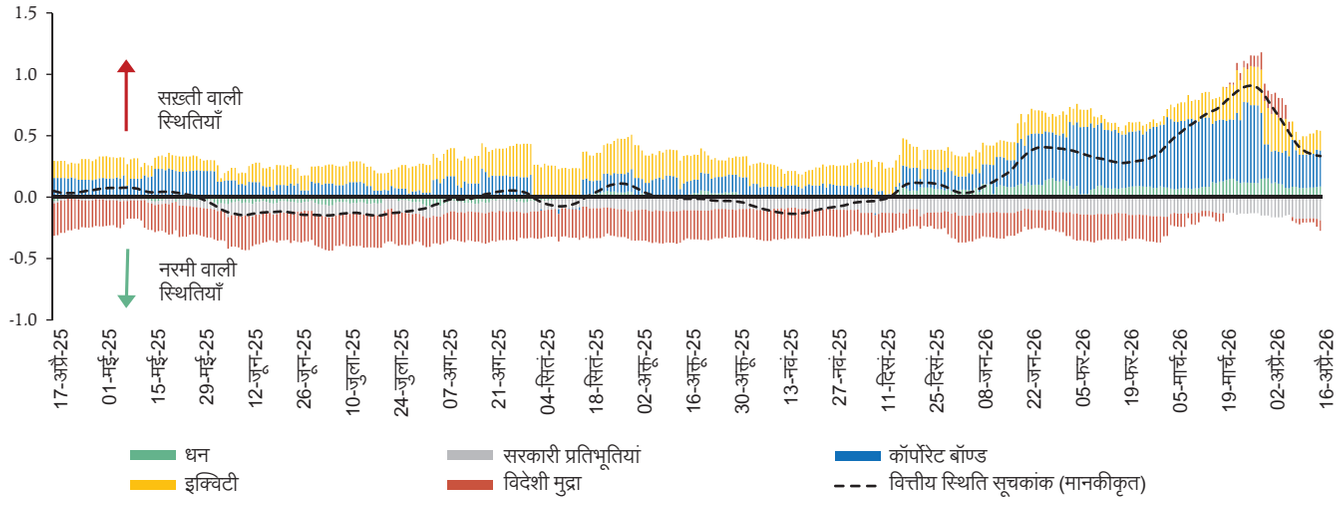

टिप्पणी: वित्तीय स्थिति सूचकांक, सूचकांक के ऐतिहासिक औसत से मानक विचलन को मापता है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ की गणना।

[29] जैसा कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत निवल अवशोषण द्वारा मापा जाता है।

[30] कुल मिलाकर, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत दैनिक औसत निवल अवशोषण मार्च में 1.66 लाख करोड़ रुपये से अप्रैल (16 तारीख तक) के दौरान बढ़कर 4.47 लाख करोड़ रुपये हो गया।

[31] रिज़र्व बैंक ने प्रणाली चलनिधि को समर्थन देने के लिए 9 मार्च और 13 मार्च को 0.5 लाख करोड़ रुपये की दो किस्तों में ओएमओ खरीद नीलामी के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये की टिकाऊ चलनिधि डाली।

[32] मार्च के दूसरे पखवाड़े के दौरान नकदी की अस्थायी तंगी को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने एक दिवसीय से लेकर 7 दिनों तक की परिपक्वता वाली सात परिवर्तनीय रेपो दर (वीआरआर) नीलामियां कीं। आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर के साथ डब्ल्यूएसीआर को संरेखित करने के लिए अप्रैल 10, 2026 और अप्रैल 17, 2026 को दो 7-दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी भी की।

[33] स्थायी जमा सुविधा के तहत औसत शेष अप्रैल (16 तारीख तक) के दौरान बढ़कर 4.67 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो मार्च में 3.22 लाख करोड़ रुपये था। नाममात्र की स्थायी सुविधा से अप्रैल (16 तक) के दौरान औसतन उधारी 0.01 लाख करोड़ रुपये की थी, जो मार्च में 0.02 लाख करोड़ रुपये से मामूली रूप से कम थी।

[34] वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन डब्ल्यूएसीआर में तेजी से वृद्धि हुई, क्योंकि असंपार्श्विक क्षेत्रों में कारोबारी मान में सामान्य वर्ष के अंत में गिरावट आई लेकिन उसके बाद इसमें वृद्धि हुई।

चार्ट IV.2: अप्रैल में प्रणालीगत चलनिधि में सुधार

(₹ लाख करोड़)

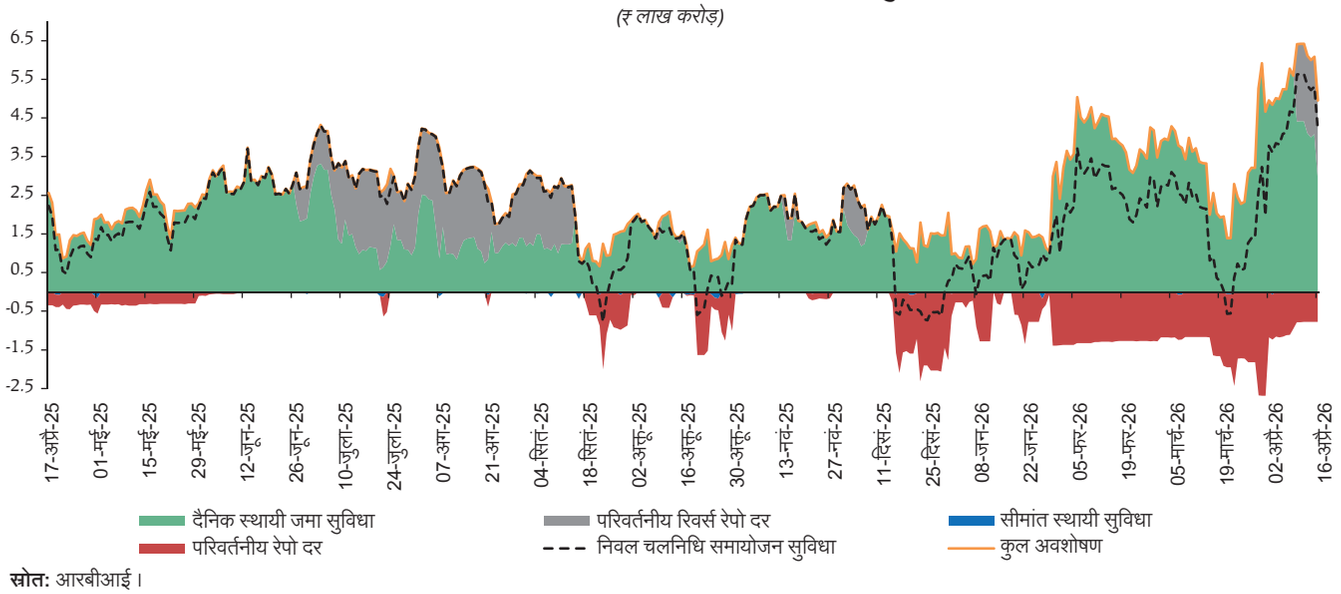

स्रोत: आरबीआई ।

अप्रैल (16 तारीख तक) में अधिशेष चलनिधि की स्थिति के कारण डब्ल्यूएसीआर रेपो दर से नीचे गिर गया (चार्ट IV.3ए)।[35] बेंचमार्क प्रतिभूतित एक दिवसीय रुपया दर (एसओआरआर) द्वारा मापे जाने वाले संपार्श्विक खंडों में एक दिवसीय दरें आमतौर पर असंपार्श्विक दर के साथ आगे बढ़ती हैं। अप्रैल (16 तारीख तक) में ढील से पहले मार्च की दूसरी छमाही के दौरान खजाना बिलों पर औसत प्रतिफल में वृद्धि हुई। मार्च में बढ़े रहने के बाद वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) पर प्रतिफल और जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) पर ब्याज दर, अप्रैल में काफी कम हो गई (चार्ट IV.3 बी)।[36]

चार्ट IV.3: डब्ल्यूएसीआर कारोबार कॉरिडोर के अंदर रहा और अप्रैल में मुद्रा बाजार दर कम रहा

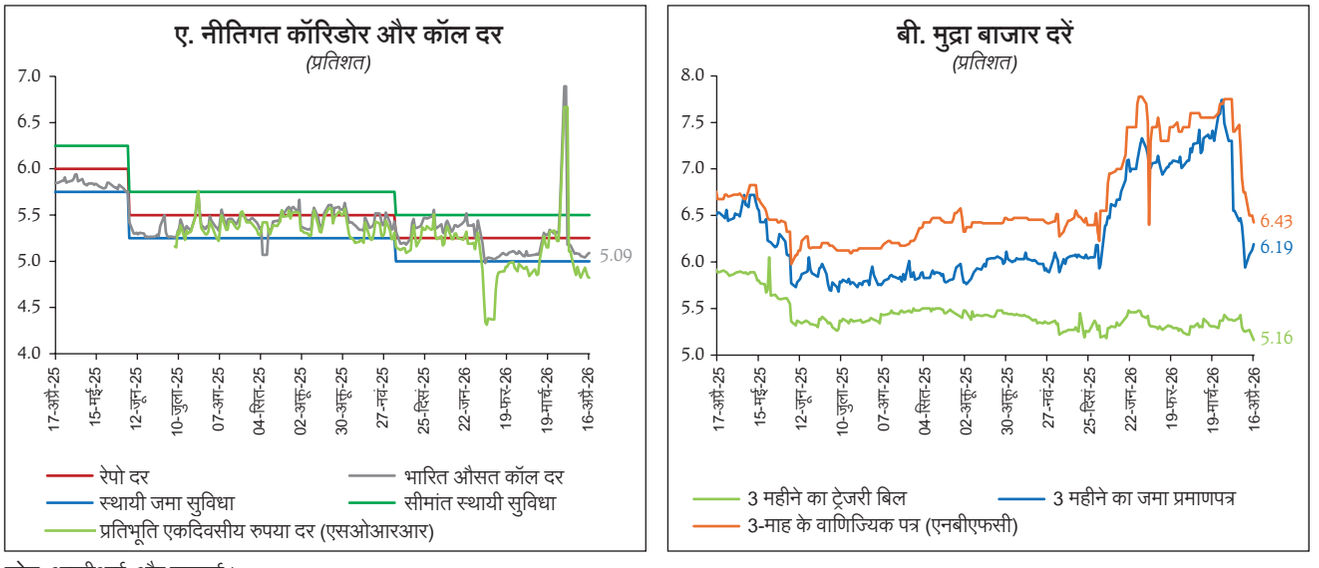

स्रोत: आरबीआई; और ब्लूमबर्ग ।

[35] अप्रैल (16 तारीख तक) के दौरान औसतन डब्ल्यूएसीआर 5.10 प्रतिशत तक कम हो गया, जो मार्च के दौरान 5.28 प्रतिशत था।

[36] मार्च की तुलना में अप्रैल (16 तारीख तक) के दौरान 3 महीने के खजाना बिलों पर औसत प्रतिफल में 2 आधार अंकों (बीपीएस) की कमी आई है, जबकि एनबीएफसी द्वारा जारी 3 महीने के वाणिज्यिक पत्रों पर प्रतिफल और 3 महीने के जमा प्रमाण पत्र पर ब्याज दर में क्रमशः 59 बीपीएस और 97 बीपीएस की कमी आई है।

चार्ट IV.4: सीज़फ़ायर की घोषणा के बाद सरकारी प्रतिभूति के प्रतिफल में कमी आई

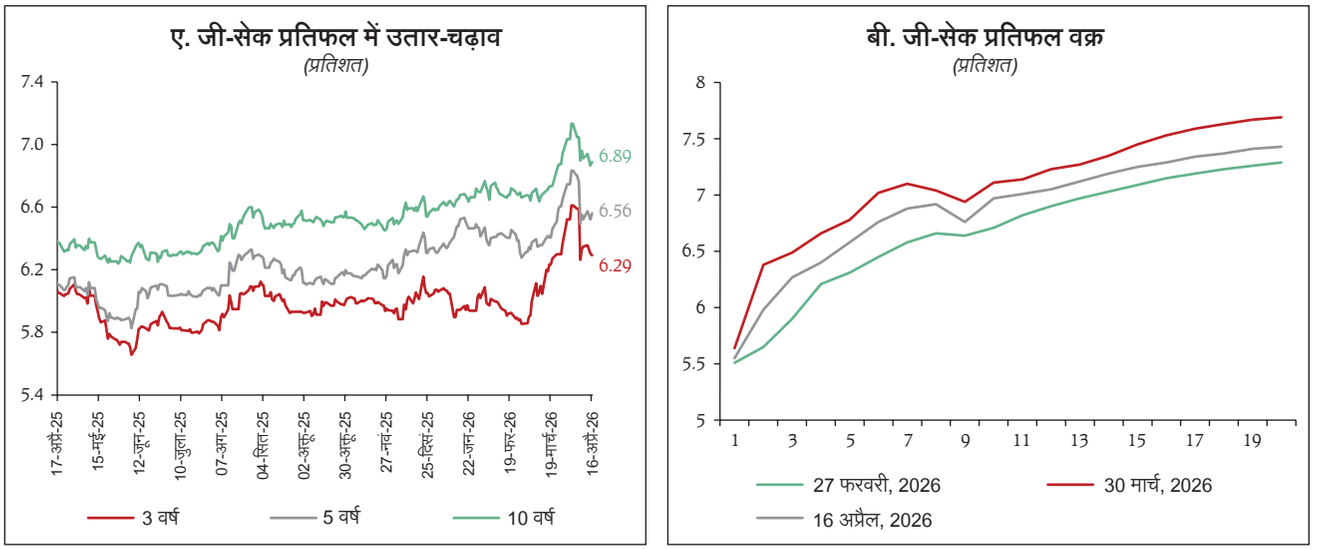

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और वित्तीय बेंचमार्क भारत प्राइवेट लिमिटेड।

मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (3 महीने के वाणिज्यिक पत्र और 91-दिवसीय खजाना बिल पर प्रतिफल के बीच का प्रसार) कम हो गया।[37]

सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार

पश्चिम एशिया संघर्ष के आरंभ होने के साथ मार्च के दौरान परिपक्वताओं में दिनांकित सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) प्रतिफल में वृद्धि हो गई (चार्ट IV.4 ए)।[38] अप्रैल की शुरुआत में प्रतिफल में वृद्धि जारी रही, लेकिन अस्थायी युद्धविराम की घोषणा के बाद यह बहुत कम हो गई। हालांकि, प्रतिफल ने फरवरी के अंत के स्तर से अधिक कारोबार किया, जो मौजूदा अनिश्चितता को दर्शाता है (चार्ट IV.4बी)।

कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार

मार्च (15 मार्च तक) की तुलना में अप्रैल में अधिकांश अवधि और रेटिंग स्पेक्ट्रम में कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल में बढ़ोतरी हो गई, जबकि उनके प्रसार में कमी आई (सारणी IV.1)। फरवरी 2026 की तुलना में मार्च 2026 में नए कॉरपोरेट बॉण्ड जारी करने में

सारणी IV.1: कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल में कमी आई

	ब्याज दरें *(प्रतिशत)*			स्प्रेड *(आधार बिन्दु)* (संबंधित जोखिम-मुक्त दर से अधिक)		
लिखत	**मार्च 2026**	**अप्रैल 2026 (15 अप्रैल तक)**	**अंतर (बीपीएस)**	**मार्च 2026**	**अप्रैल 2026 (15 अप्रैल तक)**	**अंतर**
1	**2**	**3**	**(4 = 3-2)**	**5**	**6**	**(7 = 6-5)**
(i) एएए (1-वर्ष)	7.40	7.31	-9	171	161	-10
(ii) एएए (3-वर्ष)	7.36	7.61	25	112	110	-2
(iii) एएए (5 वर्ष)	7.52	7.68	16	92	88	-4
(iv) एए (3-वर्ष)	8.22	8.44	22	198	193	-5
(v) बीबीबी माइनस (3-वर्ष)	11.92	12.14	22	567	563	-4

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना संबंधित अवधि के लिए औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: फीमडा।

[37] मार्च में 228 बीपीएस के औसत से अप्रैल में 170 बीपीएस (16 तारीख तक) तक कम हो गया.

[38] 10 साल के जी-सेक पर सामान्य प्रतिफल 30 मार्च को 7.04 प्रतिशत से घटकर 16 अप्रैल को 6.89 प्रतिशत रह गई। 27 फरवरी को प्रतिफल 6.66 प्रतिशत थी।

वृद्धि हुई। हालांकि, संचयी आधार पर, पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में कुल निर्गम कम रहे हैं।[39]

निधि और ऋण

मार्च 2026 के दौरान, आरक्षित निधि (सीआरआर के लिए समायोजित) ने अपने उच्च विकास पथ को बनाए रखा और प्रचलन में मुद्रा का मजबूत गति से विस्तार हुआ।[40] मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि भी उच्च रही (चार्ट IV.5)।[41]

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण और जमा वृद्धि में मार्च के दौरान वृद्धि हुई, जिसमें 2025-26 की दूसरी छमाही (चार्ट IV.6) के बाद से जमा की तुलना में ऋण में वृद्धि हुई।[42]

बैंक ऋण के साथ-साथ, गैर-बैंक स्रोतों से वित्त का भी 2025-26 (31 मार्च तक) विस्तार हुआ। वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह एक वर्ष पहले के 32.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 44.7 लाख करोड़ रुपये हो गया (सारणी IV.2ए)। वर्ष के दौरान गैर-बैंक स्रोतों - कारपोरेट बॉण्ड जारी करने और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश[43] में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।[44] 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए कुल बकाया ऋण में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें गैर-बैंक स्रोतों में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (सारणी IV.2बी)।

फरवरी 2026 में, गैर-खाद्य बैंक ऋण[45] ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक-आधारित विस्तार दर्ज किया (चार्ट IV.7)। कृषि

चार्ट IV.5: आरक्षित धन और प्रचलन में मुद्रा ($एम_3$) में टिकाऊ प्रसार

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

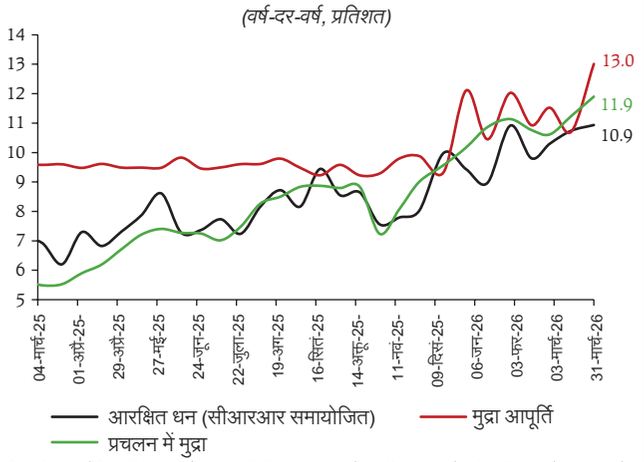

टिप्पणियां: बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 के ज़रिए पखवाड़े की परिभाषा में बदलाव के साथ, आरक्षित धन और मुद्रा आपूर्ति का डेटा 15 दिसंबर, 2025 से प्रभावी होकर महीने के 15वें और आखिरी दिन से जुड़ा होगा।

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.6: बैंक ऋण और जमा वृद्धि में बढ़ोतरी

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

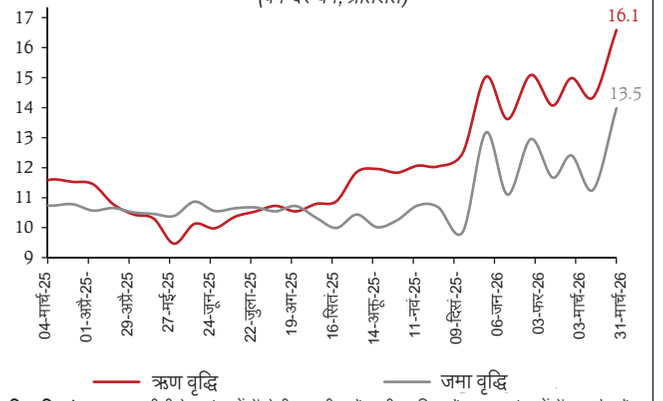

टिप्पणियां: 1. एससीबी के आंकड़ों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं। उक्त आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का असर भी शामिल है।

2. बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 के ज़रिए पखवाड़े की परिभाषा में बदलाव के साथ, एससीबी के लिए डेटा 15 दिसंबर, 2025 से प्रभावी होकर महीने के 15वें और आखिरी दिन से जुड़ा होगा।

स्रोत: पाक्षिक धारा 42 विवरणी, आरबीआई।

[39] सेबी के आंकड़ों के अनुसार, मार्च में निर्गम बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो फरवरी में 0.66 लाख करोड़ रुपये था। संचयी आधार (अप्रैल 2025-मार्च 2026) पर, यह 2025-26 में ₹9.11 लाख करोड़ था, जो पिछले वर्ष में ₹9.95 लाख करोड़ से कम था।

[40] आरक्षित धन वृद्धि (नकद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित) 30 मार्च, 2026 को बढ़कर 10.9 प्रतिशत हो गई, जो 28 फरवरी, 2026 को 10.3 प्रतिशत थी। इसी अवधि के दौरान प्रचलनगत मुद्रा में वृद्धि 10.6 प्रतिशत से बढ़कर 11.9 प्रतिशत हो गई।

[41] मुद्रा आपूर्ति वृद्धि 31 मार्च, 2026 को बढ़कर 13.0 प्रतिशत हो गई, जो 28 फरवरी, 2026 को 11.5 प्रतिशत थी।

[42] एससीबी की ऋण और जमा वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) 31 मार्च, 2026 को क्रमशः 16.1 प्रतिशत और 13.5 प्रतिशत हो गई, जो 28 फरवरी, 2026 को क्रमशः 14.5 प्रतिशत और 11.9 प्रतिशत थी।

[43] भारत में निवल आधार पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (अर्थात् प्रत्यावर्तन/विनिवेश के लिए समायोजित सकल अंतर्वाह)।

[44] 2025-26 (फरवरी 2026 तक) के दौरान गैर-वित्तीय संस्थाओं और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा जारी किए गए 44 कॉरपोरेट बॉण्ड क्रमशः 3.01 लाख करोड़ रुपये और 3.24 लाख करोड़ रुपये हो गए, जो 2024-25 की इसी अवधि के दौरान 1.35 लाख करोड़ रुपये और 2.17 लाख करोड़ रुपये थे।

[45] अनंतिम डेटा। बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण संबंधी आंकड़े क्षेत्र-वार और उद्योग-वार बैंक ऋण (एसआईबीसी) विवरणी पर आधारित होते हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा प्रदान किए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा 41 चुनिंदा बैंकों को शामिल किया जाता है। 31 दिसंबर, 2025 से बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत अंतिम रिपोर्टिंग पखवाड़े की परिभाषा को महीने के अंतिम दिन में बदल दिया गया है। तदनुसार, दिसंबर 2025 से वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर चालू वर्ष के महीने के अंत के आंकड़ों और पिछले वर्ष के इसी महीने के लिए अंतिम रिपोर्टिंग पखवाड़े (पुरानी परिभाषा के अनुसार) के आंकड़ों पर आधारित है। गैर-खाद्य ऋण वृद्धि की गणना पाक्षिक धारा-42 विवरणी के आधार पर की जाती है, जिसमें सभी एससीबी शामिल हैं।

सारणी IV.2ए: वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह बढ़ा

(₹ लाख करोड़)

स्रोत	अप्रैल-मार्च		31 जनवरी तक	
	2023-24	2024-25	2024-25	2025-26 पी
ए. गैर-खाद्य बैंक ऋण	**22.95**	**18.08**	**18.08**	**29.19**
बी. गैर-बैंक स्रोत (बी1+बी2)	**12.64**	**17.10**	**14.25**	**15.48**
बी1. घरेलू स्रोत	10.20	13.86	10.98	10.56
बी2. विदेशी स्रोत	2.43	3.25	3.27	4.92
सी. संसाधनों का कुल प्रवाह (ए+बी)	**35.59**	**35.18**	**32.33**	**44.67**

पी: अनंतिम।

टिप्पणियाँ: 1. संख्याओं को पूर्णांकित करने के कारण आकड़ों का योग भिन्न हो सकता है।
2. विस्तृत टिप्पणियों और डेटा के लिए, कृपया वर्तमान सांख्यिकी सारणी संख्या: 18 (ए) देखें।

स्रोत: आरबीआई; सेबी; एआईएफआई; और आरबीआई कर्मचारियों की गणना।

सारणी IV.2बी: वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बकाया ऋण

(₹ लाख करोड़; कोष्ठक में आंकड़े वर्ष दर वर्ष प्रतिशत परिवर्तन हैं)

स्रोत	मार्च के अंत में		31 मार्च तक	
	2024	2025	2025	2026 पी
ए. गैर-खाद्य बैंक ऋण	**165.64**	**183.72**	**183.72**	**212.91**
	(21.3)	**(10.9)**	**(10.9)**	**(15.9)**
बी. गैर-बैंक स्रोत (बी1+बी2)	**77.57**	**88.86**	**85.57**	**98.91**
	(4.2)	**(14.6)**	**(13.4)**	**(15.6)**
बी1. घरेलू स्रोत	56.59	66.37	62.65	73.27
	(4.9)	(17.3)	(14.8)	(17.0)
बी2. विदेशी स्रोत	20.98	22.49	22.92	25.64
	(2.4)	(7.2)	(9.8)	(11.9)
सी. कुल ऋण (ए+बी)	**243.21**	**272.58**	**269.29**	**311.82**
	(15.3)	**(12.1)**	**(11.7)**	**(15.8)**

पी: अनंतिम।

टिप्पणियाँ: 1. कॉलम में आंकड़े पूर्णांकन के कारण कुल से मेल नहीं खा सकते हैं।
2. गैर-बैंक स्रोतों के आंकड़ों में घरेलू स्रोतों के तहत इक्विटी और हाइब्रिड लिखत जारी किए जाने और विदेशी स्रोतों के तहत इक्विटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल नहीं है।
3. बकाया डेटा के आधार पर प्रवाह सारणी IV.2ए में प्रदान किए गए प्रवाह के साथ मेल नहीं खा सकता है। इसका कारण निम्नलिखित हो सकता है:
   (ए) 1 जुलाई 2023 को एचडीएफ़सी बैंक के साथ एचडीएफ़सी लिमिटेड का विलय;
   (बी) कुछ आवास वित्त कंपनियों का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में परिवर्तन; और
   (सी) विदेशी स्रोतों के मामले में मूल्यांकन प्रभाव।
4. विस्तृत नोट्स और डेटा के लिए, कृपया वर्तमान सांख्यिकी सारणी संख्या: 18 (बी) देखें।

स्रोत: आरबीआई; सेबी; एआईएफआई; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान ।

और औद्योगिक ऋण वृद्धि में बढ़ोतरी देखी गई। बड़े उद्योगों और एमएसएमई, दोनों के लिए ऋण मजबूत गति से बढ़ता रहा। एनबीएफसी और वाणिज्यिक स्थावर संपदा को बैंक ऋण देने में लगातार दो अंकों की वृद्धि के कारण सेवा क्षेत्र में ऋण प्रवाह में तेजी बनी रही। व्यतिगत ऋण के दायरे में आवास और वाहन क्षेत्र में स्थिरता रही, जबकि स्वर्ण ऋण में वृद्धि अधिक रही।

जमा और उधार दरें

नीतिगत रेपो दर में संचयी 125 आधार अंकों (बीपीएस) की कमी के परिणामस्वरूप, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने फरवरी 2025 से फरवरी 2026 के दौरान रेपो-सम्बद्ध बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दरों और निधि -आधारित उधार दरों की सीमांत लागत दोनों को समायोजित किया है (सारणी IV.3)। भारित औसत उधार दरों (डबल्यूएएलआर) के लिए संचरण सभी क्षेत्रों में चल रहे सहजता चक्र के दौरान मजबूत रहा है (चार्ट IV.8)। जमा पक्ष पर, नई जमाओं पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर में नरमी मुख्य रूप से थोक जमाओं के कारण हुई।

फरवरी 2025 से फरवरी 2026 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी बैंकों के लिए डब्ल्यूएएलआर का संचरण अधिक था। जमा पक्ष पर, संचरण की सीमा मोटे तौर पर दोनों समूहों में समान थी। विदेशी बैंकों के लिए जमा और उधार दरों दोनों में कमी अधिक रही है (चार्ट IV.9)।

इक्विटी बाजार

लगातार भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच मार्च में भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट आई। सभी क्षेत्रों में व्यापक

चार्ट IV.7: व्यापक आधार पर बैंक ऋण वृद्धि

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

स्रोत: आरबीआई ।

आधार पर गिरावट देखी गई, जिससे अस्थिरता में तेज वृद्धि हुई।[46] अप्रैल (16 तारीख तक) में, हालांकि, अमेरिका-ईरान शांति वार्ता की बहाली और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच बाजारों में सुधार हुआ (चार्ट IV.10)।

सारणी IV.3: बैंकों की जमा और ऋण दरों में मजबूत संचरण

(आधार अंक)

		सावधि जमा दरें		ऋण दरें				
अवधि	रेपो दर	डबल्यूएडीटीडीआर – नया जमा	डबल्यूएडीटीडीआर-बकाया जमा	ईबीएलआर	1-वर्षीय एमसीएलआर (माध्यिका)	डबल्यूएएलआर – नया रुपया ऋण		डबल्यूएएलआर-बकाया रुपया ऋण
						कुल मिलाकर	ब्याज दर प्रभाव#	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
सख़्ती वाली अवधि मई 2022 से जनवरी 2025 तक	250	259	206	250	175	182	191	115
ढील वाली अवधि फर 2025 से फर 2026 तक	-125	-97	-47	-125	-55	-89	-92	-87

#: जनवरी 2025 की भारतिा के आधार पर गणना की गई।
डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर। डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर;
एमसीएलआर: निधि-आधारित उधार दर की सीमांत लागत; ईबीएलआर: बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दर।
टिप्पणी: ईबीएलआर संबंधी आंकडे 32 घरेलू बैंकों से संबंधित हैं।
स्रोत: आरबीआई।

[46] इंडिया VIX फरवरी के अंत में 13.7 से मार्च के अंत में दोगुना से बढ़कर 27.9 के स्तर पर पहुंच गया। यह 16 अप्रैल, 2026 को घटकर 18.1 के स्तर पर आ गया।

चार्ट IV.8: विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक आधार पर संचरण (फरवरी 2025 - फरवरी 2026)

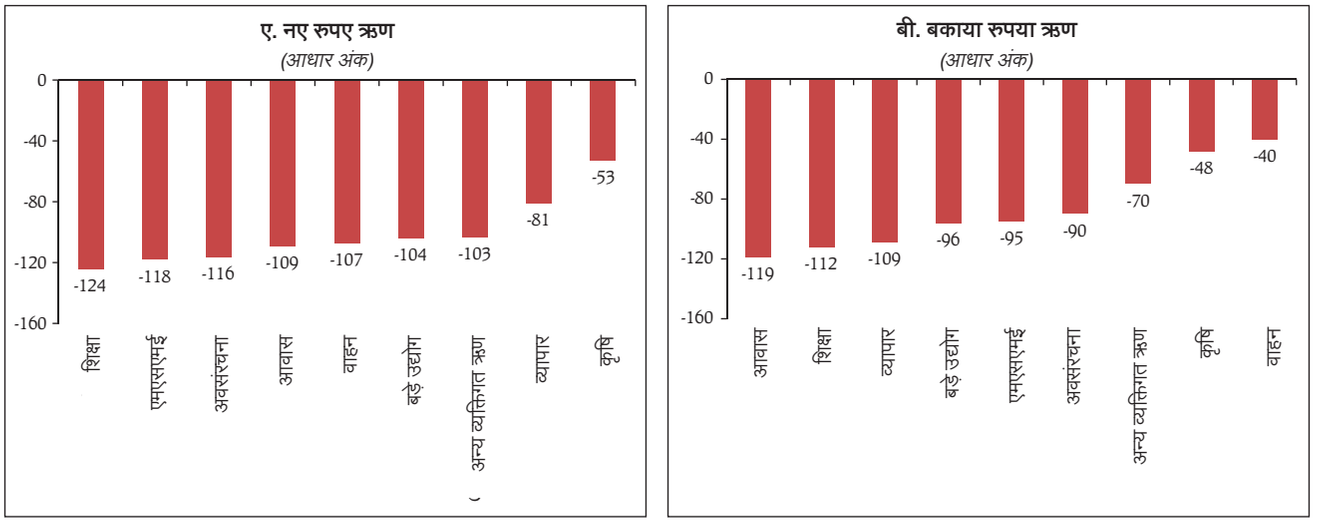

टिप्पणी: फरवरी 2025 से फरवरी 2026 के दौरान अंतरण की गणना जनवरी 2025 की भारित औसत दर को फरवरी 2026 की भारित औसत दर से घटाकर की जाती है।
स्रोत: आरबीआई।

वित्त के बाहरी स्रोत

अप्रैल 2025 - फरवरी 2026 के दौरान, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह सकल और निवल दोनों स्थितियों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहा।[47] फरवरी में, उच्च सकल अंतर्वाह और कम प्रत्यावर्तन के कारण लगातार छह महीनों तक ऋणात्मक रहने के बाद निवल एफडीआई धनात्मक हो गया। फरवरी में बाहरी एफडीआई प्रवाह का लगभग 75 प्रतिशत सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और यूके में किया गया था (चार्ट IV.11)।

2025-26 के दौरान, निवल एफपीआई ने मुख्य रूप से इक्विटी खंड द्वारा संचालित बहिर्वाह दर्ज किया।[48] मार्च में, पश्चिम

चार्ट IV.9: बैंक समूह में मौद्रिक संचरण (फरवरी 2025 - फरवरी 2026)

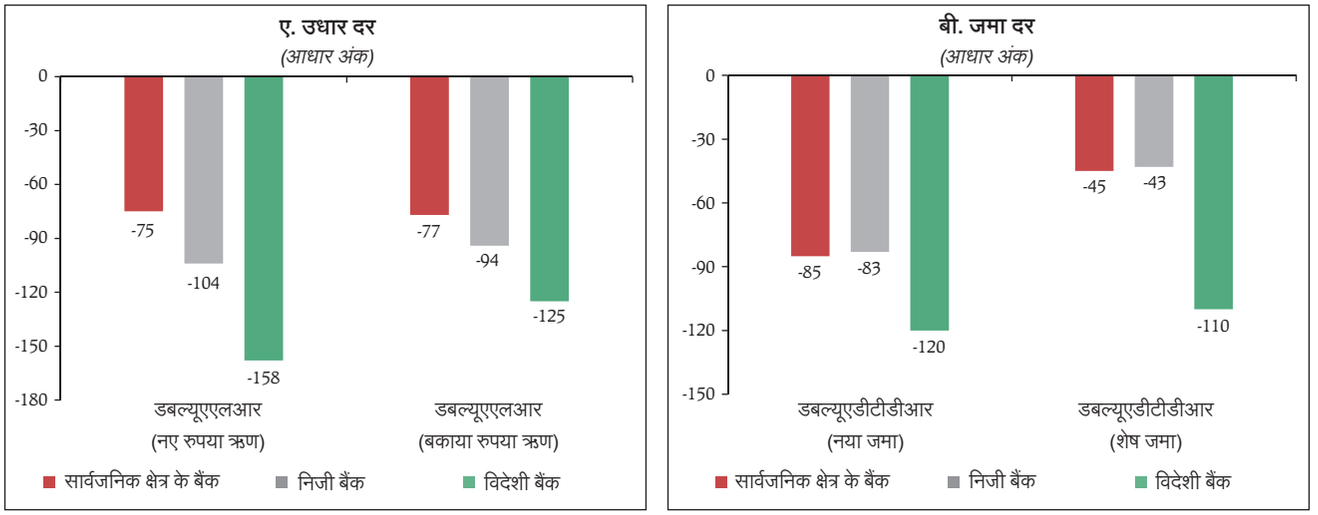

टिप्पणी : फरवरी 2025 से फरवरी 2026 के दौरान अंतरण की गणना जनवरी 2025 की भारित औसत उधार और जमा दर को फरवरी 2026 की भारित औसत दर से घटाकर की जाती है।
स्रोत: आरबीआई।

[47] अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के दौरान सकल एफडीआई प्रवाह बढ़कर 88.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले की इसी अवधि के दौरान 74.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसी तरह, इसी अवधि के दौरान निवल एफडीआई प्रवाह 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

[48] वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 48 निवल एफपीआई बहिर्वाह 16.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। मार्च 2026 में, निवल एफपीआई ने 13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह दर्ज किया।

चार्ट IV.10: पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद से अप्रैल में इक्विटी मार्केट में सुधार हुआ

(इंडेक्स, बायां स्केल; हजार करोड़, दायां स्केल)

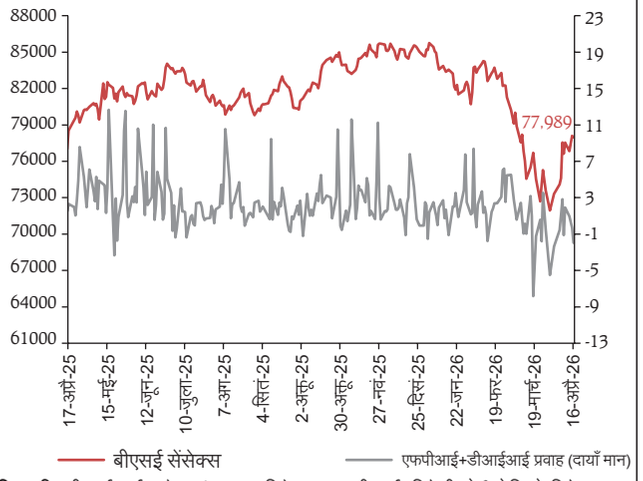

टिप्पणी: डीआईआई: घरेलू संस्थागत निवेशक; एफपीआई: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक।

स्रोत: ब्लूमबर्ग

IV.12: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक मार्च में निवल विक्रेता

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

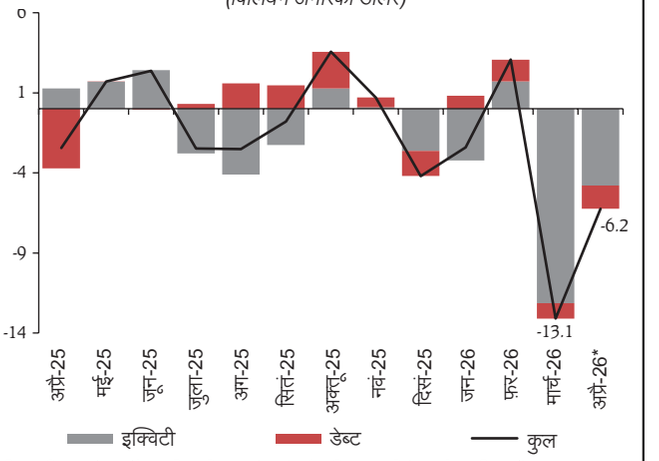

टिप्पणी: 1. डेब्ट में हाइब्रिड लिखत के अंतर्गत किए गए निवेश भी शामिल हैं।
2. *: 16 अप्रैल तक का डेटा।

स्रोत: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)।

एशिया संघर्ष के बाद वैश्विक निवेशकों की भावनाओं में गिरावट के कारण निवल एफपीआई बहिर्वाह में वृद्धि हुई (चार्ट IV.12)।

पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल 2025 - फरवरी 2026 के दौरान बाहरी वाणिज्यिक उधारों के पंजीकरण और निवल प्रवाह में कमी आई, जो अपतटीय धन उगाहने वाली गतिविधि में मंदी को दर्शाता है (चार्ट IV.13)।[49] उधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कॉरपोरेट द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए जुटाया गया था।[50]

चार्ट IV.11: फरवरी में निवल एफडीआई धनात्मक हुआ

ए. सकल और निवल एफडीआई

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

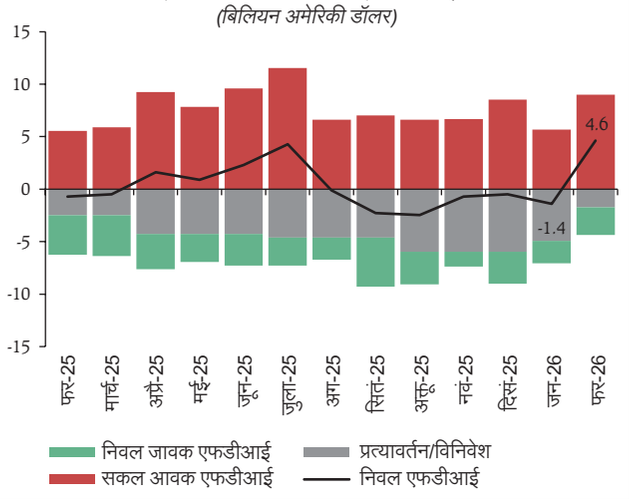

बी. देश-वार बाह्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

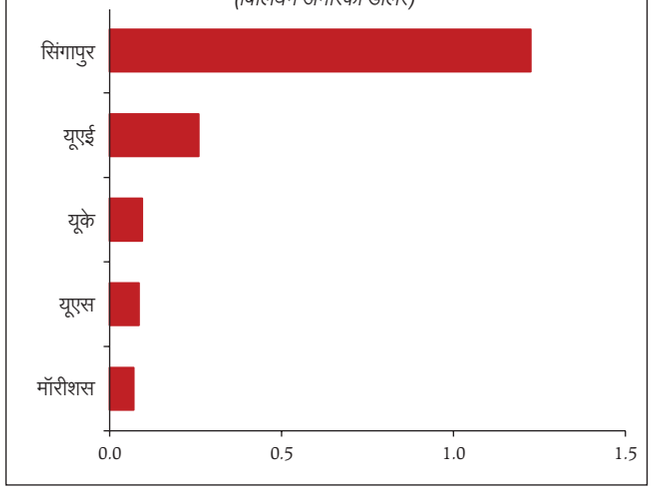

स्रोत: आरबीआई।

[49] कुल ईसीबी पंजीकरण अप्रैल 2025-फरवरी 2026 के दौरान घटकर 37.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले की इसी अवधि में 50.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

[50] पूंजीगत व्यय के उद्देश्य के लिए जुटाई गई उधार का हिस्सा अप्रैल 2025-फरवरी 2026 के दौरान 42.8 प्रतिशत से थोड़ा कम था, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के दौरान 43.9 प्रतिशत था।

चार्ट IV.13: बाह्य वाणिज्यिक उधारी में कमी

(बिलियन यूएस $)

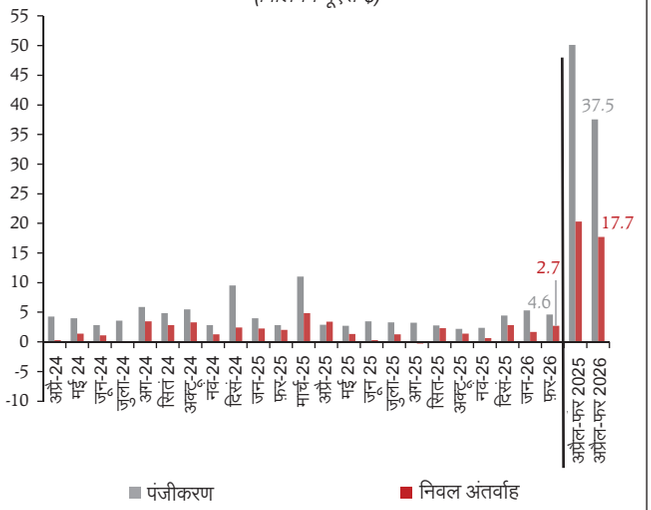

स्रोत: आरबीआई

चार्ट IV.15: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त रहा

(बिलियन यूएस $, बायां मान; माह, दायां मान)

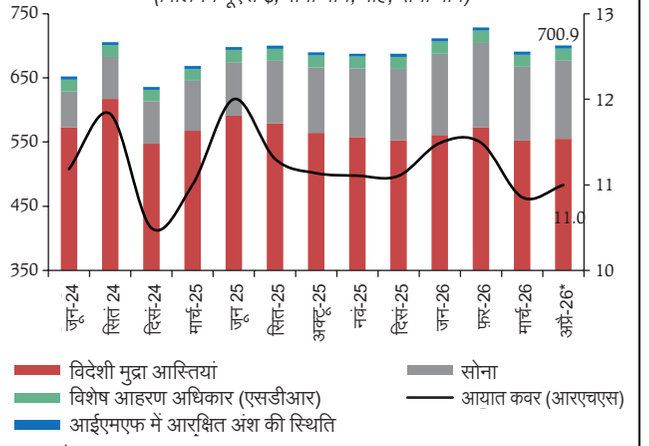

*: 10 अप्रैल, 2026 तक

टिप्पणी: भुगतान शेष आंकड़ों के अनुसार आयात कवर डेटा वार्षिक पण्य आयात पर आधारित है।

स्रोत: आरबीआई।

प्रमुख बाहरी क्षेत्र सुभेद्यता संकेतक, अर्थात, बाहरी ऋण-से-जीडीपी अनुपात, सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के लिए निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) और कर्ज चुकौती अनुपात, दिसंबर 2025 के अंत में स्थिर रहे। दिसंबर 2025 के अंत में भारत का विदेशी ऋण 765.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो सितंबर 2025 के अंत में अपने स्तर से 18.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज करता है (चार्ट IV.14)।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार संतोषजनक बना हुआ है, जो दिसंबर 2025 के अंत तक लगभग 11 महीने[51] के माल आयात और बकाया विदेशी ऋण का लगभग 92 प्रतिशत[52] कवर प्रदान करता है (चार्ट IV.15)।

चार्ट IV.14: भारत के बाहरी सुभेद्यता संकेतक नियंत्रित रहे

(प्रतिशत)

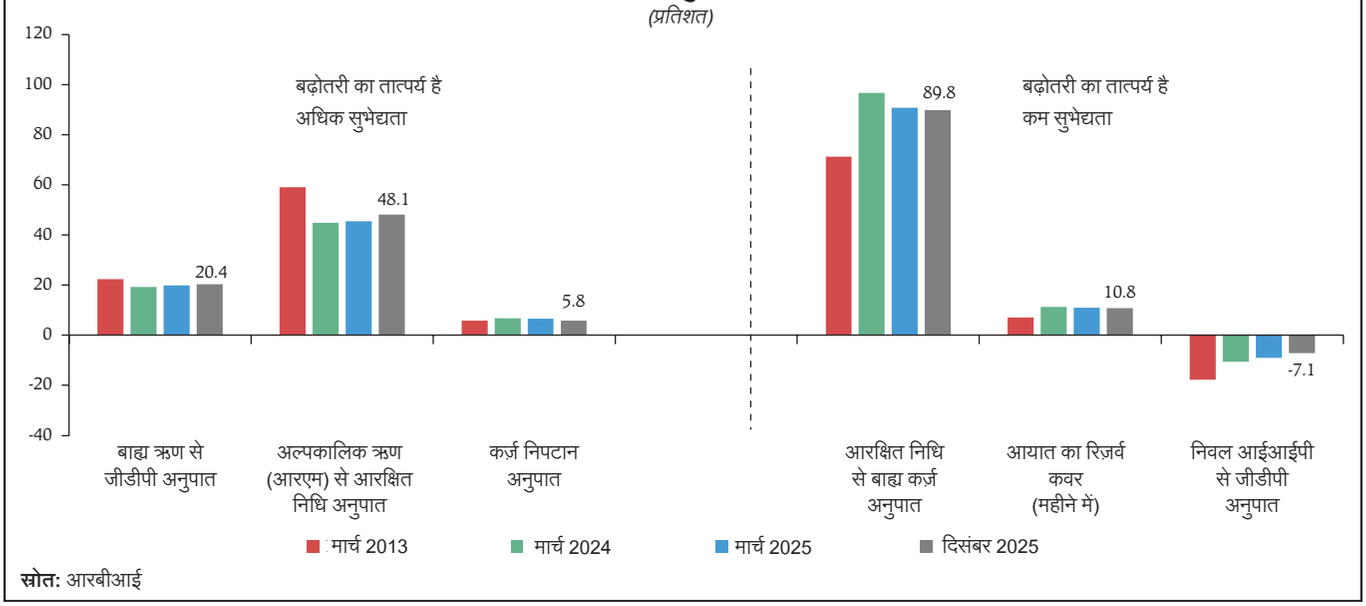

स्रोत: आरबीआई

[51] 10 अप्रैल, 2026 तक, वस्तुओं और सेवाओं के लिए आयात कवर लगभग 8.7 महीने था।

[52] गणना 10 अप्रैल, 2026 तक के आरक्षित निधि का उपयोग करती है।

2025-26 की तीसरी तिमाही (चार्ट IV.16) के दौरान भारत की निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) में सुधार हुआ।[53] यह सुधार भारत में विदेशी स्वामित्व वाली आस्तियों की तुलना में भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय आस्तियों में उच्च वृद्धि से प्रेरित था।[54]

चार्ट IV. 16: भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति में सुधार

(बिलियन यूएस $, बायां मान; बिलियन यूएस $, दायां मान)

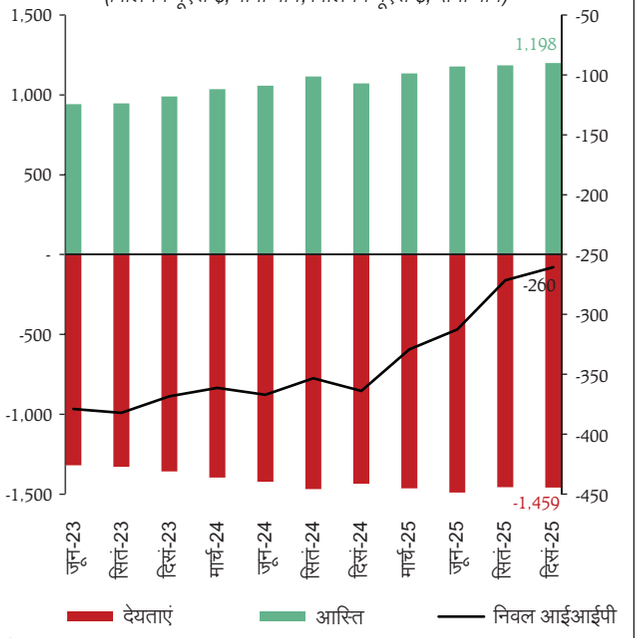

स्रोत: आरबीआई

विदेशी मुद्रा बाजार

पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच, मार्च में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये (आईएनआर) में गिरावट देखी गई (चार्ट IV.17)।[55] तथापि, रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों[56] और अमरीका और ईरान के बीच युद्धविराम की घोषणा के बाद अप्रैल में मूल्यह्रास के दबावों को नियंत्रित कर लिया गया था। वास्तविक अर्थों में, भारतीय रुपये में नाममात्र प्रभावी स्थितियों में मूल्यह्रास और अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की तुलना में भारत में अपेक्षाकृत कम मुद्रास्फीति के कारण मार्च में भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ (चार्ट IV.18)।

चार्ट IV.17: मार्च में अवमूल्यन के बाद अप्रैल में आईएनआर में मजबूती आई

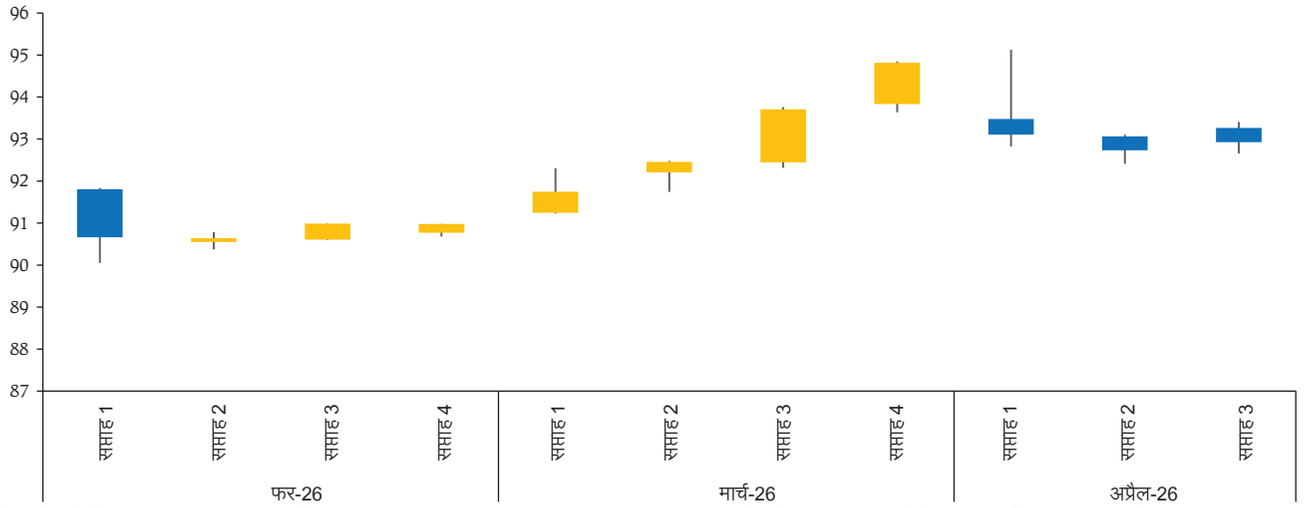

टिप्पणी : पीली कैंडल्स अवमूल्यन को दर्शाती हैं, अर्थात, सप्ताहांत पर आईएनआर खुलने के मुकाबले मजबूत स्थिति में बंद हुआ है। नीली कैंडल्स अधिमूल्यन को दर्शाती हैं, अर्थात सप्ताहांत पर आईएनआर खुलने के मुकाबले कमजोर स्थिति में बंद हुआ है।

स्रोत:आरबीआई।

[53] 10.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सुधार हुआ और यह 260.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

[54] अंतरराष्ट्रीय देयताओं के लिए भारत की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों का अनुपात दिसंबर 2025 में मामूली रूप से सुधरकर 82.1 प्रतिशत हो गया, जो सितंबर 2025 में 81.4 प्रतिशत था।

[55] मार्च में फरवरी के अंत में रुपये में 3.9 प्रतिशत की गिरावट आई।

[56] इन उपायों में तटवर्ती सुपुर्दगी योग्य बाजार में प्राधिकृत डीलरों की निवल खुली स्थिति को सीमित करना और गैर-सुपुर्दगी योग्य वायदा बाजार में उनकी गतिविधियों को सीमित करना शामिल है।

चार्ट IV.18 : 40 मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में परिवर्तन

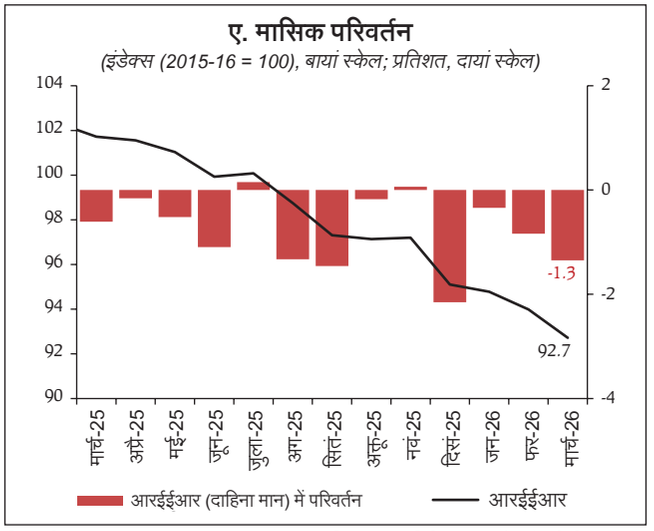

टिप्पणी: धनात्मक बदलाव नाममात्र और वास्तविक प्रभाव विनिमय दर में बढ़ोतरी दिखाता है और ऋणात्मक बदलाव अवमूल्यन दिखाता है।
स्रोत: आरबीआई ।

V. निष्कर्ष

पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण आपूर्ति शृंखला में व्यवधान और बढ़ती ऊर्जा लागत के साथ वैश्विक व्यापक आर्थिक परिवेश में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। पण्य की कीमतों और वित्तीय बाजारों में बढ़ी हुई अस्थिरता ने अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। संघर्ष का और तेज होना, इसका विस्तार और व्यापक भौगोलिक प्रसार वैश्विक दृष्टिकोण के लिए प्रमुख नकारात्मक जोखिम बने हुए हैं। संघर्ष की तीव्रता और अवधि तथा ऊर्जा एवं अन्य बुनियादी ढांचे को परिणामी नुकसान मुद्रास्फीति और विकास के दृष्टिकोण में जोखिम बढ़ाते हैं।[57] यदि संघर्ष बना रहता है और आपूर्ति शृंखलाओं को जल्दी बहाल नहीं किया जाता है, तो यह उच्च ऊर्जा लागत, इनपुट लागत दबाव, व्यापार प्रवाह में व्यवधान और वित्तीय बाजार के स्पिलओवर के रूप में घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। हालांकि मुद्रास्फीति सहनीयता बैंड के भीतर निहित है, लेकिन मौसम से संबंधित अनिश्चितताओं सहित आपूर्ति-पक्ष के व्यवधानों से प्रेरित होने वाले जोखिम में वृद्धि हुई है। आपूर्ति के आघातों के साथ संभावित दूसरे दौर के प्रभाव भी मांग के आघातों को बदल सकते हैं, जो सावधानीपूर्वक और निरंतर मूल्यांकन की अपेक्षा दर्शाते हैं। हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के अस्थायी संघर्ष विराम ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कुछ राहत दी है। यह अपेक्षा की जा सकती है कि सुदृढ़ समष्टि-आर्थिक स्थितियां, भारतीय अर्थव्यवस्था को इस तरह के आघातों का सामना करने के लिए अपनी लोचनीयता बनाए रखने में मदद प्रदान कर सकती हैं।

[57] मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2026-27 मौद्रिक नीति समिति का संकल्प, अप्रैल, 2026

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

आवसरिक श्रृंखलाएं

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	161
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	162
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	163
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	164
4(ए)	भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का परिपक्वता विश्लेषण (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	165
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	165
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	166
7	मुद्रा स्टॉक (एम3) के स्रोत	167
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	168
9	कुल चलनिधि राशियाँ	169
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	170
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	170
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	171
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	171
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	172
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	173
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	174
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते	175
18 (ए)	भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों का प्रवाह	176
18 (बी)	भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र को बकाया ऋण	177
	मूल्य और उत्पादन	
19 (ए)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2024=100): ग्रामीण	178
19 (बी)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2024=100): शहरी	178
19 (सी)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2024=100): संयुक्त	179
20	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	179
21	मुंबई में स्वर्ण और चांदी का मासिक औसत मूल्य	179
22	थोक मूल्य सूचकांक	180
23	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)	184
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
24	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	184
25	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	185
26	खज़ाना बिलों की नीलामी	185

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	वित्तीय बाजार	
27	दैनिक मांग मुद्रा दरें	186
28	जमाराशि प्रमाण-पत्र	187
29	वाणिज्यिक पत्र	187
30	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	187
31	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	188
	बाह्य क्षेत्र	
32	विदेशी व्यापार	189
33	विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां	189
34	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ	189
35	विदेशी निवेश अंतर्वाह	190
36	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण	190
37	भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और	191
	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक	192
38	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण	193
39(ए)	भारत से माल और सॉफ्टवेयर के निर्यात और भारत को माल के आयात के लिए आईएनआर में बिलिंग	193
39(बी)	भारत से माल और सॉफ्टवेयर के निर्यात और भारत को माल के आयात के लिए आईएनआर में निपटान	194
40	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	195
41	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (₹ करोड़)	196
42	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	197
43	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (₹ करोड़)	198
44	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	93
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
45	भुगतान प्रणाली संकेतक	199
	आवसरिक शृंखलाएं	
46	लघु बचत	201
47	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	202
48	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	203
49	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	204
50	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	205
51	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	206
52(ए)	हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह-लिखत-वार	207
52(बी)	हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक-चुनिंदा संकेतक	210

टिप्पणियां: .. = उपलब्ध नहीं।

– = शून्य/नगण्य।

प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम। आंसं = आंशिक रूप से संशोधित।

सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2025-26	2024-25		2025-26	
		ति2	ति3	ति2	ति3
	1	2	3	4	5
1. वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	7.8	6.5	7.8	8.6	7.8
1.1.1 कृषि	2.5	4.1	5.8	2.3	1.4
1.1.2 उद्योग	10.2	4.6	9.7	11.4	11.1
1.1.3 सेवाएं	8.6	7.8	7.9	9.2	9.1
1.1ए अंतिम खपत व्यय	8.2	5.8	6.2	7.8	8.1
1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण	7.1	6.6	6.3	8.4	7.8
	2024-25	**2025**		**2026**	
		जन.	फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	4.0	5.2	2.7	5.1	5.2
2. मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियाँ	10.3	11.4	10.8	10.6	11.9
2.1.2 ऋण#	11.0	11.8	11.6	13.4	14.5
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण#	11.0	11.8	11.5	13.3	14.3
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	9.7	9.6	9.4	2.8	3.2
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	4.3	4.4	5.3	5.0	5.0
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	9.4	9.3	9.4	12.0	12.6
3. अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.3	4.5	4.5	3.4	3.3
3.4 ऋण-जमा अनुपात	80.8	80.3	80.4	82.3	82.4
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात#	86.1	80.5	82.1	97.0	96.1
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.7	29.5	29.5	27.4	27.6
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	28.1	26.2	26.5	5.2	9.9
4. ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रेपो दर	6.25	6.50	6.25	5.25	5.25
4.2 स्थायी रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर*	6.00	6.25	6.00	5.00	5.00
4.4 सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	6.50	6.75	6.50	5.50	5.50
4.5 बैंक दर	6.50	6.75	6.50	5.50	5.50
4.6 आधार दर	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	8.35/10.00	8.35/10.00
4.7 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	7.70/7.95	7.70/7.95
4.8 मीयादी जमा दर >1 वर्ष	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/6.50	6.00/6.60
4.9 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.50/2.50	2.50/2.50
4.10 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.35	6.57	6.33	5.34	5.09
4.11 91-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	6.52	6.56	6.45	5.50	5.30
4.12 182-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	6.52	6.67	6.60	5.68	5.51
4.13 364-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	6.47	6.63	6.54	5.74	5.59
4.14 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियां सममूल्य प्रतिफल (एफबीआईएल)	6.62	6.71	6.73	6.77	6.71
5. संदर्भ दर और वायदा प्रीमियम					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	85.58	86.64	87.40	91.90	90.95
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	92.32	90.01	90.78	109.57	107.37
5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमियम 1-माह (%)	3.12	2.80	3.21	2.36	3.09
3-माह (%)	2.56	2.69	2.46	2.83	2.64
6-माह (%)	2.28	2.30	2.20	2.65	2.59
6. मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	4.6	4.1	3.5	2.7	3.2
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	3.39	3.1	2.6	3.8	4.0
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	2.3	2.5	2.4	1.7	2.1
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	5.2	4.6	2.9	2.3	3.3
6.3.2 ईंधन और उर्जा	-1.3	-1.9	-1.0	-4.0	-3.8
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	1.7	2.6	3.0	2.6	2.9
7. विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	6.9	10.7	-14.8	19.8	25.0
7.2 निर्यात	0.1	-2.6	-10.9	0.4	-0.8

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार 31 मार्च 2018 से जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।

#: 3 दिसंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक सभी पखवाड़ों के लिए चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा बैंक ऋण वृद्धि और संबंधित अनुपात को पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए समायोजित किया जाता है।

1 जुलाई 2023 के बाद के आंकड़ों में गैर-बैंक का बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, 15 दिसंबर 2025 से 'पखवाड़े' की परिभाषा को संशोधित कर दिया गया है। अब यह हर दूसरे शुक्रवार के बजाय महीने की 15 तारीख और महीने के अंतिम कैलेंडर दिन को माना जाएगा।

*: दिनांक 8 अप्रैल 2022 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2022-2023/41 के अनुसार।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	पिछले शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति में						
	2025-26	2025	2026				
		मार्च	फर. 27	मार्च 06	मार्च 13	मार्च 20	मार्च 27
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	4091324	3683836	4034832	4057771	4091324	4113616	4126019
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	13	11	11	16	13	10	12
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	**4091338**	**3683847**	**4034843**	**4057787**	**4091338**	**4113626**	**4126031**
1.2 आस्तियां							
1.2.1 स्वर्ण	428379	235379	424601	422898	428378	389324	381463
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	-	3448129	3609893	3634589	3662761	3723771	3744091
1.2.3 रुपया सिक्का	-	340	349	300	198	532	477
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियाँ	-	1709285	1759898	1752791	1743719	1855470	1822486
2.1.1.1 केंद्र सरकार	101	100	100	100	101	100	100
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 राज्य सरकारें	43	42	43	43	43	43	43
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	736422	943060	739420	762554	736422	776296	786905
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6473	7776	7119	6625	6473	6549	6727
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4586	5963	4444	4702	4586	4695	5379
2.1.1.7 अन्य बैंक	38570	46963	38323	38029	38570	38440	38899
2.1.1.8 अन्य	786640	593085	779645	774398	786640	853873	812295
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	170885	112296	190804	166340	170885	175473	172137
2.1.2 अन्य देयताएं	3140647	2150508	3150150	3125513	3140647	3110305	3074277
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	**4884366**	**3859793**	**4910048**	**4878305**	**4884366**	**4965775**	**4896763**
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	-	11	11	16	13	10	13
2.2.2 विदेशों में धारित राशियाँ	-	1413591	1632329	1559901	1501318	1529814	1509375
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	21412	26284	9787	36708	21412	21213	22268
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	114593	251984	125410	115878	114593	186057	173636
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.7 एक्ज़िम बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	9041	36426	9530	9530	9041	15102	20327
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	169878	111768	190967	166210	169878	173563	169987
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	-	1560630	2136074	2187938	2255307	2297232	2270517
2.2.6 अन्य आस्तियां	-	459101	805941	802124	812803	742784	730640
2.2.6.1 स्वर्ण	779790	429510	772915	769814	779790	708698	694389

* डेटा अनंतमि हैं।

सं. 3: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तन-शील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
फर. 1, 2026	-	-	-	-	614	198361	-	-	-	-197747
फर. 2, 2026	-	-	-	-	618	320805	-160	-	-	-320347
फर. 3, 2026	-	-	-	-	636	364627	-2167	-	-	-366158
फर. 4, 2026	-	-	-	-	786	342323	-1881	-	-	-343418
फर. 5, 2026	-	-	-	-	1018	357731	-482	-	-	-357195
फर. 6, 2026	-	-	-	-	732	503743	468	-	50000	-452543
फर. 7, 2026	-	-	-	-	75	394150	-	-	-	-394075
फर. 8, 2026	-	-	-	-	32	365647	-	-	-	-365615
फर. 9, 2026	-	-	-	-	712	451983	-270	-	-	-451541
फर. 10, 2026	-	-	-	-	754	477450	-345	-	-	-477041
फर. 11, 2026	-	-	-	-	716	424012	-932	-	-	-424228
फर. 12, 2026	-	-	-	-	729	440116	-146	-	-	-439533
फर. 13, 2026	-	-	-	-	726	459633	-345	-	-	-459252
फर. 14, 2026	-	-	-	-	20	370372	-	-	-	-370352
फर. 15, 2026	-	-	-	-	15	370924	-	-	-	-370909
फर. 16, 2026	-	-	-	-	908	395533	-	-	-	-394625
फर. 17, 2026	-	-	-	-	787	396525	-306	-	-	-396044
फर. 18, 2026	-	-	-	-	806	385884	-	-	2815	-382263
फर. 19, 2026	-	-	-	-	74	323427	-	-	-	-323353
फर. 20, 2026	-	-	-	-	773	361050	-	-	-	-360277
फर. 21, 2026	-	-	-	-	159	297305	-	-	-	-297146
फर. 22, 2026	-	-	-	-	90	251663	-	-	-	-251573
फर. 23, 2026	-	-	-	-	984	326598	-769	-	3680	-322703
फर. 24, 2026	-	-	-	-	842	368828	1275	-	-	-366711
फर. 25, 2026	-	-	-	-	868	360176	225	-	6220	-352863
फर. 26, 2026	-	-	-	-	762	345621	-	-	-	-344859
फर. 27, 2026	-	-	-	-	944	425596	-	-	-	-424652
फर. 28, 2026	-	-	-	-	358	373419	-	-	-	-373061

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय

i) तटीय/ अपतटीय ओटीसी खंड में परिचालन

मद	2024-25	2025	2026	
		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	-34511	-1621	2526	7409
1.1 क्रय (+)	364200	45030	27999	21403
1.2 विक्रय (-)	398711	46651	25473	13994
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (₹ करोड़)	-291233	-14024	23706	66881
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	-34511	-48866	-50783	-43374
(₹ करोड़)	-291233	-415819	-446550	-379669
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	-84345	-88753	-67772	-77666

ii) मुद्रा वायदा खंड में परिचालन

मद	2024-25	2025	2026	
		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	31415	4071	2593	1405
1.2 विक्रय (-)	31415	4071	2593	1405
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	0	-1002	-610	-522

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का परिपक्वता विश्लेषण (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	28 फरवरी 2026 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	0	10950	-10950
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	0	5910	-5910
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	0	11701	-11701
4. 1 वर्ष से अधिक	0	49105	-49105
कुल (1+2+3+4)	**0**	**77666**	**-77666**

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार							
	2024-25	2025				2026		
		मार्च 21	अक्तू. 31	नवं. 28	दिसं. 31	जन. 31	फर. 28	मार्च 31
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	9961	9961	5489	2144	1936	2260	450	3250
2 अनुसूचित बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	9900	9900	14900	14900	14900	14900	14900	14900
3.2 बकाया	9517	9517	11518	9637	10788	13252	7418	13219
4 अन्य								
4.1 सीमा	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	19478	19478	17007	11781	12724	15512	7868	16469

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2024-25	2025	2026		
		फर. 21	जन. 31	फर. 15	फर. 28
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	3630751	3557833	3906775	3959179	3986334
1.1 संचलन में नोट	3687816	3615412	3960724	4004152	4034832
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	35889	35274	39479	39629	39794
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	93696	93596	94172	85345	89035
2 जनता की जमाराशियाँ	2953329	2778287	3406068	3288693	3488496
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियाँ	2840023	2664975	3288801	3169171	3370574
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	113307	113312	117267	119522	117922
3 एम1 (1+2)	**6584081**	**6336120**	**7312843**	**7247872**	**7474830**
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियाँ	213981	212332	224085	224085	224085
5 एम2 (3+4)	**6798062**	**6548452**	**7536928**	**7471957**	**7698915**
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियाँ	**20702508**	**20577221**	**22590697**	**22606868**	**22823514**
7 एम3 (3+6)	**27286589**	**26913341**	**29903539**	**29854740**	**30298344**
8 कुल डाकघर जमाराशियाँ	1458844	1443556	1575869	1575869	1575869
9 एम4 (7+8)	**28745433**	**28356897**	**31479408**	**31430609**	**31874213**

सं. 7: मुद्रा भंडार ($एम_3$) के स्रोत

(₹ करोड़)

स्रोत	मार्च 31 / माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2024-25	2025	2026		
		फर. 21	जन. 31	फर. 15	फर. 28
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	**8510825**	**8150550**	**8944038**	**9046265**	**9190938**
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1508105	1193390	1806724	1872294	1913185
1.1.1 सरकार पर दावे	1591591	1421675	2078313	2139032	2144130
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1558903	1399564	2063818	2117456	2134344
1.1.1.2 राज्य सरकारें	32688	22112	14495	21576	9787
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियाँ	83485	228285	271588	266739	230945
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	83443	228243	271545	266695	230901
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	43	43	43
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	7002720	6957160	7137313	7173971	7277752
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	**19068129**	**18801586**	**21312579**	**21262658**	**21585702**
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	38246	28593	17876	11543	11593
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	19029883	18772993	21294703	21251115	21574109
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	18243972	17989979	20475237	20431530	20751207
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	766659	764165	794464	796039	799148
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	19252	18849	25003	23545	23753
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	**6148527**	**5873487**	**7056518**	**7091979**	**7140338**
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	5550947	5396630	6356081	6391542	6439901
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	5550956	5396628	6356068	6391535	6439901
3.1.2 विदेशी देयताएं	9	-2	-14	-7	0
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	597580	476857	700437	700437	700437
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**36632**	**36017**	**40222**	**40372**	**40537**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	**6477524**	**5948300**	**7449818**	**7586535**	**7659171**
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	2147427	2108450	3097683	3053152	3122568
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	4330098	3839850	4352134	4533382	4536604
$एम_3$ (1+2+3+4-5)	**27286589**	**26913341**	**29903539**	**29854740**	**30298344**

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31 / माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2024-25	2025	2026		
		फर. 21	जन. 31	फर. 15	फर. 28
	1	2	3	4	5
समग्र मौद्रिक राशियाँ					
एनएम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	6584081	6336120	7312843	7247872	7474830
एनएम2 (एनएम1 + 1.2.2.1)	15768688	15464806	17336563	17280499	17604996
एनएम3 (एनएम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	27909568	27523064	30503867	30447762	30869324
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3557833	3906775	3959179	3986334
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियाँ	23250261	22950944	25563735	25463898	25882053
1.2.1 मांग जमाराशियाँ	2840023	2664975	3288801	3169171	3370574
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ	20410239	20285969	22274935	22294727	22511480
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ	9184607	9128686	10023721	10032627	10130166
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	527375	515732	587099	659713	661504
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ	11225631	11157283	12251214	12262100	12381314
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	113307	113312	117267	119522	117922
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	915248	900975	916090	905164	883014
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	28800727	28171386	31524326	31616457	32066106
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8150550	8944038	9046265	9190938
2.1.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1508105	1193390	1806724	1872294	1913185
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	7002720	6957160	7137313	7173971	7277752
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	20289901	20020836	22580288	22570192	22875168
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई ऋण	38246	28593	17876	11543	11593
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	20251656	19992243	22562413	22558649	22863575
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	1208294	1206485	1252927	1279361	1258181
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	36632	36017	40222	40372	40537
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5605462	5428386	6489772	6455116	6531321
2.3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5396630	6356081	6391542	6439901
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	54514	31756	133691	63574	91420
2.4 पूंजी खाता	4481184	4551049	5805144	5733325	5770294
2.5 अन्य मदें (निवल)	2052068	1561676	1745309	1930858	1998347

सं. 9: चलनिधि समग्र राशियाँ

(₹ करोड़)

समग्र राशियाँ	2024-25	2025		2026	
		फर.	दिसं.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5
1 एनएम$_3$	**27896780**	**27523064**	**30303667**	**30503867**	**30869324**
2 डाकघर जमाराशियाँ	756787	746346	826918	826918	826918
3 एल$_1$ (1 + 2)	**28653567**	**28269410**	**31130585**	**31330785**	**31696242**
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	95148	80416	133272	160291	180091
4.1 सावधि मुद्रा उधार	10	16	5	5	5
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	80810	66365	117150	143700	162615
4.3 सावधि जमाराशियाँ	14328	14035	16117	16587	17471
5 एल$_2$ (3 + 4)	**28748715**	**28349826**	**31263857**	**31491077**	**31876333**
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियाँ	121178	..	133871	..	..
7 एल$_3$ (5 + 6)	**28869893**	**..**	**31397729**	**..**	**..**

टिप्पणी: संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31 / माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2024-25	2025	2026		
		फर. 21	जन. 31	फर. 15	फर. 28
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	3724448	3651428	4000947	4044524	4075369
1.2 आरबीआई के पास बैंकरों की जमाराशियाँ	991488	947488	804977	771521	796087
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	926001	888462	756290	722585	745804
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	113307	113312	117267	119522	117922
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	4829243	4712228	4923190	4935567	4989378
2 स्रोत					
2.1 आरबीआई के देशी ऋण	1389090	1388031	1624570	1556805	1631508
2.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1508105	1193390	1806724	1872294	1913185
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1475460	1171321	1792273	1850761	1903442
(2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)					
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1558574	1399251	2063554	2116943	2133994
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1558574	1399251	2063554	2116943	2133994
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	329	313	264	514	349
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियाँ	83443	228243	271545	266695	230901
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल आरबीआई ऋण	32646	22069	14452	21532	9743
2.1.2 बैंकों पर आरबीआई के दावे	-157261	166048	-200030	-327032	-293271
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-157261	166048	-200030	-327032	-293271
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई के ऋण	38246	28593	17876	11543	11593
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	9182	9096	13252	6994	7418
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	36632	36017	40222	40372	40537
2.3 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5396630	6356081	6391542	6439901
2.3.1 स्वर्ण	668162	646668	1167319	1164484	1197517
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4882794	4749960	5188748	5227051	5242384
2.4 पूंजी खाता	1875114	1950057	2841813	2768851	2804341
2.5 अन्य मदें (निवल)	272313	158394	255871	284301	318227

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	2024-25	मार्च 31/माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया			
		2025		2026	
		फर. 21	जन. 31	फर. 15	फर. 28
	1	2	3	4	5
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	4829243	4712229	4923190	4935567	4989378
1. घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	3724448	3651428	4000947	4044524	4075369
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियाँ	991488	947488	804977	771521	796087
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	113307	113312	117267	119522	117922
2. स्रोत					
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1508105	1193390	1806724	1872294	1913185
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-157261	166048	-200030	-327032	-293271
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	38246	28593	17876	11543	11593
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5396630	6356081	6391542	6439901
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	36632	36017	40222	40372	40537
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	2147427	2108450	3097683	3053152	3122568

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2024-25	2025	2026		
		फर. 21	जन. 31	फर. 15	फर. 28
	1	2	3	4	5
1. घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियाँ	22288331	21993052	24566193	24461619	24878111
1.1.1 मांग जमाराशियाँ	2698049	2524095	3141415	3020105	3221327
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ	19590283	19468957	21424778	21441514	21656784
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ	8815627	8761031	9641150	9648681	9745553
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	527375	515732	587099	659713	661504
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ	10774655	10707926	11783628	11792832	11911231
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	915248	900975	916090	905164	883014
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	26154974	25851561	28550801	28583003	28988027
2.1.1 सरकार को ऋण	6697298	6650508	6816054	6852135	6955551
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	19457676	19201054	21734747	21730868	22032476
2.1.2.1 बैंक ऋण	18243972	17989979	20475237	20431530	20751207
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	18207441	17942532	20385941	20346225	20668564
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	13742	13028	15046	28437	31549
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	630	524	500	502	502
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	1199332	1197522	1243964	1270398	1249218
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	54514	31756	133691	63574	91420
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	529621	501065	611886	539134	563978
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियाँ	292270	291252	315762	312141	312034
2.2.3 ओवरसीज़ विदेशी मुद्रा उधार	182837	178057	162433	163420	160525
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	791777	804174	1038671	1122708	1115730
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	882415	888462	756290	722585	745804
2.3.2 उपलब्ध नकदी	81874	81760	82350	73091	76655
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	172512	166048	-200030	-327032	-293271
2.4 पूंजी खाता	2581900	2576822	2939161	2940303	2941782
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	1215785	1216642	1301719	1462199	1492270
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	878795	843551	953784	965940	961593
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	116551	115810	49979	66449	76948

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(₹ करोड़)

मद	21 मार्च, 2025 की स्थिति	2025	2026		
		फर. 21	जन. 31	फर. 15	फर. 28
	1				
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	6697928	6651031	6816555	6852637	6956053
2 अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ (गैर-एसएलआर)	165500	163938	169071	168992	168597
3 वाणिज्यिक पत्र	63163	56570	49208	52135	54460
4 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
4.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	13874	12782	14239	14361	14168
4.2 निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	95984	96188	103935	104215	103913
4.3 अन्य	7664	7518	7422	7409	7424
5 निम्नलिखित द्वारा जारी बॉण्ड / डिबेंचर					
5.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	130308	125744	129457	134066	135325
5.2 निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	248138	237306	262889	266335	270637
5.3 अन्य	150000	156217	184501	189877	179911
6 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
6.1 म्यूचुअल फंड	119867	145589	120274	133712	115369
6.2 वित्तीय संस्थाएं	204865	195618	202968	199297	199415

टिप्पणी: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में, एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, 15 दिसंबर 2025 से 'पखवाड़े' की परिभाषा को संशोधित कर दिया गया है। अब यह हर दूसरे शुक्रवार के बजाय महीने की 15 तारीख और महीने के अंतिम कैलेंडर दिन को माना जाएगा।

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2024-25	2025	2026		2024-25	2025	2026	
		फर.	जन.	फर.		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5	6	7	8
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	208	208	197	197	135	135	121	121
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	**458011**	**443848**	**468420**	**484747**	**451305**	**438922**	**459585**	**476551**
1.1 बैंकों से माँग और मीयादी जमाराशियाँ	315675	287294	344451	369371	309414	282773	336474	361684
1.2 बैंकों से उधार राशि	112027	118234	81308	78565	111976	118149	81053	78512
1.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	30310	38320	42661	36811	29916	38000	42057	36355
2 अन्य के प्रति देयताएं	**25053097**	**25090360**	**27450892**	**27741954**	**24557481**	**24603094**	**26914261**	**27195276**
2.1 कुल जमाराशियाँ	23055487	23098180	25398756	25715492	22580601	22630598	24881954	25190145
2.1.1 माँग	2748263	2753855	3194033	3276458	2698049	2705279	3141415	3221327
2.1.2 मीयादी	20307224	20344326	22204723	22439035	19882552	19925320	21740540	21968818
2.2 उधार	920568	889316	920813	887695	915248	884179	916090	883014
2.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	1077042	1102863	1131324	1138766	1061632	1088317	1116217	1122118
3 रिज़र्व बैंक से उधार	**311466**	**229480**	**136073**	**124916**	**311466**	**229480**	**136073**	**124916**
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	311466	229480	136073	124916	311466	229480	136073	124916
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	**985044**	**1031337**	**856579**	**841456**	**964289**	**1010913**	**838641**	**822459**
4.1 उपलब्ध नकदी	84399	86176	84875	79738	81874	83724	82350	76655
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	900645	945160	771704	761718	882415	927189	756290	745804
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	**432645**	**414933**	**515936**	**533202**	**348496**	**335873**	**424652**	**431152**
5.1 अन्य बैंकों के पास शेषराशि	273720	261237	343322	349656	215801	206970	278787	281681
5.1.1 चालू खाते में	13239	13523	12231	13080	10619	10912	9588	10221
5.1.2 अन्य खातों में	260481	247714	331091	336575	205182	196058	269199	271460
5.2 माँग और अल्पसूचना पर मुद्रा	44772	42526	52274	46980	25838	25496	35468	23925
5.3 बैंकों को अग्रिम	43856	44597	38975	45888	39504	39833	35428	41912
5.4 अन्य आस्तियां	70296	66574	81365	90678	67353	63574	74968	83634
6 निवेश	**6850574**	**6830178**	**6990918**	**7130107**	**6697928**	**6676664**	**6816555**	**6956053**
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	6842024	6821889	6976618	7117057	6697298	6676060	6816054	6955551
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	8550	8289	14301	13051	630	604	500	502
7 बैंक ऋण	**18708286**	**18667299**	**20969154**	**21252041**	**18243972**	**18202174**	**20475236**	**20751207**
7ए खाद्यान्न ऋण	87145	96468	141269	134617	36531	45854	89295	82643
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	18370704	18334125	20557184	20833450	17909851	17872448	20065187	20334593
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	76523	75858	98715	101240	74963	74221	98704	101212
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	222320	218916	276782	280333	221059	217743	275480	279023
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	15357	15279	13197	13408	15122	15032	13002	13190
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	23382	23120	23275	23611	22977	22730	22865	23190

टिप्पणी: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में, एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, 15 दिसंबर 2025 से 'पखवाड़े' की परिभाषा को संशोधित कर दिया गया है। अब यह हर दूसरे शुक्रवार के बजाय महीने की 15 तारीख और महीने के अंतिम कैलेंडर दिन को माना जाएगा।

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 21, 2025	2025	2026		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		फर. 21	जन. 31	फर. 28	2025-26	2026
	1	2	3	4	%	%
I. बैंक ऋण (II+III)	**18243972**	**18125413**	**20475382**	**20754078**	**13.8**	**14.5**
II. खाद्यान्न ऋण	**36531**	**42552**	**89295**	**82643**	**126.2**	**94.2**
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	**18207441**	**18082860**	**20386087**	**20671435**	**13.5**	**14.3**
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	**2287060**	**2264305**	**2509789**	**2543477**	**11.2**	**12.3**
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	**3985660**	**3916783**	**4388308**	**4447192**	**11.6**	**13.5**
2.1 सूक्ष्म और लघु	798473	791321	1031291	1031799	29.2	30.4
2.2 मध्यम	363245	355603	426211	430263	18.4	21.0
2.3 बड़े	2823942	2769858	2930806	2985130	5.7	7.8
3. सेवाएं	**5093565**	**4995649**	**5722969**	**5807798**	**14.0**	**16.3**
3.1 परिवहन परिचालक	261575	260651	267665	280409	7.2	7.6
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	32915	33063	40695	46183	40.3	39.7
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्टरां	83366	82298	97418	98895	18.6	20.2
3.4 शिपिंग	7304	7411	10373	10502	43.8	41.7
3.5 विमानन	46072	45982	49613	49830	8.2	8.4
3.6 पेशेवर सेवाएं	195957	192799	209054	210543	7.4	9.2
3.7 व्यापार	1184550	1154669	1309115	1320670	11.5	14.4
3.7.1 थोक व्यापार1	646099	629036	723122	737574	14.2	17.3
3.7.2 खुदरा व्यापार	538451	525633	585993	583096	8.3	10.9
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	523264	516850	597880	606612	15.9	17.4
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)2 जिसमें से	1635102	1610744	1905207	1947584	19.1	20.9
3.9.1 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	323182	324611	353406	359226	11.2	10.7
3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएं (पीएफआई)	228678	217593	305670	316124	38.2	45.3
3.10 अन्य सेवाएं3	1123459	1091183	1235949	1236570	10.1	13.3
4. व्यक्तिगत ऋण	**5971696**	**5898808**	**6723042**	**6796850**	**13.8**	**15.2**
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	23201	24301	22360	21925	-5.5	-9.8
4.2 आवास	3010477	2978759	3278420	3305691	9.8	11.0
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	141842	135169	154360	154183	8.7	14.1
4.4 शेयरों और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	10080	9808	10264	10085	0.1	2.8
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	284366	287047	296417	292067	2.7	1.7
4.6 शिक्षा	137456	136821	154899	155590	13.2	13.7
4.7 वाहन ऋण	622793	619797	720567	726037	16.6	17.1
4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण4	206284	188051	400517	428578	107.8	127.9
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	1535197	1519054	1685238	1702695	10.9	12.1
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
(i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां5	2287794	2257407	2565250	2600490	13.7	15.2
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम6	2239409	2223184	2735314	2841889	26.9	27.8
(iii) मध्यम उद्यम7	601451	584615	682981	692153	15.1	18.4
(iv) आवास	746651	747503	1030805	1033416	38.4	38.2
(v) शिक्षा ऋण	62826	62874	77853	77935	24.1	24.0
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	10325	8490	12243	13955	35.2	64.4
(vii) सामाजिक अवसंरचना	1316	1233	1255	1221	-7.3	-1.0
(viii) निर्यात ऋण	11805	11954	10663	10270	-13.0	-14.1
(ix) अन्य	49552	51733	40417	41690	-15.9	-19.4
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1864606	1789945	2007819	2032409	9.0	13.5

टिप्पणियाँ: (1) आंकड़े अनंतिम हैं। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण आंकड़े सेक्शन-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को कवर करते हैं, जबकि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण आंकड़े क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं, जो महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित, सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा देने वाले चुनिंदा बैंकों को कवर करते हैं।

(2) 28 जुलाई, 2023 से आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

1 थोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर खाद्य खरीद ऋण शामिल हैं।

2 एनबीएफसी में एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई), स्वर्ण ऋण देने वाली एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।

3 "अन्य सेवाओं" में म्यूचुअल फंड (एमएफ), एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग और वित्त, और अन्य सेवाएँ शामिल हैं जो सेवाओं के अंतर्गत कहीं और इंगित नहीं की गई हैं।

4 एक बैंक ने मई 2024 से, खुदरा खंड के तहत कृषि ऋण की एक श्रेणी के वर्गीकरण को "स्वर्ण के आभूषणों पर ऋण" में बदल दिया है।

5 प्राथमिकता क्षेत्र के तहत "कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ" में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।

6 प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "सूक्ष्म और लघु उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल है और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।

7 प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "मध्यम उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 21, 2025	2025	2026		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		फर. 21	जन. 31	फर. 28	2025-26	2026
	1	2	3	4	%	%
2 उद्योग (2.1 से 2.19)	**3985660**	**3916783**	**4388308**	**4447192**	**11.6**	**13.5**
2.1 खनन एवं उत्खनन (कोयला सहित)	**56818**	**53077**	**64669**	**64501**	**13.5**	**21.5**
2.2 खाद्य प्रसंस्करण	**219525**	**219091**	**238126**	**241445**	**10.0**	**10.2**
2.2.1 चीनी	28522	26872	24554	28560	0.1	6.3
2.2.2 खाद्य तेल एवं वनस्पति	20927	21082	23812	23424	11.9	11.1
2.2.3 चाय	5084	6069	5077	4880	-4.0	-19.6
2.2.4 अन्य	164992	165067	184683	184581	11.9	11.8
2.3 पेय पदार्थ एवं तंबाकू	**35515**	**31297**	**37884**	**39190**	**10.3**	**25.2**
2.4 वस्त्र	**277267**	**273763**	**294365**	**296136**	**6.8**	**8.2**
2.4.1 सूती वस्त्र	107495	106389	107782	108696	1.1	2.2
2.4.2 जूट वस्त्र	4288	4330	4899	4980	16.1	15.0
2.4.3 मानव निर्मित वस्त्र	49186	49158	51493	51246	4.2	4.2
2.4.4 अन्य वस्त्र	116298	113886	130190	131214	12.8	15.2
2.5 चमड़ा एवं चमड़े से बने उत्पाद	**12980**	**12982**	**13792**	**13835**	**6.6**	**6.6**
2.6 लकड़ी एवं लकड़ी से बने उत्पाद	**27826**	**27293**	**30571**	**30676**	**10.2**	**12.4**
2.7 कागज एवं कागज से बने उत्पाद	**52848**	**51944**	**58104**	**57993**	**9.7**	**11.6**
2.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं आण्विक ईंधन	**154179**	**154425**	**176716**	**185431**	**20.3**	**20.1**
2.9 रसायन एवं रासायनिक उत्पाद	**267815**	**263173**	**305421**	**313413**	**17.0**	**19.1**
2.9.1 उर्वरक	32011	30529	34976	39432	23.2	29.2
2.9.2 औषधी और दवाइयाँ	88524	88727	96762	98753	11.6	11.3
2.9.3 पेट्रो केमिकल्स	28797	27615	38231	37301	29.5	35.1
2.9.4 अन्य	118482	116302	135453	137927	16.4	18.6
2.10 रबर, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	**103465**	**101710**	**110156**	**110982**	**7.3**	**9.1**
2.11 कांच और कांच के बर्तन	**13443**	**13199**	**13826**	**13702**	**1.9**	**3.8**
2.12 सीमेंट और सीमेंट से बने उत्पाद	**59753**	**60327**	**64549**	**64332**	**7.7**	**6.6**
2.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	**433501**	**431340**	**494119**	**496720**	**14.6**	**15.2**
2.13.1 लोहा और स्टील	300156	301746	333268	334966	11.6	11.0
2.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	133345	129593	160851	161754	21.3	24.8
2.14 सभी इंजीनियरिंग	**240136**	**232477**	**311363**	**316185**	**31.7**	**36.0**
2.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	52863	49652	64380	63623	20.4	28.1
2.14.2 अन्य	187273	182826	246983	252562	34.9	38.1
2.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपकरण	**119450**	**117457**	**135522**	**137108**	**14.8**	**16.7**
2.16 रत्न और आभूषण	**85814**	**83119**	**117215**	**116543**	**35.8**	**40.2**
2.17 निर्माण	**160037**	**158884**	**167086**	**170519**	**6.5**	**7.3**
2.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	**1364369**	**1337436**	**1426796**	**1443544**	**5.8**	**7.9**
2.18.1 ऊर्जा	692160	668584	789193	811927	17.3	21.4
2.18.2 दूरसंचार	123850	120294	105860	104935	-15.3	-12.8
2.18.3 सड़क	334147	334566	331485	326875	-2.2	-2.3
2.18.4 हवाई अड्डा	9156	8799	6419	6577	-28.2	-25.3
2.18.5 बंदरगाह	5916	5879	8156	9124	54.2	55.2
2.18.6 रेलवे	13415	13132	9964	7107	-47.0	-45.9
2.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	185726	186182	175719	176998	-4.7	-4.9
2.19 अन्य उद्योग	**300921**	**293789**	**328027**	**334937**	**11.3**	**14.0**

टिप्पणी : बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 से 'अंतिम रिपोर्टिंग पखवाड़े' की परिभाषा को बदलकर 'महीने का अंतिम दिन' कर दिया गया है। तदनुसार, दिसंबर 2025 से वर्ष-दर-वर्ष विकास दरें चालू वर्ष के महीने के अंत के आंकड़ों और पिछले वर्ष के संबंधित महीने के लिए (पुरानी परिभाषा के अनुसार) अंतिम रिपोर्टिंग पखवाड़े के आंकड़ों पर आधारित हैं।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(₹ करोड़)

मद	रिपोर्टिंग दिवस की स्थिति में								
	2024-25	2025						2026	
		जन. 24	अक्टू. 31	नवं. 14	नवं. 28	दिसं. 15	दिसं. 31	जन. 15	जन. 31
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	34	34	34	34	34	34	34	34	34
1 कुल जमाराशियाँ (2.1.1.2+2.2.1.2)	**146871.0**	**140580.6**	**151855.9**	**150082.8**	**153247.4**	**155555.7**	**158419.1**	**157312.0**	**156325.4**
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	**29215.6**	**24519.2**	**26385.0**	**27891.5**	**27456.8**	**28841.6**	**29874.2**	**31640.0**	**28699.1**
2.1.1 जमाराशियाँ									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	9022.9	6903.9	6223.1	6758.9	6058.8	6630.5	5675.4	6994.5	6057.4
2.1.1.2 अन्य	14063.9	12582.5	13407.9	14723.0	14397.7	14992.1	16407.0	16286.3	15070.7
2.1.2 बैंकों से उधार	700.0	12.0	521.9	874.7	810.7	959.4	1059.6	470.9	916.2
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	5428.9	5020.9	6232.2	5534.9	6189.6	6259.6	6732.1	7888.4	6654.8
2.2 मीयादी देयताएं	**201100.7**	**182418.4**	**203386.8**	**203565.6**	**204259.5**	**206280.9**	**212765.8**	**208153.0**	**214248.4**
2.2.1 जमाराशियाँ									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	66874.3	52718.8	63251.3	66600.1	63747.4	64062.5	64975.2	65400.4	71241.9
2.2.1.2 अन्य	132807.1	127998.0	138448.0	135359.8	138849.7	140563.6	142012.1	141025.8	141254.7
2.2.2 बैंकों से उधार	643.9	650.8	610.4	610.4	610.4	610.2	609.4	610.4	610.4
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	775.4	1050.8	1077.1	995.3	1052.1	1044.5	5169.2	1116.5	1141.4
3 रिज़र्व बैंक से उधार	699.5						200.0	200.0	
4 अधिसूचित बैंक/ सरकार से उधार	126928.5	114464.9	118368.0	116858.6	114537.1	110012.2	108704.4	101728.2	114287.5
4.1 मांग	53459.8	44280.0	51539.0	51639.4	51408.3	49688.8	51075.8	50411.7	51777.9
4.2 मीयादी	73468.7	70184.9	66829.0	65219.2	63128.8	60323.4	57628.5	51316.5	62509.6
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	**13390.9**	**10837.2**	**10267.4**	**10556.4**	**9537.0**	**10331.1**	**8890.6**	**9212.9**	**9849.4**
5.1 उपलब्ध नकदी	1052.1	699.7	856.3	840.0	847.3	931.7	853.9	928.0	797.5
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	12338.8	10137.5	9411.1	9716.4	8689.7	9399.4	8036.8	8284.9	9051.9
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेषराशि	**1656.3**	**1262.1**	**2667.8**	**1000.7**	**1220.1**	**935.0**	**1151.2**	**1036.2**	**1004.1**
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**77220.1**	**75514.9**	**85525.4**	**84883.9**	**84862.8**	**85173.2**	**84894.1**	**85064.6**	**85444.3**
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	**26531.1**	**15819.4**	**21181.3**	**23692.4**	**23910.4**	**20517.2**	**21836.6**	**20595.4**	**23358.5**
9 बैंक ऋण (10.1+11)	**174828.8**	**170580.3**	**174327.4**	**175598.5**	**174894.0**	**176043.0**	**175694.4**	**180678.8**	**184566.8**
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	**174590.4**	**170385.3**	**174150.0**	**175411.9**	**174724.0**	**175856.8**	**175487.4**	**180470.0**	**184363.9**
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	124607.6	112689.7	123042.1	123039.7	123414.0	123501.3	126937.8	122407.5	124590.5
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	238.4	195.0	177.4	186.5	170.0	186.2	207.0	208.9	202.9

सं. 18(ए) भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों का प्रवाह

(₹ करोड़)

स्रोत	अप्रैल-मार्च		31 मार्च तक	
	2023-24	2024-25	2024-25	2025-26 अ
	1	2	3	4
1 गैर-खाद्य बैंक ऋण	**22,95,121**	**18,08,036**	**18,08,036**	**29,19,166**
2 गैर-बैंक स्रोत (2.1+2.2)	**12,63,721**	**17,10,346**	**14,24,965**	**15,47,794**
2.1 घरेलू स्रोत	**10,20,302**	**13,85,609**	**10,97,953**	**10,56,130**
2.1.1 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा इक्विटी निर्गम	1,35,008	3,81,161	3,69,462	3,45,296
2.1.2 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा कारपोरेट बॉण्ड निर्गम	1,67,374	1,97,795	1,35,172	3,01,491
2.1.3 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा हाइब्रिड लिखत(आरईआईटीएस/आईएनवीआईटीएस)	39,024	31,442	22,702	20,989
2.1.4 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक पेपर निर्गम	19,712	18,819	18,819	7,948
2.1.5 आवास वित्त कंपनियों द्वारा ऋण (बैंक ऋण निवल)	1,41,816	1,34,852	1,22,439	1,109
2.1.6 आरबीआई-विनियमित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण	73,386	99,501	56,759	16,561
2.1.7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण (बैंक ऋण निवल)	4,43,982	5,22,037	3,72,600	3,62,734
2.2 विदेशी स्रोत	**2,43,419**	**3,24,737**	**3,27,012**	**4,91,664**
2.2.1 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार	27,916	19,090	12,484	31,720
2.2.2 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा एडीआर/जीडीआर	0	0	0	0
2.2.3 विदेश से अल्पकालिक ऋण	-6,741	58,859	97,039	1,35,813
2.2.4 भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	2,22,244	2,46,788	2,17,489	3,24,131
3 संसाधनों का कुल प्रवाह (1+2)	**35,58,842**	**35,18,382**	**32,33,001**	**44,66,960**

अ: अनंतिम

स्रोत संख्या 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.2.1, 2.2.2 और 2.2.4 से कॉलम 4 और 5 के लिए डेटा का कवरेज: फरवरी तक।

2.1.7 और 2.2.3: सितंबर तक।

टिप्पणियाँ: i. गैर-खाद्य बैंक ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से संबंधित है और इसमें सहकारी बैंकों द्वारा दिया गया ऋण शामिल नहीं है।

ii. बैंकों, एनबीएफसी और एचएफसी द्वारा दिए गए ऋण में व्यक्तिगत ऋण शामिल हैं।

iii. इक्विटी और हाइब्रिड लिखतों जो सकल आधार पर हैं, को छोड़कर सभी मदों पर डेटा निवल आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

iv. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) शामिल हैं। एआईएफआई द्वारा दिए गए ऋण में एससीबी, एनबीएफसी और एचएफसी को पुनर्वित्तपोषण तथा घरेलू विदेशी सरकारों/संस्थानों को प्रदत्त प्रत्यक्ष ऋण शामिल नहीं हैं।

v. एचडीएफसी लिमिटेड जिसका 1 जुलाई, 2023 से एचडीएफसी बैंक में विलय हो गया, से संबंधित डेटा, विलय से पहले आवास वित्त कंपनियों द्वारा दिए गए ऋण के अंतर्गत आता है, जबकि विलय के बाद यह बैंक ऋण के अंतर्गत आता है।

vi. आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा दिए गए ऋण के डेटा को कुछ एचएफसी के एनबीएफसी में रूपांतरण के लिए समायोजित किया गया है।

स्रोत: आरबीआई; सेबी; एआईएफआई; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सं. 18(बी): भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र को बकाया ऋण

स्रोत	(₹ करोड़)						प्रतिशत संवृद्धि			
	मार्च के अंत तक			31 मार्च तक			मार्च के अंत तक		31 मार्च तक	
	2023	2024	2025	2024	2025	2026 P	2023 की तुलना में 2024	2024 की तुलना में 2025	2024 की तुलना में 2025	2025 अ की तुलना में 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. गैर-खाद्य बैंक ऋण	**1,36,55,330**	**1,65,63,961**	**1,83,71,998**	**1,65,63,961**	**1,83,71,998**	**2,12,91,163**	**21.3**	**10.9**	**10.9**	**15.9**
2. गैर-बैंक स्रोत (2.1+2.2)	**74,43,091**	**77,57,256**	**88,86,394**	**75,43,371**	**85,56,774**	**98,91,297**	**4.2**	**14.6**	**13.4**	**15.6**
2.1 घरेलू स्रोत	**53,95,038**	**56,59,037**	**66,37,411**	**54,56,577**	**62,65,122**	**73,27,255**	**4.9**	**17.3**	**14.8**	**17.0**
2.1.1 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करना	16,58,140	18,25,514	20,23,310	17,95,126	19,60,686	23,24,801	10.1	10.8	9.2	18.6
2.1.2 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक पत्र जारी करना	89,816	1,09,528	1,28,347	1,09,528	1,28,347	1,36,295	21.9	17.2	17.2	6.2
2.1.3 आवास वित्त कंपनियों द्वारा ऋण (बैंक ऋण निवल)	10,39,420	5,98,965	6,27,125	6,01,440	6,21,700	6,28,234	-42.4	4.7	3.4	1.1
2.1.4 आरबीआई - विनियमित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण	3,51,224	4,24,610	5,24,111	3,78,690	4,81,369	5,40,672	20.9	23.4	27.1	12.3
2.1.5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण (बैंक ऋण निवल)	22,56,439	27,00,421	33,34,518	25,71,794	30,73,021	36,97,252	19.7	23.5	19.5	20.3
2.2 विदेशी स्रोत	**20,48,053**	**20,98,219**	**22,48,983**	**20,86,795**	**22,91,652**	**25,64,043**	**2.4**	**7.2**	**9.8**	**11.9**
2.2.1 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक ऋण	10,29,403	10,72,181	11,34,552	10,65,704	11,38,950	12,55,381	4.2	5.8	6.9	10.2
2.2.2 विदेश से अल्पकालिक ऋण	10,18,650	10,26,037	11,14,432	10,21,091	11,52,702	13,08,662	0.7	8.6	12.9	13.5
3. कुल ऋण (1+2)	**2,10,98,421**	**2,43,21,217**	**2,72,58,392**	**2,41,07,332**	**2,69,28,772**	**3,11,82,460**	**15.3**	**12.1**	**11.7**	**15.8**

अ: अनंतिम।

स्रोत संख्या: 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 और 2.2.1 से कॉलम 5, 6 और 7 के डेटा का कवरेज:नवंबर के अंत तक।

2.1.5 और 2.2.2: फरवरी के अंत तक।

टिप्पणियाँ: i. गैर-खाद्य बैंक ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से संबंधित है और इसमें सहकारी बैंकों द्वारा दिये गए ऋण शामिल नहीं है। सहकारी बैंकों (जैसे, शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक) द्वारा प्रदत्त ऋण सहित, मार्च 2023, 2024 और 2025 के अंत तक गैर-खाद्य बैंक ऋण क्रमशः ₹1,46,22,252 करोड़, ₹1,74,63,674 करोड़ और 1,93,43,418 करोड़ था। तदनुसार, मार्च 2023, 2024 और 2025 के अंत में कुल बकाया ऋण क्रमशः ₹2,20,65,343 करोड़ 2,52,19,988 करोड़ और 2,82,28,852 करोड़ था।

ii. गैर-बैंक स्रोतों के आंकड़ों में घरेलू स्रोतों के अंतर्गत इक्विटी और हाइब्रिड लिखतों के निर्गम और विदेशी स्रोतों के अंतर्गत इक्विटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल नहीं हैं।

iii. कॉरपोरेट बॉण्ड के मामले में, मार्च 2024 और 2025 के अंत के लिए बकाया आंकड़े वित्तीय और गैर-वित्तीय निगमों द्वारा जारी बॉण्ड पर सेबी के नए आंकड़ों की शृंखला पर आधारित हैं। मार्च 2023 के अंत के बकाया आंकड़े मार्च 2024 के अंत के बकाया आंकड़ों से 2023-24 के प्रवाह को समायोजित करके निकाले गए हैं।

iv. बकाया आंकड़ों पर आधारित प्रवाह सारणी 18 (ए) में दिए गए प्रवाह से मेल नहीं खा सकते हैं, इसके कारण निम्नलिखित हैं:
   ए) 1 जुलाई, 2023 को एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में विलय;
   बी) कुछ आवास वित्त कंपनियों का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में रूपांतरण; और
   सी) विदेशी स्रोतों के मामले में मूल्यांकन प्रभाव।

v. गैर-वित्तीय गैर-सरकारी सार्वजनिक और निजी लिमिटेड कंपनियों के मामले में घरेलू देनदारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान और गैर-वर्तमान व्यापार देय को आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत: आरबीआई; सेबी; एआईएफआई; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

कीमत और उत्पादन

सं. 19 (ए) : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2024=100): ग्रामीण

प्रभाग	भार	सूचकांक					मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)	
		2025*	फर-25	मार्च-25	फर-26	मार्च-26 (अ)	फर-26	मार्च-26 (अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. खाद्य और पेय पदार्थ	41.98	102.31	100.42	100.19	103.80	104.00	3.36	3.81
2. पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ	3.73	103.10	101.90	102.07	105.44	106.30	3.47	4.15
3. वस्त्र और फुटवियर	7.12	104.97	103.46	103.83	106.80	107.12	3.23	3.17
4. आवास, जल, बिजली, गैस और अन्य ईंधन	11.76	101.55	100.84	100.92	102.19	103.07	1.34	2.14
5. सज्जा, घरेलू उपकरण और घरेलू नियमित रखरखाव	4.61	102.45	101.67	101.90	103.25	103.53	1.55	1.60
6. स्वास्थ्य	6.76	102.79	101.83	102.06	103.63	103.75	1.77	1.65
7. परिवहन	8.64	100.86	100.75	100.75	100.70	100.76	-0.05	0.01
8. सूचना और संचार	3.65	103.54	103.31	103.29	103.65	103.74	0.32	0.44
9. मनोरंजन, खेल और संस्कृति	1.36	102.70	102.04	101.95	104.08	104.06	2.00	2.08
10. शिक्षा सेवाएं	2.38	103.39	101.73	101.79	104.79	104.79	3.00	2.95
11. रेस्तरां और आवास सेवाएं	2.84	103.81	102.99	103.09	105.07	105.52	2.02	2.36
13. व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और विविध वस्तुएं एवं सेवाएं	5.15	108.20	103.85	104.48	125.24	124.91	20.60	19.55
समग्र अखिल भारतीय सीपीआई	100.00	102.78	101.33	101.34	104.74	105.01	3.37	3.63
मेमो मद								
खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई#	47.45	103.66	102.36	102.58	106.52	106.73	4.07	4.05

अ: अनंतिम
'*': कैलेंडर वर्ष 2025 के सभी मासिक सूचकांकों का अंकगणितीय माध्य।
'#': इस सारणी में 'ईंधन' दो श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात 'बिजली, गैस और अन्य ईंधन' तथा 'व्यक्तिगत परिवहन उपकरणों के लिए ईंधन और स्नेहक', जिसमें 'पेट्रोल', 'डीजल' और 'अन्य प्राकृतिक गैस (सीएनजी)' शामिल हैं। विस्तृत विवरण के लिए कृपया अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट के बॉक्स आइटम IV.2 देखें।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार और आरबीआई स्टाफ की गणनाएं।

सं. 19 (बी) : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2024=100): शहरी

प्रभाग	भार	सूचकांक					मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)	
		2025*	फर-25	मार्च-25	फर-26	मार्च-26 (अ)	फर-26	मार्च-26 (अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. खाद्य और पेय पदार्थ	30.25	102.89	100.64	100.76	103.99	104.31	3.33	3.53
2. पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ	2.06	102.78	101.75	101.91	105.37	106.41	3.56	4.42
3. वस्त्र और फुटवियर	5.46	103.89	102.81	103.07	104.98	105.19	2.11	2.06
4. आवास, जल, बिजली, गैस और अन्य ईंधन	25.00	101.19	100.39	100.58	102.02	102.46	1.62	1.87
5. सज्जा, घरेलू उपकरण और घरेलू नियमित रखरखाव	4.30	102.35	101.68	101.90	102.82	103.03	1.12	1.11
6. स्वास्थ्य	5.28	103.32	102.17	102.47	104.33	104.43	2.11	1.92
7. परिवहन	8.98	100.79	100.73	100.70	100.67	100.69	-0.06	-0.01
8. सूचना और संचार	3.56	103.11	102.91	102.94	103.07	103.13	0.15	0.19
9. मनोरंजन, खेल और संस्कृति	1.71	102.64	101.81	101.66	104.28	104.19	2.43	2.49
10. शिक्षा सेवाएं	4.52	104.11	102.12	102.22	105.74	105.83	3.54	3.53
11. रेस्तरां और आवास सेवाएं	3.98	104.71	103.28	103.60	106.75	107.06	3.36	3.35
13. व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और विविध वस्तुएं एवं सेवाएं	4.90	108.40	104.23	104.81	123.42	123.11	18.41	17.46
समग्र अखिल भारतीय सीपीआई	100.00	102.73	101.30	101.47	104.36	104.62	3.02	3.11
मेमो मद								
खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई#	59.99	103.08	101.89	102.11	105.29	105.44	3.34	3.27

अ: अनंतिम
'*': कैलेंडर वर्ष 2025 के सभी मासिक सूचकांकों का अंकगणितीय माध्य।
'#': इस सारणी में 'ईंधन' दो श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात 'बिजली, गैस और अन्य ईंधन' तथा 'व्यक्तिगत परिवहन उपकरणों के लिए ईंधन और स्नेहक', जिसमें 'पेट्रोल', 'डीजल' और 'अन्य प्राकृतिक गैस (सीएनजी)' शामिल हैं। विस्तृत विवरण के लिए कृपया अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट के बॉक्स आइटम IV.2 देखें।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार और आरबीआई स्टाफ की गणनाएं।

सं. 19 (सी) : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2024=100): संयुक्त

प्रभाग	भार	सूचकांक					मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)	
		2025*	फर-25	मार्च-25	फर-26	मार्च-26 (अ)	फर-26	मार्च-26 (अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. खाद्य और पेय पदार्थ	36.75	102.52	100.50	100.40	103.87	104.12	3.35	3.71
2. पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ	2.99	103.00	101.85	102.02	105.42	106.33	3.50	4.23
3. वस्त्र और फुटवियर	6.38	104.55	103.21	103.54	106.11	106.39	2.81	2.75
4. आवास, जल, बिजली, गैस और अन्य ईंधन	17.66	101.33	100.56	100.71	102.08	102.69	1.52	1.97
5. सज्जा, घरेलू उपकरण और घरेलू नियमित रखरखाव	4.47	102.41	101.68	101.90	103.06	103.32	1.37	1.39
6. स्वास्थ्य	6.10	102.99	101.96	102.22	103.90	104.01	1.90	1.75
7. परिवहन	8.80	100.83	100.74	100.73	100.69	100.73	-0.05	0.00
8. सूचना और संचार	3.61	103.35	103.14	103.14	103.39	103.47	0.25	0.33
9. मनोरंजन, खेल और संस्कृति	1.52	102.67	101.92	101.80	104.18	104.13	2.21	2.28
10. शिक्षा सेवाएं	3.33	103.83	101.97	102.05	105.36	105.42	3.33	3.30
11. रेस्तरां और आवास सेवाएं	3.35	104.29	103.15	103.36	105.96	106.34	2.73	2.88
13. व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और विविध वस्तुएं एवं सेवाएं	5.04	108.28	104.01	104.62	124.45	124.13	19.65	18.65
समग्र अखिल भारतीय सीपीआई	100.00	102.75	101.32	101.39	104.57	104.84	3.21	3.40
मेमो मद								
खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई#	53.04	103.37	102.12	102.34	105.90	106.08	3.70	3.65

अ: अनंतिम

'*': कैलेंडर वर्ष 2025 के सभी मासिक सूचकांकों का अंकगणितीय माध्य।

'#': इस सारणी में 'ईंधन' दो श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात 'बिजली, गैस और अन्य ईंधन' तथा 'व्यक्तिगत परिवहन उपकरणों के लिए ईंधन और स्नेहक', जिसमें 'पेट्रोल', 'डीजल' और 'अन्य प्राकृतिक गैस (सीएनजी)' शामिल हैं। विस्तृत विवरण के लिए कृपया अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट के बॉक्स आइटम IV.2 देखें।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार और आरबीआई स्टाफ की गणनाएं।

सं. 20: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	जोड़ने वाला कारक	2024-25	2025	2026	
				फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5	6
1. औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	142.6	142.8	148.6	148.5
2. कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2019	9.69	-	133.2	137.1	136.6
3. ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2019	9.78	-	133.4	136.9	136.5

फर 2025 (आधार वर्ष 2019) के लिए सीपीआई-एएल और आरएल सूचकांकों की गणना प्रकाशित मुद्रास्फीति दरों का उपयोग कर की गई है।

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 21: मुंबई में स्वर्ण और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2024-25	2025	2026	
		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4
1. मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	75842	84995	145947	154039
2. चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	89131	95524	285593	256061

स्रोत: मुंबई में स्वर्ण और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

सं. 22: थोक मूल्य सूचकांक

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2024-25	2026		
			जन.	फर.(अ)	मार्च (अ)
	1	2	3	4	5
1 सभी पण्य	**100.000**	**154.9**	**157.6**	**158.2**	**160.8**
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	**22.618**	**192.5**	**194.0**	**192.9**	**197.3**
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	**15.256**	**205.3**	**203.1**	**200.2**	**198.5**
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	210.1	206.6	205.8	203.7
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	241.4	221.0	206.4	200.9
1.1.1.3 दूध	4.440	185.8	191.7	192.1	192.1
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	173.4	181.1	180.7	181.7
1.1.1.5 मसाले	0.529	232.7	223.3	231.5	230.6
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	213.6	223.3	226.2	224.8
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	**4.119**	**161.7**	**180.4**	**181.7**	**181.3**
1.1.2.1 फाइबर	0.839	161.4	175.1	176.8	184.3
1.1.2.2 तिलहन	1.115	181.5	218.7	224.3	220.2
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	138.7	141.0	142.0	143.7
1.1.2.4 पुष्पोत्पादन	0.204	277.4	371.2	350.9	318.6
1.1.3 खनिज	**0.833**	**229.0**	**253.1**	**253.1**	**253.4**
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	219.2	246.6	246.6	247.0
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	263.4	276.1	276.2	275.7
1.1.4 कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस	**2.410**	**151.3**	**139.1**	**144.9**	**197.3**
1.2 ईंधन और ऊर्जा	**13.152**	**150.0**	**145.9**	**147.6**	**153.7**
1.2.1 कोयला	**2.138**	**135.6**	**138.0**	**138.0**	**138.0**
1.2.1.1 कुकिंग कोयला	0.647	143.4	152.6	152.6	152.6
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोयला	1.401	125.8	126.6	126.6	126.6
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	232.4	209.4	209.4	209.4
1.2.2 खनिज तेल	**7.950**	**156.2**	**146.3**	**149.3**	**162.4**
1.2.3 बिजली	**3.064**	**144.1**	**150.2**	**149.8**	**142.2**
1.3 विनिर्मित उत्पाद	**64.231**	**142.6**	**147.1**	**148.2**	**149.5**
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	**9.122**	**172.0**	**179.8**	**180.7**	**183.4**
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	155.7	159.9	161.7	164.1
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	144.9	156.1	157.3	152.9
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	132.6	134.2	133.9	133.8
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	168.5	188.7	190.3	194.6
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	180.8	190.5	191.4	192.8
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	186.9	185.4	185.4	186.0
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	167.0	144.3	145.3	144.2
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	170.5	180.2	180.7	182.0
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	139.1	143.9	145.1	145.7
1.3.1.10 कोकोआ, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	160.6	176.6	175.5	175.3
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	156.7	154.0	153.4	158.1
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	190.7	178.5	178.2	200.4
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	192.6	194.0	195.5	198.7
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	152.7	154.6	154.8	155.7
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	185.1	192.2	192.7	192.8
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	204.1	206.5	208.9	211.1
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	**0.909**	**134.1**	**135.7**	**135.8**	**135.3**
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	136.0	138.4	138.5	138.0
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	138.7	140.6	140.5	140.8
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी का उत्पादन	0.275	127.5	127.5	127.9	126.9
1.3.3 तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण	**0.514**	**177.8**	**183.3**	**191.1**	**191.7**
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	177.8	183.3	191.1	191.7

सं. 22: थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2024-25	2026		
			जन.	फर.(अ)	मार्च (अ)
	1	2	3	4	5
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	**4.881**	**136.3**	**140.2**	**141.4**	**143.2**
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	121.4	120.3	121.4	122.8
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	158.3	170.6	172.6	176.0
1.3.4.3 बुने हुए और क्रोशिए से बना कपड़ा	0.193	124.0	127.0	123.4	124.0
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	160.4	161.1	160.9	161.4
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	142.7	171.7	172.7	175.7
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	134.9	134.5	135.5	136.0
1.3.5 तैयार वस्त्र का विनिर्माण	**0.814**	**153.4**	**157.3**	**157.6**	**157.3**
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर, तैयार वस्त्र (बुने हुए) का विनिर्माण	0.593	150.9	155.4	155.9	155.7
1.3.5.2 बुने हुए और क्रोशिए से बने वस्त्र	0.221	160.1	162.3	162.0	161.6
1.3.6 चमड़ा और संबंधित उत्पाद का विनिर्माण	**0.535**	**125.3**	**128.7**	**128.4**	**129.2**
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगाई	0.142	106.1	110.7	110.5	111.8
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और हार्नेस	0.075	142.5	144.1	144.9	145.2
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	129.7	133.0	132.5	133.2
1.3.7 लकड़ी व लकड़ी और कॉर्क के उत्पादों का विनिर्माण	**0.772**	**149.2**	**151.2**	**151.2**	**151.7**
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	141.1	145.2	144.9	145.9
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड, लैमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पैनल और बोर्ड का विनिर्माण	0.493	148.6	150.0	149.9	150.3
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	215.3	213.9	213.9	214.0
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	140.6	143.7	144.2	145.3
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पादों का विनिर्माण	**1.113**	**139.2**	**140.6**	**140.7**	**142.2**
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और पेपर बोर्ड	0.493	144.6	145.2	145.3	146.9
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	147.3	150.7	151.2	152.3
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	122.4	122.7	122.6	124.2
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	**0.676**	**187.3**	**191.1**	**191.3**	**191.0**
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	187.3	191.1	191.3	191.0
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	**6.465**	**136.5**	**137.5**	**137.9**	**139.9**
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	138.6	143.6	145.1	147.2
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	143.1	144.1	144.3	146.0
1.3.10.3 प्लास्टिक और प्राथमिक रूप में सिंथेटिक रबड़	1.001	133.6	132.1	133.3	136.5
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	128.8	130.8	130.5	130.9
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	139.5	138.3	137.0	138.4
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	139.7	142.8	142.0	142.6
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	135.4	132.8	132.7	134.7
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	104.9	101.8	102.4	107.7
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	**1.993**	**144.3**	**145.4**	**145.9**	**146.7**
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	144.3	145.4	145.9	146.7
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	**2.299**	**129.0**	**128.5**	**129.2**	**131.2**
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रिट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	115.6	114.0	114.6	114.4
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	112.1	112.1	112.7	113.9
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	138.1	137.9	138.6	141.7
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	**3.202**	**131.5**	**133.3**	**133.7**	**134.1**
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	163.2	162.8	163.3	163.3
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	121.6	124.3	124.1	128.0
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	124.4	143.1	143.1	143.1
1.3.13.4 चीनी मिट्टी और चीनी मिट्टी के उत्पाद	0.222	124.6	126.3	126.2	126.2
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	130.4	131.8	132.4	132.4

सं. 22: थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*

(आधार: 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ		भार	2024-25	2026		
				जन.	फर.(अ)	मार्च (अ)
		1	2	3	4	5
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं		0.292	139.2	138.4	138.5	139.2
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना		0.234	134.4	141.4	141.4	141.8
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद		0.169	95.2	91.2	91.1	91.2
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण		**9.646**	**139.7**	**141.6**	**143.9**	**145.1**
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री		1.411	133.6	131.1	133.7	134.8
1.3.14.2 धात्विक लोह		0.653	141.8	134.2	139.5	138.8
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात		1.274	117.9	117.6	118.0	118.7
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद		1.081	140.4	137.6	141.0	141.8
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद		1.144	134.2	131.9	136.4	139.0
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार		0.067	135.4	133.2	135.0	136.6
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील - अर्ध निर्मित		0.924	131.1	128.6	128.7	129.7
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब		0.205	164.7	161.2	162.5	162.2
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु		1.693	157.4	179.0	182.2	185.0
1.3.14.10 कास्टिंग		0.925	144.9	143.9	144.0	144.6
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं		0.271	172.2	171.9	171.8	171.0
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण		**3.155**	**136.0**	**136.7**	**136.3**	**136.2**
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद		1.031	130.8	132.0	130.5	131.9
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे		0.660	149.5	150.1	151.9	152.1
1.3.15.3 वाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर		0.145	109.8	113.2	113.7	113.7
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैम्पिंग और रोल फोर्मिंग, पाउडर धातुकर्म		0.383	138.0	130.6	129.2	123.6
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर		0.208	102.0	104.4	104.1	104.2
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद		0.728	144.9	148.2	147.9	148.1
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	**S**	**2.009**	**121.5**	**121.8**	**121.3**	**121.2**
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे		0.402	117.9	121.2	121.1	121.1
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण		0.336	134.2	129.7	129.7	129.7
1.3.16.3 संचार उपकरण		0.310	146.0	146.9	146.1	146.5
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स		0.641	101.1	98.1	96.8	96.4
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण		0.181	119.9	127.8	127.8	127.8
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी		0.076	167.9	178.1	179.7	179.7
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण		0.055	114.4	116.8	117.2	116.9
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण		0.008	107.4	119.0	119.0	119.5
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण		**2.930**	**133.7**	**138.4**	**139.2**	**139.5**
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण		1.298	132.3	133.9	134.9	135.3
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर		0.236	141.3	144.3	144.2	144.3
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल		0.133	118.6	120.6	121.8	119.2
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रानिक और बिज़ली के वायर और केबल		0.428	154.4	174.0	175.3	176.3
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण		0.263	118.4	124.6	125.4	125.5
1.3.17.6 घरेलू उपकरण		0.366	131.8	131.3	131.4	131.3
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण		0.206	123.4	128.3	128.8	129.2
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण		**4.789**	**130.8**	**132.8**	**133.1**	**132.9**
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर		0.638	132.8	136.5	136.4	136.5
1.3.18.2 तरल ऊर्जा उपकरण		0.162	134.5	134.9	135.7	135.7
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व		0.552	118.5	122.9	123.2	123.2
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण		0.340	128.5	133.5	131.8	132.0
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर		0.008	86.6	92.6	92.6	92.6
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने – उतारने वाले उपकरण		0.285	130.0	131.8	132.3	132.3

सं. 22: थोक मूल्य सूचकांक *(समाप्त)*

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2024-25	2026		
			जन.	फर.(अ)	मार्च (अ)
	1	2	3	4	5
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	145.3	141.1	142.5	142.4
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	145.5	145.0	145.7	145.7
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	123.2	127.6	128.0	128.0
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	89.8	93.5	93.6	93.4
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	126.1	125.9	125.9	126.2
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	141.4	146.4	146.5	145.2
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	144.9	148.0	148.2	146.8
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	69.2	68.7	68.7	68.9
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	**4.969**	**129.9**	**130.4**	**130.6**	**130.8**
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	130.6	130.3	130.5	130.6
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	129.1	130.5	130.7	131.0
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	**1.648**	**145.2**	**153.0**	**153.2**	**154.7**
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली – वस्तुओं का निर्माण	0.117	180.5	190.8	190.8	205.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	108.9	110.7	110.7	110.7
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	146.0	154.5	154.8	155.2
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	134.9	137.9	137.8	139.5
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	163.2	167.3	170.8	170.8
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	**0.727**	**160.3**	**164.2**	**164.6**	**165.1**
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	160.3	164.2	164.6	165.1
1.3.22 अन्य विनिर्माण	**1.064**	**183.8**	**286.8**	**304.7**	**316.2**
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	185.4	294.9	314.0	326.3
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	201.9	208.1	209.4	209.4
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	164.9	173.3	174.1	174.3
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	163.1	169.9	166.2	169.3
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और संबंधित सामग्री	0.049	158.6	164.2	164.7	164.7
2 खाद्य सूचकांक	**24.378**	**192.9**	**194.4**	**192.9**	**192.8**

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 23: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भार	2023-24	2024-25	अप्रै.-फर.		फरवरी	
				2024-25	2025-26	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	**100.00**	**146.7**	**152.6**	**151.4**	**157.6**	**151.1**	**159.0**
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	128.9	132.8	130.5	131.6	141.9	146.3
1.2 विनिर्माण	77.63	144.7	150.6	149.5	157.0	148.4	157.3
1.3 बिजली	7.99	198.3	208.6	207.6	209.8	194.0	198.4
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	147.7	153.5	152.0	153.8	152.3	155.0
2.2 पूंजीगत माल	8.22	106.6	112.6	110.4	118.7	115.4	129.8
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	157.3	164.0	162.9	172.4	159.1	171.3
2.4 अवसंरचना/निर्माण वस्तुएं	12.34	176.3	188.2	185.8	204.7	191.7	213.2
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	118.6	128.0	127.1	134.6	126.4	135.6
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	153.7	151.4	151.6	151.5	146.7	145.8

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खजाना बिल

सं. 24: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(₹ करोड़)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रै. - फर.			
	2025-26 (संशोधित अनुमान)	2025-26 (वास्तविक आंकड़े)	2024-25 (वास्तविक आंकड़े)	संशोधित अनुमानों का प्रतिशत	
				2025-26	2024-25
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	**3342323**	**2726396**	**2508953**	**81.6**	**81.2**
1.1 कर राजस्व (निवल)	2674661	2145223	2015634	80.2	78.8
1.2 करेतर राजस्व	667662	581173	493319	87.0	92.9
2 गैर कर्ज पूंजीगत प्राप्तियां	**64027**	**65547**	**37364**	**102.4**	**63.3**
2.1 ऋण की वसूली	30190	21596	21655	71.5	83.3
2.2 अन्य प्राप्तियां	33837	43951	15709	129.9	47.6
3 कुल प्राप्तियां (लिए गए उधार को छोड़कर) (1+2)	**3406350**	**2791943**	**2546317**	**82.0**	**80.9**
4 राजस्व व्यय	3869087	3115270	3081282	80.5	83.3
जिसमें से :					
4.1 ब्याज भुगतान	1274338	1065305	952844	83.6	83.7
5 पूंजी व्यय	1095755	929322	811887	84.8	79.7
6 कुल व्यय (4+5)	**4964842**	**4044592**	**3893169**	**81.5**	**82.5**
7 राजस्व घाटा (4-1)	**526764**	**388874**	**572329**	**73.8**	**93.8**
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	**1558492**	**1252649**	**1346852**	**80.4**	**85.8**
9 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]	**284154**	**187344**	**394008**	**65.9**	**91.3**

स्रोत: महालेखानियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय बजट 2026-27।

सं. 25: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2024-25	2025	2026					
		फर. 28	जन. 23	जन. 30	फर. 6	फर. 13	फर. 20	फर. 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	26554	7786	9423	11852	11495	13123	17961	16216
1.2 प्राथमिक व्यापारी	25258	14025	13956	12338	9936	10057	11678	12437
1.3 राज्य सरकारें	40315	73415	92335	81335	79586	75086	68427	62941
1.4 अन्य	115688	116990	79421	80610	83868	89120	89661	97647
2. 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	44887	37126	41116	39614	39116	35988	36090	38079
2.2 प्राथमिक व्यापारी	62218	54510	60364	64620	69016	75616	82592	86843
2.3 राज्य सरकारें	11078	7528	7264	7264	7264	7264	5264	4964
2.4 अन्य	104994	85164	85820	89066	91168	94296	93218	92978
3. 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	72304	66240	62136	63543	60373	57493	56059	54829
3.2 प्राथमिक व्यापारी	86939	112173	96615	98996	103049	99433	103825	107032
3.3 राज्य सरकारें	37389	36713	41257	38336	40946	42359	42623	42395
3.4 अन्य	162757	151587	151548	148760	147878	154374	152416	151439
4. 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	188072	291002	229929	215805	152931	243069	270170	264716
4.4 अन्य	572	38	2228	548	1010	480	1192	853
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर) #	790381	763256	741256	736334	743696	754209	759814	767799

#: 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल, 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे बिक्री योग्य नहीं हैं। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।

सं. 26: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियाँ			कुल निर्गम (6+7)	निर्दिष्ट मूल्य (₹)	निर्दिष्ट मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2025-26										
जन. 28	9000	111	23280	8013	66	8987	8013	17000	98.65	5.4997
फर. 4	9000	127	30828	2807	40	8633	2807	11440	98.69	5.3447
फर. 11	14000	137	39804	1026	71	13974	1026	15000	98.69	5.3200
फर. 18	14000	148	44580	2028	67	13977	2028	16006	98.69	5.3176
फर. 25	14000	147	46399	1538	69	13981	1538	15519	98.70	5.2998
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2025-26										
जन. 28	12000	82	35407	1008	32	11992	1008	13000	97.25	5.6793
फर. 4	12000	114	51285	2311	17	11400	2300	13700	97.28	5.5973
फर. 11	12000	131	56962	610	19	11990	610	12600	97.30	5.5581
फर. 18	12000	165	51327	29	28	11971	29	12000	97.31	5.5361
फर. 25	12000	149	52283	1511	29	11989	1511	13500	97.33	5.5096
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2025-26										
जन. 28	8000	105	24003	1009	61	7991	1009	9000	94.59	5.7391
फर. 4	8000	145	36735	3204	18	7600	3170	10770	94.67	5.6475
फर. 11	8000	136	40566	1881	24	7819	1881	9700	94.70	5.6100
फर. 18	8000	142	29355	694	61	7606	694	8300	94.71	5.5997
फर. 25	8000	148	31215	64	50	7936	64	8000	94.72	5.5863

वित्तीय बाजार

सं. 27: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

की स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा	भारित औसत दरें
	उधार लेना / उधार देना	उधार लेना / उधार देना
	1	2
फरवरी 02, 2026	4.25-5.30	5.20
फरवरी 03, 2026	4.40-5.26	5.06
फरवरी 04, 2026	4.40-5.65	4.99
फरवरी 05, 2026	4.40-5.15	5.03
फरवरी 06, 2026	4.40-5.10	5.03
फरवरी 07, 2026	4.00-5.10	4.55
फरवरी 09, 2026	4.10-5.10	5.03
फरवरी 10, 2026	4.35-5.10	5.02
फरवरी 11, 2026	4.40-5.10	5.03
फरवरी 12, 2026	4.40-5.10	5.04
फरवरी 13, 2026	4.50-5.75	5.05
फरवरी 16, 2026	4.50-5.20	5.09
फरवरी 17, 2026	4.50-5.20	5.08
फरवरी 18, 2026	4.50-5.20	5.07
फरवरी 20, 2026	4.50-5.78	5.09
फरवरी 21, 2026	4.50-5.15	4.72
फरवरी 23, 2026	4.50-5.50	5.11
फरवरी 24, 2026	4.50-5.50	5.10
फरवरी 25, 2026	4.50-5.20	5.09
फरवरी 26, 2026	4.50-5.20	5.08
फरवरी 27, 2026	4.50-5.22	5.11
मार्च 02, 2026	4.50-5.20	5.06
मार्च 04, 2026	4.50-5.20	5.11
मार्च 05, 2026	4.50-5.15	5.06
मार्च 06, 2026	4.20-5.25	5.06
मार्च 07, 2026	4.60-5.15	4.76
मार्च 09, 2026	4.20-5.22	5.07
मार्च 10, 2026	4.50-5.20	5.07
मार्च 11, 2026	4.50-5.15	5.08
मार्च 12, 2026	4.50-5.15	5.07
मार्च 13, 2026	4.60-5.20	5.10

टिप्पणी: इसमें नोटिस मनी शामिल है।

सं. 28: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2025	2026			
	मार्च 21	फर. 15	फर. 28	मार्च 15	मार्च 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	532971.66	662414.76	663845.18	679391.41	692680.56
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (₹ करोड़)	117053.02	134618.68	73093.24	107613.36	107211.64
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.98-8.05	5.25-7.37	5.24-7.64	5.25-7.56	5.25-8.15

सं. 29: वाणिज्यिक पत्र

मद	2025	2026			
	मार्च 21	फर. 15	फर. 28	मार्च 15	मार्च 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	442892.70	481234.60	478434.45	476150.85	460151.55
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (₹ करोड़)	77133.85	110283.75	79734.20	100794.60	77688.35
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	7.00-14.46	6.06-13.56	5.96-11.18	6.27-12.00	5.92-14.40

सं. 30: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(₹ करोड़)

मद	2024-25	2025	2026					
		फर. 28	जन. 23	जन. 30	फर. 6	फर. 13	फर. 20	फर. 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	18990	25329	27303	28120	19656	21624	21864	23035
2 नोटिस मुद्रा	2506	8886	713	7851	4921	652	6771	587
3 मीयादी मुद्रा	941	1425	1342	1521	1387	1419	2486	1488
4 त्रिपक्षीय रेपो	692068	802167	825908	1038585	805550	808798	985652	798950
5 बाजार रेपो	578912	627685	631318	771848	581184	570489	685917	619354
6 कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो	5212	7237	18256	17852	20688	22847	20938	21222
7 विदेशी मुद्रा (यूएस मिलियन डॉलर)	131877	155172	147647	182645	157068	130093	108328	137674
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	56065	86173	109698	97876	140333	126041	103912	95979
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	3971	16088	4220	6460	8020	9331	9442	10626
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	2514	5438	2715	2592	3764	3128	2923	3587
10.2 182-दिवसीय	2218	4596	3928	2519	3793	8930	5195	4999
10.3 364-दिवसीय	1854	4148	3734	6353	5603	5534	5487	4537
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	-	-	-	-	-	-	-	-
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	66622	116444	124295	115800	161513	152964	126960	119728
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	1715	704	13597	14335	11567	2449	1836	2537

सं. 31: गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2024-25		2024-25 (अप्रै.-फर.)		2025-26 (अप्रै.-फर.) *		फर. 2025		फर. 2026 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	**464**	**210190**	**443**	**208151**	**467**	**224949**	**31**	**15513**	**24**	**4949**
1.1 पब्लिक	322	190478	310	189947	347	180198	21	14745	17	4650
1.2 राइट्स	142	19712	133	18204	120	44751	10	768	7	299
2 बॉण्ड और डिबेंचर्स के सार्वजनिक निर्गम	**43**	**8149**	**39**	**7694**	**38**	**9580**	**1**	**297**	**3**	**896**
3 कुल (1+2)	**507**	**218339**	**482**	**215845**	**505**	**234529**	**32**	**15810**	**27**	**5845**
3.1 पब्लिक	365	198627	349	197641	385	189778	22	15042	20	5546
3.2 राइट्स	142	19712	133	18204	120	44751	10	768	7	299

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़े कुल में न जुड़ पाने की संभावना है।

3. सारणी में केवल इक्विटी और डेट के पब्लिक और राइट्स निर्गम शामिल हैं। इसमें डेट के निजी प्लेसमेंट, पात्र संस्थागत प्लेसमेंट और अधिमान्य आबंटन के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

बाह्य क्षेत्र

सं. 32 : विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2024-25	2025			2026	
			फर.	अक्तू.	नवं.	दिसं.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	₹ करोड़	3703412	321327	301546	336681	344846	331263	332159
	यूएस $ मिलियन	437705	36911	34105	37904	38277	36483	36609
1.1 तेल	₹ करोड़	535157	49785	32727	32924	37546	33459	31088
	यूएस $ मिलियन	63383	5719	3701	3707	4168	3685	3426
1.2 तेल से इतर	₹ करोड़	3168255	271542	268820	303757	307300	297804	301071
	यूएस $ मिलियन	374321	31192	30404	34197	34110	32798	33183
2 आयात	₹ करोड़	6089909	443663	678398	559434	580879	646715	578078
	यूएस $ मिलियन	720241	50964	76728	62981	64477	71225	63713
2.1 तेल	₹ करोड़	1570226	103528	130752	125315	129693	121689	117692
	यूएस $ मिलियन	185779	11892	14788	14108	14396	13402	12972
2.2 तेल से इतर	₹ करोड़	4519683	340135	547646	434120	451186	525026	460386
	यूएस $ मिलियन	534462	39071	61939	48873	50081	57823	50742
3 व्यापार शेष	₹ करोड़	-2386497	-122336	-376852	-222753	-236033	-315452	-245919
	यूएस $ मिलियन	-282537	-14053	-42622	-25078	-26199	-34742	-27104
3. 1 तेल	₹ करोड़	-1035069	-53743	-98026	-92391	-92147	-88230	-86604
	यूएस $ मिलियन	-122396	-6173	-11087	-10401	-10228	-9717	-9545
3. 2 तेल से इतर	₹ करोड़	-1351428	-68593	-278826	-130363	-143886	-227222	-159314
	यूएस $ मिलियन	-160141	-7879	-31536	-14676	-15971	-25025	-17559

टिप्पणी: सारणी में डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय।

सं. 33: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

मद	इकाई	2025	2026					
		अप्रै. 04	फर. 20	फर. 27	मार्च. 06	मार्च. 13	मार्च. 20	मार्च. 27
		1	2	3	4	5	6	7
1. कुल आरक्षित निधियां	**₹ करोड़**	**5764903**	**6583899**	**6627548**	**6575627**	**6561849**	**6543246**	**6520745**
	यूएस $ मिलियन	**676268**	**723608**	**728494**	**716810**	**709759**	**698346**	**688058**
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	₹ करोड़	4893864	5209603	5214072	5166923	5136326	5225529	5222593
	यूएस $ मिलियन	574088	572564	573125	563245	555568	557695	551072
1.2 स्वर्ण	₹ करोड़	676510	1159988	1197517	1192711	1208169	1098021	1075852
	यूएस $ मिलियन	79360	127489	131630	130017	130681	117186	113521
	मात्रा (मीट्रिक टन)	879.58	880.34	880.34	880.34	880.34	880.34	880.34
1.3 एसडीआर	एसडीआर मिलियन	13706	13714	13714	13714	13714	13714	13714
	₹ करोड़	156526	171419	171635	171725	172857	174583	176739
	यूएस $ मिलियन	18362	18840	18866	18720	18697	18632	18649
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	₹ करोड़	38003	42889	44324	44267	44497	45113	45561
	यूएस $ मिलियन	4459	4716	4873	4828	4814	4833	4816

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन की वजह से है।
टिप्पणी : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर, सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा एवं नेक्सस ग्लोबल पेमेंटस को निधियन के रूप में आरबीआई के अंशदान शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में विदेशी मुद्रा आस्तियों को रिज़र्व में रखी गैर-यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए लिया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपये में परिवर्तित किया गया है।

सं. 34: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2024-25	2025	2026		2024-25	2025-26
		फर.	जन.	फर. (अ)	अप्रै.-फर.	अप्रै.-फर. (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियाँ	**164677**	**160339**	**165876**	**167579**	**14558**	**11039**
1.1 एफसीएनआर (बी)	32809	32492	33754	33720	6759	911
1.2 एनआर (ई) आरए	100733	97938	98930	99766	4010	5188
1.3 एनआरओ	31135	29908	33193	34092	3790	4940

अ: अनंतिम।

सं. 35: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2024-25	2024-25	2025-26 (अ)	2025 (अ)	2026 (अ)	
		अप्रै.-फर.	अप्रै.-फर.	फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	**959**	**1461**	**6268**	**-703**	**-1393**	**4620**
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.1.2)	**29130**	**25742**	**37041**	**3066**	**750**	**7245**
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह / सकल निवेश	**80615**	**74736**	**88297**	**5558**	**5665**	**8981**
1.1.1.1.1 इक्विटी	50993	47753	58706	2919	2659	5667
1.1.1.1.1.1 सरकारी	2208	1901	1805	37	74	51
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	34686	32246	40717	2291	1720	4391
1.1.1.1.1.3 शेयरों का अधिग्रहण	13124	12719	13059	502	556	916
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	975	887	3126	88	310	310
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	22759	20704	23256	2055	2308	2308
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	6863	6280	6335	584	698	1006
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	**51486**	**48994**	**51256**	**2491**	**4916**	**1735**
1.1.1.2.1 इक्विटी	49525	47126	48987	2400	4868	1504
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	1960	1869	2269	92	48	231
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	**28171**	**24281**	**30773**	**3770**	**2143**	**2625**
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	16945	14537	18935	2701	1620	1527
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	6846	6276	7074	571	643	643
1.1.2.3 अन्य पूंजी	7955	6722	7584	821	414	688
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	3575	3253	2819	322	534	232
1.2 निवल पोर्टफोलियो निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	**3564**	**-478**	**-3327**	**-3972**	**-1924**	**2913**
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	3283	-714	-2404	-4017	-2407	3074
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	-281	-236	922	-45	-482	161
1. विदेशी निवेश अंतर्वाह	**4523**	**982**	**2941**	**-4675**	**-3318**	**7534**

अ: अनंतिम।

सं. 36: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2024-25	2025		2026	
		फर.	दिसं.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5
1. एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	**29563.12**	**1964.21**	**2263.67**	**2680.43**	**2338.60**
1.1 जमाराशियाँ	705.26	51.62	54.60	48.60	56.90
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	322.82	28.76	47.90	57.33	51.36
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	1698.94	173.84	218.14	178.86	265.99
1.4 उपहार	2938.69	190.82	201.30	185.82	202.09
1.5 दान	11.81	0.59	0.89	0.55	0.86
1.6 यात्रा	16964.57	1090.61	1300.17	1658.33	1307.03
1.7 निकट संबंधियों से संबंधित खर्चे	3722.03	234.99	262.70	270.97	266.18
1.8 चिकित्सा उपचार	81.19	3.43	4.20	4.68	4.21
1.9 विदेश में शिक्षा	2918.91	182.17	165.88	267.42	175.68
1.10 अन्य	198.90	7.38	7.89	7.87	8.30

सं. 37: भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक

मद	2023-24	2024-25	2025	2026	
			मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा समूह (आधार: 2015-16 = 100)					
1. व्यापार-भारित					
1.1 नीर	91.01	84.72	89.00	81.70	80.80
1.2 रीर	105.41	97.47	101.72	93.99	92.72
2. निर्यात-आधारित भारांक					
2.1 नीर	93.52	86.84	91.71	84.27	83.33
2. 2 रीर	102.50	94.90	98.95	92.12	90.62
6- मुद्रा समूह (व्यापार-भारित)					
1. आधार : 2015-16 =100					
1.1 नीर	82.38	76.73	80.24	73.76	72.71
1.2 रीर	102.72	95.85	99.20	92.45	91.23
2. आधार : 2022-23 = 100					
2.1 नीर	95.87	89.30	93.38	85.83	84.62
2.2 रीर	100.90	94.16	97.44	90.82	89.61

टिप्पणी : 2024-25 और 2025-26 के लिए अब तक का डेटा अनंतिम है।

सं. 38: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(राशि मिलियन अमेरिकी$ में)

मद	2024-25	2025	2026	
		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4
1. स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1328	107	113	121
1.2 राशि	47800	2627	4183	4231
2. अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	51	1	3	2
2.2 राशि	13384	197	1152	400
3. कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1379	108	116	123
3.2 राशि	61184	2824	5335	4631
4. भारित औसत परिपक्वता (वर्षो में)	5.05	5.40	7.60	5.50
5. ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 अस्थिर दर के ऋणों@ के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) पर भारित औसत मार्जिन	1.48	1.87	1.42	1.73
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-11.67	0.00-11.00	0.00-11.00	0.00-11.00
उधारकर्ता श्रेणियाँ				
I. कॉरपोरेट विनिर्माण	13900	1389	337	214
II. कॉरपोरेट - अवसंरचना	15462	527	1266	2258
ए) परिवहन	614	371	0	43
बी) ऊर्जा	6900	49	608	2173
सी) पानी और सफाई व्यवस्था	28	0	0	0
डी) संचार	13	0	0	0
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना	184	0	0	1
एफ) अन्वेषण, खनन और रिफाइनरी	5356	100	600	0
जी) अन्य उप-क्षेत्र	2367	7	58	41
III. कॉरपोरेट सेवा क्षेत्र	3226	211	778	230
IV. अन्य संस्थाएं	1026	0	1000	0
ए) एसईज़ेड में इकाइयां	26	0	0	0
बी) सिडबी	0	0	0	0
सी) एक्ज़िम बैंक	1000	0	1000	0
V. बैंक	0	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी के अलावा)	0	0	0	0
VII. एनबीएफसी	26318	623	1884	1879
ए) एनबीएफसी - आईएफसी / एएफसी	12389	472	596	161
बी) एनबीएफसी - एमएफआई	459	0	0	150
सी) एनबीफसी - अन्य	13470	151	1288	1568
VIII. गैर -सरकारी संगठन (एनजीओ)	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)	0	0	0	0
X. अन्य	1252	74	70	50

@ 01 जुलाई, 2023 से बेंचमार्क दर को बदलकर वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) कर दिया गया है।

टिप्पणी: ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों के आधार पर जिन्हें निर्धारित अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या आबंटित की गई है।

2. फरवरी 2026 के लिए 'स्वचालित मार्ग' और 'अनुमोदन मार्ग' में क्रमशः 'फॉर्म ईसीबी 1' में पेश किए गए 'सामान्य अनुमति' और 'विशेष अनुमति' के तहत लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल हैं।

सारणी 39ए: भारत से माल और सॉफ्टवेयर के निर्यात और भारत को माल के आयात के लिए आईएनआर में बिलिंग

(आईएनआर बिलियन)

मद	अप्रै.-फर. 2025-26	अप्रै.-फर. 2024-25	अप्रै.-मार्च 2024-25	अप्रै.-मार्च 2023-24
	1	2	3	4
निर्यात	2959.15 (6.14%)	2752.43 (5.89%)	3070.45 (5.90%)	2866.38 (5.87%)
आयात	2660.16 (4.65%)	2284.79 (4.37%)	2599.11 (4.54%)	1941.58 (3.70%)

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सभी मुद्राओं की तुलना में आईएनआर का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. सभी आंकड़े एडी बैंक द्वारा ईडीपीएमएस/आईडीपीएमएस पोर्टल पर दी गई रिपोर्टिंग पर आधारित हैं और इसलिए समय-समय पर इनमें अद्यतन/सुधार हो सकते हैं।

स्रोत: ईडीपीएमएस/आईडीपीएमएस पोर्टल।

सारणी 39b: भारत से माल और सॉफ्टवेयर के निर्यात और भारत को माल के आयात के लिए आईएनआर में निपटान

(आईएनआर बिलियन)

मद	अप्रै.-फर. 2025-26	अप्रै.-फर. 2024-25	अप्रै.-मार्च 2024-25	अप्रै.-मार्च 2023-24
	1	2	3	4
निर्यात	1458.98 (2.82%)	1514.50 (3.20%)	1663.39 (3.16%)	1743.40 (3.55%)
आयात	1390.74 (2.35%)	961.54 (1.80%)	1128.54 (1.94%)	995.96 (1.85%)

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सभी मुद्राओं की तुलना में आईएनआर का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. सभी आंकड़े एडी बैंक द्वारा ईडीपीएमएस/आईडीपीएमएस पोर्टल पर दी गई रिपोर्टिंग पर आधारित हैं और इसलिए समय-समय पर इनमें अद्यतन/सुधार हो सकते हैं।

स्रोत: ईडीपीएमएस/आईडीपीएमएस पोर्टल।

सं. 40: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी $)

मद	अक्तू.-दिसं. 2024			अक्तू.-दिसं. 2025 (प्रा)		
	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**544481**	**582141**	**-37660**	**734969**	**759378**	**-24409**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**261726**	**273065**	**-11338**	**274865**	**288062**	**-13198**
1.1 पण्य	**109817**	**189126**	**-79309**	**111694**	**205324**	**-93629**
1.2 अप्रत्यक्ष मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**151909**	**83939**	**67970**	**163170**	**82739**	**80432**
1.2.1 सेवाएं	103487	52277	51210	111227	53726	57502
1.2.1.1 यात्रा	10068	8371	1698	9924	9052	872
1.2.1.2 परिवहन	8278	8847	-569	8278	8481	-203
1.2.1.3 बीमा	870	894	-24	888	832	56
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	167	307	-139	166	335	-170
1.2.1.5 विविध	84104	33859	50245	91972	35026	56947
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	47619	6561	41057	53502	6437	47065
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	29603	18252	11352	32121	19261	12859
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	2086	741	1346	1935	875	1060
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	580	616	-37	706	614	93
1.2.2 अंतरण	36081	2898	33182	37949	2821	35128
1.2.2.1 आधिकारिक	89	334	-244	105	344	-239
1.2.2.2 निजी	35992	2565	33427	37844	2477	35367
1.2.3 आय	12341	28763	-16422	13994	26192	-12198
1.2.3.1 निवेश आय	10161	27718	-17557	11742	25046	-13305
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	2180	1046	1135	2253	1146	1107
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**282456**	**309077**	**-26620**	**460105**	**470109**	**-10005**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**192047**	**206229**	**-14182**	**208007**	**211843**	**-3836**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	20635	23445	-2810	22457	26116	-3659
2.1.1.1 भारत में	19722	16218	3505	21804	17926	3879
2.1.1.1.1 इक्विटी	11136	15637	-4501	13589	17273	-3684
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	5934		5934	6659		6659
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	2653	581	2072	1556	652	904
2.1.1.2 विदेश में	913	7228	-6315	652	8190	-7538
2.1.1.1.1 इक्विटी	913	3313	-2400	652	4613	-3960
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	0	1712	-1712	0	1929	-1929
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	0	2203	-2203	0	1648	-1648
2.1.2 पोर्टफोलियो निवेश	171412	182784	-11372	185550	185727	-177
2.1.2.1 भारत में	170667	182102	-11435	184185	184270	-85
2.1.2.1.1 एफआईआई	170667	182102	-11435	184185	184270	-85
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	144811	156671	-11860	157600	158838	-1238
2.1.2.1.1.2 ऋण	25856	25431	425	26585	25431	1154
2.1.2.1.2 एडीआर / जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	745	682	63	1365	1458	-93
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**43114**	**34052**	**9062**	**211981**	**198665**	**13317**
2.2.1 बाह्य सहायता	2955	2289	666	3029	3229	-200
2.2.1.1 भारत द्वारा	6	26	-20	6	10	-4
2.2.1.2 भारत को	2949	2263	686	3023	3219	-196
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	20906	16522	4384	184501	182401	2100
2.2.2.1 भारत द्वारा	9621	9593	28	176565	177759	-1194
2.2.2.2 भारत को	11285	6929	4356	7936	4642	3294
2.2.3 भारत को अल्पावधि	19253	15241	4012	24451	13034	11417
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	14260	15241	-980	20106	13034	7072
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	4993	0	4993	4345	0	4345
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**39538**	**49311**	**-9774**	**35825**	**35133**	**692**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	39530	49306	-9776	35825	35016	810
2.3.1.1 आस्तियां	11853	25923	-14070	6142	13305	-7162
2.3.1.2 देयताएं	27677	23383	4294	29683	21711	7972
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियाँ	25912	22771	3141	25932	20877	5054
2.3.2 अन्य	8	5	2	0	118	-118
2.4 रुपया कर्ज चुकौती		**0**	**0**		**0**	**0**
2.5 अन्य पूंजी	**7757**	**19484**	**-11727**	**4291**	**24468**	**-20177**
3 भूल-चूक	**298**	**0**	**298**	**0**	**1206**	**-1206**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	**37660**	**0**	**37660**	**24409**	**0**	**24409**
4.1 आई.एम.एफ.	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	37660		37660	24409		24409

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक ।

सं. 41: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(₹ करोड़)

मद	अक्तू.-दिसं. 2024			अक्तू.-दिसं. 2025 (प्रा)		
	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**4598686**	**4916766**	**-318081**	**6549391**	**6766900**	**-217509**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**2210541**	**2306305**	**-95764**	**2449348**	**2566955**	**-117607**
1.1 पण्य	**927514**	**1597355**	**-669841**	**995321**	**1829663**	**-834342**
1.2 अप्रत्यक्ष मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**1283026**	**708950**	**574077**	**1454028**	**737293**	**716735**
1.2.1 सेवाएं	874055	441535	432520	991157	478754	512403
1.2.1.1 यात्रा	85035	70697	14338	88432	80662	7771
1.2.1.2 परिवहन	69916	74723	-4807	73762	75571	-1809
1.2.1.3 बीमा	7347	7553	-206	7910	7415	495
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	1413	2590	-1177	1477	2989	-1512
1.2.1.5 विविध	710344	285972	424372	819575	312117	507458
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	402186	55417	346769	476760	57362	419398
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	250030	154153	95877	286231	171639	114591
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	17623	6256	11367	17241	7793	9448
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	4896	5207	-310	6292	5468	824
1.2.2 अंतरण	304738	24479	280259	338167	25135	313032
1.2.2.1 आधिकारिक	753	2817	-2064	932	3061	-2129
1.2.2.2 निजी	303985	21662	282323	337235	22074	315160
1.2.3 आय	104233	242936	-138702	124704	233403	-108700
1.2.3.1 निवेश आय	85820	234105	-148285	104630	223191	-118561
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	18413	8831	9582	20074	10212	9861
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**2385627**	**2610461**	**-224834**	**4100043**	**4189196**	**-89153**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**1622029**	**1741812**	**-119783**	**1853572**	**1887758**	**-34186**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	174285	198020	-23735	200114	232721	-32607
2.1.1.1 भारत में	166573	136974	29599	194301	159739	34562
2.1.1.1.1 इक्विटी	94051	132068	-38017	121097	153925	-32828
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	50117	0	50117	59336	0	59336
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	22405	4905	17500	13868	5813	8055
2.1.1.2 विदेश में	7712	61046	-53334	5814	72983	-67169
2.1.1.2.1 इक्विटी	7712	27980	-20268	5814	41104	-35291
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	14456	-14456	0	17192	-17192
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	18610	-18610	0	14686	-14686
2.1.2 पोर्टफोलियो निवेश	1447744	1543792	-96048	1653457	1655037	-1580
2.1.2.1 भारत में	1441453	1538030	-96577	1641292	1642046	-754
2.1.2.1.1 एफआईआई	1441453	1538030	-96577	1641292	1642046	-754
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	1223076	1323243	-100167	1404393	1415426	-11033
2.1.2.1.1.2 ऋण	218376	214787	3590	236899	226620	10279
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	6291	5762	529	12165	12990	-825
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**364145**	**287604**	**76541**	**1888990**	**1770325**	**118665**
2.2.1 बाह्य सहायता	24961	19334	5626	26994	28775	-1781
2.2.1.1 भारत द्वारा	52	217	-166	52	86	-34
2.2.1.2 भारत को	24909	19117	5792	26942	28689	-1747
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	176574	139548	37025	1644108	1625398	18709
2.2.2.1 भारत द्वारा	81258	81026	232	1573392	1584033	-10641
2.2.2.2 भारत को	95315	58522	36793	70716	41365	29351
2.2.3 भारत को अल्पावधि	162611	128721	33889	217889	116152	101737
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	120442	128721	-8280	179169	116152	63017
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	42169	0	42169	38720	0	38720
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**333936**	**416483**	**-82547**	**319243**	**313076**	**6167**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	333872	416438	-82566	319243	312027	7215
2.3.1.1 आस्तियां	100112	218949	-118837	54736	118561	-63825
2.3.1.2 देयताएं	233760	197489	36271	264506	193466	71041
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियाँ	218851	192322	26530	231079	186041	45038
2.3.2 अन्य	64	45	19	0	1048	-1048
2.4 रुपया ऋण चुकौती	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.5 अन्य पूंजी	**65518**	**164562**	**-99045**	**38239**	**218037**	**-179799**
3 भूल-चूक	**2518**	**0**	**2518**	**0**	**10749**	**-10749**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	**318081**	**0**	**318081**	**217509**	**0**	**217509**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	318081	0	318081	217509	0	217509

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक।

सं. 42: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमेरिकी $)

मद	अक्तू.-दिसं. 2024			अक्तू.-दिसं. 2025 (अ)		
	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	**261720**	**273035**	**-11315**	**274857**	**288029**	**-13172**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**213304**	**241403**	**-28099**	**222921**	**259049**	**-36128**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**109817**	**189126**	**-79309**	**111694**	**205324**	**-93629**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	109391	169659	-60268	111359	182444	-71085
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	426	0	426	335	0	335
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		19467	-19467		22879	-22879
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**103487**	**52277**	**51210**	**111227**	**53726**	**57502**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	244	31	213	369	65	304
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	82	305	-223	120	465	-345
1.अ.ख.3 परिवहन	8278	8847	-569	8278	8481	-203
1.अ.ख.4 यात्रा	10068	8371	1698	9924	9052	872
1.अ.ख.5 निर्माण	1047	834	213	1371	822	549
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	870	894	-24	888	832	56
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	2086	741	1346	1935	875	1060
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	621	4573	-3952	491	4562	-4070
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	48296	7416	40880	54315	7275	47039
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	29603	18252	11352	32121	19261	12859
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	1148	1242	-95	1193	1120	73
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी माल और सेवाएं	167	307	-139	166	335	-170
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	977	465	512	58	582	-524
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**12341**	**28763**	**-16422**	**13994**	**26192**	**-12198**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	2180	1046	1135	2253	1146	1107
1.आ.2 निवेश आय	8094	26925	-18831	7909	23722	-15813
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	2631	17134	-14503	2793	15041	-12249
1.आ.2.2 पोर्टफोलियो निवेश	95	2596	-2502	80	1833	-1753
1.आ.2.3 अन्य निवेश	690	6991	-6301	1075	6686	-5612
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	4678	204	4474	3962	161	3801
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	2067	793	1274	3832	1324	2508
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**36074**	**2868**	**33206**	**37942**	**2788**	**35154**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	35992	2565	33427	37844	2477	35367
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	35063	1871	33192	36888	1862	35026
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	928	694	234	956	615	341
1.इ.2 सामान्य सरकार	83	303	-221	97	310	-213
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**185**	**322**	**-137**	**228**	**211**	**17**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	16	151	-135	25	73	-48
2.2 पूँजी अंतरण	169	171	-2	203	138	65
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**319938**	**308785**	**11154**	**484292**	**469931**	**14361**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**20635**	**23445**	**-2810**	**22457**	**26116**	**-3659**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	19722	16218	3505	21804	17926	3879
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	17069	15637	1433	20248	17273	2975
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	11136	15637	-4501	13589	17273	-3684
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	5934		5934	6659		6659
3.1.अ.2 डेट लिखत	2653	581	2072	1556	652	904
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	2653	581	2072	1556	652	904
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	913	7228	-6315	652	8190	-7538
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	913	5024	-4111	652	6542	-5890
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	913	3313	-2400	652	4613	-3960
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		1712	-1712		1929	-1929
3.1.आ.2 डेट लिखत	0	2203	-2203	0	1648	-1648
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		2203	-2203		1648	-1648
3.2 पोर्टफोलियो निवेश	**171412**	**182784**	**-11372**	**185550**	**185727**	**-177**
3.2अ भारत में पोर्टफोलियो निवेश	170667	182102	-11435	184185	184270	-85
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	144811	156671	-11860	157600	158838	-1238
3.2.2 डेट प्रतिभूतियां	25856	25431	425	26585	25431	1154
3.2आ. भारत द्वारा पोर्टफोलियो निवेश	745	682	63	1365	1458	-93
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**6569**	**12105**	**-5536**	**6549**	**12194**	**-5646**
3.4 अन्य निवेश	**83662**	**90450**	**-6789**	**245328**	**245894**	**-565**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	25919	22776	3143	25932	20995	4936
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी कर्ज मूवमेंट; एनआरजी)	8	5	2	0	118	-118
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	25912	22771	3141	25932	20877	5054
3.4.2.3 सामान्य सरकार			0			0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र			0			0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	37480	45347	-7867	197424	199769	-2345
3.4.3अ भारत को ऋण	27853	35728	-7875	20853	22000	-1147
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	9627	9619	8	176571	177769	-1198
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	52	59	-7	52	34	18
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	19253	15241	4012	24451	13034	11417
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	958	7028	-6071	-2530	12061	-14592
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार			0			0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**37660**	**0**	**37660**	**24409**	**0**	**24409**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण			0			0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए			0			0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए			0			0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	37660	0	37660	24409	0	24409
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**319938**	**308785**	**11154**	**484292**	**469931**	**14361**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	170159	190178	-20019	186466	196340	-9874
4.2 ऋण लिखत	111161	111578	-418	275948	261530	14418
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	38618	7028	31590	21878	12061	9817
5. निवल भूल-चूक	**298**	**0**	**298**	**0**	**1206**	**-1206**

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक।

सं. 43: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़)

मद	अक्टू.-दिसं. 2024			अक्टू.-दिसं. 2025 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	**2210485**	**2306051**	**-95566**	**2449283**	**2566661**	**-117378**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**1801569**	**2038890**	**-237321**	**1986477**	**2308416**	**-321939**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**927514**	**1597355**	**-669841**	**995321**	**1829663**	**-834342**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	923917	1432939	-509021	992333	1625781	-633449
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	3597	0	3597	2988	0	2988
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	164417	-164417	0	203881	-203881
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**874055**	**441535**	**432520**	**991157**	**478754**	**512403**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	2061	262	1798	3288	575	2713
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	689	2574	-1886	1066	4143	-3078
1.अ.ख.3 परिवहन	69916	74723	-4807	73762	75571	-1809
1.अ.ख.4 यात्रा	85035	70697	14338	88432	80662	7771
1.अ.ख.5 निर्माण	8843	7044	1799	12218	7322	4896
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	7347	7553	-206	7910	7415	495
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	17623	6256	11367	17241	7793	9448
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	5245	38627	-33383	4380	40651	-36272
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	407907	62636	345271	484003	64829	419174
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	250030	154153	95877	286231	171639	114591
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	9693	10492	-799	10633	9979	654
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी माल और सेवाएं	1413	2590	-1177	1477	2989	-1512
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	8255	3926	4329	516	5185	-4669
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**104233**	**242936**	**-138702**	**124704**	**233403**	**-108700**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	18413	8831	9582	20074	10212	9861
1.आ.2 निवेश आय	68363	227407	-159044	70480	211391	-140911
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	22221	144710	-122490	24884	134035	-109151
1.आ.2.2 पोर्टफोलियो निवेश	800	21930	-21130	713	16337	-15624
1.आ.2.3 अन्य निवेश	5827	59043	-53216	9575	59580	-50005
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	39515	1724	37791	35307	1438	33869
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	17457	6698	10760	34150	11801	22350
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**304682**	**24225**	**280457**	**338102**	**24841**	**313261**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	303985	21662	282323	337235	22074	315160
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	296144	15800	280343	328712	16591	312121
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	7842	5862	1980	8522	5483	3039
1.इ.2 सामान्य सरकार	697	2563	-1866	867	2767	-1900
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**1564**	**2720**	**-1156**	**2034**	**1879**	**155**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	136	1275	-1139	223	650	-427
2.2 पूँजी अंतरण	1428	1445	-17	1811	1229	582
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**2702200**	**2607995**	**94204**	**4315583**	**4187611**	**127972**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**174285**	**198020**	**-23735**	**200114**	**232721**	**-32607**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	166573	136974	29599	194301	159739	34562
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	144168	132068	12100	180432	153925	26507
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	94051	132068	-38017	121097	153925	-32828
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	50117	0	50117	59336	0	59336
3.1.अ.2 ऋण लिखत	22405	4905	17500	13868	5813	8055
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	22405	4905	17500	13868	5813	8055
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	7712	61046	-53334	5814	72983	-67169
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	7712	42436	-34724	5814	58297	-52483
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	7712	27980	-20268	5814	41104	-35291
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	14456	-14456	0	17192	-17192
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	18610	-18610	0	14686	-14686
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	18610	-18610	0	14686	-14686
3.2 पोर्टफोलियो निवेश	**1447744**	**1543792**	**-96048**	**1653457**	**1655037**	**-1580**
3.2अ भारत में पोर्टफोलियो निवेश	1441453	1538030	-96577	1641292	1642046	-754
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1223076	1323243	-100167	1404393	1415426	-11033
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	218376	214787	3590	236899	226620	10279
3.2आ. भारत द्वारा पोर्टफोलियो निवेश	6291	5762	529	12165	12990	-825
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**55483**	**102239**	**-46756**	**58355**	**108666**	**-50311**
3.4 अन्य निवेश	**706607**	**763945**	**-57338**	**2186148**	**2191187**	**-5039**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	218915	192367	26549	231079	187090	43989
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी कर्ज मूवमेंट; एनआरजी)	64	45	19	0	1048	-1048
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	218851	192322	26530	231079	186041	45038
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	316555	382999	-66444	1759265	1780159	-20894
3.4.3अ भारत को ऋण	235245	301756	-66511	185821	196040	-10219
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	81310	81243	67	1573443	1584119	-10675
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	437	497	-59	463	305	158
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	162611	128721	33889	217889	116152	101737
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	8089	59361	-51272	-22548	107481	-130029
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**318081**	**0**	**318081**	**217509**	**0**	**217509**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	318081	0	318081	217509	0	217509
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**2702200**	**2607995**	**94204**	**4315583**	**4187611**	**127972**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	1437168	1606245	-169077	1661622	1749610	-87988
4.2 ऋण लिखत	938862	942390	-3527	2459000	2330520	128480
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	326170	59361	266809	194960	107481	87480
5. निवल भूल-चूक	**2518**	**0**	**2518**	**0**	**10749**	**-10749**

टिप्पणी : प्रा : प्रारंभिक

सं. 44: भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी $)

मद	वित्तीय वर्ष/तिमाही के अंत की स्थिति के अनुसार							
	2024-25		2024		2025			
			दिसं.		सितं.		दिसं.	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	270441	556974	260755	547234	288909	562196	296446	558998
1.1 इक्विटी पूंजी*	173559	521931	166493	512997	187193	525834	193082	522188
1.2 अन्य पूंजी	96882	35043	94262	34237	101716	36362	103364	36810
2. पोर्टफोलियो निवेश	15396	272039	12039	276516	16649	258740	16532	255905
2.1 इक्विटी	10339	141938	9197	155573	12559	133005	10126	130110
2.2 डेट	5057	130101	2843	120943	4091	125735	6407	125795
3. अन्य निवेश	179812	634065	162267	610964	179570	635651	197307	643603
3.1 व्यापार ऋण	33680	131163	33324	135571	31849	135032	34483	146442
3.2 ऋण	27058	250520	23408	240572	25838	258489	26795	259928
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	80425	167598	69581	165713	80770	168875	90192	173889
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	38649	62797	35954	47527	41113	50569	45836	40682
3.5 विशेष आहरण अधिकार (निवल)		21987		21581		22687		22662
4. आरक्षित निधियाँ	668326		635701		700089		687734	
5. कुल आस्तियां/देयताएं	1133976	1463079	1070762	1434714	1185216	1456587	1198020	1458506
6. निवल आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)	-329103		-363951		-271371		-260486	

टिप्पणी: * इक्विटी पूंजी में निवेश निधि और पुनर्निवेशित अर्जन का शेयर शामिल है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 45: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2024-25	2025	2026		वि.व. 2024-25	2025	2026	
		फर.	जन.	फर.		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	4	5	6	7
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)	**47.40**	**3.72**	**4.35**	**4.37**	**296218030**	**25171733**	**32155354**	**29363078**
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	17.87	1.16	1.61	1.62	185733719	14137926	18709470	17227564
1.1.1 आउटराइट	10.56	0.63	0.90	0.94	16056018	1088598	1235356	1339433
1.1.2 रेपो	4.72	0.33	0.46	0.46	77286611	5916603	7775968	6696115
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.58	0.20	0.25	0.22	92391091	7132725	9698147	9192017
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	28.06	2.45	2.64	2.62	100639565	9957432	12450917	11010746
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.46	0.12	0.10	0.13	9844746	1076374	994967	1124767
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	**3024.55**	**244.20**	**316.99**	**305.85**	**201387682**	**16099371**	**19176704**	**18859418**
1.1 ग्राहक लेनदेन	3010.32	243.05	315.76	304.72	181153129	14226027	17580604	17509377
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	14.23	1.16	1.23	1.14	20234553	1873344	1596100	1350041
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	**2061014.91**	**177394.61**	**233364.66**	**219247.40**	**79881976**	**6497660**	**8078680**	**7793908**
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	3.64	0.28	0.24	0.23	190	16	14	14
2.2 एपीबीएस $	32964.43	3103.12	2616.49	2119.52	554034	57097	81195	51081
2.3 आईएमपीएस	56249.68	4048.29	3740.33	3360.96	7139110	563082	672989	642474
2.4 एनएसीएच जमा $	16938.86	1533.06	1248.95	1702.37	1670223	140881	161580	164970
2.5 एनईएफटी	96198.05	7647.93	8724.20	8122.47	44461464	3540103	4329421	4251141
2.6 यूपीआई @	1858660.25	161061.93	217034.45	203941.84	26056955	2196482	2833481	2684229
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	17.24	1.15	1.14	2.32	185	13	12	25
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	**21659.95**	**1862.80**	**2016.80**	**1989.09**	**2208583**	**193068**	**240345**	**235001**
3.1 भीम आधार पे @	230.08	15.67	17.87	16.45	6907	494	648	636
3.2 एनएसीएच नामे $	19762.28	1701.10	1865.64	1849.39	2199327	192387	239514	234191
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1667.59	146.03	133.29	123.25	2349	186	184	174
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	**63861.15**	**5052.09**	**6415.41**	**5855.08**	**2605110**	**201522**	**237042**	**210427**
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	47740.76	3969.59	5397.11	4937.96	2109197	167208	199085	177292
4.1.1 पीओएस आधारित $	24571.10	1999.96	2674.95	2434.00	795022	62125	75988	67435
4.1.2 अन्य $	23169.66	1969.63	2722.16	2503.95	1314175	105083	123097	109857
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	16120.39	1082.50	1018.29	917.12	495914	34314	37957	33135
4.2.1 पीओएस आधारित $	11980.33	803.42	773.20	689.77	332556	23216	25513	21862
4.2.2 अन्य $	4140.06	279.07	245.10	227.36	163358	11098	12444	11273
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	**70254.08**	**6398.44**	**9537.91**	**8359.24**	**216751**	**19236**	**27626**	**25969**
5.1 वालेट	52898.40	4850.75	7716.41	6652.06	154066	14404	20985	19829
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	17355.68	1547.69	1821.50	1707.18	62686	4833	6641	6140
5.2.1 पीओएस आधारित $	8240.14	641.84	827.76	793.50	11512	969	1582	1427
5.2.2 अन्य $	9115.54	905.86	993.74	913.68	51174	3863	5059	4713
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	**6095.38**	**462.02**	**458.71**	**430.51**	**7113350**	**540834**	**601415**	**579783**
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6095.38	462.02	458.71	430.51	7113350	540834	601415	579783
6.2 अन्य	0.00	–	–	–	–	–	–	–
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**2222885.46**	**191169.95**	**251793.49**	**235881.31**	**92025771**	**7452321**	**9185108**	**8845088**
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**2225910.01**	**191414.16**	**252110.48**	**236187.16**	**293413453**	**23551692**	**28361812**	**27704507**
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**2219814.63**	**190952.14**	**251651.77**	**235756.65**	**286300103**	**23010857**	**27760397**	**27124723**

भाग II- भुगतान माध्यम और चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	FY 2024-25	2025	2026		FY 2024-25	2025	2026	
		फर.	जन.	फर.		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	4	5	6	7
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1. मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	**1756976.91**	**150031.46**	**199030.19**	**186834.81**	**39206221**	**3215517**	**4120743**	**3914509**
1.1 इंट्राबैंक $	110801.96	8703.42	10652.94	9717.48	7207439	558355	709083	685836
1.2 अंतर-बैंक $	1646174.95	141328.04	188377.24	177117.33	31998782	2657162	3411659	3228673
2. इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	**47478.09**	**3635.80**	**3722.95**	**3521.30**	**131858133**	**10339284**	**13897998**	13824038
2.1 अंतबैंक @	13056.37	1003.69	844.98	804.89	69086996	5354635	7378948	7438766
2.2 अंतर-बैंक @	34421.72	2632.11	2877.97	2716.41	62771136	4984649	6519051	6385272
बी. एटीएम								
3. एटीएम से नकद निकासी $ (3.1 से 3.3)	**60308.11**	**4497.97**	**4437.06**	**4168.36**	**3063077**	**235618**	**240472**	**231465**
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना $	97.25	6.84	6.97	6.35	5084	370	394	364
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	59965.70	4473.77	4412.00	4145.12	3046987	234408	239172	230242
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	245.16	17.36	18.09	16.89	11005	840	906	859
4. पीओएस पर नकद निकासी $ (4.1 से 4.2)	**3.58**	**0.22**	**0.15**	**0.14**	**37**	**2**	**2**	2
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	3.33	0.19	0.12	0.11	35	2	2	2
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	0.25	0.03	0.02	0.03	3	0	0	0
5. माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	**11640.55**	**921.64**	**956.67**	**867.37**	**296622**	**23605**	**24737**	24595
5.1 एईपीएस @	11640.55	915.09	926.03	956.67	296622	23246	24737	24595

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2025 तक	2025	2026	
		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1. कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	**11006.97**	**10949.92**	**11544.09**	**11594.71**
1.1 क्रेडिट कार्ड	1098.85	1093.15	1166.52	1177.05
1.2 डेबिट कार्ड	9908.12	9856.77	10377.57	10417.67
2. पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	**13401.46**	**13619.31**	**22053.38**	**22673.29**
2.1 वॉलेट @	8678.44	9006.43	17268.45	17930.89
2.2 कार्ड @	4723.02	4612.88	4784.92	4742.40
3. एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	**2.56**	**2.58**	**2.52**	**2.53**
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम $	2.20	2.22	2.14	2.15
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम $	0.36	0.36	0.38	0.38
4. माइक्रो एटीएम की संख्या @	**14.82**	**14.68**	**13.92**	**13.90**
5. पीओएस टर्मिनलों की संख्या	**110.98**	**107.18**	**115.45**	**116.65**
6. भारत क्यूआर @	**67.18**	**65.48**	**58.44**	**58.97**
7. यूपीआई क्यूआर *	**6579.30**	**6496.91**	**7383.80**	**7542.04**

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
#: सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया है जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।
$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिला दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के बाद से डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

भाग I-ए. निपटान प्रणाली
1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-पक्षीय रेपो 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।

भाग I-बी. भुगतान प्रणाली
4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।
5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल है।
5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।
6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।

भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल
1: मोबाइल भुगतान -
o बैंकों के मोबाइल ऐप्स और यूपीआई ऐप्स के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।
o जुलाई 2017 के डेटा में मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत केवल व्यक्तिगत भुगतान और कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉरपोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके किए गए वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।

भाग II-बी. एटीएम
3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना
3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलए को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

आवसरिक शृंखला

सं. 46: लघु बचत

(₹ करोड़)

प्रणाली		2024-25	2024	2025		
			नवं.	सितं.	अक्तू.	नवं.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	**प्राप्तियां**	**192292**	**12130**	**31653**	**17124**	**18664**
	बकाया	**2052408**	**1940611**	**2160573**	**2177404**	**2195873**
1.1 कुल जमाराशियां	**प्राप्तियां**	**144769**	**9998**	**28654**	**14627**	**16185**
	बकाया	**1443556**	**1361210**	**1545057**	**1559684**	**1575869**
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	20641	-205	1780	-2367	374
	बकाया	212332	199017	226078	223711	224085
1.1.2 सुकन्या समृद्धि योजना	प्राप्तियां	41391	2005	3546	2762	2255
	बकाया	199001	169154	213616	216378	218633
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	16620	1710	4019	2403	2207
	बकाया	285630	278161	298250	300653	302860
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	24859	2436	6421	3760	3099
	बकाया	200326	187824	218562	222322	225421
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	32755	3052	10752	7075	6502
	बकाया	338531	322122	368264	375339	381841
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	165641	152099	185890	190552	194944
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	14819	13491	17741	18526	19228
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	10816	9773	12538	13020	13379
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	147255	146759	152095	153241	154290
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	9171	1005	2284	1073	1804
	बकाया	206307	202963	219737	220810	222614
1.1.9 डाक घर संचयी मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	-676	-6	-147	-77	-56
	बकाया	1071	1617	192	115	59
1.1.11 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन	प्राप्तियां	8	1	-1	-2	0
	बकाया	358	352	358	356	356
1.2 बचत प्रमाणपत्र	**प्राप्तियां**	**32992**	**1788**	**3097**	**2387**	**2328**
	बकाया	**446106**	**431065**	**455242**	**457336**	**459469**
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	10891	1180	3914	2376	2269
	बकाया	194798	190261	206112	208488	210757
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	12166	-174	1977	1582	1057
	बकाया	232726	225184	241167	242749	243806
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.7 एम.एस. प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	9935	782	-2794	-1571	-998
	बकाया	28212	22543	19507	17936	16938
1.2.8 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	-9630	-6923	-11544	-11837	-12032
1.3 लोक भविष्य निधि	**प्राप्तियां**	**14531**	**344**	**-98**	**110**	**151**
	बकाया	**162746**	**148336**	**160274**	**160384**	**160535**

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डेटा निवल प्राप्तियाँ हैं, *अर्थात* सकल प्राप्तियों से सकल भुगतान को घटाने पर प्राप्त।
स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

सं. 47: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2024	2025			
	दिसं.	मार्च	जून	सितं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	**11422728**	**11642652**	**11854200**	**12137000**	**12393606**
1. वाणिज्यिक बैंक	37.98	36.18	35.28	35.43	34.31
2. सहकारी बैंक	1.36	1.29	1.29	1.32	1.33
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.65	0.76	0.59	0.60	0.55
4. बीमाकृत कंपनियां	26.14	25.81	25.95	25.81	25.89
5. म्यूच्युअल फंड	3.11	2.68	2.46	2.77	2.74
6. भविष्य निधियां	4.25	4.24	4.35	4.45	4.58
7. पेंशन निधि	5.05	4.91	4.96	4.90	4.77
8. वित्तीय संस्थाएं	0.64	0.71	0.74	0.76	0.76
9. कॉरपोरेट	1.45	1.49	1.26	1.25	1.23
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	2.81	3.12	2.80	2.97	2.96
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	10.55	12.78	14.21	13.54	14.52
12. अन्य	6.01	6.01	6.13	6.22	6.35
12.1 राज्य सरकार	2.21	2.25	2.29	2.37	2.43

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2024	2025			
	दिसं.	मार्च	जून	सितं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	**6055711**	**6399564**	**6524417**	**6721556**	**6905975**
1. वाणिज्यिक बैंक	35.11	35.40	35.54	35.00	35.31
2. सहकारी बैंक	3.22	3.08	3.02	3.06	3.07
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.53	0.61	0.60	0.65	0.64
4. बीमाकृत कंपनियां	25.16	24.07	24.12	24.12	23.97
5. म्यूच्युअल फंड	1.89	1.93	1.84	2.16	2.04
6. भविष्य निधियां	22.90	23.60	23.72	23.65	23.43
7. पेंशन निधि	4.82	5.07	4.96	5.10	5.16
8. वित्तीय संस्थाएं	1.58	1.48	1.59	1.61	1.62
9. कॉरपोरेट	1.97	2.05	1.93	1.93	1.98
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.03	0.05	0.02	0.02	0.01
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.58	0.55	0.54	0.53	0.51
12. अन्य	2.19	2.10	2.12	2.17	2.26
12.1 राज्य सरकार	0.26	0.25	0.25	0.27	0.28

खज़ाना बिल					
श्रेणी	2024	2025			
	दिसं.	मार्च	जून	सितं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	**760045**	**790381**	**784059**	**754280**	**765131**
1. वाणिज्यिक बैंक	40.45	46.58	42.87	39.45	35.79
2. सहकारी बैंक	1.22	2.17	1.80	1.58	1.21
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	1.41	2.09	1.10	2.03	1.46
4. बीमाकृत कंपनियां	4.73	4.23	4.07	4.26	4.45
5. म्यूच्युअल फंड	15.41	16.15	15.72	17.60	17.98
6. भविष्य निधियां	0.04	0.20	0.09	0.07	0.09
7. पेंशन निधि	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
8. वित्तीय संस्थाएं	6.77	7.73	6.31	6.34	5.57
9. कॉरपोरेट	4.56	4.50	3.77	3.80	3.74
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.12	0.09	0.02	0.01	0.02
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. अन्य	25.29	16.23	24.26	24.85	29.68
12.1 राज्य सरकार	20.11	11.23	18.34	18.53	21.91

टिप्पणियाँ: (1) बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फॉर्मेट संशोधित किया है।
(2) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों में विशेष प्रतिभूतियां और सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड शामिल हैं।
(3) राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।
(4) वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है।
(5) अन्य' श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।
(6) सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक गैर-बैंक का एक बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 48: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़)

मद	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 संअ	2025-26 बअ
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	**6353359**	**7098451**	**7880522**	**8579810**	**9780079**	**10552103**
1.1 विकास संबंधी	3823423	4189146	4701611	5080834	5902870	6267297
1.1.1 राजस्व	3150221	3255207	3574503	3662324	4242036	4460702
1.1.2 पूंजी	550358	861777	1042159	1330917	1516738	1641425
1.1.3 ऋण	122844	72163	84949	87593	144096	165170
1.2 गैर-विकास संबंधी	2442941	2810388	3069896	3379466	3740051	4132065
1.2.1 राजस्व	2271637	2602750	2895864	3182576	3547080	3867191
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	1060602	1226672	1377807	1557492	1685503	1883576
1.2.2 पूंजी	169155	175519	171131	192384	187711	259891
1.2.3 ऋण	2148	32119	2902	4506	5259	4983
1.3 अन्य	86995	98916	109015	119510	137158	152741
2. कुल प्राप्तियां	**6397162**	**7156342**	**7855370**	**8637956**	**9518133**	**10451896**
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3688030	4823821	5447913	6105757	7125956	7875214
2.1.1 कर प्राप्तियां	3193390	4160414	4809044	5407849	6080098	6808169
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	2076013	2626553	2865541	3170243	3545348	3937254
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	1114805	1530636	1939559	2233860	2530235	2866137
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	2572	3225	3943	3745	4516	4778
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	494640	663407	638870	697908	1045858	1067045
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	33448	35250	42975	53199	56247	70403
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	64994	44077	62716	62275	62562	104103
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	16951	27665	15970	28918	26747	32172
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	48044	16412	46746	33357	35815	71931
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**2600335**	**2230553**	**2369892**	**2411778**	**2591561**	**2572787**
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	2530155	2194406	2332768	2356657	2559568	2549296
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	890012	627255	687904	438038	907254	...
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	107493	350911	529	-257913	314894	...
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	1640143	1567151	1644864	1918619	1652314	...
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	70180	36147	37124	55121	31992	23490
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	2530155	2194406	2332768	2356657	2559568	2549296
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	1696012	1213169	1651076	1921529	1996297	2050268
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	458801	526693	358764	415472	437189	304076
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	41273	28100	13880	19847	16957	17531
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	4545	42153	68803	90431	76177	42662
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	25682	42203	51989	22555	7954	48430
3ख.1.6 नकद शेष	-43802	-57891	25152	-58146	261946	100207
3ख.1.7 अन्य	347643	399980	163104	-55032	-236951	-13878
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	70180	36147	37124	55121	31992	23490
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल वितरण	*32.0*	*30.1*	*29.3*	*28.5*	*29.6*	*29.6*
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियां	*32.2*	*30.3*	*29.2*	*28.7*	*28.8*	*29.3*
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां	*18.6*	*20.4*	*20.3*	*20.3*	*21.5*	*22.1*
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियां	*16.1*	*17.6*	*17.9*	*18.0*	*18.4*	*19.1*
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल वित्तीय घाटा	*13.1*	*9.5*	*8.8*	*8.0*	*7.8*	*7.2*

... : उपलब्ध नहीं। सं.अ. संशोधित अनुमान, ब.अ. बजट अनुमान।

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

टिप्पणियाँ : जीडीपी डेटा 2011-12 के आधार पर है। 2025-26 के लिए जीडीपी केंद्रीय बजट 2025-26 से है।
डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
1 और 2: डेटा केंद्र सरकार (एनएसएसएफ को पुनर्भुगतान सहित) और राज्य सरकारों के निवल पुनर्भुगतान से संबंधित है।
1.3: राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर और समनुदेशन का प्रतिनिधित्व करता है।
2: डेटा केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में निवल भिन्नता को दर्शाता है और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियां शामिल हैं।
3ए.1.1: आरबीआई रिकॉर्ड के अनुसार डेटा।
3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधार।
3बी.1.2: राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवल निवेश को दर्शाता है।
नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण यह डेटा पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।
3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।
3बी.1.7: ट्रेजरी बिल, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकद शेष निवेश लेखा शामिल हैं।

स्रोत : केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

सं.49: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	फरवरी-2026 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	5110.16	28	2695.40	8	1948.16	3
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	दिल्ली	-	-	-	-	-	-
7	गोवा	-	-	-	-	-	-
8	गुजरात	-	-	-	-	-	-
9	हरियाणा	1074.07	6	-	-	-	-
10	हिमाचल प्रदेश	-	-	596.87	7	-	-
11	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	41.79	2	-	-	-	-
12	झारखंड	-	-	-	-	-	-
13	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
14	केरल	1891.08	27	1061.10	20	-	-
15	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
16	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
17	मणिपुर	-	-	-	-	-	-
18	मेघालय	463.78	14	-	-	-	-
19	मिज़ोरम	58.65	3	-	-	-	-
20	नगालैंड	-	-	-	-	-	-
21	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
22	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
23	पंजाब	5986.71	28	605.92	20	-	-
24	राजस्थान	3978.84	21	194.76	5	-	-
25	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
26	तेलंगाना	3360.29	22	1891.95	5	-	-
27	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
29	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
30	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणियाँ: 1) राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेष तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपार्श्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्पकालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

3) राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

4) प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, प्राप्त औसत राशि निकाली जाती है।

5) -: नगण्य।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 50: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	फरवरी 2026 के दौरान			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	बजट स्थिरीकरण कोष (बीएसएफ)	नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	8066	8099	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	3171	9	0	5300
3	असम	6734	97	0	0
4	बिहार	15471	1211	0	6000
5	छत्तीसगढ़	8882	1032	0	9596
6	दिल्ली	-	-	0	0
7	गोवा	1265	441	0	0
8	गुजरात	16518	551	0	0
9	हरियाणा	2821	1842	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
11	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	56	56	0	0
12	झारखंड	3243	-	810	0
13	कर्नाटक	22809	2499	0	28378
14	केरल	3603	1951	0	0
15	मध्य प्रदेश	-	1376	0	1200
16	महाराष्ट्र	67626	11388	0	0
17	मणिपुर	75	152	0	0
18	मेघालय	1376	132	0	0
19	मिज़ोरम	596	104	0	0
20	नगालैंड	2046	50	0	0
21	उड़ीसा	19717	2211	22262	15269
22	पुदुचेरी	626	-	0	1350
23	पंजाब	10820	991	0	0
24	राजस्थान	3015	2394	0	5750
25	तमिलनाडु	3719	-	0	11457
26	तेलंगाना	7597	6253	0	0
27	त्रिपुरा	1425	32	0	0
28	उत्तराखंड	29045	7359	0	20000
29	उत्तरप्रदेश	6104	328	0	0
30	पश्चिम बंगाल	15429	1166	0	6000
	कुल	**261854**	**51722**	**23072**	**110299**

टिप्पणियाँ: 1. सीएसएफ, जीआरएफ और बीएसएफ आरबीआई के पास रखी गयी आरक्षित निधियां हैं।
2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल में राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं।
3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।

सं. 51: राज्य सरकारों की बाजार उधारियाँ

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य	2023-24		2024-25		2025-26						2025-26 में अब तक ली गई कुल राशि	
						दिसंबर		जनवरी		फरवरी			
		ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	सकल	निवल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश	68400	55330	78205	57123	7000	5000	9000	6000	6900	5900	71972	54922
2	अरुणाचल प्रदेश	902	672	1010	704	375	375	-	-	-	-	575	445
3	असम	18500	16000	19000	13850	1900	1900	4000	2550	4000	1750	18204	12054
4	बिहार	47612	29910	47546	30890	5310	5310	6000	2000	6100	1100	51910	37332
5	छत्तीसगढ़	32000	26213	24500	16913	2000	500	4000	3300	6000	6000	21470	13770
6	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	गोवा	2550	1560	1050	250	100	-54	-	-100	100	-	1300	96
8	गुजरात	30500	11947	38200	16280	6000	3200	2000	-1500	7000	4700	41500	17240
9	हरियाणा	47500	28364	49500	31710	4000	2100	3000	1900	8000	5500	41500	25670
10	हिमाचल प्रदेश	8072	5856	7359	4725	1350	1350	-	-	-	-289	8269	5830
11	जम्मू और कश्मीर	16337	13904	13170	11416	1070	920	1100	1100	1000	650	10725	8335
12	झारखंड	1000	-2505	3500	-2005	-	-500	-	-500	-	-1850	2000	-3350
13	कर्नाटक	81000	63003	92025	71525	12000	7813	24000	21000	31000	29000	67000	47813
14	केरल	42438	26638	53666	37966	3850	2800	2000	1250	3000	1250	41338	25038
15	मध्य प्रदेश	38500	26264	63400	47206	6400	4900	4000	1500	15350	14150	68827	54127
16	महाराष्ट्र	110000	79738	123000	90917	10000	6000	3000	500	20350	17350	122350	91850
17	मणिपुर	1426	1076	1500	1037	150	75	-	-	-	-100	1650	1050
18	मेघालय	1364	912	1882	997	984	934	-	-80	-	-70	2634	1454
19	मिज़ोरम	901	641	1169	939	105	105	115	50	115	115	1030	830
20	नगालैंड	2551	2016	1550	950	500	500	-	-100	500	300	1400	650
21	उड़ीसा	0	-4658	20780	17780	1000	500	3000	1500	-	-	11000	9000
22	पुदुचेरी	1100	475	1600	880	350	350	-	-100	-	-150	900	200
23	पंजाब	42386	29517	40828	32466	2000	1400	4000	3700	5000	4000	40750	29196
24	राजस्थान	73624	49718	75185	49479	6000	4500	4300	1300	4000	776	68600	42544
25	सिक्किम	1916	1701	1951	1621	-	-	-	-225	250	250	1750	1300
26	तमिलनाडु	113001	75970	123625	89894	23000	20250	18700	15700	18000	13475	132000	94725
27	तेलंगाना	49618	39385	56209	42199	9300	8300	3500	2500	9000	8000	81800	66450
28	त्रिपुरा	0	-550	0	-150	500	500	-	-	800	725	2100	1525
29	उत्तरप्रदेश	97650	85335	45000	23185	11015	9437	-	-4000	12000	7000	46515	15728
30	उत्तराखंड	6300	3800	10400	8000	1500	1300	2500	2500	500	-300	10000	6600
31	पश्चिम बंगाल	69910	48910	76500	54600	11965	9665	10000	7500	12255	8755	61720	41220
	कुल	**1007058**	**717140**	**1073310**	**753345**	**129724**	**99429**	**108215**	**69245**	**171220**	**127987**	**1032789**	**703644**

- : शून्य।

टिप्पणी: 31 अक्तूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देयताएं जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देयताओं के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं.52 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह लिखत-वार

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2022-23				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
	1	2	3	4	5
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**287802.7**	**297217.6**	**293954.9**	**451660.3**	**1330635.4**
जीडीपी का प्रतिशत	*4.4*	*4.6*	*4.3*	*6.4*	*4.9*
I. वित्तीय आस्तियां	**577822.4**	**632335.6**	**748109.7**	**968986.1**	**2927253.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*8.9*	*9.8*	*11.0*	*13.6*	*10.9*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	**185429.1**	**317361.2**	**280233.1**	**325852.7**	**1108876.2**
(ए) बैंक जमाराशियां	**163172.4**	**299532.7**	**256399.7**	**307866.8**	**1026971.5**
i. वाणिज्यिक बैंक	158613.3	300565.0	248459.8	284968.0	992606.2
ii. सहकारी बैंक	4559.0	-1032.4	7939.8	22898.9	34365.3
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	**22256.8**	**17828.6**	**23833.5**	**17985.9**	**81904.7**
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	**6504.8**	**2076.7**	**8081.6**	**2234.0**	**18897.1**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	4230.6	3267.2	3246.9	3945.8	14690.4
ii. आवास वित्त कंपनियां	2274.2	-1190.5	4834.7	-1711.8	4206.6
2. जीवन बीमा निधियाँ	**73357.5**	**151737.1**	**167581.7**	**156268.5**	**548944.9**
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	**146719.1**	**118171.9**	**136388.4**	**216513.6**	**617793.1**
4. मुद्रा	**66438.9**	**-54579.3**	**76760.1**	**148990.1**	**237609.7**
5. निवेश	**51502.6**	**48530.1**	**49778.6**	**64150.6**	**213961.9**
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	35443.5	44484.0	40205.9	58954.5	179087.8
(बी) इक्विटी	13560.9	1378.2	6434.1	1664.9	23038.1
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	**54375.1**	**51114.5**	**37367.7**	**57210.6**	**200068.0**
II. वित्तीय देयताएँ	**290019.7**	**335118.0**	**454154.8**	**517325.8**	**1596618.3**
जीडीपी का प्रतिशत	*4.5*	*5.2*	*6.7*	*7.3*	*5.9*
ऋण/उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	**289781.5**	**334879.7**	**453916.6**	**517087.5**	**1595665.3**
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**234235.0**	**263450.2**	**370782.9**	**383843.2**	**1252311.4**
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	230283.8	261265.3	368304.6	331291.0	1191144.8
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	**55546.4**	**71429.5**	**83133.7**	**133244.3**	**343353.9**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	30531.7	36650.3	55791.7	94565.3	217539.1
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	22336.7	33031.2	24903.3	36745.8	117017.0
iii. बीमा कंपनियाँ	2678.0	1747.9	2438.7	1933.2	8797.8
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	**33.7**	**33.7**	**33.7**	**33.7**	**135.0**
3. सामान्य सरकार	**204.5**	**204.5**	**204.5**	**204.5**	**818.0**

सं.52 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह लिखत-वार *(जारी)*

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2023-24				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
	1	2	3	4	5
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**349607.1**	**283994.4**	**294431.6**	**666547.4**	**1594580.4**
जीडीपी का प्रतिशत	*4.8*	*3.9*	*3.8*	*8.4*	*5.3*
I. वित्तीय आस्तियां	**671244.1**	**810128.8**	**805066.2**	**1187279.1**	**3473718.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*9.3*	*11.2*	*10.4*	*14.9*	*11.5*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	**266680.3**	**407948.0**	**296931.3**	**406706.9**	**1378266.4**
(ए) बैंक जमाराशियां	**253004.1**	**501768.5**	**277432.0**	**390720.4**	**1422924.9**
i. वाणिज्यिक बैंक	243833.9	502260.7	280096.7	383460.6	1409651.9
ii. सहकारी बैंक	9170.2	-492.2	-2664.7	7259.8	13273.0
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	**13676.2**	**-93820.5**	**19499.4**	**15986.5**	**-44658.5**
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	**-485.4**	**-107982.1**	**5337.7**	**1824.9**	**-101304.9**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	6119.3	4782.3	4895.8	1942.9	17740.3
ii. आवास वित्त कंपनियां	-6604.7	-112764.4	441.9	-118.0	-119045.2
2. जीवन बीमा निधियाँ	**157301.9**	**140356.8**	**160135.2**	**189267.6**	**647061.4**
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	**163686.0**	**148356.1**	**153435.1**	**253882.9**	**719360.2**
4. मुद्रा	**-48636.2**	**-36700.8**	**56719.0**	**146643.8**	**118025.7**
5. निवेश	**41014.3**	**72664.6**	**79238.2**	**108336.6**	**301253.8**
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	32085.6	55768.8	60134.6	90973.0	238962.1
(बी) इक्विटी	3756.7	7146.3	9941.1	8236.1	29080.1
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	**91197.8**	**77504.1**	**58607.4**	**82441.4**	**309750.7**
II. वित्तीय देयताएँ	**321637.1**	**526134.4**	**510634.6**	**520731.7**	**1879137.8**
जीडीपी का प्रतिशत	*4.5*	*7.3*	*6.6*	*6.5*	*6.2*
ऋण/उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	**321519.8**	**526016.2**	**510516.4**	**520613.5**	**1878665.8**
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**213606.3**	**868873.9**	**402647.1**	**392330.5**	**1877457.7**
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	208026.5	875654.0	389898.0	382557.9	1856136.4
(बी)अन्य वित्तीय संस्थान	**107913.6**	**-342857.7**	**107869.2**	**128283.0**	**1208.0**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	81448.8	59683.7	85031.8	100836.5	327000.7
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	23784.0	-404294.0	21233.4	25852.9	-333423.7
iii. बीमा कंपनियाँ	2680.7	1752.6	1604.0	1593.6	7631.0
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	**33.7**	**34.7**	**34.7**	**34.7**	**138.0**
3. सामान्य सरकार	**83.5**	**83.5**	**83.5**	**83.5**	**334.0**

सं.52 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह लिखत-वार *(समाप्त)*

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2024-25				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
	1	2	3	4	5
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**551994.2**	**496676.1**	**271043.1**	**674489.0**	**1994202.4**
जीडीपी का प्रतिशत	*7.0*	*6.3*	*3.2*	*7.6*	*6.0*
I. वित्तीय आस्तियां	**840665.3**	**901135.4**	**689663.5**	**1129381.1**	**3560845.4**
जीडीपी का प्रतिशत	*10.6*	*11.5*	*8.1*	*12.8*	*10.8*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	**274567.9**	**403591.4**	**158320.8**	**418183.6**	**1254663.6**
(ए) बैंक जमाराशियां	**254885.4**	**388328.6**	**141290.0**	**401577.5**	**1186081.4**
i. वाणिज्यिक बैंक	251171.1	389734.0	147864.7	395337.4	1184107.2
ii. सहकारी बैंक	3714.3	-1405.4	-6574.7	6240.0	1974.2
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	**19682.4**	**15262.8**	**17030.8**	**16606.1**	**68582.2**
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	**7461.4**	**3041.8**	**4809.8**	**4385.1**	**19698.2**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	6289.7	3230.0	4444.5	4220.0	18184.2
ii. आवास वित्त कंपनियां	1171.7	-188.2	365.4	165.1	1514.0
2. जीवन बीमा निधियाँ	**175427.0**	**178835.2**	**90159.4**	**90393.0**	**534814.6**
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	**170218.2**	**170219.6**	**170758.3**	**281332.6**	**792528.6**
4. मुद्रा	**34212.5**	**-57615.2**	**70840.8**	**162236.1**	**209674.1**
5. निवेश	**120638.2**	**152637.1**	**159255.2**	**103720.8**	**536251.4**
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	106987.0	137618.0	124132.0	97193.0	465930.0
(बी) इक्विटी	14448.0	15645.0	36063.1	7410.3	73566.5
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	**65601.6**	**53467.4**	**40329.0**	**73515.0**	**232913.0**
II. वित्तीय देयताएँ	**288671.1**	**404459.3**	**418620.4**	**454892.1**	**1566642.9**
जीडीपी का प्रतिशत	*3.7*	*5.2*	*4.9*	*5.2*	*4.7*
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	**288492.4**	**404280.6**	**418441.7**	**454713.3**	**1565928.0**
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**205040.4**	**322147.7**	**319626.6**	**387045.6**	**1233860.3**
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	208525.3	321241.4	302569.3	379856.5	1212192.4
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	**83452.0**	**82132.9**	**98815.0**	**67667.7**	**332067.7**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	65813.7	65488.7	75764.5	39833.9	246900.8
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	15125.2	14233.6	20561.4	25756.8	75677.0
iii. बीमा कंपनियाँ	2513.1	2410.7	2489.1	2077.1	9489.9
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	**34.7**	**34.7**	**34.7**	**34.7**	**139.0**
3. सामान्य सरकार	**144.0**	**144.0**	**144.0**	**144.0**	**576.0**

टिप्पणियां: 1. हाउसहोल्ड की निवल वित्तीय बचत से तात्पर्य निवल वित्तीय आस्तियों से है, जिन्हें वित्तीय आस्ति और देयताओं के प्रवाह के बीच अतंर के रूप में मापा जाता है।
2. 2024-25 के लिए प्रारंभिक अनुमान और 2022-23 और 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान।
3. एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, 2024-25 के पहले संशोधित अनुमान जारी होने के साथ 2024-25 के प्रारंभिक अनुमानों में संशोधन किया जाएगा।
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ, सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं।
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

सं.52(बी): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2022	सितं-2022	दिसं-2022	मार्च-2023
	1	2	3	4
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़+जी+एच)	**25621348.1**	**26423992.1**	**27187715.6**	**27844981.1**
जीडीपी का प्रतिशत	*102.8*	*102.6*	*103.3*	*103.5*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	**11843527.1**	**12143059.7**	**12399459.4**	**12707326.2**
i. वाणिज्यिक बैंक	10987692.1	11288257.2	11536717.0	11821685.0
ii. सहकारी बैंक	855834.9	854802.6	862742.4	885641.2
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	**216170.0**	**218246.7**	**226328.2**	**228562.2**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	74794.2	78061.4	81308.3	85254.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	141375.8	140185.3	145020.0	143308.2
(सी) जीवन बीमा निधि	**5325967.3**	**5559681.9**	**5786592.6**	**5795430.6**
(डी) मुद्रा	**2950343.2**	**2895763.9**	**2972524.0**	**3121514.1**
(ई) म्यूचुअल फंड	**2048097.3**	**2260209.7**	**2355315.8**	**2367792.5**
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	**851913.4**	**858591.1**	**864730.6**	**939449.0**
(जी) पेंशन निधि	**744459.2**	**796454.0**	**853412.0**	**898343.0**
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	**1640870.6**	**1691985.1**	**1729352.9**	**1786563.5**
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**8911860.9**	**9246740.6**	**9700657.2**	**10217744.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*35.8*	*35.9*	*36.9*	*38.0*
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**7095467.7**	**7358918.0**	**7729700.9**	**8113544.1**
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	6620073.1	6881338.5	7249643.0	7580934.1
ii. सहकारी बैंक	473897.0	476024.8	478486.9	530915.0
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	**1816393.1**	**1887822.6**	**1970956.3**	**2104200.7**
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	869174.9	905825.3	961617.0	1056182.3
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	835181.3	868212.5	893115.8	929861.7
iii. बीमा निगम	112036.9	113784.8	116223.5	118156.7

सं.52(बी): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक *(जारी)*

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2023	सितं-2023	दिसं-2023	मार्च-2024
	1	2	3	4
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़+जी+एच)	**28754605.9**	**29637615.0**	**30737884.8**	**32025210.0**
जीडीपी का प्रतिशत	*104.2*	*104.4*	*105.0*	*106.3*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	**12960330.3**	**13462098.8**	**13739530.7**	**14130251.1**
i. वाणिज्यिक बैंक	12065518.9	12567779.6	12847876.2	13231336.9
ii. सहकारी बैंक	894811.4	894319.2	891654.5	898914.3
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	**228076.8**	**120094.7**	**125432.4**	**127257.3**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	91373.3	96155.6	101051.4	102994.3
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	136703.5	23939.1	24381.0	24263.0
(सी) जीवन बीमा निधि	**6064436.9**	**6255801.1**	**6553726.0**	**6820611.8**
(डी) मुद्रा	**3072877.9**	**3036177.0**	**3092896.0**	**3239539.8**
(ई) म्यूचुअल फंड	**2626046.1**	**2829859.3**	**3156299.3**	**3387208.3**
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	**955060.6**	**960343.6**	**964851.5**	**1051376.5**
(जी) पेंशन निधि	**970016.0**	**1017975.0**	**1091276.0**	**1172651.0**
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	**1877761.2**	**1955265.4**	**2013872.8**	**2096314.2**
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**10539264.5**	**11065280.7**	**11575797.1**	**12096410.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*38.2*	*39.0*	*39.6*	*40.2*
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**8327150.3**	**9196024.2**	**9598671.3**	**9991001.8**
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	7788960.6	8664614.6	9054512.6	9437070.5
ii. सहकारी बैंक	536409.2	529527.7	542240.6	551852.1
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	**2212114.2**	**1869256.5**	**1977125.7**	**2105408.7**
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	1137631.1	1197314.8	1282346.6	1383183.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	953645.7	549351.7	570585.1	596438.0
iii. बीमा निगम	120837.4	122590.0	124194.0	125787.7

सं.52(बी): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक *(समाप्त)*

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2024	सितं-2024	दिसं-2024	मार्च-2025
	1	2	3	4
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़+जी+एच)	**33253098.6**	**34421189.5**	**34532805.6**	**35264710.9**
जीडीपी का प्रतिशत	*107.9*	*109.6*	*107.2*	*106.6*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	**14385136.5**	**14773465.1**	**14914755.1**	**15316332.6**
i. वाणिज्यिक बैंक	13482508.0	13872242.0	14020106.6	14415444.1
ii. सहकारी बैंक	902628.6	901223.2	894648.5	900888.5
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	**134718.7**	**137760.5**	**142570.3**	**146955.5**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	109284.0	112514.0	116958.5	121178.5
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	25434.7	25246.5	25611.9	25777.0
(सी) जीवन बीमा निधि	**7123527.6**	**7385938.1**	**7272871.3**	**7293099.1**
(डी) मुद्रा	**3273752.3**	**3216137.1**	**3286977.8**	**3449213.9**
(ई) म्यूचुअल फंड	**3866386.1**	**4291914.4**	**4224091.7**	**4128924.5**
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	**1059829.5**	**1063056.1**	**1064212.0**	**1157449.2**
(जी) पेंशन निधि	**1247832.0**	**1337535.0**	**1371615.0**	**1443509.0**
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	**2161915.8**	**2215383.2**	**2255712.2**	**2329227.2**
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**12384902.9**	**12789183.5**	**13207625.1**	**13662338.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*40.2*	*40.7*	*41.0*	*41.3*
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**10196042.2**	**10518189.9**	**10837816.5**	**11224862.1**
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	9645595.7	9966837.1	10269406.4	10649262.8
ii. सहकारी बैंक	548284.4	549069.4	566104.4	573131.8
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	**2188860.7**	**2270993.6**	**2369808.7**	**2437476.4**
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	1448996.8	1514485.5	1590250.0	1630083.9
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	611563.2	625796.8	646358.2	672115.0
iii. बीमा निगम	128300.7	130711.4	133200.5	135277.5

टिप्पणियां: 1. डीपी के अनुपात के रूप में डेटा की गणना एनएसओ द्वारा 30 मई 2025 को जारी राष्ट्रीय आय 2024-25 के अनंतिम अनुमान के आधार पर की गई है।
2. पेंशन निधि में राष्ट्रीय पेंशन योजना की निधि शामिल है।
3. लघु बचत के साथ बकाया जमा राशि भारत सरकार के लेखा महानियंत्रक से प्राप्त की जाती है।
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ, सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं। बकाया जमाराशियों के लिए आकंड़े केवल अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध हैं।
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

1.2 और 6 : वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं ।
3.5 और 3.7 : वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
4.5, 4.6 और 4.7 : माह / वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
4.10 से 4.12 : माह/ वित्त वर्ष के अंतिम नीलामी दिन से संबंधित है।
4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
7.1 और 7.2 : यूएस डॉलर में विदेशी व्यापार से संबंधित है।

सारणी सं. 2

2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल हैं।
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियाँ और अल्पावधि प्रतिभूतियाँ / बॉण्ड जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी, शामिल हैं।

सारणी सं. 4

http ://nsdp.rbi.org.in के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया वायदा संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य अर्थात एक्ज़िम बैंक को विशेष पुनर्वित्त सुविधा 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकडे अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।
1.1: संचलन में मौजूद नोटों में सीबीडीसी-खुदरा (आर) और सीबीडीसी-थोक (डब्ल्यू) शामिल हैं।
1.4: बैंकों द्वारा धारित नकदी में सीबीडीसी-डब्ल्यू शामिल है।
2.2 : आईएमएफ खाता सं. 1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4 : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्ड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम$_2$ और एनएम$_3$ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
2.4 : चुकता पूंजी और आरक्षित राशियां शामिल हैं।
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्ज़िम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल$_1$ और एल$_2$ मासिक आधार पर और एल$_3$ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कॉलम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़े अंतिम और कॉलम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 14

कॉलम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

2.1.1 : राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।
2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं हैं।
4: आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 25

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 31

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।
1 : बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।
2 : संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 33

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/ मूल्यह्रास के लिए शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 35

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान
1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान
'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं / शाखाओं के बीच के ऋण सबंधी लेनदेनों से संबंधित है।
हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 36

1.10 : पत्र-पत्रिकाओं के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 37

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि और विपरीत क्रम का संकेतक है। 6- मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2022-23 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतित किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। नीर//रीर सूचकांकों के संकलन के लिए प्रयुक्त कार्यप्रणाली का ब्यौरा आरबीआई बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में उपलब्ध है।

सारणी सं. 38

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 40, 41, 42, 43 और 44

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 45

भाग I-ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रि-पक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से किए गए डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: वॉलेट के माध्यम से माल और सेवाओं की खरीद और निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेनों के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नै से संबंधित।

6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल हैं। जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृह से संबंधित है।

भाग II-ए अन्य भुगतान चैनल

1 : मोबाइल भुगतान -

- इसमें बैंकों के मोबाइल ऐप और यूपीआई ऐप के जरिए किए गए लेनदेन शामिल हैं।
- जुलाई 2017 के बाद के डेटा में मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत किए गए केवल व्यक्तिगत भुगतान और कॉरपोरेट भुगतान शामिल हैं। मोबााइल के माााध्यम से शुरू, संसााधित और अधिकृत नहीं किए गए, अन्य कॉरपोरेट भुगतान शाामिल नहीं हैं।

2 : इंटरनेट भुगतान - 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी. एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलए को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 47

(-): शून्य/ नगण्य को दर्शाता है।

बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फार्मेट संशोधित किया है।

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में विशेष प्रतिभूतियाँ और सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड शामिल हैं।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है।

'अन्य' श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।

सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक का एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

सारणी सं. 48

जीडीपी डेटा वर्ष 2011-12 के आधार पर आधारित है। वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी केंद्रीय बज़ट 2025-26 से ली गई है। डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन: चुकौती सहित) और राज्य सरकार की निवल चुकौती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डेटा केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार हैं।

3बी. 1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में किए गए निवल निवेश को दर्शाते हैं।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी. 1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी. 1.7: खजाना बिल, वित्तीय संस्थानों से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकदी शेष निवेश खाता सहित।

सारणी सं. 49

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपार्श्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्पकालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ / डब्ल्यूएमए / ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य।

सारणी सं. 50

सीएसएफ और जीआरएफ वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

एटीबी में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों के खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी के लिए अवधारणाएं और कार्यप्रणाली आरबीआई मासिक बुलेटिन की वर्तमान सांख्यिकी के लिए व्यापक मार्गदर्शिका में उपलब्ध हैं (**https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618**)

'वर्तमान सांख्यिकी' का समय शृंखला डेटा https://data.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

विस्तृत व्याख्यात्मक नोट आरबीआई द्वारा जारी प्रासंगिक प्रेस प्रकाशनियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों/विज्ञप्तियों जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका में उपलब्ध हैं।**

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2026	₹350 एक प्रति ₹250 एक प्रति (रियायती दर*) ₹4,000 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,000 (एक वर्ष रियायती दर*)	15 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति 150 अमेरिकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी पुस्तिका 2024-25	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका 2024-25	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्तः 2024-25 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (कांउटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2023-24	₹575 एक प्रति (कांउटर पर) ₹625 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	22 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 45, सं. 1, 2024	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. पंचायती राज संस्थाओं का वित्त	₹300 एक प्रति (कांउटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
8. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2024-25	आरबीआई बुलेटिन जनवरी, 2026 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
9. वार्षिक रिपोर्ट 2024-25	आरबीआई बुलेटिन जून, 2025 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
10. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट-दिसंबर 2025	आरबीआई बुलेटिन जनवरी, 2026 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
11. मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अक्तूबर 2025	आरबीआई बुलेटिन अक्तूबर 2025 में शामिल है।	
12. नगर निगम वित्त पर रिपोर्ट - नवंबर 2024	₹300 एक प्रति (कांउटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
13. बैंकिंग शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी)	₹100 एक प्रति (कांउटर पर) ₹150 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (https://data.rbi.org.in) |
3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-2008 (5 खंड), भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।

* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक / शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

सामान्य अनुदेश

1. सभी संचार निम्न को संबोधित किए जाएँ:
   निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग,
   आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीआरकेडी, डीईपीआर),
   भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर भवन, तल मंजिल,
   सर पी. एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स सं. 1036. मुंबई- 400 001
   टेलीफोन: 022-2260 3000 विस्तार: 4002, ईमेल: spsdepr@rbi.org.in
2. बिक्री के लिए प्रकाशन प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) उपलब्ध हैं।
3. प्रकाशनों को कैश ऑन डिलीवरी के आधार पर नहीं दिया जाएगा।
4. एक बार बेचे गए प्रकाशनों को वापस नहीं लिया जाएगा।
5. प्रकाशन के पिछले अंक आम तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं।
6. जहां रियायती मूल्य का संकेत नहीं दिया गया है, भारत में छात्रों, शिक्षकों, शैक्षिक/ अकादमिक संस्थानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है, बशर्ते पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
7. सदस्यता शुल्क के भुगतान के लिए एनईएफटी को प्राथमिकता दी जाए और भुगतानकर्ता के नाम, सदस्यता संख्या (यदि कोई हो), खाता संख्या, तारीख और राशि सहित लेनदेन विवरण **spsdepr@rbi.org.in** पर ईमेल किया जाए या डाक द्वारा भेजा जाए।
   ए. एनईएफटी ट्रांसफर के लिए अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा और पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाता प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19

   बी. गैर- डिजिटल मोड के माध्यम से सदस्यता के मामले में, कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के नाम पर मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट/ चेक भेजें।
8. 'प्रकाशन प्राप्त न होने' संबंधी शिकायतें दो माह की अवधि के अंदर भेजी जाएं।